

सातवां अंग्रेजी संस्करण १९५६

प्रथम हिन्दी संस्करण १९५३

द्वितीय हिन्दी संस्करण १९५४

तृतीय हिन्दी संस्करण १९५७

चतुर्थ हिन्दी संस्करण
(द्वि० भाग) १९५६

पंचम हिन्दी संस्करण
(द्वि० भाग) १९६१

अनुवादक
मरोत्तम भार्गव
अनुवाद-मन्त्रालय
प्रभुदयाल मेहरावा

© १९६१. द अपर इण्डिया पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड,
नयनऊ

मद्रास
दिल्ली प्रेस, नई दिल्ली

अनुवादकीय

राजनीति-शास्त्र (द्वितीय भाग) के इस पंचम सम्स्करण को पाठकों के हाथों में देते हुए मुझे बड़ी प्रमत्नता हो रही है। पिछले कई वर्षों से लगातार मैं इस ग्रन्थ को मरल और सुबोध बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ ताकि विद्यार्थी राजनीति-शास्त्र के गूढ़ विषयों को मरलता से समझ सकें और उन्हें यह विषय मरल प्रतीत होने लगे। हिन्दी सम्स्करण की बढ़ती हुई माग देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कदाचित् मुझे अपने प्रयत्न में सफलता मिली है और यही मेरी प्रमत्नता का कारण है। पुस्तक के अन्त में अनुक्रमणिका भी दे दी गयी है। आशा है कि इसमें पाठकों को बहुत लाभ होगा।

राजनीति-शास्त्र के विषयों को भली प्रकार से समझने के इच्छुक पाठकों को प्रसिद्ध विचारकों के मूलग्रन्थों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जितना ही विस्तृत उनका अध्ययन होगा उनका ही अधिक उनको विषय का ज्ञान होगा।

—नरोत्तम भागवत

१५ मई, १९६१

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ

१६ विधि (Law)

८०७-८८६

विधि का अर्थ ८०७, विधि की परिभाषा ८२८, विधि के स्रोत (Sources of Law) ८२९, विधि के प्रकार (Types of Law) ८३२, विधि और नैतिकता (Law and Morality) ८३४, नैतिकता और विधि में समानता ८३६, विधि और राज्य (Law and State) ८३७, अन्तर्राष्ट्रीय विधि (International Law) ८३९, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सम्बन्ध ८८६।

१७. राजनीति में उपयोगितावाद (Utilitarianism in Politics)

८८७-९६३

उपयोगितावाद की परिभाषा और आलोचना ८८७, उपयोगितावाद का मूल्यांकन ८९०, उपयोगितावादी विचारक (Utilitarian Thinkers) ९१०, १. जेरेमी बेन्थम ९१३, २. जेम्स मिल ९१९, ३. जॉन स्टुअर्ट मिल ९५९।

१८. राजनीति में आदर्शवाद (Idealism in Politics)

९६६-९८८

१. राजनीति में आदर्शवाद की परम्परा (The Idealistic Tradition in Politics) ९६४, २. राज्य के आदर्शवादी सिद्धान्त की व्याख्या (Statement of the Idealistic Theory of the State) ९६६, ३. टी. एच. ग्रीन (T. H. Green) ९६९।

१९. राष्ट्रियतावाद, साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद (Nationalism, Imperialism and Internationalism)

९८९-१०६१

राष्ट्र और राष्ट्रियता की परिभाषा (Definition of Terms—Nation and Nationality) ६८०,
 राष्ट्रियता का अर्थ ६९०, राष्ट्रियता के तत्त्व (Factors of Nationality) ६९०, राष्ट्रियता का आत्मनिर्णय (The Self-determination of Nationality) ७००, साम्राज्यवाद (Imperialism) ७०४, साम्राज्यवाद का अर्थ (The Meaning of Imperialism) ७०४, साम्राज्यवाद के कारण (Causes of Imperialism) ७०५, आधुनिक साम्राज्यवाद (Modern Imperialism) ७१२, खुला द्वार और बन्द द्वार (The Open door and closed door) ७१५, सैनिक गठबन्धन (Military Alliances) ७१६, मन्त्रालय (The Mandates) ७१६, क्या साम्राज्यवाद का औचित्य है? (Is Imperialism Justified?) ७१९, अन्तर्राष्ट्रियतावाद (Internationalism) ७३६, राष्ट्र-मण्डल (The League of Nations) ७३८, राष्ट्र मण्डल के अंग (The Organs of the League) ७३९, राष्ट्र मण्डल का मूल्यांकन (Appraisal of the League of Nations) ७६४, अन्तर्घट विकास (The Inter War Development) ७७३ ।

२० संयुक्त राष्ट्र-मण्डल (The United Nations) ७८०-८०७

संयुक्त राष्ट्र-मण्डल के उद्देश्य (Purposes of the U. N.) ७८४, सिद्धान्त (Principles) ७८४, सदस्यता (Membership) ७८५, संयुक्त राष्ट्र-मण्डल के अंग (The Organs of the United Nations) ७८६, आम-सभा (The General Assembly) ७८६, सुरक्षा परिषद (The Security Council) ७८९, वीटो (Veto) ७९०, आर्थिक और सामाजिक परिषद (The Economic and Social Council) ७९६, प्रत्याम-परिषद (The Trusteeship Council) ७९९, विभिन्न निकाय (Specialised Agencies) ७८३, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Ju-

ture) १८३, सचिवालय (The Secretariat) १८४, घोषणा-पत्र पर पुनर्विचार (The Revision of the Charter) १८६, कार्य-सम्पादन (Operation) १८७, आर्थिक आयोग (Economic Commission) ६०२, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (The International Bank for Reconstruction and Development) ६०६, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) ६०५, खाद्य और कृषि-संगठन (Food and Agriculture Organization) ६०६, विश्व स्वास्थ्य-संगठन (World Health Organization) ६१०, संयुक्त राष्ट्र-संघ का अन्तर्राष्ट्रीय बाल संवत् बोध (UNICEF) ६११, अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (International Labour Organization) ६१२, संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन (UNESCO) ६१३, संयुक्त राष्ट्र-संघ और विश्व सरकार (The United Nations and World Government) ६१९ ।

२१. समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा का विकास (The Evolution of Socialistic and Communistic Thought)

६०६-६६६

समूहवाद (Collectivism) ६२७, मार्क्स का सिद्धांत ६२८, द्वन्द्ववादी भौतिकवाद (Dialectical Materialism) ६२८, इतिहास की आर्थिक व्याख्या ६२८, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (The Doctrine of Surplus Value) ६३०, साम्यवाद का आकर्षण (Appeal of Communism) ६३४, श्रमिक संगठनवाद (Syndicalism) ६३८, फैबियनवाद (Fabianism) ६४०, धर्म समाजवाद (Guild Socialism) ६४३, लेनिन और लेनिनवाद (Lenin and Leninism) ६४०, स्तालिनवाद (Stalinism) ६४३, माओवाद (Maoism) ६४६, भारत के लिए समाजवादी दावा या समाजवादी समाज ६४८ ।

२२. सर्वोच्चकारीवादी राज्य (The Totalitarian State) ६६५-७०७

१. सर्वोच्चकारीवाद का अर्थ ६६५, २. सर्वोच्चकारीवादी राज्य की विशेषताएँ (Features of the Totalitarian State) ६६७, ३. सर्वोच्चकारीवाद की मफलना (What Totalitarianism Has Done?) ६७३, ४. सर्वोच्चकारीवाद का भविष्य (What of the Future?) ६७३, ५. रूस में सर्वोच्चकारीवाद (Totalitarianism in Russia) ६७५, इटली का फासिस्टवाद (Fascism in Italy) ६७९, जर्मनी का नाजीवाद (Nazism in Germany) ६९१।

७०८-७२७

२३. बहुलवाद (Pluralism)

- (क) राज्य की सम्प्रभुता और मय की स्वायत्तता (State Sovereignty and Group Autonomy) ७०९, (ख) राज्य की सम्प्रभुता और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद (State Sovereignty and Internationalism) ७१७, (ग) राज्य की सम्प्रभुता और विधि (State Sovereignty and Law) ७१९, राजनीतिक बहुलवाद और भारत (Political Pluralism and India) ७२६।

२४. महात्मा गांधी की राजनीतिक विचारधारा (The Political Thought of Mahatma Gandhi) ७२७

- गांधीजी के विचारों के सार ७२६, राजनीति का आध्यात्मिकीकरण (Spiritualisation of Politics) ७३०, दार्शनिक अराजकतावाद (Philosophical Anarchism) ७३०, राज्य का अर्थ (State Action) ७३१, कल्याणकारी राज्य (The Welfare State) ७३२, बच्चे और शोषण का विरोध (Against Misery and Exploitation) ७३२, अहिंसा का दर्शन-शास्त्र (The philosophy of Non-Violence) ७३३, अहिंसा की

अन्य आवश्यकताएँ (Other Requisites of Non-Violence) ७३७, अर्थ-शास्त्र पर गांधीजी के विचार (Gandhiji's Views on Economics) ७४३, क्या गांधीजी अन्तर्राष्ट्रीयतावादी थे? (Was Gandhiji an Internationalist?) ७४६, गांधीजी के धार्मिक विचार (The Religious Ideas of Gandhiji) ७४७ ।

Bibliography

७५३-७५६

अनुक्रमणिका

७५७-७६८

मार्क की बात यह है कि सामाजिक विधिमें उस प्रकारका जोर दबाव नहीं होता जैसा कि राजनीतिक विधिमें होता है। 'प्रत्येक संघ अपने-अपने नियम या विधियाँ बनाता है' परन्तु मैकाडवर के शब्दोंमें 'एक विवर्धित राज्य में राज्यके अलावा अन्य संघों की विधियाँ अपने मदस्यों को तभी तक बन्धन में रख सकती हैं जब तक कि ये मदस्य अपनी मदस्यतामें प्राप्त लाभोंको खोनेके बजाएँ उन बन्धनोंको स्वीकार करना पसन्द करते हैं (५५.१७) अर्थात् 'एक उन्नत समाजमें राज्यकी विधि ही अनिवार्य और दबाव पूर्ण होती है।' सामाजिक विधियोंको माननेकी प्रेरणा पूर्णरूप से हमारे ही भीतर रहती है, पर राजनीतिक विधि बाहरी होती है और व्यवस्था कायम रखनेके लिए उनका पालन करना अनिवार्य कर दिया जाता है।

विधिकी परिभाषा

विधि का विश्लेषणात्मक सिद्धान्त जिसे *ह्यू या शास्त्रीय सिद्धान्त* भी कहते हैं, ऑस्टिन के नामसे सम्बन्धित है (The analytical theory of law known also as the orthodox or classical theory is associated with the name of Austin)। उनका कहना है कि विधि वह आदेश है जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण अधिक शक्तिमान द्वारा राजनीतिक दृष्टिकोण कम शक्तिमानको दिया जाता है। अन्तिम विश्लेषणमें विधिकी एक निश्चित उच्चतर सत्ताका आदेश कहा जा सकता है।

सर हेनरी मेन को इस दृष्टिकोण पर आपत्ति है। वह इस परिभाषा को अत्यन्त सर्वांगी मानते हैं, क्योंकि समाजमें जो प्रचलन (usages) हैं वे भी विधि के अंग हैं किन्तु उनको इस परिभाषामें कोई स्थान नहीं दिया गया है। न्यायशास्त्र (jurisprudence) के इस दृष्टिकोण से अनुसार विधि विभिन्न सामाजिक वर्गोंका प्रतिफल है।

विधिके निम्नलिखित तीन मुख्य स्रोत हैं—(१) सार्वजनिक स्वीकृति, (२) रीति-रिवाज तथा प्रथाएँ (customs and conventions), और (३) राजनीतिक अधिकार सत्ता। इनमें से प्रथम दोनों विधिके सामान्य स्रोत (material source) हैं और तीसरा औपचारिक (formal) स्रोत है। इस दृष्टिकोणसे विधिकी परिभाषा यह की जा सकती है कि वह समाज के भीतर काम करने वाले कुछ दृष्टिकोण, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों का योग है।

युंही विष्मन् की परिभाषा उक्त दोषों, अर्थात्, विश्लेषणात्मक और दृष्टिकोणीय मुन्दर सामान्य है। उनके अनुसार विधि हमारे के आधार-विचार है जिसको सर्वसम्मान नियमोंके रूपमें निश्चित मान्यताएँ प्राप्त हो जानी हैं और जिसको सरकार की शक्ति और मन्त्रालय सम्पत्ति प्राप्त रहता है (Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules

backed by the authority and power of government.)। (गिल्क्राइस्ट द्वारा उद्धृत २८: १६१)

हॉल्लण्ड जो ऑस्टिन की परम्पराके अनुयायी मालूम पड़ते हैं, विधिकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं: 'विधि हमारे बाहरी आचरणों को नियंत्रित करनेवाले वह सामान्य नियम हैं जिनको कि एक निश्चित मानवी सत्ता लागू करती है और यह सत्ता एक राजनीतिक समाजमें उपलब्ध सभी मानवी सत्ताओंमें सर्वोपरि होती है; या मक्षेपमें विधि हमारे बाहरी आचरणको नियंत्रित करनेवाले वह सामान्य नियम हैं जिनको कि एक सम्प्रभु राजनीतिक सत्ता लागू करती है।' (गिल्क्राइस्ट से उद्धृत, २८: १६१)

ऊपर दी गयी परिभाषाओंसे यह स्पष्ट है कि विधिके लिए एक न्यायिक समाज का होना आवश्यक है। इसके अलावा, ऊपर की परिभाषाओंमें विधि की निम्नलिखित विशेषताएँ प्रकट होती हैं: (१) विधि किसी राज्यकी सामाजिक दशाको प्रतिबिम्बित करती है; (२) विधि एक नियम निकाय है (law is a body of rules), (३) विधि व्यक्तिके बाहरी व्यवहारका नियन्त्रण करनेवाली शक्ति है, (४) विधिमें दबाव निहित है जो कि नैतिककी अपेक्षा भौतिक अधिक है (more physical than moral)।

विधिके स्रोत (Sources of Law)

राज्यकी तरह विधिका विकास भी क्रमशः हुआ है और वह अनेक कारकों (factors) का प्रतिकूल है। हॉल्लण्ड विधिके निम्नलिखित स्रोत बताते हैं:

(१) रीति-रिवाज. प्रत्येक समाजमें विधिका सबसे पहला स्वरूप रीति-रिवाज है। जहाँ सामाजिक संगठन सरल या सीधेसादा है वहाँ रीति-रिवाज बहुत महत्त्व रखते हैं। रीति-रिवाज ही वहाँ के राजा हैं। उनका पालन विविध कारणोंसे किया जाता है। एक तो रीति-रिवाजोंको माननेकी आदत हो जाती है। दूसरे उनके पालनमें सुरक्षा प्राप्त होती है। आज भी विधिका बहुत बड़ा धर्म रीति-रिवाज ही है। यह यही है कि लोग रीति-रिवाजोंका पालन आदत या अभ्यासवश ही करते हैं पर इस आदतके पीछे सामाजिक उपयोगिता है। उदाहरणार्थ रक्त सम्बन्धकी कुछ शृंगलाओं तक विवाह यदि निषिद्ध है तो वह भिन्न इसलिए नहीं कि आशुतवाजी लोगों में इस रिवाजका अन्यायुक्त हो रहा है बल्कि इस रिवाज के पीछे प्राणिशास्त्र और सन्ततिशास्त्रके गम्भीर कारण भी हैं। जब रीति-रिवाज राज्यद्वारा स्वीकृत हो जाते हैं और उन्हें जबरदस्ती भी मनवाने का वय प्राप्त हो जाता है तब वे विधिके पद पर प्रतीष्ठ हो जाते हैं। इसी सम्बन्ध में मैनाइवर लिखते हैं:—“विधिके विशाल ग्रन्थ में राज्य केवल एकाध नये वाक्य लिख देना है और इधर उधर एकाध पुराने वाक्य काट देना है। ग्रन्थका अधिकांश राज्य द्वारा कदापि नहीं लिखा गया है (५५:

मारुकी बात यह है कि सामाजिक विधिमें उस प्रकारका जोर दबाव नहीं होता जैसा कि राजनीतिक विधिमें होता है। 'प्रत्येक सभ अपने-अपने नियम या विधिया बनाता है' परन्तु मैकाइवर के शब्दोंमें 'एक विवक्षित राज्य में राज्यके अलावा अन्य संघों की विधिया अपने सदस्यों को तभी तक बन्धन में रख सकती हैं जब तक कि ये सदस्य मधकी सदस्यतामें प्राप्त लाभोंको खोनेके बजाए उन बन्धनोंको स्वीकार करना पसन्द करते हैं (५५, १७) अर्थात् 'एक उन्नत समाजमें राज्यकी विधि ही अनिवार्य और दबाव पूर्ण होती है।' सामाजिक विधियोंको माननेकी प्रेरणा पूर्णरूप से हमारे ही भीतर रहनी है, पर राजनीतिक विधिया बाहरी होंगी हैं और व्यवस्था कायम रखनेके लिए उनका पालन करना अनिवार्य कर दिया जाता है।

विधिकी परिभाषा

विधिका विश्लेषणात्मक सिद्धान्त जिसे सख या शास्त्रीय सिद्धान्त भी कहते हैं, ऑस्टिन के नामसे सम्बन्धित है (The analytical theory of law known also as the orthodox or classical theory is associated with the name of Austin)। उनका कहना है कि विधि वह आदेश है जो कि राजनीतिक दृष्टिमें अधिक शक्तिमान द्वारा राजनीतिक दृष्टिसे कम शक्तिमानको दिया जाता है। अन्तिम विश्लेषणमें विधिकी एक निश्चित उच्चतर सत्ताका आदेश कहा जा सकता है।

सर हेनरी मेन को इस दृष्टिकोण पर आपत्ति है। वह इस परिभाषा को अत्यन्त सकोप मानते हैं, क्योंकि समाजमें जो प्रचलन (usages) हैं वे भी विधि के अंग हैं किन्तु उनको इस परिभाषामें कोई स्थान नहीं दिया गया है। न्यायशास्त्र (jurisprudence) के इस इतिहासीय मतके अनुसार विधि विभिन्न सामाजिक वर्गोंका प्रतिफल है।

विधिके निम्नलिखित तीन मुख्य स्रोत हैं (१) मार्बर्जनिज स्वीकृति, (२) रीति-रिवाज तथा प्रथाएँ (customs and conventions), और (३) राजनीतिक अधिकार सत्ता। इनमें से प्रथम दोनों विधिके सांख्यिक स्रोत (material source) हैं और तीसरा औपचारिक (formal) स्रोत है। इस दृष्टिकोणमें विधिकी परिभाषा यह की जा सकती है कि वह समाज के भीतर काम करने वाले कुल इतिहासीय, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक वर्गोंका योग है।

मुद्रो विन्सन की परिभाषा उक्त दोनों, अर्थात्, विश्लेषणात्मक और इतिहासीय दृष्टिकोणोंका सुन्दर सामंजस्य है। उनके अनुसार विधि हमारे वे आचार-विचार हैं जिनको सर्वत्रयमान नियमोंके रूपमें निश्चित मान्यताएँ प्राप्त हो जाती हैं और जिनको सरकार की शक्ति और सत्ताका समर्थन प्राप्त रहता है (Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules

backed by the authority and power of government.)। (गिलक्राइस्ट द्वारा उद्धृत २८: १६१)

हॉर्लेण्ड जो ऑस्टिन की परम्पराके अनुयायी मालूम पड़ते हैं, विधिकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं: 'विधि हमारे बाहरी आचरणों को नियंत्रित करनेवाले वह सामान्य नियम हैं जिनको कि एक निश्चित मानवी मत्ता लागू करती है और यह मत्ता एक राजनीतिक समाजमें उपलब्ध सभी मानवी मत्ताओंमें सर्वोपरि होती है; या संक्षेपमें विधि हमारे बाहरी आचरणको नियंत्रित करनेवाले वह सामान्य नियम हैं जिनको कि एक सम्प्रभु राजनीतिक मत्ता लागू करती है।' (गिलक्राइस्ट में उद्धृत, २८: १६१)

ऊपर दी गयी परिभाषाओंमें यह स्पष्ट है कि विधिके लिए एक नागरिक समाज का होना आवश्यक है। इसके अलावा, ऊपर की परिभाषाओंमें विधि की निम्नलिखित विशेषताएँ प्रकट होती हैं: (१) विधि किसी राज्यकी सामाजिक दशाको प्रतिबिम्बित करती है; (२) विधि एक नियम निकाय है (law is a body of rules); (३) विधि व्यक्तिके बाहरी व्यवहारका नियन्त्रण करनेवाली शक्ति है; (४) विधिमें दबाव निहित है जो कि नैतिककी अपेक्षा भौतिक अधिक है (more physical than moral)।

विधिके स्रोत (Sources of Law)

राज्यकी तरह विधिका विकास भी क्रमशः हुआ है और वह अनेक कारकों (factors) का प्रतिकूल है। हॉर्लेण्ड विधिके निम्नलिखित स्रोत बताते हैं:

(१) रीति-रिवाज प्रत्येक समाजमें विधिका सबसे पहला स्वरूप रीति-रिवाज है। जहाँ सामाजिक संगठन सरल या सीधामादा है वहाँ रीति-रिवाज बहुत महत्व रखते हैं। रीति-रिवाज ही वहाँ के राजा हैं। उनका पालन विविध कारणोंसे किया जाता है। एक तो रीति-रिवाजोंको माननेकी आदत हो जाती है। हमारे उनके पालनमें सुरक्षा प्राप्त होती है। आज भी विधिका बहुत बड़ा अंश रीति-रिवाज ही है। यह सही है कि लोग रीति-रिवाजोंका पालन आदत या अभ्यासवश ही करते हैं पर इस आदतके पीछे सामाजिक उपयोगिता है। उदाहरणार्थ रस्ते सम्बन्धकी कुछ शृङ्खलाओं तक विवाह यदि निषिद्ध है तो वह भिन्न इसलिए नहीं कि आदतवश लोगों में इस रिवाजका अभ्यास हो रहा है बल्कि इस रिवाज के पीछे प्राणिशास्त्र और मनुष्यशास्त्रके गम्भीर कारण भी हैं। जब रीति-रिवाज राज्य द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं और उन्हें जबरदस्ती भी मनवाने का बल प्राप्त हो जाता है तब वे विधिके पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसी सम्बन्ध में मैकाइवर लिखते हैं:—“विधिके विद्यालय ग्रन्थ में राज्य केवल एकाध नये वाक्य लिख देता है और इधर उधर एकाध पुराने वाक्य काट देता है। अन्यथा अधिकांश राज्य द्वारा कदापि नहीं लिखा गया है (५५:

अधिकारोको स्वीकार तो करती है पर उनकी प्राप्ति या रखाके लिए पर्याप्त नहीं होती। उन समस्याओं से सम्बन्धित साम्याधिकार सहायक कहलाता है जिनमें पर्याप्त साक्ष्य (evidence) नहीं प्राप्त हो सकता (equity is auxiliary where the necessary evidence cannot be procured) (२८ : १६८)।

(६) विधान (Legislation). यह विधिका अन्तिम लेकिन सबसे मजबूत स्रोत है। यह जनताकी इच्छाकी अभिव्यक्ति है। लोकतन्त्रीय देशोंमें यह अभिव्यक्ति जनता द्वारा चुनी गयी विधायिकाओं द्वारा होती है। साम्याधिकार, कानूनी फैसलों और वैज्ञानिक टीकाओं आदि का प्रभाव तो इस अभिव्यक्ति पर निरन्तर पड़ता रहता है पर यह उन सबको आत्मसात् कर लेती है।

बुडो विल्सन ने विधिके विकासकी मारी प्रक्रियाका निम्नलिखित शब्दोंमें जड़ी विद्वत्तापूर्ण माराच दिया है —

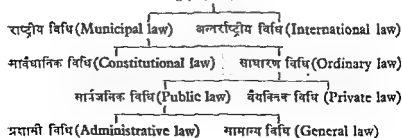
रीति-रिवाज विधिका आदिम आधार है, लेकिन धर्म भी रीति-रिवाजके समकालीन और उसीके समान सफल स्रोत है। राष्ट्रीय विकास की समान अवस्थाओं में रीति-रिवाज और धर्म दोनों ही समान रूप से विधि के स्रोत हैं। पच-निर्णय (adjudication) का उदय ही एक अधिकार सत्ता के रूप में होता है। और यह पचनिर्णय बहुत पुराने समय से साम्याधिकार के साथ-साथ विधि के विकासमें भाग लेते आये हैं। रीति-रिवाज, धर्म, पचनिर्णय और साम्याधिकार इन चारों के आधार पर जब समाजमें विधिका पर्याप्त विकास हो चुका होता है उसके बाद ही विधान (विधि निर्माण) अर्थात् विधिका चेतन और सायाससंगठन (conscious and deliberate organisation of law) और वैज्ञानिक विचार विमर्श (विधि के सिद्धान्तों का तर्कयुक्त प्रतिपादन (reasoned development of principles) ये दोनों विधि-निर्माण को प्रभावित कर विधि के स्रोत बनते हैं।

विधिके प्रकार

(Types of Law)

मैकवाइवर ने दस प्रकार विधिका वर्गीकरण किया है :

राजनीतिक विधि



सांविधानिक विधि (Constitutional law). जिस विधि द्वारा राज्य स्वन नियमित होता है और जिस विधि द्वारा राज्य जनता पर शासन करता है इन दोनों में प्रायः भेद किया जाता है। पहले प्रकारकी विधिको सार्वधानिक विधि और दूसरे प्रकारकी विधिको साधारण विधि कहते हैं। सार्वधानिक विधि अमल लिखित और अमल अलिखित होती है। साधारण विधियो विधि निर्माणकी नियमित प्रक्रिया द्वारा अर्थात् विधायिका द्वारा बनायी जाती है किन्तु सार्वधानिक विधि विधायिका की इच्छाके भी ऊपर अन्तिम मन्त्रमुकी इच्छामे बनती है। मैकाइवर कहते हैं कि सार्वधानिक विधि सरकारके विभिन्न विभागोंके कृत्यों को निश्चित करती है और शासकी और शासितो के बीच सम्बन्ध निर्धारित करती है। इसका उद्देश्य समाजकी एकताके उत्तर में होता है जो निश्चिन्त और स्पष्ट रूपमे यह स्पष्ट करना है कि राज्यको क्या करना चाहिए और उसका संगठन कैसा होना चाहिए। सार्वधानिक विधि सरकारकी सत्ता और शक्ति को मर्यादित कर देती है। फलतः सरकार निर्धारित सीमाके भीतर ही अपनी अधिकार-सत्ता का उपयोग कर सकती है, उसके बाहर नहीं।

साधारण विधि (Ordinary law) मैकाइवर ने ठीक कहा है कि राज्य विधिमे बनता भी है और उसको बनाता भी है (५५, २३२)। जनकके रूपमें राज्य विधायिकाओं द्वारा विधि बनाता है। ये विधिया नागरिकोंके पारस्परिक सम्बन्धों और राज्यके साथ नागरिकोंके सम्बन्धों का नियमन करती हैं, और इन्हे साधारण विधि या लिखित विधि (statute, स्टैट्यूट) कहते हैं। अदालतें उन्हें स्वीकार करती हैं और उन्हें भंग करने वालों को दण्ड देती हैं।

सार्वजनिक विधि और वैयक्तिक विधि (Public law and private law). साधारण विधिको सार्वजनिक और वैयक्तिक दो वर्गोंमे बांटनेका श्रेय होर्नैण्डको है। उनके अनुसार सार्वजनिक विधिको सम्बन्ध राज्यके संगठन, सरकारी कार्योंके परिमोदन (limitation of governmental functions) और राज्य तथा व्यक्तिके सम्बन्धोंमे है। इसके विपरीत वैयक्तिक विधि व्यक्तियोंके पारस्परिक सम्बन्धों का नियमन करती है। यह व्यक्तियोंके अधिकारों और उत्तरदायित्वोंको निर्दिष्ट करती है और उनका नियमन (regulation) करती है। स्वयं होर्नैण्ड के शब्दोंमें वैयक्तिक विधिमें सम्बन्धित 'उच्च-पक्ष अर्थात् दोनो पक्ष नागरिक होते हैं, राज्य जिनके ऊपर और जिनके बीच एक निष्पक्ष पक्षके रूपमें विद्यमान रहता है। यद्यपि सार्वजनिक विधिमें भी राज्य एक निष्पक्ष पक्षके रूपमें रहता है तथापि वह सम्बन्धित पक्षोंमें से एक पक्ष स्वयं होता है।

राष्ट्रीय विधि (Municipal law). सार्वजनिक और वैयक्तिक विधि दोनो मिलकर राष्ट्रीय विधि कहलाती है। यह राज्यकी सीमाके अन्दर सभी व्यक्तियों और मधों पर लागू होती है और राज्यकी सर्वोच्च सत्ता द्वारा लागू की जाती है।

क्षेत्रमें घेर ले । और आगे चलकर यह आशाकी जाती है कि मालिबका ऐसा कृत्य वैधिक दृष्टिसे भी अनुचित ठहरा दिया जायगा । यह भी जरूरी नहीं है कि जो राज्य द्वारा निषिद्ध हो वह सब नैतिक दृष्टिमें अनुचित हो । भारत, ब्रिटेन और कई अन्य देशों में सड़कके बाईं ओर से जाना वैधिक है पर इसमें नैतिक औचित्य का कोई विशेष प्रदन नहीं है । बल्कि सयुक्त राज्य अमेरिका और योरोप के कई देशोंमें तो दाहिनी ओरसे जानेका नियम है । विधि के निर्माणमें कार्यान्विन करनेकी क्षमता और सुविधा का ध्यान रखना पड़ता है जब कि नैतिकता पूरी तौर से यह देखती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित । वह नैतिकता ही क्या जो सुविधा से समझौता (compromise) कर ले ।

राजनीतिक विधि बाह्य होती है पर नैतिक विधि आन्तरिक होती है । राजनीतिक विधि का सम्बन्ध उन कार्यों में होता है जिन्हें करने की इजाजत राज्य का कानून देता है या जिन्हें करनेसे वह रोकता है । दूसरी ओर सार्वलौकिक सत्यो (universal values) की जो धाराएँ व्यक्तिके अन्दर बन जाती हैं और उनके जो अर्थ वह लगाता है उन्हींसे नैतिकताका निर्माण होता है । "मभी नैतिक दायित्वोंको वैधिक दायित्व बना देना नैतिकताको नष्ट करना होगा (५५:१५७)।" इसका अर्थ यह है कि राज्य नैतिकताके आदेश नहीं दे सकता क्योंकि नैतिकता तो वह है जो स्वतःप्रेरित हो । राज्य द्वारा लायी गयी नैतिकता, जबदेस्ती है, नैतिकता नहीं । जैसा कि ऊपर कहा गया है नैतिकता आन्तरिक विद्वान और अन्तःकरणवा विषय है और इसलिए यह आसानीसे बाहरी नियन्त्रणमें नहीं आती ।

नैतिकता और विधिमें समानता

फिर भी विधि और नैतिकतामें काफी हद तक समानता है । यदि जनता अच्छी है तो राज्य भी अच्छा होगा, और यदि राज्य अच्छा है तो जनता भी अच्छी होगी । प्लेटो के प्रसिद्ध शब्दों में 'सबसे अच्छा राज्य वह है जिसमें इतनी अच्छाईया हों जितनी कि एक व्यक्तिमें सम्भव है । यदि राज्यके किसी अंगको क्षति पहुँचती है तो पूरे राज्यकी क्षति होती है ।' या जैसा कि किसी अन्य लेखक ने कहा है : "यह सही है कि आत्माका उद्धार (salvation) मनुष्यके प्रयत्नोंमें ही सम्भव है, किन्तु आत्मा का घर अर्थात् मनुष्य तो राज्यमें ही रहता है ।" दूसरे शब्दोंमें व्यक्ति अपना पूर्ण विकास राज्यमें ही, राज्यकी सहायता से ही कर सकता है । उसके नैतिक जीवनकी सबसे बड़ी शक्ति यही है । व्यवस्था, सप्तानता और न्यायके अभावमें आत्मा घुटने लगेगी और इन तीनों की व्यवस्था राज्य ही अपनी विधियों द्वारा करता है ।

राज्य एव और उन परिस्थितियोंकी वृद्धि कर सकता है जो नैतिकताके लिए हितकर हैं और दूसरी ओर उन परिस्थितियोंको दूर कर सकता है जो उसके लिए अहितकर हैं । गिलब्राइस्ट इसी बातको इस प्रकार कहते हैं : 'नैतिक प्रवृत्तियोंके रूपमें राज्य एक ओर तो अच्छी विधियाँ बनाता है अर्थात् ऐसी विधियाँ बनाना है जो

जनताके सर्वोच्च नैतिक हितोंके अनुकूल होती है, और दूसरी ओर उन विधियोंको रद्द करता चलता है जो जनताके लिए अहितकर हो गयी हो।'

विधि और नैतिकता का इतना गहरा सम्बन्ध है कि अक्सर अवैधिक और अनैतिक में अन्तर करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि प्रायः जो अवैधिक है वह अनैतिक भी है और जो वैधिक तौर पर ठीक है वह नैतिक भी है। किन्तु जो आज गैरकानूनी है वह कल नैतिक हो सकता है और इसलिए तब विधिको बदलनेकी आवश्यकता पड़ेगी अग्यथा नैतिकताका अहित हो सकता है। हर हालतमें इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि राज्य स्वयं साध्य नहीं है। माध्य तो मनुष्य के व्यक्तित्व की समृद्धि है। राज्य तो असली उद्देश्य तक पहुँचनेका यानी मनुष्य के व्यक्तित्व की समृद्धि का एक साधन मात्र है।

विधि और राज्य (Law and State)

फोकर के अनुसार, राज्यकी सत्ताको सीमित करनेके अनेक प्रयत्न, तीन दृष्टिकोणोंमें किये गये हैं। प्रथम तो यह कि व्यक्ति की कुछ जीवनवर्षा ऐसी भी होती है जिसमें राज्य का दखल अनुचित होगा। अपने इस कार्यक्षेत्र को वह अपनी और अपने समाजकी प्रवृत्ति और प्रवृत्तिके अनुसार और सत्य-असत्यके सार्वभौमिक या निर्विवाद सिद्धान्तों के ऊपर आधारित करना चाहता है। इस दृष्टिकोणको राजनीतिशास्त्र में आमतौर पर व्यक्तिवाद कहा जाता है और इसके साथ प्राकृतिक अधिकारों और विवेककी स्वाधीनता जैसे सहगामी विचार जुड़े रहने लगे।

राज्यके अन्दर बहुतसे सामाजिक और आर्थिक सघ होते हैं जो स्थायी रूपसे क्रियाशील रहते हैं। कुछ लेखकोंका मत है कि इनको पूर्ण आन्तरिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए। राज्यको इनके कामोंमें किसी प्रकारका भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि राज्य सघोका सघ ही तो है। यह दूसरा दृष्टिकोण है जो राज्यकी सत्ताको सीमित कर देना चाहता है। इसको बहुलवाद (pluralism) कहते हैं।

कुछ विचारक विधिके दृष्टिकोणमें ही राज्यके ऊपर एक तीसरे प्रकारका प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। इन विचारकों का कहना है कि विधि केवल राज्यको सृष्टि मात्र नहीं है बल्कि वह राज्यमें पूर्वकालीन और उससे उच्चतर भी है। यूनानके दार्शनिक, राजकीय आज्ञापियों (State decrees) और विधियोंमें अन्तर मानते थे और विधियोंको उच्चतर स्थान देते थे। अहा एक ओर हर समुदायकी एक लिखित विधि होती थी जिसका उपयोग सीमित होता था और जो समयके साथ बदलती रहती थी, वहा उसके पीछे एक अलिखित विधि भी होती थी जिसे 'प्राकृतिक विधि', 'देवी विधि' या 'सार्वभौमिक विधि' के नामोंसे पुकारा जाता था और जो समयके साथ बदलती नहीं थी। जिस राज्यमें 'मानव विधि' अर्थात् मनुष्यों द्वारा बनायी गयी विधि 'देवी विधि' के अनुरूप नहीं होती थी उसे भ्रष्ट राज्य कहा जाता था।

क्षेत्रसे घेर ले । और आगे चलकर यह आयाकी जाती है कि मालिकका ऐसा कृत्य वैधिक दृष्टिसे भी अनुचित ठहरा दिया जायगा । यह भी जरूरी नहीं है कि जो राज्य द्वारा निषिद्ध हो वह सब नैतिक दृष्टिसे अनुचित हो । भारत, ब्रिटेन और कई अन्य देशों में सड़कके बाईं ओर से जाना वैधिक है पर इसमें नैतिक औचित्य का कोई विशेष प्रश्न नहीं है । बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कई देशों में तो दाहिनी ओरसे जानेंका नियम है । विधि के निर्माणमें कार्यान्वित करनेकी क्षमता और सुविधा का ध्यान रखना पड़ता है जब कि नैतिकता पुरो तौर से यह देखती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित । वह नैतिकता ही क्या जो सुविधा से समझौता (compromise) कर ले ।

राजनीतिक विधि बाह्य होती है पर नैतिक विधि आन्तरिक होती है । राजनीतिक विधि का सम्बन्ध उन कार्यों से होता है जिन्हें करने की इजाजत राज्य का कानून देता है या जिन्हें करनेसे वह रोकता है । दूसरी ओर सार्वभौमिक सत्य (universal values) की जो धाराएँ व्यक्तिके अन्दर बस जाती हैं और उनके जो अर्थ वह लगाता है उन्हींसे नैतिकताका निर्माण होता है । "सभी नैतिक दायित्वोंको वैधिक दायित्व बना देना नैतिकताको नष्ट करना होगा (५५-१५७)।" इसका अर्थ यह है कि राज्य नैतिकताके आदेश नहीं दे सकता क्योंकि नैतिकता तो वह है जो स्वतः प्रेरित हो । राज्य द्वारा लायी गयी नैतिकता, जबर्दस्ती है, नैतिकता नहीं । जैसा कि ऊपर कहा गया है नैतिकता आन्तरिक विश्वास और अन्तःकरणकी विषय है और इसलिए यह आसानीसे बाहरी नियंत्रणमें नहीं आती ।

नैतिकता और विधिमें समानता

फिर भी विधि और नैतिकतामें बाकी हद तक समानता है । यदि जनता अच्छी है तो राज्य भी अच्छा होगा, और यदि राज्य अच्छा है तो जनता भी अच्छी होगी । प्लेटो के प्रसिद्ध शब्दों में 'सबसे अच्छा राज्य वह है जिसमें इतनी अच्छाईया हो जितनी कि एक व्यक्तिमें सम्भव है । यदि राज्यके किसी अंगकी क्षति पहुँचती है तो पूरे राज्यकी हानि होती है ।' या जैसा कि किसी अन्य लेखक ने कहा है : "यह सही है कि आरमाका उद्धार (salvation) मनुष्यके प्रयत्नोंमें ही सम्भव है, किन्तु आरमा का घर अर्थात् मनुष्य तो राज्यमें ही रहना है ।" दूसरे शब्दोंमें व्यक्ति अपना पूर्ण विकास राज्यमें ही, राज्यकी सहायता से ही कर सकता है । उसके नैतिक जीवनकी सबसे बड़ी शर्त यही है । व्यवस्था, समानता और न्यायके अभावमें आरमा घुटने लगेंगे और इन तीनों की व्यवस्था राज्य ही अपनी विधियों द्वारा करता है ।

राज्य एक ओर उन परिस्थितियोंकी वृद्धि कर सकता है जो नैतिकताके लिए हितकर हैं और दूसरी ओर उन परिस्थितियोंको दूर कर सकता है जो उसके लिए अहितकर हैं । गिलबर्ट आर्सेन वानको इस प्रकार कहते हैं : 'नैतिक प्रवृत्तियोंके रूपमें राज्य एक ओर तो अच्छी विधियाँ बनाता है अर्थात् ऐसी विधियाँ बनाता है जो

जनताके सर्वोच्च नैतिक हितोंके अनुकूल होनी हैं, और दूसरी ओर उन विधियोंको रद्द करना चलना है जो जनताके लिए अहितकर हो गयी हो।'

विधि और नैतिकता का इतना गहरा सम्बन्ध है कि अन्तर अवैधिक और अनैतिक में अन्तर करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि प्रायः जो अवैधिक है वह अनैतिक भी है और जो वैधिक तोर पर ठीक है वह नैतिक भी है। किन्तु जो आज गैरकानूनी है वह कल नैतिक हो सकता है और इसलिए तब विधिको बदलनेकी आवश्यकता पड़ेगी अन्यथा नैतिकताका अहित हो सकता है। हर हालतमें इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि राज्य स्वयं माध्य नहीं है। माध्य तो मनुष्य के व्यक्तित्व की समृद्धि है। राज्य को अमली उद्देश्य तक पहुँचनेका यानी मनुष्य के व्यक्तित्व की समृद्धि का एक माध्य मात्र है।

विधि और राज्य (Law and State)

कोरर के अनुसार, राज्यकी मत्ताको सीमित करनेके अनेक प्रयत्न, नीतिदृष्टिकोणोंमें किये गये हैं। प्रथम तो यह कि व्यक्ति की कुछ जीवनचर्या ऐसी भी होती है जिनमें राज्य का दखल अनुचित होगा। अपने इस कार्यक्षेत्र को वह अपनी और अपने समाजकी प्रवृत्ति और प्रवृत्तिके अनुसार और मनुष्यके सार्वभौमिक या निर्विवाद मिट्टालों के ऊपर आधारित करना चाहता है। इस दृष्टिकोणको राजनीतिशास्त्र में आमनौर पर व्यक्तिवाद कहा जाता है और इसके माय प्राथमिक अधिकारों और विवेककी स्वाधीनता जैसे महत्त्वपूर्ण विचार जुड़े रहते हैं।

राज्यके अन्दर बहुतसे सामाजिक और आर्थिक संघ होते हैं जो स्थायी रूपमें त्रिपक्षीय रहते हैं। कुछ लेखकोंका मत है कि इनको पूर्ण आन्तरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्यको इनके कार्योंमें किसी प्रकारका भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि राज्य सघोका मध्य ही तो है। यह दूसरा दृष्टिकोण है जो राज्यकी मत्ताको सीमित कर देना चाहता है। इनको बहुलवाद (pluralism) कहते हैं।

कुछ विचारक विधिके दृष्टिकोणमें ही राज्यके ऊपर एक तीसरे प्रकारका प्रभावण्य लगाया चाहते हैं। इन विचारकों का कहना है कि विधि केवल राज्यकी सृष्टि मात्र नहीं है बल्कि वह राज्यमें पूर्वकायोन और उसके अन्तर्गत भी है। यूनानके दार्शनिक, राजकीय आत्मनियों (State decrees) और विधियोंके अन्तर मानते थे और विधियोंको अन्तर्गत स्थान देते थे। जहाँ एक ओर हर मनुष्यको एक निश्चित विधि होनी थी जिसका उपयोग सीमित होता था और जो मनुष्यके माय बदलती रहती थी, वहाँ उनके पीछे एक अलिखित विधि भी होती थी जिसे 'प्राइमि' विधि, 'ईवी विधि' या 'सार्वभौमिक विधि' के नामोंसे पुकारा जाता था और जो समयके माय बदलती नहीं थी। जिन राज्यमें 'मानव विधि' अर्थात् मनुष्यों द्वारा बनायी गयी विधि 'ईवी विधि' के अनुकूल नहीं होती थी उसे अप्रष्ट राज्य कहा जाता था।

आधुनिक विधिकी नींव रखनेमें प्राकृतिक विधि (natural law) के विचार ने रोमन युग, मध्ययुग और उसके बाद भी बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया। इसने विधि का एक आदर्श स्तर कायम किया। इसे सही विवेक का आदेश माना जाता था। आधुनिक युगमें अन्तर्राष्ट्रीय विधिके जन्मदाता ह्यूगो घोशियसकी शिक्षाओंमें भी यह दृष्टिकोण पाया जाता है।

आधुनिक राजनीतिशास्त्रके विवाद प्रश्नोंमें से एक प्रश्न यह भी है कि क्या विधायिकाएँ और न्यायालय इस बात का निर्णय करते हैं कि विधि क्या है और क्या होनी चाहिए? अथवा क्या राज्यके ये सस्यान कहीं अन्यत्र हुए वैधिक निर्णयोंको केवल अंगीकार और लागू भर करते हैं? कुछ लोग विधिको समस्त राजनीतिक सत्तासे ऊंचा मानते हैं।

इतिहासीय मत (ऐतिहासिक नहीं) (Historical school) जिसको जर्मनीमें गुस्ताव फॉन ह्यूगो (१७६४-१८४४) ने प्रतिपादित किया और साविग्नो (Savigny, १७९९-१८६१) ने भी माना, यह है कि प्राकृतिक या सार्वभौमिक विधि जैसी कोई चीज नहीं है। विधि तो किसी राष्ट्रके निजी अनुभवों और लक्षणों (characteristics) से तय होती है। उसकी उत्पत्ति तो उसी राष्ट्रके विचारों और इच्छा (will) से होती है। भौतिक बल ऐसी विधिकी वास्तविक शक्ति नहीं होता। यह शक्ति तो राष्ट्रकी आदतोंमें, उसकी धारणाओं (opinions) में, उसके संवेगों (emotions) में और गलत तथा सही या पाप और पुण्यके उसके मानदण्डों में है।

आदेशवादियों (Positivists) का कहना है कि विधि निश्चित राजनीतिक सत्ताओंके आदेश है। उपयोगितावादी विधिको, मानवकरमाणा का एक साधन—मानव सुखके स्थिर लक्ष्यका एक परिवर्तनशील उपाय—मानते हैं। फॉन जेरिंग (Von Jhering) के अनुसार विधि लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है और यह लक्ष्य व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि समाज का कल्याण है।

डिग्वी, फ्रीड और लास्की विधि का अन्तिम स्रोत राज्य के बाहर बतलाना चाहते हैं। डिग्वी सामाजिक एकता की धारणा (conception of social solidarity) को और फ्रीड समाजके विवेक (sense of right) को विधि का स्रोत बताते हैं। डिग्वी के अनुसार, समाजमें रहनेवाले मनुष्योंके आचरण का नियंत्रण करनेवाले नियमोंको विधिकी मज्ञा दी जाती है। लोग उनका पालन आदेशके रूपमें नहीं बल्कि सामाजिक जीवनकी आवश्यकताओंके रूपमें करते हैं। विधि राज्यसे स्वतंत्र उससे प्राचीन, उच्चतर और अधिक व्यापक है (Law is independent of, anterior to, above and more comprehensive than the state)। फ्रीड ने विधिकी परिभाषा यह दी है: विधि उन नियमोंकी सम्पूर्ण महति है जो सामान्य या विशिष्ट, लिखित या अलिखित होते हैं और जिनका उद्भव मनुष्य के विवेक तथा उनकी न्याय भावनामें होता है। विधि समाज का वह नियम है जिसकी मांग समाजने मही बुद्धिवाले

वट्टमन्त्री न्याय मादना करती है। विधि इन प्रकार राज्यमें ऊपर और उनमें स्वामीन है।

"विधिकी कमीटी क्या है?" इस प्रश्नका उत्तर देने हुए लास्की कहते हैं कि केवल वैधिक औचित्य ही सरकारको इस बातका अधिकार नहीं देता कि वह अपनी आज्ञाओंका बलान् पालन कराये, बल्कि इन अधिकारमें नैतिक औचित्य का भी होना आवश्यक है। इस दृष्टिकोणको मानते हुए लास्की ने हाँथ के परमपूर्ण सम्प्रभुताके दृष्टिकोणकी आलोचना की है। लास्की का मत है कि जिन लोगों ने चार्ल्स प्रथमके विरुद्ध, १८वाँ शतीके फ्रांसीसी राज्यपत्र के विरुद्ध और १९१७ में रुसके जार के विरुद्ध विद्रोह किया था, उन्होंने विधिकी कोई अवज्ञा नहीं की। अपितु वे लोग उस विधि के प्रति निष्ठावान थे जो राज्यके ऊपर है। लास्की का कहना है कि विरिक्ता खान न तो राज्य है और न समुदाय; बल्कि विधिका खान व्यक्ति है जो अपने अन्तःकरणके अनुसार चलता है। विरिक्ता खान के विचार हैं जिनकी कि मत गवाही देता है। इस प्रकार विधिकी अवज्ञा खान व्यक्तिकी महानि है। उत्तम विधि वह है जो व्यक्तिकी मयासम्भव अधिकमें अधिक आकांक्षाओंको पूरा करे। ऐसी ही विधि पालनकी जानेकी अधिकारिणी है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि

अपनी प्रसिद्ध इति 'इष्टरनेशनल पॉलिटिक्स' में एफ० जी० शुमन ने लिखा है कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय समाजकी निम्नलिखित तीन आधारभूतलाएँ हैं

राष्ट्रीय सम्प्रभुताकी धारणा (concept of national sovereignty), शक्ति सन्तुलनकी राजनीति (politics of balance of power) और अन्तर्राष्ट्रीय विधिके सिद्धान्त (principles of international law)।

हम यहाँ इनमें से तीसरी, अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विधि, पर विचार करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय विधिकी प्रकृति और अर्थ (The Nature and Meaning of International law).

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय विधिका आरम्भ बहुत पुराने जमानेमें हुआ था; किन्तु यह अधिकतर योरोपीय इतिहासकी पिछली तीन शताब्दियोंमें प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय समझौते अनुभवोंकी देन है। श्वार्ज़ेनबर्गर (Schwarzenberger) और ब्रिज़ली (Brierly) के अनुसार निम्नलिखित कारकों (factors) ने अन्तर्राष्ट्रीय विधिके विज्ञानमें बहुत अधिक योग दिया है।

(१) अमेरिकाकी श्रेष्ठ और भारतके लिए नये उल्लेखनीय दितनेने व्यापार और साहसिक अभियानोंकी विज्ञान की प्रेरणा और शक्ति।

(२) आधुनिक युगकी नवजागृति द्वारा निम्न सामान्य बौद्धिक दृष्टिकोण (The common intellectual background created by the renaissance)।

(३) योरोपके विभिन्न देशोंमें रहनेवाले ईसाई धर्मावलम्बियोंमें परस्पर सहानुभूति । सहानुभूतिकी इस भावनाके कारण एक देशमें रहने वाले ईसाई अन्य देश या देशोंमें रहने वाले स्वधर्मावलम्बियोंके प्रति सहानुभूति रखने लगे। फलतः एक ऐसी निष्ठा का उदय हुआ जिसने राज्यों की सीमाओं से सीमित न रह कर और इन सीमाओं को पार कर अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण किया ।

(४) आधुनिक युगके आरम्भमें जिस नृगसत्ताके साथ युद्ध लड़े गये उसके कारण सब लोगोंमें उत्पन्न युद्धके विरुद्ध घृणा और विरक्तिकी भावना । ह्यूगो प्रोशियम ने इप्पूर बेल्जी ए पासो (De jure belli et pacis) नामक जो ग्रन्थ रचा उसने युद्धों को हमेशाके लिए बन्द करने की नहीं तो कमसे कम उन्हें तर्क सगत (rational) बनानेकी मफल प्रेरणा तो दी ही ।

राष्ट्रीय सम्प्रभुता और अन्तर्राष्ट्रीय विधि.

राष्ट्रीय सम्प्रभुताकी चरम धारणा और प्रकृतिवादियों द्वारा इन धारणाकी अम्बीवृत्तिके झगड़ोंको घोशियस ने सम्प्रभुताकी परिभाषित परिभाषा देकर तम कर दिया है । उनके अनुसार राष्ट्रीय सम्प्रभुता बाहरी कारकोंसे सीमित होती है । उन्होंने सम्प्रभुताकी परिभाषा इस प्रकारकी "वह व्यक्ति जिसके कृत्य किसी दूसरी शक्ति के नियन्त्रणमें न हों ताकि उन कृत्योंको कोई दूसरी मानवी इच्छा अपने कृत्यों द्वारा प्रभावहीन न कर सके" । घोशियस सम्प्रभुता को निरकुश नहीं मानते थे । उनका कहना था कि सम्प्रभुता ईश्वी विधि द्वारा, प्रकृति की विधि द्वारा, राष्ट्रोंकी विधि द्वारा तथा शासक और घासितोंके बीच हुए करार द्वारा सीमित है । घोशियस के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि जहाँ एक ओर सम्प्रभुताको ऊपर बताये गये कारक सीमित करते हैं वहाँ दूसरी ओर यदि कोई राज्य बाहरी तौरसे किसी दूसरे राज्यके नियन्त्रणमें मुक्त है तो अन्य राज्योंके साथ अपने सम्बन्धोंमें वह सम्प्रभुतासम्पन्न है । जैसा कि एक आधुनिक लेखक ने कहा है, 'आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधिकी पूरी इमारत इसी विचारकी नींव पर खड़ी की गयी है' ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधिकी परिभाषाएं.

लॉरेंस (Lawrence) अन्तर्राष्ट्रीय विधिकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं. 'वे नियम जो सम्य राष्ट्रोंके समुदायके पारस्परिक व्यवहारोंमें उनके आचरणका निर्धारण करते हैं ।' ब्रायली (Brierly) के अनुसार, 'यह आचरणके उन नियमों और सिद्धान्तोंका समूह है जो सम्य राष्ट्रों पर उनके पारस्परिक सम्बन्धोंमें लागू होते हैं ।' फेनिक (Fenwick) के लिए इसका अर्थ है 'उन सामान्य सिद्धान्तों और निश्चित नियमोंका समूह जो अन्तर्राष्ट्रीय समाजके सदस्यों पर उनके पारस्परिक सम्बन्धोंमें लागू होते हैं ।' पिट कॉबेट (Pitt-cobbet) का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि 'उन नियमोंका निष्कर्ष है जो सम्य राष्ट्रों द्वारा एक दूसरेके

प्रति और एक दूसरेकी प्रजाके प्रति उनके आचरणोंके लिए स्वीकार किय गये हो। ओपेनहेम (Oppenheim) इसकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं: 'रीति-रिवाजों और प्रथाओं पर आधारित ऐसे नियमोंका समूह जो मन्त्र राष्ट्रीय द्वारा उनके पारम्परिक व्यवहारमें वैध रूपसे मान्य माने जायें।'।

सबसे मुख्य प्रश्न तो यह है कि विधिकी प्रकृतिको देखने हुए अन्तर्राष्ट्रीय विधिका विधि माने जानेका दावा कहा तक उचित है? अब हम इस प्रश्नका उत्तर देंगे।

क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि वास्तवमें विधि है?

यदि विधिकी व्याख्या 'समूहप्रभुताकी इच्छा' के उन्नी अर्थमें करनी है तबमें हाज़ि और ऑन्टिनने की है तब तो अन्तर्राष्ट्रीय विधिका विधि होनेका दावा बुर-बुर हो जायगा। ओपेनहेम (इण्टर नेशनल लॉ, पृष्ठ ७) ठीक ही कहते हैं कि विधिकी ऐसी मर्यादों और अकड़ों परिभाषा रीति-रिवाज पर आधारित विधि (customary law) के अस्तित्वकी नुमा देनी है और साथ ही यह परिभाषा गलत ही मान बैठती है कि विधिके पूर्व एक ऐसी प्रभुताका होना जरूरी है जो विधि का निर्माण करे और विधि सभी विधि नहीं जा सकती है जब इसे मान्यता मिल चुकी हो। विधिकी त्रिभारणा पर यहां विचार किया जा रहा है वह केवल अमनः ठीक है क्योंकि यह विधिके तत्त्व और व्याप्ति (essence and comprehension) की सम्पूर्णताकी उपेक्षा करती है।

ओपेनहेम विधिकी और अधिक वैज्ञानिक परिभाषा देकर इस उलझन का दूर करने हैं। वह परिभाषा यह है: "समाजके भीतर मानव आचरण सम्बन्धी ऐसे नियमोंका समूह जिन्हें समाजकी सामान्य स्वीकृतिने बाहरी शक्ति द्वारा लागू किया जाय।" इसका अर्थ है कि विधिके निम्नलिखित तीन तात्त्विक अंग हैं: (१) एक समाज, (२) उस समाज के भीतर मानव आचरणके लिए नियमोंका एक समूह (प्रथागत और रीति-रिवाज दोनों ही) और (३) इन नियमोंका बाहरी शक्ति द्वारा लागू किया जाना। ओपेनहेम कहते हैं कि समाज ऐसे व्यक्तियोंका एक समूह है जो सभ्यता के अन्तर्गत सामान्य हितों द्वारा एक दूसरेमें बंधे हैं। ये ऐसे सामान्य हित होने हैं जो सदस्योंके बीच एक निरन्तर और बहुमुखी सम्बन्ध बनाये रखते हैं। इसमें यह स्पष्ट है कि मनुष्योंके जन समूहमें निम्न अन्तर्राष्ट्रीय समाज हो सकता है। जहां कहीं भी ऐसा समाज है वहां आचरणके कुछ प्रथागत और रीति-रिवाजगत नियम हमें मिलते हैं। फिर भी उन नियमोंको लागू करनेके बारेमें कठिनाई पैदा होती है। यह तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विधिके कार्यान्वयकी अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय विधिका कार्यान्वय निश्चित रहता है। इस निश्चितताका कारण एक ऐसी 'स्थायी व्यवस्था' की कमी है जो अन्तर्राष्ट्रीय समाजकी सामान्य स्वीकृतिको प्रकट कर सके। पर जहां ऐसी

सामान्य स्वीकृति मौजूद रहती है, जैसा कि प्रायः होता है, वहा अन्तर्राष्ट्रीय विधिकी लागू किया जाना सम्भव हो जाता है।

जो लोग ऊपरकी इस व्याख्या पर आपत्ति करते हैं वे यह कह सकते हैं कि जिसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहा जाता है वह अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकतामे अधिक कुछ नहीं है। ओपेनहेम इसका समुचित उत्तर यह देते हैं : "कोई नियम यदि वह समाज की सामान्य स्वीकृतिसे केवल मनुष्य के अन्तःकरण पर ही लागू होता है तो वह नैतिकताका नियम है, इसके विपरीत कोई भी नियम, यदि समाजकी सामान्य स्वीकृतिसे अन्ततोगत्वा बाहरी बल द्वारा लागू किया जाता है तो वह विधिकी नियम हो जाता है।"

इस प्रकार विधिके अस्तित्वके लिए न तो विधि बनानेवाली प्रभुता (authority) की और न एक न्यायालयकी अनिवार्य आवश्यकता है—अपने आपमे वे दोनों चाहे जितने महत्त्वपूर्ण हों। इस सत्यके बावजूद यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रोंकी बीचकी विधि राष्ट्रीय या स्थानीय विधिकी तुलनामें गिथिल रहती है। यदि यह भी हो तो इसे मान लेनेसे राष्ट्रोंकी विधि अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विधिकी विधिपन मिट नहीं जाता है। शिथिलताका कारण यह तथ्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रोंके बीच है, उनके ऊपर नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय विधिके स्रोत.

राष्ट्रोंकी सामान्य स्वीकृति राष्ट्रोंके बीच विधिकी आधार है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्वीकृति एक साथ एक समय पर ही दी जाय। इसका अर्थ केवल यह है कि कोई भी राष्ट्र अकेले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय विधिमें एकपक्षीय परिवर्तन नहीं कर सकता।

यह स्वीकृति व्यक्त या मौन दोनों ही प्रकारकी हो सकती है, जिन्हें क्रमशः प्रथागत (conventional) और रीति-रिवाजगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयकी विधि-महिताकी ३८वीं धारामें न्यायालयकी निम्नलिखित आधारों (canons) का उपयोग करनेका आदेश दिया गया है। यही आधार राष्ट्रीय विधिकी स्रोत हैं (देखिए ब्रायर्नी—दि ऑ ऑफ नेशनल्, पृष्ठ ५७६)।

(क) अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाएं चाहे वह सार्व राष्ट्र्रीय हों या विशिष्ट, जिनकी स्वीकृति प्रतियोगी (contesting) राष्ट्रों द्वारा घोषित की जा चुकी हो।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाजें। जिन रिवाजोंका सामान्यतया इतना चलन है कि यह विधि ममझे जाने लगे हो।

(ग) विधिकी सम्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत सामान्य निदान्त।

(घ) ५९वीं धाराके प्रतिबन्धके माध्यम, न्यायाधीशोंके निर्णय और विविध

राष्ट्रों के सर्वोच्च योग्य लेखकों (publicists) के उपदेश, विधिके नियमों का निर्धारण करने के उपमाधनों के रूप में।

अन्तर्राष्ट्रीय विधिके स्वरूप के सम्बन्ध में वाद.

(१) प्राचीनतम वादों में से एक वाद है, प्रकृतिवादी (naturalist)। पुफेंडॉर्फ (Pufendorf) इस मत के जनक है। उनके विचारों को १८वीं शताब्दी में रदरफोर्ड (Rutherford) ने विवक्षित किया। इस वाद के अनुसार प्रकृतिकी विधि ही राष्ट्रों की विधिका एक मात्र स्रोत है। यह सिद्धान्त रीति-रिवाजगत अन्तर्राष्ट्रीय विधिकी विधि ही नहीं मानता। इसके अनुसार राष्ट्रों की विधि प्रकृति की सर्वव्यापी विधिका ही एक अंग है।

(२) दूसरा वाद अस्तित्ववादी (positivist) है जिसके नेता रिचार्ड जूच (Richard Zouche, १५९०-१६६०) और व्याख्याता ओपेन हेम हैं। इस वाद के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के ऊपर न होकर उनके बीच है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रों की बीच की विधि का मुख्य स्रोत राज्यों की स्वीकृति है और इसलिए प्राकृतिक विधिका इससे बहुत कम सम्बन्ध है।

(३) उक्त दोनों वादों के बीच का रास्ता ग्रीशियस (Grotius) के मतानुसार ने अपनाया है। इस मत का विकास वुल्फ (Wolf, १६७९-१७५४) और वाटेल (Vattel, १७१४-१७६७) ने किया। ओपेनहेम के शब्दों में "जैसे प्रकृतिकी विधि मनुष्यों पर व्यक्तिगत रूप में लागू होती है उसी प्रकार वह मनुष्यों पर सामूहिक रूप में मानी समझित राज्यों पर भी लागू होगी"।^१ इस प्रकार राष्ट्रीय सम्प्रभुता के दावों की स्वीकार करते हुए भी यह मत जोरदार शब्दों में घोषणा करता है कि उस सम्प्रभुता को सीमित करने वाले बाहरी तत्व भी प्रकृतिकी विधिके ही अंग हैं।

उक्त तीनों मतों में से प्रकृतिवादी मत का मध्ययुग के अन्त तक बोलबाला रहा। इस मत की मूलानी, रोमन और मध्ययुग के लेखकों जैसे अरस्तू, सिसरो, और एक्विनास के ग्रन्थों से बहुत अधिक समर्थन मिला। आधुनिक युग के आरम्भ में सम्प्रभुता के सिद्धान्त की स्थापना से अस्तित्ववादी मत का उत्थान हुआ। बोटां, होम्स तथा ऑस्टिन की रचनाओं से इस मत को और अधिक बल मिला।

बीसवीं सदी की घटनाओं को ग्रीशियस मत का ही अधिक तर्कमंगत रूप में पुनरुत्थान कहा जा सकता है। इस पुनरुत्थान के दो कारण हैं, पहला कारण है अन्तर्राष्ट्रीय संधि व प्रथाओं (conventions) का पनपना (growth) जो राष्ट्रीय सम्प्रभुता के निरंकुशता के दावों को सीमित करते हैं। उदाहरण के लिए हेग सम्मेलन (१८९९-१९०७), राष्ट्रसंधि प्रसविदा (covenant) (१९१९);

^१ पृष्ठ ९३-९४

हम यह स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय विधिसे बाध्य नहीं हैं और वे ऐसी विधियोंको भी लागू कर सकते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय विधिके प्रति कूल हो। पर हम बातसे केवल अन्तर्राष्ट्रीय विधि व संगठनकी सिधिलता ही प्रकट होती है। इसलिए मौलिक समस्या तो यह है कि इन दोनों विधियोंमें ऐसा मुक्ति-संगत सम्बन्ध स्थापित किया जाय जिससे राष्ट्रीय विधिके निर्जोब बोझसे अन्तर्राष्ट्रीय विधिकी प्रगतिमें बाधा न पड़े।

SELECT READINGS

- DICEY, A. V.—*The Law of the Constitution*.
 FINER, H.—*Theory and Practice of Modern Government—Vol. 2*.
 GARNER, G. W.—*Political Science and Government*.
 GETTLELL, R. G.—*Introduction to Political Science*.
 GILCHRIST, R. N.—*Principles of Political Science*.
 IYENGAR, S. S.—*Problems of Indian Democracy*.
 MARRIOTT, J. A. R.—*The Mechanism of the Modern State—Vol. 2*.
 RAMAIAH—*Politics*.

राजनीति में उपयोगितावाद

(Utilitarianism in Politics)

उपयोगितावाद सारतः अंग्रेजी विचारधारा है। उन्नीसवीं सदी के ब्रिटेन में, विशेषकर पूर्वार्द्ध में, इसके प्रभाव से व्यापक मुबार हुआ। आज भी यह विचारधारा निर्जीव नहीं है। जब तक समाज में दुष्प्रवृत्तियों से होने वाले क्लेश रहेंगे तब तक उपयोगितावादका महत्त्व बना रहेगा। उपयोगितावाद एक ओर राज्य की अन्ध शक्ति और दूसरी ओर इसकी विरोधी भाव-भूइम प्राकृतिक अधिकारकी धारणा, इन दोनोंकी गलतियोंको ठीक कर, सही मार्ग दिखलाने वाली स्वस्थ विचारधारा है। हैलोवेल (Hallowell) के अनुसार उपयोगितावादका आधार उन्नीसवीं सदीका उत्तरवाद था जिसमें 'स्वतन्त्रताकी कल्पना प्राकृतिक अधिकारकी अपेक्षा सामाजिक उपयोगिताके रूप में अधिकाधिक की जाती थी।' उनके ही शब्दों में: 'नीतिशास्त्र और राजनीतिशास्त्रको एक व्यापक वैज्ञानिक अनुभववादके आधार पर प्रतिष्ठित करनेका उपयोगितावाद एक प्रयास था (११: १९८)।' उपयोगितावादी विचारधारा का आधार मानव-प्रकृति की वास्तविकताएँ हैं। इसका लक्ष्य व्यावहारिक है।

१. उपयोगितावाद की परिभाषा और आलोचना

(Statement and Criticism of Utilitarianism)

उपयोगितावाद मुख्यतः एक नैतिक सिद्धान्त है, जिसका आधार वह मनोवैज्ञानिक मत है जिसे सुखवाद (hedonism) कहा जाता है। सुखवादी सिद्धान्तके अनुसार हर व्यक्ति सुख की खोज करता है और दुखसे बचना चाहता है। मनुष्यके काम और भी प्रेरकों (motives) से प्रभावित हो सकते हैं, पर अन्तिम प्रेरक सुख बनाम दुख ही होता है। सुखवादी विचारधारा किसी प्रकार भी आधुनिक नहीं है। इसका आरम्भ यूनानी युग में, विशेषतया सैरेनाइक विचारधारा (Cyrenaic school) के संस्थापक एरिस्टिपस (Aristippus) की शिक्षाओं में, और कुछ-कुछ एपिक्यूरस (Epicurus) की शिक्षाओं में हुआ था। यद्यपि आधुनिक सुखवाद अत्यन्त सुरक्षित बहूत निरर्थक है फिर भी सुख की प्राप्ति ही दोनोंका मुख्य उद्देश्य है। प्राचीन सुखवादका स्वरूप स्वार्थवाद या जबर्जस्ती आधुनिक सुखवाद परोपकारवादी है। उपयोगितावाद परोपकारवादकी ही अपना आधार बनाता है इसलिए इसे कभी-कभी परोपकारवाद या सार्वजनिक सुखवाद कहा जाता है। इसका लक्ष्य अधिकतम लोगोंका अधिकतम सुख अथवा सार्वजनिक सुख (the greatest happiness of the greatest number)

हैं पर उपहास करन वालों का कहना है कि अधिकतम सस्या एक है यानी अधिकतम लोगों के मुखका असली मतलब अपना सुख है।

आजकल यह साधारणतया स्वीकार कर लिया गया है कि उपयोगितावादके मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार स्वस्थ नहीं है। मनुष्य निस्सन्देह अपने सुखको खोज करता है अर्थात् स्वार्थी होता है परन्तु स्वार्थ ही उसकी एकमात्र प्रवृत्ति नहीं है। मभीमें अपनी भलाई और दूसरोंकी भलाईकी भावनाएँ विभिन्न मात्राओंमें पायी जाती हैं। हेनरी ड्रमण्ड (Henry Drummond) के शब्दों में: "प्रत्येक मनुष्यके भीतर केवल अपने अस्तित्वके लिए ही नहीं बल्कि दूसरोंके अस्तित्वके लिए भी सधर चलता रहता है।" इसीलिए दूसरे पक्षों पर ध्यान न देकर मानव-स्वभावके केवल एक पक्षके आधार पर ही मनोवैज्ञानिक और नैतिक सिद्धान्त बनाया अत्यन्त दोषपूर्ण है। बेंथम (Bentham) यह कह कर इस समस्याको टाल जाते हैं कि हर मनुष्य स्वार्थी तो होता है पर यह स्वार्थ दूसरोंकी भलाई करनेका रूप ग्रहण कर लेता है। यह मानना होगा कि शुद्ध परोपकारवाद मनुष्यके लिए सम्भव है।

सुखवादीके लिए इन्द्रिय-जन्य सन्तोष ही सुख है। जैसा जेम्स सेठ (James Seth) कहते हैं, इन्द्रियचैतना (sensibility) मानव जीवनमें एक बड़ा और महत्वपूर्ण तत्त्व है परन्तु वह अन्तिम और लाक्षणिक तत्त्व नहीं है (it is not the ultimate and characteristic element)। अनुभूति ही मनुष्यके लिए सब कुछ नहीं है। मनुष्यमें सर्कका तत्त्व भी रहता है। 'जीवनका सुखवादी सिद्धान्त अत्यधिक सरल है, पर इस सिद्धान्तकी यह सरलता गहराई और व्यापकता खोकर ही मिली है। इसका सूत्र आवश्यकतासे अधिक सरल है (१७ ११५)।' इन्हीं लेखकके शब्दोंमें 'सुखवाद कल्याणकी गुणमूलक व्याख्या नहीं कर सकता, वह तो केवल कल्याणकी परिमाणमूलक व्याख्या ही कर सकता है।' वह केवल 'अधिक' और कम का विभेद ही कर सकता है 'उच्चतर' और 'निम्नतर' का नहीं। वह सर्वाधिक कल्याणकी ओर तो सकेत करता है पर सर्वोच्च कल्याणकी ओर नहीं।

उपर्युक्त आलोचनाओंको करते समय हम यह नहीं भूल सकते कि उपयोगितावाद मनुष्यकी परोपकार भावनाको सबल रूपसे आकृष्ट करनेवा दावा करता है। पर हमारा कहना है कि ऐसा करके वह स्वयं अपना विरोध करता है। सार्वजनीन सुखवाद (universalistic hedonism) आत्मविरोधी है। जो बात 'सार्वजनीन' होगी वह (आत्म) सुखवादी नहीं हो सकती और इसी प्रकार जो बात (आत्म) सुखवादी होगी, वह 'सार्वजनीन' नहीं हो सकती। सुख स्वभावतः व्यक्तिगत होता है। यह आत्मगत (subjective) अनुभव है। अतः उपयोगितावादियोंकी भांति सार्वजनिक सुखमें सार्वजनिक आनन्दके अर्थ निकालना निरर्थक है। 'क' यह जानता है कि उसे किस चीजसे आनन्द मिलता है और 'ख' भी जानता है कि उसे किस चीजसे आनन्द मिलता है पर 'क' और 'ख' दोनोंमें मे किसीको भी यह पता नहीं है कि सार्वजनिक आनन्द क्या है? हम दूसरोंसे आनन्द और पीड़ामें सहानुभूति कर

सबसे है पर स्वयं उसका अनुभव नहीं कर सकते। आनन्द इस अर्थमें भी वैयक्तिक होता है कि हर व्यक्ति अपने सुखका निर्णायक स्वयं ही है। केवल वही मह बतला सकता है कि कोई चीज उसे आनन्द प्रदान करती है अथवा नहीं। परन्तु उपयोगितावादियों का नैतिक माप दण्ड (criterion) तो सार्वजनिक सुख है। हमारा कहना है कि आनन्दके लक्ष्यको सार्वजनिक सुखके लक्ष्यमें परिणत करना युक्ति संगत नहीं है।

इस कारण उपयोगितावादीको अपने सिद्धान्तका विकास करनेमें इन विरोध का सामना करना पड़ा कि व्यक्ति समूचे समाजके सुखकी उन्नति क्यों करे? जे० एम० मिल ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्तिको आनन्द दूसरोंके आनन्दके साथ जुड़ा होना है जैसे कि माता-पिता और बच्चोंका आनन्द। मिल का तर्क है कि व्यक्ति पर सदैव जोर देना आवश्यक नहीं है क्योंकि हमारे बहुतसे आनन्द दूसरोंके आनन्दके साथ घनिष्ठ रूपसे जुड़े हुए हैं। पर बेन्थम का उत्तर भिन्न है। वह यह मानने है कि व्यक्ति बहुधा समुदायके हितोंको हानि पहुँचाकर अपने आनन्दकी खोजमें रहता है। फिर भी 'सार्वजनिक सुख' के लिए बेन्थम की इच्छा इतनी प्रबल है कि वह चाहते हैं कि व्यक्तिको कभी-कभी तो इस बातके लिए मजबूर किया जाय करे कि वह समाजके सुखके लिए अपने सुखका बलिदान करे। इसके लिए वह अनुशास्ति (sanction) के सिद्धान्तका सहारा लेते हैं। ये अनुशास्तियाँ (sanctions) चार हैं : शारीरिक, राजनीतिक (अथवा देगकी विधि), नैतिक (अथवा लोकमतका दबाव) और धार्मिक।

यद्यपि उपयोगितावाद एक दोषपूर्ण नैतिक सिद्धान्त है फिर भी इसके प्रभाव से व्यावहारिक राजनीतिमें अनेक महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। इस अन्तर्बिरोधका क्या कारण है? इसका उत्तर यह तथ्य है कि उपयोगितावादी जब नैतिक धर्मको छोड़कर राजनीति के क्षेत्रमें आया है तब उसका रूप एकदम उलटा हो जाता है। एक नैतिक विचारके रूपमें उपयोगितावादी सार्वजनिक सुखका अर्थ सार्वजनिक आनन्द समझता है। उनके विचारमें मनुष्यके व्यवहारका अन्तिम उद्देश्य यह है कि वह यथासम्भव अधिक से अधिक मनुष्योंको आनन्द देनेवाले अधिक से अधिक काम करे। उसका विश्वास है कि चूँकि आनन्दमें केवल मात्राका अन्तर होता है, गुणका नहीं इसलिए उसकी दृष्टि की जा सकती है (पर जे० एम० मिल के अनुसार जो उपयोगितावादके अग्रगण्ययोगी नहीं हैं, आनन्दमें गुण और मात्रा दोनोंका अन्तर होता है)। इस विचारधाराके नेता बेन्थम का कहना है कि "आनन्दकी मात्रा ममान होनेसे बच्चोंका खेल उगना ही अच्छा है जिनकी अच्छी बर्तिता होगी है।" आनन्दकी दृष्टि करनेमें और सार्वजनिक आनन्द तथा सार्वजनिक सुखको एक करनेमें जो श्रद्धाद्रव्य होती है वे इतनी स्पष्ट है कि उनके विषयमें कुछ लिखना अनावश्यक है। उपयोगितावादी स्वयं यह निष्कल प्रयत्न करनेकी अत्यधिक इच्छुक नहीं हैं।

एक राजनीतिक विचारके रूपमें उपयोगितावादी सार्वजनिक सुखकी व्याख्या बड़े ढीले-ढाले तरीकेसे करता है और उसका अर्थ सार्वजनिक मलाई या सामाजिक

कल्याण निकालता है। वह आनन्दकी धारणाको कमसे कम महत्त्व देता है और उपयोगिता पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह तो स्पष्ट है कि 'सामाजिक कल्याण' और 'उपयोगिता' जैसे शब्द इतने व्यापक और व्यावहारिक हैं कि जो कोई भी इन्हें अपने राजनीतिक कार्यक्रमका आधार बनायेगा वह अवश्य ही जनताका बहुत हित कर सकेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयोगितावादियों द्वारा की गयी अपने उद्देश्यकी व्याख्यामें जो असंगति है, उसीके कारण उन्होंने व्यावहारिक राजनीतिमें बड़े हितकर कार्य किये। उनका राजनीति-शास्त्र, राज्य-शास्त्र (theory of state)की अपेक्षा शासन-शास्त्र (theory of government)ही अधिक था।

यदि उपयोगितावादकी आलोचना करने चले तो हम हैलोवेल की तरह यह कह सकते हैं कि अधिकतम लोगोंके अधिकतम सुखके लिए अल्पसङ्ख्यको के बन्दी-विधियो (concentration camps) को भी उचित ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार निरकुशता और दासताको भी उचित कहा जा सकता है। हैलोवेल के अनुसार वेन्यमवाद एक ऐसा उदारतावाद है जो निरकुशताके लिए बहुत ही अनुकूल है (१३. २१७)। परवेन्यमने उपयोगितावादकी व्याख्या इस रूपमें नहीं की थी और न उसका यह अर्थ ही निकाला था।

२. उपयोगितावाद का मूल्यांकन (Appreciation of Utilitarianism)

ऊपर उपयोगितावादकी एक नैतिक सिद्धान्तके रूपमें जो आलोचनाकी गयी है उसका अर्थ यह नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्रमें भी हम इसकी उचित प्रशंसा न करें। उपयोगितावाद मनुष्य जातिके कल्याणमें हमारी अभिरुचिका द्योतक है। अभिरुचि के साथ ही तर्क-संगत सिद्धान्तोंके आधार पर मानव जीवनकी परिस्थितियोंको सुधारनेके व्यावहारिक प्रयत्न इसमें शामिल हैं। इसका विश्वास है कि प्रभावपूर्ण सरकारी विधियों द्वारा जनताका जीवन स्तर उठाया जा सकता है। सभी उपयोगितावादियोंके मनमें सार्वजनिक कल्याणकी भावना रहती है। उन्हे सबसे पहली और सबसे अधिक चिन्ता मानव जीवन, मानव कार्य-बलाप और मानव कल्याणकी रहती है। वे निरकुशता और अन्यायके प्रबल विरोधी और वैयक्तिक स्वार्थ्यके प्रबल समर्पक हैं। वे सभी प्रकारके 'कुटिल' स्वार्थ्यके विरोधी हैं। अतः उपयोगितावाद निश्चित रूपसे एक व्यावहारिक सिद्धान्त है। यह सुधारवादी है। उपयोगितावाद मानववादका ही दूसरा नाम है।

बहुधा उपयोगितावादकी अनुचित आलोचना इसे एक लाभमूलक सिद्धान्त या सुविधामूलक दर्शन कहकर की जाती है। लाभका अर्थ है किसी उद्देश्य या लक्ष्यकी सिद्धि। सामान्य मोलचालकी भाषामें इसका अर्थ बहुधा निम्नकोटिका उद्देश्य या लक्ष्य होता है। उपयोगितावादी मनुष्यकी कल्पना केवल एक व्यक्तिके रूपमें ही न

करके उसे एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो स्वभावतः सामाजिक होता है। उपयोगिता-वादो के लिए उपयोगिताका अर्थ है "वह वस्तु जो मानव स्वभावके सभी तत्त्वोंके लिए सबसे अधिक उपयोगी हो, जिससे उसके पूर्ण और चरम कल्याणके साथ ही साथ उसके साथियोंके पूर्ण और चरम कल्याणकी मिद्धि हो सके।" उपयोगितावादके सिद्धान्तोंको इन वाक्यांशोंमें व्यक्त किया गया है - 'अधिकतम लोगोंका अधिकतम सुख', 'प्रबुद्ध उदारता' (enlightened benevolence) और 'सार्वजनिक सुख' (general happiness) (१३:१३)।

उपयोगितावादको कभी-कभी निम्नतम कोटिके भौतिकवादका पर्याय भी माना गया है। इस गलत धारणामें बचनेके लिए यह सांचा गया है कि 'उपयोगिता' और 'सुख' के स्थान पर 'कल्याण' और 'मलाई' शब्दोंका उपयोग किया जाय। 'कल्याण' में वे सभी तत्त्व आ जाते हैं जिनमें मानव सुखी होता है। इस मुद्दाके विरुद्ध केवल एक यही आपत्ति है कि यह उपयोगितावादी सुखवादके प्रस्थान बिन्दुमें बहुत दूर है। यदि उपयोगितावादी सुखवादके साथ अपने सम्बन्धको छोड़नेको तैयार हो तो उनका सिद्धान्त स्वीकार करनेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदर्श उपयोगितावाद सुखवादको अस्वीकार करता है और आदर्शवाद तथा उपयोगितावादके सर्वोत्तम तत्त्वोंका समन्वय करता है। यह मानव व्यक्तित्वके विकासको सामाजिक कल्याणके साथ सम्बद्ध करता है। टी० एच० ग्रीन जिनमें यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, और जिनके विचार अनेक प्रश्नों पर मिलके विचारोंमें मिलते-जुलते हैं, यह तर्क देते हैं कि सुखवादसे आरम्भ होनेवाले उपयोगितावादको सामाजिक कल्याणके परस्परनेका कोई अधिकार नहीं है। 'स्वाधी आत्म सन्तोषकी सिद्धिको अपना लक्ष्य बनाते हुए ग्रीन आनन्द और पीडाका सन्तुलन करनेमें पड़ने-वाली कठिनाईयोंको टाल जाते हैं।' उपयोगितावादके विषयमें ग्रीन के विवेचन पर टीका करते हुए डी० जी० रिचो (D. G. Ritchie) लिखते हैं: 'इस बातका कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि सुखवादके सम्बन्धमें अपनी आपत्तियोंको स्पष्ट कर देनेके बाद आदर्शवादी उपयोगितावादियोंमें मेल क्यों न करे।' इन्हीं लेखक का कहना है कि ग्रीनकी नैतिक व्यवस्था मिल का उपयोगितावाद ही है। हा, उसमें मिलने उपयोगितावादके अनिश्चित एक सुदृढ़ आधार और एक मापदण्ड भी है।

यदि हम उपयोगितावादके सर्वोत्तम रूप पर विचार करें तो उपयोगिता-वादीका कहना है कि दूसरोंका ख्याल किये बिना स्वतंत्र रूपसे सुखको प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि व्यक्तिको केवल एक व्यक्तिमात्र समझना भूल है। उनका विश्वास है कि व्यक्तित्व सुख राज्यके अस्तित्व और सगुण पर आवश्यक तोर पर निर्भर करता है। रीति-रिवाजों, विधि और विधानको व्यक्तिको सुखी बनानेमें और साथ ही उनके सुखकी सीमित करनेमें योग देना चाहिए। क्योंकि व्यक्तित्वका स्वार्थमूलक सन्तोष ही सुख नहीं है। उपयोगितावादोके अनुसार विषादको सामान्य जनताके

कल्याणका ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए। उपर्युक्त विधानके निषेधात्मक और आदेशात्मक दो पहलू होते हैं। निषेधात्मक रूपमें उसे उन परिस्थितियोंको समाप्त करना चाहिए जो पतन लानेवाली और कष्टकारक होती हैं और इन परिस्थितियोंके स्थान पर राज्यको आदेशात्मक रूपमें अनुकूल प्रोत्साहनोंकी व्याख्या करनी चाहिए।

कभी-कभी यह कहा जाता है कि उपयोगितावादमें आदर्शवादियोंकी कमी है। यह आरोप ठीक नहीं है। 'समाजके भावी उत्थान और मानव जातिके सुधारके आदर्श स्वप्न ही उपयोगितावादी को प्रेरणा देते, उत्साहित करते और सक्रिय बनाते हैं तथा कठिनाइयों और असफलताओंके मध्य उसे स्थिर रखते हैं (१३ : २६)।' उपयोगितावादीके आदर्श मूलतः व्यावहारिक और मानवी हैं। जिन आदर्शोंको उपयोगितावादी अस्वीकार करता है वे उसकी दृष्टिमें या तो अवाञ्छनीय या अप्राप्य, या दोनोंही प्रकारके हैं। उपयोगितावादी न तो हठधर्मी होता है और न स्वप्नदर्शी। उसके पैर ठोस भूमि पर ही रहते हैं।

उपयोगितावाद अनुभव पर आधारित है। अनुभव ही इसकी अन्तिम कसौटी है। उपयोगितावादीके लिए परिणाम ही सब कुछ है। वह अनुभवको ही ज्ञानका मूल स्रोत और उद्गम तथा सत्यका अन्तिम मापदण्ड मानता है। वह कोरी कल्पना और भाव-सूदमताका विरोधी है।

इस प्रकार उपयोगितावाद एक अत्यन्त मानवी और अत्यन्त व्यावहारिक दर्शन है। यह कोई नवीन नीतिशास्त्र नहीं है। 'यह राजनीतिक क्षेत्रमें प्रवेश करके अपनेको राज्य विधानमें व्यवृत देखना चाहता है (१३ : २९)।' लोगोंकी सक्रियता और उनको अभिशक्तियोंके साथ इसका सीधा सम्बन्ध रहता है (१३ : २९)। समय ने इसमें बहुत कुछ सुधार किये हैं—इसकी बहुत-सी बातोंका निरस्कार भी किया गया है और समय इससे बहुत आगे बढ़ गया है परन्तु अन्यायका तीव्र विरोध करना, दोनो और दलितोंकी सहायता करना और मानव कल्याणके लिए उत्साहपूर्वक प्रयत्न करना उपयोगितावादियोंकी विशेषताएँ रही हैं और स्पष्ट रूपसे अब भी हैं (१३ : २४९-५६)। उपयोगितावादियोंमें कमियाँ भी रही हैं और उन्होंने असफलताएँ भी पायी हैं पर उनकी दृष्टि मदैव भविष्यकी ओर लगी रही है।

३. उपयोगितावादी विचारक (Utilitarian Thinkers)

ब्रिटेन में उपयोगितावादके नेता जेरेमी बन्थम (Jeremy Bentham) थे। सीमाव्यवस्था उनके साथ योग्य और श्रद्धालु लोगोका एक दल था। इन लोगोंने ब्रिटेन के सामाजिक जीवनके विभिन्न पहलुओंमें उपयोगितावादी सिद्धान्तोंका प्रयोग करनेमें अपनेको अर्पित कर दिया था। इनमें जेम्स मिल (James Mill) और उनके पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill), इतिहासकार प्रोटे

(Grote), मनोवैज्ञानिक अलेक्जेंडर बेन (Alexander Bain), विधि-वेत्ता जॉन ऑस्टिन (John Austin) और अर्थशास्त्री रिकार्डो (Ricardo) मुख्य थे। आशिक रूपमें एक्को छोड़कर सेप सब नास्तिकारी, दार्शनिक और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। तत्कालीन ब्रिटेन सामाजिक कुरीतियोंसे कराह रहा था और इस दुर्व्यवस्थाने उन्हें अपनी 'सुधारकी प्रबल इच्छा' को कार्यान्वित करनेका पर्याप्त अवसर दिया।

१. जेरमी बेन्थम (१७४८-१८३२) ने उपयोगितावादी विचारधाराकी आधारसिला रखी। उन्होंने अन्यायको दूर करने और स्थायी सुधार करानेमें बहुत महत्त्वपूर्ण भाग लिया। अपने गहरे वैधिक शिक्षण, स्वस्थ व्यावहारिक बुद्धि और पदबलिष्ठ तथा दुखी लोगोंके प्रति अपनी गहरी सहानुभूतिके कारण बेन्थम अपने इस महान् कार्यके लिए विशेष तौर पर उपयुक्त थे। उनके दर्शनका सार यह है—'प्रकृतिने मनुष्यको दो सम्प्रभु अधिपतियोंके अधीन रखा है। ये अधिपति हैं—दुःख (क्लेश) और सुख (आनन्द)। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं—सबमें हम इनके अधीन हैं और अपनी इस अधीनताको दूर करनेके लिए हम जो भी प्रयत्न करते हैं उनसे भी इसी सत्यकी पुष्टि होती है और इसी बातका प्रमाण मिलता है। उनके अनुसार उपयोगिताका सिद्धान्त इस अधीनताको स्वीकार करता है क्योंकि सुखकी वृद्धि करने अथवा दुःखका विरोध करनेकी प्रकृतिके अनुसार ही यह प्रत्येक कार्यको स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है। आगे चलकर वह इस सिद्धान्तको 'सर्वाधिक सुख-सिद्धान्त' (greatest happiness principle) कहते हैं। उनका कहना है कि सुखका बटवारा करते समय प्रत्येककी गणना 'एक और केवल एक इकाईके रूपमें' की जानी चाहिए किसीको एक इकाईसे अधिक नहीं माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दोंमें व्यक्तियोंके साथ पूर्ण निष्पक्षताका व्यवहार किया जाना चाहिए।

बेन्थम के अनुसार प्रगाढ़ता (intensity), अवधि (duration), निश्चयात्मकता (certainty) और सम्बन्ध-समीप्य (propinquity) की दृष्टिसे सुखोंमें अन्तर होता है। पर गुणकी दृष्टिसे वे सब एक ही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हम एक सुख या आनन्दको दूसरेकी अपेक्षा 'उत्तम' या 'उच्चतर' नहीं मान सकते। इसके माने यह भी हुए कि सुखोंको गणितके नियमोंके अनुसार जोड़कर उनका योग भी निकाला जा सकता है।^१ यह कथन बिल्कुल निस्मार मालूम पड़ता है। परन्तु बेन्थमका व्यावहारिक उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि मद्भावना-पूर्ण व्यक्ति, दूसरोंके बारेमें, यह तय करनेका ठेका स्वयं न ले ले कि उनके लिए क्या यथार्थ सुख होगा। बेन्थम का सिद्धान्त निस्मन्देह संकीर्ण और मनोवैज्ञानिक दृष्टि

^१ उन्होंने लिखा है कि 'पूरे समुदायका हित' 'उम समुदायके सब सदस्योंके हितों का पूर्ण योग' ही है न उससे कम और न उससे अधिक।

मे गलत है। फिर भी जैसा कि आइवर ब्राउन (Ivor Brown) ने कहा है, 'यह सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बातको माननेसे इन्कार करता है कि वे बड़े लोग अश्रुत (infallible) हैं और कभी कोई गलती नहीं कर सकते जो नैतिकता और सुख सम्बन्धी अपनी धारणाको दूसरों पर इस विश्वासके सहारे लाद देनेका प्रयत्न करते हैं कि दूसरे लोग अज्ञानताके दयनीय दास हैं (६: ९६)।' 'अग्ने दोषोंसे मुक्त होकर बेन्थमवाद मानववाद ही है (६: १०२)।'

बेन्थमका मूल उद्देश्य समाजका हित अथवा कल्याण था। उनका विश्वास था कि उनके उपयोगिताके सिद्धान्तका सभी सामाजिक समस्याओंमें विशेषकर सावधानिक, विधायी और विधि-मुच्यार सम्बन्धी प्रश्नोंमें सफल और लाभप्रद प्रयोग हो सकता है। एक सजीव और व्यावहारिक हित उनका लक्ष्य था।

जिस समय बेन्थम एक महान् सुधारक और विचारकके रूपमें आये, उस समय नैसर्गिक अधिकार-सिद्धान्तका और अंग्रेजी संविधान तथा विधिकी महत्ताके बारेमें ब्लैकस्टन (Blackstone) के भारीभरकम सिद्धान्तका बोलबाला था। बेन्थमने इन दोनोंकी खूब खिल्ली उड़ाई और उनकी निर्मम आलोचना की। नैसर्गिक अधिकारोंको उन्होंने केवल एक प्रलाप नैसर्गिक और अविच्छेद्य अधिकारोंको आ-लंकारिक प्रलाप और मूर्खताका नया नाच बताया। नैसर्गिक अधिकार सिद्धान्तके स्थान पर बेन्थमने अपने उपयोगिता के सिद्धान्तको रखा। यद्यपि नैसर्गिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थॉमस पेन (Thomas Paine) और बेन्थमके दार्शनिक दृष्टिकोणों में बहुत अधिक अन्तर था, फिर भी दोनोंने अनेक उदार सुधारोंका समर्थन किया। जैसा कि आइवर ब्राउन ने लिखा है, 'शायद ही कभी अन्य दो व्यक्ति इतने पृथक् मार्गोंसे एक ही लक्ष्यकी ओर बड़े होंगे (६. ९८)।'

बेन्थम ने १७७६ में प्रकाशित अपनी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक '*A Fragment on Government*' में ब्लैकस्टन की कड़ी आलोचना की। ब्लैकस्टन ने अंग्रेजी संविधान को देवी इच्छाके अनुसार एक त्रिमिक स्वाभाविक विकास बताते हुए इसकी बड़ी प्रशंसाकी थी। 'बेन्थम ने सिद्ध किया कि अंग्रेजी विधि-व्यवस्था केवल दुर्बल और गरीबोंकी सतानेवाली एक निर्लज्ज निरकुशता थी। यह शिक्षित और शक्ति सम्पन्न लोगोंकी सहायता देनेकी एक व्यापक योजना थी ताकि ये लोग अज्ञानी और दलित लोगोंको दबाए रख सकें (६. १०२)।' बेन्थम ने ब्लैकस्टन की आलोचना इसलिए भी की कि ब्लैकस्टन ने प्रारम्भिक सामाजिक सविदा को राजनीतिक दायित्वका आधार माना था। बेन्थमका कहना था कि अनीतकालमें कभी कोई ऐसी सविदा नहीं हुई और यदि हुई भी हो तो वर्तमान पीढ़ी उससे बाध्य नहीं है। आजापालनका एवमात्र न्याय मगत कारण है उपयोगिता अथवा सावैज्ञानिक बन्धन। सरकारोंका अस्तित्व इसलिए कायम है क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि उनके द्वारा उनके अधीन लोगोंकी सुख वृद्धि होती है। बेन्थमकी अपनी विशिष्ट भाषामें 'आजा-पालन से जिन बुराइयोंकी सम्भावना है वह उन बुराइयोंकी अपेक्षा कम है' जो

आजापानन करनेसे सम्भव है। डनिंग (Dunning) का यह कहना ठीक ही है कि रुडिवादी ब्रिटेन के आदरणीय मिद्धान्तों और रीतियोंका परखना और उनका मूल्य समझना बेन्थम के लिए उतना ही मुश्किल था जितना बन्दर के लिए अदरक का स्वाद समझना (२७:२१२)।

शासन-सिद्धान्त (Theory of Government). अपने समकालीन विचारकोंकी भांति अंग्रेजी संविधानकी अत्यधिक प्रशंसा करनेके बजाय बेन्थम ने दृढ़ता और विश्वासपूर्ण उत्साहके साथ उसकी आलोचना की। उन्होंने वार्षिक संसद (annual parliaments), मत-पत्र द्वारा मतदान का समर्थन किया और मांगकी कि पड़नेकी योग्यता रखने वाले सभी जालिग पुरुषोंको मताधिकार दिया जाय। उनके सभी सुझावोंका उद्देश्य जनता का वास्तविक और प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व कायम करना और राजनीतिक भ्रष्टाचारको रोकना था। यह उल्लेखनीय है कि इन सुझावों में से दो सुझाव तब से अब तक विधि बन चुके हैं। वार्षिक संसदकी मांग छोड़ दी गयी है और अब यह सम्भावना नहीं है कि यह भाग फिरकी जायगी। बेन्थमकी कामना थी कि लोकतन्त्रका पूरा बोलबाला हो। इसी उद्देश्यसे उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रोंकी समानता और समाचारपत्रोंकी स्वतन्त्रताकी भी सिफारिशकी। उन्होंने हाउस आफ़ लार्ड्स और राजतन्त्रकी उपयोगिता पर भी इस आधार पर आपत्तिकी कि इनके हिनोका सामान्य जनताके हितोंसे कोई मेल नहीं बैठता। उन्हें इस बातका विश्वास हो गया था कि एक संसदात्मक विधायिका जिसका निर्माण प्रतिवर्ष हुआ करे, लोक-तंत्रीय सिद्धान्तोंके सबसे अधिक अनुकूल है। बेन्थम गणतन्त्रमें विश्वास करते थे और उनका विचार था कि गणतन्त्रसे न्याय-निपुणता बढ़ने और शासन-व्ययमें कमी होनेके साथ ही जनताकी सर्वोच्चता भी कायम हो जायगी।

सार्वभारिक संहिता (constitutional code) की सहायतासे जिसकी उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार किया था वह 'इस कूटिल संसारको गणतन्त्रोंका जाल बिछाकर' अच्छा बनानेकी आशा करते थे। उनके विचारमें न तो पूर्ण राजतन्त्र और न सीमित राजतन्त्र ही जनताकी सर्वाधिक मुक्त प्रदान कर सकता है। 'जब लोकतन्त्रात्मक शासन होगा है तभी शासन और सामिनोंके हित एक हो जाते हैं क्योंकि तब अधिकतम् लोगोंका अधिकतम् सुख ही चरम् लक्ष्य होता है (१३:७८-८९)।'

विधान (Legislation). इसी क्षेत्रमें बेन्थमका सबसे अधिक योगदान रहा है। अपनी पुस्तक *Principles of Morals and Legislation* के प्रकाशित होने पर वह विधानके एक प्रकारके नये पैगम्बर बन गये। संसारके विभिन्न देशोंके राजनीतिज्ञ व्यावहारिक पथ प्रदर्शनेके लिए उनकी ओर तारने लगे। प्लेटो की धारणाके अनुसार बेन्थम एक आदर्श विधायक होनेके लिए विनोद उपयुक्त थे, क्योंकि वह राजनीतिक दलों और व्यक्तिगत स्वार्थोंसे ऊपर उठे हुए सार्वजनिक कल्याणमें रत व्यक्ति थे। उनके अनुसार विधान में लक्ष्य है—मुराता, आजीविका

प्राचुर्य और समानता। सीधी-भादी मापामें जनताका बर्याण ही उनका उद्देश्य है। बेन्थमका कथन है कि यदि विधियोंका पालन कराना है तो यह आवश्यक है कि विधिको जनताका समर्थन प्राप्त हो। बलपूर्वक कानून मनवाने और सार्वजनिक असन्तोषका परिणाम अन्ततोगत्वा क्रान्ति होता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जनता प्रसन्नतापूर्वक विधियोंका पालन करे तो जनताको विधानकी आवश्यकता सरल और स्पष्ट शब्दोंमें समझायी जानी चाहिए। मय और पारितोषिकके द्वारा लोगोंको अपनी स्वार्थ-सिद्धिमें लगनेसे रोका जाना चाहिए।

बेन्थम ने बहुत सारे व्यावहारिक सुधारोंकी सिफारिश की थी। डेविडसन के अनुसार उन सुधारोंमें मुख्य ये हैं—भ्रष्ट और नीमित संमन्वीय पद्धतिका सुधार; नगरपालिकाओंका व्यापक सुधार; तत्कालीन अत्यन्त कठोर दण्ड-विधिको नरम करना; जेल और जेल-प्रबन्धमें सुधार; ऋणके लिए कारावास-दण्डका अन्त; सूदखोरी-सम्बन्धी विधियोंकी समाप्ति; धार्मिक परीक्षणका अन्त; दरिद्र-रक्षा विधि (poor law) में सुधार; 'स्वस्थ मित्रमणों' की निष्ठा वृत्तिकी रोकना; शरीर से समर्थ दरिद्रोंका उपयोग; मित्रमणोंके बच्चोंका प्रशिक्षण; राष्ट्रीय शिक्षा की एक व्यापक योजना बनाना और कार्यान्वित करना; 'मितव्ययिता बैंको' (जिन्हें आजकल बचत बैंक्स (savings banks) कहते हैं और 'सहायता देने वाली सत्समाजों' (friendly societies) की स्थापना करना; वाणिज्य जहाजरानीके लिए विधिसंहिता बनाना; आविष्कारकोंकी रक्षा; स्थानीय न्यायालयोंको प्रोत्साहन देना; स्वास्थ्यके सम्बन्धमें व्यापक विधान, गरीबोंके लिए सरकारी अधिवक्ताओं (prosecutors) और चकीलोंकी व्यवस्था; बंधानुगत अधिकारोंका व्यापक संशोधन; वैज्ञानिक और दार्शनिक मस्यानोंकी देख-रेख रखना और जन-पदाधिकारियोंका प्रत्यावर्तन (recall)। यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि जिन सुधारोंका बेन्थम ने इसनी तत्परता और लगनके साथ समर्थन किया था उनमें से अनेक सुधार विभिन्न देशोंमें विधिका रूप पा चुके हैं।

विधि सुधार (Law reform). बेन्थम एक महान् विधि-सुधारक बनना चाहते थे। वह इस बातके लिए बहुत व्यग्र थे कि 'दलितों और योग्य व्यक्तियों को न्याय और सुत्र मिले (१३:९२)।' इसी उद्देश्यसे उन्होंने तत्कालीन विधियों की और उन विधियोंको लागू करने वाली व्यवस्थाकी आलोचना की। पर वह केवल विध्वंसक आलोचक नहीं थे। उनका उद्देश्य मौलिक रूपसे रचनात्मक था और आलोचना तो इस लक्ष्यकी प्राप्तिका साधन थी। उन्होंने न केवल विभिन्न योरोपीय देशोंकी विधियोंको, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय विधिकी भी विवेचना की और बड़े महत्वपूर्ण मिद्दान्त प्रतिष्ठित किये। सर हेनरी मेनने न्यायिक-सुधारके इतिहासमें बेन्थमके योगदानकी प्रशंसा यह कह कर की है कि 'बेन्थमके समयमें लेकर आज तक ऐसा कोई भी विधि-सुधार मेरी दृष्टिमें नहीं आता जिस पर उनका प्रभाव न हो।'।

बेन्थम ने यह अनुभव किया कि तत्कालीन विधियां बहुत अस्त-व्यस्त अव थीं और उन विधियोंको संहिताबद्ध करनेकी जिम्मेदारी स्वयं उन्होंने अपने ली। पर अपने देशमें उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। हां, अन्य देशोंसे—विशेषकर फ्रांस और इससे—उन्हें प्रोत्साहन मिला। इन देशोंकी विधि-व्यवस्थामें उपयोगितावादी सिद्धान्तों को लागू करके बेन्थम ने यह दिता दिया कि किस प्रकार उनका सिद्धान्त व्यावहारिक रूपसे कार्यान्वित किया जा सकता है।

विधियों को संहिताबद्ध करनेके अलावा उन्होंने अपना ध्यान उनके स्वरूप संगठनकी ओर भी दिया। बेन्थम उस अनावश्यक पारिभाषिकता और प्राविधिकता (technicality), व्यर्थ के शब्दजाल और अप्रचलित शब्दावलीसे चिढ़ते थे जो विधि-निर्माताओंको बहुत प्रिय थी। उनका कहना था कि विधियोंको सीधे-सादे, आसानीसे समझमें आनेवाले छोटे-छोटे वाक्यों में व्यक्त किया जाना चाहिए। विधियां उन लोगोंके लिए सुलभ और सुगम होनी चाहिए, जिन पर उनके पालन करनेका उत्तरदायित्व है। बेन्थमने विधियोंको लागू करनेकी उस पद्धतिकी कड़ी आलोचना की जिसके फलस्वरूप गरीबों पर अत्यधिक बोझ पड़ता था। न्यायाधीशोंके उन विलम्बकारी तरीकोंकी उन्होंने बड़ी भत्सना की जिनसे मुकदमोंसे सम्बन्धित पक्षोंका अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है और कानून की प्राविधिकताके कारण न्याय ही नहीं हो पाता है। न्यायाधीशोंके प्रति उनके हृदयमें बहुत कम सम्मान था और न्यायाधीशोंकी निर्दुसताकी रोक-थामके लिए वह जूरियोंका बहुत समर्थन करते थे। न्यायिक पदाधिकारियों पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व डालने पर वह बहुत जोर देते थे और इसीलिए वह एक न्यायाधीशकी अदालतको उस अदालतसे अच्छी मानते थे जिसमें कई न्यायाधीश एक साथ बैठकर मुकदमोंका फैसला करते हैं। उनका कहना था कि मुकदमोंकी सुनवाईमें अनेक न्यायाधीशोंके होनेका मतलब है हरेक न्यायाधीशके उत्तरदायित्वकी शिथिलता (१३: ९७)।

शिक्षा (Education). मानव-जातिका सुधार करनेमें शिक्षाकी शक्ति पर बेन्थम का ठोस विश्वास था। उन्होंने दो प्रकारकी शिक्षा-पद्धतियोंकी रूप-रेखाएं बनायी थी—एक गरीब बालकोंके लिए और दूसरी धनी बालकोंके लिए। इनकी शिक्षा-पद्धतिका प्रस्थान-बिन्दु यह था: 'सबसे पहले उस बातकी शिक्षा दो जो उपयोगी है—जो आगे चलकर विद्यार्थीके जीवनमें सबसे अधिक लाभप्रद हो सके' (१३: ८९)। उन्होंने ही इस वर्तमान सिद्धान्तकी नींव डाली कि 'सबसे पहले वही चीजें निसाओ जो सबसे अधिक सुगमतासे सीखी जा सकती हैं अर्थात् विद्यार्थी की सामर्थ्यका ध्यान रखो और उसे उसकी दक्षता और स्वभाविक प्रवृत्तिके विषय विषयों में करो' (१३: ९०)।

दण्ड और कारावास सम्बन्धी सुधार (Punishment and prison reforms). बेन्थम का कहना था कि दण्डका प्रधान उद्देश्य अपराधोंको रोकना है। दण्ड केवल प्रतिहिमात्मक नहीं होना चाहिए। बेन्थम यह मानते थे कि

प्रतिहिंसासे सन्तोष मिलता है पर उनका मत था कि दण्ड देनेमें प्रतिहिंसाको गौण स्थान दिया जाना चाहिए। दण्ड अपने उद्देश्यके ठीक अनुकूल होना चाहिए—न उससे अधिक और न उससे कम। इस दण्डसे समाजको लाभ होना चाहिए। यदि समाज की सुरक्षा और प्रतिष्ठाके लिए मृत्यु-दण्ड आवश्यक हो तो वह उचित और न्यायपूर्ण है, अन्यथा नहीं। हत्याके अपराधोके अलावा अन्य अपराधोंमें मौतकी सजा दी जाय या नहीं, इसका निर्णय बेंन्यम की सम्मतिसे, उपयोगिताके आधार पर यानी इस बात पर होना चाहिए कि सार्वजनिक कल्याण पर इसका कंसा प्रभाव पड़ेगा। जहां तक सम्भव हो, दण्ड जनताकी आंखोंके सामने ही दिया जाय जिससे अपराधो प्रवृत्तिवाले उसे देखकर भयभीत हो और अपराध न करें। यह मत आधुनिक विचारधाराके विपरीत है।

बेंन्यम निरोधात्मक दण्ड-सिद्धान्त (deterrent theory of punishment) पर जोर देते थे। पर अपराधोका सुधार उसकी परिधिसे बाहर नहीं है। बेंन्यमका कहना था कि दण्डसे होने वाले परिणामोंका अन्दाज लगाते समय अपराधोके सुधारका भी ध्यान रखा जाय (१३:१०१)। उनका विश्वास था कि अनेक अपराधी और दुर्वृत्ति वाले लोग सुधारे जा सकते हैं और समाजके उपयोगी और सम्मानित सदस्य बनाये जा सकते हैं। इसी विश्वासके बल पर उन्होंने अपराधियोंके पुनर्वासके लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधारोका समर्थन किया था, जैसे कारावासमें अपराधियों को औद्योगिक शिक्षा देना। अपराधियोंके दैनिक जीवनकी व्यवस्थित देख-रेखके लिए 'उन्होंने एक योजना बनायी थी जिसका उन्होंने 'पैनोप्टिकन' (panopticon) नामकरण किया। इस योजनाके अनुसार कारागारकी इमारतें इस ढंगसे अर्द्धचन्द्राकार बनायी जानी चाहिए कि जेलका सुपरिन्टेण्डेंट अपने निवास-स्थानसे जेलकी सभी कोठरियोंको देख सके। इस योजनाकी मुख्य बातें थी—सावधानी-पूर्वक निरीक्षण, सहानुमतिपूर्वक अनुशासन और उन्नत वातावरण। अपराधियोंको लाभप्रद व्यवसायोंकी शिक्षाके अतिरिक्त प्रारम्भिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। अपराधियोंको नैतिक और धार्मिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। उनके सामने आदर्श चरित्रोंको इस ढंगसे रखना चाहिए कि वे स्वयं अपने चरित्रका सुधार करने लगें। इस योजनाके अनुसार कारावाससे छूटने पर अपराधियोंके लिए तब तक रोजी की व्यवस्था कीजानी चाहिए जब तक उन्हें जनताका विश्वास फिरसे न मिल जाय और वे स्वयं अपने पैरों पर न खड़े हो जायें। यद्यपि इनमेंसे अनेक सुधार बेंन्यमके जीवन-कालमें कार्यान्वित न हो सके, फिर भी 'उनके समयसे अब तक कारागारों और अनुत्पालयों (penitentiaries) में जो व्यापक सुधार हुए हैं और औद्योगिक विद्यालयों तथा सुधार-शालाओं (reformatories) की जो स्थापना हुई है उन सबकी प्रेरणा उन्हींमे प्राप्त हुई है और उनका आधार वही सिद्धान्त है जिन्हें वह प्रतिष्ठित कर गये थे (१३:१११)।'

एक और दृष्टिसे भी बेंन्यम अपने समयसे आगे थे। उनका विश्वास था कि

दण्ड अपराधीके अनुरूप होना चाहिए न कि अपराधी दण्डके अनुरूप बनाया जाय । उनका विश्वास था कि अपराधियोंको दण्ड देते समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिए . अपराध कैसा था, अपराध करनेमें पहले अपराधी का चरित्र कैसा रहा है, अपराधीका वशानुक्रम, वह परिस्थितियाँ जिनमें अपराध किया गया, अपराधीका उद्देश्य क्या था और जिन्हें दण्ड पहुँची है वे किस कोटिके व्यक्ति हैं । दण्ड मुनिश्चित और पक्षपात रहित होना चाहिए ।

उन्नोमवी शताब्दीके आरम्भमें बेन्थमने समाज सुधारका जो प्रयत्न किया उसकी उपर्युक्त विस्तृत रूपरेखामें पाठकोंको यह स्पष्ट हो गया होगा कि उपयोगितावादका स्वरूप कितना अधिक व्यावहारिक और सुधारवादी है । पर यह याद रखना चाहिए कि इन सब सुधारोंका आधार 'सार्वजनिक सुख' का सिद्धान्त नहीं है, बल्कि सार्वजनिक कल्याण या सामाजिक सुविधा अथवा सार्वजनिक उपयोगिताका सिद्धान्त है । बेन्थमके सम्बन्धमें यह टीका ही कहा जाता है कि उन्होंने सभी समस्याओंकी परख यह रखी थी कि उनके अन्तिमका औचित्य उनकी उपयोगितामें प्रदर्शित होता है या नहीं ।

२. जेम्स मिल (१७७३-१८३६) आजीवन बेन्थम के शिष्या अनुयायी रहे । वह 'बेन्थम के सभी सिद्धांतों से सबसे अधिक उद्यमी, सम्भवतः सबसे अधिक बुद्धिमान् और किसी बात पर न झुकने वाले व्यक्ति थे (१३:११४) ।' सामाजिक और राजनीतिक समस्याओंमें उनकी सबसे अधिक रचि थी । उपयोगितावादकी प्रयोगात्मक और आगमनात्मक (experimental and inductive) पद्धति पर उनकी निष्ठा थी । बेन्थम की भाँति समाजके निम्न और उच्च दोनों ही वर्गोंके लिए शिक्षाकी उपयोगिता पर उनकी पूरा विश्वास था । बेन्थम की तरह उनकी भी विधि में और विधिके सुधारमें गहरी दिलचस्पी थी । राजतन्त्रके विरुद्ध उन्हें ज्यादा आपत्ति नहीं थी । उनका विश्वास था कि एक मुख्यवस्थित प्रतिनिधियुक्तनिम्न सरकारको स्वार्थ-मिद्धि पर रोक लगनी है । यद्यपि बेन्थम की तरह उन्होंने लॉर्ड-सभाके उन्मूलन का समर्थन नहीं किया फिर भी उसके अधिकारोंको कम करनेके लिए उन्होंने कान्ति-कारी प्रस्ताव रखे और इन मानेमें ब्रिटेन के मन् १९११ के अधिनियमकी पूर्ववर्त्यता उन्होंनेकी थी । उनका विश्वास था कि यदि देशके मध्यवर्गके हाथोंमें राजनीतिक सत्ता रहेगी तो उसमें व्यवस्था और प्रगतिकी सबसे अधिक बल मिलेगा । डेविडसन (Davidson) के कथनानुसार जेम्स मिल 'बेन्थम के बाद आमूल परिवर्तनवादी (radical) उपयोगितावादियोंके नेता थे और इस विचारधाराके व्यावहारिक सुधारोंको कार्यान्वित करवानेमें उनका प्रधान योग था (१३:१४२) ।'

३. जोन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill, १८०६-७३) जेम्स मिलके पुत्र थे और अपने पितामें अधिक प्रसिद्ध हैं । उन्होंने बेन्थमकी कठोर नैतिक मान्यताओंको नरम बनाया और ऐसा करके 'उन्होंने उपयोगितावादको अधिक मानवी, पर साथ ही कम मगल (consistent) बना डाला (६:११९) ।' उन्होंने यह

स्वीकार किया कि सुखमें केवल मात्राका ही नहीं, गुणका भी भेद होता है। उनके इन शब्दोंका बहुधा उल्लेख किया जाता है कि 'एक सन्तुष्ट सुखर होनेकी अपेक्षा एक असन्तुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है और एक सन्तुष्ट मूर्ख बने रहनेकी अपेक्षा असन्तुष्ट मुकरात (बुद्धिमान्) होना अधिक अच्छा है और यदि उम मूर्ख या सुखर की राय इससे भिन्न है तो वह इसलिए कि वह प्रश्नके केवल एक पहलू—अपने पहलू को ही देखता है। तुलनाका दूसरा पक्ष दोनों पहलुओंको देखता है।' रवार्थ और सार्वजनिक सुखके अन्तरको कम करनेमें भी मिलकी मान्यताएँ वैय्यमसे भिन्न हैं। मिल कहते हैं—'उपयोगितावादी मानदण्ड व्यक्तिका अधिकतम सुख न होकर अधिकतम सामूहिक सुख है।' 'अपने और अन्य लोगोंके सुखके बीच व्यक्तिको, उपयोगितावाद की मान्यताओंके अनुसार, एक निरपेक्ष और उदार दर्शककी तरह पक्षपातहीन होना चाहिए।' नजारेय के ईनामसीह के स्वर्णिम मिढान्तमें हमें उपयोगिताकी पूर्ण नैतिक भावना मिलती है। 'जैसे व्यवहारकी हम दूसरोंसे अभिलाषा करते हैं, दूसरोंके साथ वैसा ही व्यवहार करना और अपने पड़ोसीको आत्मघत्यू प्रेम-भावनासे अपनाता—इन दोनों उपदेशोंमें उपयोगितावादी नैतिकताकी पूर्णता है (६१: अध्याय ११)।' वैय्यमका कहना था कि केवल बाह्य अनुशास्तियों (external sanctions) में ही व्यक्ति को सार्वजनिक सुख की वृद्धि के लिए विवश किया जा सकता है। पर मिल का कहना था कि बाह्य और आन्तरिक दोनों ही प्रकारकी अनुशास्तियों से ऐसा किया जा सकता है। मिलका कहना था कि प्रत्येक व्यक्तिमें 'मानव जातिके सुखकी भावना' रहती है और इसीलिए उसे सार्वजनिक सुखके लिए उत्सुक होना चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए। उनका तर्क यह है कि 'चूँकि 'क' का सुख कल्याणकारी है, 'ख', 'ग' आदिका भी सुख कल्याणकारी है, इसलिए इन सब सुखों का योग भी अवश्य कल्याणकारी होगा (६१: ११-११६)।'

मिलको समाज-मुधारमें उतनी ही रुचि थी जितनी दार्शनिक चिन्तन में। १८२९ में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध निबन्ध 'स्वतन्त्रता' (Liberty) में वैय्यमिक स्वतन्त्रताका उन्होंने निर्भीक समर्थन किया। उनकी यह रचना बड़ी योग्यतासे, विचार-स्पष्ट, भाषण-स्वातन्त्र्य और कर्म-स्वातन्त्र्यका औचित्य तर्कपूर्वक सिद्ध करती है। लोकतन्त्रके प्रबल समर्थक होते हुए भी मिलको दम बातकी आगवा थी कि लोकतन्त्रमें व्यक्तिगत और मौलिकताके कुचलनेकी प्रवृत्ति होती है। इसीलिए उन्होंने विचार, भाषण और कर्मके क्षेत्र में यथामध्य अधिकतम अधिक स्वतन्त्रताका समर्थन किया। वह मनभेदको सहानुभूतिपूर्वक सहन करनेमें और विचार-विमर्शकी पूर्ण स्वतन्त्रतामें विश्वास करते थे। उनका यह पक्का विश्वास था कि विचारोंके मध्य में

* उपयोगितावादका इस प्रकार सशोधन करनेमें मिल ने एक प्रकारसे उमका सगुण ही कर दिया। उनके विचारोंके अनुसार कुछ सुख दूसरोंकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।

राजनीति में उपयोगितावाद

सत्यकी ही अन्तमें विजय होगी। विचारोंके क्षेत्रमें उन्होंने योग्यताकी (survival of the fittest) की ही शिक्षा दी है। उनका कहना था कि सामाजिक शान्तिके पहले सामाजिक चेतना का होना जरूरी है। उनका यह भी था कि व्यक्तियों और मवोंको काम करने की पूरी स्वतंत्रता तब तक दी जानी चाहिए जब तक उनके कार्योंसे दूसरोंके हितों और अधिकारोंमें कोई गम्भीर हानि नहीं होता।

व्यावहारिक राजनीतिमें मिल आमूल परिवर्तनवादी (radical) थे। वह निम्न के अधिकारोंके प्रबल समर्थक थे और स्त्रियोंको पुरुषोंको 'दामता' में 'मुक्त' कराना चाहते थे। उनका विश्वास था कि पुरुषों और महिलाओंमें असमानता मौलिक और अनिवार्य नहीं है। १८६६ से १८६८ तक समयमें एक आमूल परिवर्तनवादीके रूपमें उन्होंने मजदूरोंके हितों, स्त्रियोंके मताधिकारों, राष्ट्रीय रूपके कम किये जाने और आयरलैण्ड में भूमि-सुधारका जोरोंमें समर्थन किया उन्होंने सभी प्रकारके वर्ग-स्वार्थोंका और एकपक्षीय विधानका विरोध किया। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश पार्लियामेंटमें अल्पसंख्यकोंको उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। इसी कारण उन्होंने सभी वर्ग-दाताओंके मताधिकारका समर्थन करते हुए भी मिल उच्च चरित्र और बौद्धिक शक्तिवाले व्यक्तियोंके लिए बहुत मताधिकारके पक्षपाती थे। सरकारकी गूढ़ता और दक्षताको बनाये रखनेके लिए वह समद-सुदत्तोंको बेतन दिये जानेके विरोधी थे और गुप्त मतदानका विरोध इस आधार पर करते थे कि इससे स्वार्थ प्रेरित अनुसरदायित्वपूर्ण मतदानको प्रोत्साहन मिलता है। यद्यपि मिल कॉमन्स-सभाकी उच्चतर विधायी अधिकार-शक्तिको मानते थे पर उनका विश्वास था कि समझे सम्मुख वेग किये जाने के लिए विधेयकोंकी रचनाका काम लॉर्ड-सभाकी मीरा जाना चाहिए; क्योंकि उसमें वैधिक क्षमतावाले लोग होते हैं। वह राज्य द्वारा व्यवस्थित अनिवार्य शिक्षाके पक्षपाती थे, यद्यपि उन्हें इस बातका भी भय था कि इससे सरकारों विमर्ग द्वारा निर्धारित एक ही साचेके ढले नागरिक निकलेंगे। यह कहते थे कि अनिवार्य शिक्षा 'लोगोंको ठीक एक दूसरेके समान बनानेका तरीका' है।

आर्थिक क्षेत्रमें मिल कट्टर व्यक्तिवादी न होकर उनमें बड़ी दूर थे। समाज कल्याणके लिए किये जाने वाले व्यापक राजकीय कार्योंका उन्होंने समर्थन किया। अपने जीवनके अन्तिम वर्षोंमें वह ऐसे समाजवादी आदर्शोंको और बाहृष्ट हुए त्रिनमें 'समाजके बच्चे माल पर मार्चबन्धित प्रभुत्व होगा और सभी लोग सामूहिक धनमें होनेवाले पदोंके समान भागीदार होंगे।' उन्होंने राजनीतिक उदारवादके साथ प्राथमिक समाजवादको जोड़ दिया था। जैसा कि आइवर ब्राउन कहते हैं - 'जहां तक समाजवादका आधार व्यक्तिगत कल्याण है मिलके राजनीतिक आदर्शोंका समाज-वादके साथ पूरा-पूरा मेल बैठ जाता है (६:१२९)।'

मिलने जो कुछ भी लिखा है और कहा है उस सबका मुख्य लक्ष्य सामाजिक कल्याण और व्यक्तित्वको रक्षा है। उन्होंने अपनी पूरी ताकतसे विक्रम और उन्नति का समर्थन किया। उन्हें विश्वास था कि विवेकपूर्ण मानवी प्रयासोंसे मानव-जाति का सुधार व उत्थान हो सकता है। एक सच्चे उपयोगितावादीकी तरह उन्होंने सुख को ही मानव व्यवहारका अन्तिम लक्ष्य माना और उसी पर जोर दिया। साथ ही साथ वह स्वतन्त्रताको भी अत्यन्त आवश्यक मानते थे। जिस स्वतन्त्रताका वह इतना जोरदार समर्थन करते थे वह स्त्री-पुरुषोंकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता थी, वह गुटों और सूक्ष्म धारणाओं (abstractions) की स्वतन्त्रता नहीं थी। उनकी मुख्य विशेषता यह है कि वह सभी सामाजिक समस्याओं पर मनुष्यको सामने रखकर विचार करते थे। यद्यपि उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारोंमें बड़ी आसानीसे छिद्रान्वेषण किया जा सकता है, पर इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उनको विचार धारामें स्थायी महत्त्वकी बातें हैं। 'यही कारण है कि, यद्यपि उपयोगितावादी सिद्धान्तकी बहुत दिनोंसे निन्दा होती आई है, फिर भी उसमें स्थायित्वकी सम्भावना है (६:१२९)।'

अन्य उपयोगितावादी विचारकों पर विस्तारसे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। जॉन ओस्टिन (१७७०-१८५९) की सबसे बड़ी देन न्याय-शास्त्रकी दृष्टिमें विधि दर्शनका व्यापक विवेचन है। व्यावहारिक राजनीतिमें उन्हें लोकतन्त्रीय सरकारके प्रति कोई अधिक उत्साह नहीं था। वह पक्के रुढ़िवादी थे और १८५९ के मसदीय सुधारके विरोधी थे। जॉर्ज घोट (१७९४-१८७१) कट्टर बेन्थमवादी थे। वह व्यावहारिक राजनीतिज्ञ होनेके साथ ही राजनीतिक दार्शनिक भी थे। वह गुप्त मतदानके पक्षपाती थे। वह परिवर्धित मताधिकार (extended franchise) के उत्साही समर्थक थे (१३:२३८)।' प्रसिद्ध मनो-वैज्ञानिक अलेक्जेंडर बेन (१८१८-१९०३) ने उपयोगितावादी नीति-शास्त्रको एक वैज्ञानिक रूप दिया, जिसकी उसे आवश्यकता थी। उन्होंने 'अनुभव' (experience) को अपने साहचर्य-मूलक मनोविज्ञान (associationist psychology) का सवेत-सूत्र बना दिया।

अगर जिन आमूल परिवर्तनवादी उपयोगितावादियोंका विवेचन किया गया है उनके प्रति ब्रिटेन बहुत श्रेणी है। उन्नीसवीं शताब्दीके अधिकांशमें उनके विचारों का बोलवाला रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि व्यावहारिक राजनीति, सामाजिक सुधार और कल्याणकारी विधानमें जनताकी रुचि इतनी अधिक रही जिगकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गयी थी। उससे होने वाले लाभका आनन्द हम आज उठा रहे हैं। अपने मिष्ठान्तोंको उन्होंने जमजमः एक-एक कदम आगे बढ़ाया। प्रत्येक महान् विचारकने स्थायी महत्त्वकी कुछ न कुछ नयी बात जोड़ी। प्रगति उनका सवेत-सूत्र था और स्वतन्त्रता तथा जन-हितके लिए उनके उत्साहमें उन्हें आगे बढ़नेकी प्रेरणा और शक्ति मिलती थी। आधुनिक युगके लिए यही उनकी देन है। उन्होंने संसारको

कोई पूर्ण दार्शनिक पद्धति नहीं दी, पर वह कुछ ऐसे सुनिश्चित सिद्धान्त दे गये हैं जो परिणामोंकी कसौटी पर खरे उतरे हैं और जिनमें भविष्यमें कल्याणकारी प्रयोग किये जानेकी अपरिमित क्षमता अब भी है (१३: २४९-५०)।

‘अधिकतम सुखका सिद्धान्त’ निस्सन्देह निरर्थक है। पर उपयोगिता और उपयोगितावादके नाम पर बहुतसे कल्याणकारी काम किये जा चुके हैं। उन्नीसवीं सदीमें जो अंग्रेज नागरिक भारत आये थे उनमें से अधिकांशने सामाजिक सुधार और सामाजिक विधान का समर्थन किया था। ऐसा करनेमें वे लोग उपयोगितावाद के आदर्शोंसे ही प्रेरित थे। उन्होंने अनेक भारतीय सुधारकोंको भी प्रभावित किया था।

आज भी उपयोगितावाद या ‘अधिकतम सुखका सिद्धान्त’ बहुत कल्याण कर सकता है, बसने कि उसकी व्याख्या करनेमें और उसे कार्यान्वित करने में उसके शब्दों पर अत्यधिक जोर न दिया जाय। उपयोगितावाद और आदर्शवादका समन्वय किया जा सकता है, जैसा कि टी० एच० ग्रीन ने, राजनीति-शास्त्रके क्षेत्रमें, किया है। व्यावहारिक राजनीतिके क्षेत्रमें इस प्रकारका समन्वय मिथित अर्थ-व्यवस्था का और भारतमें कल्याणकारी-राज्यके आदर्शका प्रोत्थन कर सकता है।

SELECT READINGS

ALBEE, E.—*History of English Utilitarianism*.

BENTHAM, J.—*An Introduction to the Study of Morals and Legislation*
—*A Fragment on Government*.

BROWN, I.—*English Political Theory*—Chs. VIII and X.

DAVIDSON, W. L.—*Political Thought in England, The Utilitarians from Bentham to Mill*.

DUNNING, W. A.—*Political Theories, from Rousseau to Spencer*—
Ch. VI.

HALLOWELL—*Main Currents in Modern Political Thought*—Ch. 7.

JOAD, G. E. M.—*Guide to Philosophy of Morals and Politics*—
pp. 334-5.

MACCUNN, J.—*Six Radical Thinkers*—Chs. I-II.

MILL, J. S.—*Utilitarianism*.

POLLOCK, F.—*History of the Science of Politics*—pp. 98-III.

RITCHIE, D. G.—*Principles of State Interference*.

SETH, JAMES—*Ethical Principles*—Part I, Ch. I.

STEPHEN, LESLIE—*The English Utilitarians*.

WILLOUGHBY, W. W.—*Nature of the State*—Chs. IX and XI.

राजनीतिमें आदर्शवाद

(Idealism in Politics)

१. राजनीतिमें आदर्शवादकी सरम्परा (The Idealistic Tradition in Politics)

राज्यका आदर्शवादी सिद्धान्त अनेक नामोंसे प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसे परमवादी सिद्धान्त (absolutist theory), कुछ लोग इसे दार्शनिक सिद्धान्त (philosophical theory) और कुछ लोग इसे आध्यात्मिक सिद्धान्त (metaphysical theory) कहते हैं। मेकाइवर तो इसे 'रहस्यवादी' (mystical) सिद्धान्त तक कह डालते हैं। नाम चाहे जो कुछ हो पर आदर्शवादी परम्पराका एक लम्बा इतिहास है, यद्यपि इसकी शृंखला कभी-कभी टूटी हुई है। हमें इसकी पहली मूलक प्लेटो और अरस्तू की रचनाओंमें मिलती है। यह दोनों यूनानी विचारक, अपने अनेक समकालीन विचारकोंकी तरह, राज्यको स्वाभाविक और आवश्यक मानते थे। वह राज्यको सब कुछ मानते थे। उनका कहना था कि राज्यसे अलग रह कर मनुष्य अपनी चरमपूर्णताको नहीं प्राप्त कर सकता। अरस्तूका मत था कि राज्यका उद्देश्य तो मानव जीवनकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए ही हुआ था, पर उसका अस्तित्व नैतिक जीवनकी आवश्यकताओंके कारण बना रहा। प्लेटो और अरस्तू दोनों ही राज्यको उसके सर्वोच्च रूपमें एक नैतिक सस्या मानते थे। सच्चा राज्य एक सद्गुण सम्पन्न जीवनकी 'सामेदारी' थी।

राज्य पर इस प्रकार एक नैतिक दृष्टिमें विचार करने और नीतिशास्त्रके अनुसार राजनीतिक सिद्धान्तकी विवेचना करनेका, बादके आदर्शवादी विचारकों पर, बहुत प्रभाव पड़ा। यूनानी दार्शनिकोंका प्रभाव आपुनिक आदर्शवादियों पर एक और दृष्टिसे पड़ा है और वह है राज्य और समाज को करीब-करीब एक रूप मानना। यह प्रवृत्ति बॉसाके के विचारोंमें विशेष रूपसे दिखायी देती है। यूनानी चिन्तनका, विशेष कर प्लेटोके विचारोंका, तीसरा प्रभाव आदर्शवादियों पर यह पड़ा है कि वे राज्यको एक जैविक इकाई (organic unity) मानते हैं। आदर्शवादियोंका प्रस्थान-बिन्दु यह है कि राज्य एक केन्द्रीय सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तिको अपना उपयुक्त स्थान बनाना होता है। व्यक्तिका स्वयं अपने आपमें न कोई महत्व है न मूल्य। उसका जो कुछ भी महत्व है वह इसलिए है कि वह एक जैविक इकाईका अभिन्न अंग है। व्यक्ति और राज्यके बीचके ज़िम्मेदार विभेद (the sharp contrast

between the individual and the state) से आज हम इतना अधिक परिचित हैं वह यूनानियों की अज्ञात था। उनकी दृष्टि में नागरिकता का जीवन ही सामाजिक जीवन था और नागरिक-जीवन ही पूर्ण जीवन था। वह राज्य में अलग व्यक्तिको एक 'अनैतिक मूल्य भाव-मात्र' (unethical abstraction) मानते थे (७१. २८८)।

यूनानी युग में भी प्लेटो और अरस्तू के राज्य-सम्बन्धी महान् आदर्शों को सब लोग नहीं मानते थे। जैसा कि जेम्स सेठ कहते हैं, यूनानी नीति-शास्त्र "व्यक्तिवाद और विद्वत्-व्युत्पत्तिकी पुकार के माथ समाप्त होता है (७१. २८९)।" इनका आभास एथोक्रैटियन और स्टोइक-विचारों के उपदेशों में कमजोर मिलता है। मध्ययुग में जब नए राज्य को पद-व्युत्पत्ति करके उसका स्थान बहुत कुछ ग्रहण कर लिया और जब (धर्म-मय) तथा राज्य के अधिकार-क्षेत्र के बारे में विवाद चल पड़ा। इस युग में एक ओर तो धर्म-मय और राज्य में, और दूसरी ओर राजतन्त्र और सामन्तशाही के बीच संघर्ष चलता। ऐसी हालत में यूनानी चिन्तन के तत्त्वों को सफलता के अनुकूल वातावरण में मिल सका। इस प्रकार लगभग एक हजार वर्ष तक यूनानी राजनीतिक दर्शन प्रायः सुप्तावस्थामें रहा। पुनर्जागरण (renaissance) और सुधार (reformation) के बाल में लोगों की अभिरुचि फिर से यूनानी ज्ञान की ओर अग्रसर हुई। यूटोपिया (Utopia) नामक ग्रन्थ लिखने में सर थॉमस मूर पर प्लेटो की रचना 'रिपब्लिक' का काफी प्रभाव पड़ा। पर प्लेटो के जिन विचारों ने मूर को सबसे अधिक प्रभावित किया वह उनका साम्यवाद था न कि उनके आदर्शवादी उपदेश। व्यक्तिकी महत्ता के सुधारयुगीय सिद्धान्त ने व्यक्तिको एक नयी स्वाधीनता दी और व्यक्ति-व्युत्पत्तिकी लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह सिद्धान्त ही आधुनिक आदर्शवाद की आधारभूत है। सुधार-युग के बाद व्यक्तिवाद, राष्ट्रीयता, प्रतिपक्षिता और वाणिज्यवाद का जमाना आया। इनमें से अन्तिम दो का गठबन्धन हुआ जिससे पूँजी-वाद का बेरोकटोक प्रसार बढ़ा (६:२६)। इस युग में भी आदर्शवादी परम्परा बहुत मार्ग में बड़ सकी। राजाओं के दैवी अधिकार सिद्धान्त का काफी समय तक बोलबाला रहा इस प्रकार राज्य के दैवी अधिकार सम्बन्धी हीगेल के सिद्धान्त को पूर्व-व्युत्पत्ति दो शताब्दी पहले की जा चुकी थी।

आधुनिक विचार-धारा पर यूनानी राजनीतिक चिन्तन का स्थायी और निरन्तर प्रभाव रूसो के साथ आरम्भ होता है। इसलिए रूसो को यह श्रेय दिया जाना ठीक ही है कि रूसो ने पहले यूनानी दार्शनिकों द्वारा खोजे गये महान् मूल्यों को उन्होंने फिर से खोजकर हमारे सामने रखा।

रूसो के विचारों पर सबसे अधिक प्रभाव प्लेटो का पड़ा। प्लेटो की सहायता से ही रूसो अपने को सॉक्रेट्स के व्यक्तिवादी सिद्धान्त में मुक्त कर सामाजिक सन्धि (Social Contract) में निहित समष्टिवादी सिद्धान्त (collectivist theory) को अपना मने। अपनी युगान्तरकारी पुस्तक 'सामाजिक सन्धि' में रूसो ने राज्य की धारणा एक नैतिक प्राणी (moral organism) के रूप में की है और लोकसम्मति

का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उनकी रायमें राज्य मूलतः नागरिकोंके वैधिक अधिकारोंकी रक्षा करनेके लिए वैधिक संगठन नहीं है। तत्त्वतः राज्य एक नैतिक संगठन है जिसके सामान्य जीवन-यापनमें ही मनुष्य अपनी नैतिक पूर्णताको प्राप्त करता है। राज्यका सदस्य न रहनेसे व्यक्ति भूख और संकुचित जीवमात्र रह जाता है। राज्यकी सदस्यताके कारण ही वह 'एक समझदार और मानवी प्राणी बनता है'। राज्य मनुष्यकी नैसर्गिक प्रवृत्ति (instinct) के स्थान पर न्याय और भुधा (आकांक्षा) के स्थान पर विधिकी प्रतिष्ठा करता है। मनुष्यके कार्योंको वह ऐसी नैतिकता प्रदान करता है जो उन्हें पहले प्राप्त न थी। राज्यका प्रधान कर्त्तव्य अपने नागरिकोंको भौतिक परतन्त्रतासे मुक्त कर उनके लिए नैतिक स्वतन्त्रताका जीवन सम्भव बनाना है। राज्यको चाहिए कि वह मनुष्यको स्वतन्त्र बननेके लिए विवश करे। प्लेटो की तरह रूसो को भी राज्यसे तीव्र अनुराग था, पर राज्य सम्बन्धी उनकी धारणा कुछ मानोमें प्लेटो की धारणामें भिन्न थी। रूसो ने लोक-सम्मति (general will) के सिद्धान्तका और इस बातका प्रतिपादन किया कि इस सम्मतिके निर्माणमें हर व्यक्तिका भाग है।

रूसो के प्रगाढ़ उपदेशोंका प्रभाव काण्ट और अन्य समकालीन जर्मन दार्शनिकों के चिन्तन पर और उनके माध्यमसे अंग्रेज आदर्शवादियों पर पड़ा। उनकी विचार-धाराकी विस्तृत समीक्षा इसी अध्यायमें बादमें की जायगी। इस समय हम सामान्य आदर्शवादी धारणाका संक्षिप्त विवेचन करेंगे।

२. राज्यके आदर्शवादी सिद्धान्तकी व्याख्या

(Statement of the Idealistic Theory of the State)

आदर्शवादियोंका विश्वास है कि राज्य एक नैतिक संस्था है बोगा के (Bosanquet) के शब्दोंमें राज्य नैतिक विचारका मूर्त रूप है। समाजकी अन्य महत्वपूर्ण नैतिक संस्थाएँ परिवार और धर्म-संघ (church) हैं। इन सभी संस्थाओंमें राज्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक दृष्टिसे राज्यमें अन्य सब संस्थाएँ सम्मिलित हैं। संकुचित दृष्टिकोण से तो राज्य एक वैधिक संगठन जरूर है पर व्यापक दृष्टिकोणमें राज्य एक नैतिक संगठन है जो करोड़-करोड़ समाजके माथ एक रूप होना है। व्यक्तिके प्रति न्याय इस बातमें है कि समाजके जीवन और कार्य-व्यापारमें उसे अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त हो और उस स्थानसे सम्बद्ध कर्त्तव्योंको वह पूरा करे।

राज्यके बिना मानव व्यक्तित्वका पूरा विकास और उत्थान सम्भव नहीं है। मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है और राज्य नैतिक लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए समाजका प्रभावपूर्ण संगठन है। व्यक्ति और राज्यके उद्देश्योंमें कोई वास्तविक विरोध नहीं है। दोनोंका उद्देश्य व्यक्तित्वकी पूर्णता है। नैतिक दृष्टिमें राज्य स्वयं अपने आपमें उद्देश्य नहीं है। वह एक साधन है जिसके माध्यमसे लक्ष्य तब पहुँचा जा सकता है।

व्यक्ति ही नैतिक इकाई है। 'राज्य व्यक्तिके लिए है, व्यक्ति राज्यके लिए नहीं। राज्यका काम व्यक्तिका अवकमण करना नहीं है। राज्यका काम यह है कि वह व्यक्तिको उसके व्यक्तित्वके विनाशमें गिराकर पतुवाये और अपना विनाश करनेका उसे अवसर दे। राज्य व्यक्तिकी कार्य-क्षेत्र, उसके नैतिक जीवनका माध्यम है (७१: २९३)।'

इस दृष्टिमें राज्य व्यक्तिकी सबसे अच्छा मित्र है। मनुष्य और राज्यमें विरोध समझना एकदम गलत है। अराजकतावादी जो राज्यको शत प्रतिशत बुराई मानते हैं और व्यक्तिवादी जो राज्यको एक अनिवार्य बुराई मानते हैं, दोनों ही राज्यके सच्चे महत्त्वको नहीं समझे हैं। अराजकतावादका दुष्परिणाम है 'भीड़शाहीकी खराबियाँ (evils of mob rule) और आज दिन व्यक्तिवाद तो करीब-करीब हास्यास्पद हो चुका है (७१: २९३)। यह आदर्श कि हर व्यक्तिको अपने ही लिए जीनेका अधिकार मिलना चाहिए, एक अमम्भव और आत्मविरोधी आदर्श साबित हो चुका है। अनिवार्य व्यक्तिवादकी प्रतिप्रियाके फलस्वरूप ही समाजवाद और आदर्शवादका उदय हुआ है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, आदर्शवादके अनुसार व्यक्ति और राज्यके सच्चे हित एक ही हैं। दोनों ही का लक्ष्य है मनुष्यके व्यक्तित्वका पूर्ण और स्वतन्त्र विकास। आदर्शवादी इस पुरानी यूनानी धारणाको मानता है कि समाज व्यक्ति और व्यक्ति समाज पर निर्भर है। उसका विश्वास है कि 'राज्य व्यक्ति पर बाह्यले लादी गयी शक्ति नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूपमें राज्य और व्यक्ति एक रूप हैं (७१: २९२)।' इसलिए राज्यकी आज्ञाका पालन करना नागरिकके स्वयं अपने ही उत्तम अंगकी आज्ञाका पालन है।

यद्यपि व्यक्ति ही नैतिक इकाई है और राज्यका अस्तित्व व्यक्तिके लिए है फिर भी आदर्शवादियोंका विश्वास है कि राज्यकी अपनी इच्छा और अपना व्यक्तित्व है। उसका अतीत इतिहास, वर्तमान जीवन और उसकी भावी सम्भावनाएं हैं और इस प्रकार कुछ अर्थोंमें राज्य व्यक्तियोंमें भिन्न है यद्यपि उनको मिलाकर ही वह बनता है। उसके उद्देश्यमें निरन्तरता और लक्ष्यमें स्थिरता है। एक आदर्श राज्य, जिसमें व्यक्ति-मग्न इच्छा अपने पूर्ण रूपमें व्यक्त हुई हो, सभी कोई ऐसी इच्छा नहीं कर सकता जो उसके व्यक्तिगत सदस्योंके सर्वोच्च हितोंके विरुद्ध हो। आदर्शवादी इस बात से विचलित नहीं हो जाते कि ऐसे राज्यका कभी वही अस्तित्व नहीं रहा। वे उसे एक ऐसी लक्ष्य मानते हैं जिसके लिए सभी राज्योंको प्रयत्न करना चाहिए।

आदर्शवादियोंके अनुसार राज्यका आधार लोक इच्छा होती है, दबाव डालने वाली शक्ति नहीं। निस्सन्देह राज्य शक्तिका उपयोग करता है, पर शक्ति राज्यकी मुख्य विशेषता नहीं है। राज्य सामूहिक इच्छाका मूर्तरूप है। आदर्शवादियोंके अनुसार हमें राज्यका आदेश इसलिए मानना चाहिए कि हम यह अनुभव करते हैं कि इस आदेशपालन से एक ऐसे सार्वजनिक हितकी वृद्धि होती है, व्यक्तिकी हित जिसका एक अभिन्न अंग है। आदर्शवादियोंका विश्वास है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है

और उसके विवेकको लगातार उद्बुद्ध करने रहनेसे स्थायी कल्याण हो सकता है। उसे विचारोकी शक्ति पर विश्वास है।

सामान्यतः आधुनिक विचार और प्रयत्नोंकी प्रवृत्ति राज्यका प्रभावक्षेत्र घटानेकी ओर न होकर 'राज्यके सामाजीकरण अथवा समाजके राष्ट्रीयकरणकी ओर है (७१ : २९२)।' 'राज्यका सच्चा कर्तव्य यह है कि वह नागरिकके व्यक्तिगत जीवनको मुलझाये और उसे परिपूर्ण बनाये (७१ : २९४)।' व्यावहारिक भाषामें इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यको चाहिए कि वह सुन्दर जीवनके मार्गमें पड़ने-वाली बाधाओंको दूर करे। धर्म और नैतिकताको न तो राज्य बलपूर्वक लागू कर सक्ता है और न उसे लागू करना ही चाहिए। व्यक्तिका चरम उद्देश्य है व्यक्तित्वका विकास, जिसे आत्मानुभूति (self-realization) या आत्मलोप भी कहते हैं। राज्यको व्यक्तिके इस सबसे महान् उद्देश्यको निरन्तर अपने सम्मुख रखना चाहिए। निष्पक्षतामें सबके लिए समान अधिकार लागू करके उसे स्वतन्त्रताकी वह परिस्थितिया बनाये रखनी चाहिए जो मनुष्यके सुन्दर जीवनके लिए जरूरी हैं। और, जैसा पहले कहा गया है, अधिकार वह बाहरी परिस्थितिया हैं जो मनुष्यके आन्तरिक विकासके लिए आवश्यक हैं।

राज्यकी सेवा करनेसे हम अपने उच्चतम अंशके प्रति निष्ठाहीन नहीं हो जाते। हम दो स्वामियोंकी सेवा नहीं करते हमारी सेवाका अधिकारी तो केवल एक ही स्वामी होता है और वह नैतिक और वैयक्तिक आदर्श (१७ : २९४)।' राज्यसे विन्तुल अलग व्यक्तिको आदर्शवादी कोई महत्त्व नहीं देता। 'ऐसा व्यक्ति समाज-विरोधी और राज्य-विरोधी होता है (७१ : २९५), उसका जीवन बे-लगाव होता है (७१ : २९५)।' आदर्शवादी, व्यक्तिको 'सामाजिक और राजनीतिक तथा साथ ही वैयक्तिक मानता है (१७ : २९५)।' 'व्यक्तिको अन्य व्यक्तियोंसे पृथक् करने का अर्थ होगा उसके जीवनको कुण्ठित कर देना। यदि यह कहा जाय कि राज्य वैयक्तिक जीवनमें भी हस्तक्षेप करता है तो उसका स्पष्टीकरण यह है कि वह हस्तक्षेप केवल व्यक्तिके साथ होता है, उसकी अन्तरात्माके साथ नहीं और राज्यके इस हस्तक्षेप का उद्देश्य अन्तरात्माको दूम्मे व्यक्तियोंके हस्तक्षेपसे बचाना होता है। न तो राज्य और न व्यक्ति ही सर्वोच्च नैतिक उद्देश्य और इकाई है। यह उद्देश्य और इकाई तो मनुष्यको अन्तरात्मा है (७१ : २०१)।'।

साधारणतया व्यक्तिको राज्यकी आज्ञाका पालन करना चाहिए। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह राजनीतिक व्यवस्थाकी आलोचना नहीं कर सकता। व्यक्ति सम्प्रभु और प्रजा दोनों ही हैं। पर राज्य जब उसके व्यक्तित्वके क्षेत्रका अति-प्रमण करता है तब उसे अधिकार है कि वह राज्यके विरुद्ध विद्रोह कर दे। ऐसी अवस्थामें विद्रोह करना एक सार्वजनिक कर्तव्य हो जाता है। विद्रोहकी अवस्थामें भी व्यक्तिको यह याद रखना चाहिए कि वह अब भी उस सर्वोत्तम तत्त्वके प्रति एक निष्ठावान नागरिक है जिसके लिए राज्यका अस्तित्व है। जेम्स मैक का कहना है

कि निम्नलिखित दो स्थितियोंमें व्यक्तिवा विरोह करना उचित है - (क) जब राज्य एक व्यक्तिगत नागरिक अथवा एक व्यक्ति-समूहके रूपमें काम करने लगता है; (ख) जब लोकसम्मतिवा तत्कालीन स्वरूप इतना अनुपयुक्त हो जाता है कि उसके सुधारकी आवश्यकता होती है। [(a) when the State act as a private individual or a body of individuals, (b) when the present formulation of the general will becomes so inadequate as to require reformation.]

(क) ब्रिटेन और फ्रांस की क्रांतिवा पहली स्थिति के अच्छे उदाहरण हैं। उस समय 'बाल्जविक राज्य आदर्श' राज्यके प्रतिबुल हो गया था। राज्य व्यक्तित्वके उन्हीं अधिकारोंको समायोजन करनेकी कोशिश कर रहा था जिनका उसे सरलक बनना चाहिए था और जिसके सम्मुख अपनी मरझताका उत्तरदायित्व निद्व करना चाहिए था। इसलिए क्रांति निम्नन्देह एकदम उचित और व्यापपूर्ण थी। मन्त्रे सम्प्रभुकी राज्यकी किसी वस्तुको 'अपना निजी' नहीं समझना चाहिए। 'सार्वजनिक' कामोंमें उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जनताका हित ही उसका हित होना चाहिए और जनताकी इच्छा उसकी इच्छा। यदि वह इसके विरुद्ध चलता है, अपनी व्यक्तिगत इच्छा पर डोर देता है और नागरिकोंके हितोंको अपने व्यक्तिगत हितोंके अधीन बना देता है तो वह अपने ही कारणोंमें अपना मिहामन और अपनी सम्प्रभुता खो देता है। ऐसी हालतमें उस मन्त्रे की शक्तिको उपयोगमें लानेकी जरूरत होती है जो जनताके ही हाथोंमें होती है (७१-१०१)।

(ख) सुधार कानून (Reform Bills) के पहले ब्रिटेन की हालत उस अवस्था का अच्छा उदाहरण है जब लोक-सम्मतिके फिरे निदिधन किये जानेकी आवश्यकता थी। इन प्रकारकी स्थितियोंमें यह जरूरी नहीं है कि यह काम क्रांतिके द्वारा ही हो; सुधार ही पर्याप्त होता है। एक अच्छे राज्यमें जहां लोकमन गतिशील और प्रबुद्ध है, ऐसा सुधार निरन्तर होता रहता है।

आदर्शवादकी बहुत अधिक अनुचित आलोचनाकी गयी है। इसका कारण यह है कि जर्मन और अंग्रेज आदर्शवादियोंकी गिशाओं और वैयक्तिक आदर्शवादों विचारकोंकी गिशाओंके अन्तरको नहीं समझा गया। उदाहरणके लिए जोह महोदय सम्पूर्ण आदर्शवादी विचारधाराकी इस कारण निन्दा करते हैं कि होपेल ने उसका एक अनिवार्य रूप चित्रित किया है। ऐसा करना बिन्दुल अनुचित है।

३. टी० एच० ग्रीन एक गम्भीर आदर्शवादी

(T. H. Green as a Sober Idealist)

अब हम टी० एच० ग्रीन (१८३६-१८८२)की गिशाओंका विवेचन करेंगे। वह आदर्शवादियोंमें सर्वोत्तम थे। अर्नेस्ट बार्कर के शब्दोंमें वह एक उच्च आदर्शवादी और एक गम्भीर यथार्थवादी थे।

(१) ग्रीन के विचारों के स्रोत (Sources of Green's Thought).

ग्रीन के विचारों के स्रोत प्लेटो, अरस्तू, रुमो, काण्ट और हीगेल हैं। यूनानी दार्शनिकों से ग्रीन इस बात में सहमत हैं कि राज्य स्वाभाविक और आवश्यक है और व्यक्तिका जीवन समाज के जीवन का एक अभिन्न अंग है। पर वह जीवन के अभिजात-वर्गीय (aristocratic) यूनानी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। यूनानी विचारक आत्मतोष और आत्मनुभूतिका जीवन कुछ थोड़े ही व्यक्तियों के लिए सम्भव मानते थे। पर ग्रीन इस बारे में यह लोकनवीय दृष्टिकोण स्वीकार करते हैं कि नागरिका का जीवन उन सब व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो सार्वजनिक हित में विश्वास रखते हैं। जहाँ तक प्लेटो और अरस्तू के तुलनात्मक प्रभाव का सम्बन्ध है, ग्रीन पर प्लेटो की अपेक्षा अरस्तू का प्रभाव अधिक पड़ा है। अरस्तू की तरह ही ग्रीन अपने नीतिशास्त्र को राजनीति-शास्त्र से पूरा करते हैं। और विश्वास करते हैं कि राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य यह है कि वह अपने व्यक्तिगत सदस्यों के लिए एक ऐसे कल्याण की सिद्धि सम्भव बनाये जो सार्वजनिक कल्याण हो। ग्रीन अपने नीति-शास्त्र में 'आत्मतोष' या 'आत्मानुभूति' को आचरण का लक्ष्य बताते हैं, और अपने राजनीति-शास्त्र में सार्वजनिक कल्याण को वह हमेशा परम कल्याण कहते हैं। उनकी विचार-धारा में यह सभी शब्द एक दूसरे के साथ बदले-बदले जा सकते हैं।

काण्ट और हीगेल की भाँति ग्रीन भी रुमो की इस धारणा को मानते हैं कि 'नैतिक स्वाधीनता' मनुष्य का विशेष और अनुपम गुण है। वह मनुष्य की स्वाधीन इच्छा को मान लेते हैं यद्यपि यह स्वोक्ति-मीमित है। यह 'ऋणात्मक' और 'धनात्मक' स्वाधीनता में, सामान्य और विशिष्ट स्वाधीनता में, 'न्यायमूलक' स्वाधीनता तथा 'आध्यात्मिक' स्वाधीनता में और 'भौतिक' अह (ego) और 'शुद्ध' अह में अन्तर मानते हैं। इनमें से ऋणात्मक, सामान्य, (generic), न्याय-मूलक और भौतिक-स्वाधीनता का सीधा-सा अर्थ है, आत्मनिर्णय या अपनी वरीयत्व की भावना के अनुसार काम करना। [He assumes the free will of man—although within certain limits—and distinguishes between 'negative' and 'positive' freedom between freedom in the generic and freedom in the particular sense, between 'juristic' and 'spiritual' freedom and between the 'empirical' ego and the 'pure' ego. Freedom of the former kind—negative, generic, juristic, and empiric—means simply self-determination or acting on preference] इसका मतलब अपने मन की आज्ञा का अनुकरण करना भी हो सकता है। दूसरी कोटि की—अर्थात् धनात्मक, विशिष्ट, आध्यात्मिक और शुद्ध स्वाधीनता उद्देश्य होता है, तर्क या विवेक और इच्छा के लक्ष्यों का अधिकाधिक एकरूप होना। दूसरे शब्दों में स्वतंत्र कार्य विवेकशील कार्य होते हैं। जैसा कि रिपी कहते हैं, ग्रीन ने हीगेल के इस सिद्धान्त को कि राज्य का मुख्य स्वाधीनता ही है। इसी अर्थ में स्वीकार किया है।

मही अर्थोंमें स्वाधीनताका मतलब यह नहीं होना कि व्यक्तिको बिन्दुल अकेला स्वच्छन्द छोड़ दिया जाय। मनुष्य जिस मूलोपकी शोख करना है वह यदि मन्वा मूलोप नहीं है तो यह कहा जा सकता है कि उनकी इच्छा स्वतन्त्र नहीं है। ऐसी स्थितिमें नैतिक स्वाधीनता नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति दामनामें है। सच्चे सन्तोषको शान्ति या परमानन्दकी स्थिति कहा जा सकता है। यह मनकी वह स्थिति है जिसमें व्यक्तिकी सम्पूर्ण इच्छाकी पूर्ति हो चुकी होती है। वह किसी विगिष्ट इच्छाकी पूर्ति-भाष नहीं है। वह मनुष्यके मारे अहंकी स्वाभूति है। जैना काण्ड ने कहा है 'ऐसा व्यक्ति इसलिए स्वाधीन होना है कि वह जानता है कि जिस विधि-का वह पालन कर रहा है उसे अपने स्वयं बनाया है।' स्वाधीनताका अर्थ है विवेक-पूर्ण उद्देश्योंके लिए लोक इच्छाका निश्चयन (determination)—ऐसे उद्देश्योंके लिए जो विवेकपूर्ण आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें और पूर्णताके प्रयत्नोंकी सकल बनानेमें सहायक हो।

हीगेल की इस उक्ति को धीन ज्योंका त्यों स्वीकार नहीं करने कि राज्य स्वाधीनताकी प्राप्ति या स्वाधीनताका मूलरूप है। वह इस बातको स्वीकार करते हैं कि सम्पूर्ण व्यक्तिकी बचनमें जड़डनेके लिए नहीं होती, बल्कि वह नैतिक धारणाओं की पूर्णरूप होती है। छाप हो वह यह भी कहते हैं कि किसी भी राज्यको स्वाधीनता की पूर्ण प्राप्ति मानना विडम्बना है। आदर्श और यथार्थके बीच एक खाई रहती है और इसलिए राज्य स्वाधीनताकी जोनी-आगनी मूर्ति बनानेकी कागिदा भर कर सकता है। धीन हीगेल की इस उक्तिका समर्थन नहीं करते कि 'जो यथार्थ है वह तर्क-मंगन है और जो तर्क-मंगन है वह यथार्थ है।' प्रतिष्ठित नैतिकताका भी वह इनका ऊँचा स्थान नहीं देते। धीन यह स्वीकार करते हैं कि व्यक्तिके राजनीतिक विकासमें प्रतिष्ठित नैतिकताका बड़ा हाथ रहता है। पर विकासकी अल्पिम स्थिति सभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति पूर्णताके लिए शोख करना है। तभी वह वास्तवमें स्वतन्त्र हो पाता है।

धीन कई एक दृष्टियोंमें हीगेल के विचारोंमें दूर हो जाते हैं और काण्ड के विचारोंके समीप पहुँचते हैं; इसके उदाहरण हैं व्यक्तिगत स्वाधीनता, दुष्ट और अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता सम्बन्धी उनके विचार। इन सम्प्रदायोंके विवेचनमें यह हीगेल की अंगुष्ठा काण्ड के अधिक नजदीक है। काण्डकी भांति धीन का विश्वास है कि सद्-इच्छा ही एक मात्र अच्छी वस्तु है। स्वाधीनता ऋणान्तक नहीं है, वह घनात्मक है। राज्यके विरोधका औचित्य, प्रतिनिधित्व-शासनका महत्व, सविधानमें राजाका स्थान, दण्डको तर्क-मंगन आदि प्रश्नोंके बारेमें उनके विचार काण्ड और हीगेल दोनों ही जर्मन लेखकोंके विचारोंमें निग्रह हैं। पर माम ही यह राज्यके गौरवकी नैतिक महता पर जोर देने हैं और इस मानेमें वह हीगेल के अनुयायी हैं। पर राज्यके गौरवकी महता पर जोर देनेमें उन्होंने 'जनताकी स्वाधीनता' का बलिदान नहीं किया है।

(२) ग्रीनका राज्य-सिद्धांत. अर्नेस्ट वाकरका कहना है कि ग्रीन के राजनीतिक दर्शनको तीन परस्पर सम्बन्धित प्रमेयो (propositions) द्वारा व्यक्त किया जा सकता है : (१) मनुष्यकी चेतनामें स्वाधीनता पूर्वकल्पित है (human consciousness postulates liberty); (२) स्वाधीनतामें अधिकार निहित है; और (३) अधिकारोंके लिए राज्यकी आवश्यकता है।

ग्रीन की स्वाधीनता-सम्बन्धी धारणा पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं और अब दुबारा उस पर विचार करनेकी जरूरत नहीं है। इतना ही कहना काफी है कि स्वाधीनताके बारेमें ग्रीन का सिद्धान्त काण्ट का स्वतन्त्र नैतिक इच्छाका सिद्धान्त है जिसके बल पर मनुष्य हमेशा अपने आपको एक लक्ष्य माननेकी इच्छा करता है (३ : ३२)। ग्रीन का विश्वास है कि राज्य द्वारा व्यक्तिगत सदस्योंके लिए आत्मानुभूतिका जीवन सम्भव और सुगम बनानेका सर्वोत्तम साधन यह है कि राज्य व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष और सब पर एक समान लागू होने वाले अधिकारोंकी व्यवस्था करे। उनका कहना है कि अधिकार मनुष्यके आन्तरिक विकासके लिए आवश्यक बाहरी परिस्थितियाँ हैं। हर विवेकशील व्यक्तिका सबसे बड़ा अधिकार यह है कि वह वैसा बन सके जैसा मनुष्यको होना चाहिए, 'अपने अस्तित्वकी विधिको पूरा करते हुए उसे जो कुछ होना है' वह हो सके (२९.१७)। दूसरे सभी अधिकार इसी अधिकारसे प्राप्त होते हैं। समाजसे पूर्व अधिकारोंके अर्थमें प्राकृतिक अधिकारोंकी कल्पना अर्थहीन है; पर नैतिक अथवा आदर्श अधिकारोंके रूपमें प्राकृतिक अधिकार सारपूर्ण हैं। 'जिस उद्देश्यकी पूर्ति मानव-समाजका लक्ष्य है, उसके लिए ये अधिकार आवश्यक हैं (२९.३४)।' केवल वैधिक स्वीकृति ही अधिकारोंका आधार नहीं है। यह आधार सार्वजनिक नैतिक चेतना है। अधिकारोंका सम्बन्ध विधिमें न होकर नैतिकता से अधिक है। मनुष्यके नैतिक लक्ष्यकी सिद्धिके लिए अधिकार आवश्यक शर्तें हैं। अर्थात् अधिकारोंके बगैर मनुष्य अपने नैतिक लक्ष्यको प्राप्त नहीं कर सकता।

किसी भी व्यक्तिको कोई भी अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि वह समाजका एक सदस्य न हो और वह सदस्य ऐसे समाजका हो जिसके सदस्य सार्वजनिक कल्याणको आदर्श कल्याण मानते हों, ऐसा कल्याण 'जो उनमेंसे प्रत्येक व्यक्तिका कल्याण हो (२९.४४)।' इसका मतलब यह है कि अधिकार केवल ऐसे व्यक्तियोंके बीच हो सकते हैं जो नैतिक दृष्टिये मनुष्य हो (२९.४४)। एक सच्चा नैतिक मनुष्य अधिकारोंको पाकर सार्वजनिक कल्याणको अपना कल्याण मानता है। अधिकारोंका नियमन पारम्परिक स्वीकृतिमें होना चाहिए।

आदर्शवादी परम्पराके अनुसार ग्रीन राज्यकी प्राकृतिक और आवश्यक मानते हैं। यह एक नैतिक समस्या है जो व्यक्तिके नैतिक विभागके लिए जरूरी है। इसका मूल उद्देश्य अधिकारोंको लागू करना है, यदि आवश्यक हो तो बलका उपयोग करने भी। राज्यको शक्तिका उपयोग करनेका न्यायपूर्ण अधिकार है क्योंकि राज्य लोगोंकी सामान्य इच्छाकी अभिव्यक्ति करना है। ग्रीन सार्वजनिक उद्देश्यकी

लोकचेतनाको सामान्य इच्छा मानते हैं। 'शक्ति नहीं बरन् इच्छा ही राज्यका आधार है।'

घोनके अनुसार राज्य न तो परमपूर्ण है और न सर्वगन्तिमान। वह भीतर और बाहर दोनों ओरसे सीमित है। भीतरसे वह इस बानसे सीमित है कि विधि केवल बाहरी कामों और अभिप्रायोंमें ही सम्बन्ध रख सकती है, प्रेरक वृत्तियोंमें नहीं। इसलिए राज्य प्रत्यक्ष रूपमें अच्छे जीवनकी उत्पत्ति नहीं कर सकता। वह केवल अच्छे जीवनके मार्गकी बाधाओंको ही दूर कर सकता है। राज्य इस बानसे भी सीमित है कि कुछ साम्य परिस्थितियोंमें राज्यका प्रतिरोध करना व्यक्तिका कर्त्तव्य हो जाता है। घोन यह भी मानते हैं कि राज्यके भीतर विभिन्न स्थायी मणोंकी अपनी-अपनी अधिकार-व्यवस्था होती है और उनमें केवल समन्वय कायम करना ही राज्यका अधिकार होता है। जैसा जॉर्ज बर्कर कहते हैं: 'राज्य हर सचकी आन्तरिक अधिकार-व्यवस्थाका और साथ ही हर अधिकार-व्यवस्थाका क्षेत्र व्यवस्थाओंके साथ समायोजन करता है (३:४३)।' घोन का कहना है कि समायोजन स्थापित करनेके इस अधिकारके कारण ही राज्यको अन्तिम अधिकार-भक्ता प्राप्त है। बहुल-वादी मिदाल्लको पूरी तरहसे न अपनानेके कारण घोन की आलोचना मैकावर इन परिस्थितियोंमें व्यक्ति एक स्वतन्त्र नैतिक प्राणीके रूपमें कार्य कर सकता है, उन परिस्थितियोंको मुलम बनानेके लिए राज्य क्या कर सकता है और उसे क्या करना चाहिए। उनके चिन्तनके आधार-स्तम्भ राज्य और व्यक्ति ही बने रहते हैं। वह इस बात पर विचार नहीं करते कि राजनीतिक विधिमें मित्र अन्य साधनोंमें सम्पन्न जो दूसरे संप हैं उनके अस्तित्वका व्यक्ति और राज्य पर क्या प्रभाव पड़ना है। यदि उन्होंने इसका विचार किया होता तो उन्हें यह स्पष्ट हो गया होता कि प्रश्न केवल इसका हो नहीं है कि राज्यको क्या करना चाहिए, बल्कि प्रश्न यह भी है कि राज्यको क्या करनेकी अनुमति है; क्योंकि राज्य दूसरी शक्तियोंमें घिरा हुआ है, दूसरे किस्मके समूहोंमें सीमित है जो अपने हकमें अपने उद्देश्योंकी प्राप्ति कर रहे हैं। घोन सम्प्रभुताकी आधुनिक समस्याके शुरू के बिन्दु तक ही पहुँचकर—उसे छूकर ही रह जाते हैं, उसका हल नहीं दे पाते (४४:४९)।'

घोन के मतमें राज्य बाहरसे अन्तर्राष्ट्रीय विधिमें सीमित है। राष्ट्र की भांति घोन भी मानव जातिके विश्व बन्धुत्व पर विश्वास करते हैं और इस दृष्टिमें वह हीगेल से निम्न है। मानवकी तरह स्वतन्त्र जीवन बिगानेके मनुष्यके अधिकारोंमें मारी मानवताको एक माननेकी और मनुष्यको एक ही मनाजका सदस्य माननेकी धारणा निहित है।

(३) युद्ध. (२९), उपर्युक्त विचारोंके कारण युद्धके प्रति घोन का दृष्टिकोण हीगेल और उनके जर्मन निष्पक्षोंके दृष्टिकोणमें विन्तुल निम्न है। घोन का कहना है कि युद्ध कभी भी एक पूर्ण अधिकार नहीं है; अधिकसे अधिक वह एक मापेज

अधिकार है। वह मनुष्यके स्वाधीन जीवन बितानेके अधिकारका अतिक्रमण करता है। पहले की गमी एक बुराई या अपराधको ठीक करनेके लिए एक दूसरी बुराई अपराधके रूपमें युद्धका औचित्य माना जा सकता है अर्थात् युद्ध एक “निर्दय आवश्यकता” है। पर फिर भी है वह एक बुराई या अपराध ही। नैतिक दृष्टिसे युद्ध हत्या नहीं है। सैनिक हत्यारा नहीं है। यदि हम यह कहे कि युद्ध छेड़नेवाले हत्यारे हैं तो कठिनाई यह है कि हम पक्की तौर पर नहीं कह सकते कि युद्ध छेड़नेकी जिम्मेदारी किन-किन पर है।^१ यदि हम यह सच भी कर ले कि युद्धकी जिम्मेदारी किन-किन लोगों पर है तो भी यह इतने पक्के तौर पर सच नहीं हो सकता जितना व्यक्तिगत हत्याओंके मामलेमें होता है। उनके उद्देश्य चाहे जितने स्वार्थ पूर्ण रहे हो, पर न्यायपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि युद्धमें मारे जानेवाले व्यक्तियोंके प्रति उनके हृदयमें दुर्भावना थी।

फिर भी युद्ध एक नैतिक अपराध है। इस दलीलसे कि युद्धमें मारने वालोंका अभिप्राय किसी व्यक्ति विरोधकी हत्या करना नहीं होता, अधिकारका अतिक्रमण किसी प्रकार भी कम गम्भीर नहीं हो जाता। युद्धके कारण हुई मृत्युको किसी जगली जानवर द्वाराकी गयी हत्या या विजली गिरने जैसी दैवी आपत्ति द्वारा हुई मौतके समान नहीं कहा जा सकता। युद्धमें होनेवाली मौतें स्पष्टतः मनुष्य द्वारा होती हैं और जानबूझ कर की जाती हैं।

युद्धके समयमें एक दूसरी दलील यह दी जाती है कि सभ्य जातियोंके बीच होने वाले युद्धोंमें सैनिक स्वेच्छा-पूर्वक मौतका खतरा स्वीकार करते हैं और इसलिए, स्वतंत्र जीवनके अधिकारका अतिक्रमण नहीं होता। ग्रीन इस दलीलका खण्डन करते हैं। ग्रीन का कहना है कि व्यक्तिको इस बातका अधिकार नहीं है कि वह अपने जीवित रहनेके अधिकारको चाहे तो कायम रखे और चाहे छोड़ दे। (इसलिए आत्महत्या सब वही निन्दनीय मानी गयी है)। सेनामें चाहे लोग अपने मनमें भरती हुए हो या अनिवार्य भरतीके आधार पर भरती हुए हो, पर राज्य युद्धके द्वारा कुछ लोगों पर जीवनका खतरा उत्पन्न लादता है। युद्धका मतलब है, मानव जीवनका सहार जो मनुष्यों द्वारा जानबूझ कर किया जाता है।

कभी-कभी युद्धके समयमें युद्धके पक्षमें एक तीसरी दलील यह देते हैं कि पारिव्य जीवनके अधिकारका अतिक्रमण नैतिक-जीवनकी आवश्यकताओंमें उत्पन्न अधिकार द्वारा किया जा सकता है। दूसरे शब्दोंमें कभी-कभी यह कहा जाता है कि कुछ विरोध परिस्थितियोंमें युद्ध न करना युद्ध करनेसे भी बुरा होता है। ग्रीन इस तर्क पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि इस तर्क द्वारा केवल युद्धकी जिम्मेदारी उन लोगों पर लाद दी जाती है जो उन परिस्थितियोंके लिए जिम्मेदार

^१ द्वितीय विश्व-युद्ध समाप्त होनेके बाद विजयी मित्र राष्ट्रोंने युद्ध-अपराधियों पर मुकदमें चलाये और उन्हें दण्ड दिया है।

हैं। पर युद्ध तो फिर भी एक बंसी ही बुराई और अपराध बना रहता है। युद्धमें मानवजीवनका महार करना अपराध है, अपराध करने वाले चाहे जो भी हो।

कुछ लोग युद्धके समर्थनमें एक बोधी दलील यह देते हैं कि युद्धमें मनुष्यके कुछ खास गुणोंका विकास होता है जैसे वीरता और आत्मवर्तिदानका। यह कहा जाता है कि युद्धसे ही मनुष्यके नैतिक विकासके उपयुक्त सामाजिक परिस्थितियाँ बनायी रखी जा सकती हैं। इस प्रकार इन लोगोंका तर्क है कि युद्ध मानव-प्रगतिके लिए आवश्यक है। इस तर्कके बलको मानते हुए भी चीन का कहना है कि युद्धमें जीवनका सहार हमेशा एक अपराध है। फ्रांसमें सौजरके विजय अभिमानों और भारतमें अंग्रेजी युद्धके बाद अवश्य ही लाभदायक परिवर्तन हुए, पर चीन का कहना है कि यह परिवर्तन अन्य साधनोंसे भी लाये जा सकते हैं। युद्ध मनुष्यके अधिकारोंका अनिक्रमण करता है। यदि मनुष्यका अद्भुत कल्याण केवल युद्ध द्वारा होता हो तो इसका कारण मनुष्यकी दुष्टता ही है। चीन यह बात मानने को तैयार है कि युद्ध द्वारा मानव-जाति का कल्याण करनेकी इच्छा युद्धके अपराधको कम कर देती है, फिर भी युद्ध अपराध ही रहता है। वह कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि युद्धमें भाग लेने वाले अधिकांश लोग इन प्रवासनीय उद्देश्योंमें प्रेरित होकर युद्ध नहीं करते। बहुधा उनके उद्देश्य स्वार्थ पूर्ण होते हैं। मनुष्य जातिकी सामान्य स्वार्थ-परता ही युद्धका कारण है।

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका निचोड़ यह निकलता है कि यदि राज्य अपने विद्वान्तके प्रति सच्चा हैं तो वह दूसरे राज्योंके साथ संघर्ष करके मनुष्यके हितमें प्राप्त अधिकारोंका उत्सर्जन नहीं करेगा। राज्यकी पूर्ण उत्कृष्ट स्थितिमें युद्ध उभरा अनिवार्य उपकरण नहीं है। राज्यकी अपूर्ण स्थितिमें ही युद्ध उसका अनिवार्य उपकरण हो सकता है, पर जैसे-जैसे राज्य अधिकाधिक रूपमें पूर्ण होता जायगा जैसे-जैसे युद्धकी आवश्यकता कम होगी जायगी।

अब हम युद्धके भयभङ्गोंकी इस एक और दलीलको स्वीकार नहीं करते कि राज्योंके बीच सभ्य अनिवार्य है। एक राज्यको हानि वाले कामसे किन्हीं दूसरे राज्योंकी हानि होना जरूरी नहीं है। किसी निश्चित क्षेत्रमें रहने वाले सभी लोगोंको विकासका पूरा अवसर देनेका उद्देश्य जितना ही अधिक कोई राज्य पूरा करेगा उतना ही अधिक आसान यह काम दूसरे राज्योंके लिए होगा जायगा। और जितनी मात्रामें सभी राज्य इस उद्देश्यकी पूर्ति करेंगे उन्हींके अनुपातमें सभ्यका स्वरा मयाप्त होगा जायगा। युद्ध इसलिए नहीं होता कि राज्योंका अस्तित्व है, बल्कि इसलिए कि सार्वजनिक अधिकारोंके सम्मूलन और संरक्षणका वर्तमान राज्य पूरा नहीं करने। इस प्रकार चीन इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि युद्ध कर मनुष्य जातिके प्रति अपराध करना किसी भी राज्यके लिए राज्यके नाते किसी भी हालतमें उचित नहीं ठहराया जा सकता। भले

ही कुछ विशेष परिस्थितियोंमें युद्ध करना किसी राज्य विशेषके लिए कुछ अशो-
तक उचित हो। युद्धको इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा-सकता कि वह-
राज्योंके अस्तित्वका आवश्यक परिणाम है। इस दावेका कोई भी आधार नहीं
है कि किसी राज्यको वह काम करनेका अधिकार है जो वह अपने स्वार्थोंकी सिद्धिके
लिए आवश्यक समझता है और वह भी इस बातकी परवाह किये बिना कि दूसरे
लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। युद्ध, अपने सर्वोत्तम रूपमें भी, केवल एक
आपेक्षिक अधिकार है।

युद्धके समर्थनमें छठा और अन्तिम तर्क यह है कि ग्रीनका विद्व-अन्वित-
वाला दृष्टिकोण देश प्रेम और राष्ट्रीय जीवनको नष्ट कर देगा और एक विद्व-
व्यापी साम्राज्यको आवश्यक बना देगा। इस तर्कका उत्तर ग्रीन यह देते हैं-कि
शुद्ध जनभावनाको राष्ट्रीय होना ही चाहिए, पर जितना ही अधिक कोई जाति-
एक सच्चे राज्यका रूप धारण करती है उतने ही अधिक मार्ग उसकी
राष्ट्रीय भावनाकी अभिव्यक्तिके लिए मिलते हैं और ये मार्ग अन्य जातियों-के
साथ सघर्षसे भिन्न दूसरे मार्ग होते हैं। यह कहना बिल्कुल भूलंतापूर्ण है कि दूसरी
जातियोंकी अपेक्षा अपनी जातिको अधिक प्रबल सैनिक शक्तिके रूपमें देखने
की इच्छा ही देश-भक्तिकका मज्जा स्वरूप है। जिस हद तक प्रत्येक राष्ट्रके भीतर
अधिकारोंकी पूर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है, उसी हद तक राष्ट्रोंके बीच
सघर्षके अवसर कम होते जाते हैं।

ग्रीन यह मानते हैं कि राष्ट्रीयता एक अच्छी चीज है। उनका विश्वास है कि
जीवन और जीवनके कार्य-व्यापार पर अधिकार प्राप्त करनेके लिए यह जरूरी है-
कि मानव-जातिके प्रेमको किसी भूलण्ड जाति या राष्ट्र विशेषमें निरिष्ट-
(particularized) किया जाय। पर इस बातका कोई कारण नहीं मालूम होता-
कि यह स्थानीय या राष्ट्रीय-प्रेम दूसरी जातियोंके प्रति द्वेषमें या उनसे स्वयं या अपने
प्रतिनिधियोंके द्वारा युद्ध करनेकी इच्छामें बदल जाय। जिस हद तक राज्योंका
गठन ठीक प्रकार हो जाता है, उस हद तक देश-भक्तिको सैनिक रूप धारण
करनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। देशभक्तिको सैनिकवाद समझना उस
युगका अवशेष है जब राज्योंका गठन पूर्ण नहीं था। देशभक्ति और सैनिकवाद
किसी प्रकार भी एक नहीं है। स्यामी मेनाए इस बातका मबूत है कि मानव-जातिका
राजनीतिक-जीवन अभी पूर्णरूपेण व्यवस्थित नहीं है। ये सनाए राज्योंकी-
किसी एक व्यवस्थाके विकसमके कारण नहीं हैं बल्कि उन परिस्थितियोंके-कारण-
हैं जो उस व्यवस्थाकी चूटियोंको प्रकट करती हैं।

हमने ग्रीन द्वारा युद्धकी की गयी आलोचनाका विस्तारमें वर्णन इसलिए किया
है कि यह आलोचना 'उनके भाषणके सर्वोत्तम अंशोंमें से एक है' (३:४६)। और
हीगेलके साथ उनके विभेदको स्पष्ट करती है जिनका कहना था कि 'युद्धकी स्थिति
राज्यके व्यक्तित्वकी सर्वशक्तिमत्ताको प्रकट करती है।'

(४) राज्यका कार्य (State Action). जैसा पहले कहा जा चुका है, ग्रीनने राज्यके कार्योंको धारणा नकारात्मक रूपमें की है। सुन्दर जीवन अधिकांश स्वतः अर्जित जीवन होता है। राज्य प्रत्यक्ष रूपमें उसकी उन्नति नहीं कर सकता। राज्य केवल यह कर सकता है और यही उसे करना चाहिए कि करने योग्य कामोंके करनेमें मनुष्यके मार्गमें जो बाधाएँ आती हों उनको दूर करे। अच्छा काम तभी अच्छा होता है जब वह अपने मनमें एक निरपेक्ष उद्देश्यसे किया जाय। दबावके कारण किये गये कार्योंका नैतिक महत्त्व नष्ट हो जाता है। इसलिए राज्यको केवल यह करना चाहिए कि वह ऐसे कार्योंको करावे जिनका किया जाना समाजके भीतर सुन्दर जीवनके लिए आवश्यक हो, वह कार्य चाहे जिस प्रेरक वृत्तिसे किये जायें।

अपने समयकी व्यावहारिक परिस्थितियों पर इतना सिद्धान्त लागू करते हुए ग्रीन अमान, नशाखोरी, और भिक्षावृत्तिको मानव-शक्तिकी पूर्ण अभिव्यक्तिमें बाधक मानते हैं। इन बाधाओंको दूर करनेके लिए वह काफ़ी बड़े क्षेत्रमें राज्यके सक्रिय होनेका समर्थन करते हैं। प्राकृतिक अधिकारी या निहित स्वार्थों पर आधारित तर्कोंके फलस्वरूप ग्रीन अपनी विचारधारासे विचलित नहीं होते। और न वह इन सिद्धान्त पर आधारित तर्कमें विचलित होते हैं कि मनुष्यकी स्वतंत्र इच्छाको इस बातका पूरा अवसर मिलना चाहिए कि वह 'निरक्षरता, नशाखोरी और दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर, अपना छुटकारा करले (२ : ११)।' ग्रीन यह समझते हैं कि स्वतंत्र इच्छा जीवनकी बाहरी परिस्थितियोंमें मुक्त या उनके ऊपर नहीं है; और इसलिए स्वतंत्र इच्छा अपनी स्वतंत्रताका उपयोग तभी कर सकती है जब इन परिस्थितियोंकी मनुष्यव्यवस्था हो जाय। इस धारणा पर जोर देनेकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आदर्शवादकी कभी-कभी यह आलोचना होती है कि वह दक्षिणपूर्व रुढ़िवाद (hide-bound conservatism) का औचित्य सिद्ध करनेकी एक आढम्बरपूर्ण चेष्टा है। मेबाइन लिखते हैं: "ग्रीन ने उदारवादी सिद्धान्तमें यह बड़ाया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उत्तरदायित्वके लिए आवश्यक है कि पहले सामूहिक-वस्थापन का कार्य हो।

ग्रीन द्वारा दिये गये उदाहरणमें अनिवार्य शिक्षा माता-पिता पर बच्चेके वस्थापनके लिए दबाव डालती है। मध्य-निरपेक्षमें हर व्यक्ति और सब व्यक्तियों पर, हर व्यक्ति और सब व्यक्तियोंके वस्थापनके लिए, दबाव डाला जाता है।

(५) दण्ड (Punishment). दण्डके बारेमें ग्रीन की विवेचना उनके राज्य कार्य सिद्धान्तका एक अभिन्न अंग है। अपराधोंकी इच्छा, जो समाज-विरोधी है, स्वतंत्रता विरोधी शक्ति है। ऐसी हालतमें दण्ड उस समाज-विरोधी शक्तिका विरोध करने-वाली शक्ति है। दण्डका सम्बन्ध अपराधीके किसी पिछले नैतिक अपराधमें नहीं होता और न उसका सम्बन्ध उसके भावी नैतिक सुधारसे होता है (३ : ४८)। दण्डकी नाप-तोल नैतिक अपराधके अनुसार करना अमम्भव है।

राज्य न तो दण्ड द्वारा होने वाले कष्टकी नाप-जोख और न अपराधके नैतिक दोषकी नाप-जोख कर सकता है। यदि राज्यके लिए यह सम्भव भी हो कि वह दण्डमें होने वाले क्लेश, और अपराधकी अनैतिक दुष्टताके बीच अनुपात तय कर सके तो हर अपराधके लिए भिन्न प्रकारका दण्ड देना होगा। इसका मतलब होगा दण्ड सम्बन्धी सभी सामान्य नियमोंका अन्त। इसके अतिरिक्त दण्ड और नैतिक अपराधके बीच अनुपात तय करनेका मतलब यह है कि राज्यका काम अपराधकी अपराधके जोते दण्डित करना है। ग्रीनका विचार है कि यह राज्यका कार्य नहीं है। यदि राज्य अनैतिकता (गुद) को ही दण्डित करने लगे तो उसमें निरपेक्ष नैतिक प्रयत्न पर रोक लग जायगी। अपराधके लिए दण्ड 'न तो अपराधमें छिपी हुई तथा-कथित अनैतिक दुष्टताके अनुरूप होता है, न हो सकता है और न होना चाहिए' (३ : १९२)।

इसी प्रकार दण्डका मुख्य उद्देश्य अपराधीका नैतिक सुधार करना नहीं है। सभी सच्चे सुधार मनुष्यकी अन्तरात्मामें ही होने हैं। अतः भारीमे भारी दण्ड अपराधीकी इच्छाके विरुद्ध उमका सुधार नहीं कर सकता। राज्य अधिकसे अधिक यही कर सकता है कि वह अपराधीकी सुधारकी इच्छाको फिरसे जागृत कर दे। वास्तवमें दण्ड इसलिए दिया जाता है कि इच्छाके स्वतंत्र रूपसे कार्य करनेके लिए जिन बाहरी परिस्थितियोंकी जरूरत होती है वे बनी रहें। आन्तरिक इच्छाके साथ दण्डका कोई मेल नहीं बिठाया जाता (३ : ४९)। दण्डका अन्तिम उद्देश्य यह है कि 'ममात्रके हर सदस्यकी नैतिक इच्छाके लिए, काम करनेकी स्वाधीनता सुरक्षित रहे' (३ : ४९)। इसका मतलब यह है कि अपराधी द्वारा जिन अधिकारोंकी उल्लंघन किया गया हो उसकी मरहताके अनुसार अपराधीको दण्ड दिया जाता चाहिए। अपराधके रूपमें दण्ड अपनी दुरासह पूर्ण इच्छाका सुधार करनेके लिए अपराधीको प्रेरित कर सकता है। 'पर इस दृष्टिमें भी दण्ड केवल 'बाधाओंको दूर करना' ही है, क्योंकि जिन बाधाओंको विरोध अपराधी करता है वह केवल बल ही नहीं, बल्कि एक इच्छा है' (३ : ५०)।

ग्रीन इस नीति पर पहुँचते हैं कि दण्डका मूल उद्देश्य 'अपराधीको बलेरी पहुँचानेके लिए ही दण्ड देना नहीं है, अपराधीको दुबारा अपराध करनेसे रोकना भी मुख्य उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य है अपराधके बारेमें ऐसे लोगोंके दिमागोंमें भय पैदा कर देना जिनमें ऐसा अपराध करनेकी प्रवृत्ति हो' (३ : १९२)। इसका मतलब यह हुआ कि दण्डका प्रयत्न उद्देश्य, भविष्यमें अपराधको-रोकना है। इस उद्देश्यकी सिद्धि का मापन है जनताके दिमागमें अपराधके बारेमें इतना भय भर देना जितना अपराधका निवारण करनेके लिए जरूरी हो।

(६) सम्पत्ति (Property). अन्य अनेक प्रश्नोंकी तरह सम्पत्तिके प्रश्न पर भी ग्रीन अपने समयकी अपेक्षा अधिक उदारवादी हैं। वह व्यक्तिगत सम्पत्ति का न तो हर पहलूमें समर्थन करते हैं और न उसकी शुरूसे आखिर तक

आलोचना ही करते हैं। इस प्रकार आधुनिक भाषामें न तो बहु-व्यक्तिवादी हैं और न समाजवादी। वह आमतौर पर सम्पत्तिका समर्थन इन-आधार पर-करने हैं कि मनुष्यके व्यक्तित्वकी अभिव्यक्तिके लिए सम्पत्ति अनिवार्य है। सम्पत्ति मनुष्यके स्वाधीन जीवनके अधिकारका सहज परिणामी (corollary) है। उनका कहना है कि हर व्यक्तिको सम्पत्ति पैदा करनेका मौका मिलना चाहिए क्योंकि हर-व्यक्तिमें सामान्य सामाजिक कल्याणमें भाग लेनेकी शक्ति होती है। चूंकि व्यक्तियोंमें यह सान्ध्य एक-भी नहीं होती, इसलिए सम्पत्ति भी असमान होनी चाहिए। विभिन्न व्यक्तियोंको पूरे समाजके जीवनमें विभिन्न कर्तव्य पूरे करने होते हैं और सम्पत्तिकी असमानता इसकी एक आवश्यक शर्त है। पर जब कुछ लोग सम्पत्तिका संग्रह इस ढंगसे करे कि दूसरे लोगोंकी इच्छाओंकी पूर्तिमें गम्भीर रूपसे बाधा पड़ती हो तब राज्यको दखल देना चाहिए और अवस्था सुधारनी चाहिए। इन आधार पर ग्रीन व्यक्तिगत भू-सम्पत्तिका सीमा-बन्धन उचित मानते हैं और पारिवारिक व्यवस्थाओं (family settlements) का विरोध करते हैं। धीनका आदर्श है, छोटे-छोटे भू-स्वामियोंका वर्ग जो अपने खेत स्वयं जोतते हो। राज्यको अनुशासित वृद्धिको अपने काममें नहीं लाना चाहिए (The State is not to appropriate unearned increment)। ग्रीन उत्तराधिकार और व्यापारकी स्वाधीनताका समर्थन करते हैं।

(७) प्रतिनिधि-सरकार और व्यावहारिक राजनीति. काण्ट और हीगेलके विपरीत, ग्रीन प्रतिनिधि-सरकारमें पक्का विश्वास रखते थे और व्यापक मताधिकारके समर्थक थे। राजनीतिमें वह एक सक्रिय उदारवादी थे, केवल शास्त्रीय पश्चित नहीं। 'मध्य वर्ग और अल्पसंख्यक धर्मावलम्बियोंके प्रति उनका हमेशा सक्रिय सहानुभूति रही। इनके अलावा उन्हें शिक्षा और दुराचारियोंके सुधार (licensing reform) में बहुत अधिक रुचि थी.....। ऑक्सफोर्डकी राजनीतिमें उन्होंने ऐसा भाग लिया था कि उनका नाम विश्वविद्यालयमें अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। राष्ट्रीय राजनीतिमें वह जोन बाण्डकी विचारधारा के उदारवादी थे। १८६७ के बाद वह राजनीतिमें बराबर भाग लेने रहे (३: २१)।'

(८) आलोचना और मूल्यांकन (Criticism and Appreciation). आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाने वालोंमें धीन सबसे अधिक गम्भीर मान्य पड़ते हैं। विस्तारमें जाने पर धीनमें हानाए मतभेद होता है पर सामान्य रूपमें उनके सिद्धान्त आज भी गंरे हैं। सम्भव है, पूँजी-मूलक सम्पत्तिका समर्थन राज्य द्वारा अनुशासित वृद्धि का अपने काममें लाये जानेका विरोध तथा दण्डके निरोधक (deterrent) सिद्धान्त पर उनका जोर देना हमें आज उचित न मान्य हो। 'पर किन्हीं विशेष परिस्थितियोंका जो विस्तृत उन्हीं विद्याया विनी नीति विशेषके जो सुझाव उन्होंने दिये, उन सबकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण वे सिद्धान्त हैं जिनकी स्थापना उन्होंने की। यदि उनके सिद्धान्त सत्य हैं तो हर युग अपनी आवश्यकताओंके अनुसार

उनकी प्रगतिशील ध्यास्या कर सकता है।' व्यक्तिके महत्त्व पर उनका दृष्टि विश्वास, व्यक्तिकी स्वाधीनता पर उनकी गहरी आस्था, उनका यह विश्वास कि व्यक्तिकी कल्याण सामाजिक-कल्याणका एक अभिन्न अंग है, राज्यको रहस्यमयी उच्चता पर पदासीन करनेमें उनकी अस्वीकृति, विश्व-बन्धुत्व और अन्तर्राष्ट्रीय विधिकी स्वीकृति, नैतिक कृत्योकी आत्मप्रेरणाको जीवित रखनेके लिए राज्यकी शक्तिका परिसीमन करनेकी उनकी उत्सुकता, अधिकारों पर जोर देना, उनका यह विचार कि सम्पत्ति व्यक्तित्वकी अभिव्यक्तिका एक माधन है और उनका यह स्वीकार करना कि अतिवादी परिस्थितियोंमें व्यक्तिको प्रतिरोधका अधिकार है— यह सब आज भी उतना ही ठीक है जितना उस समय था जब प्रीतने अपने भाषण दिए थे (१८७९-८०)।

राज्यकी आदर्शवादी व्याख्याकी अनेक और विभिन्न आलोचनाएं की गयी हैं। यद्यपि उनमें से अनेक आलोचनाओंमें सचाई है फिर भी हमारा विश्वास है कि आदर्शवाद इन आलोचनाओंके बावजूद अपनेको कायम रख सकता है।

आदर्शवाद : आलोचना और समर्थन. (१) आदर्शवादके आलोचकोंका कहना है कि यह एक भाव-मूढम और आध्यात्मिक सिद्धान्त है और जीवनकी वास्तविकताओंका विवेचन नहीं करता। आलोचकोंका कहना है कि आदर्शवाद की धारणाएं जीवनकी वास्तविक परिस्थितियोंसे बहुत दूर हैं। उदाहरणार्थ विलियम जेम्स आदर्शवादी सिद्धान्तको एक ऐसा बुद्धिवादी दसन कहते हैं 'जो अपनेको धार्मिक कह सकता है पर जो ठोस सत्यो, गुणों और दुखोंके निश्चित सम्पर्कसे विल्कुल अलग रहता है। यह एक शुद्ध बौद्धिक सिद्धान्त है।' आदर्शवाद व्यक्तिको 'केवल एक विवेकशील प्राणी मानता है और मानव-स्वभावके दूसरे पहलुओं पर कोई ध्यान नहीं देता। आदर्शवाद द्वारा, राज्यको केवल चेतन विवेक (conscious reason) या इच्छा बताया गया है, और आदत, अनुकरण-भावना तथा आवेग आदि तत्वोंकी विल्कुल ही अवहेलनाकी गयी है।

यह सही है कि आदर्शवाद विचारोंकी प्रकृतिको बहुत ऊँचा स्थान देता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह केवल ग्राम पर ही आधारित है। मनुष्यकी बुद्धिको अस्वीकार करके केवल उसके आवेगों और तात्कालिक अनुभवोंका सहारा लेना, जैसा कि कुछ आधुनिक लेखक करते हैं, मनुष्यको नीची श्रेणीके प्राणियोंकी श्रेणीमें गिरा देता है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि हमारे सामाजिक हितों और हमारी सामाजिक भावनाओं तथा अभिरूचियोंका उद्गम आदिम प्रेरणाओं तक श्रोजा जाय। पर वहीं पर रुक जाना एक ऐसी नींव रखना है जिस पर कोई दीर्घकाल न उठाया जाय। निम्न-देह मनुष्यके महान् सामाजिक प्रयत्नोंकी आधुनिक मनोवैज्ञानिक विवेचनामें बहुत कुछ प्रशमनीय है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हम विवेककी निम्नाजलि देकर मोतह आने भावनाओं और आवेगोंके अधीन होनेकी तैयार हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि विनाश क्रममें जो उच्चतर (नरें या

विवेक) है उसीको निम्नतरकी ध्यास्या करनी चाहिए, न कि उल्टा ही। व्यवस्थित विचारोंकी शक्तिको अस्वीकार करके मनोवैज्ञानिक हमें एक विचित्र 'अज्ञेयतावाद (agnosticism)' की ओर ले जाता है। उसकी स्थिति तुरन्त निराशावादी हो जाती है।

हम स्वीकार करते हैं कि आदर्शवादियोंके मिद्धान्तका अधिकतर अंश भाव-मूढम और आध्यात्मिक है। वह व्यावहारिक तत्त्वोंकी एक भैदान्तिक आधार प्रदान करता है। राजनीति-शास्त्र एक आदर्श-मूलक विज्ञान है और इसलिए यदि वह हमें आदर्शनीतियां और आदर्श मानदण्ड नहीं देता तो अपने कर्तव्यको पूरा नहीं करता। वह केवल एक वर्णनात्मक विज्ञान नहीं है। इस बारेमें मार्नर लिखते हैं: 'नीतिशास्त्रकी तरह राजनीति-शास्त्र भी इस प्रश्न पर विचार करता है कि क्या होता है और क्या होना चाहिए। किसी वस्तुका जमनी स्वरूप तो वह है जो उसके पूर्ण विचारमके बाद होता है, इसलिए राजनीतिशास्त्र दार्शनिक राज्यके आदर्श रूप पर भली प्रकार प्रकाश डालकर उसकी काल्पनिक महिमा और पूर्णताकी विवेचना कर सचता है (२३:२३८)।' तथाकथित यथार्थवादी बहुधा अपने सङ्कुचित दायरेके बाहर देख नहीं पाता। आदर्शवाद आलोचक चर्तमान अपूर्ण राज्य पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। आदर्शवादियों इतना विश्वास और इनकी कल्पना-शक्ति होनी है कि वह भविष्यमें एक आदर्श राज्यकी आशा करता है। उसका आदर्श जब आदर्श न होकर सजीव, सक्रिय आदर्श है और उसमें परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल बननेकी क्षमता है। 'विचारोंके हाथ-पैर होते हैं।' उनमें जीवन होता है, प्राण-शक्ति होनी है।

यथार्थवादी अधिकतर केवल आदर्शवादीकी आलोचना ही करता है। उसकी रचनात्मक देन बहुत कम है। एक राजनीतिक दार्शनिकका काम केवल यह बतलाना नहीं है कि व्यवस्थित समाजके सदस्योंके रूपमें मनुष्य एक दूसरेके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसे यह भी बतलाना चाहिए कि उन्हें किस प्रकारका व्यवहार करना चाहिए। यथार्थवादियोंकी आलोचना करते हुए हेनरी जोन्स (Henry Jones) टीका ही कहते हैं, 'वे अपना कोई मिद्धान्त नहीं प्रतिष्ठित करते। वे केवल आदर्शवादमें बुद्धियां और कमियां गिनाकर और यह दिखाकर कि आदर्शवाद ने कौन-कौन समझाए हुए नहीं हैं—जो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है—अपनी डावाडोल स्थिति बनाये रहते हैं (४२:१३)।'।

आदर्शवादी जब यह कहता है कि राज्य विवेक और तर्कपूर्ण इच्छाकी उत्पत्ति है तब वह यह दावा नहीं करता कि राजनीतिक जीवन और राजनीतिक मण्डाए भावधानीगत सोच-विचार पर बनती हैं। उनके कहनेका मतलब केवल इतना है कि 'युगोंमें होने वाले विकासको देखते हुए यह स्पष्ट है कि मनुष्यका विवेक सदा सक्रिय रहा है, भले ही वह अल्पप्रभ और गिरे हुए रूपमें सक्रिय रहा हो।' 'यदि विवेक सक्रिय न रहा होता तो विकासका अल्प मण्डित जीवनकी एक तर्क संगत

व्यवस्थाके स्थान पर स्वाभाविक प्रेरणाओं, आदेशों और नियमोंका एक ऐसा गड़बड़-घोटाला सम्मिश्रण तैयार हुआ होता जिसका न कोई अर्थ होता, न कोई सम्बन्ध होता और न कोई कारण होता (३ : ८३)।

आदर्शवादी यह स्वीकार करता है कि विभिन्न दिशाओंमें इतनी अधिक प्रगति कर लेनेके बाद आज भी मनुष्य अपने काम बहुधा चैतन्य विवेक द्वारा प्रेरित होकर नहीं करता। उसके काम बहुधा आदतवश या अनायास किये जाते हैं। फिर भी आदर्शवादीका कहना है कि तर्क-बुद्धि द्वारा इन कामोंकी व्याख्या की जा सकती है। आदर्शवादी चाहता है कि आदत और अनुकरणको विवेकका सहायक बनाया जाय, क्योंकि वे विवेकके दास हैं, उसके स्वाधी नहीं।

(२) जो लोग राज्यके जीवनकी विवेचना करनेमें विवेक और इच्छा के महत्वको स्वीकार करते हैं वे कभी-कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि आदर्शवाद वास्तविक तत्वोंकी ही आदर्श मान लेनेकी भूल करता है। आदर्शोंको प्राप्त करनेके बजाय वह यमार्थोंकी ही आदर्श मान बैठता है। रुसो और हीगेलमें यह प्रवृत्ति विशेष तीव्रसे पायी जाती है। होब्सन तो आदर्शवादको “रूढ़िवादिका एक चाल (the tactics of conservatism)” तक बताते हैं। समाज-सुधारक हमने हताश होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आदर्शवाद जो जिस रूपमें है उसीके देवी अधिकारका उपदेश देना मालूम पड़ता है।

यह आलोचना बहुत गलत नहीं है। अरस्तू दास-श्रमिकोंको आदर्श बताते हैं, हीगेल युद्धको गौरव प्रदान करते हैं और ग्रीन अपनी उदार प्रवृत्तियोंके साथ पूँजीके व्यक्तिगत स्वामित्वका मेल बिठाते हैं। हमारा केवल यह कहना है कि आदर्शवाद और रूढ़िवाद (conservatism) में कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं है। आदर्शवादके आधार पर एक क्रान्तिकारी सामाजिक सुधार योजनाका समर्थन भी उसी प्रकार किया जा सकता है जिन प्रकार रूढ़िवादका। ‘सुन्दर जीवनकी बाधाओंको दूर करना’ एक इतना व्यापक उद्देश्य है कि उसमें राज्यका विस्तृत कार्य-क्षेत्र समा जाता है। हा, यह जरूर है कि यह बाहरी परिस्थितियों और आदर्शवादी मिद्धान्त का उपयोग करने वाले व्यक्तियोंके राग-द्वेष पर बहुत कुछ निर्भर करता है।

(३) उपर्युक्त आलोचनाने घनिष्ठ रूपसे सम्बन्धित एक दूसरी आलोचना यह है कि आदर्शवादी मिद्धान्तका स्वरूप अत्यधिक नकारात्मक है—विशेषकर राजकीय कार्य-क्षेत्रके सम्बन्धमें। आदर्शवादियोंका कहना है कि राज्य केवल बाहरी कार्योंमें सम्बन्ध रख सकता है, क्योंकि वह दबाव डालनेकी शक्ति का उपयोग करता है। वह प्रेरक वृत्तियों (motives) के सम्बन्धमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे राज्य प्रत्यक्ष रूपमें नैतिकता की उन्नति कर सके। समस्याके इन पहलुका विवेचन करते हुए बोमके लिखते हैं : राज्य मयोंगवश ही आध्यात्मिक प्रभावोंका आध्यात्मिक रूपमें उपयोग कर सकता है पर बाहरी साधनों द्वारा—मान कर ऐसे बाहरी साधनों द्वारा जिनमें दबाव डाला जाना हो—आध्यात्मिक

उद्देश्योंकी उप्रति करना केवल नाज़ुक और अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा ही सम्भव है (५. ३२)।'

आदर्शवादके समर्थनमें कहा जा सकता है कि यद्यपि इसमें राज्यके कार्य क्षेत्रका सिद्धान्त ऋणात्मक या नकारात्मक शब्दोंमें व्यक्त किया गया है, पर परिणाम धनात्मक है। राज्यके कार्य-व्यापारके ऋणात्मक स्वरूप पर अधिक जोर देनेका मुख्य कारण है उस आत्म-प्रेरणा या निरपेक्षताको सुरक्षित रखना जिसके द्वारा ही नैतिक कार्य किये जाने चाहिए। यदि राज्य मनुष्यके सुन्दर जीवनके हितमें प्रत्यक्ष रूपसे कार्य करना शुरू कर दे तो उसका नतीजा यह होगा कि लोग राज्य पर अनुचित रूपसे निर्भर रहने लगेंगे और अपनेको असहाय समझेगे। फलतः राज्यके कार्यों का उद्देश्य ही विकल हो जायगा। व्यक्तिवाद व्यक्तिके गौरव-गीत गाता है। यह व्यक्तिको एक ऐसा उद्देश्य मानता है, समाज जिसकी सिद्धिका केवल एक साधन है। समाजवाद और हीगेलवाद बिल्कुल दूसरे छोर पर हैं और राज्यको 'बहु रहस्यात्मक' महत्व देते हैं जो उच्चतम आत्माभिव्यक्तिकी वस्तु हैं और जिनके द्वारा मनुष्य अपने पृथक् एकाकीपनसे ऊपर उठ जाता है (५. ३३)।' इसके विपरीत अंग्रेजी आदर्शवादियोंने बीचका मार्ग अपनाया है, यद्यपि हमें यह मानना पड़ता है कि ग्रीन और बोसाके दोनोंने ही राजकीय कार्य-व्यापारके शुद्ध नकारात्मक पक्षको बढ़ा-बढ़ाकर कहा है। निम्न कोटिका व्यक्ति और समाज एक उच्च कोटिके व्यक्ति और समाजके लिए साधन है।

(४) बोसाके का कहना है कि आदर्शवादी सिद्धान्तको बहुत मकीर्ण और कठोर बनाया जाता है। आलोचकोंका कहना है कि यह सिद्धान्त प्राचीन मूलानके सीधे-सादे नगर राज्यों पर लागू हो सकता था। क्योंकि उनमें राज्य और समाजके बीच कोई विभेद नहीं किया जाता था। पर आधुनिक युगकी बदली हुई परिस्थितियोंमें राज्य और समाजके बीच सावधानीसे विभेद किया जाना चाहिए और समाजके भीतर स्थायी संघोंको परम्परागत एकात्मवादी सिद्धान्त (monistic theory) द्वारा जो स्थान अब तक प्राप्त रहा है उसकी अपेक्षा अधिक उचित स्थान दिया जाना चाहिए।

हम यह मानते हैं कि अनेक आदर्शवादी, राज्य और समाजके बीच विभेद नहीं कर पाते और उनकी इन अमफलताका परिणाम समाजके लिए व्यक्तिका बलिदान होता है। साथ ही हम बहुलवादी सिद्धान्तको भी माननेको तैयार हैं, जो राज्यको समाजके अन्य संघोंके बिल्कुल समान मानता है। यह सही है कि आजकी परिस्थितियों पहलेकी परिस्थितियोंमें भिन्न हैं। पर फिर भी, बोसाके के शब्दोंमें, राज्य विभिन्न संघों और समुदायोंको नीचेमे ऊपर तक एक सूत्र में बांधकर उनमें मनुजान स्थापित करने वाला सोच है। हम बहुधा राज्यको राजा, सरकार या स्थानीय सस्थाओंके साथ एक रूप करना चाहते हैं। पर राज्य इन तीनोंकी भांति विभाज्य नहीं है (५. २८-२९)।'

एक ओर दृष्टिसे आदर्शवादकी बहुत संकीर्ण बहा जाता है। आदर्शवादके विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि वह भौतिक कल्याणको एकदम भुलाकर मनुष्यके नैतिक और आध्यात्मिक हितों पर ही बहुत अधिक जोर देता है। राज्यका उद्देश्य निस्सन्देह सुन्दर जीवन या आत्माओंकी श्रेष्ठता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आदर्शवादी इस बातका समर्थन करता है कि राज्य प्रत्यक्ष स्वयं सुन्दर जीवनकी वृद्धि करे। और न इसका यहो अर्थ है कि वह व्यक्तिकी भौतिक आवश्यकताओंकी ओरसे विल्कुल ही आखें मूंद ले। इसका उदाहरण ग्रीनका सिद्धान्त है। इस सिद्धान्तका अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रीन सामाजिक जीवनकी ठोस वास्तविकताओंके विल्कुल निकट है।

आदर्शवादको अनस्य या कठोर भी कहा जाता है। आदर्शवादके विरुद्ध यह आरोप लगाने वालोंका कहना है कि आदर्शवादी सिद्धान्तके अन्तर्गत सार्वजनिक इच्छा की स्थितिका निदधय कर सकना अर्थात् यह निदधय कर सकना कि किमकी इच्छा सार्वजनिक इच्छा है, बहुत कठिन है। बहुलवादी या तो यह कहते हैं कि सार्वजनिक इच्छाके नामकी कोई चीज होती ही नहीं या फिर यह दावा करते हैं कि समाजके भीतर हर स्थायी मंषकी सार्वजनिक इच्छा और अपना व्यक्तिस्व होता है। आदर्शवादी यह माननेसे इनकार नहीं करता कि राज्यके अलावा अन्य सघों या समुदायोंकी भी अपनी इच्छा या अपना व्यक्तिस्व हो सकता है। पर वह इनका ज़रूर चाहता है कि राज्यको समाजमें अद्वितीय स्थान मिलना चाहिए क्योंकि उसे विशेष प्रकारके कर्तव्य पूरे करने होते हैं।

(५) ऊपर जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए यह ज़रूरी नहीं जान पड़ता कि जोड़ और मैकाइवर जैसे सहानुभूतिहीन लेखकोंकी आलोचनाओं पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाय।

जोड़ आदर्शवादको सिद्धान्ततः विवृत और सध्यतः असत्य बताते हैं और कहते हैं कि इससे वर्तमान राज्यकी वैदेशिक मामलोंमें तथा अधिक अनैतिक एवं अविचार पूर्ण कार्य करनेका खतरनाक अधिकार मिल जायगा।

(क) जोड़ और मैकाइवर दोनोंका कहना है कि आदर्शवादी सिद्धान्तका एक बहुत बड़ा दोष यह है कि इसमें राज्य और समाजको एकरूप माना जाता है अर्थात् इन दोनोंमें किसी प्रकारका कोई अन्तर नहीं समझा जाता। जर्मन आदर्शवादियों और ब्रेडले जैसे अंग्रेज आदर्शवादियों पर यह आलोचना ज़रूर लागू होगी है; पर ग्रीन जैसे सम्पूर्ण आदर्शवादियों पर यह आलोचना लागू नहीं होगी। मैकाइवर का तर्क है कि समाजकी 'स्थायी बुद्धि (enduring mind)' (५५:४५१) सम्पूर्ण माना जा सकता है पर राज्यको नहीं। हम इस तर्कको स्वीकार करनेमें अग्रमंथ हैं।

(ख) हम जोड़ के इस तर्कमें सहमत हैं कि व्यक्तिका पूरा विकास राज्यमें गुप्त रहकर नहीं हो सकता—इस कथनका यह अर्थ नहीं है कि राज्य सार्वजनिकमान

है, पर इनका यह मान लेना भारी गलती है कि सभी आदर्शवादी राज्यकी सब कुछ कर सकनेकी शक्ति पर विश्वास करते हैं। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि ग्रीन और बोसाके राज्यके कार्य-क्षेत्रको कितना सकुचित कर देते हैं। जोड़ यह कहकर कि 'राज्यका अस्तित्व व्यक्तियोंके लिए है, व्यक्तियोंका अस्तित्व राज्यके लिए नहीं है', व्यक्ति और राज्यके बीच एक गलत विभेद करते हैं। उद्देश्य और साधनका सम्बन्ध व्यक्ति और राज्यके बीच लागू नहीं किया जा सकता। हीगेलके अतिरिक्त कोई भी अन्य आदर्शवादी राज्यके कल्याणकी व्यक्तियोंके कल्याणमें पूरक और श्रेष्ठ नहीं मानता। पर फिर भी जोड़ सभी आदर्शवादियोंको एक ही तराजूसे तोलते हैं।

(ग) जोड़ और मैकाइवर दोनों ही 'मर्याद' और 'वास्तविक' इच्छाओंके विभेदको सिद्धान्ततः विवृत और व्यवहारतः अमर्याद मानते हैं। इस आलोचनाके विरुद्ध हम आदर्शवादका समर्थन पहले ही कर चुके हैं। जोड़ 'मर्याद' इच्छाकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं: "जिस समयका मैं सदस्य हूँ उसके बहुमत द्वारा किये गये सभी निर्णयोंकी कार्यान्वित करनेकी इच्छा (४१:१९)।" यह तो 'मर्याद' इच्छा का ध्वंगचिह्न है। यह कहना भी अत्युक्ति है कि जब कभी व्यक्ति और राज्यके बीच संघर्ष होता है तब "आदर्शवाद राज्यको ही अनिवार्यतः सही मानता है (४१:१९)।"

(घ) मैकाइवर साम तौरसे राज्यके व्यक्ति-सम्बन्धी आदर्शवादी सिद्धान्तकी आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि यह सही है कि राज्यका निर्माण व्यक्तियोंसे होता है, पर उसका यह अर्थ नहीं कि राज्य एक व्यक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे बूझोंको मिलाकर बनने वाला बाग स्वयं कोई बूझ नहीं है या जानवरकी कोई सन्तति स्वयं एक जानवर नहीं है। इस मुलनामें भूल यह की गयी है कि भौतिक सम्बन्धोंको मानसिक सम्बन्ध माना गया है। भौतिक जगत्में हम सब पूरक-पूरक व्यक्ति हैं। पर मानसिक और नैतिक जगत्में एक व्यक्तित्वका दूसरे व्यक्तित्वके साथ सम्पर्क होता है और यह सम्भव है कि एक मूष-मनोवृत्ति (group-mind) और मूष-नैतिकता (group-morality) का विकास किया जाय। एक ही लूठी पर एक दर्जन कोट टांग देने से एक कोट नहीं बन जाता। पर जब ऐसे लोग जिन्होंने एक प्रश्न पर पहलेसे ही अपना मत निश्चित नहीं कर लिया है, एक स्थान पर एक साथ मिलकर किसी प्रश्न पर विचार करते हैं, तब विचार विमर्शके परिणाम स्वरूप एक मार्गनिर्वाह इच्छा और एक सामान्य मतकी उत्पत्ति होती है।

इस सबका मतलब यह नहीं है कि राज्य एक 'उच्चतर बुद्धि' है, या एक अविमानव है, जिसका उद्देश्य या जिसकी इच्छा उन सब व्यक्तियोंकी इच्छाओंसे उच्चतर होती है जो उसका निर्माण करते हैं (२५:४४९-४०)। इसका अर्थ केवल इतना है कि राज्यकी अपनी एक इच्छा होती है, उसकी अपनी एकता होती है और ये दोनों चीजें किसी भी एक व्यक्तिमें किसी एक समय पर नहीं पायी जानी हैं। राज्य एक सजीव व्यक्ति है।

JONES, SIR H.—*The Working Faith of the Social Reformer*:

KANT, I.—*Critique of Pure Reason*.

„ —*Critique of Practical Reason*.

„ —*Principles of Politics*.

„ —*Perpetual Peace*.

LASKI, H. J.—*Authority in the Modern State*.

LORD, A. R.—*Principles of Politics*—Ch. XI.

MACCUNN, J.—*Six Radical Thinkers*—Ch. VI

MACKENZIE, J. S.—*An Introduction to Social Philosophy*.

MERRIAM, C. E.—*New Aspects of Politics*.

MUTRHEAD, J. H.—*The Service of the State*.

RITCHIE, D. G.—*The Principles of State Interference*.

ROCKOW, J.—*Contemporary Political Thought in England*.

SABINE, G. H.—*A History of Political Theory*.

SETH, J.—*Ethical Principles*—pp. 287-320.

VAUGHAN, C. E.—*Studies in the History of Political Philosophy*—
Vol. II.

WALLAS, G.—*Human Nature in Politics*.

WILDE, N.—*The Ethical Basis of the State*.

राष्ट्रीयतावाद, साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद

(Nationalism, Imperialism and Internationalism)

राष्ट्र और राष्ट्रीयताकी परिभाषा

(Definition of Terms—Nation and Nationality)

राजनीति शास्त्रके लेखक 'राष्ट्र', 'राष्ट्रीयता' और 'राष्ट्रीयतावाद' शब्दोंके सटीक अर्थोंके प्रश्न पर एकमत नहीं है। अंग्रेजोंके 'नेशन' (nation) शब्दकी उत्पत्ति लेटिनके नामियो (natio) शब्दसे हुई है जिसका अर्थ है 'जन्म' या 'जाति'। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रीयता और जातीयताकी धारणाएँ एक हैं। मजहबी पातानी में 'नेशन' (राष्ट्र) शब्दका उपयोग किसी राज्यकी उस आबादीको व्यक्त करनेके लिए किया जाता था जिसमें जातीय एकता पायी जाती थी। बर्नड जोसेफ का कहना है कि यह अर्थ अधिकांश रूपमें आज भी कायम है। फ्रांस की राज्य क्रांतिके जमानेमें 'नेशन' शब्द बहुत लोकप्रिय हो गया और उसका उपयोग देशभक्ति (patriotism) के अर्थमें किया गया। "राष्ट्रीयता उन दिनों एक सामूहिक भावना थी (४३-२०)।"

पर उन्नीसवीं सताब्दीसे 'नेशन' (राष्ट्र) और 'नेशनलिटी' (राष्ट्रीयता) शब्दोंके निश्चित अर्थ हो गये हैं। नेशन या राष्ट्र शब्द द्वारा राजनीतिक स्वाधीनता अथवा प्रभुताका आदर्श—चाहे वह प्राप्त हो या इच्छित—प्रकट होता है। इसके विपरीत राष्ट्रीयता (nationality) अधिकतर एक अराजनीतिक धारणा है और विदेशी सामनमें भी उसका अस्तित्व रह सकता है। राष्ट्रीयता एक मनोवैज्ञानिक गुण है। यद्यपि उसका उपयोग बहुधा नैतिक और सांस्कृतिक धारणाको भी व्यक्त करनेके लिए किया जाता है। इस अर्थमें व्याख्या करने पर 'राष्ट्र' और 'राष्ट्रीयता' दोनों एक रूप धारणाएँ नहीं हैं। स्वयं अपना शासन करनेवाले एक राज्यकी जनताके अर्थमें 'राष्ट्र' के भीतर अनेक राष्ट्रीयताएँ हो सकती हैं। उदाहरणार्थ यद्यपि ब्रिटेन एक राष्ट्र है फिर भी उसमें चार विभिन्न राष्ट्रीयताएँ या जातियाँ—अंग्रेज, स्कॉच, वेल्श और उत्तरी आयरिश सम्मिलित हैं। जैसे ही कोई एक राष्ट्रीयता या जाति राजनीतिक एकता और सम्प्रभुता सम्पन्न स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती है वैसे ही वह राष्ट्रीयता या जाति एक राष्ट्र बन जाती है। लॉर्ड वाइम का कहना है कि राष्ट्रीयताकी भावना उस अनुभूति या अनुभूतियोंका संकलन है जो एक व्यक्ति समूहको उन बन्धनोंके प्रति सजग बनाता है जो पुरी तरहसे न तो राजनीतिक होते हैं, न धार्मिक और जो उन व्यक्तियोंको ऐसे सामाजिक रूपमें संगठित कर देते हैं जो या

तो वाम्बन्धुमें या बीज रूपमें एक राष्ट्र होना है (७:११८)। 'राष्ट्रीय ग्रुप' (national group) शब्दका उपयोग एक ऐसे समाजको व्यक्त करनेके लिए किया जाता है जिसमें राष्ट्रीयताका अभी निर्माण ही हो रहा हो और जिसमें एक राष्ट्रकी तरह रहनेकी इच्छाकी कमी हो।

जिन दो शब्दोंके सम्बन्धमें बहुत अधिक भ्रम होता है वे हैं 'राष्ट्रीयता' और 'राष्ट्रीयतावाद'। राष्ट्रीयतावादका उपयोग कभी-कभी राष्ट्रीयताकी एक ऐसी अत्युक्तिपूर्ण भावनाके लिए किया जाता है जो आश्रमक सी होती है। यह द्वितीय भावना जो अपने राष्ट्रमें और अपने राष्ट्रके कार्यमें अच्छाईके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखती, सच्ची राष्ट्रीयतावादकी भावना नहीं है। ठीक-ठीक समझने पर राष्ट्रीयतावाद वह ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रीयताएँ या जातियाँ राजनीतिक इकाइयोंमें बदल जाया करती हैं। भ्रष्टा राष्ट्रीयतावाद ऐसे लोगोंके उचित अधिकारों का समर्थक होता है जो एक अलग बलवान् जानि या राष्ट्रका निर्माण धरती पर अपना स्थान प्राप्त करनेके लिए करते हैं। जैसा जोर्जेन्स कहते हैं, जो भावना राष्ट्रीयताका आधार है उसे राष्ट्रीयताकी भावना वह सचते है; पर राष्ट्रीयतावाद नहीं वह सचते।

राष्ट्रीयताका अर्थ (The Meaning of Nationality). आजकल विचारक इस बात पर आमनीर पर एक मत है कि राष्ट्रीयता मूलतः एक मानसिक प्रवृत्ति या भावना है। ए० इ० जिमैन्स लिखते हैं: "धर्मकी भाँति राष्ट्रीयता भी आत्मपरक (subjective) है; मनोवैज्ञानिक है; मनकी एक स्थिति है, एक आध्यात्मिक धारणा है; भावनाकी, विचारकी और जीवनकी एक मंडति है"। इन्हीं शैलिकका कहना है कि राष्ट्रीयता एक राजनीतिक धारणा न होकर शिक्षा-सम्बन्धी धारणा है। मोटेतीर पर यदि जनता अपनेको एक राष्ट्रीयता या जातिके रूपमें मानती है तो वह राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयताका एक राजनीतिक प्रत्यक्षन जाना तो आत्मस्थिक है, मूल रूपमें राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक और शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न है।

इसी विचारको दूसरे शब्दोंमें प्रकट करते हुए कुछ लेखक कहते हैं कि राष्ट्रीयता एक महज वृत्ति या स्वाभाविक प्रेरणा है। जे० एच० रोज़ राष्ट्रीयताकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं: "दिलोकी एक ऐसी एकता जो एक धार बनकर बनी न बिगड़े।" राष्ट्रीय या जातीय राज्य और राष्ट्रीयताके अन्तरको स्पष्ट करते हुए मो० जे० एच० हेज लिखते हैं: "एक राष्ट्रीय राज्य हमेशा राष्ट्रीयता पर आधारित रहता है पर राष्ट्रीयताका अस्तित्व राष्ट्रीय राज्यके बغير भी हो सकता है। राज्य तत्त्वतः राजनीतिक होता है, राष्ट्रीयता ध्रुवान् रूपसे मासृतिक होती है और केवल संयोगवश राजनीतिक हो जाती है (२३:२)"।

राष्ट्रीयताके तत्त्व (Factors of Nationality). यदि राष्ट्रीयता एक आत्मपरक (subjective) धारणा है तो वे कौन सी बाहरी बमोटियाँ हैं जो

उम पर लागू की जा सकती हैं? वे कौन सी शक्तें हैं जिनको पूरा करना राष्ट्रीयता के पदको प्राप्त करनेके लिए जरूरी रहता है? उन प्रश्नोंके उत्तरके लिए राष्ट्रीयता के तत्त्वोंका समझना जरूरी है।

राजनीति-शास्त्रके लेखकोंने उन तत्त्वोंका विस्तृत विवेचन किया है जिनसे राष्ट्रीयताका निर्माण होता है। पर वे सब यह मानते हैं कि जितने तत्त्वोंका विवेचन उन्होंने किया है उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीयताके लिए अनिवार्य हो; यद्यपि उनमें में कुछके बिना सच्ची राष्ट्रीयताका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। कोई ऐसा सार्वभौम नियम नहीं बनाया जा सकता जिसमें उन तत्त्वोंके आपेक्षिक महत्वका निर्देश किया जा सके। पश्चिमी दुनियामें काफी असेंसे धर्म राष्ट्रीयताका तत्त्व नहीं रह गया है। किन्तु पूर्वमें विशेषकर भारत में, धर्म अब भी एक शक्ति है जिसका सामना करना पड़ता है। यदि किसी देशमें राष्ट्रीयताके कुछ तत्त्व कमजोर हो तो राष्ट्रीयताके अस्तित्वको बनाये रखनेके लिए दूसरे तत्त्वोंको बलवान् बनाना जरूरी है।

(१) भौगोलिक एकता (Geographical Unity). निस्सन्देह राष्ट्रीयता के लिए प्रकृति द्वारा अलग किया गया एक क्षेत्र या भौगोलिक एकता जिसे प्रायः मानभूमि कहते हैं, जरूरी है। पर इसके अनेक अपवाद भी पाये जाते हैं। गुणोंसे यहूदियोंके पास उनका कोई अपना देश नहीं था; फिर भी यह आशा ही यहूदी राष्ट्रीयता को जीवित रख सकी और उसे शक्ति देती रही कि किसी न किसी दिन पेलेस्टाइन उन्हें वापस मिल जायगा। जर्मनी और फ्रान्स के बीचकी सीमा प्राकृतिक नहीं है फिर भी इन दोनों देशोंमें बड़ी सबल राष्ट्रीयताएं हैं।

जहां मानभूमि नहीं है या उस के होने की आशा नहीं है वहां राष्ट्रीयताकी भावनाका अस्तित्व या उसका विकास बहुत कठिन है। ज़िम्बियो या कजरोका कभी कोई निश्चित स्थान नहीं रहा। वे एक स्थानसे दूसरे स्थानको घूमते-फिरते हैं। प्राचीन समयमें विश्व साम्राज्यके लिए अपनी जन्मभूमिको छोड़नेवाले रोमन लोगोंने अपनी राष्ट्रीयता खो दी थी। इस प्रकार प्राकृतिक सीमाएं राष्ट्रीयताका विकास करने और उसे कायम रखनेमें बड़ा महत्वपूर्ण काम करती हैं। और जब किसी देश की प्राकृतिक सीमाओंको छीननेका प्रयत्न किया जाता है तो उसका परिणाम मुद्द होता है।

प्रकृति द्वारा बनायी गयी भौगोलिक सीमाएं राष्ट्रीयताके निर्माणमें अनेक कारकोंमें बहुत सहायक होती हैं। भौगोलिक स्थिति तथा जलवायुका मनुष्योंके चरित्र और नारीरिक गठन पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। इनसे सामान्य नारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक गुणोंकी उत्पत्ति होती है जिससे सहयोग और पारस्परिक सहानुभूतिमें सहायता मिलती है। यह देखा गया है कि अन्य देशोंमें अमेरिका में जाकर बसनेवालोंके मिरकी आदतियोंमें एक या दो पीढ़ी बाद रहस्यमय परिवर्तन हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि मनुष्यकी सहानुभूति सीमित होती है और मनुष्यके विकासकी वर्तमान स्थितिमें राष्ट्रीय जन्मभूमि ही वह उपयुक्त भौगोलिक इकाई है जिसमें मनुष्यकी पारमार्थिक भावनाएं और प्रेरणाएं सक्रिय और सफल बनायी जा सकती हैं। एक समय था जब ये भावनाएं अपने गांव या अपने कबीले तक ही सीमित थीं पर सभी प्रगतिशील देशोंमें इन सबीर्ण निष्ठाओंका स्थान राष्ट्रीय निष्ठा ने ले लिया है। भारत के एक निवासीके लिए अपने एक पड़ोसी व्यक्तिकी भावनाओंकी स्पष्ट कल्पना कर सकना आसान है; पर लेबोडोर या ग्रीनलैण्डमें रहने वाले व्यक्तिकी भावनाओंकी कल्पना उसके लिए उतनी आसान नहीं है। गांधीजी-तथा 'एक विश्व नागरिक' की सहानुभूति या निष्ठा बहुत गहरी नहीं होती। वह बहुत छिछली होती है।

प्रकृति द्वारा भूमी-भाति अलग किये गये एक प्रदेशके महत्त्व पर राष्ट्रीयताके एक महत्त्वपूर्ण तत्त्वके रूपमें जोर देनेका तीसरा कारण यह है कि पशुओंकी भांति मनुष्योंमें भी अपने निवास स्थानके प्रति प्रेम होना है। हर मानवके हृदयमें अपनी जन्मभूमिके प्रति अगाध प्रेम होता है। देशसे निकाले जाने पर देशका प्रेम और भी गहरा हो जाता है। प्राचीन इस्राईल वासियोंने किसी विदेशमें अपने बन्दी जीवनमें अपनी इस भावनाकी इस प्रकार प्रकट किया है: "ओ! जेरूसलम यदि मैं तुझे भूल जाऊ तो मेरा दाहना हाथ अपने कौशलको भूल जाय। यदि मैं तेरा स्मरण न करूं तो मेरी जीभ तानूमें चिपक जाय; मैं जेरूसलम को अपने सर्वप्रधान सुखसे भी उच्चतर समझू।"^१ आधुनिक राष्ट्रीयतावादके आध्यात्मिक जन्मदाता मैजिनी ने लिखा है: "हमारा देश हमारा घर है, वह घर जो परमात्मा ने हमें दिया है, जिसमें उसने अनेक परिवार रखे हैं, जो परिवार हमें प्यार करते हैं और जिन परिवारोंको हम प्यार करते हैं। एक ऐसा परिवार जिसके साथ दूसरोंकी अपेक्षा हम अधिक तत्परतासे सहानुभूति रखते हैं और जिसे हम दूसरोंकी अपेक्षा अधिक आसानीसे समझ पाते हैं; और जो एक निश्चित प्रदेशमें रहनेके कारण और अपने तत्त्वोंकी सजानीयताके कारण एक विशेष प्रकारकी क्रियाशीलताके लिए उपयुक्त है।"

"हमारा देश हमारी कार्यशाला (workshop) है जहासे हमारे श्रमका उत्पादन पूरे ममारके लाभके लिए बाहर भेजा जाता है, और जहा से सभी उपकरण-औजार इकट्ठे किये गये हैं जिनका हम बहुत अधिक सफलताके साथ उपयोग कर सकते हैं (५९: खण्ड ४, पृष्ठ २७६)।"

यद्यपि ऊपरके विचारोंमें एक राष्ट्रीय जन्मभूमिका महत्त्व मिट्ट होना है कि भी यह कहना ही होगा कि संसारकी प्रकृति द्वारा निर्धारित प्रदेशोंके आधार पर बाटनेका परिणाम निरन्तर भयंकर और युद्ध ही होगा। प्रो० हेज़ इस धारणाकी कि राष्ट्रीयताका निर्माण भूगोल द्वारा होना है, आलोचना करते हुए कहते हैं कि जानियेंगे

^१ म्नात्र १३७, पृष्ठ ५ और ६।

बीच प्राकृतिक सीमाओंका विचार एक कोरी कल्पना है।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, १९४७ के विभाजनके पहले तक वह गेप संसारसे पृथक् एक निश्चित भौगोलिक इकाई था। उच्चतम देशभक्तिकी भावनाओंको सजग बनानेके लिए "देश" सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक इकाई है। यदि आधुनिक समारमें भारतको जीविन रहना है तो यह आवश्यक है कि हम धाम-राजनीति, जाति-राजनीति और क्वायली-राजनीतिको छोड़कर तुरन्त राष्ट्रीय राजनीतिको अपनाए। "दि प्रोजेक्शन ऑफ़ इण्डिया" शीर्षकके अपने एक विचारोत्तेजक लेखमें श्री एम० रत्नास्वामी ने लिखा है कि वर्तमान राजनीतिक स्थितिमें भारत की जनताको आवश्यकतामें अधिक महत्व दिया जा रहा है, पर देशकी घरेलूकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निर्वाचन क्षेत्रोंका निर्धारण (स्वतंत्रताके पूर्व) विशिष्ट प्रदेशोंके आधार पर न करके विशिष्ट सम्प्रदायोंके आधार पर किया जाना है। शिक्षाके क्षेत्रमें भी सम्प्रदायोंके प्रति अनुरक्ति "हिन्दू विश्वविद्यालय", "मुस्लिम विश्वविद्यालय" आदि नामोंमें स्पष्ट प्रकट होनी है।

श्री रत्नास्वामी की यह दलील बिन्दुल ठीक है कि यदि भारत की जनताके अधिकार हैं तो भारतकी भूमिके भी अधिकार हैं। "उमके भी अपने अधिकार और अपनी स्वाधीनताएं हैं, अपने हित हैं और अपना महत्व है।" भारत हमारी जन्म-भूमि है, पुण्यभूमि (a sacred land) है; और मानूँभूमिके प्रत्येक पुत्रका यह कर्त्तव्य है कि वह "अपने देशका ऐसा निर्माण करे, उसका ऐसा विकास करे कि लोगोंको अपने देश, उसकी स्वाधीनता, और उसकी उन्नतिके प्रति उन्माह हो। भारतकी आहुति, उसका स्वरूप, उसका मौन्दर्य, उसकी नदिया, उसका रेगिस्तान, उसकी वनस्पतिया और उसके पशु इन सबमें भारतके हर पुरुष, स्त्री और बच्चेको परिचित होना चाहिए। देशाटन और यात्राको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आम जनताके लिए देशके सभी हिस्सोंकी यात्राका प्रबन्ध होना चाहिए। समाचार पत्रों, मित्रमा और रेडियोंको एक सुमस्तित राष्ट्र-योजना ममिनिके निर्माणके लिए परस्पर एक दूसरेसे सहयोग करना चाहिए और सरकारको इसमें सहायता देना चाहिए।" "राजनीति हमें विभाजित करती है, धर्म हमारे बीच दीवार खड़ी करता है, सन्धति हमें टुकड़ोंमें बांटती है; पर हमारा देश और देशकी घरेलूकी प्यार हमें एक सूत्रमें बांध सकता है।" उक्त तर्कोंके कारण भारत का विभाजन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

(२) जातीय एकत्वता या जातीय एकता (Identity of Racial Type or Racial Unity). कुछ लेखक राष्ट्रीयताका निर्माण करने और उसकी मजबूत बनानेमें जातीय एकताको महत्व देने हैं। जिमर्न (Zimmern) इसे बहुत ऊंचा स्थान देते हैं और ब्राइस (Bryce) इसे राष्ट्रीयताकी भावना उत्पन्न करनेवाले तत्वोंमें से केवल एक तत्व मानते हैं। दूसरी ओर मैजिनी (Mazzini) का कहना है कि राष्ट्रीयताके लिए जाति अनिवार्य नहीं है। रेनन (Renan) का

बहना है कि "जाति एक ऐसी चीज है जो स्वयं ही बनती विगड़ती रहती है और राजनीतिमें इसका कोई प्रयोजन नहीं है"। जे० एच० रोज (J. H. Rose) का कहना है कि राष्ट्रीयता बहुत भदे रूपमें ही जाति पर निर्भर रहती है। हेज (Hayes) कहते हैं "शुद्धता यदि नहीं है तो आजकल असम्भ्य कवायली लोगोंमें ही है।" पिल्सबरी (Pillsbury) लिखते हैं, "साधारणतया राष्ट्रीयताके निर्माणमें जाति का अब कोई महत्व नहीं है। किसी भी राष्ट्रमें कोई भी शुद्ध जाति नहीं है। मनुष्य सब वही वर्ण कर सकर है।" मुसोलिनी (Mussolini) तक ने एक बार कहा था, "जाति एक भावना है, वास्तविकता नहीं। कोई भी बात मुझे विश्वास नहीं दिला सकती कि जीवशास्त्रकी दृष्टिसे आज कही भी कोई शुद्ध जाति है।"

इस प्रकार शास्त्रीय सम्प्रतिका पस्त्या उन लोगोंके पक्षमें भारी है जो जातिको अपेक्षाकृत निम्न स्थान देते हैं। स्विटजरलैण्ड और केनाडा ऐसे उदाहरण हैं जहाँ विभिन्न जातिके लोग एक साथ रहते हैं और एक शुद्ध राष्ट्रीयताका निर्माण कर चुके हैं। कई पीढ़ियों तक समुक्त राष्ट्र अमेरिका "जातियोंका संगम" रहा है। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है हम विश्वास करते हैं कि जातीय एकतासे राष्ट्रीयता मुदुद होती पर वह अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीयताकी प्रारम्भिक अवस्थामें जातीय एकता अधिक महत्वपूर्ण है, बादकी अवस्थामें कम। समुक्त राष्ट्र अमेरिकामें जातीय वर्गों को बहुत अधिक विभिन्नता है, पर साथ ही साथ वहाँ एक प्रभावशाली प्रधान जातीय मूल भी है जिसमें पुराने प्रवासियोंके वंशज हैं और देशके राष्ट्रीय जीवनको एक निश्चित रूप देनेमें समर्थ हैं।

साधारणतया यह कहा जा सकता है कि जातीय एकरूपताकी एक निश्चित मात्रा राष्ट्रीयताके लिए सहायक होती है। जब तक जातीय भेदोंकी अनेककरनामे साधारण विभेद ही उत्पन्न होते हैं तब तक कोई बड़ी कठिनाई नहीं पड़ती। पर यह समझनेमें कठिनाई होनी है कि आग्ल-सैक्सनी, चीनी और नीचो लोग अपने बीच वर्तमान सामाजिक विभेदोंके बावजूद रहते हुए किस प्रकार एक राष्ट्रीयताका निर्माण कर सकते हैं। कोई भी राष्ट्रीयता अधिक समय तक नहीं टिक सकती यदि उसके जातीय वर्गोंमें तीव्र विभेद हो।

संसारके इतिहास पर दृष्टिपात करिए तो यह स्पष्ट हो जायगा कि जिनो जमानेमें भी ऐसा नहीं हुआ कि एक पूरी जातिने एक ही राष्ट्रीयता बचलकी हो। फिन (Finns) लोगोंको एक जाति माना जा सकता है पर वह विभिन्न राष्ट्रीयताओंमें बटे हुए हैं। जाति और राष्ट्रीयता वही भी एकरूप नहीं है। जोसेफ (Joseph) का कहना है, "राष्ट्रीयता वास्तवमें जानियोंके व्यापार निरुल जाती है।" कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि राष्ट्रीयता ही जातिकी मृष्टि करती है, जाति राष्ट्रीयता की मृष्टि नहीं करती। हमारे देशमें जातीय अनेकरूपता बहुत स्पष्ट है, पर यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतके विभिन्न मन्प्रदाय पूरी तरहसे एक दूसरेमें अलग जातीय समुदाय हैं। उदाहरणके लिए पंजाबी मुसलमानमें बंगाली या मद्रासी मुसलमानकी

अपेक्षा पत्रावी हिन्दूमें अधिक जातीय समानता है। इस सम्बन्धमें धार्मिक या साम्प्रदायिक वर्गीकरणकी अपेक्षा प्रादेशिक वर्गीकरण अधिक सहायक हो सकता है।

(३) विचारों और आदर्शोंकी एकता या सामान्य संस्कृति (Unity of Ideas and Ideals or a Common Culture). यदि राष्ट्रीयता मूलरूपमें सांस्कृतिकधारणा है तो विचारों और आदर्शोंकी एकता अवश्य ही उसका एक मुख्य तत्त्व है। संस्कृतिकी एकतामें सामान्य रीतियाँ और व्यवहार, सामान्य परम्पराएँ और साहित्य, सामान्य ग्रामगीत, काव्य और कला भी शामिल हैं। संस्कृतिकी एकता जीवनका एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें 'जीवनके सामान्य मानदण्ड, कर्तव्य और नियम मौजूद होने हैं।' विचारों और आदर्शोंकी एकता लोगोंको परस्पर समीप खींच लाती है और उनमें सहयोगकी एक ऐसी भावना पैदा कर देती है जो आमानीमें नष्ट नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और कला, राष्ट्रीयताके कारण और परिणाम दोनों ही हो सकते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय साहित्य स्वयं राष्ट्रीयताका निर्माण नहीं करता, फिर भी वह राष्ट्रीयताकी भावनाको मजबूत अवश्य ही बना सकता है। आधुनिक कालमें बोहेमिया और सर्बियाको राष्ट्रीयताओंको फिरसे जीवित करनेमें राष्ट्रीय साहित्यने महत्वपूर्ण काम किया है। "राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रीय परम्पराओंका सृजन करता है, उन्हें जीवित रखता है और राष्ट्र में राष्ट्रीय साहित्यके प्रति अनुराग भर देता है। इन सब कारणोंसे राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रीयताकी भावनाके विकासमें महत्वपूर्ण योग देता है। एक शब्दमें, राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रीय परम्पराओं के प्रसार का माध्यम है (४३:११४)।" राष्ट्रके सदस्य अपने राष्ट्रीय साहित्य पर गौरव करते हैं और उसमें श्रद्धा रखते हैं। वॉल्टेयर (Voltaire) ने गर्वके साथ कहा था: "हमारे भाषा और हमारे साहित्यने चार्लमैग्ने (Charlemagne) (एक प्रसिद्ध विजेता) की अपेक्षा अधिक प्रदेश जीते हैं।"

जीवनके दृष्टिकोणमें समानता लाने तथा एक ही मानदण्ड कायम करनेमें राष्ट्रीय शिक्षा महत्वपूर्ण भाग ले सकता है। "संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विभिन्न जातियों और सांस्कृतिक यूँकोकी एक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रीयताका रूप देनेमें "अमेरिकीकरण" के रूपमें नागरिकताकी शिक्षाने बहुत बड़ा काम किया है। पर जब राष्ट्रीय शिक्षाका दुरुपयोग किया जाता है जैसा कि नाज़ी जर्मनीमें हुआ था, तब राष्ट्रीय शिक्षासे राष्ट्रीय कट्टरता तथा मतान्धता और पूर्वं द्वेष (Prejudice) बड़ी आमानीमें उत्पन्न हो जाते हैं। यदि राष्ट्रीय शिक्षाका सही उपयोग किया जाय तो वह नैतिक एकता, सत्य-असत्यका सामान्य विवेक, तथा अधिवास विषयोंमें विचारोंकी एकता उत्पन्न कर सकती है (४३:११८)।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक निर्माणमें राष्ट्रीय इतिहास और परम्पराएँ मार्मिक तत्त्व हैं। रैम्से म्योर (Ramsay Muir) का कहना है कि 'बीरताके बाप, धैर्यपूर्वक सेने गये कष्ट, हीनो के मुन्दर तत्व हैं जिनसे राष्ट्रीयताकी भावनाका पोषण होता है। अपने

अतीत पर उचित गर्व, वर्तमान पर स्वस्थ विश्वास और सुन्दर भविष्यकी जिन्दादिलसे आशा—ये सभी राष्ट्रीय भावनाको सजीव और सबल बनाते हैं। बी० जोसेफ (B. Joseph) का कहना है कि खेल, राष्ट्रीय नौसेना (navy) पर गर्व और चाय पीने जैसी आदतोंका भी अंग्रेजी राष्ट्रीयताको सुदृढ़ बनानेमें हाथ है। यद्यपि यह बातें देखनेमें अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ती। जे० एस० मिल (J. S. Mill) ने ठीक ही कहा है कि “पूर्वकालीन राजनीतिक घटनाओंसे उत्पन्न एकता; एक राष्ट्रीय इतिहास के फलस्वरूप अतीतकी सामान्य स्मृतियाँ, सामूहिक गर्व, सामूहिक लज्जा, आनन्द और परचाताप।

यदि हम चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता सबल और ओजपूर्ण बने तो हमें विचारों और आदर्शोंकी उस एकता पर जोर देना चाहिए जो भारतीय संस्कृतिके मूलमें है। हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियोंने एक दूसरे पर इतना अधिक प्रभाव डाला है कि भारतीय और पाकिस्तानी इस्लाम आज अरब या पड़ोस के किसी दूसरे मुस्लिम देशका इस्लाम नहीं है। इसलिए हमारे सांस्कृतिक विभेदोंको बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए और यदि यह दोनों बड़े सम्प्रदाय एक दूसरेको समझनेका यत्न करें और सहिष्णुतासे काम ले तो ये विभेद धुधले पड़ जायेंगे। आज सबसे बड़ी आवश्यकता एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धतिकी है। हमारा इतिहास एक बार फिरसे इस ढंग से लिखा जाय कि दोनों सम्प्रदायोंके बीच होने वाले रक्तरजित युद्धों और अत्याचारोंके अत्युक्तिपूर्ण उल्लेख निकाल दिये जायें। इस सम्बन्धमें हमें यह न भूलना चाहिए कि योरोपके कुछ देशोंमें कैथोलिकों और प्रोटेस्टेण्टोंके बीच जितनी भयावह लड़ाइयाँ हुई हैं उतनी भारतमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच नहीं हुई हैं।

(४) भाषा की एकता (Unity of Language). राष्ट्रीयताका सबसे अधिक स्पष्ट तत्व भाषा है। रैम्से म्योर (Ramsay Muir) का विश्वास है कि राष्ट्रके निर्माणमें जातिकी अपेक्षा भाषाका महत्त्व कहीं अधिक है। ‘सामान्य भाषा का अर्थ एक सामान्य साहित्य, महान् विचारोंकी एक सामान्य प्रेरणा और गीतों तथा गान-गायकोंकी एक सामान्य पंतुक सम्पत्ति भी है।’ रोज (Rose) का कहना है कि राजनीतिक क्षेत्रमें भाषाका प्रभाव सबसे अधिक होता है। जोसेफ (Joseph) का कहना है कि सामान्य भाषा लोगोंके विचारों और भावोंमें समानता लाती है। नैतिकता, आचार और न्यायके सामान्य मानदण्ड स्थिर करती है; सामान्य ऐतिहासिक परम्पराओंको कायम रखती है (preserves) और एक सामान्य राष्ट्रीय मनोवृत्तिकी उत्पत्ति करती है। वर्तमान समयमें दूसरे लोगोंकी अपेक्षा पोल (people of Poland) लोगोंने राष्ट्रीय भावनाको जीवित रखनेमें सामान्य भाषाके महत्त्वको अधिक प्रदर्शित किया है। जब लोग अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक एकता कायम रखनेको कठिबद्ध होते हैं तब उन्हें सफलता प्राप्त करनेमें भाषाकी एकतामें बहुत बड़ी महायता मिलती है। सामान्य भाषाके अनेक लाभोंके बावजूद अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी एक सामान्य भाषा नहीं है। स्विट्जरलैण्ड में

कमसे कम तीन भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। यदि राष्ट्रीयताके अन्य तत्त्व सुदृढ़ हों तो सामान्य भाषाके बिना भी काम चल सकता है। अलास्काकी जर्मन भाषी जनता जर्मनीकी अपेक्षा फ्रांससे अधिक प्रेम रखती है। अमेरिका और केनाडाके नागरिक एक ही भाषा बोलते हैं और एक दूसरेके पड़ोसी भी हैं। फिर भी इन दोनों देशोंके लोग आपसमें मिलकर एक राष्ट्र बनने को तैयार नहीं हैं।

भारतमें भाषाका विभेद राष्ट्रीय एकात्ममें बाधक रहा है। हिन्दीको राष्ट्र-भाषा बना देनेसे यथासमय हालत सुधर आयगी। एक राष्ट्र भाषाका विकास करनेकी प्रवृत्ति होती चाहिए। स्कूलोंमें और मोहल्लोंमें उसका उपयोग हो, मस्जिदोंके विकास और विस्तारमें उसको काममें लाया जाय और उसे न केवल परम्परागत और आधुनिक साहित्य तथा कला का, बल्कि आधुनिक टेक्निकल और वैज्ञानिक विचारों का भी सुबोध माध्यम बनाया जाय। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हिन्दीके अनिश्चित तामिल, तैलंगू आदि अन्य प्रादेशिक भाषाको नष्ट कर दिया जाय। ब्रिटिश शासनमें अंग्रेजी भाषा कुछ लोगोंके विचार विमर्शका माध्यम बन गयी पर वह स्वभावतः जनताकी भाषा नहीं बन सकी। फिर भी उच्चशिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियोंके लिए अंग्रेजीका काम सहायक ज्ञान लाभप्रद होगा। बड़े पैमाने पर अंग्रेजीके साहित्यिक अध्ययनकी अपेक्षा जरूरत इस बातकी है कि अंग्रेजी भाषाके अध्ययन द्वारा उसमें उपलब्ध टेक्निकल, सामाजिक तथा अन्य व्यावहारिक विषयोंके साहित्यका अध्ययन किया जाय ताकि व्यावहारिक ज्ञानसे भारतवासी वंचित न रह जाय।

(५) धर्मकी एकता (Unity of Religion) राष्ट्रोंके इतिहाससे पता चलता है कि प्रारम्भिक अवस्थाओंमें धर्मका प्रमुख स्थान रहा है। प्रारम्भिक सामाजिक जीवनका केन्द्र धर्म, रीति-रिवाज और आचार व्यवहार ही रहा है। उदाहरणार्थ यहूदियोंमें धर्म ही उनके राष्ट्रीय जीवनका मुख्य आधार था। धर्म ही उनके सामान्य जीवनका ताना-बाना था। यही बात आजकल जापानियों, पोलों और अमेरिकी लोगोंके बारे में कही जा सकती है। मस्जिदोंके अन्धाचारमें यूनानका कैथोलिक धर्म-मय ही एक जातिके रूपमें यूनानियोंको जीवित रख सका। स्कॉटलैण्ड के बारेमें विचार करने पर हमें मालूम होता है कि जॉन मॉक्स और प्रोटेस्टेण्ट धर्म-मुधारने स्कॉटिश राष्ट्रीयताकी उत्पत्ति और उसके स्थायित्वमें महत्वपूर्ण भूमिका ली।

धर्मकी एकता अब कोई महत्वपूर्ण तत्त्व नहीं रह गया है, यद्यपि ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें विशेष पूर्ववर्ती ऐतिहासिक परिस्थितियोंके कारण अब भी धर्म राष्ट्रीयताका आधार बना हुआ है। हेज (Hayes) कहते हैं कि अधिकांश आधुनिक राष्ट्रीयताएं धार्मिक विस्वासा या धार्मिक वृत्तियोंकी एकरूपता पर जोर दिये बिना ही फूल-फूल रही हैं। आजकल अधिकांश राज्य धार्मिक सहिष्णुताका व्यवहार करते हैं। धार्मिक विभेद उनके राष्ट्रीय जीवनमें हस्तक्षेप नहीं कर पाता। सभी गणिगोल देशोंमें धर्म दिन प्रति दिन अधिकाधिक रूपमें व्यक्तिगत प्रश्न बनता जाता है। संयुक्त राष्ट्र

अमेरिका में तो धर्म जनताके राष्ट्रीय जीवनमें प्रवेश ही नहीं कर पाया है। पर इसके विपरीत भारतमें स्वार्थी दलों द्वारा अपने लाभके लिए धार्मिक विभेदों पर बहुत जोर दिया जाता है। धार्मिक कट्टरपन और धर्मान्यता कभी किसी जातिको महान् नहीं बना सकती। किन्तु हमारे यहां इस तथ्यको व्यापक रूपसे नहीं स्वीकार किया जाता। "धर्म स्वतरेमें है" एक अर्थहीन नारा है। अब समय आ गया है कि भारतके शिक्षित लोगोंको यह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय एकताके हितमें सहानुभूति और ज्ञानमें उत्पन्न होनेवाली सच्ची धार्मिक सहिष्णुताकी आवश्यकता है, केवल इस प्रश्नको ओर से एक दुलभुल उदासीनतासे काम नहीं चलेगा। कम-से-कम पढ़े-लिखे लोगोंको तो एक दूसरेके धार्मिक विश्वास और भावनाओंका बहुत सम्मान करना चाहिए। राजनीतिको धर्म निरपेक्ष बनाना चाहिए। हमारे कहनेका मतलब यह नहीं है कि धर्म और नैतिकताके उच्चतम सिद्धान्त राजनीतिका निर्देश और नियंत्रण न करे। राजनीतिको एक आदर्शवादकी आवश्यकता है। यह आदर्शवाद राजनीति नहीं दे सकती, धर्म और नैतिक सिद्धान्त ही दे सकते हैं। पर सकीर्ण साम्प्रदायिकता को राजनीतिमें स्थान नहीं मिलना चाहिए।

(६) सामान्य आर्थिक हित (Common Economic Interest). जानान और ऑस्ट्रेलियाकी राष्ट्रीयताका सबसे प्रमुख कारण सामान्य आर्थिक हित रहा है। निम्नन्देह आर्थिक उद्देश्य अन्य तत्वोंके साथ जातिमें एकताकी भावना पैदा करता है। ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिज्ञोंने युद्धके दौरानमें "श्वेत ऑस्ट्रेलिया-नीति" का जोरदार समर्थन इस भय के कारण किया था कि यदि प्रवासियोंके बारेमें लगे हुए प्रतिवन्ध हटा दिये गये या ढीले कर दिये गये तो आस्ट्रेलिया में मंगोल और भारतीय आकर भर आयगे और आस्ट्रेलियन लोगोंके आर्थिक जीवनको सबटमें डाल देंगे।

किसी जाति को एक सूत्रमें बांध रखनेमें सामान्य आर्थिक हितोका चाहे कितना ही महत्व हो, पर हम यह नहीं मानते कि केवल आर्थिक हितों ही राष्ट्रीयताकी भावना पैदा हो सकती है। यदि केवल आर्थिक हित ही राष्ट्रीयताके निर्माणके लिए पर्याप्त होंगे तो हमें मजदूरोंकी राष्ट्रीयता और पूँजीपतियोंकी राष्ट्रीयता देखनेको मिलनी। युद्धके समय राष्ट्रीयताकी भावना आर्थिक विभेदोंको पार करके विभिन्न आर्थिक हितोंवाले लोगोंको एक कर देती है। रेनन (Renan) का यह कहना ठीक है कि आर्थिक हितोंकी एकता एक सीमा-सुन्ध-मण (customs union)^१ का निर्माण करती है, एक राष्ट्रवा नहीं।

(७) सामान्य अधीनता (Common Subjection). कभी-कभी मजदूर और गुल्मवर्गियन सरकारकी अधीनता भी राष्ट्रीयताका सबल कारण होती है। अंग्रेजोंके गुदूद शासनने कुछ हद तक भारतीय राष्ट्रीयताका विकास किया है। इसी

^१ A territory treated as if one state for purposes of custom duties—Chamber's XX Century Dictionary—translator.

प्रकार दूसरे देशोंमें एक धाननकी आज्ञानुवर्तिगाने भी राष्ट्रीय भावना उत्पन्नकी है, यद्यपि यह राष्ट्रीयता बड़ी भयावह हुई है; जैसे हिटलर के अधीन जर्मनीमें और मुनोल्फिनी के अधीन इटलीमें। राष्ट्रीयताके लिए मुद्द सरकार चाहे जिननी महत्वपूर्ण हो, पर वह स्वयं राष्ट्रीयता उत्पन्न नहीं कर सकती। रैम्स म्योर (Ramsay Muir) का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि 'शासनकी एकता-भाव, वह चाहे जिननी सुन्दर डगकी हो, कभी स्वयः राष्ट्रीयताकी उत्पत्ति नहीं कर सकती'।

(८) सामान्य कष्ट (Common Suffering). कभी-कभी सामान्य मुसीबानोंने राष्ट्रीयतामें बड़ा शक्तिशाली योग दिया है। इतिहासमें इस बातके उदाहरण हैं कि अत्याचारोंने राष्ट्रीयताको मुद्द कर दिया है। जिमर्न (Zimmern) का कहना है कि "यूरोप में राष्ट्रीयताकी भावना राजनीतिक अत्याचारोंके फलस्वरूप निर्दयतापूर्वक सजग हो उठी है (८४: ७४)"। फ्रान्स और प्रमिया के बीच होनेवाली १८७० की लड़ाईके बाद फ्रान्सको राष्ट्रीय भावना बड़ी तीव्र हो गयी थी। मूरोंके अत्याचार और नेपोलियन के मुद्दोंने स्पेन वामियोंमें राष्ट्रीय भावना पैदा कर दी थी। पोलैण्ड के विभाजनने राष्ट्रीय भावनाको तीव्र बना दिया और अत्यन्त विरोधी परिस्थितियोंमें भी उसे जीविन रखा। अफेंगो द्वारा अत्याचार किये जाने पर दामरलैण्डकी राष्ट्रीयताने अत्यधिक उष और अवाछनीय रूप तक ग्रहण कर लिया। इन उदाहरणोंके होने हुए भी, जैसा जोसेफ (Joseph) ने कहा है: "जिमी एक वर्ग पर होनेवाला अत्याचार स्वतः उस वर्गको राष्ट्र या जाति नहीं बना देता। उसमें एक जाति अनेक स्वार्थी सम्प्रदायोंमें बंट भी सकती है। और प्रत्येक सम्प्रदाय अत्याचारीका कृपा-भाव बननेकी कोशिश करता है, जैसा कि प्रायः भारतीय इतिहासमें होता आया है।

(९) राजनीतिक सम्प्रभुता (Political Sovereignty). कभी-कभी यह दर्शन हो जाती है कि राज्यमें राष्ट्रीयता बनती है, राष्ट्रीयतामें राज्य नहीं बनता। इस दावेको मिट्ट करना बर्जित है। ग्रेट ब्रिटेन एक ही राजनीतिक सम्प्रभुताके अधीन है पर उसमें चार पृथक् राष्ट्रीयताएँ या जातियाँ सम्मिलित हैं। आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि आधुनिक राज्योंके स्थायी रूप धारण करनेके पहले भी राष्ट्रीयताओं या जातियोंका अस्तित्व रहा है फिर भी राजनीतिक सम्प्रभुताने विकासशील राष्ट्रीयताको मुद्द बनानेमें सहायता दी है। स्विट्जरलैण्ड जैसा अपवादोंको छोड़कर, जहाँ सम्भवतः सामान्य राजनीतिक सम्प्रभुताने राष्ट्रीयताको जन्म दिया है, राजनीतिक सम्प्रभुता अधिक-से-अधिक यही कर सकती है कि बर्तमान राष्ट्रीय चेतनाओं नवमान्य विधियों और राजनीतिक समस्याओं द्वारा और अधिक दृढ़ बनाये। राष्ट्रीयताकी जैसी परिभाषा हमने की है वैसी राष्ट्रीयता राजनीतिक सम्प्रभुता द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती।

(१०) सार्वजनिक इच्छा (Popular Will). सहयोग करनेकी इच्छा और "राष्ट्र बननेकी इच्छा" के महत्वकी हम सरलतासे उपेक्षा नहीं कर सकते। इन

दोनों पर डॉ० अम्बेदकर भारतीय राष्ट्रीयताके मिलसिलेमें बहुत जोर देते थे। उनके शब्दोंमें, "एकताकी सुसंयुक्त भावनाके कारण ही जिन लोगोंमें यह भावना होती है वे सब अपनेको एक दूसरेसे सम्बन्धित समझते हैं।" टॉएन्बी (Toynbee) "एक राष्ट्र बननेकी इच्छाको" राष्ट्रीयताका प्रधान तत्त्व मानते हैं। इसी प्रकार मैजिनी (Mazzini) मार्वांजनिक इच्छाको राष्ट्रीयताका आधार मानते हैं।

राष्ट्रीयताका आत्मनिर्णय (The Self-determination of Nationality). क्या प्रत्येक जाति या राष्ट्रीयताको स्वशासित सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य बननेका अन्तर्निहित अधिकार है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें राजनीति-शास्त्रके विद्यार्थी और व्यावहारिक राजनीतिज्ञ, दोनोंको रुचि है। वियना कांग्रेस (१८१५) से शुरू होकर पूरी १९वीं सदी भर योरोपीय राजनीति पर 'एक राष्ट्रीयता, एक राज्य' का सिद्धान्त छाया रहा। १९१४-१८ के विश्व युद्धमें इस सिद्धान्तको उस समय और अधिक बल मिला जब जातियोंके आत्मनिर्णयके अधिकारका सिद्धान्त मानने आया। इस सिद्धान्तके समर्थकोंका कहना है कि विभिन्न राष्ट्रीयताके लोगोंको एक साथ एक राज्यमें रखा देनेसे देशभक्ति की भावना नष्ट हो जाती है और आन्तरिक विवाद पैदा हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि एक राष्ट्रीयता विभिन्न राज्योंमें बिखरी हो तो वह कदापि सुखी और सम्पन्न नहीं रहे सक्ती और ऐसी राष्ट्रीयता एक विचलाग सामाजिक सङ्गठन (dismembered social organism) के समान है। ये बातें अब स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। अनेक लोग यह स्वीकार करते हैं कि और सब बातोंके समान होने पर राजनीतिक और राष्ट्रीय सीमाएं एक ही होनी चाहिए। जे० एम० मिल (J. S. Mill) अपनी पुस्तक "प्रतिनिधि सरकार" में लिखते हैं: "सामान्यतः स्वतन्त्रताके हितमें यह जरूरी है कि सरकारकी सीमाएं और राष्ट्रीयताकी सीमाएं एक ही हों।"

लॉर्ड ऐक्टन (Lord Acton) और अन्य अनेक विचारकोंका दृष्टिकोण इसके विपरीत है। लॉर्ड ऐक्टन का कहना है कि राष्ट्रीयताका सिद्धान्त [अर्थात् एक राष्ट्रीयता (जाति) एक राज्य] समाजवादके सिद्धान्तमें भी अधिक अर्थहीन और अपराधमूलक है। जिमर्न (Zimmern) लिखते हैं कि अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय राज्यके सिद्धान्तकी वही गति होगी जो आठवें हेनरी और लूयर के राष्ट्रीय धर्म-मण्डाने सिद्धान्तकी हुई थी। बर्नार्ड जोसेफ (Bernard Joseph) का कहना है कि 'एक-राष्ट्रीयता, एक-राज्य' का सिद्धान्त एक खतरनाक सिद्धान्त है और विश्वकी प्रगति में प्रधान बाधा है। उनका कहना है कि राष्ट्रीयता और राज्य दो भिन्न धारणाएं हैं और राष्ट्रीयताका अस्तित्व राज्यका अस्तित्व समाप्त हो जाने पर भी बना रहे सकता है। या तो एक राज्यमें एकसे अधिक राष्ट्रीयताओं और जातियोंका समावेश रहना है अथवा एक राष्ट्रीयता या जाति एक से अधिक राज्योंमें बिखरी रहती है। राष्ट्रीय निष्ठा और राज्यकी निष्ठा दो भिन्न वस्तुएं हैं और जोसेफ (Joseph) के अनुसार दोनोंका अस्तित्व एक साथ रहे सकता है क्योंकि राष्ट्रीयता केवल इनका

चाहती है कि सामूहिक और सामाजिक जीवनके लिए स्वाधीनता हो और कुछ हद तक यूय-स्वायत्तता (group autonomy) हो—बनाकर साम्प्रदायिक मामलोंमें। उनका विश्वास है कि भंमारमें शान्ति और व्यवस्थाकी आशा इस निदानके माने जानेमें ही है कि अनेक राष्ट्रीयताएँ या जानियाँ एक ही राज्यके भीतर सहयोग और शान्तिके साथ रह सकती हैं और उनमेंमें प्रत्येक अपने राष्ट्रीय जीवनका अनुगमन कर सकती है (४३: ३३१)।

हम प्रो० हॉकिंग (Prof. Hocking) के इस विचारसे महमत हैं कि किसी भी राष्ट्रीयता या जाति को एक राज्य बननेका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं प्राप्त है। हमारे सभी अधिकार शर्तों सहित (conditional) अथवा आनुमानिक (presumptive) होते हैं। रैम्से म्योर (Ramsay Muir) के शब्दोंमें 'मोटे तौर पर ही यह बात सही है कि प्रत्येक राष्ट्र या जातिको स्वाधीनता और एकताका अधिकार होना है। व्यक्तियोंकी भाँति राष्ट्रों या जातियोंको भी अपने अधिकारोंका अर्जन करना होता है।' 'किसी जातिको तभी जीवित रहनेका अधिकार है जब इस अधिकार के उपयोगमें स्वयं उसका और समाजका लाभ हो।' किसी सत्त या जाति या राष्ट्रीयता को राज्यका पद मिलना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय उस जातिको परिपक्वता पर, और कुछ अंशमें उसके आकार तथा उसकी दृढ़ता पर निर्भर करता है।

किसी राष्ट्रके स्वतंत्र और सम्प्रभु बन सकनेमें पहले उसमें निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है: (क) उसमें अपनी सम्पत्तिकी व्यवस्था करने और अपने प्राकृतिक माधनो तथा अपनी पूँजीका विकास कर सकनेकी क्षमता होनी चाहिए। (ख) उसे अच्छी विधियाँ बनानी चाहिए और न्यायकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। राज्यभेदातीत न्यायालयों (extra-territorial courts) की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। (ग) उसे एक उपयुक्त श्रृंगकी सरकार स्थापित करनी चाहिए। (घ) उसे व्यापार करने देने, श्रृंखला बढ़ा करने और यात्रा की अनुमति देने का अपना कर्तव्य स्वीकार करना चाहिए। (च) उसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलोंमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उसे राजदूतोंको अपने यहां आमंत्रित करना चाहिए, विवादोंमें मध्यस्थता स्वीकार करना चाहिए और सन्धिपत्र करनी चाहिए, आदि आदि। उसके पास ऐसे नागरिक होने चाहिए जो गौरवके साथ उचित ढंगमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनोंमें उसका प्रतिनिधित्व कर सकें। (छ) जब तक युद्धोंका होना जारी है तब तक उसे विदेशी आक्रमणोंमें अपनी रक्षा करनेमें समर्थ होना चाहिए।

क्या राष्ट्रीयता एक बरदान है? (Is Nationalism a Blessing?). अनेक विचारक राष्ट्रीयतावादके बहुत बड़े प्रशंसक और भक्त हैं। वे इसमें अच्छाईयाँ ही अच्छाईयाँ पाते हैं। पर अन्य लोगोंका कहना है कि व्यवहारमें राष्ट्रीयतावाद में अनेक बुरे परिणाम निकले हैं। इन लोगोंका विश्वास है कि राष्ट्रीयतावाद अपने वर्तमान रूपमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सद्भावनाका सबसे बड़ा शत्रु है। राष्ट्रीयतावाद पर अपने निबन्ध में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर

ने निस्मंकोच राष्ट्रीयतावादको बुरा कहा है। वह उसे समूची जातिका मामूहिक और सगठित स्वार्थ; 'आत्म पूजा' 'स्वार्थी उद्देश्योंकी सिद्धिके लिए राजनीति और व्यवसायका सगठन'; 'शोषण के लिए सगठित शक्ति' आदि कहते हैं। राष्ट्रीयता देशोके पारस्परिक सम्बन्धोको इतना कटु बना देती है कि एक दूसरेकी संस्कृति और सम्यताका ठीक-ठीक अध्ययन प्रायः असम्भव हो जाता है। हेज (Hayes) ऐसी राष्ट्रीयताकी निन्दा करते हैं जिसमें अपनी जाति या राष्ट्रके बारेमें तो अभिमान और गर्व रहता है और अन्य राष्ट्रोंके प्रति तुच्छता और विद्वेषके भाव रहते हैं। उनका कहना है कि १९वीं और २०वीं शताब्दीमें राष्ट्रीयतावादका इतिहास गौरवपूर्ण नहीं रहा है। शिलिटो (Shillito) के शब्दोंमें राष्ट्रीयता 'मनुष्य का दूसरा धर्म' बन गयी है। यह भावनात्मक (sentimental), मवेगात्मक (emotional) और प्रेरणा-मूलक (inspirational) है। किसी भी धर्मकी अपेक्षा इसके कहीं अधिक कट्टर अनुयायी हैं। यह सत्ताके लिए एक मन्देश रखनेका दावा करती है। आधुनिक समयमें राष्ट्रीय अधिकारों, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय नीतिके नाम पर लाखों व्यक्तियोंका जीवन और करोड़ोंकी सम्पत्ति बर्बादकी जा चुकी है। राष्ट्रीयतावाद विदेशोंमें घृणा करना सिखाता है। इस प्रकारकी आक्रामक राष्ट्रीयताकी 'भेड़ियोंकी आक्रामक राष्ट्रीयता' ठीक ही कहा गया है। और यही राष्ट्रीयता युद्धके बीज बोती है और निम्नतम कोटिके साम्राज्यवादमें बदल जाती है। इस प्रकारकी भेड़ियो-सी आक्रामक राष्ट्रीयता के उदाहरण सैनिकवादी जापान, फासिस्ट इटली और नाज़ी जर्मनी में मिलते हैं।

हम राष्ट्रीयताका पूरा-पूरा अर्थ तब तक नहीं समझ सकते जब तक सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रोंमें भी उसकी व्याख्या न की जाय। सांस्कृतिक क्षेत्र में तो राष्ट्रीयता एकता बढ़ानेवाली शक्ति रही है पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में वह विभेद उत्पन्न करनेवाली शक्ति ही रही है। अतिवादी आर्थिक राष्ट्रीयताका {जिसे आर्थिक आत्मनिर्भरताका नाम दिया गया है (Autarchy)} उद्देश्य पूर्ण आर्थिक आत्मनिर्भरता है। आर्थिक राष्ट्रीयता एक निश्चित सीमासे आगे बढ़ने ही मुश्किल कारण बन जाती है। यह एक ऐसा हथियार है जो लौटकर, चलानेवालेके मिर पर ही घातक चांद करता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता मूलतः है। पिछले वर्षोंमें वेनाइसामें गेहूँके जलाये जाने, अमेरिका में सेब और दूधके नदियोंमें बहाये जाने और ब्राज़ीलमें कॉफी समुद्रमें फेंके जानेके दृश्य हमने उम समय देखे हैं, जब कि मगारके अन्य देशोंमें लाखों व्यक्ति भूखसे मर रहे थे। आर्थिक आत्मनिर्भरता की इन आणविकताका मतलब यह नहीं है कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रोंको अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलोंमें पूरी छूट रहे। हम चाहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्रके भीतर भी और राष्ट्रोंके बीच भी आयोजित अर्थ-नीति बरती जाय।

ऊपर बनायी गयी आक्रामक राष्ट्रीयता और आत्मशोषक राष्ट्रीयतामें अन्तर हमें पहचानना होगा। आत्मशोषक राष्ट्रीयताका आदर्श है 'जियो और दूसरोंको जीनेमें

महायुद्धों को। ऐसी राष्ट्रीयता अपने पड़ोसी देशों, राष्ट्रों, सुदूर अफ्रीका या एशिया के पिछड़े प्रदेशों वगैरह समुद्र के द्वीपों को हड़पने की नीयत नहीं रखती। यह राष्ट्रीयता राष्ट्रीय आत्मसम्मान का पर्याय है। कभी-कभी इसे 'भेड़ों की आत्मरक्षा-मूलक राष्ट्रीयता' कहते हैं।

जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयता हमारे लिए जरूरी है। हमारा अस्तित्व ही राष्ट्रीयता पर निर्भर है; यह हमारे जीवन-मरण का प्रश्न है। यद्यपि अपने सारे दुर्भाग्यों के लिए विदेशियों को जिम्मेदार ठहराना मूल्यवाना है, फिर भी हममें कोई सन्देह नहीं कि अंग्रेजों की लम्बी गुलामीने हममें काफी बुराईया पैदा कर दी हैं जिनका वास्तविक प्रतिकार आत्मनिर्णय (self-determination) है। भय, वादरता और छलछन्द जैसी बुराईयों को राजनीतिक राष्ट्रीयता ही दूर कर सकती है।

राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हो जाने पर अब भारत को सांस्कृतिक और मानवतावादी राष्ट्रीयता की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। 'मानवता का आदर्श, एक लक्ष्य और पथ-प्रदर्शक के रूप में समस्त राष्ट्रों से ऊँचा है (हैलोवेल)।' अधिक तौर पर पिछड़े होने के कारण भारत को अगले कुछ वर्षों तक अपने उद्योगों की ही प्राथमिकता देनी होगी। पर हमारा लक्ष्य एक ऐसी सुविकारित राष्ट्रीय योजना होना चाहिए जो संसार की योजना का एक अभिन्न अंग हो।

राष्ट्रीयता एक लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। यह प्रेरणा-मूलक है। इसका मूल है मनुष्य की सामाजिक भावना और ब्यापली-मनोवृत्ति। एक यूहूदी अमेरिकी लेखक का कहना है कि 'लोग अपनी राजनीतिक, अपनी पालियों की, अपने धर्म की और अपने दार्शनिक निदानों को बदल सकते हैं पर वे अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते (३२ : १०८)।' पर राष्ट्रीयता नाम की चौड़ आजकल अक्सर एक 'जंगलीपन की देश-भक्ति' से अधिक कुछ और नहीं है; यह अक्रामक बट्टर-संघी साम्राज्यवाद है। इसलिए यदि हम फ्रैंज ग्रिलपार्जर (Franz Grillparzer) द्वारा बनाये गये 'मानवता में राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता में पारस्परिकता' वाले त्रय में अपने को बचाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हमारे लिए राष्ट्र 'एक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का, सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय सम्भावना का और मैत्री का विकास करे।' यह तभी किया जा सकता है जब उपर्युक्त मार्शजनिन सिद्धांत हो, संस्कृतियों का अन्तर्गमन और उनका विकास हो, जातीय अविहिताता दूर की जाय, दूरियों को परेगान करने वाले आयात-निर्गत-सम्बन्धी विधियों और प्रचलन-सम्बन्धी प्रतिवन्धों को हटाया जाय, निराश्रयता दूर हो और चरम सम्भ्रमण के पिटे-पिटारे निदानों का परित्याग किया जाय। हेज (Hayes) के शब्दों में 'राष्ट्रीयता अब विमुक्त देश-भक्ति का पर्याय बन जायगी तब यह मानवता और समस्त मनुष्यों के लिए एक अनुपम सदान निद होगी (३२ : २०५)।'।

ऐसी ही राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता का मार्ग बन सकती है। 'एक आदर्श अन्त-

राष्ट्रीय ससारका अर्थ एक ऐसा ससार है, जिसमें सभी राष्ट्र अपनी श्रेष्ठतम स्थितिमें हों (४३ : ३३८)।' विश्वके भावी कल्याणके लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीयता के हितमें न केवल हमारे दिमागको शिक्षित किया जाय, बल्कि हमारी इच्छाओं और हमारी भावनाओंका भी सुस्कार किया जाय। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अलगपनको प्रवृत्तिको दूर करे और पारस्परिक सहयोग और समझौतेकी भावनाको बढावा दे—ऐसी शिक्षा जो हमारी दाम-वृत्तिको समाप्त कर सके, हमारे भीतर विवेक-बुद्धि जाग्रत् कर सके और स्वयं निर्णय लेनेकी शक्ति दे सके (३२ : २७२)।' अपनेको दूसरोंसे अलग रखनेवाली राष्ट्रीयताका और जातीय उच्चताका सिद्धान्त आधुनिक ससारके अभिशाप है।

साम्राज्यवाद (Imperialism)

साम्राज्यवादका अर्थ (The Meaning of Imperialism). कुछ लोगों की राममें साम्राज्यवादका अर्थ है, शुद्ध भौतिक लाभके लिए कमजोर जातियोंका आर्थिक शोषण और उन पर राजनीतिक प्रभुत्व। हमारे लोग उसे पिछड़े हुए देशोंके प्रति प्रगतिशील देशोंका ऐसा पावन कर्तव्य मानते हैं जिसे पूरा करनेमें प्रगतिशील देशोंकी हिचकना नहीं चाहिए। ये दोनों ही दृष्टिकोण अतिवादी हैं। पिछड़े हुए देशोंका निर्दयतापूर्वक शोषण करनेकी एक सावधानीपूर्वक सुविचारित कार्य-योजना साम्राज्यवादके इतिहाससे उतनी ही परे है, जितना परे दूसरोंको सम्य बनानेका सुविचारित पवित्र ध्येय है जिसे श्वेतांगोंका भार (white man's burden) कहकर इन शब्दोंका बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया है।

साम्राज्यवादकी एक ऐसी परिभाषा दे सकना बहुत कठिन है जो प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकारके साम्राज्यों पर सटीक लागू हो सके। आधुनिक युगमें ही साम्राज्यवादने अनेक रूप धारण किये हैं। ऐसा कोई स्वतः सिद्ध प्रमेय नहीं है जिसके द्वारा यह निश्चय किया जा सके कि 'साम्राज्यवादका झण्डा व्यापार का अनुगमन करता है या व्यापार झण्डेका अनुगमन करता है।' कुछ साम्राज्योंका जन्म सों आश्रितिक घटनाओंमें हुआ है और कुछ साम्राज्य, जानबूझकर पहलेसे बनायी गयी योजनाओंके परिणाम हैं। प्राचीन साम्राज्य अधिकतर कर बमूल करने और सैनिक भरती करनेके साधन थे। हारे हुए राज्यों पर विजयी राष्ट्रोंके उच्चतर सैनिक बलकी अभिव्यक्ति इन साम्राज्योंके रूपमें होती थी। आधुनिक साम्राज्य अधिकतर आर्थिक और सामरिक उद्देश्योंके लिए होते हैं।

मो० डी० बर्न्स (C. D. Burns) का कहना है कि 'साम्राज्यवाद उम सामान्य पद्धति का नाम-मात्र है जिसके अनुसार विभिन्न देशोंमें विविधता बननी है और शासन होना है। यह क्षेत्रीय राष्ट्रीयता के जहर को मारता है और इसकी स्थिति क्षेत्रीय राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता के बीचोबीच यानी इन दोनों के समान

अन्तर पर है।' इस परिभाषाका बाद वाला अंश निश्चय ही यथार्थ नहीं है। यह अंग उम नीति के अन्तर्गत आता है जिसे प्रो० हॉकिंग (Prof. Hocking) 'वाक्यलकी नीति' (ethics of evasion) कहते हैं और 'यथार्थताकी नीति' (ethics of severity) के साथ जिसका विरोध बताने हैं। प्रो० शूमन का कहना है कि चाहे जितने बहाने किये जायें और नैतिकता का चाहे जितना टिकोरा पीटा जाय, यथार्थता यह है कि अधीन देशों पर शक्ति और हिमाके बल पर, विदेशी राज्य स्थापित रखना ही साम्राज्यवाद है।

सामाजिक विज्ञानों के विश्व-कोश में साम्राज्यवादकी जो काम चलाऊ परिभाषा दी गयी है वह यह है कि साम्राज्यवाद एक नीति है जिसका उद्देश्य एक साम्राज्यकी रचना, व्यवस्था और प्रतिष्ठा करना है। वह एक ऐसा राज्य है जिसका आकार बहुत बड़ा होता है जिसमें अनेक पृथक राष्ट्रीय इकाइयाँ शामिल रहती हैं और जो एक केन्द्रीय इच्छा के अधीन रहता है।' इस परिभाषाको हम यदि अंग्रेजी साम्राज्य पर लागू करने हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ तक साम्राज्य के स्वतन्त्र भागों का सम्बन्ध है, उनमें यद्यपि कुछ 'विशिष्ट आध्यात्मिक सम्बन्ध' है, फिर भी कोई एक केन्द्रीय इच्छा नहीं है क्योंकि प्रत्येक उपनिवेश को पूर्ण स्वायत्त अधिकार प्राप्त है जिसे कुछ लोगों ने 'औपनिवेशिक सम्प्रभुता' (Dominion Sovereignty) कहा है। जहाँ तक शेष साम्राज्य का सम्बन्ध है, केन्द्रीय इच्छा विभिन्न मात्राओं और रूपों में अपनेको व्यक्त करती है।

आधुनिक साम्राज्यवादका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि उपनिवेशीकरण उमका उतना महत्वपूर्ण अंग नहीं है जितना समारके पिछड़े हुए भागों का आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण है। इसलिए व्यापार, अतिरिक्त पूँजी लगाने (investment of surplus capital) और राजनीतिक नियंत्रण पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना है। दूसरे शब्दों में जिन उपनिवेशों में आबादी बनाई जा सकती है उनकी अपेक्षा उन उपनिवेशों का मूल्य अधिक है जिनका शोषण किया जा सकता है।

साम्राज्यवादके कारण (Causes of Imperialism). साम्राज्यवाद के कारण विभिन्न हैं। अपने प्रारम्भिक और आदिम रूप में साम्राज्यवाद मनुष्य की लुटेरी प्रवृत्ति का परिणाम था और इस प्रकारके साम्राज्यवादका आज भी अभाव नहीं है। निम्न-कोटिके जीवों में भी हम देखते हैं कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं और बन्दरों की एक जाति दूसरी जानिको नया आश्रय खोजने के लिए सदैव देती है। मही प्रवृत्ति हमें मनुष्यों में भी दिखायी देती है। चरागाहों, भोजन और अन्य ऐसी ही वस्तुओं की खोज में जानियों के समारके एक भाग में दूसरे भाग को जाने तथा एक बर्बाद द्वारा दूसरे बर्बाद के जीने जाने में मनुष्य की इस लुटेरी प्रवृत्ति का परिचय हमें पर्वत माता के किमी न किमी रूप में मिलता है। कहीं-कहीं यह प्रवृत्ति निर्दय आक्रमण और रक्तपात-पूर्ण युद्धों के रूप में व्यक्त होती है और कभी उच्चतर कोमल और चतुराई द्वारा तमिष इगने दूसरों को उनके स्थानों से हटाने का रूप धारण करती है।

जब हम प्रारम्भिक साम्राज्योको छोड़कर उत्तरकालीन साम्राज्यों पर विचार करते हैं तो हमें उनके विस्तारमें विजय-लालसा और शक्तिके लिए प्रतियोगिता मूलक सधर्प महत्वपूर्ण काम करता दिखायी पड़ता है। आधुनिक साम्राज्योंके निर्माण को सबल प्रेरणा निस्सन्देह ससारके मानचित्रको लाल या किमी और रंग से रंग देने की अनियंत्रित इच्छा से मिली है। सेसिल रोड्स (Cecil Rhodes) को इस बातका अभिमान था कि वह महाद्वीपोंकी बांटे सोचता था। उपनिवेशों और सैनिक सफलताओंको प्रायः राष्ट्रीय शक्ति और गौरव माना जाता है। प्रो० शुमन (Prof. Schuman) का विश्वास है कि आधुनिक साम्राज्यवाद शक्ति-प्राप्तिकी इच्छा और विजय-लालसाकी एक नयी अभिव्यक्ति है। १९३२ में मुसोलिनी (Mussolini) ने इस आदर्शको बड़े स्पष्ट शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त किया था: 'फासिस्ट राज्य, शक्ति और साम्राज्य-प्राप्तिकी इच्छा है। शक्तिका विचार ही रोमन परम्परा है। फासिस्ट सिद्धांतके अनुसार साम्राज्यवादका मतलब केवल प्रादेशिक, सैनिक, और व्यावसायिक विस्तार ही नहीं है। अपितु इसका मतलब आध्यात्मिक और नैतिक प्रसार भी है। फासिस्टवादकी दृष्टिमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तिका अर्थ है, राष्ट्रका विस्तार और राष्ट्रीय ओजकी अभिव्यक्ति। साम्राज्यवादका अर्थ है विस्तार।

देशोंकी बड़ी हुई आबादीको स्थान देनेके लिए भी उपनिवेशों की इच्छाकी जाती है। १९४१ तक जापानकी यही दलील थी। लेकिन उसके बाद दूसरे देशों पर अधिकार करनेकी अभिलाषा भी उसमें आ गयी। इटली भी वषों तक यही कहता रहा कि उसका 'सकीर्ण, पर सुन्दर प्रायद्वीप' उसके समियों लाख नियामियोंके लिए काफी नहीं पड़ता और इसलिए उसे नये उपनिवेशोंकी खोज करनी है। साम्राज्यवादको अधिक आबादीका प्रतिकार बताने वाले तकके बारेमें एक विशेष बात यह है कि व्यवहारमें यह तर्क इसी रूपमें कार्यान्वित नहीं होता। बहुत घोंडे ही जापानी कोरिया, फारमोसा और मन्चूरियामें बसने गये। लीबिया और इटैलियन सोमाली-लैण्डमें बसनेके लिए इटलीको छोड़कर जाने वालोंकी समस्या नगण्य थी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि किनी ने हमीमें कहा है, "किमी देशको छोड़कर जाने वालोंके बदले उम देशमें शीघ्र ही स्वर्गसे नये प्रवासी आकर बस जाते हैं।' अर्थात् जितने छोड़कर जाते हैं उतने ही नये पैदा हो जाते हैं।

आधुनिक साम्राज्यवादके सबसे अधिक मौलिक कारणोंमें से एक कारण आर्थिक है। आजकल समारके अधिकांश साम्राज्यवादी राष्ट्र अत्यधिक उद्योग विवर्गित राष्ट्र हैं जो कच्चे मालके लिए पिछड़े हुए देशों पर निर्भर करते हैं। डॉ० शाख्ट (Dr. Schacht) कहते हैं कि "कच्चे मालके लिए होने वाला मधर्प समारकी राजनीतिमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग लेता है। प्रथम महायुद्धके बाद से तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पर आखिरीमें पता चलता है कि सम्भवतः ब्रिटेनको छोड़कर अन्य कोई भी साम्राज्यवादी देश अधिकांश कच्चे मालके लिए अपने उपनिवेशों पर ही निर्भर नहीं रह सकता। पार्कर मून (Parker Moon) का

कहता है कि इस मामान्य धारणामें कोई मज्जाई नहीं है कि साम्राज्यवादी देशको अपने उपनिवेशोंमें पैदा होने वाले कच्चे मालका अधिकांश भाग मिल जाता है। वह लिखते हैं कि साधारणतया कच्चे माल रगान्ध होते हैं। वे किसी राष्ट्रीय झण्डेको नहीं पहचान पाते; वे मांस और पूतिका के नियमका पालन करते हैं, दूरी और यातायात के व्ययमें प्रभावित रहते हैं; राजनीतिक नियंत्रणके बजाय वे आर्थिक नियंत्रणके अधिक आजानुबर्ती होने हैं।

उपनिवेशोंका मूल्य कच्चे मालके उत्पादकोंकी अपेक्षा तैयार मालके बाजारों के रूपमें अधिक होता है। जोसेफ चेम्बरलेन (Joseph Chamberlain) का कहना है कि साम्राज्यका मतलब है वाणिज्य। अपने देशमें तैयार की गयी वस्तुओंको अपने उपनिवेशोंमें खपानेके लिए रियायती शुुगी (preferential tariffs) और वाणिज्य भेदभाव (Commercial discrimination) का सहारा लिया जाता है। एक उपनिवेशमें जिस देशका अधिकार होता है; उस उपनिवेशमें उस देशमें आने वाली वस्तुओं पर अन्य देशोंमें आने वाली वस्तुओं की अपेक्षा कम शुुगी लगायी जानी है। फलतः उस देशकी वस्तुएं अन्य देशोंकी वस्तुओंके मुकाबिलेमें मस्ती पड़ती हैं और अधिक विक्रती हैं। पर ये तरीके पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं। एंड्रयू कारनेगी (Andrew Carnegie) के कथनानुसार व्यापार किसी झण्डेके पीछे नहीं चलता, वह प्रचलित निम्नतम मूल्यके पीछे चलता है। आर० एल० ब्युएल (R. L. Buell) का अनुमान है कि 'ममारके व्यापारका केवल पाचवां भाग उन देशोंके माध्य होता है जो साम्राज्यवादी आधिपत्य में हैं; शेष ५ व्यापार स्वतंत्र देशोंके माध्य होता है। फिर भी, साम्राज्यवादसे एक औद्योगिक राष्ट्रके तैयार मालकी बिक्रीके लिए अतिरिक्त बाजार तो प्राप्त होते ही हैं (१३:३५१)।' सबसे अधिक ध्यान देनेकी बात यह है कि सामान्य जनताको साम्राज्यवादमें कोई लाभ नहीं होता। थोड़ेसे उद्योगोंको ही साम्राज्यवादमें लाभ होता है। इन उद्योगोंमें रुई, मोहा, इस्पात और तेलके उद्योग प्रमुख हैं। ईरानकी वर्तमान विप्लोटक स्थिति मनोरंजक अध्ययनकी वस्तु है। बहा साम्राज्यवाद और समाजवादका समर्थ हैं; एक दरिद्र बनाया गया राष्ट्र अपनी सम्प्रभुताके लिए और अपने प्राकृतिक साधनों यानी तेल का लाभ स्वयं पानेके लिए समर्थ कर रहा है।

साम्राज्यकी उपयोगिता और उसका मूल्य केवल यह नहीं है कि वह अतिरिक्त वस्तुओंकी बिक्रीके लिए बाजारका काम देता है, बल्कि उसकी उपयोगिता और महत्व इस बातमें भी है कि वहां अतिरिक्त पूंजी लगायी जा सकती है। मयूक्त राष्ट्र अमेरिका मध्य और दक्षिणी अमेरिकामें तथा ममारके दूसरे भागोंमें बड़ी-बड़ी पूंजी लगाकर उनकी आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियोंको प्रभावित करता है। इसे 'डालर-दूतनीति (Dollar diplomacy)' कहते हैं और यह उतनी ही प्रभावशालिनी होती है जितनी अधिकार करने वाले विदेशी सेना।

सरकारी और कूटनीतिक साधनोंका प्रयोग पिछड़े हुए देशोंको उन्नतिशील देशोंसे धन उधार लेनेके लिए मजबूर करनेमें न सही पर फुसलानेमें तो किया ही जाता है।

केवल साम्राज्यवादी देशोंकी सरकार द्वारा ही नहीं; बल्कि उन देशोंके व्यक्तिगत नागरिकों और गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा भी पूँजी उधार दी जा सकती है। यह बात उन देशोंमें खास तौरसे पायी जाती है जहाँ मजदूरी सस्ती होती है, मजदूर बहुत अधिक होते हैं और वे अपनी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होते। इस प्रकार के साम्राज्यवादके समर्थनमें बहुधा यह कहा जाता है कि यदि कोई देश अपने प्राकृतिक साधनोंका पूरा उपयोग नहीं कर सकता है तो किसी भी दूसरे प्रगतिशील देशको इस बातका प्राकृतिक अधिकार है कि वह उस देशके प्राकृतिक साधनोंका उपयोग करे; क्योंकि ससारके साधन उन लोगोंकी सम्पत्ति हैं जो उनका सबसे अच्छा उपयोग कर सके। पर यह तर्क सबल राष्ट्रों द्वारा दुर्बल राष्ट्रोंके पक्षमें कभी नहीं स्वीकार किया जाता। यदि यह स्वीकार किया जाय तो केनाडा, आस्ट्रेलिया और अफ्रीकाके कुछ हिस्सोंमें जो बड़े-बड़े भू-प्रदेश ऐसे पड़े हैं जिनमें कोई खेती-बाड़ी नहीं की जाती है उनको अपनी सम्पत्ति बनानेका सहज अधिकार जापान, चीन और भारत के लाखों गरीब, पर मेहनती लोगोंको मिल जाय। पर यह आशा करना व्यर्थ है कि साम्राज्यवादी दूसरोंका शोषण करते समय जो तर्क दूसरों पर लागू करते हैं वही तर्क अपने ऊपर भी लागू करेंगे।

साम्राज्यवाद कुछ चुने हुए थोड़ेसे लोगोंको ही अनेक प्रकारकी सुविधाएं देता है। वह विदेशी पूँजी लगानेका, विदेशी उप-वाणिज्य दूतों (pro-consuls), कूटनीतिज्ञों और विदेशी असैनिक प्रशासन-सेवकों (civil servants) को जगहें देनेका, तथा विदेशी सेनाके भरण-पोषणका बहुत बड़ा अवसर उत्पन्न करता है और इन सबका वर्दास्तके बाहर भारी खर्च आश्रित देशके निवासियोंके मध्ये मँड दिया जाता है। एमरी (Amery) महोदय भले ही रोषके साथ कहे कि 'भारत ने ब्रिटेनको कोई कर नहीं दिया' पर वह भूल जाते हैं कि ब्रिटेनके अर्धसरकारी इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफैयर्स (Institute of International Affairs) ने अपने वक्तव्यमें कहा है कि प्रत्येक चार अंग्रेजोंमें से एककी जीविका भारत पर सीधे निर्भर करती थी। जो देश विदेशी आधिपत्यके अधीन होता है उसकी नागरिक और सुरक्षा-सम्बन्धी अधिमेवाए निर्दिष्ट रूपसे सीमित रहती हैं। और विदेशी व्यापारी, सौदागर, बगीचे लगाने वाले (चाय आदिके) और सयुक्त पूँजीवाली कम्पनियाँ (joint stock companies) सभी उस देशके स्वशासन प्राप्त करनेके प्रत्येक प्रयत्नका विरोध करनेकी एक दृढ़ दीवार, बन जाने हैं।^१ इनके

^१ अल्जीरियामें जो कुछ हो रहा है उस पर दृष्टिपात करिए। अल्जीरिया को फ्रांस का एक भाग बनाया जा रहा है और वहाँके फ्रांसीसी प्रवासी अल्जीरिया-वासियों को स्व-शासन दिये जानेके हर प्रयत्नका विरोध कर रहे हैं।

अतिरिक्त जो दूसरे लोग साम्राज्यवादमें लाभ उठाते हैं और जिनसे निहित स्वार्थोंका एक वर्ग बनता है वे हैं जहाजोंके मालिक, शस्त्रास्त्रों और सैनिक सामानोंके निर्माता, सैनिकों और रेल्वे कर्मचारियोंकी बर्दियों और रेल्वे तथा समुद्री तार सम्बन्धी वस्तुओंके उत्पादक।

आधुनिक युगमें साम्राज्यवादका दूसरा महत्वपूर्ण कारण कूटनीति है। साम्राज्यवादसे साम्राज्यवादका जन्म होता है। स्वेज नहर में ब्रिटेन की गहरी रुचि, मित्र पर उसका अग्रत्यक्ष नियंत्रण, निकट पूर्वमें किसी न किसी रूपमें अपनी अधिकार सत्ता और मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए उसके प्रयत्न और ईरान पर उसका आशिक आधिपत्य आदि सबका रहस्य और महत्व भारत पर उसके भूतपूर्व आधिपत्यकी भूमिकामें ही समझमें आता है।^१ सिंगापुरका अग्नेयी जहाजी बेड़ा जापानको यह चेतावनी देनेके लिए था कि वह ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्वमें ब्रिटिश साम्राज्यके और किसी हिस्से पर कदम रखनेका साहस न करे। ऐसे ही सैनिक और समुद्री कारणोंसे फ्रांस ने कुछ समय तक जिबूटी (Jibuti, Somaliland protectorate) पर अपना नियंत्रण रखा था। अफ्रीकाके अधीन प्रदेशोंके वह अपने लिए फौजोंकी खान समझता था। दूसरे प्रदेशोंको हथियानेके प्रधान कारणोंमें से एक कारण अपनी सैनिक शक्तको बढाना है।

साम्राज्यवादियोंकी श्रेणीमें शामिल होनेवाले दो नये राष्ट्र हैं—सोवियत रूस और समुक्तराष्ट्र अमेरिका। यद्यपि दोनोंका साम्राज्यवाद एक ही प्रकारका नहीं है। सोवियत रूसका आरम्भ बड़े ही सुन्दर ढंगसे साम्राज्यवाद विरोधी शक्ति के रूपमें हुआ। पर रूस जल्दी ही राष्ट्रीयतावादी हो गया और फिर आगे चलकर १९३९ के बादसे वह साम्राज्यवादी और सैनिकवादी हो गया। रूस अपने साम्राज्यवादको आदर्शात्मक मानता है तथा वह अपने पिछलग्गू राष्ट्रोंकी नकेल अपने हाथमें रखता है। उसका प्रिय तरीका यह रहा है कि जो देश उसके प्रभावमें आ चुके होते हैं या जो देश उसके प्रभावमें आ रहे हैं उन सब देशोंकी कम्युनिस्ट पार्टियोंको अपना साधन बनाकर अपना काम निकाला जाय। ये राज्य सोवियत रूसको कोई राज्य-कर नहीं देते। पर रूस द्वारा उनकी अर्थनीति और राजनीतिका यदि नियंत्रण नहीं तो सूक्ष्म निरीक्षण अवश्य होता रहता है। इनमें से कुछ का उपयोग कभी-कभी रूस की उद्देश्य-सिद्धिके लिए साधन रूपमें भी होता है। स्तालिन की मृत्युके बादमें हालतें बदलने लगी हैं। रूस अपने कुछ पड़ोसी और पिछलग्गू राष्ट्रों पर अपना नियंत्रण

^१ आज परिस्थिति बदल गयी है। मित्र आज स्वतंत्र हैं और स्वेज नहर मित्रके अधिकारमें है। ईरान भी अपना शासन करनेके लिए और एक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रणमें अपने तेल-याधनोंके लाभ उठानेके लिए स्वतंत्र है। इस सारी हानिको पूरा करनेके लिए ब्रिटेनने बगदाद-सन्धिकी है जिसमें तुर्की, ईराक, पाकिस्तान और स्वयं यह शामिल है।

अब ढीला कर रहा है। पर हालमें उसने हगरीको अपने चंगुलमें कर लिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिकाने, द्वितीय विश्व-युद्धके बादसे स्वाम कर, अप्रत्यक्ष तौर पर साम्राज्यवादी-नीति अपनाई है। उमका प्रधान उद्देश्य समार भरमें सामरिक महत्वके समुद्री और हवाई अड्डोंको प्राप्त करना तथा राष्ट्रोंमें मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है ताकि साम्यवादको सीमित रखा जा सके जिससे अमेरिका बहुत ही भयभीत है। अमेरिकी साम्राज्यको प्रतिनिधि साम्राज्यवाद (Imperialism by proxy) या अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद कहा जा सकता है जैसा कि हिन्द चीन में था। यदि नेदर-लैंडकी सरकारको अमेरिकी सहायता न मिली होती तो हिन्देशिया बहुत पहले स्वाधीन हो गया होता। अमेरिका हिन्देशियामें जो कुछ करनेमें असफल रहा है वही काम उसने हिन्दचीन, मलाया और फॉर्मोसा में तथा प्रचान्त महासागरके कुछ सामरिक महत्वके द्वीपोंमें सफलतापूर्वक कर दिखाया है। अमेरिकाने पश्चिमी योरोपके साथ सैनिक सन्धि की है जो 'नाटो' (NATO) के नामसे प्रसिद्ध है। वह जापान, फिलिपाइन्स, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तानके साथ सैनिक सम्बन्ध जोड़ रहा है। योरोप और एशियाके अनेक देश, जैसे फिलिपाइन्स, दक्षिणी वियतनाम, थाईलैंड और पाकिस्तान प्रधानतः सैनिक सहायता द्वारा और गौणतः आर्थिक सहायता द्वारा अमेरिकाके प्रभावमें लाये जा चुके हैं। उधार पट्टा करार (Lend-lease Agreement) इस प्रकारका नियंत्रण स्थापित करनेमें महत्वपूर्ण साधन रहा है। अमेरिकी प्रभावमें जानेसे बचनेमें भारत अब तक सफल रहा है, यद्यपि उसने अमेरिकी गैरू खरीदनेके लिए कर्ज और बाकी मागमें मुपन आर्थिक सहायताको इतनाता पूर्वक स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघका मचालन कुछ इस ढंगमें किया जाता है कि उससे अमेरिकी वैदेशिक नीतिको ही बढ़ावा मिलता है। ब्रिटेन एक प्रकारसे अमेरिकाका नवीनतम "अपनिवेशिक प्रदेश" बन चुका है।

अमेरिकी लोग अब भी साम्राज्यवादकी पाप समझते हैं। उन्हे अब भी याद है कि ब्रिटेन के जाँज तृतीय के समयमें अमेरिकी उपनिवेशोंकी क्या दुर्गति हुई थी। पर वह यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आधिपत्य जमानेकी वर्तमान होड़में, राष्ट्रीय आकाशाओंके कुचलनेमें वे अप्रत्यक्ष रूपसे सहायक हो रहे हैं—विशेषकर एशियामें— तथा अन्य लोगोंके हित या अहितके एकमात्र निर्णायक बन रहे हैं जैसा कि आज जापानमें हो रहा है। चीन अब पूर्ण स्वतन्त्र है। अतः उसमें अमेरिका का कोई दखल नहीं है। पाकिस्तानको हथियारोंमें लैम करके और पाकिस्तानी सैनिकोंको प्रशिक्षित करके वर्तमान अमेरिकी नीति चीन-युद्धको भारतके दरवाजे तक ले आयी है।

साम्राज्यवादके समर्थनमें सभी-कमी धार्मिक और मानवतावादी तर्क भी दिये जाते हैं। १७वीं शताब्दीमें धर्म प्रचार साम्राज्यवादका एक महत्वपूर्ण कारण था। उस समय फ्रांस द्वारा द्याम का हस्तगत किया जाना अधिकतर जेसुइट (Jesuit) धर्म प्रचारकोंका काम था। धर्म प्रचारक साम्राज्य निर्माताओंमें से अफ्रीकाके डेविड लिविंग्स्टन (David Livingstone) का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है।

अफ्रीकामें ब्रिटिश साम्राज्यवादके विस्तारके साथ रुन्दनकी धर्म प्रचार समिति (Missionary Society) का नाम घनिष्ठताके साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिकाके भूतपूर्व राष्ट्रपति कॉल्विन कूलिज (Calvin Coolidge) का भी कहना था कि "जो सेनाएँ अमेरिका बाहर भेजती हैं वह तलवारोंके बजाय क्रॉस (ईसाइयो के धर्म-चिन्ह) से लैम होकर जाती हैं"। १९४५ में जापानकी पराजयके बाद जनरल मैकआर्थर (MacArthur) ने जापानके साथ भी ऐसी ही नीतिके बरते जानेका समर्थन किया था। आजकल साम्राज्यवाद पिछड़े हुए देशोंके निवासियोंको ईसाई बनानेकी ओरसे उदासीन है। कमो-कमो तो धर्म प्रचारकोंके कार्योंका विरोध भी किया जाता है, क्योंकि धर्म प्रचारकोंके कार्योंके फलस्वरूप अशोधित देशोंके निवासियोंमें नवीन प्रतिष्ठा और स्वाधीनता प्राप्त कर लेनेकी भावनाके उदय होनेकी आशंका रहती है। जहाँ कहीं ईसाई धर्म प्रचारकोंके साथ साम्राज्यवादियोंकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साठ-गाठ रही, जैसा कि पिछले दिनों था, वहाँ साम्राज्य निर्माता उनका खुले दिलसे स्वागत करते थे। इस बातके अनेक उदाहरण हैं कि धर्म प्रचारक व्यापारियों और शासकों के अपद्रुत थे।

श्वेतांगोंका बोझ^१ (the white man's burden) के पिटै-पिटाये नारे द्वारा एक विशेष प्रकारका मानवतावादी उद्देश्य व्यक्त किया जाता है। इसे "उत्तर-दायित्वका साम्राज्यवाद" (imperialism of responsibility) भी कहते हैं। इसमें जातीय उच्चता और गौरवकी भावना सूक्ष्म रूपसे छिपी रहती है। अपने सुन्दरतम रूपमें यह साम्राज्यवाद अज्ञानके स्थान पर ज्ञान, अविश्वसित शासनके स्थान पर व्यवस्थित और प्रगतिशील शासन और न्याय सम्बन्धी आदिम विचारोंके स्थान पर आधुनिक विचारोंको प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न करता है। इसका उद्देश्य मनुष्य भक्षण, दामता, अर्ध-दामता और मूढत्वोरीका विनाश करना है। आज हालत चाहे जो कुछ हो, पर मानवतावाद निश्चित रूपसे साम्राज्यवादका मूल कारण नहीं था। यह तो बादमें सोची हुई बात है। आजकल साम्राज्यवादके इस पहलू पर बहुत जोर दिया जा रहा है, यद्यपि यह सब केवल जबानी जमा-खर्च है। जो लोग बड़े उरमाहके साथ इसकी चर्चा करते हैं, वे भूल जाते हैं कि यदि "श्वेतांगोंका बोझ" सही मिथ्या है तो "अश्वेतांगोंका बोझ" भी तो बड़ी बाल्मविकता है और इसके लिए बाले लोगोंको अपनी स्वावलम्बन शक्ति, अपनी प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रीय आत्म-सम्मानने हाथ धोना पड़ता है।

मानवतावादी उद्देश्योंका इतना दिडोरा पीटे जाने पर भी मार्क्सवादी शिक्षा, सफ़ाई और अनताके उत्थान पर बहुत ही कम धन व्यय किया जाता है। जूलियन हक्सले (Julian Huxley) के कथनानुसार अफ्रीकामें बच्चोंकी मृत्यु संख्या २५ में सेकर १० प्रतिशत तक है; प्रत्येक बालिग अफ्रीकी एक या एकसे अधिक प्रकारके कृमियों

^१ इसका प्रचलित अमेरिकी समानार्थक वाक्य है 'सत्तारका नैतिक नेतृत्व'।

(worms) का शिकार रहता है जिनमें अकुशकिमि (hook worms) भी हैं और प्रायः मलेरिया से भी वे पीड़ित रहते हैं। कुछ क्षेत्रोंमें ९० प्रतिशत लोग गुप्त अगोंके रोगों (venereal disease) से पीड़ित रहते हैं जिन्हें श्वेतागाने ही वहाँ ले जाकर फैलाया है। साथ ही साथ लोगोंको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता और विटामिनकी कमी रहती है। अफ्रीकामें एक प्रतिशत बच्चे भी स्कूल नहीं जाते। इन सब बातोंको देखते हुए शुमन (Schuman) के इस कथनकी स्वीकार करना पड़ता है कि "साम्राज्यका उद्देश्य अपने जालमें फंसे लोगोंकी भलाई करना विस्तृत नहीं है। असली उद्देश्य तो अपने देशवासियोंका कल्याण करना और उन्हें समृद्ध बनाना है (७० : २६)"।

आधुनिक साम्राज्यवाद (Modern Imperialism). साम्राज्यवादने २०वीं शतीमें पहलेकी अपेक्षा अधिक अप्रत्यक्ष रूप धारण किये हैं। अब सलवारकी अपेक्षा कूटनीति और अन्तर्राष्ट्रीय करारों पर अधिक भरोसा किया जाता है, यद्यपि प्रदेशोंको बिना बात जीत लेना और हड़प लेना आधुनिक युगमें भी अनोखी बात नहीं है। जैसा कि एक लेखक ने कहा है आजकल व्यापार, उद्योग, रेलों, बन्दरगाहों, महत्वपूर्ण अड्डों, कच्चेमाल और तैयार माल तथा पूँजीके लिए बाजारों पर दाव लगाये जाते हैं।

आजकल संसारके अनेक भागोंमें साम्राज्यवादके निम्नलिखित अप्रत्यक्ष रूप पाये जाते हैं :

(१) पट्टा (Leasehold). कमजोर और पिछड़े हुए देशोंको अपने देशके कुछ हिस्सों पर से प्रायः ९९ वर्षोंके लिए अपना आधिपत्य हटा लेनेके लिए तैयार या विवश किया जाता है। ऐसा व्यावसायिक अथवा सामरिक कारणोंसे किया जाता है। राष्ट्रीय सम्प्रभुता तो नाममात्रके लिए पट्टा देनेवाले देशके हाथोंमें रहती है पर वास्तविक अधिकार पट्टेदार का हो जाता है। "पट्टे द्वारा प्राप्त भूमि पट्टेकी अवधि समाप्त होने तक पूरी तरहसे उपनिवेश हो जाती है (८ : ४४३)"। पट्टे द्वारा भूमिके हस्तान्तरणके उदाहरण हैं, चीन द्वारा १८९८ में २५ वर्ष के लिए रूस को दिये गये मन्चूरियाके बन्दरगाह, चीनके पोर्ट आर्थर और डायरेन बन्दरगाह जिन पर जापानका अधिकार रह चुका है और ब्रिटेनके आधिपत्यमें वीहाइवी (Wei-hai-wei, China 37.25 N, 122.13 E)। समुक्त राज्य अमेरिकाके पास पनामा नहरका पट्टा है और इस पट्टेमें नहरके दोनों तरफ पाच-पाच मील तक की भूमि शामिल है। इस पट्टेके चल पर संयुक्त राज्य अमेरिकाने पनामाके गणराज्य को व्यवहारतः अपना एक अर्ध-रक्षित राज्य (semi-protectorate) बना रखा है।

(२) संरक्षित राज्य और अर्ध-संरक्षित राज्य (Protectorate and Semi-protectorate). ये कई प्रकारके होते हैं। सभी संरक्षित राज्योंके वैदेशिक सम्बन्धों और सुरक्षा पर साम्राज्यवादी शक्ति का नियन्त्रण रहता है। कभी-कभी तो

आन्तरिक प्रशासनिक मामलों तथा आर्थिक मामलों पर भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ नियंत्रण रहती हैं। अंग्रेजी साम्राज्यमें एक मरझिन राज्यको स्थिति करोड़-करोड़ वर्षों होती है जो कि एक उपनिवेश (crown colony) की होती है, यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय विधिकी दृष्टिसे ये दोनों एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न हैं। मरझित राज्योंमें विदेशी शक्तियोंके साथ की सभी पुरानी सम्बन्धना कायम रहती है; पर उपनिवेशों में ऐसा नहीं होता। प्रायः मरझित राज्य अन्तर्गतता या तो साम्राज्यवादी देश द्वारा अपनेमें मिला लिये जाते हैं या उन्हें स्वतन्त्रता दे दी जाती है।

मरझित राज्यका सबसे अच्छा उदाहरण कुछ समय पूर्व तक मिस्र था। वैसे तो मिस्र को "स्वाधीनता" की घोषणा २८ फ़रवरी, १९२२ को कर दी गयी थी, पर १९३६ में ब्रिटेन और मिस्र के बीच मैत्री सन्धि होने तक यह स्वाधीनता इतनी बड़ी-छड़ी रही कि मिस्र सभी प्रकारसे ब्रिटेन का मरझित राज्य ही बना रहा। १९२२ की घोषणाके अनुसार अंग्रेजोंने अपने लिए निम्नलिखित चार बातें सुरक्षित रखी थीं: मिस्र में अंग्रेजी साम्राज्यके संचार (communication) की सुरक्षा; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विदेशी आक्रमण या हस्तक्षेपसे मिस्र की रक्षा; मिस्र में विदेशी स्वार्षीकी तथा अल्पमङ्गलकी रक्षा, और मूद्रा। कुछ लेखक मिस्र को अर्धसंरक्षित राज्य ही मानना अधिक पसन्द करते थे। आज मिस्र पूर्ण स्वतन्त्र है।

अर्ध-संरक्षित राज्योंके उदाहरण क्यूबा और हैटी हैं जो स्वयं अपने नामसे कुछ प्रकारकी सन्धियाँ कर सकते हैं पर विदेशी शक्ति बिन पर रोक लगा सकती हैं। संरक्षित राज्योंका एक दूसरा प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मरझित राज्य है जिसका एक उदाहरण कुछ समय पूर्व अर्जीन्टीना था। १९०६ में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली में हुए करारके अनुसार इन तीनों देशोंने अर्जीन्टीना की अखण्डताकी रक्षा करना और सुविधाएँ प्राप्त करनेमें एक दूसरेसे होड़ न करना, स्वीकार किया। पर यह करार रही कागजका टुकड़ा ही साबित हुआ।

(३) प्रभाव-क्षेत्र (Spheres of Influence). प्रभाव-क्षेत्रका मतलब यह होता है कि जिस शक्तिके हाथोंमें क्षेत्र होता है उसे 'बज्र' देने, रेलें निकालने, खानोंके खाने, खनन या सार्वजनिक कार्योंका विकास करनेके लिए बरीय (preferential) अधिकार या एकाधिकार दे दिया जाता है (८: ४४७)। प्रायः प्रभाव-क्षेत्र अन्तर्गतता या तो मरझित राज्य बना लिये जाते हैं या एकदम अपनेमें मिला लिये जाते हैं। यद्यपि वे न तो उपनिवेश और न आश्रित राज्य ही होते हैं। बर्मी-बर्मी तो सम्बन्धित बिजड़े राज्योंकी सहमतिके बिना भी ये क्षेत्र अलग कर लिये जाते हैं। बुटेल (Butell) का कहना है कि "इन प्रकारके निदोषनने हाइडे कम करनेके बजाय बड़ा दिव्य है (८: ४४८)।" आधुनिक युगमें एशिया, अफ्रीका तथा प्रशान्त महासागर में प्रभाव-क्षेत्र साम्राज्यवादके सुविधाजनक साधन रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के इशाम में प्रभाव-क्षेत्र थे।

बर्मी-बर्मी "प्रभाव-क्षेत्र" और "हित-क्षेत्र" (sphere of interest) में अन्तर

किया जाता है। 'हित-क्षेत्र' केवल अधिक होता है जब कि प्रभाव-क्षेत्रमें, एक मरुक्षित राज्यसे कुछ कम अस्पष्ट राजनीतिक सुविधाएँ भी रह सकती हैं। एशिया की अपेक्षा अफ्रीका में प्रभाव-क्षेत्र अधिक रहे हैं।

(४) संयुक्त विदेशी शासन (Condominium). संयुक्त विदेशी शासनका मतलब है किसी विवाद ग्रस्त क्षेत्र पर औपनिवेशिक होड़ बचानेके लिए दो या अधिक राज्योंका नियंत्रण। ऐसा नियंत्रण ब्रिटेन और मिस्र का सूडान में नील नदीके पानी पर, मोरक्को के टेंजियर शहर पर फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन का और न्यू हैन्ड्रीड्स पर फ्रांस और ब्रिटेन का रहा है। इस प्रकारका नियंत्रण न तो उन विदेशी राष्ट्रोंकी ही सन्तुष्ट कर पाता है जिनका नियंत्रण होता है और न उन देशवासियोंको ही जो उस नियंत्रणमें रहते हैं। इस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण प्रायः सर्वदा अमनोपजनक रहता है और अन्ततोगत्वा हमेशा असफल सिद्ध होता है। इसका अर्थ विभाजित उत्तरदायित्व है।

(५) वित्तीय नियंत्रण (Financial Control). "ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें पूँजीपति देश सरकारी कर्मचारियों या बैंकोंके प्रतिनिधियोंके माध्यम से पिछड़े हुए देशोंकी सरकारोंकी आय और व्ययका नियंत्रण करते हैं, यद्यपि अन्य बागोंमें ये देश स्वतंत्र होते हैं (२४५५)।" इस प्रकारका नियंत्रण कई राज्यों द्वारा मिल-जुल कर अथवा एक ही राज्य द्वारा किया जा सकता है। एक ही राज्य द्वारा किये जाने वाले नियंत्रणका उदाहरण है कैरीबियन और मध्य अमेरिकी राज्यों तथा लाइबीरिया और ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का वित्तीय नियंत्रण।

(६) चुंगी नियंत्रण (Tariff Control). स्वयं लाभ उठानेके लिए पश्चिमी शक्तियोंने बहुधा पिछड़े देशोंको इस बातके लिए विवश किया है कि वे विदेशी वस्तुओं पर चुंगी एक निश्चित सीमासे अधिक न बढ़ायें। इस प्रकारका नियंत्रण जापान पर १९११ तक रहा। चीन, तुर्की, मोरक्को, इरान और ईरान पर भी इस प्रकारका नियंत्रण रह चुका है। इस नियंत्रणका उद्देश्य यह रहा है कि पश्चिमी राज्योंको अपना माल पिछड़े हुए देशोंमें पाट देने और इस प्रकार उनके अपने देशी उद्योग-व्यवसायोंके विकासको रोकनेका अवसर मिले।

(७) बहिर्देशिता (Extra-territoriality). इसका मतलब है विदेशी सरकार द्वारा पिछड़े देशोंमें रहनेवाले अपने देशवासियोंके लिए अपनी अदालतें स्थापित करनेका अधिकार। इस अधिकारका आधार यह बतलाया जाता है कि पिछड़े देशकी अपनी ऐसी कोई विवेकपूर्ण न्याय प्रणाली नहीं है जो सब पर लागू की जा सके। इस प्रकारके बहिर्देशीय अधिकारकी मांग प्रायः सभी मुसलमान देशोंमें, जहाँ ईसाइयों को बहुत कम अधिकार दिये जाते हैं और जापान, इरान, कोरिया तथा चीनमें की गयी, और सभी जगह यह दावा स्वीकार कराया गया। जब ये देश न्यायके पश्चिमी मान-दण्डोंको स्वीकार कर लेते हैं और तदनुसार अपनी न्यायप्रणाली में सुधार कर लेते हैं तब धीरे-धीरे विदेशी शक्तियाँ अपने बहिर्देशीय

दावाओंको छोड़ देती हैं। इस प्रकार १८९४ में मयुक्त राज्य अमेरिकाने जापान पर मे और १९२४ में संविमत संधि ने चीन पर मे अपने दावाओंको ममान कर दिया। तुर्की ने यही बहिर्देशीय अधिकारोंको ममान कर दिया है। द्वितीय विश्व-युद्ध आरम्भ हो जानेके बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने चीनमें अपने बहिर्देशीय दावाओंको छोड़ दिया। प्रायः इन अधिकारोंका प्रयोग प्राद्वनिक न्यायालयों (consular courts) अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा किया जाता है, और जैसी आगा की जाती चाहिए, इन अधिकारोंका दुरुपयोग हो जाता है। बहिर्देशीयताका अर्थ स्थानीय करोंसे मुक्ति भी लगाया जा सकता है। कभी-कभी विदेशियों द्वारा कानून कायम बना लिये गये देशों लोगोंको भी बहिर्देशीयताके अधिकार दिलाये जाने हैं।

(८) अनौपचारिक नियंत्रण (Informal Control) कभी-कभी कुछ विदेशी देश आपसमें सौद-गोठ करके किसी निष्ठे राष्ट्रकी सरकारको स्वीकार करनेसे ठव तक के लिए इन्कार कर देते हैं जब तक उनके कूटनीतिकों द्वारा रखी गयी कुछ शर्तोंको वह राष्ट्र पूरा न कर दे। ब्यूल (Buell) इस प्रकारके नियंत्रण को बाह्यवर्षिक (extra legal) या चार मीटी (back stairs) वाला अथवा अतत्पक्ष नियंत्रण कहते हैं। इस प्रकारका नियंत्रण अनेक ठगोंसे किया जाता है। निकासगुआ, सान्टो डोमिंगो तथा कैरीबियन आदिमें सयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी जलसेनाका उपयोग किया है। ईरान, मिस्र और ईराकमें ब्रिटेन ने अपने देशवासियोंको मनाहकारोंके रूपमें—विशेषकर विनीय मामलोंमें—रखनेका तरीका अपनाया था।

खुला द्वार और बन्द द्वार (The Open Door and Closed Door). दिवली गलाबदीमें चीन पर खुला द्वार नीति लागू करनेके लिए उसे कई बार दृढ़में पसींदा गया। इस नीतिका मतलब है व्यापारकी इच्छुक सभी विदेशी शक्तियोंको दिखड़े हुए देशमें व्यापार करनेकी सामान्य सुविधाओंका दिया जाना। इन नीतिके अनुसार किसी भी विदेशी राष्ट्रके माल या नागरिकोंके साथ किसी भी प्रकारका विवेद नहीं किया जा सकता। कभी-कभी खुले द्वार नीतिको जहाजरानों और बम्बोंके सम्बन्धमें भी लागू किया जाता है। इन नियमनमें इन नीतिका मतलब होता है, साम्राज्यवादी राष्ट्र तथा अन्य विदेशी राष्ट्रोंके लिए अवसरकी समानता। अमेरी साम्राज्यमें यही नीति बरती जाती रही है, पर आजकल उसमें काउरी संशोधन हो गये हैं। मना-कारित प्रणाली (mandatory system) के अनुसार प्रथम और द्वितीय धर्मोंके समानाधिकार प्रदेशोंमें खुला द्वार नीतिका अपनाया जाना जरूरी था। इन संघर्षों राष्ट्र सभके हर सदस्यको पूर्ण आपिक, व्यावसायिक और औद्योगिक समानता प्राप्त हो सकती थी। तृतीय धर्मोंके मनाकारित प्रदेशोंमें खुला द्वार नीति अपनाया आवश्यक नहीं था। दुरुपयोग द्वारा नीतिवा परिणाम यह होता है कि विदेशी शक्तियोंमें पातक प्रतिस्पर्धिता होने लगती है। इसलिए इन प्रतिस्पर्धितासे बचनेके लिए कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगका सम्मान अपनाया जाता है। मशीन सरकारकी

स्थापनाके पहले चीनमें किसी भी एक राज्य या राज्योंके गुटको कर्ज देकर राजनीतिक सुविधाएँ हासिल करनेकी आज्ञा नहीं थी।

बन्द द्वार नीति खुला द्वार नीतिकी उल्टी है। इसका अर्थ है न केवल व्यापार व्यवसायके क्षेत्रमें बल्कि जहाजरानी, पूँजी लगाने (investment) और बस्ती बनानेमें भी विशेष सुविधाएँ और एकाधिकार देना तथा विदेशी राष्ट्रोंके बीच विभेद करना। उपनिवेश और मातृ-देशके बीच आर्थिक सम्बन्ध मजबूत करना और अन्य देश वालों की लाम न उठाने देना, उसका उद्देश्य होता है। समुक्तराज्य अमेरिकाने फिलिपाइन द्वीपोंमें कई वर्षों तक यही नीति बरती। शुमन (Schuman) का कहना है कि यह नीति पुरानी व्यापारी-पद्धति (mercantalistic system) का शेषांश है।

बन्द द्वार नीति प्रायः इन तीन रूपोंमें बरती जाती है— (क) चुगी (tariffs), (ख) जहाजरानी, (ग) रियामते। कुछ देश चुगी समीकरण (tariff assimilation) की नीति अपनाते हैं, जिसके द्वारा मातृ-देश और उपनिवेशके बीच मुक्त व्यापार होता है अर्थात् आपसमें चुगी नहीं लेते-देते और दोनों ही देश अन्य देशोंके प्रति चुगीकी एक ही प्रणाली लागू करते हैं। कुछ दूसरे देश चुगी बरीयता (tariff preference) की नीति अपनाते हैं। इसके द्वारा मातृ-देश और उपनिवेशकी चुगी प्रणालियाँ भिन्न होती हैं, पर दोनों ही देश एक दूसरेके मालके लिए विशेष रियामते देते हैं।

ब्युएल (Buell) का यह कहना सही है कि बन्द द्वार नीतिका मतलब उपभोक्ताके लिए बड़ी हुई कीमतें हैं। उपनिवेशमें रहने वालेके लिए यह नीति एक नये प्रकारका शोषण है। शोष समस्त संसारके लिए इसका मतलब निम्नतम कीटिके राष्ट्रीयतावादी साम्राज्यवाद (nationalistic imperialism) को स्थायी बनाना है (पृ. ४२६)।”

सैनिक गठबन्धन (Military Alliances). वैसे तो सैनिक गठबन्धन हमेशा होते रहे हैं पर आज वे नया महत्व ग्रहण कर रहे हैं। इन गठबन्धनोंमें शामिल होनेवाली राष्ट्र प्रायः अपनी सम्प्रभुता बनाये रहते हैं पर वे एक सामान्य सैनिक नीति बरतते हैं; बहुधा ऐसा किसी शक्तिशाली राष्ट्रके सरक्षणमें किया जाता है। ऐसे गठबन्धनोंके उदाहरण हैं, अमेरिकी देशों द्वारा सन्स्थास्थोत्रा स्तरणीकरण और एक सामान्य सैनिक नीतिका बरता जाना; नाटो, सीटो, और बगदाद सन्धिपत्रोंमें शामिल राष्ट्रोंके बीच पारस्परिक सैनिक सहायता आदि।

समाज्ञाएँ (The Mandates). प्रथम विश्व-युद्धके दौरानमें बड़ो विज्ञान ने जिस आदर्शवादकी नींव डाली थी उसीका मूर्तरूप समाज्ञापित प्रणाली है जिसकी व्यवस्था राष्ट्रमण्डलके प्रसविदा (covenant) की २२वीं धारामें की गयी थी। योरोपीय देशोंमें पहले जो युद्ध होते थे उनका नतीजा यह होता था कि विजयी देश पराजित देशोंके औपनिवेशिक प्रदेशोंको हूब लेते थे। वारसाई के शान्ति-सम्मेलनमें यह कहा गया कि पिछड़ी जातियोंके अधिकारोंकी रक्षा भिन्न-राष्ट्रोंका प्रधान

कर्तव्य होना चाहिए और किसी भी मित्रराष्ट्रको पराजित शत्रु देशोंके किसी भी औपनिवेशिक प्रदेशका एकमात्र स्वामी बननेका अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसी उद्देश्यसे समाज्ञापित प्रणाली (mandatory system) की व्यवस्था की गयी। इस प्रणालीके निम्नलिखित उद्देश्य थे: (क) उपनिवेशोंके मूलनिवासियोंके हितोंकी रक्षा करना और (ख) साम्राज्यवादी शक्तियोंके बीच परस्पर सघर्ष और प्रतियोगिताका अवसर न आने देना, क्योंकि यदि सघर्ष और प्रतियोगिताको रोकना न गया तो भविष्य में युद्ध अनिवार्य हो जायेंगे। इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि जिन क्षेत्रोंमें लोग अपने पैरों पर खड़े होनेमें असमर्थ हैं उन क्षेत्रोंके लिए न्यासधारी नियुक्त किये जायें। ये न्यासधारी उन क्षेत्रोंके शासनकी बागडोर अपने हाथोंमें तब तक रखें जब तक कि वे क्षेत्र स्वयं अपना शासन करने योग्य न हो जायें। राष्ट्रपति विस्तारकी इच्छाके विस्तृत विरुद्ध समाज्ञापित प्रदेशोंको प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियोंमें बांटा गया। इसके लिए दलील यह दी गयी कि भूतपूर्व शत्रु देशोंके लिये गये सभी प्रदेश विकासकी एक ही स्थितिमें नहीं हैं। इसलिए उनकी अलग-अलग आवश्यकताओंके अनुकूल विभिन्न शासन-प्रणालियाँ आवश्यक हैं। प्रथम श्रेणीके समाज्ञापित प्रदेशोंको निकट भविष्यमें स्वाशासन प्राप्त करनेके लिए सबसे अधिक योग्य और तृतीय श्रेणीके प्रदेशोंको सबसे अधिक अयोग्य समझा गया। द्वितीय श्रेणीके प्रदेशोंको इन दोनोंके मध्यमें रखा गया। इन समाज्ञापित प्रदेशोंका रक्षण (tutelage) "उन्नत राष्ट्रों" को सौंपा गया और इन राष्ट्रोंके लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे अपने कार्यकी वार्षिक रिपोर्टें हर साल राष्ट्र-संघकी कौंसिलके सामने पेश किया करें। समाज्ञापित प्रदेशोंमें न्यासधारी देशोंके शासन-कार्य के देख-भाल के लिए राष्ट्र-संघकी कौंसिल अपनी स्थायी समाज्ञा आयोग (Permanent Mandates Commission) के माध्यमसे करती थी।

यद्यपि समाज्ञापित प्रणालीका निर्माण युद्ध हृदयसे किया गया था पर जो उच्च आशाएँ इससे की गयी थी वे पूरी नहीं हुईं। समाज्ञापी शक्तियों (mandatory powers) ने समाज्ञापित प्रदेशों के कार्य-भारको जबरदस्ती लादी गयी 'सम्पत्ता प्रसारकी जिम्मेदारी' (Trusts of civilisation) माननेके बजाय उन्हें अपने विजित प्रदेश (annexations) समझना शुरू कर दिया। शुमन (Schuman) लिखते हैं: "तृतीय कोटिके समाज्ञापित प्रदेश तो करीब-करीब विजित प्रदेश ही समझे जा रहे हैं और द्वितीय कोटिके समाज्ञापित प्रदेशोंका शासन उस शासनसे शायद ही भिन्न कहा जा सके जो सीधे-सीधे युद्धमें जीते गये प्रदेशों पर लादा जाता है। प्रथम श्रेणीके समाज्ञापित प्रदेशों पर भी समाज्ञापी राष्ट्रोंका प्रभावपूर्ण नियंत्रण रहता है (८: ६१७)।" केवल ईराक को छोड़कर सभी समाज्ञापित प्रदेशोंमें जनताकी स्वतंत्रता और स्वशासनकी वंश इच्छाओंको निर्दयतापूर्वक कुचला गया। अपना समाज्ञापी चुननेके मामलेमें भी समाज्ञापित प्रदेशोंकी इच्छाको ठुकरा दिया गया, जैसा कि सीरियाके मामलेमें किया गया। सीरिया ने मांग की थी कि उसे

अमेरिकाके मुपुर्द किया जाय; और यदि ऐसा न हो सके तो फिर ब्रिटेनके मुपुर्द किया जाय। अमेरिका और ब्रिटेन इन दो में से ही किसी एक को उसने पसन्द किया था। पर फिर भी उसे फ्रांस के हाथोंमें सौंप दिया गया। १९३२ में ईराक को एक स्वतंत्र अंग्रेजी सरक्षित राज्य घोषित किया गया, पर उसकी 'स्वाधीनता' मिस्र की स्वाधीनतासे अधिक वास्तविक नहीं थी। सीरिया की हालत और भी अधिक दोषनीय थी। फ्रांस और सीरिया के लोग एक दूसरेको समझने और एक दूसरेसे सहयोग करनेमें स्वभावतः असमर्थ मालूम पड़ते थे।

समाज्ञापित प्रणालीमें एक अच्छाई यह थी कि उसमें प्रभावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षणकी बहुत कुछ व्यवस्था थी। पर, जैसा प्रोफेसर शुमन (Schuman) ने कहा है, "समाज्ञापि आयोग (Mandates Commission) ने एक स्वतंत्र और साहसी सत्ता के रूपमें ओजके साथ काम नहीं किया।" उनके मुद्दाव केवल परामर्श के रूपमें होते थे और कोई भी उन्हें माननेके लिए मजबूर नहीं था। समाज्ञापित प्रदेशोंकी जनता की पहुंच समाज्ञापि आयोग तक उतनी नहीं थी जितनी समाज्ञापि राष्ट्र शक्तियोंकी थी। यदि समाज्ञापित प्रदेशोंकी जनता समाज्ञापि आयोगको कोई प्रार्थनापत्र देना चाहती थी तो वह प्रार्थनापत्र समाज्ञापि सरकारके माध्यमसे ही आयोग तक पहुंच सकता था। १९२७ के बाद राष्ट्र-मंषकी कौंसिल ने प्रार्थियों को मौखिक साक्ष्य (oral evidence) की सुविधा भी अस्वीकार कर दी। आयोग ने समाज्ञापित प्रदेशोंमें जाकर स्वयं यह कभी नहीं देखा कि समाज्ञापि शक्तियों ने अपने अधीन रक्षित जनताको सम्य बनाने और उनमें से जो अधिक उन्नत थे उन्हें सुशासनके योग्य बनानेका कार्य कहा तक पूरा किया है। उसने समाज्ञा प्रथाके खुले आम दुरूपयोगोंकी जांच करनेके लिए कोई समिति भी नहीं भेजी। इस प्रकार समाज्ञापित प्रदेशोंकी जनताके विरुद्ध पलड़ा बहुत भारी रहा।

इन बुराइयोंके बावजूद समाज्ञा प्रणाली उपनिवेशीय प्रणालीसे निश्चित तौर पर अच्छी थी। यह ठीक दिशा में उठाया गया एक कदम था, यद्यपि कदम बहुत छोटा था। उपनिवेशोंकी जनता के हितोंकी अपेक्षा समाज्ञापित प्रदेशोंकी जनताके हितोंकी रक्षा अधिक हो सकी। जनताको अन्तःकरण और धर्मकी स्वाधीनता मिली और दास व्यापार (slave trade), शस्त्रास्त्रों तथा शराबका त्रय-विक्रय बन्द कर दिया गया। आवश्यक मार्गजनिक कार्योंको छोड़कर अन्य कार्योंमें बेगार (forced labour) ने और मजदूरीके ठेकोंमें बेईमानीसे जनताकी रक्षा की गयी। सरकारकी स्पष्ट मजदूरीके बिना समाज्ञापित प्रदेशोंकी जनताको अपनी भूमि विदेशियोंको हस्तान्तरित करनेमें रोक दिया गया।

इनमें से अधिकांश मरक्षण केवल बागज पर ही रहे। पर उनमें एक अच्छाई यह थी कि समाज्ञा आयोगकी रिपोर्टका राष्ट्रमंषकी असेम्बलीमें पहुंचने पर, प्रचार हो जाता था। साम्राज्यवादी देश जो काम किसी समय बिना किसी मय या हानिके कर सकते थे वही काम अब सभारके जनमतकी बठोर आलोचनाका खतरा उठाये

बिना नहीं किया जा सकता था। दक्षिणी-पूर्वी अफ्रीकाके बॉण्डेलज्वार्टम् मामलेमें जिसमें समाजवादी चर्कि ने अत्याचार किये थे अपनी सम्मति देने हुए समाजवादी आयोगके अध्यक्ष ने माहमपूर्वक कहा था : "भवमें पहले देगवानियोंके हितोंको महत्व दिया जाना चाहिए। उनके बाद ही श्वेतांगोंके हितोंकी बारी आती है। श्वेतांगोंके हितों पर विचार केवल उन्नी गीमा तक किया जाना चाहिए जहां तक मूल निवासियोंकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रक्षामें उनका सम्बन्ध हो।"

दोनों विश्व-युद्धोंके बीचकी अवधिमें संसारका जनमत अधिकधिक उन पिछड़े हुए प्रदेशों पर प्रभावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण और नियंत्रण रखनेके पक्षमें होता गया जो स्वयं अपने पैरों पर खड़े होनेमें असमर्थ थे। कुछ विचारकोंका कहना था कि वास्तवमें पिछड़े देशोंको अन्तर्राष्ट्रीय समाजके अन्तर्गत रखना चाहिए। और वह भी एक निश्चित उद्देश्य और एक निर्धारित अवधिके लिए ही। इसके विपरीत लार्ड लुगार्ड (Lord Lugard) जैसे अनुभववी औपनिवेशिक राजनीतिज्ञका कहना था कि "राष्ट्रीय भावनामें विहीन और देश-प्रेमका गला घोटनेवाले कर्मचारीनृप (bureaucracy) के कारण इस पद्धतिमें सारी पहलकदमी को लंबा मार जायगा। और यह पद्धति सम्बन्धित देशोंके लिए बहुत ही हानिप्रद होगी।" कुछ दूसरे लोगोंका कहना था कि जब तक सरकारका मण्डन राष्ट्रीय आधार पर होता है तब तक अन्तर्राष्ट्रीय समाज सम्भव नहीं है।

क्या साम्राज्यवाद का औचित्य है ? (Is Imperialism Justified?)

धुमा-फिराकर बान बनानेवाले तरीकेमें साम्राज्यवाद का औचित्य सिद्ध करनेका समय अब नहीं रहा। अब शायद ही कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें सी०डी० बर्न्स (C. D. Burns) के इस कथन पर विश्वास हो कि साम्राज्यवाद गली-कूचोंके स्तरकी मकीर्ण राजनीतिको समाप्त करता है और उसके स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीयतावाद और विश्व-अन्धधुक्को प्रेरणा देता है। इस विषयमें ठीक इसका उल्टा सब है। शोषण और आधिपत्य साम्राज्यवादका मूल तत्व^१ है। यह कहना नाम्मिकना नहीं है कि साम्राज्यवादका इतिहास आदरणीय नहीं रहा, यद्यपि उसके विरुद्धके इतिहासमें एक ऐसी अवस्था भी आती है जब शोषणकी 'प्रणाम (trusteeship)' का और पश्चिम द्वारा पूर्वी देशोंकी मध्य और मद्धमानव बनानेके पवित्र उद्देश्यका जामा पहनाया जाना है। अनेक आधुनिक साम्राज्योन्मी उत्पत्ति मनुषी लूट और दास व्यापारमें हुई है। बार्न्स (Barnes) का कहना है कि अंग्रेजी साम्राज्य भी इसका अपवाद नहीं है (४०११)।

^१ उदाहरणके लिए, आर्य साइप्रसमें बरती जानेवाली दमन-नीतिको देखिए। इस सबके बावजूद यह कहा जा सकता है कि कोई भी दूसरा आधुनिक साम्राज्य शामिलोन्मी भावनाओंके प्रति इतना विचारशील नहीं रहा जितना अंग्रेजी साम्राज्य रहा है। इसके उदाहरण हैं, भारत, पाकिस्तान, बर्मा, मरा, मलाया तथा गोंड कांन्ट (धाना) को दी गयी स्वाधीनता। इनके बाद नाइजीरिया का नम्बर है।

साम्राज्यवादके औचित्य-अनौचित्य पर विचार करते समय निम्नलिखित चार प्रश्नोंको ध्यानमें रखना होगा :

(क) जिन लोगों पर साम्राज्यवाद लादा जाता है क्या उनकी भौतिक और नैतिक अवस्थामें इससे कोई सुधार होता है।

(ख) क्या इसमें साम्राज्यवादी देशकी जनताकी भौतिक और नैतिक स्थिति में सुधार होता है?

(ग) क्या इसमें समारके विभिन्न देशोंके बीच संघर्ष के अवसर कम होते हैं और विद्व-शान्ति तथा समृद्धिको प्रेरणा तथा सहायता मिलती है?

(घ) क्या साम्राज्यवादका कोई ऐसा विकल्प (alternative) नहीं है जो समारको अधिक सुन्दर और सुखी बना सके?

(१) क्या साम्राज्यवाद औपनिवेशिक जनताके लिए लाभप्रद है? (Does Imperialism Benefit the Colonial People?). साम्राज्यवादी शासन में वास्तविक मानवतावादी कार्योंके उदाहरण तो थोड़ेसे ही मिलते हैं पर निमंत्रणके उदाहरण बहुत अधिक दिखायी देते हैं। लियोनार्ड बार्नस् (Leonard Barnes) का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि "अंग्रेजी साम्राज्य मानवता का पिढारा है, जो कभी-कभी जीर्ण है, कहीं-कहीं अत्याचारी है, अधिकांश भागोंमें लक्ष्महीन है और बहुत थोड़े स्थानोंमें लाभदायक है (४: २१)।" यह तथ्य अंग्रेजी साम्राज्यके इस परिचित चित्रके विपरीत है कि "अंग्रेजी साम्राज्य विश्व व्यापी न्याय और उदारताका चिरन्तन स्रोत (perennial spring) है जिस पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता (४: २०)।" यह सही है कि अफ्रीकाके आन्तरिक प्रदेशोंमें साम्राज्यवादने मनुष्य भक्षण, दासता और न्याय तथा शासनके अविकसित रूपोंको समाप्त कर दिया है। पर इन इने-गिने लाभों की तुलनामें हमें इन अनेक बातों पर भी विचार करना होगा कि डच ईस्ट इंडीजमें हॉलैण्डने अपनी संस्कृति घोपनेकी नीति अपनाई थी, बेल्जियम वालोने कांगोंमें भीषण अत्याचार किये थे। उष्ण प्रदेशीय साम्राज्य (Tropical Empire) के अनेक भागोंमें प्रतिज्ञाबद्ध कुलीगीरी और दासता की प्रथाएँ प्रचलित हैं और दक्षिण अफ्रीका तथा केनियामें मुड़ड़ी भर श्वेतांगोंने विस्तृत भूखण्ड हड़प लिये हैं। दक्षिण अफ्रीकामें १५ लाख श्वेतांगोंने २० करोड़ एकड़ भूमि हड़प रखी है। जबकि ५५ लाख हम्बियोंके पास केवल २ करोड़ ७० लाख एकड़ जमीन है।

जानीय विलगाव (apartheid) की नीतिको कार्यान्वित करनेमें हम्बियों, भारतीयों और अन्य रंगीन चमड़ीवाले लोगोंको प्रमत्त भूखण्डों (ghettos) में सदेहा जा रहा है। द्वितीय विश्व-युद्धके बादमें हालत और भी बिगड़ गयी है।

बार्नस् (Barnes) का कहना है कि अफ्रीका के सानवाले जिलोंमें "दासताकी सी हालत" है। देशी मजदूरोंको अधिकतर घोगा देकर भरती किया जाता है और उनमें से अधिकांश ऐसे महानोंमें रहते हैं जो स्वास्थ्य, नैतिकता और आर्थिक उन्नति के लिए घातक हैं। बार्नस् उन महानोंको जेल व बैरकके बीचकी चीज मानते हैं।

अफ्रीका में सैतिहरोकी हालत भी अधिक अच्छी नहीं है। जैसा कि बार्नस् कहते हैं : दक्षिण अफ्रीका के संघमें मूलनिवासियोंके प्रति एक ऐसी नीति अपनाई गयी है जो न्याय और ईमानदारीकी प्रत्येक परम्पराकी जानबूझकर नष्ट करनेका प्रयत्न करती है। ट्रान्सवाल और नेटाल में "किसी भी देशी पुरुषको जिस खेत या फॉर्ममें वह रहता और काम करता है उसके बाहर तब तक कोई नौकरी नहीं दी जा सकती जब तक उस फॉर्मका मालिक उसे नौकरी तलाश करनेकी लिखित अनुमति न देवे (४२५६)।" अत्याचारमें बर्बरताका पुट दे दिया गया है।

यह तो सभी जानते हैं कि साम्राज्यवादी देश उन देशोंकी जनताकी हालत सुधारने में बहुत ही कम पैसा खर्च करते हैं जिनका न्यामधारी उन्होंने अपनेको बना लिया है। लिपोनर्ड वूल्फ (Leopard-Woolf) का कहना है कि केनिया की सरकारने १९२४ में २० लाख पौण्डकी आयमें से ४४ हजार पौण्ड जेलो पर और सिर्फ ३६ हजार पौण्ड शिक्षा पर खर्च किया। सरकारकी नीति यह है कि २३ लाख अफ्रीकावासियों और ३६ हजार एशियाई लोगोंके हितोंका बलिदान करके लगभग १० हजार योरोपीय लोगोंका भला किया जाय। देशकी सम्पूर्ण उपयोगी भूमि इन योरोपीय लोगोंके लिए सुरक्षित रख ली गयी है। और "मूलदेशवासियोंको गरीबीकी राह भटकनेके लिए आजाद छोड़ दिया गया है (५३ : ५६)।" दक्षिणी या पूर्वी अफ्रीका की हालतें यह साबित करती हैं कि यदि देशी जनताका भाग्य उस देशमें बम जानेवाले श्वेतांग प्रवासियोंके हाथोंमें छोड़ दिया जाता है तो उनकी हालत मानू-देशके औपनिवेशिक विभाग (colonial office of the mother country) के अधीन रहनेकी अपेक्षा और भी अधिक बुरी हो जाती है। उत्तरी और दक्षिणी रोडेसिया और न्यासालैण्डके मूल वासी इन प्रदेशोंको मिलाकर एक स्वशासन युक्त केन्द्रीय अफ्रीकी संघ बनाने का जो जोरदार विरोध करते थे उसका मुख्य कारण यही है। साधारणतया साम्राज्यवादी देशोंका दृष्टिकोण सकीर्ण होता है। उन्हें इस बातकी बहुत जल्दी रहती है कि मुर्गी को बीरबर जितनी जल्दी हो मके सोनेके मुल अण्डे निकाल लिये जाय। वे यह नहीं सोच पाते कि यह उन्हींके हितमें है कि उपनिवेशोंकी जनता मुर्गी रहे, उसके जीवनका स्तर ऊंचा हो और उसकी कम शक्ति अच्छी हो।

अफ्रीका को छोड़कर जब हम भारत पर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि यहा भी हालत अंग्रेजोंके अधीन बहुत अच्छी नहीं थी, यद्यपि ब्रिटेन अन्य अधिकार साम्राज्यवादी देशोंसे अच्छा रहा है। आर्थिक शोषण तथा देशके धनका देशसे बाहर जाना बेरोकटोक जारी रहा। पार्कर मून (Parker Moon) ने लिखा है :

* माऊ-माऊ संगठनका उदय इसीका परिणाम है। यह एक आतंकवादी संगठन है। यह संगठन विविध बबोलेमें है और श्वेतांगों, तथा उनके साथ सहानुभूति रखने वालों और भेदियोंकी हत्या करता है।

“अंग्रेज पहले-पहल भारत क्यों आये और आकर क्यों भारतमें बने रहे, इसका प्रधान कारण यह नहीं है कि वे भारत की भलाई चाहते थे, बल्कि यह है कि वे ब्रिटेनका भला चाहते थे (६३-२९०)।” १७५ वर्षोंमें अधिक अंग्रेजी शासनके बाद भी इस शासनके समाप्त होने पर भारतके मजदूरकी औसत मजदूरी लगभग ६ आना प्रति दिन थी। आज भी जनताकी दयनीय दरिद्रता एक ऐसा दुखदामो तथ्य है, जिस पर किसी भी पर्यवेक्षककी दृष्टि तुरन्त आती है। महात्मा गांधी के शब्दोंमें: “अंग्रेजी भारतमें विधि द्वारा स्थापित सरकार जनताके इसी शोषणके लिए है। चाहे कितनी ही धाते बनायी जाय, आकड़ों से चाहे जैसे करिश्में दिखाये जाय पर अनेक गांधीजों हड्डीके ढाँचे नजर आते हैं उनके कारण सत्यता पर धूल नहीं डाली जा सकती।” गरीबीके अलावा देशमें निम्नतम कोटिवा अज्ञान छाया है। १९४० में ८७ प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे, यद्यपि अब स्वतंत्र भारतकी सरकार अपनी जनताको शिक्षित करनेका हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बहुत ही बुरा था। जन्म और मृत्यु की सख्या बहुत ऊँची थी। हम मानते हैं कि साम्राज्यवादी दक्षिण पर ही इस सयका सारा दोष नहीं मढ़ा जा सकता। देशकी आमदनीका बहुत अधिक भाग खर्चीली सेना पर खर्च किया जाता था और उतना ही अधिक भार एक बड़ी महंगी अर्धैनिक अधिसेवा (civil service) और पेन्शन पानेवालों पर खर्च हो जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे राष्ट्र निर्माणके विभागोंको एन-केन-प्रकारेण जीवित रहना पड़ता था। पूँजीके रूपमें ब्रिटेन से आनेवाली सम्पत्तिसे जनताका कोई कल्याण नहीं हो पाता था। जैसा कि बार्नम् (Barnes) ने कहा है: “इस सम्पत्तिमें धनी लोगोंका शिकंजा गरीबों पर तथा ब्रिटेनका शिकंजा भारत पर और अधिक मजबूत हो गया था।”

भूदा प्रणाली और सैनिक बजट पर तथा कुछ सीमा तक सीमान्त चुगी (tariff) और वित्त नीति (fiscal policy) पर अपना नियंत्रण रखकर ब्रिटेन भारतकी दरिद्र जनताके हितोंका बलिदान करके अपने देशवासियोंका कल्याण करनेमें समर्थ होता था। भारतके नुद्दीर तथा गृह-उद्योगोंकी जो हजारों व्यक्तियों की जीविकाके साधन थे और जिनमें लोगोंकी रचनात्मक कार्यों द्वारा अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्तिका अवसर मिलता था साम्राज्यवादी प्रतियोगिताकी होड़में बरीब-बरीब समाप्त कर डाला गया। यह सबको मालूम है कि भारतके व्यापक वस्त्र व्यवसायको पिछड़ी धनीके आरम्भमें ब्रिटेनमें, भारत के बढ़िया कपड़ों पर बहुत अधिक आयात चुगी लगाकर तथा अन्य तरीकोंमें समाप्त कर दिया गया। इन सब चीजोंको देखते हुए साम्राज्यवादकी मानवतावादी वस्तुस्थिति बताना ढोंग मालूम होता है। सेसिल रोड्स (Cecil Rhodes) का यह कथन सत्यके अधिक निकट है कि “गुड लोकोगवार अपने आपमें बहुत अच्छा है, पर लोकोगवारके माय ५ प्रतिशतका लाभ

भी हो तो और भी अच्छा है।" शुमन (Schuman) का कहना है कि "मानवतावाद, सम्म्य बनानेका उद्देश्य, धर्म परिवर्तन और पिछड़े हुए लोगोंका भौतिक कल्याण आदि ऐसे शब्द हैं, जिनके पीछे लाभ उठानेके उद्देश्य, शक्ति प्राप्त करनेकी लालमा और आत्म प्रतिष्ठाकी बड़ी चतुराईमें छिपाया गया है (७० : ४२२)।" इसी लेखक का कहना है कि जो देश साम्राज्यवादके जुएके नीचे हैं उनमें निरक्षरता दूर करने पर और शिक्षाके विकास पर बहुत कम धन व्यय किया जाता है। इसके विपरीत सैनिक कार्यों पर, प्रशासन पर और रेल निर्माणमें बहुत अधिक धन व्यय किया जाता है। इस्तेमाल प्रवासियोंको लाभ सबसे अधिक भाग मिलता है। सब वही भिन्नभाषी, भूबन्धे मौनें और सामाजिक बिभ्रमलता दिखायी देनी हैं। अफ्रीका के लोगोंके निरो पर और झोंपड़ियों पर कर लगाये जाते हैं जिनका उद्देश्य देशके राजस्वको बढ़ाना बनना नहीं होता है, जिनका कि मूल देशवासियोंको मफेद चमड़ीवाले मालिकोंकी सेवाके लिए मजबूर करना होता है।

यदि यह भी मान लिया जाय, जैसा कि है भी, कि साम्राज्यवादके नीचे पिछले वाले देशोंकी जनताको कुछ अग्रगण्य आर्थिक लाभ हो जाया करते हैं तो भी यह कहना ही पड़ेगा कि इस लाभके लिए उन्हें अपनी राजनीतिक स्वाधीनता, आत्म-सम्मान और आत्मगौरवको खोना पड़ता है। राजनीतिक दामता साम्राज्यवादका बनना ही अभिन्न अंग है जिनका आर्थिक योग्य। शक्तिकी प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि जो लोग बहुत अधिक समय तक उसके अधीन रहते हैं उन्हें अपनी बेइया ही धमन्द आने लगनी है। जैसा कि रूसो (Rousseau) ने कहा है : "यदि ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रकृतियों ही दास हैं तो इसका कारण यह है कि पहले प्रकृतिके विरुद्ध लोगों को दाम बनाया गया है। "मिस्र, मीरिया, पेल्लेस्टाइन, भारत, बर्मा और लका का आधुनिक इतिहास यह साबित करता है कि साम्राज्यवादी शक्तिया अधिकार छोड़नेके लिए कभी तैयार नहीं होती और जनताको स्वशासनके योग्य बननेमें जितनी भी बाधाएँ सम्भव हैं उतनी बाधाएँ ये शक्तियाँ पैदा करनी हैं। साम्राज्यवादी देशोंने अभी इस मन्त्रको स्वीकार नहीं किया है कि "कोई भी व्यक्ति इनका अच्छा नहीं होता कि वह दूसरोंका मालिक बन जाय।"

जब अयोग्य देशों की जनताका स्वशासन और स्वाधीनताका आन्दोलन प्रबल हो जाता है तब साम्राज्यवादी शक्ति निम्नलिखित उपायोंसे से एक या अधिक उपायोंका सहारा लेती है (७० : पृष्ठ ६२४-२९):

(क) जनताके प्रतिरोधको शक्तिको ताकतमें कुचल दिया जाता है और उसे कमजोर कर देनेके उपाय किये जाते हैं।

(ख) जनताको साम्राज्यके प्रति वफादार बनानेके लिए लाभ, दाम, दण्ड, भेद और शिक्षा आदिका सहारा लिया जाता है।

(ग) देशी भाषा और संस्कृतिको हटाकर उनके स्थान पर विजेताओंकी भाषा और संस्कृति बनना पर लादी जाती है।

(घ) "राष्ट्रीय सरकारमें उपनिवेशकी प्रजाको प्रतिनिधित्व देनेका ढांग रचा जाता है। इस व्यवस्थाको राष्ट्रीय आत्मनिर्णयके स्थान पर लागू किया जाता है।"

(ङ) स्वायत्त धामन, सुरक्षा और स्वानीय नासनके अनेक रूप और प्रकार खोज निकाल कर जनताको छोटे-छोटे मामलोमें कुछ अधिकार दे दिये जाते हैं। पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि असली शक्ति साम्राज्यवादी देशके ही हाथमें रहे।

(च) देशी राजाओं (princes) और अन्य निहित स्वार्थोंका उपयोग औपनिवेशिक सरकारके अभिकर्ता (agents) के रूपमें किया जाता है।

(छ) इस बातका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि कार्यपालिका (executive) पर व्यवस्थापिका (legislature) का नियंत्रण न होने पावे।

(ज) आपदादिक अवस्थामें ही साम्राज्यवादी शक्ति बिना युद्ध के अपना अधिकार छोड़ती है जैसा कि अंग्रेजोंने अपने कुछ उपनिवेशों और भारतमें किया।

विदेशी धामनका विरोध करनेवालोंकी शक्ति जब तक विजेताओंकी शक्तिसे कमजोर रहती है तब तक विदेशी अत्याचार और विदेशी तानाशाही बढ़ती ही जाती है (७० : ६२९)।" सार्वजनिक अव्यवस्था, साम्प्रदायिक तनातनी और सशर्प, निरक्षरता, निम्न नैतिक स्तर आदिका घटाना लेकर स्वधामनको अनिश्चित काल तकके लिए स्थगित रखनेका प्रयत्न किया जाता है और इन बाधाओंको दूर करनेका प्रयत्न नहीं किया जाता। पिछड़े देशोंको आत्मविकास करने और मजबूती करके मीथने का कोई अवसर नहीं दिया जाता। इस दृष्टिसे अफ्रीका बाकी सम्भवतः सबसे अधिक अभाग्य रहे हैं।

साम्राज्यवादके तत्वावधित लाभोंके प्रगममें शुमन (Schuman) ने हमें इस तथ्यकी याद दिलायी है कि पश्चिमी सम्पत्ता शूद्र वरदान ही नहीं है। ऐसे उदाहरण कम नहीं हैं जिनमें सफेद चमड़ीवालोंके धर्म, नैतिक आदर्श, भाषा और सामाजिक व्यवस्थाओंका परिणाम देशवासियोंकी सभ्यतिके विनाश, सामाजिक अव्यवस्था और नैतिक पतनमें हुआ है। हमें यह बताया गया है कि साउथ सीजके मूलनिवासी पश्चिमके साथ अपने सम्पर्कके कारण या तो मर चुके हैं या मर रहे हैं, क्योंकि शराब पीने, बन्दूकबाजी और उपद्रव रोम इस सम्पर्कके निरुपेक्ष परिणाम हुए हैं। सगरके अन्य भागोंमें साम्राज्यवादी धामनके अधीन रहनेवाले लोगोंने अपना धर्म, अपनी कला, अपने नैतिक आदर्श और अपनी ग्राम्य परम्पराओंकी गो दिया है और वे पश्चिमी सफेद चमड़ीवालोंके धर्म और पवित्र उपहास नमूने (caricature) बन गये हैं (७० : ५९२)।" प्राचीन साम्राज्यवाद अपने अधीन लोगोंके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता था। अधिकतर वह उन्हें अपनी मौखिक प्रतिभाके विनाशके लिए स्वयं छोड़ देता था। पर आधुनिक साम्राज्यवाद लोगोंके जीवन पर व्यापक प्रभाव डालता है और उनकी सभ्यता और सम्पत्तियों को कुछ भी भेष्ट और सुन्दरतम होता है उन सबका विनाश कर देता है। अपने अधीन लोगोंको वह "तुच्छ और निम्न कोटिके विधि हीन व्यक्ति समझता है और अपनी

सैनिक श्रेष्ठता तथा उच्च उद्योग विज्ञानको साम्प्रतिक श्रेष्ठता मानता है।”

जानाँय सम्बन्धोंकी विगाड़नेमें साम्राज्यवादका दायित्व बहुत अधिक है। एशिया और अफ्रीकामें जातियोंके सम्बन्धोंको विगाड़नेवाला जानीय सघर्ष साम्राज्यवादकी विरासत है। सी० एफ० एण्ड्रूज (C. F. Andrews) पूछते हैं “आप एक ऐसे व्यक्तिके मित्र कैसे बन सकते हैं जो हमेशा आपको अपनेसे निम्नतर स्थितिमें रखनेको उतारूँ है?” वॉल्टेस्टर के प्रधानाचार्यने भारत पर भाषण देते हुए कहा था: “हमें भारत के कलेशोंका मूल कारण खोजना चाहिए। उस देश पर हमारे शासनसे निस्सन्देह उस देशके बामिषोंका बहुत लाभ हुआ है। आपसमें लड़नेवाले ममूशायोंके बीच हमने बहुत समय तक शान्ति कायम रखी है। हमने रेलें बिछाई हैं, अकालसे युद्ध किया है, लोगोंका स्वास्थ्य सुधारा है और देशकी उपज बढ़ायी है। “...” हमने भारतकी भौतिक आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिए बहुत कुछ किया है लेकिन फिर भी हमें भारत वासियोंका प्रेम नहीं प्राप्त हो सका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उनकी आत्मा को चोट पहुँचाई है।” एच० जी० वेल्ल्स (H. G. Wells) का कहना है कि साम्राज्यवादका मतलब है “हिन्दी-शेखी, विश्वव्युत्पन्न का उल्टा।” सशुक्र राज्य अमेरिकाके प्रसिद्ध समाजवादी नेता नॉर्मन थॉमस (Norman Thomas) व्यप्य पूर्वक कहते हैं “अनेक ऐसे लोग हैं जिनके पास इकनाये जानेके लिए ६ फुट जमीन नहीं है पर वे इस गवंसे फूले नहीं समाते कि उनका देश एक साम्राज्यका स्वामी है।” हमें बताया गया है कि प्रथम विश्व-युद्धके पहले जर्मनोंके उपनिवेशोंमें “भीरे लोग अपने साथ कोड़ा लेकर उसी प्रकार चलते थे, जिन प्रकार कोई कुमाल लेकर चलता है।”

जैसा कि प्रो० हॉकिंग (Prof. Hocking) ने कहा है, पश्चिम वाले यह मान बैठे हैं कि जो कुछ उनके लिए अच्छा है वह सबके लिए अच्छा है। “वह बहुत-सी अच्छी बातोंका विनाश कर रहे हैं—यह जाने बिना कि वह ऐसा कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण, अरब संस्कृतिका विनाश है। पश्चिम यह नहीं समझता कि जीवनके सौन्दर्य, विचार और भाषाकी महत्ता, शिष्टता, आतिथ्य, सम्भावण, अन्तःप्रेरणा, काव्य और दार्शनिक ज्ञानके क्षेत्रमें पूर्व पश्चिमकी अपेक्षा बड़ी अधिक आये है।” (हॉकिंग)

इसमें भी बड़ी दूमरी बुराई यह है कि युद्ध साम्राज्यवादका आवश्यक अंग है। युद्ध पहले पिछड़े देशोंके साथ और बादमें दूसरे साम्राज्यवादी देशोंके साथ होता है। ऐसा एन भी उपनिवेश नहीं है जो बिना किसी रक्तपातके जीता गया हो। एक आधुनिक लेखकने लिखा है कि साम्राज्यवाद भाग्य उसके अधीन आ पड़ने वाले लोगोंके खूनसे लाल है। एक दूसरे लेखकने लिखा है कि कूटनीति, दबाव और सैनिक शक्ति साम्राज्यवादके आवश्यक साथी हैं। पिछड़े देशोंको अपने अधीन कर लेनेके बाद भी साम्राज्यवादी देशोंको एन बहुत बड़ी मेना रखनी पड़ती है। यह नेता तीन बारणों से रण्यो जानी है: अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिए; देशवासियोंके सम्भावित विद्रोहके भयके कारण और इस आशंकाके कारण कि वहाँ कोई प्रतिस्पर्धी साम्राज्य-

वादी देश लूटके मालको हृष्ट न लें। एक साम्राज्यवादी देश हमेशा बाटो पर रहता है और उसकी मनोवृत्ति साधारण स्वस्थ मानव सम्बन्धोंके प्रतिकूल रहती है।

इन सब घुराइयोंके होते हुए भी साम्राज्यवादके समर्थक उसके पक्षमें निम्न-लिखित दलीले देते हैं। साम्राज्यवाद अराजकता और अव्यवस्थाको समाप्त करके शान्ति और व्यवस्था स्थापित करता है; पिछड़े समाजके आपसमें लड़नेवाले विभिन्न समुदायोंमें साम्राज्यवाद पंचका काम करता है। वह जनताको देशवासियोंके शोषण से बचाता है; साम्राज्यवाद देशके उन प्राकृतिक साधनोंको समार भरके लिए मुलभ बनाता है जिनका उपयोग पहले नहीं हुआ होता, विस्तृत प्रदेशों पर साम्राज्यवाद सामान्य विधि लागू करता है। आजकल जब सैयार माल और कच्चे मालके बाजारोंके लिए भयानक प्रतियोगिता चल रही है, अपने पैरों पर न खड़े हों। अपने वाले देशोंके लिए यह निश्चिन्त रूपमें लाभदायक है कि वे एक ऐसे बड़े साम्राज्यके अंग बन जाय जो उन्हें ध्वस्त जीवन और मुरझाकी मुक्ति दे सके। हम मानते हैं कि इन सब तर्कोंके पीछे काफी बल है पर हमें यह मानना ही होगा कि ये सब बातें साम्राज्यवादकी घुराइयोंको केवल कम कर देती हैं वे किमी प्रकार भी साम्राज्यवाद का औचित्य सिद्ध नहीं करती। साम्राज्यवादका औचित्य अभी सिद्ध किया जा सकता है जब उसका उपयोग सबसे पहले और सबसे अधिक शान्ति लोकोके कल्याणके लिए किया जाय और उन्हें जल्दीमें जल्दी स्वशासन और स्वाधीनताके योग्य बनाया जाय। ईमानदारी हमें यह कहनेके लिए मजबूर करती है कि इनमें से कोई भी बात उचित मात्रामें आजके साम्राज्यवादी ससारमें नहीं भी पूरी होनी नहीं दिलायी देती है। विदेशी शासन पुरुषत्व और आत्म-सम्मानकी हानि के रूपमें क्षामितोमें जो कीमत लेता है वह ऐसे शासनके लाभोंसे नहीं अधिक होती है।

(२) क्या साम्राज्यवाद मातृदेशकी जनताके लिए लाभप्रद है? (Does Imperialism Benefit the People of the Mother Country?). बहुतया यह मान लिया जाता है कि साम्राज्यवाद मातृदेशकी जनताको बहुत अधिक भौतिक लाभ पहुंचाता है। पर ध्यानपूर्वक विचार करनेसे यह कल्पना सही नहीं साबित होती। जहां तक भावनाका सम्बन्ध है निस्सन्देह हेय मनोवृत्ति वाले लोगोंके लिए साम्राज्यवाद एक सुन्दर रमायन है। पर इसमें जनताको कोई भौतिक लाभ नहीं होता। लीविणके बारेमें इस तथ्यकी गन्यता गिद्ध करते हुए शूमन (Schuman) ने कहा है : "लीविण एक ऐसे औपनिवेजित प्रदेशका अच्छा उदाहरण है जिसे मातृ-देशकी जनता की बाकी हानि पहुंचाकर प्राप्त किया गया है और कूटनीति शक्ति तथा प्रतिष्ठाके कारण मातृदेशके कर दानाओंकी भारी हानि पहुंचाकर उसे अधिकारमें बनाये रखा जा रहा है। जो कुछ थोड़ा बहुत लाभ होता भी है वह यूरोप लाने वाले और कुछ थोड़ेसे मुक्ति प्राप्त लोगोंको ही होता है। समूचे राष्ट्रको कोई भी अधिक लाभ नहीं होता (७०:५०६)।"

आमतौर पर साम्राज्यवादी अभियानोंमें जो कुछ अधिक लाभ होता है, वह

राज्यानुग्रह प्राप्त बड़ेसे लोगोंको ही होता है। समूचे राष्ट्रको तो 'गुनाह बेलज्जत' ही बनना पड़ता है। उदाहरणके लिए ब्रिटेनकी आम जनताको भारत पर ब्रिटेनके अधिकारसे होनेवाला प्रत्यक्ष लाभ सम्भवतः बहुत ही कम था; यद्यपि यह सही है कि "एक उपनिवेशके रूपमें किसी भी औद्योगिक साम्राज्यको कभी भी प्राप्त होने वाले बाजारोंमें भारत सबसे बड़ा बाजार है (६३-५२०)।" वस्त्र और लोहे आदि के कुछ खास उद्योगोंको लाभ हो सकता है, पर सम्पूर्ण उद्योगको लाभ नहीं होता। यदि भारत और अन्य औपनिवेशिक प्रदेशोंमें लगी हुई कुल पूँजी ब्रिटेनमें ही लगी होती तो ब्रिटेनके मजदूरोंकी हालत उनकी आजकी हालतकी अपेक्षा बहुत अधिक अच्छी होती। लियोनार्ड बार्न्स (Leonard Barnes) लिखते हैं "उपनिवेश विशेष तौर पर कुछ वर्गोंके लिए लाभप्रद होते हैं। वे पूँजी लगाने वालों और उत्पादकोंके लिए लाभप्रद होते हैं, पर बेतन भोगी मजदूरोंके लिए हानिकारक होने हैं (४-२१)।"

साम्राज्यवादके समर्थकोंका प्रायः यह कहना है कि साम्राज्यवादी देशको अपने उपनिवेशोंमें पैदा होनेवाला कच्चा माल बहुतायतसे मिल जाता है। पर वास्तविक तथ्योँसे इस दावेकी पुष्टि नहीं होती। जैसा कि पार्कर मून (Parker Moon) ने कहा है, कच्चे माल रगभेदको नहीं पहचानते। कच्चे माल राजनीतिक नियमोंकी अपेक्षा आर्थिक नियमोंका अनुगमन करते हैं। यह सोचना मूर्खता है कि साम्राज्यवादी देश द्वारा अपने उपनिवेशोंमें लगाई गयी पूँजी हमेशा प्रत्यक्ष लाभ देती है। यह विचार भी बिल्कुल गलत मालूम पड़ता है कि एक साम्राज्य कच्चे मालके मामलेमें आत्म-निर्भर बन सकता है, विशेषकर युद्धके समयमें। इस उद्देश्यकी सिद्धि जो बलिदान चाहती है वह उद्देश्यके लाभसे बड़ी अधिक है। एक ही साम्राज्यके भीतर के देश अपनत्वके जोंगमें आकर इस बातके लिए तैयार हो सकते हैं कि वे पर्याप्त आर्थिक हानि उठाकर भी आपसमें ही एक दूसरेसे कप-विक्रय करें। पर यह जोंग बहुत जल्दी ठण्डा हो जाता है। व्यापार साधारणतया कमसे कम मूल्यका अनुगमन करता है, अपनत्वकी दलीलोंका नहीं।

प्रथम विश्वयुद्धके बाद अंग्रेजी साम्राज्यमें साम्राज्यक रियायती चुगी (imperial preference) के विचार ने जोर पकड़ा। यह विचार १९३१ में ओट्टावा समझौतेमें अपनी चरम सीमा पर पहुँचा। पर इसमें साम्राज्यकी अधिक लाभ नहीं हुआ। 'टाइम्स' नामक समाचार-पत्र ने लिखा था 'ओट्टावा (Ottawa Canada) और विश्व-युद्धके बीचके मात वर्षोंमें ब्रिटेन और उनके उपनिवेशोंने एक साथ ही यह सबक सीखा कि उनकी सबसे अधिक जटिल आर्थिक समस्याएँ और उनकी हल करनेकी आशाएँ उनके पारस्परिक व्यापार पर नहीं बल्कि वेप मंसारके साथ उनके व्यापार पर निर्भर करती हैं।'

ऊपर के तर्कोंके बावजूद मानुष्यके निम्न वर्गोंको अत्यल्प लाभ होना है। विदेशी व्यापार और मन्ते कच्चे मालके आयातमें मार्गजनित्र समृद्धि और नव शक्तिमें वृद्धि होती है। यह बात समुक्त राज्य अमेरिकाके बारेमें सही है, यद्यपि अमेरिका उन अर्थोंमें

साम्राज्यवादी नहीं है, जिन अर्थोंमें ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और पुर्तगाल हैं।

लम्बे चौड़े साम्राज्यकी रक्षाके लिए ब्रिटेन को एक बहुत बड़ी जल, थल और नभ सेना रखनी पड़ती थी। और अंग्रेज करदाताको इसका बोझ उठाना पड़ता था। ब्रिटेनके साम्राज्यवादी विस्तारसे जो कुछ भी अप्रत्यक्ष लाभ उठे होता था, उसमें अधिक करोंका बोझ उसे उठाना पड़ता था। सम्भवत यह आर्थिक बोझ ही एक कारण था कि द्वितीय विश्व-युद्धके बादसे ब्रिटेन अपने अधीनस्थ विविध देशोंको स्वाधीनता या स्वशासन देनेमें जुट गया।

यह तर्क कि साम्राज्यवाद अधिक आवादीका एक प्रतिकार है, तथ्यों द्वारा सिद्ध नहीं होता। इटली और जापान हमेशा अपनी बढ़ती हुई आवादीका रोना रोते रहे, पर उपनिवेशोंसे उनकी यह समस्या हल नहीं हुई। उद्योग, कृषि और अर्थ-नीतिके समन्वयपूर्ण व्यवस्थापन और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा यह समस्या अधिक अच्छे ढंगसे हल हो सकती है।

साम्राज्यवादका एक परिणाम यह होता है कि साम्राज्यवादी देशकी जनताका जीवनस्तर और मजदूरी कम हो जाती है। जब पूँजीपति यह देखता है कि पिछड़े देशोंमें, जहाँ मजदूर सस्ते और काफी तादादमें मिल जाते हैं, अपनी पूँजी लगानेमें उसे सीधे लाभ हो सकता है, तब वह अपनी पूँजी मातृ-देशमें न लगा कर पिछड़े देशोंमें लगाता है। बहुत ही जल्दी उसे मालूम हो जाता है कि अपने देशकी अपेक्षा पिछड़े देशमें अनेक प्रकारकी वस्तुएँ बहुत कम लागतमें तैयार की जा सकती हैं। इस सबका नतीजा यह होता है कि उसके मातृ-देशमें मजदूरोंकी मजदूरी कम हो जाती है और उन्हे बेकारीका भी सामना करना पड़ता है।

विजेताओं पर साम्राज्यवादका नैतिक प्रभाव निम्नन्देह बड़ा गम्भीर होता है। प्रो० हॉकिंग (Prof. Hocking) का यह कहना विन्कुल गत्य है कि "किसी भी जातिके लिए एक लम्बी अवधि तक ऐसी जनताके बीच रहना जिसे वह हेतु दृष्टिमें देखनी हो, विशेष-रूपमें घातक होता है।" इसमें नैतिकताका स्तर गिर जाता है और अन्तःकरण अगुद हो जाता है। यह बात असाधारण नहीं है कि दवेताग लोग अपने लिए और काले लोगोंके लिए भिन्न-भिन्न मानदण्ड रखते हैं। देशकी विधि तबको इस भ्रष्ट दशाका समर्थन करनेके लिए विवश किया जाता है। नफेद चमड़ी वाले अपने अन्तःकरण को घोंवा देकर यह विश्वास करने लगते हैं कि काले लोग एक निम्न जातिके हैं, काले लोगोंको उन मुख्य मुविधाओंकी कोई जरूरत नहीं है, जिन्हे दवेताग अपने लिए आवश्यक मानता है, काले लोग बिना कुछ खाये-पिये भी जीवित रह सकते हैं, उनके आचार, व्यवहार और आदर्श इस योग्य नहीं हैं कि उन पर ध्यान दिया जाय, और उनकी भावनाओं और उनके विचारों पर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं है आदि आदि। इस प्रकारकी आन्तरिक घृणा ही इस बातका मुख्य कारण है कि भारतमें शायद ही कुछ अंग्रेज भारतीय मस्तिष्क और सम्मानका वास्तविक अर्थ और महत्व समझ पाये हों। वे यहाँके हाथियों, चीतों, साँरों, मनोरंजनके बन्दों और राज-

महत्त्वोंके बारेमें तो बहुत कुछ जानते हैं पर जनताके आन्तरिक जीवन और उसकी प्रतिभाके बारेमें उन्हें बहुत कम ज्ञान है। भारतीय दर्शन, काव्य, साहित्य और कलाके सौन्दर्यके उनमें से अनेक बिल्कुल अनभिज्ञ रहे हैं।

जहां तक तथ्यावयव पिछड़े प्रदेशोंका सम्बन्ध है, साम्राज्यवाद अपने सबसे उत्तम रूपमें एक उदार तानाशाही कहा जा सकता है। दमन तो साम्राज्यवादकी रीढ़-स्तम्भ है। अनुभव यह बताता है कि उपनिवेशोंमें काममें लाया जानेवाला दमन मानव-देहमें भी अपनी जड़ें जमा लेता है। स्वाधीनताके प्रति स्वाधीनता प्रेमी अप्रेमों का मौलिक उत्साह बहुत कुछ कम हो गया है। इसका कारण सम्भवतः यह है कि विदेशोंमें उनके देशवासियोंने जो सैनिक अत्याचार किये और उनके आश्रित साम्राज्यके विभिन्न भागोंमें स्वाधीनता पर जो कड़े प्रतिबन्ध लगाये गये उनमें अप्रेमोंकी मनोवृत्ति बदल गयी है।

साम्राज्यवादी देश और उसके अधीनस्थ देशोंके बीच जो अस्वाभाविक सम्बन्ध होता है, उसमें यह बिल्कुल असम्भव हो जाता है कि दोनों एक दूसरेमें कुछ सीख सकें। जब तक दो जातियोंके बीच स्वामी और शमका सम्बन्ध रहता है तब तक नये विचारों और मुझाबांका स्वीकार किया जाना और शिक्षार्थीकी आन्तरिक शक्ति-सामर्थ्यका उपयोग असम्भव है। इसी सम्बन्धमें प्रो० हॉकिंग (Prof. Hocking) लिखते हैं: "एक अच्छा गुरु अपने शिष्यों को सब समस्याएँ हल करके दे देना पसन्द नहीं करता बल्कि जहां तक हो उसे स्वावलम्बनके योग्य बनानेका प्रयत्न करता है। वह किसी कार्यके सम्पादनको उतना महत्व नहीं देना जितना शिष्यको आन्तरिक शक्तियोंके विकसित करनेको, ताकि कार्य-सम्पादनके योग्य हो जाय। समस्या का हल भीख मांगना नहीं, बल्कि मिश्रणोंकी आजीविका कमानेकी शिक्षा और प्रेरणा देना है।"

(३) क्या साम्राज्यवाद राष्ट्रोंके बीच संघर्षके कारण समाप्त करके विश्व-शांतिमें सहायता देता है? (Does Imperialism Help to Avoid Friction Points Among Nations and Make for World Peace?). इस प्रश्न का उत्तर अविचलित नकारात्मक ही है। साम्राज्यवादका अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय झंझ और प्रतियोगिता है। इसका अर्थ है बाजारोंके लिए, कच्चे मालके लिए और पूंजी लगानेके स्थानोंके लिए संघर्ष^१। जब तक अफ्रीका और एशिया में, धनके और शोषण करनेके लिए, काफ़ी धन थे तब तक पश्चिमी राष्ट्र आपसमें लड़े बिना उन्हें परस्पर बांटते रहे। आज प्रायः समस्त प्राप्य भूमि इसी

^१ यह संघर्ष आधुनिक शक्ति युद्धोंमें सम्भावित शक्तियोंके लिए किया जाता है: उदाहरणके लिए अमेरिका और रूसके बीच यूगोस्लावियाकी संचोरे लिए—और जहां तक रूसका सम्बन्ध है यूगोस्लाविया पर हावी होनेके लिए चलनेवाली फ़ौड को देना।

जा चुकी है और भविष्यमें साम्राज्यवादी शक्तियोंके बीच उपनिवेशों और बाजारोंके लिए मर्पण होनेकी पूरी आशंका है। द्वितीय विश्व-युद्धमें जर्मनी और जापानने युद्ध सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारीको यह कहकर उचित साबित करनेकी कोशिशकी थी कि वे साम्राज्यवादी सभारमें समानता कायम करना चाहते थे। युद्धके आरम्भके पहले ही लियोनार्ड बार्न्स् (Leonard Barnes) ने लिखा था, "यह विस्कुल मत्प और उचित कथन है कि ब्रिटेनका इतने बड़े साम्राज्यका वर्तमान एकाधिकारी स्वत्वोंके साथ स्वामी बने रहना विश्वशान्तिके साथ मेल नहीं खाता (४:२१-२२)।"

अंग्रेज लेखक आमनौर पर बार्न्स् की उक्त रायमें सहमत नहीं है। वे अंग्रेजी साम्राज्यको विश्व-शान्तिका सबसे बड़ा रक्षक मानते हैं। प्रो० ई० बार्कर (Prof. E. Barker) का कहना है कि यद्यपि मूल रूपमें अंग्रेजी साम्राज्यका अभिप्राय वस्ती बसाने और व्यापार करनेके लिए समुद्रके पार देशोंमें अपना विस्तार करना था पर अब उसने अपनी पूर्णताकी एक ऐसी प्रणाली प्रकटकी है जिससे वह पूरी तरहमें स्वशासनयुक्त राष्ट्रांके स्वेच्छाजन्य संगठित समाजके नवीन आदर्शरूपमें बदलता जा रहा है। यह संगठन विधान और स्वाधीनता सम्बन्धी अंग्रेजी विचारोंकी स्वेच्छाजन्य स्वीकृतिके आधार पर ही है। यह कहनेकी तो कोई आवश्यकता नहीं है कि स्वशासनयुक्त राष्ट्रांके स्वयं मर्पका यह दावा वही तक ठीक है जहां तक अधि-राज्यों (Dominions) का सम्बन्ध है। उपनिवेशों और आश्रित प्रदेशोंके सम्बन्धमें यह कथन लागू नहीं होना। पूरे अंग्रेजी साम्राज्यका ६/७ भाग कुछ समय पहले तक उपनिवेश और आश्रित प्रदेश ही था।

बार्न्स् के अनुसार अंग्रेजी साम्राज्यके निर्मालयित नयाकयित उद्देश्य हैं:

(क) साम्राज्यके समस्त सदस्योंके बीच शान्ति,

(ख) बाहरी आक्रमणके विरुद्ध सुरक्षाकी एक सहकारी व्यवस्था,

(ग) उसके सभी सदस्योंके लिए (१) वैयक्तिक (२) आर्थिक अर्थात् जीवनके सुन्दर और निरन्तर उन्नतनील मानदण्ड और (३) राष्ट्रीय स्वाधीनता।

बार्न्स् स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह सब केवल स्वशासन युक्त अधि-राज्योंके सम्बन्धमें ही सत्य है।

अगर दलीलके लिए यह मान भी लिया जाय कि अंग्रेजी साम्राज्यके लम्बे-चौड़े प्रदेशोंमें शान्ति कायम हो जानी है तो भी इसका यह अर्थ नहीं होता कि इसमें विश्व-शान्ति भी प्राप्त हो जानी है। युद्धोंमें सभी भाग न लेने, सभी आक्रमण न करने और अपने उपनिवेशों तथा आश्रित देशोंको यथासम्भव सीधे स्वशासनके उपयुक्त बनानेकी ब्रिटेनकी इच्छामें ईमानदारी हो गवनी है, पर जब तक ब्रिटेन के अन्तर्गत समस्त अन्य पूँजीवादी देशोंसे यह निरापण बनी रहनी है कि गगारके व्यापार और भू-प्रदेशोंमें उन्हें उपयुक्त भाग नहीं मिला है तब तक विश्वशान्ति वच्चे घासे पर ही मूलनी है। इसलिए हम इस मनीजे पर पढ़ते हैं कि व्यावहारिक साम्राज्यवाद—शान्तिक साम्राज्यवाद नहीं—शान्तिके लिए खिन्नर नहीं है।

साम्राज्यवाद अपने सर्वोत्तम रूपमें एक मजसूत तटस्थता ही कहा जा सकता है।

(४) क्या साम्राज्यवाद का कोई विकल्प है? (Is there an Alternative to Imperialism?). हमारा विश्वास है कि साम्राज्यवाद स्थायी नहीं हो सकता। शुमन (Schuman) का विश्वास है कि साम्राज्योंके दिन अब गिने हुए ही हैं, यद्यपि उनका पतन बहुत धीरे-धीरे और कमरा होगा। पार्कर मून (Parker Moon) का कहना है कि साम्राज्यवाद मध्य विक्टोरियनयुगका बचा-बूबा अंग है जो एक नितान्त भैरविक्टोरियन युगमें कायम है। यदि सत्रमण कालमें साम्राज्यवाद अपना औचित्य मिट्ट करना चाहता है तो उसे शोषण-मूलक न होकर उत्तर-दायित्व मूलक होना होगा। प्रो० हॉकिंग (Prof Hocking) का कहना है कि केवल साम्राज्यवादी मगडनमें कुछ परिवर्तन कर देनेमें काम नहीं चलेगा। आवश्यकता तो एक नयी मनोवृत्ति की है। साम्राज्यवादी प्रश्नोंको महानुभूतिपूर्वक हल करनेमें पुरानी औपनिवेशिक और मैत्रिक मनोवृत्तिमें सहायता नहीं मिलनी। इन प्रश्नोंका निपटारा मनुष्य जातिकी सुख-समृद्धि और बन्ध्याणके आधार पर होना चाहिए। समस्याका हल अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण और 'अन्तर्राष्ट्रीय महयोग' में मिल सकता है। इन प्रश्नों को हल करनेके लिए मधुस्तराष्ट्र मभ बहुत अधिक उपयोगी मस्या है पर अभी तक यह उपयोगिता अप्रगट रूपमें ही है।

बार्न्म् (Barnes) का कहना है कि आधुनिक युगमें साम्राज्यवाद तभी सहन किया जा सकता है जब औपनिवेशिक साम्राज्य भर में मुलाद्वार नीति अपनाई जाय। उनका विश्वास है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का गला नहीं घोटता है तो ब्रिटेनको अपनी परम्परागत मुक्त व्यापार नीति (free trade policy) अपनानी होगी। उनकी राय है कि कच्चा माल सभी खरीदारोंको एक ही भाव देना चाहिए। अथवाद तभी होना चाहिए जब किसी प्रकारके अपराधी राष्ट्रोंके विरुद्ध आर्थिक अनुशासिका (economic sanctions) लागू करनी हो। "यदि कच्चे मालकी पूर्तिकी किसी और प्रकारसे नियंत्रित करना हो तो उपभोक्ताओंके हितोंकी रक्षा रात्रकीय नियंत्रण द्वारा की जानी चाहिए और उस नियंत्रणमें उपभोक्ता देशोंका भी हाथ होना चाहिए" (४-१३)।"

उपनिवेशों और समाजातिन प्रदेशोंके शासनके बारेमें बार्न्म् बहुत ही ठीक कहते हैं कि चूंकि ये प्रदेश वहाँके निवासियोंके हैं, इसलिए उनके हितोंका ध्यान रखने पहले किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रदेशका हितान्तरण जरूरी हो तो यह काम वहाँके निवासियोंकी पूर्ण और स्वेच्छाजन्य स्वीकृतिसे ही किया जाना चाहिए। बार्न्म् का विश्वास है कि इस समस्याका मयमें अच्छा हल यह है कि समाजातिन प्रदेशों और उपनिवेशोंको एक अन्तर्राष्ट्रीय मताके अधीन कर दिया जाय, यद्यपि वह यह मानते हैं कि सम्भवन। यह व्यवस्था आरम्भमें अच्छी तरह मस्क नहीं होगी। जो देश स्वाशासनके लिए उपयुक्त हैं उन्हें जल्दीसे जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त करनेमें

सहायता दी जानी चाहिए। यदि इन देशोंको अब भी पश्चिमके प्रगतिशील देशोंकी सहायताकी आवश्यकता हो तो यह सहायता समुक्त राष्ट्र-संघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा विशेषज्ञों, परामर्शदाताओं और प्रशासकोंके रूपमें दी जानी चाहिए। इन देशोंको किसी एक देशका अनिश्चित कालके लिए गुलाम नहीं बनने देना चाहिए। किसी भी उपनिवेश या समाज्ञापित प्रदेशमें वहाँकी जनता का या वहाँके किसी क्षेत्रका सैन्यीकरण नहीं होना चाहिए।

साम्राज्यवादको सुधारनेके लिए दिये गये अन्य सुझाव इस प्रकार हैं :

(क) देशके मूल निवासियोंका भाग्य सफेद चमड़ीवाले प्रवासियोंके हाथ नहीं सौंपा जाना चाहिए। वूल्फ (Woolf) और बार्न्स् दोनों ही दक्षिणी अफ्रीका और केनियाकी अनेक कठिनाइयोंका मूल कारण वहाँके गौरे प्रवासियोंकी स्वार्थ-पूर्ण और सब कुछ हथिया लेनेवाली नीतिको ही बताते हैं। 'गै-भेद और वर्ग क्षेत्र विधेयक' (Class-areas Bill) आदिके आधार पर यदि निर्णय किया जाय तो ऐसा मालूम होगा कि सन् १९०९ में दक्षिण अफ्रीका संघको अधिराज्यका पद (Dominion Status) समयसे पहले ही दे दिया गया। सम्भवतः ब्रिटेनका उपनिवेश विभाग ह्यूजी लोंगोंके प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण नीति अपनाता।

यह बहुत जरूरी है कि साम्राज्यवादी देश या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या उपनिवेश की भूमिका विदेशीकरण और वहाँके मजदूरोंका शोषण न होने दे। दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीकामें मजदूरोंकी हालत करीब-करीब दामोंकी सी है। मजदूरों के "अधिकार तो कमसे कम और दायित्व अधिकसे अधिक" रहते हैं। बार्न्स्का कहना है कि दामना जैसी परिस्थितियोंका सुधार आज दिन यची-सुची दामताको मिटानेकी अपेक्षा वही अधिक महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक समस्या है। जातीय विद्वेष और अत्याचारको मूल देशवासियोंके हितमें बताकर इसका औचित्य सिद्ध किया जाता है।

(ख) पिछड़े देशोंमें वैयक्तिक पूँजीका अनियंत्रित प्रवाह न होना चाहिए। किसी भी देशके विकासमें निहित स्वार्थ, विशेष कर विदेशी स्वार्थ, प्रायः सबसे अधिक बाधा पहुँचाते हैं। ऐसी स्थितिमें बचनेके लिए यह जरूरी है कि पूँजी का प्रवाह समुक्तराष्ट्र सरकार नियंत्रणमें रखा जाय। बार्न्स् का सुझाव तो यह है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय औपनिवेशिक धन विनियोग समिति (International Board of Colonial Investment) की स्थापना की जाय, जो समाज्ञापित क्षेत्रोंमें लगानेके लिए सम्पत्ति निर्यात करे, बर्ज ले और सदस्य राष्ट्रोंमें ठेकोंका न्याय समत विवरण करे। वित्तीय और प्रशासकीय आवश्यकताओंको ध्यानमें रखते हुए जहाँ तक सम्भव हो, विराम योजनाओंके लिए वैयक्तिक सम्पत्ति (private investment) पर रोक लगनी चाहिए (४-३४)।

(ग) पिछड़े देशोंको उनकी मूल परम्पराओंके आधार पर दयानुमत्त शीघ्र स्वशासनके योग्य बनाया जाना चाहिए। बार्न्स् का विश्वास है कि भारतमें अंग्रेजी शासन यद्यपि मुचल या पर माय ही हृदयहीन था। इसका कारण वह यह

बनाते हैं कि देशी मंगडोंकी उपेक्षाकी गयी थी। "भारत बानिषोंकी दृष्टिमें मरकार का समूचा दावा उन पर ऊपरसे लादा गया था, वह उनके आह्वानका फल नहीं था।" बल्क ने लिखा था यदि "मध्य और आन्दोलनके बिना ही एंग्लिकाको साम्राज्यवादो दानताने छुटकारा दिया कर योग्य बाये, एंग्लिकाको पूर्णस्वाधीन नहीं कर देते तो क्रमाद और राष्ट्रीयताका गुबार इनकी जोरमें पड़ेगे कि उनके मानने महा-मुद्रकी विनोदिका फीकी जान पड़ेगी (८३ : ३०)।" आज दिन हम यही देख रहे हैं।

(घ) जब तक बाहरी नियंत्रण जरूरी हो तब तक पूर्ण नियंत्रणकी अपेक्षा आंगिक नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रणकी अपेक्षा देशी परम्पराओं और मस्कुनि पर आधारित अग्रप्रत्यक्ष नियंत्रण तथा एक राष्ट्रके नियंत्रणकी अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण अच्छा होगा।

(ङ) बार्न्म् ने एक बड़ा उपयोगी सुझाव यह दिया है कि यदि साम्राज्यवाद और पूँजीवादका एक दूसरेमें घनिष्ठ सम्बन्ध है इनलिए साम्राज्यवादमें व्यापक "सुधार करनेके लिए यह आवश्यक है कि मानवमै" पूँजीवादको हटाकर समाजवाद वापस किया जाय। बार्न्म् के ही शब्दोंमें 'ब्रिटेन में किसी न किसी प्रकारकी समाजवादी प्रवृत्ति हो चुकनेके बाद ही साम्राज्यवादी व्यवस्था का रुत सुधार कर सहनीय हो सकता है। "उत्पत्तिश्रमोकी स्वाधीनता और उनका विकास तथा ब्रिटेनका सामाजिकरण एक दूसरे पर आश्रित हैं। एकके बिना दूसरा नहीं हो सकता। वे एक ही अन्तर्मस्वच्छ प्रक्रियाके दो पहलू हैं"। आर० फॉक्स (R. Fox) का कहना है कि ब्रिटेनके मजदूर वर्गके मध्य और ब्रिटेनके सामाजिकरणके प्रयोग पर इन्हें अंग्रेजी साम्राज्यके लोगोंकी आकांक्षीके प्रसन्न अल्प रखकर विचार नहीं किया जा सकता। बार्न्म् और फॉक्सके कथनकी सत्यता आजके ब्रिटेनके समाजवादीमें सिद्ध हो गयी है। यद्यपि ईरान द्वारा अपने तेल उद्योगके सामाजिकरणका ब्रिटेन अवरोधन विरोधी भी है। मित्रके इन्माइल ने पिछले देशोंमें विदेशीयोंके कर्मचारियोंकी एक तालिका बनायी है जो साम्राज्यवादी शासकों और राजनीतिज्ञों पर भारी-भाति लागू होनी है। वह तालिका यह है—

"शासन नार तभी स्वीकार करो जब उसे स्वीकार करके तुम उन जानिवा बन्पान कर सको जिस पर शासन करो ;"

"जन्मदाकी एक उच्च सम्पत्ति तब उनका नेतृत्व कर ले जाओ, उसे गदेड कर नहीं ;"

"अपनी मानु-भूमिमें अपने सम्पत्ति तोड़ दो ;"

"अपने मरकारोंका मुकाबला करो और दिन राज्यका नमक पाओ उसकी सम्पत्तिओ अग्रण्ड रखो ;"

"जिन्नी भी ऐसे प्रश्न पर सम्मति देनेमें जिने स्वयं सुझाओ या जोर्ट विदेशी सरकार हल करना चाहती हो देशबानिषोंका प्रतिनिधित्व करो और ऐसा करनेमें—

"अपना आधार और अपना निर्देशक आदर्श वही रखो जो पूरे मंगारमें मरके

[illegible][illegible]

(८) निम्नलिखित दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
 (क) निम्नलिखित दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
 (ख) निम्नलिखित दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

बनाते हैं कि देशी मण्डनोंकी उपेक्षाकी गयी थी। “भारत वार्मियोंकी दृष्टिमें सरकार का समूचा ढांचा उन पर ऊपरसे लादा गया था, वह उनके आह्वानका फल नहीं था।” बूलफ ने लिखा था यदि “मंधर्ष और आन्दोलनके बिना ही एजियाको साम्राज्यवादी दामताने छुटकारा दिया कर मोरोप वाले, एजियाको पूर्णस्वाधीन नहीं कर देते तो फमाद और राष्ट्रीयताका गुवार इतनी जोरसे पड़ेंगे कि उनके सामने महा-युद्धकी विभीषिका फीकी जान पड़ेगी (८३ : ७०)।” आज दिन हम यही देख रहे हैं।

(घ) जब तक बाहरी नियंत्रण जरूरी हो तब तक पूर्ण नियंत्रणकी अपेक्षा आंशिक नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रणकी अपेक्षा देशी परम्पराओं और सम्स्कृति पर आधारित अप्रत्यक्ष नियंत्रण तथा एक राष्ट्रके नियंत्रणकी अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण अच्छा होगा।

(ङ) बार्नेम् ने एक बड़ा उपयोगी सुझाव यह दिया है कि चूंकि साम्राज्यवाद और पूंजीवादका एक दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए साम्राज्यवादमें व्यापक “सुधार करनेके लिए यह आवश्यक है कि ‘मानुदेगमें’ पूंजीवादको हटाकर समाजवाद कायम किया जाय। बार्नेम् के ही शब्दोंमें, ब्रिटेन में किसी न किसी प्रकारकी समाजवादी प्रान्ति हों चुबनेके बाद ही साम्राज्यवादी व्यवस्था का रूप सुधार कर गहनीन हो सकता है। “उपनिवेशोंकी स्वाधीनता और उनका विकास तथा ब्रिटेनका सामाजीकरण एक दूसरे पर आश्रित हैं। एकके बिना दूसरा नहीं हो सकता। वे एक ही अन्तर्मैम्बद्ध प्रक्रियाके दो पहलू हैं”। आर० फॉक्स (R. Fox) का कहना है कि ब्रिटेनके मजदूर वर्गके मध्य और ब्रिटेनके सामाजीकरणके प्रश्नों पर इन्हें अंग्रेजी साम्राज्यके लोगोंकी आजादीके प्रश्नमें अलग रखकर विचार नहीं किया जा सकता। बार्नेम् और फॉक्सके कथनकी सत्यता आदके ब्रिटेनके समाजवादमें मिट्ट हो गयी है। यद्यपि ईरान द्वारा अपने तेल उद्योगके सामाजीकरणका ब्रिटेन जबरदस्ती विरोधी भी है। मिस्रके इस्माइल ने पिछड़े देशोंमें निवेशियोंकी कर्तव्योंकी एक तालिका बनायी है जो साम्राज्यवादी शासकों और राजनीतिज्ञों पर भारी-भारि लागू होनी है। वह तालिका यह है—

“शासन भार तनी स्वीकार करो जब उसे स्वीकार करके तुम उस ज्ञानिका सम्प्राप्त कर सको जिस पर शासन करो ;”

“जनताको एक उच्च सम्मता तक उसका नेतृत्व कर ले जाओ, उन्हें सदेव कर रही ;”

“अपनी मानु-भूमिने अपने सम्पन्न तोड़ दो ;”

“अन्य सरकारोंका मुकाबला करो और जिस राज्यका नामक राजा उसकी सम्प्रभुताको अमण्ड रखो ;”

“जिगी भी ऐसे प्रश्न पर सम्मति देनेमें जिसे स्वयं तुम्हारी या बोर्ड निदेशी सरकार हल करना चाहती हो देशवासियोंका प्रतिनिधित्व करो और ऐसा करनेमें”—

“अपना आधार और अपना निर्देशक आदर्श वहीं रखो जो पूरे समारमें सबसे

लिए व्याप-मगत और उच्च हो, और जो उस देशके निवासियोंके लिए मध्यमे अधिक बन्धावश्रम हो, जिनकी सेवा मुम कर रहे हो।”

अन्तर्राष्ट्रीयतावाद (Internationalism)

सभी देशोंके विचारशील लोग अब इस बातकी आवश्यकता अनुभव करने लगे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय अराजकताको समाप्त करके उसके स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। मगार अब उतना लम्बा-खोश नहीं रह गया है जितना पहले हमारी कल्पनामें था। परिवहन (transport) और संचार (communication) के दृष्टिकोणों से हमारी सोचने की दूरी भी कम हो गई है। अधिक दृष्टिसे संचार एक इकाई है। देश (space) की दूरी और उमरे के पैदा होने वाले रहस्यमय भयको रेडियोने समाप्त कर दिया है। जैसा कि मदारियाग (Madariaga) ने कहा है : सड़कों और निवासोंके दृष्टिकोणसे सारा संचार एक बाजार सा हो गया है। जिन प्रकार बाजारके किसी एक कोनेकी सड़क आनन्द-मानवमें बाजार भर में फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार संचार के एक कोनेकी सड़क सारा संचार भर में फैल जाती है। आज वास्तवमें हम ऐसे संचारमें रह रहे हैं जिनमें एक देशके लोगोंकी समस्याका प्रभाव अनेक-पैछे सभी देशों पर पड़ता है। यदि मानव-जातिको उस दुर्भाग्यसे बचना है, जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है तो उसे राष्ट्रीय अलगावकी भावनाको छोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय ऐक्यकी भावनाको अपनाना होगा और राष्ट्रीय सम्प्रभुताके सिद्धान्तके स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय एकताके सिद्धान्त को कायम करना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीयतावादका ध्येय आत्मसम्मान और स्वतन्त्रता पूर्ण राष्ट्रीयता एक ऐसा परिवार है जो समानता, शान्ति और पारस्परिक सहयोगके सम्बन्ध सूत्रोंसे एकतामें बंधा हो। मानव विकासकी वर्तमान स्थितिमें तो अवश्य ही, एक स्वस्थ राष्ट्रीयतावाद स्वस्थ अन्तर्राष्ट्रीयतावादकी भूमिका बन सकता है। जोसेफ (Joseph) के शब्दोंमें : “राष्ट्रीयता मनुष्य और मनुष्य-जातिके बीच एक आवश्यक बन्ध है। सैनिकवाद तथा बटुटपन और युद्ध प्रियता अथवा वह जिसे पहले “नेडिओकी सी आक्रामक राष्ट्रीयता” कहा गया है, अन्तर्राष्ट्रीयतावादका निरिक्त शत्रु है। अनेक वर्गोंके प्रति निष्ठा रखनेके मतलब किसी प्रकार भी यह नहीं है कि दूसरे वर्गोंसे घृणा की जाय। सार्वजनिक, नैतिक, और आध्यात्मिक राष्ट्रीयतावाद अन्तर्राष्ट्रीयतावाद का मित्र है। विलियम लॉएड गैरीसन (William Lloyd Garrison) का कहना है कि पूरा संचार हमारा देश है, मानवमात्र हमारे देशवासी है। हम दूसरे देशोंकी धरती को उतना ही ध्यान करते हैं जितना अपनी राष्ट्रीयता की धरती की।

१९वीं सताब्दीके पहले योरोप की आतियोंको एक दूसरेके नदीप लानेके और एक दूसरेके बीच स्थायी शान्ति कायम करनेके लिए अनेक प्रयत्न किये गये। पर वे

मत्र प्रयत्न अमरुत रहे; क्योंकि उनका उद्देश्य यथार्थ्यति कायम रखना था। इन योजनाओंमें से एक योजना महान् फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ ड्यूक डु सल्लो (Duc de Sully) की थी। उसने अपनी योजना १७वीं शतीके आरम्भमें मग्राट् हेनरी चतुर्थ के नाम से प्रकाशित की थी। इस योजनाकी प्रधान विषयता यह थी कि हमने एक विश्व राज्यकी मध्यस्थानीय कल्पनाको छोड़कर तत्कालीन राज्योंकी स्वायत्तताको स्वीकार किया था। चाहे जितने अस्पष्ट रूपसे हो, पर मंत्री ने विश्व-शान्तिकी निम्नी भी योजनामें राष्ट्रीय स्वाधीनताकी आवश्यकता अनुभव कर ली थी। उन्होंने मध्य-काशीन विश्व-आदर्शकी अव्यावहारिकता भली-भांति समझ ली थी। उनकी योजनाकी महान् योजना (Grand design) कहा जाता है। इस योजनाके अनुसार योरोप एक ईसाई गणतन्त्र बनना जिसमें स्व बहिष्कृत रहता और तुर्की साम्राज्य (Ottoman Empire) मक्का शत्रु समझा जाता। इस गणराज्यमें ६ बगानुगत राजतन्त्र, पांच निर्वाचित राज्यतन्त्र और चार गणतन्त्र होते और रोमन-अर्मेन मग्राट् उसका अध्यक्ष होता। मग्राट्की महायन्त्रके लिए जो स्थायी समिति बनती उसमें ६४ सदस्य होते। ये लोग सार्वजनिक हितके प्रस्तावों का विवेचन करते और राष्ट्रों के बीच होने वाले झगड़ों का फैसला करके शान्ति कायम रखते। इस समितिके पास एक अन्तर्राष्ट्रीय म्यूल और जल सेना होती। इस मुद्रावकी काम के प्रधान मंत्रियों तारद्यू और हेरियो (Tardieu and Harriot) ने १९३२ के निदेशावलीकरण सम्मेलनमें फिरसे पेश किया था।

दूसरी महत्त्वपूर्ण योजना आबे डु सा पीर (Abbe de St. Pierre) ने उपस्थित की थी। यह योजना उत्रेख्ट (Utrecht) सम्मेलन (१७१३) के बाद तुरन्त पेश की गयी थी। पीर ने इस सम्मेलनमें भाग लिया था। नेपोलियनके युद्धोंके समाप्त हो जानेके बाद भी यह योजना योरोपके राजनीतिज्ञोंकी विचारधारा की प्रभावित करती रही। इस योजनाका मौलिक सिद्धान्त यह था कि सम्पूर्ण योरोप एक सम्राज्य है और किसी भी एक राज्यकी इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वह शेष योरोप पर हावी हो जाय। योरोपके सभी राज्योंको एक ऐसे मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होना था जिसके अनुसार वे प्रतिज्ञा करने कि वे एक दूसरेकी क्षेत्रीय अग्रगण्यताको काममें रखेंगे, शान्तियोंको कुचलेगे और राजाओंको उनके मित्रमण्डलों पर बनाये रखेंगे। यदि कोई राज्य इस करारको तोड़नेकी कोशिश करता तो उसके विरुद्ध शक्तिशाली उपक्रम किया जाता। राज्योंके बीच होनेवाले मतभेदोंको पचायत द्वारा मुद्राया जाता। उत्रेख्ट शान्ति नगर बनाया जाता। वहाँ राज्योंके प्रतिनिधियोंको "एक ऐसे मण्डल में जिनमें शान्ति कायम रखने और मन्त्रिके उद्देश्योंको पूरा करने तथा मण्डलके निदेशोंको कार्यान्वित करने के लिए बहुमतसे आवश्यक और उपयुक्त विधियाँ बनाने का अधिकार प्राप्त होता (७० : २३५-३६)"। यह योजना इसलिए अमरुत हो गयी कि इसमें मन्त्रियोंकी अभिरुता पढ़ने ही से मान ली गयी थी। इसका उद्देश्य बेजल यथार्थ्यति कायम रखना था। दूसरी बात यह थी

कि यह गण्य तानाशाही राजाओंके बीच होनेकी थी न कि देशोंकी जनताके बीच और इसलिए यह एक ऐसी व्यवस्थाकी स्थायी बना देना चाहती थी जिसका कोई औचित्य नहीं था। एक अन्तिम कारण यह था कि पीर इस राष्ट्रीय विचारके महत्त्व की नहीं समझ मने कि जहाँ तक सम्भव हो, राजनैतिक और राष्ट्रीय सीमाएँ एक ही होनी चाहिए।

पीर की योजना रुमोंके चिन्तनका आधार बनी। यह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अन्तर्राष्ट्रीय मध्यम और युद्ध स्वतंत्र राज्योंके सम्बन्धमें पैदा होने हैं। इस लिए उन्होंने मध्याय योरोरकी योजना प्रस्तुत की; जिसका मग्यन विधि सामनके रूपमें होना। राज्योंको एक अविच्छेद्यताय मठबन्धन (irrevocable alliance) में शामिल होना था। मगदे, यह नियमने तय विषय जाने। मध्य अपने मध्यम राज्योंके प्रादेशिक अग्रगण्यताकी तथा उनकी मग्यान्मीन सामन पद्धतिकी गारण्टी देना। राज्योंके आकाशका विचार विषय बिना सभी राज्योंको कावेय या प्रतिनिधि समामें मतदान का समान अधिकार और मध्यम राज्योंका बारी-बारीसे अप्पगणीय पर पर आसीन होना इस योजनाके अन्य मिद्धान्त थे। यदि कोई मध्यम राज्य सविदा की शर्तोंको तोड़ना तो उसे मार्क्जनिज पानु पॉषित किया जाना और उसके विरुद्ध सैनिक बार्बरवाड की जानी। प्रतिनिधि समामें पूर्णाधिकार प्राप्त प्रतिनिधियोंको तीन-चौथाई मतसे ऐसे नियम बनानेका अधिकार था जो सभी मध्यमोंके ऊपर लागू विषय जा सक्ते थे।

जैरमी बेंथम (Jeremy Bentham) ने अपनी पुस्तक "प्रिन्सिपल्स ऑफ इन्टरनेशनल लॉ" में रुमोंके कार्य को अपने हाथों में लिया। बेंथमको अंग्रेजी भाषामें सबसे पहले "इन्टरनेशनल" (अन्तर्राष्ट्रीय) शब्दका उपयोग करनेका श्रेय है। उन्होंने पृष्ठको "बड़ीसे बड़ी शान्ति" बनाया था। उनका विद्वान था कि रक्षात्मक सन्धियों, मार्क्जनिज गारण्टियों, निष्ठाश्रीवरण और औपनिवेशिक साम्राज्योंकी त्यागनेसे युद्धसे दूर किया जा सकता है। उनका निश्चयन मन था कि गुप्त कूटनीति, घुगी प्रणालियाँ (tariffs), सरकारी उपहार और उपनिवेश, ये सब विश्व-शान्तिमें बाधक हैं और इसलिए इन सबका उन्मूलन किया जाना चाहिए। विभिन्न देशोंकी विधियों को महिना-बद्ध (codify) करके बेंथम ने अन्तर्राष्ट्रीयतावादकी एक और सेवा की है।

१८वीं शतीके अन्तिम महान् दार्शनिक जिन्होंने विश्वशान्तिकी समस्याका विवेचन किया, इमैनुअल काण्ट (Immanuel Kant) थे। अपने प्रसिद्ध निबन्ध *Towards Eternal Peace* में उन्होंने शान्ति कायम रखनेके लिए एक मधीय योजना बनायी थी। काण्ट द्वारा निर्धारित मिद्धान्त ये हैं: "सभी राज्योंकी स्वाधीनताकी सुरक्षा, किसी दूसरेके मामलेमें हस्तक्षेप न करनेकी नीतिका पालन और स्थायी सेनाका क्रमिक उन्मूलन।" उन्होंने सभी राज्योंके लिए गणनीय सविधानों का और विश्व नागरिकताका मधर्षन किया। पर उनकी शिक्षाओंका घटनाचक्र पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा।

१९वीं शतीके आरम्भमें नेपोलियन ने विश्व-शान्तिकी समस्या पर कुछ ध्यान दिया। यदि हम "लेकासे" (Les Cases) के अमिलेसो पर विश्वास करें तो, राष्ट्रीयताके आवार पर योरोपका मानचित्र नये सिरेसे बनाया और इन नव निर्मित राज्योंको फ्रांस्के नेतृत्वमें एक संघमें शामिल करना ही नेपोलियन के मुद्दोका उद्देश्य था।

२०वीं शती में अन्तर्राष्ट्रीयतावाद : राष्ट्र संघ (Internationalism in the 20th Century: The League of Nations). अन्तर्राष्ट्रीयताके क्षेत्रमें सबसे अधिक प्रगति २०वीं शतीके प्रथम चरणमें हुई—कमसे कम इस दृष्टिमें कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गयी। यदि कभी यी तो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग भावनाकी और अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की। फिर भी जनमत धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीयतावादकी ओर झुक रहा था और यह आशा करना युक्ति-भगत हो गया था कि राष्ट्रीयतावाद और साम्राज्यवादकी भांति अब अन्तर्राष्ट्रीयतावादको मनुष्यकी विचार-धाराका एक स्वाभाविक अंग बन जानेमें अधिक समय नहीं लगेगा।

राष्ट्र-संघ (League of Nations) का जन्म १ जनवरी मन् १९२० को हुआ। यद्यपि यह किसी एक अकेले व्यक्ति या किसी एक अकेली पीढ़ीका कार्य नहीं था, फिर भी राष्ट्र संघको एक व्यावहारिक वास्तविकताका रूप देनेमें अन्य किसी भी राजनीतिज्ञकी अपेक्षा वुड्रो विल्सन ने अधिक महत्ता दी थी। विल्सन द्वारा घोषित प्रसिद्ध १४ सूचोंमें से अन्तिम सूचको व्यावहारिक रूप देनेके लिए राष्ट्र संघकी स्थापना हुई थी। इस सूचमें उन्होंने घोषित किया था कि सरकारों तथा छोटे राज्यों की रक्षाक्षमता तथा प्रादेशिक असंख्यताकी पारस्परिक गारण्टी देनेके उद्देश्य से निश्चित प्रमविशयो (covenants) के अनुसार राज्योंका एक सामान्य संगठन बनाया जाना चाहिए। राष्ट्र संघका श्रीगणेश बुरे ढंगसे हुआ क्योंकि योरोपीय राजनीतिज्ञोंका समर्थन प्राप्त करनेके लिए (और इन राजनीतिज्ञोंमें राष्ट्र संघके प्रति वैकल्पिक मौखिक उत्साह था) विल्सन को उन शान्ति सन्धिषोमे राष्ट्र संघको बाध देना पड़ा जिनमें अनेक अन्ध्यायपूर्ण और अव्यावहारिक गनें जुड़ी हुई थी और जो जगत् शान्तिकाल (uneasy piece) (१९१९-२९) में उत्पन्न होने वाली अनेक कठिनाइयोंके लिए जिम्मेदार थी।

प्रमविशय (covenant) की प्रस्तावनामें राष्ट्रसंघके उद्देश्य इस प्रकार घोषित किये गये हैं :—

‘इस गणमें शामिल होने वाले राष्ट्र

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम करने के उद्देश्यसे;

मुद्दका मार्ग न अपनावेका दायित्व स्वीकार करके;

राष्ट्रोंके बीच सुले, न्याययुक्त और सम्मानपूर्ण सम्बन्धोंको स्थापित करके,

मरवाओके बीच पारस्परिक व्यवहारके निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय विधिसे दुश्मन-पूर्वक स्थापित करने,

और गुप्तगति राष्ट्रोंके बीच पारस्परिक व्यवहारमें न्याय वायम रखर और जितने भी सधिजन्य दायित्व हो उन सबका पूरी निष्ठामें आदर करते हुए राष्ट्र-समूहके इस प्रगतिवादी स्वीकार करते हैं।

प्रगतिवादी धाराओंका ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेमें राष्ट्र-समूहके निम्न-लिखित उद्देश्य जान पड़ते हैं—

- (क) शान्ति सम्मेलन द्वारा स्थापित यथान्वयि (status quo) को स्थायी रूपमें वायम रखना,
- (ख) कुछ निश्चित प्रणामकौष और निरीक्षणक बन्धनोंको पूरा करना, जैसे राष्ट्रोंके अलग सम्बन्धोंकी रक्षा, ईजिप्टके स्वतन्त्र गृहस्थी देख-रेख, सारधाटीका प्रणामन और समानाधिकार प्रणाली (mandates system) का वायान्वय;
- (ग) जन-स्वायत्त, विन, आयात और निर्यात तथा इसी प्रकारके अन्य मागनेके सम्बन्धित समस्याओं और सामाजिक प्रश्नों पर ध्यान देना।
- (घ) युद्धोंका निवारण (prevention) और समझौता शान्तिपूर्ण निपटारा।

राष्ट्र-संघ—सदस्यता और प्रत्याहरण (Membership in the League and Withdrawal) राष्ट्र-समूहका आरम्भ ४२ प्रारम्भिक सदस्योंमें हुआ। प्रगतिवादी धाराओंके अनुसार नये सदस्योंके प्रवेशके लिए हमारे दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति जरूरी थी। सदस्यताकी दान यह थी कि सदस्य बननेवाले राष्ट्रोंको मध्य द्वारा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वको निभाने और निरन्तरस्वीकरण सम्बन्धी नियमोंको पालन करनेका वचन देना पड़ता था। सैन-सैरियों और आरम्भिकीय जैसे बहुत छोटे राष्ट्रोंको सदस्यतासे वञ्चित रखा गया था। स्विट्जरलैण्ड को सदस्य बना लिया गया था। यद्यपि उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अपनी सदस्य स्थिति के कारण अपने सैनिक दायित्वोंको पूरा नहीं करेगा। मध्यराज्य अमेरिका समझा कभी सदस्य नहीं बना क्योंकि अमेरिका की सीनेट ने प्रगतिवादी स्वीकार नहीं किया। पर अमेरिका ने सबकी अनेक बार-बारियोंमें सहयोग दिया। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायके स्थायी न्यायालयमें कुछ विन्यात अमेरिकियोंने न्यायाधीशोंके पद पर काम किया और हारे हुए देशोंमें जो रकमें जति हुए देनोंको युद्धकी क्षतिपूर्ति के लिए देनेके लिए निर्धारित हुई थी (reparations) उनको कम करना देनेमें कुछ अमेरिकियोंका महत्वपूर्ण योग था।

राष्ट्र-समूहकी सदस्यता छोड़नेके लिए दो बारकी अग्रिम सूचना आवश्यक थी। पर यदि प्रगतिवादमें किया गया कोई मजबूत किसी सदस्यको अस्वीकार हो तो सदस्यतासे अलग होनेके लिए यह प्रतिबन्ध न था। अलग होनेके पूर्व अपने सभी दायित्व पूरे कर देना सदस्यके लिए जरूरी था। प्रगतिवादी उल्लंघन करनेवाले

मदम्यको निकाला जा सकता था। द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होनेमें पूर्व जर्मनी, जापान और इटली, इन तीन राष्ट्रोंका राष्ट्रमन्त्र अलग होना महत्वपूर्ण था।

राष्ट्र-संघके अंग (The Organs of the League).

(क) असेम्बली या सभा (Assembly). प्रत्येक मदम्यको एक ओट प्राप्त था। निम्नलिखित इसका मतलब यह था कि राष्ट्रमन्त्रका नियंत्रण छोटे राज्यों के हाथोंमें था, क्योंकि बहुमत उन्हींका था। प्रत्येक मदम्य-राष्ट्रको तीन प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार था, पर उनका वोट एक ही होता था। इस सम्बन्धमें भारत और ब्रिटिश साम्राज्यके स्वशासित उपनिवेशोंका गणना पृथक् राज्योंके रूपमें होती थी। प्रतिनिधियोंका चयन प्रत्येक देशकी सरकारें करती थीं, और इस प्रकार प्रतिनिधि, जनताओं प्रतिनिधि न होकर सरकारोंके प्रतिनिधि होते थे।

प्रथम विश्व युद्ध आरम्भ होने तक इस सभाकी बैठक जेनेवा में प्रतिवर्ष एक बार होती थी। विशेष अधिवेशन करनेकी भी व्यवस्था थी। कार्यवाही अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओंमें होती थी। असेम्बली या सभाका बहुत-सा कार्य समितियोंके द्वारा होता था। राष्ट्र-संघके महत्वपूर्ण कार्योंको करनेके लिए ६ स्थायी समितियाँ थीं। निर्णायक विवाद (final debates) सभाके पूरे अधिवेशनमें होते थे। सभाकी कार्य-सूची (agenda) मन्त्र महासभा परिषदके अध्यक्षके परामर्श में तैयार करता था। पिछले अधिवेशन द्वारा अथवा परिषद द्वारा या मन्त्रके किसी मदम्य द्वारा उठाये गये प्रश्न कार्य-सूचीमें शामिल कर लिये जाते थे। सभाका सभा-पतित्व एक निर्वाचित सभापति करता था। सभापतिकी महायत्नाके लिए बारह उपसभापति होते थे जिनमें से ६ उपसभापति स्थायी समितियोंके अध्यक्ष होते थे।

सभाके कार्योंमें से एक कार्य दो तिहाई बहुमतसे नये राष्ट्रोंको मदम्य बनाना था। परिषदके नौ स्थायी सदस्योंमें से तीनका निर्वाचन भी प्रतिवर्ष सभा बहुमतसे करती थी। ९ वर्षोंमें एक बार यह सभा, और परिषद दोनों मिलकर, स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयके पन्द्रह न्यायाधीशों और ४ उपन्यायाधीशोंका निर्वाचन भी बहुमतसे करती थी। परिषद द्वारा महामंत्रीके पद के लिए मनोनीत व्यक्तिकी स्वीकृति भी यह सभा बहुमतसे देती थी। धारा २६ के अनुसार प्रसविशयों में गोपनीय करनेका अधिकार भी इस सभाको था।

एक परामर्शदाता सभाके रूपमें इस सभाका कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत था। राष्ट्र-संघ की कार्य-परिधिमें भीतर आनेवाले और समारोहो शान्तिको संकटमें डालनेवाले किसी भी प्रश्न पर विचार करनेका अधिकार सभाको था। राष्ट्र-संघका कोई भी मदम्य सभा या परिषदका ध्यान किसी ऐसे प्रसङ्गकी ओर आकर्षित कर सकता था जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिको या राष्ट्रोंके बीच स्थापित सद्भावनाको—जिन पर विश्व शान्ति टिकी थी—खतरा हो रहा हो। सभाको अधिकार था कि सदस्योंका ऐसी गतिविधियों पर धिक्कर देनेका विचार करनेकी सलाह दे जो अव्यावहारिक हो चुकी हो।

यापिक बजटको स्वीकार करना समारा विनोय वाम था। यह बजट ए. आधुनिक युद्धवोननी लागनना पाचवा भाग ही होना था। मदाराया (Madariaga) के अनुसार १९३६ में समारने सम्प्रीकरण पर १ पदम (10 billion) डॉनर तर्च चिये थे। पर राष्ट्रगपरा औमन बजट ८० लाख (8 million) डॉनरवा ही होना था अर्थात् सम्प्रीकरण पर तर्च होनेवाली रकमना १/१२५० वां भाग ही। बजट राष्ट्र मपरा मन्त्रिपालय तैयार करता था। ममा बजटमें सम्प्रीकरण कर सवो यी धोर यही तय करनी थी कि बजटको पूरा करनेके लिए किम मदम्य राष्ट्रको वित्तनी रकम देनी चाहिए। मपूवे बजटरी रकमको एक हजार इकाइयोंमें बाटा जाता था। हर मदम्यके नाम उनके आकार, उमरी जन मत्या और उनके राजनीतिक महत्त्वके अनुसार इकाइयों की कुछ मत्या निदिचन कर दी जानी थी। सम्पूर्ण आयना लगभग आधा मन्त्रिपालय पर, निहाई अन्तराष्ट्रीय श्रम कार्यालय पर और दसवा भाग म्यामालय पर ध्यय होता था।

समावा समठन ही कुछ ऐसा था कि उमवा कायं सामान्य प्रार (general nature) का ही रहा। उनके आकार और उमकी महत्ताने उनके लिए परिपदकी भाति तेजीसे काम कर गवना पठिन कर दिया। फिर भी ममा परिपदके कायोंका सामान्य निरीक्षण करनी थी।

वई एक प्राविधिक समठन (technical organisations) ममा तथा परिपद की सहायता करते थे। ममाके कायोंमें एक थापा यह थी कि यह अधिवेशनमें उपायित सदस्यांकी सर्वममतिके बिना कोई भी नियम नहीं कर सकती थी। पर चूकि उनके अधिराम कायं मुन्नाय या मिफारिमांके रूपमें होते थे इसलिए बहुमत ही बाकी सममा जाता था। समामे भाग लेनेवाले प्रतिनिधि अपनी-अपनी सरकारोता प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए वे लोग स्वतंत्र रूपसे अपना मत नहीं दे सकते थे। उन्हें अपने-अपने देशके वैदेशिक विभाग के निर्देशोंके अनुसार मत देना होता था।

इन खासिओके बावजूद ममा एक बहुत उपयोगी मत्या थी। अन्तराष्ट्रीय शिक्षायता और सगडों पर विचार विमर्श करनेके लिए वह एक अच्छे मचका वाम करती थी। किसी देशके ऐसे आन्तरिक मसलों पर भी, जिनके सम्बन्धमें राष्ट्र मय की कोई भी मत्या पचायनवा काम नहीं कर सकती थी, ममा द्वारा ग्यारहवी धारा के अन्तर्गत विचार किया जा सकता था; और यदि ऐसे मसलेका कोई अन्तराष्ट्रीय महत्त्व होता था तो उनके बारेमें ऐसी सन्धि करायी जा सकती थी जो उस सन्धि को स्वीकार करने वाले राष्ट्रों पर लागू होती थी। यद्यपि परिपद अधिक प्रभावपूर्ण थी पर जापान द्वारा मचूरिया को हडपने के मामलेमें ममा परिस्थितिका निराकरण बहुत अधिक प्रभावपूर्ण ढंगसे कर सकनेमें समर्थ हुई।

(ख) परिपद (The Council). परिपदके सदस्य तीन कोटिके होने थे: (१) स्थायी, (२) अस्थायी और (३) विनोय। स्थायी सदस्य वे मित्र राष्ट्र थे जिन्होंने १९१८ में युद्ध जीता था। जर्मनी को १९२६ में परिपदका स्थायी सदस्य

वनाया गया पर राष्ट्र सभको छोड़ने पर उनसे यह मदस्यना माँ दी।

प्रतिवर्ष परिषदकी चार नियमित बैठके होती थीं। विशेष अधिवेशनोके लिए भी व्यवस्था थी। प्रत्येक अधिवेशनके आरम्भमें राष्ट्र सभका महामंत्री बतलाना था कि परिषदके पिछले निर्णयोंको कार्यान्विन करनेके लिए क्या-क्या किया गया। परिषदके अध्यक्ष और उपाध्यक्षका निर्वाचन प्रतिवर्ष बहुमत द्वारा होता था। एक ही व्यक्ति पुनः दूसरे वर्षके लिए नहीं चुना जा सकता था।

अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ोंका निपटाना परिषदका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। जिन झगड़ोंमें दोनों पक्ष पचापन अथवा अदालतमें फ़ैसला करवाना अस्वीकार कर देते थे और जो झगड़े इन तरीक़ोंमें नहीं निपटारे जा सकते थे उनके लिए प्रमविदा में यह व्यवस्था थी कि उन्हें परिषदके पास उचित कार्रवाईके लिए भेजा जाय। इनका मतलब यह था कि वे झगड़े जिनका अदालतों फ़ैसला नहीं हो सकता था अथवा 'राजनीतिक' झगड़े परिषदकी अधिकार सीमाके अन्दर आते थे। जब तक कोई भी झगड़ा परिषद या सभाके विचारार्थीन होता था तब तक सम्बन्धित पक्षोंके लिए यह आवश्यक था कि वे युद्ध न करें।

परिषदके अधिकारोंको सदस्य राष्ट्रोंके पारम्परिक सन्धिपौने बढ़ाया जा सकता था। प्रमविदा भग करने वाले राष्ट्रोंके विरुद्ध अनुशास्तिमूलक कदम उठावेका अधिकार परिषदको था। परिषद और सभा दोनों मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशोंका निर्वाचन और महामंत्रीकी नियुक्ति करती थी। वे दोनों मिल कर परिषदके सदस्योंकी सन्धि भी बढ़ा सकती थी। सभाकी तरह परिषदमें भी सर्वसम्मतिमें ही निर्णय और निश्चय किये जा सकते थे। पर कार्रविधि (procedure) तथा इनो प्रकारके अन्य मामलोंमें बहुमत ही बाज़ी होता था।

प्रमविदाने सभा और परिषदके पारम्परिक सम्बन्ध स्पष्ट तौर पर निश्चिन नहीं किये थे। कुछ लोगोंने इन दोनों सम्थाओंकी तुलना आधुनिक विधायिकाके दोनों सदनोंकी की है और कुछ लोगोंने सभा की तुलना मन्त्रिमंडल और परिषदकी तुलना मंत्रिमण्डल में की है। ये दोनों ही तुलनाएं भ्रामक हैं। सभाका कार्य अधिकांश रूपमें विधायी (legislative) नीतिमें रहता था और परिषदका कार्य अधिकांश रूपमें अर्ध-न्यायिक (semi-judicial) और प्रशासी (administrative) होता था।

(ग) सचिवालय (The Secretariat). सचिवालय राष्ट्र सभका स्थायी प्रशासी भग था। इसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासी अधिकार (civil service) कहा जा सकता है। कार्यालयिका न होने हुए भी इसे प्रशासी अधिकार प्राप्त थे। इसका प्रधान राष्ट्र सभका महामंत्री होता था, जिनकी नियुक्ति सभाके बहुमतके अनुमोदन से परिषद करती थी। अन्य सदस्यों और सदस्योंकी नियुक्ति परिषदके अनुमोदन से महामंत्री स्वयं करता था। सचिवालयमें नियुक्त किये जानेके लिए कोई प्रति-योगी परीक्षा नहीं होती थी, पर नियुक्ति करनेमें इस बातका ध्यान रखा जाता था कि व्यक्तिमें अपने पदके अनुकूल योग्यता हो और सचिवालयके पदोंके विवरण

वा अनुपात राष्ट्र संघके सदस्य राष्ट्रोंके बीच उचित रूपमें बना रहे। नियुक्ति हो जाने पर नियुक्त किये गये व्यक्तिको अपनेको राष्ट्र सघका सेवक मानना होता था, न कि उन राष्ट्रवा जिसका वह नागरिक होता था। सचिवालयके सदस्योंके वर्तमान राष्ट्रीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय होने थे। सचिवालयके सदस्योंको अपने कार्यकालमें अपनी सरकारोंमें विभिन्न प्रकारका सम्मान आदि प्राप्त करनेकी आज्ञा नहीं थी।

सचिवालयका काम था आकड़े एकत्र करना, परिपद और सभाके अधिवेशनों की कार्यसूची बनाना, अधिवेशन बुलाना, रिपोर्ट रखना, सदस्य राष्ट्रोंको उनकी संजुरीके लिए निर्णयों और प्रवक्त्यों (arrangements) की सूचना देना, सूचना और कार्रवाईके लिए दिये गये मुझावोंको भेजना, समविदे तैयार करना और तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंको मुलमानेके लिए मुझाव देना। सचिवालय राष्ट्र सघकी पत्रिका (official journal) तैयार और प्रकाशित करता था जिसमें सभा तथा परिपदकी कार्यवाही छपती थी। अन्तर्राष्ट्रीय मामलोंमें सचिवालय एक स्थायी मलाह्वारका काम करता था।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायका स्थायी न्यायालय (The Permanent Court of International Justice). १९२० के पहले जबकि इस न्यायालयकी स्थापना हुई थी, मही मानेमें कोई अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय था ही नहीं, स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयकी बात तो दूर है। इस न्यायालय को उन सभी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय देनेका अधिकार प्राप्त था जो सम्बन्धित पक्षों द्वारा निर्णयके लिए उनके सामने पेश किये जाते थे। परिपद अथवा सभा द्वारा भेजे गये सभी मामलों पर न्यायालय परामर्शमूलक सम्मति भी देता था। यद्यपि इस सम्मतिका मान लिया जाना अनिवार्य नहीं था पर वह प्रायः स्वीकार कर ली जाती थी। राष्ट्र सघके प्रसविदाकी व्याख्या करना न्यायालयके कार्य क्षेत्रमें बाहर था। यह कार्य सदस्य राष्ट्र करते थे।

इस न्यायालयके अधिकार पूर्ववर्ती हेतु न्यायालयकी अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक थे। न्यायालयको सन्धियों और अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्बन्धी प्रश्नोंकी व्याख्या करने, अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व भग करनेके दण्ड रूप मुझावोंकी रकम और उमका स्वरूप तय करने और यह निर्णय करनेका अधिकार था कि ऐसी कोई स्थिति है या नहीं जिसके प्रतिष्ठित हो जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व भग हो जाय। पर इन मामलोंमें न्यायालयका अधिकार-क्षेत्र केवल उन्ही सदस्य राष्ट्रों पर लागू होता था जो "वैकल्पिक धारा (optional clause)" पर हस्ताक्षर कर देते थे। न्यायालय द्वारा तय न किये जा सकने वाले मामलोंको राष्ट्र सघके सदस्य परिपदके सम्मुख जाच-पड़ताल अथवा पंचायती फैसलोंके लिये पेश करते थे। बन्दरगाहों, जल मार्गों, रेलों तथा अन्य ऐसे ही मामलों पर न्यायालयका पंचायती फैसला अनिवार्य होता था।

निर्णय बहुमत द्वारा किये जाते थे और उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती

थी। पर यदि मामले में सम्बन्धित किसी पक्षको कोई ऐसा नया तथ्य मालूम हो जाय, जिससे इस मामलेमें सम्बन्ध हो तो वह निर्णय पर फिरसे विचार करनेकी माग "तथ्य ज्ञात होनेसे ६ महीनेके भीतर और निर्णयके १० वर्षके भीतर कर सकता था (= ५८८)". निर्णय देनेमें न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओंका और इन प्रथाओंके अन्तर्गत उन नियमोंका उपयोग करता था जो सविदा करने वाले राज्यों की स्वीकृतिमें वनते थे। अन्तर्राष्ट्रीय रीति रिवाजों, सम्य राज्यों द्वारा स्वीकृत विधिके सामान्य सिद्धान्तों और विख्यात न्याय शास्त्रियोंके निर्णयों तथा प्रसिद्ध विधि लेखकोंकी सम्मतियोंका भी उपयोग किया जाता था।

१९३० में न्यायाधीशोंकी संख्या १५ और उनकी कार्यविधि ९ वर्ष थी। न्यायाधीशोंके निर्वाचनकी पद्धति कुछ ऐसी थी कि छोटे और बड़े सभी राष्ट्रोंके प्रतिनिधि न्यायाधीश चुने जाते थे। यदि किसी मामलेके पक्ष या विपक्षके किसी राष्ट्रका नागरिक न्यायाधीश नहीं होता था तो वह एक न्यायाधीश चुन सकता था। नियुक्तिकी शर्तोंको पूरा न करने पर अपने सहयोगियोंकी सर्वसम्मतिसे किसी भी न्यायाधीशको उसके पदसे हटाया जा सकता था।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (The International Labour Organisation). अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनके निम्नलिखित तीन अंग थे (१) सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन, (२) शासिका परिषद और (३) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय। सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलनमें प्रत्येक सहयोग करने वाली सरकारके चार प्रतिनिधि होते थे। इनमें से दो सरकारके, एक पूँजीपति वर्गका और एक मजदूर वर्गका प्रतिनिधि होना था। यद्यपि पूँजीपति और मजदूर वर्गके प्रतिनिधियोंका चयन भी प्रत्येक देशकी सरकार ही करती थी फिर भी यह चयन सम्बन्धित औद्योगिक संगठनके परामर्शसे किया जाता था। प्रतिनिधियोंको व्यक्तिगत रूपमें अपना मत देनेका अधिकार प्राप्त था। इससे यह सम्भव था कि सम्मेलनके सभी श्रमिक वर्गके प्रतिनिधि पूँजीपतियोंके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वोट दें। जो राज्य राष्ट्र मणके सदस्य नहीं थे उन्हें भी प्रतिनिधि भेजनेकी अनुमति थी।

सम्मेलन दो तिहाई मतोंसे प्रस्तावोंको स्वीकार करता था। ये प्रस्ताव मित्रा-रिणों अथवा अभिसमयों (conventions) के रूपमें होते थे। दोनों ही अवस्थाओं में उन्हें लागू करनेके लिए सम्बन्धित सरकारोंकी स्वीकृति आवश्यक थी। सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर वे देशकी विधियोंकी भांति ही शक्तिमान हो जाते थे। सभी मित्रारिणों या अभिसमयोंको सम्बन्धित देशोंके राष्ट्रीय विधायिका अथवा अन्य उपयुक्त मस्याओंके समक्ष कार्रवाईके लिए एक वर्षके भीतर ही पेश करना होता था। भले ही उस देशके प्रतिनिधियोंने सम्मेलनमें उसके विरुद्ध ही अपना मत दिया हो। इस व्यवस्थाका दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया गया।

मासिक परिषदमें २४ सदस्य होते थे। बारह सरकारी प्रतिनिधि, छ. मजदूर

वर्षांके प्रतिनिधि और छः पूजोपनिषोंके प्रतिनिधि। इनका कार्यकाळ तीन वर्षका होता था। बारह सरकारी प्रतिनिधियोंमें से आठनी नियुक्ति समारोह प्रधान औद्योगिक देशों द्वारा की जाती थी और चार सम्मेलन द्वारा चुने जाते थे। पूजोपनिषों और श्रमिकोंके प्रतिनिधियोंका चुनाव सम्मेलनमें पूजोपनिषों तथा श्रमिकोंके प्रतिनिधि करते थे।

वासिन्गटन-परिषद्का अधिकेशन हर तीसरे महीने होता था। परिषद् सम्मेलनकी कार्यवालि (agenda) तैयार करती थी, अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालयके मंचालककी नियुक्ति और कार्यालयके कामका निरीक्षण करती थी। मंचालककी देख-रेखमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय "अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्बन्धी सूचनाएं, एकत्र करना था और उन्हें अनेक रूपोंमें प्रकाशित करना था, वार्षिक सम्मेलनोंके लिए कार्यवालि तैयार करता था, श्रमिक सन्धियोंको स्वीकार करनेकी राश्योंमें माग करता था और उनके कार्यान्वयनका निरीक्षण करता था (२५१)।" श्रमिक सन्धियोंको स्वीकार करनेमें राष्ट्रोंके मार्गमें जो रुठिनाइयां होती थीं उन्हें दूर कर इन सन्धियोंको स्वीकार किये जाने योग्य बनानेकी दिशामें अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय महत्वपूर्ण कार्य करता था।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनका प्रधान उद्देश्य सारे संसारमें एक ही श्रमिक विधि लागू करना था, यद्यपि जापान, चीन और भारतके मामलोंमें भिन्न जलवायु तथा परिस्थितियोंके कारण कुछ अपवाद भी किये गये। जो उपयोगी अभिसमय मजूरकी गयी उनमें से एक, आठ घण्टे प्रतिदिन और अड़तालिम घण्टे प्रति सप्ताह कार्यका निश्चय है। ऐसा ही एक दूसरा अभिसमय था—१४ वर्षसे कम उम्रके बच्चोंको नौकर रखनेका निषेध। जहां तक भारतका सम्बन्ध है, १४ वर्षसे कम उम्रके बच्चोंको नौकर नानो, फैक्ट्रियों तथा यानामातमें काम करनेसे रोक गया।

जिन राष्ट्रोंने इन अभिसमयों (conventions) को स्वीकार कर लिया था वे हमेशा इनका पालन नहीं करते थे। वामिका परिषद्की इस बातका अधिकार था कि वह इस तरहके उल्लंघनोंका प्रकाशन करे और राष्ट्रसंघके महामन्त्रीसे बहे कि वह ऐसे उल्लंघनोंकी जांच करनेके लिए आयोग नियुक्त करे। यदि आयोगकी रिपोर्टमें कोई पक्ष अमनुष्य होता था तो उसे स्थायी न्यायालयमें अपील करनेका अधिकार था और इस न्यायालयका निर्णय अन्तिम होता था। न्यायालय अथवा जांच-मंडाल करनेवाला आयोग अपराधी राष्ट्रके विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई किये जानेका आदेश दे सकता था। यद्यपि ऐसा कभी किया नहीं गया।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन अपनी खासियोंके बावजूद उपयोगी मस्या थी। यह संगठन राष्ट्र संघके कार्योंमें एक प्रशमनीय कार्य था। लास्की ने श्रम सम्बन्धी अभिसमयोंका महत्त्व इस प्रकार आका है—(क) ये अभिसमय समारोह सम्मुख औद्योगिक जीवनके उस न्यूनतम मानदण्डकी घोषणा करती हैं जो आधुनिक राज्योंकी सामान्य चेतना (common consciousness) को स्वीकार होता है। (ख) प्रत्येक

सम्बन्धित राष्ट्रके मजदूर आन्दोलनके हाथोंमें वह एक यथार्थ शक्ति है। (ग) सारे मसारमें गरीब लोगोंके कल्याणके लिए विधि निर्माणका जो मानदण्ड आवश्यक है उसे स्वीकार करवानेके लिए राज्यों पर दबाव डालनेका यह माधन है।

राष्ट्र-संघका मूल्यांकन (Appraisal of the League of Nations). राष्ट्र संघके बड़ेसे बड़े समर्थक भी यह दावा नहीं कर सकते कि उसे पूर्ण सफ़लता मिली। यद्यपि राष्ट्रसंघने बहुत भलाईकी पर अनेक मामलोंमें वह युद्ध और अन्याय को रोक नहीं सका, विगेपकर, चीन, अवीर्मीनिया और स्पेन में। फिर भी यह ठीक दिशामें उठाया गया कदम था। उसकी असफ़लता अधिकतर 'उच्च राजनीति' में रही। गैर राजनीतिक मामलोंमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करनेमें उसे काफी सफलता मिली, विगेपकर श्रम सम्बन्धी मामलोंमें। वह सम्प्रभु राज्योंका संगठन था। आवश्यकता है जनताके संगठनकी। केवल ऐसी सरकारोंका महामन्त्र कभी सफल नहीं हो सकता जिनमें से प्रत्येक सरकार अपना उल्लू सीधा करनेकी ताकमें ही रहे।

जिन लोगोंने राष्ट्र सघका महत्त्व आकनेका प्रयत्न किया है उनमें से अधिकांशने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ोंको शान्तिमय साधनोंसे सुलझाने और युद्ध रोकनेकी उसकी सामर्थ्यके आधार पर उसका मूल्य आका है। इस दृष्टिकोणमें राष्ट्रसघ अधिकतर विकृत रहा है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि राष्ट्रसघ बरसाईकी मन्थिके साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी एक धाराके अनुसार जर्मनीको "युद्धका दोषी" ठहराया गया था और उसे ही युद्धकी तमाम लागतका उत्तरदायी बनाया गया था। क्षति-पूर्तिमेंकी काली कहानीने और रूर (Ruhr) प्रान्त पर अधिकार करनेकी कथाने राष्ट्र सघको बहुत बदनाम कर दिया था। राष्ट्र सघको बदनाम करने वाले कुछ अन्य कारण यह हैं: फ्रांसके हितमें सार-यादी पर राष्ट्र सघकी न्यायधारिता (Trusteeship) स्थापित करना, डेन्विगकी राष्ट्र सघ और पोलैण्डका सम्मिलित मरशित राज्य बनाना, मेमेल बन्दरगाह पर, जो लिथुआनियाको दिया गया था, राष्ट्र सघका प्रणामन कायम करना।

राष्ट्र संघके प्रगविदा (covenant) का एक दोष यह है कि उसमें इस बातकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी कि मन्थियों पर कितने शान्तिमय उपायोंमें विचार किया जा सके। उसकी उन्नीसवीं धारा आरम्भमें ही निर्जीव बनी रही। अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्ति पूर्वक सुलझानेके लिए बड़ी मावधानीसे व्यवस्थाकी गयी पर महत्त्व राज्योंने उसके प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। झगड़ोंकी दो भागोंमें बांटा गया: (१) अन्तर्राष्ट्रीय और (२) घरेलू। और फिर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के भी दो भाग किये गये: (१) वैधिक और (२) राजनीतिक। वैधिक झगड़े पचनिगंधके लिए होने थे और राजनीतिक या न्यायाधिकरणके क्षेत्रमें न आने वाले मामले, जिनका सम्बन्ध देशोंके राष्ट्रीय सम्मान, महत्त्वपूर्ण शायों आदिमें होता था, आक-मडाना नया पारम्परिक समझौते या अन्य किंगी कार्रवाईके लिए परिशदके पास और कभी-कभी ममाके पास भेजे जाने थे।

प्रमयिदाके अनुगार यदि कोई झगडा परिषद या गमा अथवा गमझीना आयोग (commission of conciliation) के विचाराधीन होना या तो उम समय दोनों पक्षों से युद्ध बन्द रखना पड़ता था। परिषद उचित जाच-पड़ताल करनेके बाद दोनों पक्षोंमें गमझीना करानेकी कोशिश करती थी। यदि वह गमझीना करानेमें असफल होती थी तो झगडा पेज विये जानेके ६ महीनेके अन्दर ही वह अपनी रिपोर्ट और गुनाय प्रकाशित कर देती थी। यदि वह रिपोर्ट झगडेमें सम्बन्धित राष्ट्रोंसे अतिरिक्त अन्य मदम्य राष्ट्रोंकी सर्वसम्मतिमें होती थी और यदि झगडेमें सम्बन्धित एक राष्ट्र भी उसे स्वीकार कर लेता था तो दूसरे राष्ट्रके लिए यह आवश्यक था कि वह युद्धका महारा न ले। हर हालतमें परिषदके निर्णय अथवा रिपोर्टके बाद तीन महीने तक दोनों ही पक्षोंके लिए यह आवश्यक था कि वे युद्ध न आरम्भ करें।

राष्ट्र सभकी छोटें-छोटें मामलोंके मुलजानेमें सफलता मिली। राष्ट्र सभ आलैंड (Aaland) द्वीपों और १९२५ के ग्रीम बल्गेरिया के सीमाके झगडोंको मुलजानेमें सफल हुआ। पर वह १९३१-३२ के चीन-जापान के युद्धको न रोक सका। इस मामलेमें राष्ट्र सभ ने हीलेहवालेका मार्ग अपनाया और लिटन कमीशनने अपनी रिपोर्ट तब प्रकाशित की जब बिडिया में चम चुकी थी। रिपोर्टने जापान के विरुद्ध किसी प्रकारकी अनुशास्ति (sanction) की सिफारिश नहीं की।

इटली और अवीसीनिया के युद्धके प्रश्न पर राष्ट्र सभको सबसे अधिक दुःखदायी असफलता मिली। बहुत लम्बे विलम्बके बाद इटलीके विरुद्ध आर्थिक अनुशास्ति (economic sanctions) लागू की गयी, पर तेलके बारेमें फिर भी नहीं की गयी। इस मामलेमें फ्रांस अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करना चाहता था। इसका कारण यह था कि फ्रांस चाहता था कि जर्मनीके विरुद्ध किसी भी भावी सपर्यमें इटली फ्रांस का दक्षिणसाली मित्र बना रहे। ब्रिटेन ने अनुशास्ति आधे मनमें ही लागू की और यह स्पष्ट कर दिया कि वह इटली से युद्ध मोल लेनेको तैयार नहीं है। अमेरिका राष्ट्र सभका मदम्य नहीं था पर वह इटलीके विरुद्ध अनुशास्ति लागू करनेके लिए तैयार था और उसने लागू की भी। पर अमेरिका के सत्ताकीन राष्ट्रपति हजवेल्ड ने यह घोषणा कर दी थी कि यदि व्यक्तिगत अमेरिकी व्यापारी स्वयं अपने खतरे पर इटली को तेल भेजना चाहें तो अमेरिकी सरकार उसमें बाधा नहीं डालेगी। अनुशास्तियोंके इस प्रकार बेमन और मुर्दा टगने लागू किये जानेका परिणाम यह हुआ कि अवीसीनियाको तो इनमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ, पर इटलीने शीघ्र विजय प्राप्त करनेके उद्देश्यसे क्रुद्ध होकर युद्धको और भी बवंर बना दिया। इस प्रकार 'सामूहिक सुरक्षा' 'सामूहिक सफट' बन गयी।

युद्ध की उद्बंध करना (The Outlawry of War). राष्ट्र सभके मदम्य राष्ट्रों और बाहरी राष्ट्रों द्वारा युद्धका परित्याग करने और रक्षात्मक सन्धिवा करनेके अनेक प्रयत्न किये गये। पर ऐसे एवमे अधिक प्रयत्न राष्ट्र सभके मदम्योंका समर्थन प्राप्त करनेमें असफल रहे। उदाहरणके लिए पारस्परिक सहायताके प्रारूप-सन्धि

(Draft Treaty of Mutual Assistance 1923) और जेनेवा पूर्वपत्र, १९२४ (Geneva Protocol, 1924)। लोकार्नो मन्विषा जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, पोलैंड और जेकोम्नोवाकिया के बीच १९२४ में हुई पारस्परिक गारण्टी की मन्विषा थी। पर जेनेवा पूर्वपत्रकी तरह उन मन्विषोंके बारेमें भी कठिनाई यह थी कि यथास्थितिको बदलनेके लिए किसी शान्तिपूर्ण साधनकी व्यवस्था नहीं की गयी थी। अमेरिका और फ्रांस द्वारा आरम्भ किये गये १९२८ के कैलाश ब्रायण्ड मन्विषमें राष्ट्रीय नीतिके रूपमें युद्धको त्यागने और समझौतेके शान्तिपूर्ण उपायों को ही अपनानेका निश्चय किया गया। इसमें हस्ताक्षर करनेवालोंने हमेशाके लिए युद्ध त्यागनेकी राय ली थी।

इस मन्विषमें बड़े-बड़े विद्वान्त लो बना दिये गये किन्तु मन्विषको लागू करनेकी कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी। इसका स्वरूप नकारात्मक ही रहा (The pact was too sweeping and general in its nature. It was also negative and did not provide machinery for its enforcement)। हमारा पिछला अनुभव बताना है कि दीर्घकालीन मंत्रीकी रायों और युद्ध न करनेके बतार अमफल रहे हैं। जब राज्यकी सुरक्षा खतरामें पड़नी है तब अनेक राष्ट्र अपनी रायोंको तोड़ देने हैं और मन्विषोंको वहीं बायबलका टुकड़ा समझ लेते हैं। इसके अलावा, पहलेकी मन्विषोंमें और लोकार्नोकी मन्विषोंमें भी युद्धकी गुंजाइश आत्मरक्षा या पारस्परिक सहायताके नाममें थी (Besides, the reservations incorporated in the past were such as not to exclude the right of self-defence or mutual assistance promised in the Locarno Treaties)। सभी आधुनिक युद्धोंको, लड़नेवाले दोनों पक्ष, 'रक्षात्मक' ही बताते हैं। उदाहरणके लिए जापान का यह कहना था कि मन्चूरिया में उसकी सैनिक कार्रवाई और अन्तर्गत उस प्रदेशका अनुयोजन (annexation) न तो लीगके प्रमत्तिशाका उल्लंघन था और न कैलाश-ब्रायण्ड मन्विषा, जिन दोनों पर जापान अपने हस्ताक्षर कर चुका था। जापान को कहना था कि न तो मन्चूरिया ने और न स्वयं जापान ने वैधिक युद्ध मन्विष घोषित की थी और जापान अपने हितोंकी रक्षाके लिए कार्रवाई कर रहा था। इसलिए 'कैलाश-ब्रायण्ड मन्विषा महत्त्व युद्धका बहिष्कार करनेके अर्थमें केवल प्रतीकात्मक, नैतिक, शिक्षात्मक और प्रचारात्मक ही था (७० : ६६७)।' उसने व्यावहारिक राजनीति की बंधन बान्धविधनाका स्पर्श तक नहीं किया था।

निस्शस्त्रीकरण (Disarmament). युद्धका बहिष्कार करनेके प्रयत्नके समान ही निस्शस्त्रीकरणके प्रयत्नमें भी अधिक सफलता नहीं मिली। वॉशिंगटन सम्मेलनमें कुछ परिणाम अवश्य निकला यद्यपि उसका आयोजन मयूकनराज्य अमेरिका की सरकारने किया था, राष्ट्र मंथने नहीं। राष्ट्र मंथने स्थायी सलाहकार समिति और अन्वयायी मिश्रित आयोषके माध्यमने निस्शस्त्रीकरणके लिए प्रयत्न किया पर

प्रयत्न भी करना पड़ा। उस समय तब राष्ट्र संघकी स्वास्थ्य सगठन शाखाकी स्थापना भी न हो पाई थी फिर भी उसने इन विपत्ति ग्रस्त लोगोंकी पुनार मुनी, उन्हें मात्र मायानकी तथा टेबिनवल सहायता पहुँचाई। मिगापुर का पतन होनेमें पहले ही राष्ट्र संघने वहाँ पर एक महामारी शोधक स्थायी कुशल अधिमेवा की स्थापना कर दी थी। यह अधिमेवा बीमारियोंको फैलने और उनमें पीड़ित होने वालोंके आक्डे एक्न करके उनकी मूचना राष्ट्र संघके मन्त्रिवालयका भेजने से जल्दा उनका मरना होना था और उन्हें माप्ताहिव तथा त्रैमासिक स्वास्थ्य मन्त्रिवालय के रूपमें प्रकाशित किया जाता था।

स्वास्थ्य सगठनके आगखाम सीरमो, विटामिनो, लैंगिक हार्मोनो (sex hormones) और ग्रन्थि-निस्सारो (gland extracts) आदिके अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों और इकाइयोंको निर्धारित किया। इसने अनेक रोगोंके बारेमें गवेषणा कार्य किया। सामकर मलेरियाके बारेमें। तपेदिक, काँड और उपद्रव जैसे रोगों तथा ग्रामीण क्षेत्रोंकी स्वच्छता, सामान्य पोषाहार (nutrition) और शहरी और ग्रामीण गृह निर्माण पर भी स्वास्थ्य सगठनने ध्यान दिया। राष्ट्र संघ के प्राविधिक कार्योंके बारेमें माराम यह है कि “अन्य किसी क्षेत्रमें राष्ट्र संघके प्रयत्नोंका परिणाम इतना सफल नहीं रहा जितना इस नितान्त प्राविधिक क्षेत्रमें, जो सभी प्रकारके राजनीतिक दावोंपेचमें सर्वथा अलग है और जिसमें मानव एकता के लक्ष्यकी ओर बढ़नेमें कोई बाधा नहीं है (२५ - १५१)।”

(६) बौद्धिक सहयोग (Intellectual Co-operation). राष्ट्र संघ ने १९२८ में बौद्धिक सहयोग समिति कायम की थी। इस समिति ने शान्ति स्थापित करने में, बौद्धिक विषयोंका निरपेक्ष विवेचन प्रोत्साहित करनेमें, और राष्ट्रोंकी शिक्षा व्यवस्था के सुधार और सगठनमें सहायता दे कर बहुत अधिक उपयोगी कार्य किया। इस समिति ने राष्ट्रोंको इस बातके लिए तैयार किया कि उनके देशकी पाठ्य पुस्तकोंमें यदि कोई ऐसी बातें हों जिनसे विदेशियों और पड़ोसी देशोंके प्रति उपेक्षा और तिरस्कार प्रवृत्त होना हो तो उन्हें पुस्तकोंमें निकाल दिया जाय। इस समिति ने नवयुवकों और नवयुवतियोंकी विदेशोंका भ्रमण करनेके लिए उत्साहित किया ताकि वे विदेशोंमें जाकर विभिन्न संस्कृतियों और सम्प्रदायोंको समझें और उनमें जो अच्छाईयाँ हों उन्हें ग्रहण करें। इस समिति द्वारा तैयार किया गया रेडियो भाषण और शान्ति सम्बन्धी कार्यक्रमका प्रारूप अनेक सरकारों ने स्वीकार किया। इस बातकी व्यवस्था की गयी कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। कलाकृतियों और इतिहासीय स्मारकोंकी सुरक्षाके लिए मुझाव दिये गये। दार्शनिकों और वैज्ञानिकोंके नियतकालिक सम्मेलनोंको प्रोत्साहित किया गया।

(७) समाजसेवी और मानवता प्रेरित कार्य (Social and Humanitarian Works). राष्ट्र संघ ने डॉक्टर नैन्मेन के निर्देशनमें युद्धके बादके वर्षोंमें

पांच लाख युद्ध बन्दियोंको उनके पितृदेशमें पहुँचा कर बड़ा प्रथमनीय कार्य किया। मरणार्थियोंकी भी ऐसी ही सेवा की गयी। १९२६ में राष्ट्र सचने दाम प्रथा के सम्बन्ध में किये गये पूर्ववर्तीय करारोंको और अधिक दृढ़तासे लागू करनेका एक इकरारनामा स्वीकृत किया। दामता की परिभाषा इतनी व्यापक की गयी कि उसमें अर्ध-दामता, वैयक्तिक चाकरी, बलान्धम और लड़कियोंके क्रय आदि भी आ गये। दामताको परिभाषा इस प्रकार की गयी : "एक व्यक्तिकी ऐसी दशा जिसमें उसके ऊपर स्वामित्वके अधिकार की किसी एक या समस्त शक्तियोंका उपयोग किया जा रहा हो।" जिन देशोंने दास व्यापारको समाप्त करनेका निश्चय किया था उनके लिए यह आवश्यक था कि "कमिक रूपमें और यथामुम्भव शीघ्र दामताका पूर्ण विनाश उसके सभी रूपोंमें कर दें।" मार्चजनिक उद्देश्योंके कुछ कार्योंको छोड़ कर अन्य सभी कार्योंमें दामतासे मिलने-जुलते सभी प्रकारके बलान्धमका निरोध कर दिया गया था। राष्ट्र सचकी एक स्थायी मलाहकार समितिने १९३३ में अपना काम शुरू किया। इस समितिका उद्देश्य दामताके अन्तिम गढ़ोंको तोड़ना था।

राष्ट्र सचने एक और गम्भीर सामाजिक समस्या हल की। यह समस्या थी बच्चों और स्त्रियोंका क्रय-विक्रय। १९२१ में यह निश्चय किया गया कि कोई भी २०, २१ वर्षसे कम आयुकी स्त्री अपनेको बिकवानेकी अनुमति नहीं दे सकती। इससे कम उम्रमें ऐसा कार्य कानूनन दण्डनीय था। स्त्रियोंको व्यापारके लिए मुलभ बनाना और उन्हें प्राप्त करनेका प्रयत्न करना दोनों ही दण्डनीय घोषित किये गये। जिन सरकारोंने यह इकरारनामा स्वीकार किया था उनमें कहा गया कि वे राष्ट्र सचको हर साल एक रिपोर्ट भेज कर बताया करे कि यह इकरारनामा उनके देशमें किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्त्रियों और बच्चोंके क्रय-विक्रयकी समस्याके बारेमें राष्ट्रसचकी परिषदको परामर्श देनेके लिए, एक समिति बनाई गयी। दो बार सभारके विभिन्न भागोंमें जाब पड़ताल करके इस बातकी जानकारी प्राप्त की गयी कि स्त्रियों और बच्चोंका क्रय-विक्रय किस प्रकार और किस पैमाने पर होता है। १९३३ में यह निश्चय किया गया कि "दूसरे देशोंमें अनैतिक कार्योंके लिए ब्यस्क स्त्रियोंका अन्तर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय दण्डनीय होगा भले ही यह काम उनकी स्वीकृतिसे ही हो रहा हो"। राष्ट्रसच ने वैयक्तिकी उन जड़ोंकी समस्या पर भी ध्यान दिया जिनका अस्मिन्व समाज वर्दासन कर रहा था और उन्हें समाप्त करनेके लिए सरकारों पर जोर दिया।

राष्ट्र सचने अश्लील साहित्य की समस्या पर भी ध्यान दिया। १९२३ में एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अनुसार अश्लील प्रकाशनोंके क्रय-विक्रय और प्रचार पर रोक लगानेका निश्चय किया गया। इस इकरारनामे पर ४० से अधिक राष्ट्रोंने हस्ताक्षर किये। अश्लील साहित्य का प्रकाशन, व्यावसायिक उद्देश्यसे

उमरा राखना, उमरा आयात-निर्यात आदि, सभी बंधिक तौर पर दण्डनीय घोषित किये गये।

राष्ट्र मणने 'एक शिशु बन्ध्याण समिति' की स्थापना की। इस समितिने एक आदर्श बरारवा स्वरूप निश्चय किया जिसके अनुसार पच भ्रष्ट बच्चों, युवकों तथा मूर्खतायोंको उनके घरोंमें धापम पहुँचाना स्वीकार किया गया। इस समितिके प्रयत्नोंमें एक ऐसे इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अनुसार विदेशी बच्चों को स्वदेशके बच्चोंके समान ही व्यवहार मिलने लगा। राष्ट्रोंने अपने महा विधिया बना कर विवाहकी आयुको बढ़ाने, जारज (illegitimate) मन्त्रानोंकी वैधिक स्थिति सुधारने और उनके लिए अनिवार्य सरक्षणकी व्यवस्था करने, अन्ये बालकोंकी शिक्षा तथा उनकी रक्षा करनेके मफल प्रयत्न किये।

समाजसेवी और मानवता प्रेरित कार्य-क्षेत्रोंमें राष्ट्र मणवा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य अफीम तथा अन्य घातक औषधियोंके त्रय-विक्रयका निरीक्षण था। १९२१ के हेग सम्मेलनके निश्चयके बावजूद घातक औषधिया बड़ी आसानीसे एक देशमें दूसरे देशको भेजी जाती थी। १९२३ में राष्ट्र सभ ने निश्चय किया कि उपयुक्त प्रमाण-पत्रके बिना औषधियोंका आयात नहीं हो सकेगा। औषधियोंके निर्माणका भी नियमन किया गया और औषधियोंके राष्ट्रीय त्रय-विक्रयके कठोर निरीक्षणकी व्यवस्था की गयी। केवल अफीमके व्यापारको ही नहीं बल्कि मॉर्फिनमें बनाये गये नये-नये रस इन्हींके व्यापारको भी प्रतिबन्धित किया गया। एक स्थायी केन्द्रीय अफीम बोर्ड कायम किया गया। राष्ट्रोंको हर तीसरे महीने इस बोर्डके पाम इस बातका विवरण भेजना पड़ता था कि उनके महा इस अवधिमें प्रमौलको (narcotics) का कितना आयात, निर्यात और उत्पादन हुआ। इस व्यवस्थाका एक लक्ष्य यह भी था कि इस बातका पता लग सके कि ऐसी वस्तुएँ कहा से लुप्त-छिपकर आती जाती हैं। लगभग चाहीस राष्ट्रोंने इस इकरारनामेको मान कर अपने ऊपर कड़ी जिम्मेदारी ली। १९३१ में एक दूसरे इस इकरारनामेको और अधिक राष्ट्रोंने स्वीकार किया। इसके फलस्वरूप अफीम तथा अन्य सम्बन्धित औषधियोंके पश्चिमी देशोंमें भेजे जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। जो मानदण्ड तय किया गया वह वही था जो मेडिकल और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक था। इन औषधियों के उत्पादन पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया।

१९३१ के इकरारनामेका महत्व इस बातमें था कि सम्प्रभु राष्ट्रोंने पहली बार एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्या द्वारा "अपनी आर्थिक सक्रियताकी एक सम्पूर्ण शाखा पर, बच्चे बालके उत्पादनमें लेकर तैयार वस्तुके उपभोग तक, निरीक्षण व्यवस्था को मजूर कर लिया (८५ : १७९)।" उत्पादन और उपभोगोंमें पूरा-पूरा समन्वय कायम किया गया। इतना सब होने पर भी प्रमौलको (narcotics) का अवैध उत्पादन पूर्ण रूपसे अभी तक नहीं बन्द हो सका है यद्यपि बन्द हो सकने की पूरी सम्भावना है।

अन्तर्युद्ध विकास (The Inter War Development)

आलोचकोंने पिछले दिनों राष्ट्र मंचको पूर्व निर्धारित विचारोंका सच, लुटेरोंका सच और समस्याओंको लटकाये रखने वालोंका सच कहा है। कुछ लोगोंने कहा कि राष्ट्र मंच गरज सकता है लेकिन बरस नहीं सकता। पर इस प्रकारकी आलोचनाके बावजूद लोगोंने, प्रभावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय निरोधन और नियंत्रणके पक्षमें, भावना बढ रही थी।

१९३३ के बाद विश्व मंचके प्रश्न पर साहित्यकी एक बाढ़-नी आ गयी थी। क्लेरेन्स स्ट्रीट (Clarence Street) ने अमेरिका और पश्चिमी योरोप के लोकतन्त्र राज्यों के एक संघ (federal union) की रूपरेखा तैयार की। इस योजनाके अनुसार मंच भर के लिए एक ही विधायिका, एक ही राष्ट्रपति, एक ही प्रधान मंत्री और एक ही मन्त्रिमण्डल होना। और इस संघीय सरकारका युद्ध तथा शान्ति, सुरक्षा तथा वैदेशिक सम्बन्ध, डाक व्यवस्था तथा मुद्रा आदि प्रश्नों पर पूरा-पूरा नियंत्रण रहना। सचमें रहने वाले सभी लोग सचके ही नागरिक माने जाते, किसी देश विशेष के नहीं। मंच भर के लिए एक ही रक्षात्मक सेना होनी; सब भरमें एक ही मुद्रा चलती और एक ही टिकट व्यवस्था होती तथा सब भरमें बेरोकटोक व्यापार होना। सदस्य राष्ट्रोंके उपनिवेशोंको उनमें ले लिया जाता और उनका शासन सम्मिलित रूप से मंच द्वारा किया जाता। इस शासनका उद्देश्य यह होना कि उन प्रदेशोंको यथा-सम्भव शांतिमें दीर्घ मध्या मध्य बनने योग्य बना दिया जाय। यह सच आत्म-निर्भर मन्त्रों (self-canonized saints) का सच होना।

मदारीयागा (Madariaga) एक विश्व ममाज और विश्व-सचके प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने विश्व मंचकी कुछ नाम देशों तक ही सीमित नहीं रखा। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक मंच तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंके अनिश्चित उन्होंने, एक विश्व बैंक, एक विश्व व्यापार आयोग, उपनिवेशों के लिए एक विश्व-प्रशान्त-मन्त्रि, अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस और एक अन्तर्राष्ट्रीय पौर अधिकारी (International Civil Service) — इन सबकी आवश्यकताका अनुभव किया था।

'वर्ल्ड फंडेशन' (१९३९) के केवक ऑस्कर न्यूफंग (Oscar Newfang) के अनुसार राष्ट्र मंचका सगठन ऐसा था कि उसे बड़ी सरलतासे एक विश्व मंच में परिणत किया जा सकता था। राष्ट्र मंच की मभा विश्व विधायिका बन जानी और परिषद मंत्री परिषद बननी। विश्व न्यायालयका अधिकार क्षेत्र अनिवार्य होगा। मध्य राष्ट्रोंकी मभी सगठन-मेनाए धीरे-धीरे केन्द्रीय अधिकार गतके अधीन हो जानी। व्यापारकी हवाबदोको हटा दिया जाना और एक मौद्रिक व्यवस्था लागू कर दी जानी।

सर विलियम बेवरिज (Sir William Beveridge) का कहना था कि तन्त्रालोक परिस्थितियोंमें विषय मध्य असम्भव था। इसलिए अरबी योजनाओं उन्होंने ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी (ऑस्ट्रिया), बेल्जियम, हॉलैण्ड, फिनलैण्ड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैण्ड और पाच अंग्रेजी उपनिवेशों तक ही सीमित रखा था। केन्द्रीय नियंत्रणमें दिये जाने वाले समस्त सम विषय थे—सुरक्षा और वित्तिक नीति। आर्थिक प्रदेशोंकी व्यवस्था, मुद्रा, व्यापार और प्रवास आदि विषयोंकी क्रमशः केन्द्रके हाथों सौंपा जाना।

ग्रेटब्रिटेन गिरजाघरके भूतपूर्व डॉन डॉक्टर इन्ज (Dr. W. R. Inge) ने समस्त अंग्रेजी बोलने वाले देशोंका मध्य बनानेकी योजना तैयार की। इस योजनाके अनुसार ब्रिटेन, उसके स्वशासित उपनिवेशों और समस्त राष्ट्र अमेरिका का मध्य बनना। फलस्वरूप में प्रभावित होने वाले अंग्रेजी दैनिक स्टैंडार्ड के भूतपूर्व सम्पादक सर ए० वाट्सन (Sir A. Watson) का कहना था कि एक ब्रिटिश साम्राज्य मध्य बनाया जाय। 'ग्रेट ब्रिटेन एण्ड ईस्ट' में उन्होंने लिखा था "भविष्यकी कल्पनामें एक ऐसा साम्राज्य मध्य आना है जिसमें अलग रहनेका माहम उनमें से कोई भी देश न कर सकेगा जो आज अपनी ओछी स्थिति की शिक्षा देकर है क्योंकि उनकी सुरक्षा और उनका अस्तित्व ही राष्ट्रोंके एक ऐसे समुदायके सहयोग पर निर्भर होगा जो सम्मिलित रूपमें अजेय होगा पर पुनः रहनेसे वे अपनी स्वाधीनता कायम न रख सकेंगे।" उस समय विन्स्टन चर्चिल (Winston Churchill) भी अमेरिका, ब्रिटेन और उपनिवेशोंका एक प्रकारका मध्य बनानेका विचार कर रहे थे।

डॉ० आइवर जेनिंग्स (Dr Ivor Jennings) ने पश्चिमी योरोपीय देशों के एक सीमित मध्यकी विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उनका कहना था कि "योरोप ही वह बड़ाई है जिसमें अधिकांश युद्धोंका ममाला एक कर तैयार होता है और इसलिए एक संघ (federal union)—जामकर पश्चिमी योरोप के राष्ट्रों—इन युद्ध प्रवृत्तियोंको रोक सकेगा। उनका उद्देश्य समस्त विश्वकी शान्ति और समृद्धिकी सुरक्षा इतना अधिक नहीं जान पड़ता, जितना यह कि अफ्रीका तथा एशिया के कुछ भागोंके शोषणमें योरोपीय राष्ट्रोंकी प्रतिस्पर्धा या पारस्परिक होड़को समाप्त किया जाय। उन्होंने धर्मात्माई इस सबका प्रधान उद्देश्य "पश्चिमी योरोप के राष्ट्रोंमें परस्पर युद्धको बिल्कुल असम्भव बना देना था।"

डॉ० जेनिंग्स अपनी योजनाके अनुसार अंग्रेजी साम्राज्य और राष्ट्र मध्य इन दो में से किसी एक का भी निरन्तर नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजी साम्राज्य इस मध्य मध्यमें एक इकाईके रूपमें बना रहता। उसके उपनिवेशों और आर्थिक प्रदेशोंमें होने वाले हानि लाभमें समीय भाई बन्धु सामीदार होते और पिछड़े प्रदेश सभी समीय नागरिकोंकी पूँजी और उद्यमके लिए खुले रहते। एक समीय आयोग होता जिसका अधिकार क्षेत्र सभी औपनिवेशिक प्रदेशों पर रहता। सभी समीय देशोंके

राष्ट्रीयतावाद, साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद

लोग औपनिवेशिक अधिसेवाके पदों पर नियुक्त किये जा सकते थे। राष्ट्र संघका अस्तित्व उन राष्ट्रोंके कल्याणके लिए बना रहता जो पश्चिमी योरोपीय सघके सदस्य न हों। पश्चिमी योरोपीय सघ राष्ट्र संघकी परिषदमें एक इकाईके रूप में अपना प्रतिनिधि भेजता। यह सघ राष्ट्र संघको अपने देशोंके प्रति उत्तरदायित्वों से मुक्त रखता और राष्ट्र संघको शेष समारके कल्याण पर और अधिक ध्यान देने का अवसर मिलता। संघीय विषय प्रधान रूपसे सुरक्षा और वैदेशिक मामले होते और कुछ हद तक आर्थिक सम्बन्ध और उपनिवेश भी। शेष बचे हुए अधिकार (residuary powers) राज्योंके हाथोंमें रहने।

डॉ० एन० प्रिट (D. N. Pritt) ने सत्तारका आशिक सघ बनानेकी सभी योजनाओंकी सबसे बड़ी आलोचना की है। आपने समाजवादी आधार पर तर्क करते हुए कहा है कि जब तक पूँजीवाद और साम्राज्यवादका कायम रखा जायगा तब तक संसारका सब केवल एक माया या छत्र है। आपका कहना था कि आज दिन अमली शक्ति पूँजी और उद्योग पतियोंके छोटेसे गुटके हाथोंमें है और सरकारों का नियंत्रण करने वाले प्रायः वे ही होते हैं जो उद्योगोंका नियंत्रण करते हैं। इसलिए ऐसी हालतमें एक सघ बनानेका मतलब होगा विभिन्न देशोंके निहित स्वार्थ वाले गुटोंका एकीकरण जिससे वे स्वयं अपने देशकी जनताका और उपनिवेशोंकी जनताका और भी अधिक मोचन कर सकें। कुछ शक्तिशाली राष्ट्र और उनके पिछलगू राष्ट्रोंकी यह एक गुटबन्दी होगी। प्रिट के ही शब्दोंमें: "आधुनिक औद्योगिक राज्योंमें कुछ छोटेसे घनी व्यक्तिगत्तोंमें वित्तविक शक्ति केन्द्रित रहनी है। राज्योंके इस स्वरूपको पहले बिल्कुल बदल देना होगा सभी एक विश्व सघ सम्भव हो सकता है।"

उन्होंने विश्व संघकी विभिन्न योजनाओंकी आलोचना इस आधार पर भी की है कि उनमें सारे समारको नहीं सम्मिलित किया गया। उनका कहना है कि ऐसे आशिक सघसे तो किसी प्रकारका सघ न होना ही अच्छा है। यह आशिक संघ तो एक साम्राज्यमें भी अधिक घातक है क्योंकि अन्य राष्ट्रोंके विरुद्ध इसका उपयोग एक भालेकी नांवकी भाँति किया जा सकता है। ऐसे संघमें जो राज्य बाहर रहे जायगे वे अपना एक अलग गुट बना सकते हैं। और तब सन् और इस गुटके बीच बराबर संघर्ष और ईर्ष्या बनी रहेगी।

विश्व संघकी योजनाओंका समर्थन करने वाले भी यह अनुभव करते हैं कि ये योजनाएँ इनकी विनाश हैं कि इन्हें कार्यान्वित करना असम्भव है। इसलिए ये लोग ऊपर सीमित अधिकारों वाला एक महामघ हो सकता है।

प्रो० कॅटलिन (Prof. Catlin) ने राष्ट्रीय सम्प्रभुता के पिटे-पिटारे विद्वान्ते स्थान पर समन्वित सम्प्रभुता (pooled sovereignty) के नये विद्वान्त का समर्थन किया। उनका कहना था कि तीन पृथक् अधिकार सत्ताओंके अर्पण

तीन पूरक क्षेत्र होने चाहिए। सबसे ऊपर मारा विश्व हो जिसकी अपनी एक विश्व सरकार हो। इस सरकारके अधिकार क्षेत्रमें ढाक व्यवस्था, हवाई यातायात, विश्व मुद्रा, कुछ कच्चे मालोका उपयोग और टंगस्टन (tungsten), टाइटेनियम (titanium) तथा निकेल (nickel) जैसे महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थों (raw materials) का अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो। शक्ति द्वारा शान्ति स्थापित करने के लिए एक विश्व न्यायालय और विश्व पुलिस भी हो।

इसके बाद एक प्रादेशिक अधिकार मत्ता हो जिसके अधीन एक प्रादेशिक भू-भाग रहे। इसका काम एक बीचके क्षेत्रमें हो जिसके भीतर समाजवा एकीकरण सुरक्षित सम्भव हो। श्रम और व्यापार सम्बन्धी कुछ वानें और चुगी (tariff), आप्रजनन (immigration) उसके अधीन रहे। प्रादेशिक क्षेत्रोंमें रहने वालोंकी आदतें तथा जीवन पद्धतिया मिलनी-जुलनी होंगी। इन प्रादेशिक भू-भागोंके निर्माण में और उन्हें कायम रखनेमें भौगोलिक राजनीति (Geo-politics) का बड़ा प्रभावपूर्ण हाथ रहता। इन प्रादेशिक भू-भागोंके ऊपर एक सभ होता जो राष्ट्र सभ या विश्व सभसे बिल्कुल भिन्न होता।

लॉर्ड डेवीज (Lord Davies) का कहना था कि निम्नलिखित सभ बन सकते हैं : अंग्रेजी भाषा भाषी देशोंका सभ, ब रुग को केन्द्र बनाकर स्लाव देशोंका सभ, दक्षिणी अमेरीका के लेटिन गणराज्योंका सभ, भारत और उसके पड़ोसी राज्योंको मिलाकर मध्य एशियाई देशोंका सभ, सुदूर पूर्वी देशोंका सभ और योरोप के राष्ट्रोंका सभ। अफ्रीका का नाम बड़ी सुविधाके साथ छोड़ दिया गया था—सम्भवतः अंग्रेजी भाषा भाषी देशों द्वारा शोषण किये जानेके लिए। लॉर्ड डेवीज के अनुसार मुद्दको समाप्त कर देना, विधि राज्यकी स्थापना करना, एक सामान्य वैदेशिक नीति निर्धारित करना, न्यायाधिकरणके लिए एक विश्व अधिकार सत्ताकी स्थापनाके उद्देश्यमें विश्व महासंघमें सम्मिलित होना, शान्ति स्थापित रखना और आर्थिक समसाम्यिक निराकरणमें सहयोग देना—आदि इन सभों के उद्देश्य थे। नवीन सभमें पचास या उससे अधिक राज्योंके बजाय पाच या छ राज्य होते और उनके बीच होने वाले विवादोंका निराकरण पारस्परिक विचार विमर्श और परामर्श द्वारा किया जाता।

राजनीति की श्रृंखलामें तीसरी श्रेणी राष्ट्रीय क्षेत्रोंकी थी जिनकी एक राष्ट्रीय सरकार होती। कंटलिन इस क्षेत्रको शिक्षा और संस्कृतिके विकासके लिए उपयुक्त क्षेत्र मानते थे। राष्ट्रीय भावनाके लिए यह क्षेत्र उपयुक्त था। इस सीमाके भीतर राष्ट्रीयतावाद कल्याणकारी था; इस सीमाके बाहर राष्ट्रीयतावादको बरपना मूलक, प्रतिक्रियावादी, और कभी समाप्त न होने वाले युद्धोंका सक्रिय कारण माना गया।

इन प्रस्तावोंका निचोड़ था सांस्कृतिक क्षेत्रमें राष्ट्रीयतावाद, आर्थिक क्षेत्र में प्रादेशिकतावाद और उच्च राजनीतिक क्षेत्रमें अन्तर्राष्ट्रीयतावाद।

राष्ट्रीयतावाद, साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद

एटलांटिक घोषणापत्र या अधिकारपत्र (Atlantic Charter) से हमें इस बात का मकेत मिलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन युद्ध के बाद के समारंभों में किस प्रकार की विश्व व्यवस्था कायम करना चाहते थे। इस घोषणा पत्र को विन्स्टन चर्चिल के यथार्थवाद और कॉडेल हलके आदर्शवाद का रूजवेल्टीय समन्वय कहा जाता है। वाइकाउण्ट समुअल (Viscount Samuel) का कहना है कि इस अधिकार पत्र की प्रथम तीन धाराएँ बाइबिल (old testament) के दशम आदेश (tenth commandment) की व्याख्या-मात्र हैं। यह आदेश है "तुम लालच नहीं करोगे।" संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ने इस बात की घोषणा की कि उन्हें प्रादेशिक या अन्य किसी भी प्रकार के विस्तार की महत्वाकांक्षा नहीं है। सब बात तो यह है कि इस धारामें किसी के भी हृदयमें कोई उत्साह नहीं पैदा होता। क्योंकि अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन का उक्त निश्चय ठीक वंसा ही है जैसा ऊँचे रत्नचापसे पीड़ित एक व्यक्ति अपनेको जीवित रखने के लिए अपने सैनिकों को नियमित और नियंत्रित रखने का निश्चय करता है। इस धारामें हिटलर को युद्ध के पहले की गयी फरेवमें भारी इस घोषणाको और भी बल दे दिया कि वह जो युद्ध आरम्भ करने जा रहा था, वह धनी देशों के विरुद्ध निर्धन देशों का युद्ध था। चर्चिल के बक्तव्योंमें उनका यह इरादा साफ प्रकट था कि "जो हमारे अधिकारमें हैं उन्हे हम अपनी मुट्ठीमें निबलने न देंगे"। हम प्रिट के इस विदवासे सहमत हैं कि "जब तक साम्राज्यवाद जड़ें नष्ट नहीं होती तब तक एक सुन्दर विश्व व्यवस्था नहीं कायम की जा सकती।

इस घोषणापत्र की दूसरी धारामें यह इच्छा प्रकट की गयी थी कि "ऐसा कोई प्रादेशिक परिवर्तन नहीं होगा जो उस प्रदेश की जनता की स्वतंत्र सम्मतिमें मेल न पाता हो"। तो क्या इसका यह अर्थ था कि फ्रान्स, पोर्लैंड और बाल्टिक राज्यों को उनके वे प्रदेश वापस दिलाये जायें जो युद्ध के पूर्व उनके अधिकारमें थे? इस व्यवस्थाके प्रति रूस की क्या प्रतिक्रिया हुई?

तीसरी धारामें घोषणा की गयी कि "सभी जातियों के इस अधिकार का सम्मान किया जायगा कि वह स्वयं यह निर्णय करे कि किस प्रकार की सरकार के अधीन वह रहना चाहती है"। इस धारामें यह इच्छा भी व्यक्त की गयी कि जिन लोगों के सम्पूर्ण अधिकार और जिनका स्वशासन उनमें बलान्तीन लिया गया है वे उन्हें वापस दिलाये जायें। तो क्या इसका मतलब यह है कि केवल बहुमत का शासन होगा या इसमें उपजातियों द्वारा अपने पृथक् राज्य स्थापित करने का अधिकार भी निहित है? यदि उसका दूसरा अर्थ ही अभीष्ट है तो इस प्रकार बताये जानेवाले नये राज्यों में अन्यमध्यकों के अधिकारों की क्या व्यवस्था होगी? क्या यह धारा भारत पर भी लागू थी? चर्चिल ने कहा था कि वह भारत पर लागू नहीं होती और रूजवेल्ट का विचार था कि यह भारत पर लागू होती है।

चौथी और पाचवी धाराएँ आर्थिक पक्षमें सम्बन्धित हैं। इन धाराओंमें इस

तीन पृथक् क्षेत्र होने चाहिए। सबसे ऊपर मारा विश्व हो जिनकी अपनी एक विश्व सरकार हो। इस सरकारके अधिकार क्षेत्रमें ढाक व्यवस्था, हवाई यातायात, विश्व मुद्रा, कुछ कच्चे मालोंका उपयोग और टंगस्टन (tungsten), टाइटेनियम (titanium) तथा निकेल (nickel) जैसे महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थों (raw materials) का अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो। यन्त्रि द्वारा शान्ति स्थापित करने के लिए एक विश्व न्यायालय और विश्व पुलिस भी हो।

इसके बाद एक प्रादेशिक अधिकार मत्ता हो जिनके अधीन एक प्रादेशिक भू-भाग रहे। इसका काम एक बीचके क्षेत्रमें हो जिनके भीतर समाजका एकीकरण सुरक्षित सम्भव हो। यम और व्यापार सम्बन्धी कुछ बातें और शुगी (tariff), आप्रव्रजन (immigration) उसके अधीन रहे। प्रादेशिक क्षेत्रोंमें रहने वालोंकी आदतें तथा जीवन पद्धतियां मिलनी-जुलनी होंगी। इन प्रादेशिक भू-भागोंके निर्माण में और उन्हें कायम रखनेमें भौगोलिक राजनीति (Geo-politics) का बड़ा प्रभावपूर्ण हाथ रहता। इन प्रादेशिक भू-भागोंके ऊपर एक सभ होना जो राष्ट्र सभ या विश्व सभमें बिल्कुल भिन्न होता।

लॉर्ड डेवीज (Lord Davies) का कहना था कि निम्नलिखित सभ बन सकते हैं। अंग्रेजी भाषा भाषी देशोंका सभ, व रूस को केन्द्र बनाकर स्लाव देशोंका सभ, दक्षिणी अमेरीका के ग्रेटिन गणराज्योंका सभ, भारत और उसके पड़ोसी राज्योंको मिलाकर मध्य एशियाई देशोंका सभ, मुद्रर पूर्वी देशोंका सभ और योरोप के राष्ट्रोंका सभ। अफ्रीका का नाम बरी सुविधाके साथ छोड़ दिया गया था—सम्भवतः अंग्रेजी भाषा भाषी देशों द्वारा दोषण किये जानेके लिए। लॉर्ड डेवीज के अनुसार मुद्रको समाप्त कर देना, विधि राज्यकी स्थापना करना, एक सामान्य वैदेशिक नीति निर्धारित करना, न्यायाधिकरणके लिए एक विश्व अधिकार सत्ताकी स्थापनाके उद्देश्यमें विश्व महासंघमें सम्मिलित होना, शान्ति स्थापित रखना और आर्थिक समस्याओंके निराकरणमें सहयोग देना—आदि इन सभों के उद्देश्य थे। नवीन संघमें पचास या उससे अधिक राज्योंके बजाय पांच या छः राज्य होते और उनके बीच हाने वाले विवादोंका निराकरण पारस्परिक विचार विमर्श और परामर्श द्वारा किया जाता।

सगठनोंकी धूललामे सीसरी श्रेणी राष्ट्रीय क्षेत्रोंकी थी जिनकी एक राष्ट्रीय सरकार होनी। कैंटलिन इस क्षेत्रकी शिखा और सस्कृतिके विकासके लिए उपयुक्त क्षेत्र मानते थे। राष्ट्रीय भावनाके लिए यह क्षेत्र उपयुक्त था। इस सीमाके भीतर राष्ट्रीयतावाद कल्याणकारी था; इस सीमाके बाहर राष्ट्रीयतावादको कल्पना मूलक, प्रतिक्रियावादी, और कभी समाप्त न होने वाले युद्धोंका सक्रिय कारण माना गया।

इन प्रस्तावोंका निचोड़ था सांस्कृतिक क्षेत्रमें राष्ट्रीयतावाद, आर्थिक क्षेत्र में प्रादेशिकतावाद और उच्च राजनीतिक क्षेत्रमें अन्तर्राष्ट्रीयतावाद।

राष्ट्रीयतावाद, साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद

एटलान्टिक घोषणापत्र या अधिकारपत्र (Atlantic Charter) से हमें इस बात का मकेत मिलता है कि मयूकन राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन युद्ध के बादके समारमों किस प्रकार की विश्व व्यवस्था कायम करना चाहते थे। इस घोषणा पत्र को विन्स्टन चर्चिल के ययार्यवाद और कॉडेल हलके आदर्शवादका रुजवेलेटीय समन्वय कहा जाता है। वाइकाउण्ट सैमुअल (Viscount Samuel) का कहना है कि इस अधिकार पत्र की प्रथम तीन धाराएँ वाइविल (old testament) के दशम आदेश (tenth commandment) की ध्याख्या-मात्र हैं। यह आदेश है: "तुम लालच नहीं करोगे।" मयूकन राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन दोनोंने इस बात की घोषणा की कि उन्हें प्रादेशिक या अन्य किसी भी प्रकार के विस्तार की महत्वाकांक्षा नहीं है। सच बात तो यह है कि इस धारामें किसीके भी हृदयमें कोई उत्साह नहीं पैदा होता। क्योंकि अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन का उक्त निश्चय ठीक वैसे ही है पानकी नियमित और नियमित रखनेका निश्चय करता है। इस धारामें हिटलर की युद्धके पहले की गयी फरेवसे भारी इस घोषणाकी ओर भी बल दे दिया कि वह जो युद्ध आरम्भ करने जा रहा था, वह धनी देशोंके विरुद्ध निर्धन देशोंका युद्ध था। चर्चिल के वक्तव्योंमें उनका यह इरादा साफ झलकता था कि "जो हमारे अधिकारमें है उसे हम अपनी मुट्ठीमें निकलने न देंगे"। हम प्रिट के इस विदवासेमें सहमत हैं कि "जब तक साम्राज्यवाद जड़में नष्ट नहीं होगा तब तक एक मुन्दर विश्व व्यवस्था" नहीं कायमकी जा सकती।

इस घोषणापत्रकी दूसरी धारामें यह इच्छा प्रकटकी गयी थी कि "ऐसा कोई प्रादेशिक परिवर्तन नहीं होगा जो उस प्रदेशकी जनताकी स्वतन्त्र मम्मतिमें झेल न खाता हो"। तो क्या इसका यह अर्थ था कि फिनलैण्ड, पोलैण्ड और बाल्टिक राज्योंको उनके वे प्रदेश वापस दिलाये जायेंगे जो युद्धके पूर्व उनके अधिकारमें थे? इस व्यवस्थाके प्रति हम की क्या प्रतिक्रिया हुई?

तीसरी धारामें घोषणा की गयी कि "सभी जानियें कि इस अधिकारका मम्मान किया जायगा कि वह स्वयं यह निर्णय करे कि किस प्रकारकी सरकारके अधीन वह रहता चाहती है"। इस धारामें यह इच्छा भी व्यक्तकी गयी कि जिन लोगोंके सम्प्रभु अधिकार और जिनका स्वायत्त उनमें बलान्ती छीन लिया गया है वे उन्हें वापस दिलाये जायें। तो क्या इसका मतलब यह है कि केवल बहुमत का शासन होगा या इसमें उपजानियों द्वारा अपने पृथक् राज्य स्थापित करनेका अधिकार भी निहित है? यदि उनका दूसरा अर्थ ही अभीष्ट है तो इस प्रकार बनाये जानेवाले नये राज्यों में अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी क्या व्यवस्था होगी? क्या यह धारा भारत पर भी लागू थी? चर्चिल ने कहा था कि वह भारत पर लागू नहीं होनी और रुजवेलेट का विचार था कि यह भारत पर लागू होनी है।

चौथी और पाचवी धाराएँ आर्थिक पक्षमें सम्बन्धित हैं। इन धाराओंमें

नीन पृथक् क्षेत्र होने चाहिए। सबसे ऊपर गारा विद्व हो जिनकी अपनी एक विद्व सरकार हो। इस सरकारके अधिनार क्षेत्रमें डाक व्यवस्था, हवाई यातायात, विद्व मुद्रा, कुछ कच्चे मालोंका उपयोग और टंगस्टन (tungsten), टाइटेनियम (titanium) तथा निकेल (nickel) जैसे महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थों (raw materials) का अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो। शक्ति द्वारा शान्ति स्थापित करने के लिए एक विद्व न्यायालय और विद्व पुलिस भी हो।

हमके बाद एक प्रादेशिक अधिनार सत्ता हो जिनके अधीन एक प्रादेशिक भू-भाग रहे। इसका काम एक बीचके क्षेत्रमें हो जिनके भीतर समाजका एकीकरण तुरन्त सम्भव हो। श्रम और व्यापार सम्बन्धी कुछ घातें और चुगी (tariff), आप्रव्रजन (immigration) उसके अधीन रहे। प्रादेशिक क्षेत्रोंमें रहने वालोंकी आदतें तथा जीवन पद्धतिया मिलनी-जुलती होगी। इन प्रादेशिक भू-भागोंके निर्माण में और उन्हें कायम रखनेमें भौगोलिक राजनीति (Geo-politics) का बड़ा प्रभावपूर्ण हाथ रहता। इन प्रादेशिक भू-भागोंके ऊपर एक मध्य होता जो राष्ट्र सभ या विद्व सभसे बिल्कुल भिन्न होता।

लॉर्ड डेवीज (Lord Davies) का कहना था कि निम्नलिखित सभ बन सकते हैं : अंग्रेजी भाषा भाषी देशोंका सभ, ब्रूम को केन्द्र बनाकर स्लाव देशोंका सभ, दक्षिणी अमेरीका के लैटिन गणराज्योंका सभ, भारत और उसके पड़ोसी राज्योंको मिलाकर मध्य एशियाई देशोंका सभ, मुदूर पूर्वी देशोंका सभ और योरोप के राष्ट्रोंका सभ। अफ्रीका का नाम बड़ी सुविधाके साथ छोड़ दिया गया था—सम्भवत अंग्रेजी भाषा भाषी देशों द्वारा घोषण किये जानेके लिए। लॉर्ड डेवीज के अनुसार मुद्रकों समाप्त कर देना, विधि राज्यकी स्थापना करना, एक सामान्य वैदेशिक नीति निर्धारित करना, न्यायाधिकरणके लिए एक विद्व अधिनार सत्ताकी स्थापनाके उद्देश्यमे विद्व महासंघमें सम्मिलित होना, शान्ति स्थापित रखना और आर्थिक समस्याओंके निराकरणमें सहयोग देना—आदि इन सभों के उद्देश्य थे। नवीन सभमे पचास या उससे अधिक राज्योंके बजाय पांच या छ. राज्य होते और उनके बीच होने वाले विवादोंका निराकरण पारम्परिक विचार विमर्श और परामर्श द्वारा किया जाता।

सगठनोंकी श्रुसलामें तीसरी श्रेणी राष्ट्रीय क्षेत्रोंकी थी जिनकी एक राष्ट्रीय सरकार होती। कंटलिन इस क्षेत्रको शिक्षा और गम्भृतिके विकासके लिए उपयुक्त क्षेत्र मानते थे। राष्ट्रीय भावनाके लिए यह क्षेत्र उपयुक्त था। इस सीमाके भीतर राष्ट्रीयतावाद कल्याणकारी था; इस सीमाके बाहर राष्ट्रीयतावादको कल्पना मूलक, प्रतिक्रियावादी, और कभी समाप्त न होने वाले युद्धोंका सक्रिय कारण माना गया।

इन प्रस्तावोंका निचोड़ था सांस्कृतिक क्षेत्रमें राष्ट्रीयतावाद, आर्थिक क्षेत्र में प्रादेशिकतावाद और उच्च राजनीतिक क्षेत्रमें अन्तर्राष्ट्रीयतावाद।

राष्ट्रीयतावाद, साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद

एटलान्टिक घोषणापत्र या अधिकारपत्र (Atlantic Charter) में हमें इस बात का संकेत मिलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन युद्ध के बाद के मसालों किम प्रकार की विश्व व्यवस्था कायम करना चाहते थे। इस घोषणापत्र को विन्स्टन चर्चिल के यथार्थवाद और काउंट हल्के आदर्शवाद का रुब्रवेन्टीय कि इस अधिकार पत्र की प्रथम तीन धाराएं वाइबिल (old testament) का कहना है आदेश (tenth commandment) की व्याख्या-भाव है। यह आदेश है "तुम लालच नहीं करोगे।" संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ने इस बात की घोषणा की कि उन्हें प्रादेशिक या अन्य किसी भी प्रकार के विस्तार की महत्वाकांक्षा नहीं है। सब बात तो यह है कि इस धाराने किसी भी हृदय में कोई उल्लाह नहीं पैदा होना। क्योंकि अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन का उस निश्चय ठीक वैसा ही है जैसा ऊंचे रक्तचाप में पीड़ित एक व्यक्ति अपने को जोषित रखने के लिए अपने खान पान को नियमित और नियंत्रित करने का निश्चय करता है। इस धाराने हिटलर की युद्ध के पहले की गयी फरेवने भारी इस घोषणा को और भी बल दे दिया कि वह जो युद्ध आरम्भ करने जा रहा था, वह धन: देशों के विरुद्ध निर्धन देशों का युद्ध था। चर्चिल के वक्तव्यों में उनका यह इरादा माऊ अलक्षता या कि "जो हमारे अधिकार में है उसे हम अपनी मुट्ठी में निक्कलने न देंगे"। हम प्रिट के इस विश्वास में सहमत हैं कि "जब तक साम्राज्यवाद जड़ें नष्ट नहीं होना तब तक एक मुन्दर विश्व व्यवस्था" नहीं कायम की जा सकती।

इस घोषणापत्र की दूसरी धारामें यह इच्छा प्रकट की गयी थी कि "ऐसा कोई प्रादेशिक परिवर्तन नहीं होगा जो उस प्रदेश की जनता की स्वतंत्र सम्मति से न जाता हो"। तो क्या इसका यह अर्थ था कि क्रिन्लैण्ड, पोलैण्ड और बाल्टिक राज्यों को उनके वे प्रदेश वापस दिलाये जायेंगे जो युद्ध के पूर्व उनके अधिकार में थे? इस व्यवस्था के प्रति हम की क्या प्रतिक्रिया हुई?

तौनरी धारामें घोषणा की गयी कि "मनी जानिये कि इस अधिकार का सम्मान किया जायगा कि वह स्वयं यह निर्णय करे कि किम प्रकार की सरकार के अधीन वह रहना चाहती है"। इस धारामें यह इच्छा भी व्यक्त की गयी कि जिन लोगों के सम्पन्न अधिकार और जिनका स्वायत्त उनमें बलान् छीन लिया गया है वे उन्हें वापस दिलाये जाय। तो क्या इसका मतलब यह है कि केवल बहुमत का शासन होगा या इसमें उपजातियों द्वारा अपने पृथक् राज्य स्थापित करने का अधिकार भी निहित है? यदि उसका दूसरा अर्थ हो अमोष्ट है तो इस प्रकार बनाये जानेवाले नये राज्यों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की क्या व्यवस्था होगी? क्या यह धारा भारत पर भी लागू थी? चर्चिल ने कहा था कि वह भारत पर लागू नहीं होगी और रुब्रवेन्टी का विचार था कि यह भारत पर लागू होगी है।

बीषी और पाचवी धाराएं आर्थिक पक्ष में सम्बन्धित हैं। इन धाराओं में इस

तीन पृथक क्षेत्र होने चाहिए। सबसे ऊपर गारा विश्व हो जिसकी अपनी एक विश्व सरकार हो। इस सरकारके अधिकार क्षेत्रमें डाक व्यवस्था, हवाई यातायात, विश्व मुद्रा, कुछ कच्चे मालोंका उपयोग और टंगस्टन (tungsten), टाइटेनियम (titanium) तथा निकेल (nickel) जैसे महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थों (raw materials) का अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो। शक्ति द्वारा शान्ति स्थापित करने के लिए एक विश्व न्यायालय और विश्व पुलिस भी हो।

इसके बाद एक प्रादेशिक अधिकार सत्ता हो जिसके अधीन एक प्रादेशिक भू-भाग रहे। इसका काम एक बीचके क्षेत्रमें हो जिसके भीतर समाजका एकीकरण सुरक्षित सम्भव हो। श्रम और व्यापार सम्बन्धी कुछ बातें और धुगी (tariff), आप्रजनन (immigration) उसके अधीन रहे। प्रादेशिक क्षेत्रोंमें रहने वालोंकी आदतें तथा जीवन पद्धतियाँ मिलनी-जुलनी होंगी। इन प्रादेशिक भू-भागोंके निर्माण में और उन्हें काममें रखनेमें भौगोलिक राजनीति (Geo-politics) का बड़ा प्रभावपूर्ण हाथ रहता। इन प्रादेशिक भू-भागोंके ऊपर एक गण होना जो राष्ट्र मध्य या विश्व गणसे बिल्कुल भिन्न होना।

लॉर्ड डेवीज (Lord Davies) का कहना था कि निम्नलिखित सभ बन सकते हैं। अंग्रेजी भाषा भाषी देशोंका सभ, व ह्म को केन्द्र बनाकर स्लाव देशोंका मध्य, दक्षिणी अमेरीका के लैटिन गणराज्योंका सभ, भारत और उसके पड़ोसी राज्योंको मिलाकर मध्य एशियाई देशोंका सभ, सुदूर पूर्वी देशोंका मध्य और योरोप के राष्ट्रोंका मध्य। अफ्रीका का माम बड़ी सुविधाके साथ छोड़ दिया गया था—सम्भवतः अंग्रेजी भाषा भाषी देशों द्वारा शोषण किये जानेके लिए। लॉर्ड डेवीज के अनुसार युद्धको समाप्त कर देना, विधि राज्यकी स्थापना करना, एक सामान्य वैदेशिक नीति निर्धारित करना, न्यायाधिकरणके लिए एक विश्व अधिकार सत्ताकी स्थापनाके उद्देश्यमें विश्व महासभमें सम्मिलित होना, शान्ति स्थापित रखना और आर्थिक समस्याओंके निराकरणमें सहयोग देना—आदि इन सभों के उद्देश्य थे। नवीन सभमें पक्षान या उसमें अधिक राज्योंके बजाय पाँच या छः राज्य होंगे और उनके बीच होने वाले विवादोंका निराकरण पारस्परिक विचार विमर्श और परामर्श द्वारा किया जाता।

संगठनोंकी शृंखलामें सीमरी श्रेणी राष्ट्रीय क्षेत्रोंकी थी जिनकी एक राष्ट्रीय सरकार होनी। कंर्टलन इस क्षेत्रको शिक्षा और संस्कृतिके विकासके लिए उपयुक्त क्षेत्र मानते थे। राष्ट्रीय भावनाके लिए यह क्षेत्र उपयुक्त था। इस सीमाके भीतर राष्ट्रीयतावाद कल्याणकारी था; इस सीमाके बाहर राष्ट्रीयतावादको कल्पना मूलक, प्रतिक्रियावादी, और कभी समाप्त न होने वाले युद्धोंका सक्रिय कारण माना गया।

इन प्रस्तावोंका निचोड़ या मासृतिक क्षेत्रमें राष्ट्रीयतावाद, आर्थिक क्षेत्र में प्रादेशिकतावाद और उच्च राजनीतिक क्षेत्रमें अन्तर्राष्ट्रीयतावाद।

राष्ट्रीयतावाद, साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद

एटलांटिक घोषणापत्र या अटलांटिक (Atlantic Charter) से हमें इस बातका संकेत मिलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन युद्ध के बादके मसालों किम प्रकारकी विश्व व्यवस्था कायम करना चाहते थे। इस घोषणा पत्र को विन्स्टन चर्चिल के वयासंवाद और कॉडेल हलके आदर्शवादका रूजवेल्टीय समन्वय कहा जाता है। वाइकाउण्ट सैमुअल (Viscount Samuel) का कहना है कि इस अधिकार पत्रकी प्रथम तीन धाराएं वाइबिल (old testament) के दशम आदेश (tenth commandment) की व्याख्या-मान्य हैं। यह आदेश है: "तुम लालच नहीं करोगे।" संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन दोनोंने इस बातकी घोषणाकी कि उन्हें प्रादेशिक या अन्य किसी भी प्रकारके विस्तारकी महत्वाकांक्षा नहीं है। मंच बात तो यह है कि इस धारामें किसीकी भी हृदयमें कोई उत्साह नहीं पैदा होता। क्योंकि अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन का उक्त निश्चय ठीक वैसा ही है जैसा ऊंचे रक्तचापमें घोटिन एक व्यक्ति अपनेको जीवित रखनेके लिए अपने सान पानको नियमित और नियमित रखनेका निश्चय करता है। इस धारामें हिटलर की युद्धके पहले की गयी क्रूरकर्मों भारी इस घोषणाकी ओर भी बल दे दिया कि वह जो युद्ध आरम्भ करने जा रहा था, वह धनी देशोंके विरुद्ध नियंत्रण देगोका युद्ध था। चर्चिल के वक्तव्योंमें उनका यह इरादा साफ़ सलकता था कि "जो हमारे अधिकारमें है उसे हम अपनी मुट्ठीमें निक्कलने न देंगे"। हम प्रिट के इस विद्वानमें सहमत हैं कि "जब तक साम्राज्यवाद जड़में नष्ट नहीं होना तब तक एक सुन्दर विश्व व्यवस्था" नहीं कायमकी जा सकती।

इस घोषणापत्रकी दूसरी धारामें यह इच्छा प्रकटकी गयी थी कि "ऐसा कोई प्रादेशिक परिवर्तन नहीं होगा जो उस प्रदेशकी जनताकी स्वतंत्र सम्मतिमें मेल न पाना हो"। तो क्या इसका यह अर्थ था कि फ्रिन्लैण्ड, पोलैण्ड और बाल्टिक राज्योंको उनके वे प्रदेश वापस दिलाये जायेंगे जो युद्धके पूर्व उनके अधिकारमें थे? इस व्यवस्थाके प्रति हम की क्या प्रतिक्रिया हुई?

तीसरी धारामें घोषणा की गयी कि "सभी जातियोंके इस अधिकारका सम्मान किया जायगा कि वह स्वयं यह निर्णय करे कि किम प्रकारकी सरकारके अधीन वह रहना चाहती है"। इस धारामें यह इच्छा भी व्यक्तकी गयी कि जिन लोगोंके सम्प्रभु अधिकार और जिनका स्वशासन उनमें बलान् चीन लिया गया है वे उन्हें वापस दिलाये जायें। तो क्या इसका मतलब यह है कि बेइजिङ बहुमत का शासन होगा या इसमें उपजातियों द्वारा अपने पृथक् राज्य स्थापित करनेका अधिकार भी निहित है? यदि उसका दूसरा अर्थ ही अंगीष्ट है तो इस प्रकार बताया जानेवाले नये राज्यों में अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी क्या व्यवस्था होगी? क्या यह धारा भारत पर भी लागू थी? चर्चिल ने कहा था कि वह भारत पर लागू नहीं होती और रूजवेल्ट का विचार था कि यह भारत पर लागू होती है।

चौथी और पाचवी धाराएं आर्थिक पक्षमें सम्बन्धित हैं। इन धाराओंमें इस

जातवा वादा किया गया है कि सभी राज्य समान धनों पर मंथार भग्में व्यापार कर सकेंगे और अपनी आर्थिक समृद्धिके लिए आवश्यक बच्चा भाल समार भरने प्राप्त कर सकेंगे। एक प्रश्न जो सम्भवतः हमारे मनमें उठता है, यह है: "क्या यह आवश्यक था कि ऐसा वादा करनेके लिए युद्ध समाप्त हो जानेके बाद दो वरों तक प्रतीक्षा की जानी? यदि यह वादा युद्धके पहले कर दिया गया होता तो क्या उपनिवेशोंके बारेमें हिटलर के दावोंका आधार ही समाप्त न हो जाता। इस धाराका निहित अर्थ यह है कि १९३२ का ऑटवा करार जिसके अनुसार साम्राज्य बाहरके देशोंके विरुद्ध कठोर शृंगीकी दीवार (tariff wall) खड़ी की गयी थी, एक भयंकर भूल थी। चौथी और पाचवी धाराओंमें सभी राष्ट्रोंमें परस्पर घनिष्ठ सहयोगका आश्वासन दिया गया है ताकि धर्मके विविध मानदण्ड, आर्थिक प्रगति, और सामाजिक सुरक्षा मसालके सभी राष्ट्रोंमें सुलभ हो सकें।

अन्तिम तीन धाराओंमें उन माधनोको बनाया गया है जिनके द्वारा नाज़ी अत्याचारोंके समाप्त हो जानेके बाद स्थायी धान्ति क्रायमकी आयगी। इन माधनोंमें आक्रमण करनेवाले राष्ट्रोंका निःसम्बन्धकरण, सामुद्रिक स्वातन्त्र्य और भय तथा अभावसे मुक्ति प्रमुख थे।

इन धाराओंका मूल्य आज आका जा रहा है। जनरल स्मट्स की इस घोषणा ने इन धाराओंका पर्दाकाश कर दिया है कि एटलांटिक घोषणापत्र उत्तरी अफ्रीका स्थित इटली के उन प्रदेशों पर नहीं लागू हो सकता जो युद्धके दौरानमें समुक्त राष्ट्र संघके अधिकारमें आ गये थे।

रूडवेल्ड द्वारा घोषित चार स्वाधीनताओंको हर व्यक्तिको स्वाधीनता प्रदान करने वाला घोषणा पत्र कहा जाता है। इनमें से पहली स्वाधीनता है अकारण आक्रमणके भयसे मुक्ति, और बिना विनी प्रकारकी बाहरी बाधा या दबावके, अपना राष्ट्रीय जीवन बितानेकी स्वाधीनता। दूसरी स्वाधीनता है अभावसे मुक्ति, इसमें दरिद्रतासे मुक्ति और सामूहिक बेकारीसे मुक्ति तथा काम करनेका अधिकार और प्रत्येक व्यक्तिके लिए जीवनका एक न्यूनतम मान दण्ड सम्मिलित है। तीसरी स्वाधीनताएँ—विवेक स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्तिकी स्वाधीनता—अपने आप स्पष्ट हैं। इस सूचीमें एक महत्वपूर्ण स्वाधीनताको बाहर रखा गया है। और वह है जातीय और सामाजिक अत्याचारोंसे मुक्ति। रूडवेल्ड की भविष्यपरिपक्षमें गृह विभागोंके मंत्री आइकम् ने कहा था कि अमेरिकामें अल्प समुदायोंके साथ, विशेषकर नीचो लोगोंके साथ, जो व्यवहार किया जाता है वह उस व्यवहारसे बही खराब है जो रूस में अल्प समुदायोंके साथ किया जाता है।

हम भारतवर्षी निम्नलिखित चार स्वाधीनताएँ चाहते हैं: (१) अकारण आक्रमणसे मुक्ति; (२) आर्थिक अस्थिरता (economic insecurity) से मुक्ति; (३) सामाजिक अत्याचारों (वर्ण, वर्ग, समाज धर्म व भाषा द्वारा होने वाले) से

राष्ट्रीयतावाद, साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद

मुक्ति और (४) पूर्ण आत्मनिष्पत्ति की स्वाधीनता जिसमें विवेक की स्वाधीनता और अनिष्पत्तिकी स्वाधीनता सम्मिलित है।

युद्ध के बाद के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीयतावाद चाहे जो भी मगठान्मक रूप धारण करे पर जब तक निम्नलिखित चार बातों की व्यवस्था नहीं होती तब तक अन्तर्राष्ट्रीयतावादका द्वितीय घोटना व्यर्थ है: (१) चरम राष्ट्रीयमन्त्रभूता के मिडान्तका परिष्कार, (२) रचनात्मक शान्तिकी स्थापना और उनको बनाये रखने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था की स्थापना (३) राष्ट्रीय और राष्ट्र ममता के बीच आर्थिक न्याय और (४) व्यक्तिगत के लिए सामाजिक सुरक्षा। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है यह सुरक्षा द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना सम्बन्धी बेरोजगारी योजना के अनुसार होनी चाहिये।

हम समय अपने को केवल दूसरी बात तक ही सीमित रखने हुए हम वाइकम स्टीड (Wickham Steed) के इस कथन में सहमत हैं कि शान्तिकी अर्थ केवल युद्ध बन्दी या युद्धका न होना ही नहीं होता। शान्ति नकारात्मक नहीं है। यह रचनात्मक और गतिशील है और इसमें अविमर्श पृष्ठ होने के कारण यह एक आकर्षक उपक्रम है। लिविनोफ़ (Livino) के शब्दों में "शान्ति अविनाशक है"।

शान्ति तभी स्थायी तौर पर कायम रह सकती है जब हम परिश्रम और भावधानों में विश्व समाज की भावना को विकसित कर लें और प्रत्येक राष्ट्र अपने को समूचे विश्व समाजका ही अंग मानने लगे तथा विश्व समाज के हित को ही अपना हित समझने लगे। हम यह नहीं चाहते कि एक आगल-मेकमनी मध्य शेष समस्त समाज के लिए विनाशकारी काम करे। कौन जानता है कि ऐसा विधान किनने दिन चले। हम शक्ति मनुजल के बदनाम मिडान्तकी पुनर्प्राप्ति भी नहीं चाहते।

युद्ध के बाद के कुछ वर्षों के लिये जर्मनी की निराशा करना चाहे जितना आवश्यक रहा हो, पर एक पक्षीय निराशाशीलता युद्ध और शान्तिकी समस्या को बढ़ाकर नहीं कर सकता। प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति पर एक पक्षीय निराशाशीलताका प्रयत्न किया गया था पर योरोपीय सरकारों परस्पर वाक्-युद्ध ही करती रही और किसी एक सामान्य नीति पर एकमत न हो सकी। हर सरकार अपने सम्प्राप्ति के अपने पक्ष ही मुखरित करना चाहती थी और उनका समुच्चय किसी ने स्वीकार नहीं किया। बाद काउण्ट मैमूअल (Viscount Samuel) का यह कहना विन्तुल टोक है कि एक पक्षीय निराशाशीलता निराशाशील राष्ट्रों के मुकाबिले अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रों का एक बड़ा आर्थिक मुक्ति का मिल जायगी। इसके अतिरिक्त एक पक्षीय निराशाशीलता न तो मद्भाग्य स्थापित हो सकती है और न इस पर अधिक समय तक अवलंब हो किया जा सकता है।

सब राष्ट्रों का एक साथ निराशाशीलता और एक सामाजिक अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार मना की स्थापना जिसे विश्व न्यायान्य और एक अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस

या शान्ति-रक्षक दलना बल प्राप्त हो, ही इस ममम्याका एक मात्र हल है। इस शान्ति रक्षक सेनाका एक प्रधान सेनापति होना चाहिए और उसे कुछ ऐसी शक्तियोंकी गैरिक मैत्रीमें पड़ कर झपट न होना चाहिये जो किसी दूसरे गैरिक मैत्री वाले गुटके साथ दलदलीकरणकी होड़में लगे हो। इसमें अंग्रेजों, अमरीकियों तथा रूसी और चीनी लोगोंके साथ-साथ जर्मन, इटालियन और जापानी लोगोंकी भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि इसमें राष्ट्रीय देनामजिन समाप्त हो जाती हैं तो उनके कोई हानि नहीं होनी क्योंकि ऐसी देनामजिन स्थायी बनाये जानेके योग्य नहीं हैं। इस अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार मत्ताको यथार्थ रूपमें एक मजबूत राष्ट्र मजबूत पुलिम दल बनाना होगा। हम नहीं चाहते कि मजबूत आधा हिस्सा दूसरे हिस्सेके लिए पुलिमका कार्य करे। सत्तार भरके बल्याणके लिए साथे मजबूतको पुलिम बनना होगा। राष्ट्रीय गैर्य दलोंके स्थान पर एक वास्तविक विद्व पुलिम दल होना चाहिए जो जाने ब्रम् अपराधियोंके विरुद्ध उनके जाने-बुझे अपराधोंके लिए भीमित शक्तिका उपयोग करे।

SELECT READINGS

- Aims, Methods and Activity of the League of Nations, 1935.*
 ASIRVATHAM, E.—*A New Social Order*—Chs. IX, X, and XI.
 BARNES, LEONARD—*The Duty of Empire.*
 BARNES, LEONARD—*The Future of Colonies.*
 BARNES, LEONARD—*Empire or Democracy.*
 BRYCE, LORD—*International Relations.*
 BUELL, R. L.—*International Relations.*
 CURTIS, L.—*Civitas Dei.*
 GIBBONS, H. A.—*Introduction to World Politics.*
 GILCHRIST, R. N.—*Indian Nationality.*
 GOOCH, G. P.—*Nationalism.*
 HALLOWELL, J. H.—*Main Currents in Modern Political Thought*—
 Ch. 16.
 HAYES, C. J. H.—*Essays on Nationalism.*
 HOBSON, J. A.—*Imperialism, A Study.*
 HOCKING, W. E.—*The Spirit of World Politics.*
 JENNINGS, IVOR—*A Federation for Western Europe.*
 JOSEPH BERNARD—*Nationality.*
 KOHN, HANS—*Nationalism in the East.*
 LASKI, H. J.—*A Grammar of Politics.*
 MADARIAGA, SALVADOR DE—*The World's Design.*

- MAZZINI—Selected Writings.
 MAZZINI—The Duties of Man and other Essays.
 MILL, J. S.—Representative Government.
 MOON, P. T.—Imperialism and World Politics.
 MOON, P. T.—Syllabus on International Relations.
 MORGENTHAU, J. H.—Politics among Nations.
 MUEB, R.—Nationalism and Internationalism.
 PALMER, N. D. AND PERKINS—International Politics.
 PILLSBURY, W. B.—The Psychology of Nationality and Internationalism.
 PRITT, D. N.—Federal Illusion.
 ROSE, J. H.—Nationality in Modern History.
 SCHUMAN, F. L.—International Politics, (4th Ed., 1945).
 SITARAMAYYA—History of the Indian National Congress.
 TOTNBEE, A.—Nationality and the War.
 TOTNBEE, A.—Study of International Affairs.
 TAGORE, R.—Nationalism.
 VON TREITSCHKE—Politics—(2 Vols.).
 WOOLF, L.—Imperialism and Civilization.
 WOOLF, L. S.—International Government.
 ZIMMERN, A. E.—Nationality and Government.
 ZIMMERN, A. E.—The Third British Empire.

संयुक्त राष्ट्र-संघ

(The United Nations)

हिटलर और मुसोलिनी की तथा जापान के युद्ध नायकों की महत्वाकांक्षाओं के कारण १९३९ में समार एक भयानक युद्ध में फँस गया। इनके विरुद्ध युद्ध करने वाले मित्र राष्ट्रों को उस समय युद्ध में विजय पाना सर्व प्रमुख लक्ष्य हो गया। पर जैसे-जैसे युद्ध बढ़ता गया जैसे-जैसे मित्र राष्ट्रों के राजनीतिज्ञोंने अधिवाधिक अनुभव किया कि यदि उन्हें युद्ध जीतना है तो उन्हें अपनी जनता के सामने कोई ऐसा महत्वपूर्ण उद्देश्य रखना होगा जिसके लिए युद्ध करना उचित मालूम पड़े। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चार स्वाधीनताओं की घोषणा की और रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधान मंत्री चर्चिल ने एक गद्यबद्ध घोषणा पत्र निकाला जिसे अतलांतिक अधिकार पत्र या घोषणा पत्र (Atlantic Charter) कहते हैं।

रूजवेल्ट ने निम्नलिखित चार स्वाधीनताओं की घोषणा की थी—भय और अरक्षा (insecurity) से मुक्ति, अभाव से मुक्ति, विचार की स्वतंत्रता और उपारण की स्वतंत्रता (freedom of fear and insecurity; freedom from want; freedom of expression, and freedom of worship); जर्मनी में नाज़ियों के अत्याचारों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध इन स्वाधीनताओं का निर्धारण हुआ था। रूजवेल्ट ने घोषणा की थी कि ये स्वाधीनताएँ सारी मानव जाति पर सब कही जाएंगी। अतलांतिक अधिकार पत्र की घोषणा अगस्त १९४१ में की गयी थी। यह मौलिक सिद्धान्तों की घोषणा थी। ये सिद्धान्त विल्सन के चौदह सूत्रों से बहुत मिलते-जुलते थे। विल्सन के चौदह सूत्रों में से कुछ ये हैं—शान्तिकी स्थापना, भय और अभाव से मुक्ति, शक्ति उपयोग का निषेध, निर्यात-स्त्रीकरण, अनाक्रमण, सम्बन्धित जनता की स्वीकृति बिना प्रादेशिक सीमा परिवर्तन का निषेध, सब देशों के लिए बच्चे माल की समान मुविद्या आर्थिक क्षेत्र में सब देशों का पूर्ण पारस्परिक सहयोग आदि।

जैसे-जैसे युद्ध बढ़ता गया घुरी राष्ट्रों (axis powers) जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध करने वाले मित्र राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र या युनाइटेड नेशंस कहा जाने लगा। यह नाम रूजवेल्ट ने रखा था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं की यादगार में विश्वराष्ट्रों के संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ (The United Nations Organization) रख दिया गया। अब इसे संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र (The United Nations) या यू० एन० ही कहा जाता है।

मित्र राष्ट्रों के राजनीतिज्ञ युद्ध समाप्त होने की प्रतीक्षा किये बिना युद्ध के

दौरानमें ही संयुक्त राष्ट्र संघके संगठनमें लग गये। पिछले राष्ट्र संघ या लीग आफ नेशन्सकी असफलता सबकी आँखें खोल चुकी थी फिर भी लोगोंने महसूस किया कि राष्ट्र संघका दावा अधिकांश रूपमें सन्तोषजनक था। इसलिए वे उसी दावे पर नये संगठनका निर्माण करने लगे। पहली जनवरी १९४२ को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र (The United Nations Declaration) पर हस्ताक्षर किये गये। ब्रिटेन की ओर से चर्चिल ने, अमेरिका की ओर से रूजवेल्ट ने, रूस की ओर से लिटविनाक् ने और चीन की ओर से टोंग यूंग ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये। एक वर्षके कुछ अधिक समय बाद माँस्को में एक सम्मेलन हुआ जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रान्क के विदेश मंत्री सम्मिलित हुए। ३० अक्टूबर, १९४३ को उन्होंने यह घोषणा की—“अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखनेके लिए यथासम्भव शीघ्र एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करनेकी आवश्यकता हम अनुभव करते हैं जिसका संगठन सभी शान्तिप्रिय राष्ट्रोंकी समान सम्प्रभुताके सिद्धान्त पर हो और जिसका द्वार सभी छोटे-बड़े शान्तिप्रिय राष्ट्रोंके लिए खुला हो”।

माँस्को की इस घोषणाके बाद और कई सम्मेलन हुए जैसे काहिरा-सम्मेलन (नवम्बर १९४३, काहिरा—यूनाइटेड अरब रिपब्लिक की राजधानी), तेहरान सम्मेलन (तेहरान—ईरान की राजधानी), ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (ब्रेटन वुड्स नामक नगर संयुक्त राज्य अमेरिका में) और हॉटस्प्रिंग्स सम्मेलन (हॉटस्प्रिंग्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नगर)। अन्तिम सम्मेलनमें संयुक्त राष्ट्र संघकी शायदा “लाघ व इवि संगठन” की नींव डाली गयी जिसने शुरूसे ही महान सेवा कार्य किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघकी रूपरेखा तय करने वाला सम्मेलन अक्टूबर १९४४ में वाशिंगटन में डम्बर्टन ओक्स नामक भवनमें हुआ था। इस सम्मेलनमें एक आम सभा, एक ११ सदस्यी सुरक्षा परिषद, एक आर्थिक और सामाजिक परिषद, एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, और एक स्थायी सचिवालय कार्य करनेके प्रस्ताव रखे गये। अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस दलके प्रश्न पर भी विचार किया गया था।

एक महत्वपूर्ण बात जो इस सम्मेलनमें तय होनेसे रह गयी थी वह थी सुरक्षा परिषदमें मतदानकी पद्धति। इस प्रश्नका फ्रेमला गान्टा-सम्मेलनमें हुआ। इसमें स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल शामिल हुए थे। इस प्रश्नको तय करनेके अनिश्चित उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि अप्रैल सन् १९४५ में मैनफ्रेमिन्को में उन सभी राष्ट्रोंका एक सम्मेलन हो जो घुरी राष्ट्रोंके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। सम्मेलन होनेके पहले ही रूजवेल्ट का देहान्त हो गया और उनके स्थान पर ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। जब २५ अप्रैल सन् १९४५ को निर्दिष्ट स्थान पर सम्मेलन हुआ तब नयी बर्लिनइया पैदा हो गयी। रूस उस सम्मेलनमें बाहर निकल आया और राष्ट्रपति ट्रूमैन के बहुत सम्मानने बुलाने पर ही वह फिर सम्मेलनमें शामिल हुआ। भारत इस सम्मेलनमें सम्मिलित हुआ था। ए० रामास्वामी मुदालियर, ची० टी० कृष्णामाचारी और किरोर सा नून भारत के प्रतिनिधि थे। डम्बर्टन ओक्स

में बनी सपरेखा पर सम्मेलनने विस्तारपूर्वक विचार कर उमवा व्योरेवार विस्तार किया। सबसे अधिक और व्योरेवार विचार इस सम्मेलनमें आर्थिक और सामाजिक परिपदके गठन और उमके बायों पर किया गया क्योंकि यह अनुभव किया जा चुका था कि जब तक मनुष्य जातिके कुछ गम्भीर आर्थिक प्रश्नोंको नहीं सुलझाया जाता तब तक स्थायी शान्ति अमम्भव है।

इस सम्मेलन में ५० राष्ट्र शामिल हुए थे और वे ही संयुक्त राष्ट्र सघके प्रथम सदस्य बने। २४ अक्टूबर सन् १९४५ को हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रोंने घोषणा पत्र स्वीकार कर सत्सम्बन्धी सूचनापत्र अमेरिका के राष्ट्र विभागमें दाखिल कर दिये। १० जनवरी सन् १९४६ को संयुक्त राष्ट्र सघकी स्थापनाकी गयी। उस दिन राष्ट्र सघ (League of Nations) का २६वा जन्मदिवस था। संयुक्त राष्ट्र सघकी आम सभा की पहली बैठक लन्दन में वेस्ट मिन्स्टर के सेन्ट्रल हालमें हुई। उसके बाद राष्ट्र सघ (League of Nations) विधिवत् समाप्त कर दिया गया।

घोषणा पत्रमें एक सौ प्यारह छोटी-छोटी धाराएं हैं। घोषणा पत्रकी प्रस्तावना (Preamble) में संयुक्त राष्ट्रके मौलिक उद्देश्य बताये गये हैं। प्रस्तावना का आरम्भ इन अर्थपूर्ण शब्दोंके साथ होता है—“हम संयुक्त राष्ट्रोंके लोग”। राष्ट्र सघ (League of Nations) घोषणा पत्रमें इन शब्दोंका उपयोग किया गया था—हम सविदा करने वाले उच्चाधिकारी (The High Contracting Parties)—इसमें यह मतलब निबलता है कि संयुक्त राष्ट्र सघ सभारकी जनताकी ओरसे बोलता और काम करता है। पर इस शाब्दिक अन्तरमें बहुत अधिक अर्थ न दूटना चाहिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सघके सदस्य स्वतन्त्र और सम्प्रभु राज्य ही हैं। राष्ट्र सघकी भांति संयुक्त राष्ट्र सघ भी अपने सदस्योंमें अपनी सम्प्रभुता समर्पित करने की मांग नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र सघ “सम्प्रभु राज्योंका स्वेच्छामूलक सहयोग” है। वह राज्यों पर राज्य (super state) नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र-संघके उद्देश्य (Purposes of the U.N.).

संयुक्त राष्ट्र सघ के निम्नलिखित चार उद्देश्य हैं :

(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना;

(२) समान अधिकारों और आत्म निर्णयके प्रति निष्ठाके आधार पर—राष्ट्रोंके

बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धोंका विकास करना;

(३) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवता मूलक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंको सुलझाने और मानवीय अधिकारों तथा सबके लिए मौलिक स्वाधीनताओंके प्रति सम्मानकी भावनाका विकास करनेमें सहयोग करना; और

(४) इन सामान्य उद्देश्योंकी निदिके लिए राज्यों द्वारा किये जाने वाले कार्योंके समन्वय (harmony) का केन्द्र बनना।

मिद्दाल (principles)—ऊपर बताया गये उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ निम्नलिखित मिद्दालोंके अनुसार काम करता है :

(१) संघका संगठन अपने सभी सदस्योंकी सम्प्रभुताकी समताके मिद्दाल पर आधारित है;

(२) सदस्य राष्ट्रोंने घोषणा पत्रके अनुसार जो जिम्मेदारियां या कर्तव्य पूरा करनेका भार अपने ऊपर लिया है उन्हें सदस्य राष्ट्र ईमानदारीके साथ पूरा करें;

(३) सदस्योंको अपने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े शान्तिमय तरीक़ोंमें सुलझाने हें;

(४) सदस्योंको अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंमें ऐसे किसी ढंगमें शक्ति-प्रयोग की धमकी नहीं देना है और न शक्ति का प्रयोग करना है जो संयुक्त राष्ट्रोंके उद्देश्योंके प्रतिकूल हो;

(५) घोषणा पत्रके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी काम करे उसमें सदस्यों को हर प्रकारकी मदद करनी है और ऐसे किसी भी राष्ट्रको सहायता नहीं देनी है जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ नियोगात्मक या आदेशमूलक कार्रवाई कर रहा हो;

(६) संयुक्त राष्ट्र संघको इस बातका प्रयत्न करना है कि जो राष्ट्र संघके सदस्य नहीं हैं वे भी, जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखनेके लिए आवश्यक है, इन मिद्दालोंके अनुसार आचरण करें;

(७) संयुक्त राष्ट्र संघको किसी राष्ट्रके घरेलू मामलोंमें दखल नहीं देना है। पर जब शान्ति भंग होनेका खतरा हो या शान्ति भंगकी गयी हो तब आवश्यक किया गया हो तब यह धारा लागू नहीं होगी और संयुक्त राष्ट्र संघ आदेश मूलक कार्रवाई कर सकेगा।

सदस्यता (Membership). जैसा ऊपर बताया जा चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघके प्रथम सदस्योंकी संख्या पचास थी। १९५५ तक केवल दस सदस्य और शामिल किये गये क्योंकि नये सदस्योंके लिए जानेके प्रश्न पर संघके दो शक्तिशाली गुटोंमें संघर्ष छिड़ गया। १९५५ में दोनों गुटोंमें समझौता हो जाने पर एक साथ सोल्ह सदस्य संघमें शामिल कर लिये गये। सदस्योंकी संख्या १९५८ के अन्त तक ८२ पर पहुँच गयी थी। “सभी शान्तिप्रिय राष्ट्र” संघके सदस्य हो सकते हैं। सदस्योंको घोषणा पत्रमें लिखित उत्तरदायित्व स्वीकार करने होते हैं और उनमें इन उत्तरदायित्वोंकी निभानेकी सामर्थ्य और इच्छा होनी चाहिए। सुरक्षा परिषदकी निष्कारिता पर आम सभाके दो निरुद्ध सदस्योंके समर्थन द्वारा नये सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघमें शामिल किये जाते हैं। और सुरक्षा परिषदमें पांच बड़ों (ब्रिटेन, राष्ट्रीय चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस) में से कोई भी अपने वीटो (veto) का उपयोग कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के छोटोंमें इतिहासमें सोवियत रूस ने बहुत बार वीटोका उपयोग किया है जिसमें कई बार यह उपयोग नये सदस्योंके लिए जानेके सम्बन्धमें किया गया है। दस अधिकारका इतना अधिक दुरुपयोग किया गया है कि यह सामान्य धारणा बन गयी है कि इस स्थितिसे बचनेके लिए कोई उपाय निकालना

चाहिये। एक सम्भव हल यह है कि किसी भावी सदस्यकी सदस्यता पर वीटोका उपयोग केवल दो बार ही किया जाय। या नये सदस्य सुरक्षा परिषदकी मिफारिशके बिना ही आम सभाके दो तिहाई वोटोंमें शामिल किये जाय। राष्ट्र सभमें ऐसा ही होता था। यह बहुत आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र सभका आधार पर्याप्तम्भव अधिसाधिक व्यापक हो और केवल बड़े राष्ट्र उममें बाहर रखे जाय जिनका सफल ही उमें नष्ट कर देना हो।

धीरगता पत्रके मिद्वान्तोका बार-बार उल्लंघन करने पर किसी सदस्यको संघसे निराग्रा जा सकता है। आम सभाको अधिकार है कि सुरक्षा परिषद द्वारा जिन सदस्योंके विरुद्ध नियंघात्मक या आदेशमूलक कार्रवाईकी गयी हो उनकी सदस्यताको सुरक्षा परिषदकी मिफारिश पर दो तिहाई सदस्योंके वोटमें निलम्बित (suspend) कर दें। निलम्बित सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सभकी किसी भी मामलाकी बैठकमें शामिल नहीं हो सकता जिसका वह सदस्य है। वह किसी न्यायप्रदेश (trust) का गामन नहीं कर सकता। पर ऐसे राष्ट्रके जो नागरिक संयुक्त राष्ट्र सभके सचिवालयमें काम करते हैं वे काम करते रहने हैं।

संयुक्त राष्ट्र सभमें किसी सदस्यके सभसे अलग होनेकी कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्र सभमें यह व्यवस्था थी। पर यदि कोई सदस्य राष्ट्र विशेष परित्यक्तिपों के कारण सभसे अलग होना चाहता है तो उमें ऐसा करनेमें रोकनेका कोई इरादा नहीं है। अभी तक कोई सदस्य सभसे अलग नहीं हुआ है यद्यपि फ्रान और दक्षिणी अफ्रीका ने बैठकोंमें से विरोध प्रम्यान बिगा है (staged a walk-out)।

संयुक्त राष्ट्र-संघके अंग (The Organs of the United Nations). जहा राष्ट्र सभ (League of Nations) के तीन प्रधान अंग थे—आम सभा, परिषद और सचिवालय—वहा संयुक्त राष्ट्र सभके निम्नलिखित ६ मुख्य अंग हैं—आमसभा (the General Assembly), सुरक्षा परिषद (The Security Council), आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (The Economic and Social Council), न्याय-परिषद (The Trusteeship Council), अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (The International Court of Justice) और सचिवालय (the Secretariat)। आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा न्याय परिषद आम सभाके अधीन काम करती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयको संयुक्त राष्ट्र सभका एक अविभाज्य अंग बनाया गया है। सभके सारे प्रशासनीयकार्य सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्याय परिषदके बीच बडे हुए हैं। सुरक्षा परिषद आम सभासे अलग स्वतन्त्र रूपमें काम करती है।

आम-सभा (The General Assembly)

आम सभा ही संयुक्त सभका एक अवेला अंग है जिसमें सभके सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि रहते हैं। प्रत्येक सदस्यको पांच प्रतिनिधि रखनेका अधिकार है जिन

सबका एक वोट होता है। आम सभाकी बैठक नियमित रूपसे सालमें एक बार होती है। प्रायः यह बैठक मितम्बर के महीनेमें आरम्भ होती है। मुरझा परिषद या संघके सदस्योंके बहुमतकी प्राप्ति पर आम सभाको विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। आम सभा केवल विचार विमर्श करने वाली सभा है। वह केवल सिफारिश कर सकती है। शान्ति और मुरझाके मामले अकेले मुरझा परिषदको ही सौंपे गये हैं। जब मुरझा परिषद ऐसे मामलों पर विचार कर रही हो तब आम सभा उस सम्बन्धमें कोई सिफारिश भी नहीं कर सकती। पर १९५० में स्वीकृत "शान्तिके लिए संगठित कार्रवाई" वाले प्रस्ताव {या अचेसन प्रस्ताव (Acheson महोदयके नाम पर)} के अनुसार यदि मुरझा परिषद किसी महत्वपूर्ण मामले पर कदम उठानेमें असफल होती है तो आम सभा उस मामले पर विचार कर सकती है और उचित सिफारिश कर सकती है। आम सभाका काम "विचार विमर्श करना, विवाद करना, और सिफारिश करना है पर कार्रवाई करना नहीं"। विचार विमर्श करनेके अधिकार के साथ-साथ आम सभाको कुछ प्रणामनीय या व्यवस्था सम्बन्धी, निर्वाचन सम्बन्धी और वज्रट सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं। उसे घोषणा पत्रमें सलाहनोंके लिए कदम उठानेका भी अधिकार है।

राष्ट्र सभ और संयुक्त राष्ट्र सभकी आम सभाओंके बीच एक प्रधान अन्तर यह है कि राष्ट्र सभकी आम सभा ऐसे निर्णय कर सकती थी जो सदस्यों पर लागू होते थे, पर संयुक्त राष्ट्र सभकी आम सभा केवल मुझाव दे सकती है, यद्यपि उसके पीछे काफी नैतिक बल रहता है।

संयुक्त राष्ट्र सभकी आम सभामें मतदान की पद्धति राष्ट्र सभकी पद्धतिकी अपेक्षा सुघरी हुई है। राष्ट्र सभकी आम सभामें किसी निर्णयके लिए सर्वसम्मति मत आवश्यक था यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्योंका सर्वसम्मति मत। पर संयुक्त राष्ट्र सभकी आम सभामें मौजूद और मतदान करने वाले सदस्योंके, दो तिहाई मतमे ही निर्णय हो सकते हैं। दो तिहाई मतोंमे निर्णय किये जाने वाले प्रश्नों में निम्नलिखित विषयों पर मुझाव देना भी शामिल है: अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और मुरझा कायम करना, परिषदोंके सदस्योंका निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र सभमें नये सदस्योंका लिया जाना, या सदस्योंका निलम्बन (suspension) या निष्कासन, स्यामप्राप्ति व्यवस्थाकी कार्य विधिमें सम्बन्ध रखने वाले मामले, और वज्रट सम्बन्धी प्रश्न। अन्य मामलों पर उपस्थित और वोट देनेवाले सदस्योंके साधारण बहुमतमे ही निर्णय किये जाते हैं। आम सभाकी समितियोंमें निर्णय उपस्थित और वोट देने वाले सदस्योंके बहुमतमे किये जाते हैं।

राजनीतिक क्षेत्रमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगकी वृद्धि करने और अन्तर्राष्ट्रीय विधिके निरन्तर विकास और महिनावृद्ध करनेके कार्योंको उन्माहित करनेके लिए अध्ययन करने या कराने और करने मुझाव रखने या सिफारिश करनेके व्यापक अधिकार आम सभाको दिये गये हैं। "निर्णयोंके अन्तर्गत और सम्पत्तियोंके नियमन

सम्बन्धी निर्देशन-मिद्धानों" पर विचार करने और अपने सुझाव देनेका भी अधिकार आम सभाको है। चौदहवीं धाराके अन्तर्गत उगे अधिकार हैं कि 'ऐसी किसी परिस्थितिके शान्तिपूर्ण सुलझावके सम्बन्धमें उस परिस्थितिकी उत्पत्ति पर ध्यान न देते हुए निश्चित कदम उठानेकी मिकारिज करे जिसे वह राष्ट्रीय मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों अथवा सामान्य ब्रह्माण्डके लिए घातक या बाधक समझती हो।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षाके बारेमें आम सभा निम्नलिखित दो हालतोंमें मिकारिजें कर सकती है। (१) जब सुरक्षा परिषद अपनी उम जिम्मेदारीको पूरा न कर रही हो ओ घोंपण पत्र ने उमे मीची है। या (२) जब सुरक्षा परिषद आम सभामें मिकारिजें मागे। धारा ११ (३) के अन्तर्गत आम सभा सुरक्षा परिषदका ध्यान उन परिस्थितियोंकी ओर दिला सकती है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षाको खतरा हो। धारा १२ (२) में इस बातकी व्यवस्था है कि समुक्त राष्ट्र सभके सदस्योंको उन मामलोंमें अवगत रखा जाया करे जो चार्ल्सवार्डके लिए सुरक्षा परिषदके विचारधीन हो। समुक्त राष्ट्र सभका महामंत्री सुरक्षा परिषद (सम्भवतः सभी स्थायी सदस्य) की मजूरीमें आम सभाके प्रत्येक अधिवेशनको अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखनेमें सम्बन्धित उन मामलोंमें सूचित करेगा जिन पर सुरक्षा परिषद विचार कर रही हो। जब सुरक्षा परिषद ऐसे मामलों पर विचार करना समाप्त कर देती है, तो इसकी सूचना भी महामंत्री आम सभाको देगा। और यदि आम सभाका अधिवेशन नहीं हो रहा हो तो समुक्त राष्ट्र सभके सदस्योंको सूचित किया जायगा।

संगठनात्मक कार्योंके अन्तर्गत, आम सभा सुरक्षा परिषदके अस्थायी सदस्योंको दो वर्षोंके लिए चुनती है। वह आर्थिक और सामाजिक सदस्योंको चुनती है और न्यास-परिषद (Trusteeship Council) के निर्वाचनीय सदस्यों (elective members) को चुनती है। (बाकी सदस्य पदेन *ex-offices* होते हैं)। सुरक्षा परिषदकी मिकारिज पर आम सभा समुक्त राष्ट्र सभके महामंत्रीको नियुक्त करती है। सुरक्षा परिषदके साथ स्वतंत्र रूपमें वोट देते हुए आम सभा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीशोंको चुनती है।

आम सभा सभकी अन्य सस्याओंमें उनकी रिपोर्टें लेती है और उन पर विचार करती है। महामंत्रीकी वार्षिक रिपोर्टें आम सभामें पेश की जाती हैं। आम सभा समूचे संगठनके बजट पर विचार करती है, उसे स्वीकार करती है और सदस्योंके बीच व्ययका बटवारा करती है।

सुरक्षा परिषदकी पन्द्रहवीं और चौबीसवीं धाराओंके अन्तर्गत आम सभाके मामने वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्टें पेश करनी होनी हैं। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये रिपोर्टें कब पेशकी जानी चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि सुरक्षा परिषद को इस सम्बन्धमें पर्याप्त स्वतंत्रता है। आम सभा इन प्रतिवेदनो या रिपोर्टों को लेती है और उन पर "विचार" करती है। "विचार" करनेके सिलमिलेमें प्रतिवेदनोमें

निहित समस्याओं पर अपने मुझाव देनेका अधिकार आम सभाको है। यद्यपि शान्ति और सुरक्षा कायम रखनेका उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद पर ही है पर आम सभाके जरिए से उसे सभारके जनमतके सामने यह जवाब देना होता है कि वह इस महत्वपूर्ण कामको किस प्रकार कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयके प्रतिवेदनों या रिपोर्टों के बारेमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है। संघकी विभिन्न ममलोंसे सम्बन्धित मस्याएँ आम सभाके सामान्य निर्देशनके अन्तर्गत स्वतंत्र रूपसे काम करनी हैं।

आम सभाने आशा की जानी है कि वह अपने अधिवेशनोंके बीचकी अवधिमें अन्तरिम सभा या लघु सभाके माध्यमसे काम करे। इस अन्तरिम या लघु सभामें प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका एक प्रतिनिधि रहना है। अन्तरिम या लघु सभा एक दुर्बल मस्या है क्योंकि कम इसका कूट्टर विरोधी है। आम सभा कुछ महत्वपूर्ण स्थायी समितियोंके माध्यमसे काम करती है जैसे, प्रथम समिति जो राजनीतिक और सुरक्षा समितिके नामसे विख्यात है और द्वितीय समिति जो आर्थिक और वित्त समिति कहलाती है।

आम सभाकी प्रभावोत्पादकता (Effectiveness of the General Assembly). यद्यपि आम सभाका प्राथमिक कृत्य "विचार करना, विवाद करना और निकारिग करना" है। फिर भी उसे किसी अर्थमें भी प्रभावहीन मस्या नहीं कहा जा सकता। उनका नैतिक अधिकार दिनोदिन बढ़ता ही गया है। संयुक्त राष्ट्र सघके जीवनके प्रथम दस वर्षोंमें आम सभाकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि बढ़ी है और सुरक्षा परिषदकी कुछ घटी है। एक लेखकने आम सभाको "सभारकी नगर सभा" कहा है। एक दूसरे समकालीन लेखकके अनुसार आम सभा "सभारकी स्पष्ट नैतिक धेतना" है। यह "आलोचना करनेवाली (criticizing), पर्यालोचन करने वाली (reviewing) और निरीक्षण करनेवाली (overseeing) मस्या है; पर कार्यपालक (executive) मस्या नहीं है"। सुरक्षाके ममलोंमें कार्यपालक मस्या, सुरक्षा परिषद और आम सभा केवल "विवाद और आलोचना करने वाली मस्या" है। किन्तु कन्यागकारी मामलोंमें वह सर्वोपरि है।

सुरक्षा-परिषद (The Security Council).

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षामें सम्बन्धित ममलों पर केवल सुरक्षा-परिषद ही विचार करती है। इस माघलेमें इस परिषदकी शक्तियाँ राष्ट्र सघकी परिषदकी शक्तियोंकी ओरशा अधिक और मुनिर्धारित है। इसमें ११ सदस्य होने हैं। यह संख्या निश्चित है (राष्ट्र सघकी परिषदमें ऐसा न था)। इन ११ सदस्योंमें से पाच सदस्य स्थायी होने हैं जो पाच बड़े राष्ट्रोंके प्रतिनिधि होने हैं। अस्थायी सदस्योंका चुनाव दो वर्षके लिए होता है और प्रति वर्ष तीन सदस्य चुने जाते हैं। ये सदस्य लगानार दुबारा नहीं चुने जा सकते हैं। भारत एकबार अस्थायी सदस्य रह चुका है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव करने समय निम्नलिखित दो बातोंका ध्यान रखा जाना है: (१) चुने जाने

चाले मदस्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और मुरझा कायम रखनेमें और संपने अन्य उद्देश्योंकी पूर्तिमें योगदान (२) न्यायमगन भौगोलिक विवरण। यह केवल मामली नियम हैं जिनकी अवहेलना भी आम मभा कर सकती है। और वास्तवमें एकमे अधिक बार ऐसा किया जा चुका है। मन् १९५५ तक इस नियमकी अवहेलना की गयी है। अस्थायी मदस्योंका चुनाव तो दो दक्षिणोंके संपर्कका एक ममला बन गया है।

विशेष परिस्थितिमें प्रामाणिक (occasional) सदस्योंकी भी व्यवस्था है। ये सदस्य मपके उन सदस्य राष्ट्रोंका प्रतिनिधित्व करनेके लिए आमन्त्रित किये जाते हैं जिन्हें मुरझा परिषदमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है या जो मयूक्त राष्ट्र मपके सदस्य नहीं हैं पर विचाराधीन ममलेमें सम्बन्धित हैं। ऐसे आमन्त्रित सदस्य मुरझा परिषदकी बैठकोंमें भाग लेते हैं, पर वोट नहीं देते।

परिषदके हर सदस्यका एक वोट होता है। स्थायी सदस्य रखनेका कारण यह है कि वे मुरझाकी मारष्दी देनेवाले मममें अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र माने जाते हैं। परिषदके स्थायी सदस्योंमें परिवर्तन १०० वी और १०९ वी धाराके अनुसार मपके पीपुषा पत्रका ममोधन करके ही किया जा सकता है।

परिषदका सभापनित्व परिषदके सदस्योंमें अंग्रेजी वर्णमालाके अक्षरोंके अनुसार सदस्य राष्ट्रोंके नामके क्रममें प्रति मम बदलता रहता है। परिषद अपने कार्य करनेकी नियमावली स्वयं बनानी है और अपना काम पूरा करनेके लिए आवश्यक उपमम्याओंका निर्माण करनी है। इन प्रकार परिषद के ११ सदस्योंकी दो अस्थायी समितियां हैं (क) विशेषतः समिति जो कार्य पद्धतिकी नियमावलीका काम देखती है और (ख) नये मदस्योंके प्रवेसका काम देखनेवाली समिति।

वीटो (The Veto). मुरझा परिषदके हर स्थायी सदस्यको सभी तात्विक प्रश्नों पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। वोट न देनेका अर्थ निषेधात्मक वोट नहीं है और न अनुपस्थितिका ही अर्थ निषेधात्मक वोट होता है। इस दूमरी बातका निर्णय १९५५ में हुआ था जब रूस के प्रतिनिधि जेम्ब मलिक राष्ट्रवादी चीन के प्रतिनिधित्व-हीन प्रतिनिधिके बराबर परिषदमें भाग लेनेके विरोधमें परिषदमें अनुपस्थित रहे थे। बादमें जब वह मुरझा परिषदमें वापस आये और उन्होंने यह दावा किया कि उनकी अनुपस्थितिमें की गयी परिषदकी कार्यवाही अवैध है तब परिषदने उनका दावा अस्वीकार कर दिया। सभी तात्विक प्रश्नोंके बारेमें कोई निर्णय वैध होनेके लिए उसके पक्षमें सात वोट होने चाहिए जिनमें पांच स्थायी सदस्योंके वोट भी हों। कार्य-पद्धतिमें सम्बन्धित प्रश्नों पर किन्हीं सात मदस्योंके स्वीकारात्मक वोट पर्याप्त होते हैं। यह भी एक तात्विक प्रश्न है कि कौन-सा प्रश्न तात्विक है और कौन-सा कार्य-पद्धतिमें सम्बन्धित है।

शान्तिपूर्ण समझौता (Pacific Settlement). जब मुरझा परिषद किसी झगड़ेके शान्तिपूर्ण समझौते पर विचार करती है तब झगड़ेके दोनों पक्ष परिषद

हाथ बाँटें निश्चय करने समय वोट नहीं दे सकते। पर जब परिषद नियोजक या आदेश मूलक कार्रवाई करने जा रही हो तब झगड़े पक्षों के लिए वोट देने की मनाही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य २४वाँ धारा के अनुसार पहले ही स्वीकार करते हैं कि वे सुरक्षा परिषद के निर्णयों में बाध्य होंगे, उनके प्रतिनिधित्व को मानेंगे, भले ही परिषद में उनका प्रतिनिधि न हो। पर यदि कोई सदस्य परिषद के निर्णयों के विरुद्ध आचरण करना है तो उसके साथ सुगम कोई कार्रवाई की जाने की सम्भावना नहीं रहती। क्योंकि कार्रवाई किये जाने के प्रश्न पर अनेक बाहरी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

सुरक्षा परिषद का अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए है। दो सप्ताहों के बीच १४ दिन में अधिकतर अन्तर नहीं होना चाहिए। परिषद को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो वैसे ही उसकी बैठक हो सके। राष्ट्र मण (League of Nations) में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उनकी परिषद के सभाओं में सदस्य मण के प्रधान केन्द्र स्थान में हमें मौजूद रहें जहाँ मायारणनवा उनकी बैठकें होती थी। फलतः महत्वपूर्ण अवसरों पर देर हो जाती थी। राष्ट्र मण की परिषद की भाँति सुरक्षा परिषद को इस बात का अधिकार है कि संयुक्त राष्ट्र के केन्द्र स्थान में भिन्न ऐसे सभाओं पर भी अपनी बैठक बुलाने जहाँ उनकी राय में उचित हो।

परिषद के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उस राष्ट्र की सरकार का कोई सदस्य या विशेष रूप से नियुक्त कोई प्रतिनिधि कर सकता है। दूसरी स्थिति में सभा की प्रतिनिधि परामर्शदाता या वैकल्पिक प्रतिनिधि हो जाता है।

एक ध्यान देने की बात यह है कि निराश्रयता पर उनकी सम्मिलित विचार नहीं किया जा रहा है किना राष्ट्र मण के अन्तर्गत किया जाना था। बड़े राष्ट्र इस समझ को तब तक हाथ में नहीं लेना चाहते जब तक शान्ति और सुरक्षा निश्चित न हो जाय। सम्मिलित नियमन के लिए योजना बनाने का उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद को सौंप दिया गया है और इस सम्बन्ध में सहायिका समिति (Military Staff Committee) सुरक्षा परिषद की सहायता करती है। सारी योजनाएँ संयुक्त राष्ट्र मण के सदस्यों के सामने उनके विचारार्थ पेश की जाती हैं।

एक दूसरी शैलीय अवस्था और राजनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करने का कोई स्पष्ट उत्तरदायित्व संघ के सदस्यों पर नहीं रखा गया है। पर सदस्यों ने कहा गया है कि वे किसी राष्ट्र की शैलीय अवस्था और राजनीतिक स्वायत्तता के विरुद्ध न तो शक्ति का उपयोग करने की धमकी दें और न शक्ति का उपयोग करें (धारा २ पैरा ४)। शान्ति भंग या किसी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई किये जाने पर सुरक्षा परिषद उचित कदम उठा सकती है।

यदि किसी स्थिति का झगड़े अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को खतरा पैदा हो जाय तो उसकी ओर संयुक्त राष्ट्र सरकार ध्यान आकर्षित करने के निम्नलिखित चार तरीके हैं—

१८—रा० शा० द्वि०—

(१) राष्ट्र सभकी भाति मयुक्त राष्ट्र सभके धोषणा पत्रके अन्तर्गत सदस्योंको इस बातका अधिकार है कि वे सुरक्षा परिषद अथवा आम सभाका ध्यान ऐसी किसी भी स्थिति या ऐसे झगड़ेकी ओर आकर्षित करें जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय संधन या झगड़ा उत्पन्न हो जानेकी आशंका हो। (२) सुरक्षा परिषद स्वयं किसी भी स्थिति या झगड़ेकी जांच यह जाननेके लिए कर सकती है कि "क्या इस स्थिति या झगड़ेका घना रहना अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षाके वायम रखनेमें घातक होगा ? (धारा ३४)। (३) आम सभा ऐसी स्थितियोंकी ओर सुरक्षा परिषदका ध्यान आकर्षित कर सकती है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षाके लिये मनरा पैदा होनेकी आशंका हो। (धारा ११, पैरा ३)। (४) महासत्री सुरक्षा परिषदका ध्यान किसी भी ऐसी स्थितिकी ओर आकर्षित कर सकता है जो उसकी रायमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा वायम रखनेमें बाधा डालनेवाली हो। इस अन्तिम बातमें यह स्पष्ट है कि महासत्री एक प्रतिष्ठित प्रधान बलकें मात्र नहीं है। उसे स्वयं बंदम उठानेका अधिकार है (he is endowed with considerable initiative)। ट्रिग्वे ली (Trygve Lie) ने समय-समय पर इस अधिकारका अविवेकन उपयोग किया था। पर उनके उत्तराधिकारी हैमरसॉन्ड (Dag Hammarskjöld) ने ऐसा नहीं किया।

धारा ३४ (२) के अन्तर्गत कोई भी राष्ट्र, मयुक्त राष्ट्र सभका सदस्य न होने हुए भी अपनेमें सम्बन्धित किसी झगड़ेकी मयुक्त राष्ट्रके सामने रख सकता है, बशर्ते कि यह मामलेको मयुक्त राष्ट्र सभके धोषणा पत्रके अनुसार शान्तिपूर्वक तय करनेको राजी हो।

अन्तर्राष्ट्रीय अथवा सामूहिक आत्मरक्षा (International or collective self-defence) के मामलोंके अतिरिक्त अन्य सब मामलोंमें युद्ध न करनेका उत्तरदायित्व सदस्यों पर पूरा-पूरा है (धारा ५१)। यदि शान्तिके लिए कोई खतरा हो या शान्ति भंग हो गयी हो या किसी प्रकारकी आक्रमक कार्रवाई की गयी हो—तो सुरक्षा परिषद इसके विरुद्ध निषेधात्मक या आदेशात्मक बंदम उठा सकती है। सुरक्षा परिषद शान्तिपूर्ण भ्रमझीनेके लिए निम्नलिखित तरीके अपना सकती है। (१) झगड़ेमें सम्बन्धित पक्ष पचायत, न्यायालय, आपसी बातचीत, जांच, मध्यस्थता तथा समझौते द्वारा अवका प्रादेशिक प्रतिनिधि सस्थाओं और प्रबन्धों (regional agencies and arrangements) द्वारा अपने झगड़ेका निपटारा कर सकते हैं। (२) जब झगड़ेमें सम्बन्धित पक्ष स्वयं झगड़ा निपटानेमें असफल रहे और झगड़ेके बने रहनेमें शान्ति और सुरक्षाको खतरा हो तब सुरक्षा परिषद उन पक्षोंको ऊपर लिखे तरीकोंमें अपना झगड़ा निपटानेको कह सकती है। (३) झगड़ेकी किसी भी स्थितिमें किसी भी समय सुरक्षा परिषद झगड़ा हल करनेके लिए उचित तरीकोंकी सिफारिश कर सकती है। पर परिषदकी इस सिफारिशमें झगड़ेका कोई पक्ष विधित, बाध्य नहीं है, भले ही इस सिफारिशका अधिकतम राजनीतिक या नैतिक महत्त्व हो। वैधिक

जगडे (जिन्हें पहले न्यायमाध्य कहा जाता था) आमतौर पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने पेश किये जाते हैं। इन सबसे यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मंत्रों घोषणापत्र के अनुसार शान्तिपूर्ण ममझौतेकी पद्धति राष्ट्र मंत्रको बनाई गयी पद्धतिकी ओझा अधिक लक्षणी है।

आदेशात्मक कार्रवाई (Enforcement Action) : (१) सुरक्षा परिषद ३९वां धाराके अनुसार निर्णय करती है कि शान्तिके लिए सन्तरा है या नहीं, शान्ति भंग हुई है या नहीं और आवश्यक कार्य किया गया है या नहीं। एक बार यह निर्णय कर लेने पर कि शान्तिके लिए खतरा है, शान्ति भंग हुई है या आवश्यक कार्य किया गया है, सुरक्षा परिषद तुरन्त कार्रवाई कर सकती है। सुरक्षा परिषदका निश्चय सारे संयुक्त राष्ट्र मंत्रकी ओरसे होता है। इसलिए मंत्रों सभी सदस्य आवश्यकता-नुसार सुरक्षा परिषदकी सहायता करनेको बाध्य हैं (धारा ४८)। मंत्रों वैयक्तिक सदस्योंकी फिर निश्चय करना नहीं रह जाता। (२) सुरक्षा परिषद परिस्थितिकी विमर्शमें बचानेके लिए अस्थायी या अन्तरिम कार्रवाईका निश्चय कर सकती है। (३) नैतिक तथा अर्थनैतिक दोनों प्रकारकी अनुशासितियों (sanctions) के सम्बन्धमें मंत्रों सदस्य सुरक्षा परिषदके निर्णयोंसे बाध्य हैं। (४) राष्ट्र मन्त्र (League of Nations) के पास कोई सशस्त्रसेना नहीं थी। संयुक्त राष्ट्र मन्त्रों घोषणा पत्रमें सेनाके उपयोगके लिए अग्रिम योजना बनानेकी व्यवस्था की गयी है। ४१वीं धाराके अनुसार सदस्योंकी "सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय आदेशात्मक कार्रवाईके लिए तुरन्त मिल सकनेवाली राष्ट्रीय हवाई सेनाकी टुकड़ियाँ तैयार रखनी चाहिए।" शान्तिके लिए सामूहिक कार्रवाईवाले प्रस्तावमें सामूहिक कार्रवाई समितिकी व्यवस्थाके द्वारा हम योजनाको और अधिक मजबूत बना दिया गया है। कभी यह है कि कोई नैतिक कार्रवाई उस समय तक नहीं हो सकती जब तक सभी पाखो बड़े राष्ट्र सहमत न हों। संयुक्त राष्ट्र मन्त्र छोटे राष्ट्रोंके विरुद्ध प्रभावपूर्ण विरोधात्मक (preventive) और आदेशात्मक (enforcement) कार्रवाई कर सकता है।

सुरक्षा परिषद निम्नलिखित दो प्रकारकी आदेशात्मक कार्रवाई कर सकती है: (१) ऐसी कार्रवाई जिसमें सेनाका उपयोग आवश्यक न हो यानी आर्थिक और बौद्धिक कार्रवाई जैसे आर्थिक सम्बन्धों और रेल, तार, रेडियो, डाक, समुद्री हवाई और अन्य संचार सूत्रों व परिवहन (transport) का पूर्ण या आंशिक स्थगन और बौद्धिक सम्बन्धोंकी समाप्ति। (२) संयुक्त राष्ट्र मन्त्रों सदस्योंकी अन्न, धन और नम सेना द्वारा समुद्री, स्थलीय और हवाई कार्रवाई जिसमें प्रदर्शन, घेरा डालना और अन्य कार्रवाईया शामिल हैं। परिषद इन बातका निश्चय करती है कि कार्रवाई सब सदस्यों द्वारा की जानी चाहिए या कुछ सदस्यों द्वारा और जो कार्रवाईकी जाय वह इन संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्पात्रोंके माध्यमसे की जाय जिसके वे सदस्य हैं, या स्वयं अपने सीधी कार्रवाई होनी चाहिए।

सुरक्षा परिषद द्वारा संचालित आदेशात्मक कार्रवाई किये जानेके पन्द्रहवहन

यदि किसी राष्ट्रके सम्पूर्ण विविध आर्थिक समस्याएँ उठ सही होती हैं तो वह राष्ट्र चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सफ़ा सदस्य हो या न हो, उन समस्याओंके हल के सम्बन्धमें सुरक्षा परिषदमें परामर्श कर सकता है।

क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ (Regional Arrangements). मैनफार्मिन्गों में पश्चिमी गोलार्धके राष्ट्रोंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि क्षेत्रीय व्यवस्थाओं और समस्याओंकी रचना स्वीकार की जाय। इसका परिणाम घोषणापत्रकी ५२वीं धारा है जिसमें क्षेत्रीय समस्याओं और संयुक्त राष्ट्रके बीच एक निश्चित सम्बन्धकी व्यवस्था की गयी है। ये समस्याएँ अन्तर्राष्ट्रीय दान्ति और सुरक्षा बाधक बननेमें सहायता देनेके लिए हैं। इन व्यवस्थाओं या समस्याओंकी और उनके कार्य बलप्राप्ति मनुष्य राष्ट्र सफ़के उद्देश्य और मिशनोंके अनुकूल होना चाहिए। इन समस्याओंका उद्देश्य स्थानीय झगड़ोंकी निपटाना है। जहाँ उचित होता है वहाँ सुरक्षा परिषद अपनी आदेशात्मक कार्रवाईमें इन समस्याओं या व्यवस्थाओंमें काम ले सकती है। पर भूत-पूर्व राष्ट्रोंमें सम्बन्धित मामलोंके अतिरिक्त अन्य किसी भी मामलेमें सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकार पाये बिना किसी प्रकारकी सूचना बराबर दी जानी चाहिए की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सफ़की इस बातकी सूचना बराबर दी जानी चाहिए कि क्या कार्रवाई की जा रही है या की जायगी। क्षेत्रीय व्यवस्थाओं और समस्याओं पर सुरक्षा परिषदके प्रभावपूर्ण नियंत्रणके लिए यह आवश्यक समझा जाता है।

प्रधान पश्चिमी राष्ट्रों और उनके पिछलगू पूर्वी राष्ट्रोंका दावा है कि नाटो (NATO—North Atlantic Treaty Organization), सीटो (SEATO—South East Asia Treaty Organization) और ब्रगदाद मन्त्रि क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के दायरेमें आती हैं। पर जेप सभार इस पर विद्वाम नहीं करता। असलियत तो यह है कि सीटो होते हुए भी रक्षात्मक बड़े जानेवाले ये क्षेत्रीय गठबन्धन शान्तिके लिए आज सबसे बड़े खतरे हैं।

संयुक्त राष्ट्र सफ़के घोषणापत्रके अनुसार “स्थानीय झगड़े” पहले इन क्षेत्रीय समस्याओंके मामले में देखा जाने चाहिए और उसके बाद सुरक्षा परिषदके मामले में सुरक्षा परिषद भी फिर इन्हीं समस्याओंके झगड़े सफ़ करनेका आदेश दे सकती है। यह व्यवस्था पहलूकी उस व्यवस्थाके विरुद्ध है जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा परिषद का काम केवल कार्य पद्धति सम्बन्धी मुआव देना है। यदि क्षेत्रीय सभार झगड़ा नहीं निपटा पाती तो सुरक्षा परिषद, अपने अधिकारका उपयोग करती है।^१

पहलू या आन्तरिक मामले (Domestic Matters) परलू या आन्तरिक सम्बन्धमें संयुक्त राष्ट्र सफ़के घोषणापत्रकी व्यवस्था राष्ट्र सफ़की व्यवस्था

^१ घोषणा पत्रकी कुछ टिप्पणियाँ निम्नलिखित पुस्तकमें ली गयी हैं।
Goodrich & Hambro : Charter of the United Nations : Commentary and Documents.

की अपेक्षा अधिक व्यापक है। दूसरी धाराके सातवें पैराके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ "ऐसे मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं करेगा जो तात्त्विक रूपमें किसी राष्ट्रके घरेलू या आन्तरिक क्षेत्रमें आते हैं। और न सदस्योंमें माग करेगा कि वे ऐसे मामलोंको घोषणा-पत्रके अन्तर्गत हल करनेके लिए संयुक्त राष्ट्र संघके मामने पेश करें।

सुरक्षा परिषदके अन्य कर्तव्य (Other Functions of the Security Council) सामरिक महत्व (strategic) के न्यूनतम प्रदेशों (trust areas) की देखरेख रखना सुरक्षा परिषदका काम है। सुरक्षा परिषदके स्थायी सदस्य न्यास परिषद (Trusteeship Council) के सदस्य पदेन (*ipso facto*) होते हैं। सुरक्षा परिषद और आम सभा साथ-साथ, किन्तु स्वतंत्र रूपमें, वोट देकर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयके न्यायाधीशोंका निर्वाचन करती है। सुरक्षा परिषद आम सभाको वार्षिक और विशेष रिपोर्टें भेजती है। सामरिक महत्वके क्षेत्रोंके सम्बन्धमें सुरक्षा परिषद आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषदकी भी सहायता की प्रार्थना कर सकती है। किसी भी वैदिक मामलेमें सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयमें परामर्श ले सकती है।

सैनिक कार्रवाई समिति (Military Staff Committee), मान्य शस्त्रास्त्र समिति (Committee for Conventional Armaments), तदर्थ (*ad hoc*) समितियाँ, स्थायी (standing) समिति या आयोग सुरक्षा परिषदको अपनी रिपोर्टें भेजनेवाली सहाय सस्थाएं हैं। मान्य-शस्त्रास्त्र आयोग शस्त्रास्त्रों और सेनाओंके सामान्य नियमन और उन्हें घटानेके सम्बन्धमें अपने सुझाव या प्रस्ताव सुरक्षा परिषदको भेजता है। जनवरी सन् १९४६ में आम सभा द्वारा स्थापित अणुशक्ति आयोग सुरक्षा परिषदको अपनी रिपोर्टें भेजता है और उसीमें शान्ति और सुरक्षाके कायम रखनेमें सम्बन्धित प्रश्नों पर निर्देश प्राप्त करता है।

अधिकार पत्र या घोषणा पत्रमें संशोधन (Amendments of the Charter) (धारा १०८ और १०९). अधिकार पत्र या घोषणा-पत्रमें संशोधन आम सभा द्वारा अथवा संयुक्त राष्ट्र संघके सदस्योंके आम सम्मेलन द्वारा किये जा सकते हैं। ये संशोधन तभी लागू होते हैं जब वे आम सभाके कुल सदस्योंके (केवल उपस्थित और वोट देने वाले सदस्योंके नहीं) दो-तिहाई द्वारा स्वीकार कर लिए जायें और संघके दो-तिहाई सदस्य-राष्ट्र जिनमें सुरक्षा परिषदके सभी स्थायी सदस्य भी शामिल हैं, उन्हें मान लें।

अधिकार पत्र या घोषणा-पत्रमें संशोधन करनेका दूसरा तरीका यह है कि आम सम्मेलनमें आम सभाके दो-तिहाई सदस्य और सुरक्षा परिषदके कोई सात सदस्य संशोधनको स्वीकार कर लें। यदि आम सभाके दसवें वार्षिक अधिवेशनके पहले ऐसा सम्मेलन नहीं बुलाया जाता है तो आम सभाके दसवें वार्षिक अधिवेशनकी कार्यवाहियोंमें अधिवेशन बुलानेका प्रस्ताव अपने आप शामिल कर दिया जाता है। यदि आम सभाका बहुमत और सुरक्षा परिषदके सात सदस्य सम्मेलन बुलानेके पक्षमें वोट देने

हैं तो सम्मेलन बुलाया जाना है।
हर मनोपनके लिए, चाहे वह पहले दममे पाम किया गया हो और चाहे हमरे
दममे, यह आवश्यक होना है कि मुरदा परिपदके मभी स्थायी राष्ट्रों महिन मधने
दो-तिहाई मदम्य, उमे स्वाकार करे।

आर्थिक और सामाजिक परिषद (The Economic and Social Council)

यदि मुरदा परिपदका लक्ष्य ममारको भवते भुक्त करना है तो आर्थिक और सामाजिक
परिपदका लक्ष्य ममारको अभावमे भुक्त करना है। किसी ने बिन्तुल ठीक कहा है
कि "यह मानूँ तो मुरदा परिपदकी बुन्पी जुडवा बहिन है"।
घोषणा-मन्त्री १५वीं धारामें कहा गया है कि मयुक्त राष्ट्र मधके निम्न-
लिखित कार्य होंगे:

- (१) जीवनका स्तर ऊँचा करना और भरपूर रोजी और आर्थिक व सामाजिक
उत्पानकी परिस्थितिया उत्पन्न करना;
- (२) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य-मन्त्रन्वी तथा अन्य सम्बन्धित
गमस्याओंको हल करना और अन्तर्राष्ट्रीय मासृनिक और मिधा-मन्त्रन्वी मामलों
में महयोगकी वृद्धि करना;
- (३) जाति, लिंग, भाषा और धर्मके भेदभावोंमे रहित मधके लिए मानव
अधिकारों और मौलिक स्वाधीनताओंकी प्रतिष्ठा करना और पालन करवाना।
इनमें से अन्तिम तीसरी बात नयी है, यद्यपि राष्ट्र सवने भी बिगिष्ट "अल्प-
मध्यक समझौतेके अन्तर्गत" राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदायोंके अधिकारोंकी रक्षाके
लिए बहुत कुछ किया था। राष्ट्र मधके अधिकार आयोग और उनकी अधिराज
समितिया परिपदके प्रति उत्तरदायी थी। इनके विपरीत आर्थिक और सामाजिक
परिपद केवल आम मभाके ही अधीन काम करती है।

आर्थिक और सामाजिक परिषदमें १८ सदस्य होते हैं। ये सदस्य आम मभा
द्वारा तीन सालके लिए चुने जाते हैं। हर साल ६ सदस्योंका चुनाव होता है। अधि
पूरी होनेके बाद सदस्य दुबारा चुने जा सकते हैं। इस परिषदमें मुरदा परिपदकी
भाति स्थायी मदस्योंकी कोई व्यवस्था नहीं है और न भौगोलिक विविधताका या
औद्योगिक तथा पिछड़े राष्ट्रों या माघाग्य सम्पन्न और उपनिवेशहीन राष्ट्रोंके बीच
सन्तुलनका कोई विचार रखा गया है। फिर भी व्यवहारमें पांच बड़े राष्ट्र हमेशा
चुने गये हैं और ये राष्ट्र परिपदके स्थायी मदस्यसे हो गये हैं। "प्रतिनिधित्वके
भौगोलिक सन्तुलन" के सिद्धान्तका भी व्यवहारमें पालन किया जाता है।

आम मभाकी भाति इस परिषदमें सभी सदस्योंका पद समान है। प्रत्येक
सदस्य राष्ट्रको एक मदस्य और एक वोटका अधिकार है। कोई भी प्रस्ताव साधारण
बहुमतसे पाम हो सकता है। साधारणतया परिषदकी बैठकें वर्षमें १० बार मयुक्त

राष्ट्र मण्डल के स्थानमें होती है। यदि परिषद चाहे तो उसकी बैठक दूसरी जगह भी हो सकती है। परिषद स्वयं अपनी कार्य-पद्धतिके नियम बनाती है और अपने सभापति तथा उपसभापति का चुनाव करती है। परिषद केवल सिफारिशें कर सकती है, वास्तविक कार्यपालक शक्ति उसके पास नहीं है।

जब परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार करती है जिसका सम्बन्ध विशेष रूप से किसी गैर सदस्य राष्ट्र में होता है तब उस राष्ट्र को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वह राष्ट्र विचार विमर्श में भाग लेता है पर वोट नहीं दे सकता।

परिषद अपनी या अपने आयोगों की बैठकों में विशिष्ट समितियों या विशेषज्ञ समितियों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की भी व्यवस्था कर सकती है जो विचार-विमर्श में भाग तो ले सकते हैं पर वोट नहीं दे सकते। विशिष्ट समितियों की कार्यवाहियों में परिषद का प्रतिनिधि भी भाग ले सकता है।

परिषद गैर-सरकारी संगठनों या संस्थाओं के पर्यवेक्षकों की परामर्शदाताओं के रूप में अपनी बैठकों में बुलाने की व्यवस्था कर सकती है।

आर्थिक और सामाजिक परिषद के कुछ विशेष कृत्य ये हैं

(१) अपने में सम्बन्धित सभी विषयों का-आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा तथा अन्य सम्बन्धित मामलों का स्वयं अध्ययन करना या कराना और उन मामलों पर रिपोर्टें तैयार करना या कराना।

(२) आम सभा को या सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को या विशिष्ट समितियों को अपनी सिफारिशें या सुझाव भेजना।

(३) समझौतों के मसविदे आम सभा को भेजना। आम सभा द्वारा पाम हो जाने पर ये मसविदे सदस्य राष्ट्रों के पाम उनकी स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए भेजे जाते हैं।

(४) अपने कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोगों का निर्माण करना।

(५) अपने अधिकार-क्षेत्र के मामलों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को बुलाना।

सुरक्षा परिषद की सूचनाएँ देना और निवेदन किये जाने पर अन्य प्रकार से उसकी सहायता करना, परिषद के विशिष्ट कृत्य हैं। प्रणाम परिषद (Trusteeship Council) की इस परिषद में और उसकी विशिष्ट समितियों में व्यावसायिक सहायता (professional assistance) पाने का अधिकार है।

परिषद अपना काम विविध आयोगों, तदर्थ (ad hoc) समितियों, स्थायी समितियों और विशिष्ट समितियों के माध्यम से करती है। ये सभी परिषद को अपनी रिपोर्टें भेजती हैं। आयोग दो प्रकार के होते हैं—व्यावसायिक (functional) और क्षेत्रीय (regional)। प्रथम कोटिके आयोग हैं—आर्थिक और रोजगार सम्बन्धी, मानव अधिकार सम्बन्धी, सामाजिक, महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी, नशीली दवाओं सम्बन्धी, भूदा सम्बन्धी और आबादी सम्बन्धी। इनमें से कुछ के अधीन

उप-आयोग भी है। इन आयोगों और उप-आयोगों में लाभ यह है कि ये अपने-अपने विषयों की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निरन्तर विचार करने रहते हैं। ये आयोग और उप-आयोग अपने-अपने विषयों में संपूर्ण राष्ट्र गंभीर सचिवालयों के बराबर बड़ा पवित्र मन्त्रालय बनाये रहते हैं। ये उन समस्याओं और प्रस्तावों का अध्ययन करते हैं जो निरपेक्ष दृष्टि से उनके पास भेजी जाती हैं और फिर अपनी विस्तृत रिपोर्टें और मुद्राव विमोचन समितियाँ जिनका काम कर चुकी है, ये आयोग उनके आगे बाम कर और उन मामलों को न करे जो विशेषज्ञ समितियाँ कर चुकी हैं।

व्यावसायिक पक्ष में निम्नलिखित तीन उप-आयोग हैं (१) सांख्यिकीय विश्लेषण (statistical sampling); (२) भेदभाव निरोध और अल्पसंख्यकों का संरक्षण (prevention of discrimination and protection of minorities) और (३) मवाद या सूचना स्वातंत्र्य और समाचार-पत्र स्वातंत्र्य (freedom of information and of the press) सम्बन्धी।

तथापी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राविधिक सहायता समिति (Technical Assistance Committee) है। परिषद सदस्य राष्ट्रों को आयोगों में मददगार निर्वाचित करती है। इसके लिए परिषदका मददगार होना जरूरी नहीं है।

इस प्रकार एक गन्तव्य प्रतिनिधित्व हो जाता है।

क्षेत्रीय आयोगों को बनाने का कारण यह है कि उनमें विविध आर्थिक समस्याओं का अध्ययन और निपटारा आसान हो जाता है। इन आयोगों की मददगारता सम्बन्धित क्षेत्रों के उन राष्ट्रों को दी जाती है जो संयुक्त राष्ट्र सचयों के क्षेत्रों में और उन सदस्यों को भी जिनके विभिन्न स्वायं उद्योग क्षेत्रों में, उदाहरणार्थ अमेरिका और ब्रिटेन सम्बन्धित क्षेत्रों के राष्ट्र या क्षेत्र जो संयुक्त राष्ट्र सचयों के मददगार नहीं हैं, तथापी मददगार रूप में निर्वाचित किये जा सकते हैं।

अब तक इस प्रकार के तीन आयोग स्थापित किये गये हैं। योरोप के लिए सन् १९५७ में आर्थिक आयोग (ECE—Economic Commission for Europe) बनाया गया था जिसमें १८ सदस्य हैं। इसके अधीन निम्नलिखित विषयों के बारे में यानी समितियाँ हैं कोयला, विद्युत् शक्ति, उद्योग और कच्चा माल, देशी परिवहन, जनशक्ति (manpower), इत्यादि, इमारती लकड़ी (timber), व्यवसाय का विकास और कृषि सम्बन्धी समस्याएँ।

सन् १९५७ में ही एशिया और सुदूर पूर्व के लिए भी आर्थिक आयोग की स्थापना की गयी थी। (ECAFE—The Economic Commission for Asia and the Far East)। १९५१ के अन्त तक इनके १४ सदस्य और ११ माथी सदस्य थे। इसके अधीन अनेक महाय सस्थाएँ हैं। उनमें से एक बाढ़-नियंत्रण समिति भी है। इस आयोग ने अपने सदस्यों के लिए बहुत अधिक सन्ध्याओं आकडे तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कर दी है।

तीसरा क्षेत्रीय आयोग लैटिन अमेरिका (लैटिनो) दक्षिणी और मध्य अमेरिका के वे प्रदेश लैटिन अमेरिका कहलाते हैं जहाँ के निवासियोंकी भाषा स्पेनिश, पोर्चुगीज या फ्रेंच है) के लिए आर्थिक आयोग है जो मन् १९४८ में स्थापित किया गया था। इसके २६ सदस्य और ४ तदर्थ (ad hoc) समितियाँ हैं।

मध्य पूर्वके लिए एक आर्थिक आयोग स्थापित करनेका प्रस्ताव कार्य स्वरूप में नहीं लाया जा सका।

क्षेत्रीय आयोगोंकी अधिकार हैं कि वे अपने क्षेत्रकी सरकारोंसे मोचे बाने करें, नीतियाँ सुझावें, और विनिष्ट मेचाएँ करें। आयोग परिषद्के पास अपनी रिपोर्टें भेजते हैं जिनके आधार पर उनके कार्योंका पर्यालोचन (review) होता है।

निम्नलिखित चार स्थायी समितियाँ हैं—अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंमें बानबीत करनेवाली समिति, गैर-सरकारी संगठनों या समस्याओंमें परामर्शकी व्यवस्था करने वाली समिति; कार्यान्वित समिति और बैठकोंके कार्यक्रमकी अन्तरिम समिति।

निम्नलिखित विनिष्ट समस्याएँ हैं—स्थायी केन्द्रीय असीन बाँड, निरीक्षक समिति, अन्तर्राष्ट्रीय बाल सबड कोष (UNICEF—International Children's Emergency Fund) और संयुक्त राष्ट्र मध्य बाल चन्दा-कण्ड।

परिषद्के कार्यका सीमित स्वरूप

(Limited Nature of the Work of the Council)

आर्थिक और सामाजिक परिषद् पूरे समारके सर्वाधिक आवश्यक या महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्नों पर विचार करनेका प्रयत्न नहीं करती; उन्हें मुलज्ञानकी बात तो दूर है। अमेरिकाके एक परराष्ट्र सचिव ने अपने इस कथनमें इस परिषद्के और सम्पूर्ण राष्ट्र मन्के कार्यके सीमित स्वरूपको स्पष्ट कर दिया है—“एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आर्थिक और सामाजिक समस्याओंके हलमें सहायता दे सकता है पर सम्पूर्ण राष्ट्रोंने कार्यों और अधिकारोंमें दखल नहीं दे सकता। वह वैयक्तिक सदस्य राष्ट्रोंको कोई कार्य करनेका आदेश नहीं दे सकता। राष्ट्रोंके आन्तरिक मामलों तक उनकी पहुँच नहीं होनी चाहिए। उनके साधन और उनकी कार्य पद्धतियाँ हैं—अध्ययन, विचार विमर्श, रिपोर्टें और सुझाव”। मूलतः परिषद्को बहुत संकुचित सीमाओंके भीतर काम करनेके लिए बनाया गया था, पर मन् १९४५ में अब तक जो सम्पूर्ण आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ संसारको पीड़ित करती आ रही हैं उन्होंने परिषद् के कार्यक्षेत्र को विस्तृत बना दिया है।

प्रत्यास परिषद् (The Trusteeship Council)

प्रान्त-प्रदेश और स्वायत्तहीन क्षेत्र (Trust Territories and Non-Self-Governing Areas). संयुक्त राष्ट्र मन्के वे सदस्य जो स्वशासनहीन

उप-आयोग भी हैं। इन आयोगों और उप-आयोगोंमें लाभ यह है कि ये अपने-अपने विषयोंको अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निरन्तर विचार करने रहते हैं। ये आयोग और उप-आयोग अपने-अपने विषयमें समुक्त राष्ट्र सभके सचिवालयके कार्योंमें बड़ा घनिष्ट सम्पर्क बनाये रखते हैं। ये उन समस्याओं और प्रस्तावोंका अध्ययन करते हैं जो कि परिषद इनके पास भेजती हैं और फिर अपनी विस्तृत रिपोर्टें और मुद्राब परिषद को भेजते हैं। इन आयोगोंको स्पष्ट आदेश है कि सम्बन्धित मामलों पर विनोद समितियाँ जितना काम कर चुकी हैं, वे आयोग उनके आगे काम करे और उन कार्योंको न करे जो विनोद समितियाँ कर चुकी हैं।

व्यावसायिक पक्षमें निम्नलिखित तीन उप-आयोग हैं (१) सांख्यिकीय विस्तारण (statistical sampling), (२) भेदभाव निरोध और अल्पसंख्यकोंका संरक्षण (prevention of discrimination and protection of minorities) और (३) संचार या सूचना स्वातंत्र्य और समाचार-पत्र स्वातंत्र्य (freedom of information and of the press) सम्बन्धी।

स्थायी समितियोंमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राविधिक सहायता समिति (Technical Assistance Committee) है। परिषद सदस्य राष्ट्रोंको आयोगोंके सदस्य निर्वाचित करती है। इसके लिए परिषदका मदस्य होना जरूरी नहीं है। इस प्रकार एक मन्तुलित प्रतिनिधित्व हो जाना है।

क्षेत्रीय आयोगोंको बनानेका कारण यह है कि उनमें विविध आर्थिक समस्याओं का अध्ययन और निपटारा आसान हो जाता है। इन आयोगोंकी मदस्यता सम्बन्धित क्षेत्रके उन राष्ट्रोंको दी जाती है जो समुक्त राष्ट्र सभके मदस्य हैं और उन सदस्यों को भी जिनके विशिष्ट स्वार्थ उस क्षेत्रमें हो, उदाहरणार्थ अमेरिका और ब्रिटेन सम्बन्धित क्षेत्रके वे राष्ट्र या क्षेत्र जो समुक्त राष्ट्र सभके मदस्य नहीं हैं, माफ़ी सदस्योंके रूपमें निर्वाचित किये जा सकते हैं।

अब तक इस प्रकारके तीन आयोग स्थापित किये गये हैं। योरोपके लिए सन् १९४७ में आर्थिक आयोग (ECE—Economic Commission for Europe) बनाया गया था जिसमें १८ सदस्य हैं। इसके अधीन निम्नलिखित विषयोंके बारेमें बनी समितियाँ हैं: कोयला, विद्युत् शक्ति, उद्योग और कच्चा माल, देशी परिवहन, जनशक्ति (manpower), इस्पात, इमारती लकड़ी (timber), व्यवसायका विकास और कृषि सम्बन्धी समस्याएँ।

सन् १९४७ में ही एशिया और सुदूर पूर्वके लिए भी आर्थिक आयोगकी स्थापना की गयी थी। (ECAFE—The Economic Commission for Asia and the Far East)। १९५१ के अन्त तक इसके १४ सदस्य और ११ साथी सदस्य थे। इसके अधीन अनेक सहाय सस्थाएँ हैं। उनमें से एक बाढ़-नियंत्रण समिति भी है। इस आयोग ने अपने सदस्योंके लिए बहुत अधिक समस्यामें आकड़े तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कर दी है।

तीसरा क्षेत्रीय आयोग लैटिन अमेरिका (टिप्पणी दक्षिणी और मध्य अमेरिका के वे प्रदेश लैटिन अमेरिका कहलाते हैं जहाँ के निवासियोंकी भाषा स्पेनिश, पोर्चुगीज या फ्रेंच है) के लिए आर्थिक आयोग है जो मन् १९४८ में स्थापित किया गया था। इसके २८ सदस्य और ४ तदर्थ (ad hoc) समितियाँ हैं।

मध्य पूर्वके लिए एक आर्थिक आयोग स्थापित करनेका प्रस्ताव कार्य में नहीं आया जा सका।

क्षेत्रीय आयोगोंको अधिकार हैं कि वे अपने क्षेत्रकी सरकारोंने सीधे बानें करें, नीतियाँ सुझावें, और विनिष्ट सेवाएँ करें। आयोग परिषदके पास अपनी रिपोर्ट भेजने हैं जिनके आधार पर उनके कार्योंका परीक्षण (review) होता है।

निम्नलिखित चार स्थायी समितियाँ हैं—अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंमें बातचीत करनेवाली समिति; गैर-सरकारी संगठनों या संस्थाओंमें परामर्शकी व्यवस्था करने वाली समिति; कार्यावली समिति और बैठकोंके कार्यक्रमकी अन्तरिम समिति।

निम्नलिखित विनिष्ट समस्याएँ हैं—स्थायी केन्द्रीय अफीम बोर्ड, निरीक्षक समिति, अन्तर्राष्ट्रीय बाल सङ्कट कोष (UNICEF—International Children's Emergency Fund) और संयुक्त राष्ट्र मधु बाल चन्दा-क़ण्ड।

परिषदके कार्यका सीमित स्वरूप

(Limited Nature of the Work of the Council)

आर्थिक और सामाजिक परिषद पूरे संसारके सर्वाधिक आवश्यक या महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्नों पर विचार करनेका प्रयास नहीं करती, उन्हें सुझानेकी बात तो दूर है। अमेरिकाके एक परराष्ट्र सचिव ने अपने इस कथनमें इस परिषदके और सम्पूर्ण राष्ट्र मधुके कार्यके सीमित स्वरूपको स्पष्ट कर दिया है—“एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आर्थिक और सामाजिक समस्याओंके हलमें सहायता दे सकता है पर सम्पूर्ण राष्ट्रोंके कार्यों और अधिकारोंमें हस्तक्षेप नहीं दे सकता। वह वैयक्तिक सदस्य राष्ट्रोंको कोई कार्य करनेका आदेश नहीं दे सकता। राष्ट्रोंके आन्तरिक मामलों तक उसकी पहुँच नहीं होनी चाहिए। उसके माधन और उसकी कार्य पद्धतियाँ हैं: अध्ययन, विचार विमर्श, रिपोर्ट और सुझाव”। मूलतः परिषदको बहुत सङ्कुचित सीमाओंके भीतर काम करनेके लिए बताया गया था, पर मन् १९४५ से अब तक जो सम्पूर्ण आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ संसारको पीड़ित करती आ रही हैं उन्होंने परिषद के कार्यक्षेत्र को विस्तृत बना दिया है।

प्रत्यास परिषद (The Trusteeship Council)

रज्य-प्रदेश और स्वशासनहीन क्षेत्र (Trust Territories and Non-Self-Governing Areas). संयुक्त राष्ट्र मधुके वे सदस्य जो स्वशासनहीन

क्षेत्रोंका सामन करते हैं, ऐसे क्षेत्र चाहे अन्तर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्थाके अन्तर्गत हो या न हो, इस दायित्वको स्वीकार करते हैं कि इन क्षेत्रोंका सामन इस प्रकार वगेरे कि इन क्षेत्रोंके निवासियोंका अधिकतम अधिक बन्ध्याण हो। इस उद्देश्यकी मिट्टि के लिए ये सदस्य निम्नलिखित कार्य करते हैं-

- (१) निवासियोंकी मस्त्वतियोंको विभी प्रकारकी हानि पहुँचाये बिना उनकी राजनीतिक, आर्थिक मामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी उन्नति करना;
- (२) उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना और उनके साथ विभी प्रकारका दुर्व्यवहार न होने देना;
- (३) स्वशासनका विवास करना और जनताकी स्वतंत्र राजनीतिक मस्याओं की विकासशील उन्नतिमें उनकी महायता करना;

- (४) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षाकी वृद्धि करना;
- (५) विकासकी रचनात्मक कार्रवाईको बढ़ाना, गवेषणा कार्य (research)

की प्रोत्साहित करना, और सम्बन्धित प्रदेशोंकी आर्थिक मामाजिक और वैज्ञानिक उन्नति के लिए एक दूसरेके साथ और अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्ट मस्याओं या विवेक ममितियोंके साथ सहयोग करना, और

- (६) प्रत्याम व्यवस्थामें बाहर जो देश स्वशासनमें वचित हैं उनके बारेमें ऐसे समाचारों और आकड़ोंके अतिरिक्त जो कि सुरक्षा या विधिकी शिन्तानाके कारण नहीं बताये जा सकते उनकी आर्थिक, मामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी परिस्थितियोंके आकड़े और अन्य प्राविधिक सूचनाएँ नियमित रूपमें महामंत्रीके पास भेजना।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्याम-व्यवस्था (International Trusteeship System) यह व्यवस्था उन प्रदेशों पर लागू होती है जो ग्यामधारी देशों और संयुक्त राष्ट्र संघके बीच किये गये वैयक्तिक करारोंके अनुसार इन व्यवस्था के अधीन रहने गये हैं। इस प्रकारसे शामिल होने वाले क्षेत्रोंको प्रत्याम क्षेत्र (Trust Territories) कहा जाता है। यह व्यवस्था उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होती जो संयुक्त राष्ट्र संघके सदस्य हो गये हैं। इस व्यवस्थाके निम्नलिखित चार उद्देश्य हैं

- (१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षाकी वृद्धि करना,
- (२) जनताका राजनीतिक, आर्थिक, मामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी उत्थान करना और स्वशासन जयवा स्वाधीनताकी दिशामें उनका निरन्तर क्रमिक विकास करना,
- (३) मौलिक मानव अधिकारोंका सम्मान बढ़ाना और यह मानना कि सन्सार के सभी देश अन्योन्याश्रित (एक दूसरे पर निर्भर करते) हैं;
- (४) संयुक्त राष्ट्र संघके सभी सदस्य राष्ट्रोंके बीच समानताके व्यवहारको तथा उन देशोंके नागरिकोंके बीच मामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक मामलों

तथा न्यायाधिकरणमें उम हद् तक ममानताका व्यवहार मुरक्षित रखना त्रिम हद् तक प्रन्याम व्यवस्थाके अन्य उद्देश्योंकी मिद्धिसे उमका भेल बैटना हो।

प्रन्यास परिषद (The Trusteeship Council)

इम परिषदके मदम्य निम्नलिखित होने हैं

(१) मुरक्षा परिषदके स्थायी मदम्य, चाहे वे न्याम क्षेत्रोंका प्रमाणन करते हों या नहीं;

(२) संयुक्त राष्ट्र संघके वे मदम्य राष्ट्र जो न्याम क्षेत्रोंका प्रमाणन करने हैं,

(३) वे सदस्य राष्ट्र जो आम सभा द्वारा न्यामधारों मदम्यों और अन्याम-धारी मदस्योंमें ममानता बनाये रखनेके लिए बुने जाते हैं। इम परिषदकी बैठके प्रतिवर्ष दो बार होनी हैं। मदस्योंके बहुमतकी प्रार्थना पर इम परिषदके विशेष अधिवेशन होते हैं। उपस्थित और वोट देनेवाले मदस्योंके बहुमतमें निर्णय किये जाते हैं।

परिषदके कृत्य और अधिकार (Functions and Powers of the Council).

यह परिषद आम सभाकी अधिकार-मत्ताके अगीन ऐसे न्यम्न प्रदेशोंके प्रति संयुक्त राष्ट्र मपके कृत्योंको पूरा करती हैं जिन्हे सामरिक महत्वका नहीं माना गया है। सामरिक महत्वके क्षेत्रोंके प्रति संयुक्त राष्ट्र मपके कृत्योंको मुरक्षा परिषद पूरा करती हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी ममलोंमें मुरक्षा परिषद प्रन्याम परिषदकी महायता लेती है।

प्रन्यास परिषद शासन करने वाले राष्ट्रोंकी रिपोर्टों पर विचार करती हैं, और आये हुए प्रार्थना पत्रों पर इन्ही राष्ट्रोंके परामर्शसे विचार करती हैं, ममय-ममय पर शासन करने वाले राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत अवमरो पर न्यम्न प्रदेशोंमें भेजनेके लिए पर्यवेक्षक मण्डलीकी व्यवस्था करती हैं; और प्रन्याम करारोंकी धाराओंके अनुकूल और भी बदल उठानी हैं; प्रत्येक न्यम्न प्रदेशके निवासियोंकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी उन्नतिके सम्बन्धमें एक प्रस्तावनी तैयार करती हैं जिनके आधार पर शासन करने वाली सन्धिया अपनी वारिक रिपोर्ट भेजती हैं जिन पर प्रन्याम-परिषद विचार करती हैं।

विशिष्ट-समितियां (Specialised Agencies)

पोरणा पत्र (charter) की १७वी धारामें अन्तर्राज्यीय करारोंके आधार पर स्थापित विभिन्न विशिष्ट समितियोंकी व्यवस्थानी गयी है। इन समितियोंको, उनके मौलिक अधिकार पत्रके अनुसार, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य

तथा, अन्य सम्बन्धित क्षेत्रोंमें, व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व दिये गये हैं। ये समितियाँ अधिकार पत्रकी ६३वीं धाराके अनुसार संयुक्त राष्ट्र सचयमें सम्बन्धित की गयीं हैं।

आर्थिक और सामाजिक परिषद इन ऐंजिनियोंके साथ बातें कर उन सतों को निश्चित करती है जिनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र सचयसे उनका सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। पर इन कार्योंके लिए आम ममाकी मजुरी आवश्यक होती है। परिषद इन समितियोंके साथ परामर्श करके और आम ममा तथा राष्ट्र सचयके सदस्योंके पास अपनी सिफारिशें भेज करके इन विशिष्ट समितियोंके कार्योंमें समन्वय (co-ordinate) स्थापित करनेका प्रयत्न करती है।

निम्नलिखित विशिष्ट समितियाँ या सचयन स्थापित हो चुके हैं या स्थापित हो रहे हैं :

(१) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संगठन (The International Labour Organisation—I.L.O.)।

(२) खाद्य और कृषि-संगठन (The Food and Agriculture Organisation—F.A.O.)।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (The International Monetary Fund—I.M.F.)।

(४) पुनर्निर्माण और विकासके लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (The International Bank for Reconstruction and Development)।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मंच (The International Civil Aviation Organisation)।

(६) संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation—UNESCO)।

(७) विश्व स्वास्थ्य संगठन (The World Health Organisation—WHO)।

(८) अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन (The International Refugee Organisation)।

(९) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (The International Trade Organisation)।

(१०) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र परामर्श संगठन (The International Maritime Consultative Organisation)।

(११) विश्व डाक सच (The Universal Postal Union)।

(१२) अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार सच (The International Telecommunications Union)।

(१३) विश्व अन्तरिक्ष-विज्ञान मंड (The World Meteorological Organisation)।

कुछ गैर-सरकारी मंडलोंको भी इनकी मान्यता दी गयी है कि आर्थिक और सामाजिक परिपद इनमें विमर्श कर सकती हैं। ये मंडल निम्नलिखित तीन श्रेणियोंके हैं।

(क) वे मंडल जिन्हें परिपदके अधिकांश कामोंमें मौलिक रुचि है और जो उन क्षेत्रोंके आर्थिक और सामाजिक जीवनमें घनिष्ठ रूपमें सम्बन्धित हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरणके लिए अमेरिकाका श्रमिक मंड।

(ख) वे मंडल जिनमें एक विशेष समता है पर जो परिपदके कुछ घांटे में कामोंमें ही मुख्यतया सम्बन्धित हैं। ऐसे मंडलोंके कुछ उदाहरण ये हैं—अखिल भारतीय महिला मंड, अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिके लिए कारनेगी स्थायी दानकोष (Carnegie Endowment for International Peace), अन्तर्राष्ट्रीय ममस्या चर्च आयोग (Commission of the Churches on International Affairs), अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति, लोकनवीय युवक विश्व मंड (World Federation of Democratic Youth) और विश्व यहूदी मंडल (World Jewish Congress)।

(ग) वे मंडल जो मुख्यतया जनमतके विज्ञान और सूचनाओंके प्रचारमें सम्बन्धित हैं। इन प्रकारके मंडलोंके उदाहरण हैं—साप्ताहिक अध्यापक विश्व मंड और अन्तर्राष्ट्रीय रोटरी क्लब (Rotary International)।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) कई वर्षों में राष्ट्र मंड (League of Nations) के अन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायकी स्थायी अदालत (Permanent of International Justice) का ही है। स्थायी अदालत राष्ट्र मंडकी एक स्वायत्त मंड थी, और वर्तमान न्यायालय संयुक्त राष्ट्र मंडकी प्रथम मंडा है। यह न्यायालय अपने परिनियम (statute) के अनुसार काम करता है। यह परिनियम स्थायी अदालतके परिनियमके आधार पर बनाया गया है।

संयुक्त राष्ट्र मंडके सभी सदस्योंको इन न्यायालय तक पहुँचनेका स्वतः मित्र अधिकार है। मुद्रा परिपदकी गिफारिस पर जिन देशोंको आम मंडा स्वीकृत कर चुकी है उन देशोंके अनुसार वे राष्ट्र भी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयका उपयोग कर सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र मंडके सदस्य नहीं हैं। केवल राष्ट्र ही न्यायालयका उपयोग कर सकते हैं, व्यक्ति नहीं।

किसी राज्यको न्यायालयके सम्मुख आनेके लिए इसलिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। प्रतिवादी (defendant) राज्यकी स्वीकृतिमें ही अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय मुकदमेकी मुनवाई कर सकता है। राष्ट्रों पर न्यायालयका अनिवार्य अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघके सदस्य अपने मामले न्यायालयके सामने रखनेके लिए बाध्य नहीं हैं। किसी सन्धि पर हस्ताक्षर करते समय सन्धिमें सम्बन्धित राष्ट्र यह बचन दे सकते हैं कि सन्धिकी व्याख्यामें यदि कोई झगडा उठ खड़ा होगा तो वह झगडा न्यायालयके सामने ही पेश किया जाएगा।

वैकल्पिक धारा पर हस्ताक्षर करके राष्ट्र इस बातका बचन दे सकते हैं कि कुछ विशेष प्रकारके मामलोंमें वे न्यायालयका उपयोग करेंगे। इसमें वे सब मामले आ जाते हैं जिनका सम्बन्ध निम्नलिखित बातोंमें होता है :

(क) सन्धिकी धाराओंका अर्थ,

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विधिके क्षेत्रमें सम्बन्धित सभी मामले;

(ग) किसी ऐसे तथ्यकी स्थिति, जिसे यदि मिट्ट किया जा सके तो उसमें अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व या कर्तव्य भंग होता हो, और

(घ) किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार या दायित्वके भंग किये जाने पर दिये जाने वाले हुरजानेका स्वरूप या परिमाण।

केवल अराजनीतिक झगडोंके लिए भी कुल ६४ सदस्योंमें से केवल ३४ सदस्यों ने ही न्यायालयकी अनिवार्य अधिकार-शक्ती स्वीकार की है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयके अधिकार क्षेत्रमें वे सब मामले आते हैं जिनसे सम्बन्धित दोनों पक्ष उन्हें न्यायालयके सम्मुख लाना चाहें और वे मामले भी जिनके सम्बन्धमें संयुक्त राष्ट्रोंके घोषणा पत्रमें, चालू सन्धियों या समझौतोंमें, ऐसी व्यवस्था की गयी है। चूँकि इस न्यायालयके परिनिषय स्थायी अदालतके परिनिषयके आधार पर बने हैं, इसलिए सन्धियों या समझौतोंके जिन मामलोंको स्थायी अदालतमें पेश करनेकी व्यवस्था थी वे मामले अब अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयके क्षेत्रमें आते हैं। यह जरूरी नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघके सदस्योंके बीच होने वाले झगडे हमेशा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयके सम्मुख लाये ही जाय। वे ऐसे अन्य न्यायालयोंके सामने भी पेश किये जा सकते हैं जो पहलेसे ही मौजूद हो या भविष्यमें स्थापित किये जाय।

न्यायालयकी एक विशेषता यह है कि सुरक्षा परिषदकी भांति इसे भी राष्ट्रोंको बाध्य करने वाले निर्णय करनेकी शक्ति प्राप्त है। कुछ विशेष परिस्थितियोंमें न्यायालयके बाध्य निर्णयों पर सुरक्षा परिषद पुनर्विचार कर सकती है। एक दूसरी विशेषता यह है कि न्यायालयके गठन और उसकी कार्य-प्रणाली पर भी बड़े राष्ट्रोंके सघर्ष का कुछ हद तक असर पड़ चुका है।

न्यायालयके निर्णयोंका आधार (Basis of the Court's Decision)

मुकदमोंके फैसले करते समय न्यायालय निम्नलिखित बातोंका उपयोग करता है :

- (१) अन्तर्राष्ट्रीय अभिममय (conventions), सामान्य या विशिष्ट दोनों प्रकारकी,
- (२) अन्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाज (customs),
- (३) विधिके वे सामान्य सिद्धान्त, जिनको सम्य राष्ट्र स्वीकार करते हैं,
- (४) न्यायिक निर्णय और विविध देशोंके उच्च योग्यता प्राप्त राजनीतिक प्रवीणोंके लेख या उपदेश।

यदि झगड़ेमें सम्बन्धित पक्ष स्वीकार कर लेते हैं तो न्यायालय झगड़ेका निर्णय करनेमें सम्बन्धित राष्ट्रोंमें प्रचलित न्याय और सामान्य कल्याणके सिद्धान्तों का उपयोग कर सकता है।

न्यायालयके निर्णय (Decisions of the Court). संयुक्त राष्ट्र सभके घोषणा पत्रके अनुसार प्रत्येक सदस्य स्वीकार करता है कि जिस किसी मामलेमें वह बादी या प्रतिवादी होगा उसमें किये गये न्यायालयके निर्णयोंको वह मानेगा। यदि झगड़ेमें सम्बन्धित एक पक्ष न्यायालयके निर्णयके अनुसार अपने दायित्वको पूरा करनेके लिए तैयार है और दूसरा पक्ष तैयार नहीं है तो पहला पक्ष इस स्थितिको सुरक्षा परिषदके सामने रख सकता है। इस हालतमें सुरक्षा परिषद न्यायालयके निर्णयको कार्यान्वित करानेके लिए कार्रवाई कर सकती है या सुझाव दे सकती है। न्यायालय यह भी मकत कर सकता है कि झगड़ेके निर्णय भी पक्षके अधिकारोंकी रक्षाके लिए क्या अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाईकी जानी चाहिए। न्यायालयके निर्णय केवल निर्णय झगड़ेके सम्बन्धमें ही तथा बादी-प्रतिवादी पक्षों पर ही लागू होते हैं। न्यायालयका निर्णय अन्तिम होता है।

परामर्शमूलक सम्मतिपत्रा (Advisory Opinions). प्रापना किये जाने पर न्यायालय वैधिक प्रश्नोंके सम्बन्धमें परामर्शमूलक सम्मतिपत्रा भी देता है। आम सभा और सुरक्षा परिषद भी न्यायालयमें ऐसी प्रापना कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्रों की दूसरी संस्थाओं और विशिष्ट समितियोंके लिए जरूरी होता है कि अपने कार्य-क्षेत्र के अन्तर आने वाले वैधिक समस्याओं पर विचार करनेके लिए आम सभासे अधिकार प्राप्त करें।

सचिवालय (The Secretariat)

महामंत्री (Secretary-General) की नियुक्ति सुरक्षा परिषदकी सिफारिश पर आम सभा करता है। आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा प्रत्याम परिषदों बैठकोंमें वह इसी हैमियनमें काम करता है। सुरक्षा परिषद,

आम सभा तथा आम सभाके विशेष अधिकारन बुलानेके सम्बन्धमें, स्वशासन वित्त प्रदेशोंका सामन करने वाले देशोंमें रिपोर्ट प्राप्त करने, व मन्थियोंके पञ्जीबद्ध करने (registration) और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयके न्यायाधीशोंके चुनावके सम्बन्ध में महामंत्रीको अनेक बर्त्तव्य पूरे करने होते हैं। उसके विशेष अधिकारोंमें से एक यह है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षाके लिए जिन बिमों भी समस्याको घातक समझता हो उसकी सूचना सुरक्षा परिषद को दे सकता है। समुक्त राष्ट्र सभ के घोषणा पत्र (charter) के अनुसार मगठनके कार्य-कलापके बारेमें आम सभाके सम्मुख वार्षिक रिपोर्ट पेश करना उसके लिए आवश्यक है। प्रथम महामंत्रीकी नियुक्ति पाच वर्षके लिए हुई थी। अबधि समाप्त होने पर वही महामंत्री फिरने चुना जा सकता है।

कर्मचारी बर्ग (The Staff). महामंत्री महामभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सचिवालयके कर्मचारियोंकी नियुक्ति करता है। कुशलता, योग्यता और चारित्रिक दृढताके उच्चतम मान-दण्डोंके आधार पर नियुक्तिमा की जाती है। नियुक्तिमा करते समय न्यायोचित भौगोलिक वितरणका भी ध्यान रखा जाता है। महामंत्री या कोई भी अन्य कर्मचारी राष्ट्र सभके अतिरिक्त किसी भी अन्य अधिकार-भक्तसे या किसी सरकारसे किसी प्रकारका भी निर्देश प्राप्त नहीं कर सकता है और न उसे मान सकता है। राष्ट्र सभके सदस्य राष्ट्र भी यह जिम्मेदारी लेते हैं कि वे महामंत्री और उसके कर्मचारियोंके अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूपका सम्मान करेंगे और अपने बर्त्तव्यों और दायित्वोंकी पूर्तिमें उन्हें किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं करेंगे। पर व्यवहारमें ऐसा हमेशा नहीं किया गया। कुछ वर्ष पहले जब साम्यवाद विरोधी भावनाएं बहुत तीव्र हो गयी थी तब अमेरिका ने समुक्त राष्ट्र सभ और उस के महामंत्री पर दबाव डाल कर समुक्त राष्ट्रमें काम करने वाले उन अमेरिकी नागरिकोंको वहासे हटवाया जिन पर साम्यवादके समर्थक होने का मन्देह था।

घोषणा पत्र पर पुनर्विचार (The Revision of the Charter)

यद्यपि समुक्त राष्ट्र सभके घोषणापत्रमें और उसके कार्यमें अनेक त्रुटिया पाई गयी हैं, फिर भी अभी तक घोषणापत्र पर पुनर्विचार करनेका कोई इरादा नहीं दिखाई देता; क्योंकि जब तक वीटोका अधिकार है और दो गुटोंका सचय चालू है तब तक पाच बड़ोंमें से किसी न किसी राष्ट्र द्वारा उसका उपयोग किया जाना भी निश्चिन्त ही है। फिर भी वीडिक दृष्टिमें कुछ सुझाव दिये जा सकने हैं जिनके अनुसार भविष्य में परिवर्तन होना चाहिए।

(१) वीटो का नियन्त्रण; विशेष रूपसे जहा तक नये सदस्योंको लिये जानेका सम्बन्ध है।

(२) आन्तरिक या घरेलू अधिकार क्षेत्र (domestic jurisdiction) की

अधिक स्पष्ट व्याख्या ताकि दक्षिणी अफ्रीका जैसे देश अश्वेत जातिके लोगोंके प्रति असम्मान एवं समयके विपरीत व्यवहारके बारेमें संयुक्त राष्ट्र संघ की निरन्तर अवहेलना यह कह कर न कर सकें कि यह उनका घरेलू मामला है।

(३) ममारके समस्त उपनिवेशोंको न्याय व्यवस्थाके अन्तर्गत ले जाना और निश्चित समयके भीतर उपनिवेशोंकी समाप्ति।

(४) निशस्त्रीकरण पर अधिक ध्यान दिया जाना और एक अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस दल या शान्ति दलके निर्माणके लिए प्रभावपूर्ण कदम उठाना। जैसे-जैसे इस अन्तर्राष्ट्रीय दलकी वृद्धि हो वैसे-वैसे राष्ट्रीय सेनाओंको अनुपातमें कम करवाने जाना।

(५) धारा ५१ और ५२ की अधिक स्पष्ट परिभाषा करना ताकि भौगोलिक दृष्टिसे पूरक राष्ट्र किसी सैनिक मन्त्रि द्वारा एक गुटमें न लाये जा सकें जैसा नाटो और सीटोने किया है।

(६) इस बातकी अधिक स्पष्ट व्याख्या करना कि आतमरक्षाके लिए शक्ति उपयोगका क्या अर्थ है।

(७) परमाण्विक (atomic) और हाइड्रोजन बमों और अन्य ऐसे ही घातक अस्त्रोंके विस्फोटका परीक्षण जारी रख सकनेके किसी भी राष्ट्रके अधिकार पर बड़ी रोक लगाना।

(८) शान्तिके लिए अणुशक्तिके उपयोग पर अधिक ध्यान देना।

(९) धोपनापत्रके रूपमें पहलेसे ही मान्य मानवी अधिकारोंको लागू करनेकी पर्याप्त व्यवस्था।

(१०) विश्व नागरिकता और एक मीमित विश्व सरकारकी स्थापनाके लिए सज्जिब कदम उठाना।

कार्य-सम्पादन^१ (Operation)

संयुक्त राष्ट्र संघके कार्योंका भून्धावन करते समय हमें अत्यधिक आशावाद और निराशावाद दोनोंमें बचना चाहिए। निराशावादी कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघको तो "असंयुक्त राष्ट्र संघ" कहा जाना चाहिए। यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ को इस बात में पराजित कि सुरक्षा परिषदमें बोटोका उपयोग बितनी बार मनमाने तौर पर किया गया है इस बातमें कि बड़े-बड़े राष्ट्रोंने संघको दो दक्षिणाली गुटोंका अखाड़ा बनाने के कितने प्रयत्न किये हैं या इस बातमें कि बितनी बार संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना की गयी है तो यह आश्चर्यजनक नहीं है। इस अन्तिम बातका एक जीता-जागता

^१ इस विभागकी अधिराज्य सामग्री संयुक्त राष्ट्र संघके विभिन्न प्रकाशनोंमें ली गयी है।

उदाहरण यह है अमेरिका ने समुक्त राष्ट्र संघके दायरेके बाहर, पिछड़े राष्ट्रों को काफी आर्थिक सहायता दी। अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न आज भी उलझे पड़े हैं। उनमें से कुछ ये हैं—(१) समुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बार-बार न्याय ममता के पर जोर दिये जाने और बिद्वन्मयालय द्वारा आमेसन (incorporation) के विरुद्ध फ़ैसला दिये जानेके बावजूद दक्षिणी अफ्रीका द्वारा, दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीकाको अपने राज्य में मिला लिया जाना; (२) अणुबमों और हाइड्रोजन बमोंके नियंत्रणके सम्बन्धमें समझौतेका अभाव और कुछ दक्षिणियों द्वारा एक पक्षीय निदधम कि जहाँ वे चाहेंगे और जय चाहेंगे सब इन अस्त्रोंका परीक्षण करेंगे, (३) नये सदस्योंके लिये जाने का व्यवस्थित और प्रतिष्ठापूर्ण मार्ग निश्चालनेमें अमफलता और (४) वीटो का दुरुपयोग।

ऊपर बतायी गयी कमियाँके बावजूद अनेक राजनीतिक कठिनाइयोंको हल करनेमें सुरक्षा परिषद और आम सभाके माध्यमसे बहुतसे महत्वपूर्ण किये गये हैं। फिर भी यह कहना पड़ेगा कि समुक्त राष्ट्र संघका सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम आर्थिक और सामाजिक परिषदके क्षेत्रमें किया गया है, विशेषकर विशिष्ट समितियों के माध्यमसे। प्रत्यास परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयने अभी तक बहुत उल्लेखनीय कार्य किये हैं।

राजनीतिक और सुरक्षा-क्षेत्र (The Political and Security Fields)

(१) ईरान. इस क्षेत्रमें सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ईरान से सम्बन्ध रखता था। १९ जनवरी, १९४६ को ईरान ने सुरक्षा परिषदको सूचना दी कि सोवियत रूस उसके अजरबैजान प्रान्तमें घुस आया है और अपनी सेना वापस बुलानेसे इन्कार कर रहा है। रूसी प्रतिनिधि ग्रोमिको ने इस विषय पर विचार प्रकट कर देनेसे इन्कार किया। वह इस बात पर अड गये कि यह मसला सुरक्षा परिषदकी कार्यावलि में भी नहीं आना चाहिए। पर परिषदने इस मामलेको अपनी कार्यावलिमें रखा और कुछ ही समय बाद रूस ने अपनी फौजोंको वापस बुला लिया। इस मामले का उल्लेख बहुधा सामूहिक सुरक्षा सिद्धान्तकी अद्वितीय विजयके रूपमें किया गया है।

(२) सीरिया और लेबनान. इन देशोंकी जनता अपने महा अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओंके बने रहनेके बहुत विरुद्ध थी। सुरक्षा परिषद ने एक नरम प्रस्ताव स्वीकार किया कि इन देशोंसे ब्रिटेन और फ्रांस अपनी सेनाएँ धीरे-धीरे वापस बुला लें। पर सोवियत रूस ने इस नरमीके विरुद्ध वीटोका उपयोग किया। परिणाम यह निकला कि ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी-अपनी सेनाओंको तेजीसे वापस बुला लेना पड़ा और सीरिया तथा लेबनान के गणतन्त्रों का निर्माण हुआ।

(३) हिन्देशिया (Indonesia) का प्रश्न- युद्ध समाप्त होने पर डच लोगों ने डच ईस्ट इण्डोइज पर फिरसे अपना पंजा जमाना चाहा। इस प्रदेशमें अंग्रेजों सेना की मौजूदगीमें लाभ उठा कर वे फिर नुगस तरीकोंसे सत्तारूढ़ होनेकी कोशिश करने लगे। ३० जुलाई, १९४७ को भारत और आस्ट्रेलिया ने सुरक्षा परिषदका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि हिन्देशिया गणतन्त्र और हार्लण्ड के बीच युद्ध छिड़ गया है। दोनों पक्षोंके बीच शान्तिपूर्ण समझौता करानेके लिए परिषदने तत्काल एक सद्भावना समिति की स्थापना की। पारस्परिक सन्देश दूर करनेमें काफी समय लगा और अन्तमें प्रसिद्ध रेन्वील (Renville) करार पर १७ जनवरी, १९४८ को हस्ताक्षर हुए। युद्ध बन्द हुआ और राजनीतिक बातों आरम्भ हुई।

पर कुछ ही महीनों बाद युद्ध फिर आरम्भ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर करारों की शर्तोंको पूरा न करनेका आरोप लगा रहे थे। वार्ता चल ही रही थी कि डच लोगोंने करार को ठुकरा कर हिन्देशिया की राष्ट्रीय सरकार पर जोर-शोर से हमला बाल दिया।

सुरक्षा परिषदका एक आपाती (emergency) अधिवेशन तुरन्त बुलाया गया। परिषदने दोनों दलोंको युद्ध बन्द करनेका आदेश दिया और डच सरकार से कहा कि वह हिन्देशिया गणतन्त्रके राष्ट्रपति तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओंको जिन्हें वह बन्दी बनाये था, छोड़ दे। डच सरकार कुछ समय तक संयुक्त राष्ट्र सचके प्रस्तावों की अवहेलना करती रही पर हेग में एक गोल्मेत्र परिषद करनेके लिए वह २ मार्च १९४९ को तैयार हो गयी। लम्बी खींच-तान के बाद डच सरकारने जाबा और मुमाना से अपनी फौजे वापस बुला ली और १९४९ में २३ अगस्त से २ नवम्बर तक हेग में सम्मेलन हुआ। सम्मेलनमें दोनों पक्षोंके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सचके हिन्देशियाई आयोगने भी भाग लिया। सम्मेलन के फलस्वरूप हिन्देशियाके संयुक्त गणतन्त्रको पूर्ण सम्प्रभुता मिल गयी। हेग सम्मेलनके फलस्वरूप जो करार हुआ उसमें समानता और पारस्परिक सहयोगके आधार पर डच और हिन्देशिया के भावी सम्बन्धोंकी भी व्यवस्थाकी गयी। सम्प्रभुताका वास्तविक हस्तान्तरण २७ दिसम्बर, १९४९ को हुआ और २९ सितम्बर, १९५० को हिन्देशिया को संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य बनाया गया।

(४) स्पेन का प्रश्न- पोर्तुगल ने अप्रैल, १९४६ में सुरक्षा परिषदसे यह मांग की कि स्पेन की तत्कालीन सरकारको अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिके लिए सतर्क घोषित किया जाय क्योंकि यह सरकार फासीवाद सरकार है और पोर्तुगल प्रस्तावमें भी यही बात कही गयी थी जिसका समर्थन पुनः सैनप्रान्निगको सम्मेलनमें किया गया था। इस पर पश्चिमी राष्ट्रोंने पोर्तुगल के प्रस्तावमें यह मनोयन रखा कि "सतरा" के स्थान पर "सम्भावित सनट" शब्दका उपयोग किया जाय। परिषदने पश्चिमी राष्ट्रोंका सशोधन स्वीकार कर स्पेन की तत्कालीन सरकारको शान्तिके सम्भावित संकट घोषित किया। इस पर रूस ने वीटो का उपयोग किया और सब यह प्रश्न खामनभा

भेज दिया गया। आमसभा ने प्रस्ताव पास किया कि फ्रैंको की सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी महाय मितियों या सम्प्राप्ति की मददगार बचिन कर दी जाय।

पर बाद में, जब शीत युद्ध (cold war) बड़ा और अमेरिका की फ्रैंको के स्पेन की मददगार की आवश्यकता जान पड़ी तब सन् १९५० के अधिवेशनमें आम सभाको इस बातके लिए राजी किया गया कि वह अपनी पिछले निर्णयको बदल दे जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघके सदस्यों द्वारा स्पेनमें अपने-अपने राजदूत वापस बुला लेने और संयुक्त राष्ट्र संघकी मददगार स्पेन को बचिन रखनेकी गिफारिश की गयी थी। इसके बाद तो १९५५ में सामूहिक करारके परिणामस्वरूप स्पेनको संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य भी बना लिया गया। स्वतंत्रता और लोकतंत्रके प्रेमियों को इस फैसले पर अफसोस हुआ।

(५) दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय बंजरोंके साथ व्यवहार. सन् १९४६ में आम सभाके पहले अधिवेशनमें ही भारतीय प्रतिनिधिने दक्षिणी अफ्रीका के एशियाई भूमि व्यवस्था और प्रतिनिधित्व कानून (१९४६) (Asiatic Land Tenure and Representation Act of 1946) की अपमानजनक प्रवृत्तियोंकी ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया। दक्षिणी अफ्रीका की सरकार द्वारा बठोरताके साथ बरती जाने वाली जातीय विभेदकी नीतिकी ओर भी सभाका ध्यान आकर्षित किया गया। यह बताया गया कि इन सब बातोंमें संयुक्त राष्ट्र संघके मानव-समानता और मानव-सम्मानके आदर्शका शिरस्कार होता है।

दक्षिण अफ्रीका की सरकारकी ओरसे कहा गया कि यह उसका घरेलू मसला है और घोषणापत्रकी धारा २, पैरा ७ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को इस विषय पर विचार करनेका अधिकार ही नहीं है। उसने यह भी माँगी कि इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयकी परामर्शमूलक सम्मति माँगी जाय। इस तर्कको अस्वीकार करते हुए आम सभाने यह फैसला दिया कि चूंकि हम प्रश्नमें संयुक्त राष्ट्र संघ के दो सदस्य राष्ट्रोंके वैश्वपूर्ण सम्बन्ध खराब होनेकी आशंका है, इसलिए संघको इस पर विचार करनेका अधिकार है। इस प्रस्तावका अर्थ भारत और दक्षिणी अफ्रीका ने भिन्न-भिन्न रूपसे किया। दक्षिणी अफ्रीका ने इस प्रस्ताव को पारस्परिक वार्ताका आधार माननेसे ही यह कहकर इन्कार कर दिया कि इस प्रस्तावको वार्ता का आधार बनानेका मतलब यह होया कि दक्षिणी अफ्रीका ने आम सभाके इस निर्णयको स्वीकार कर लिया कि उसने संघके घोषणापत्रका उल्लंघन किया है।

मसला फिर आम सभाके सामने लाया गया। सन् १९४९ में आम सभाके तीसरे अधिवेशनने भारत, पाकिस्तान और दक्षिणी अफ्रीका से कहा कि एक गोल्डमेज सम्मेलन करके संयुक्त राष्ट्र संघके घोषणापत्रके उद्देश्यों और मिद्धान्तों तथा मानव अधिकारोंकी विश्व व्यापी घोषणाको ध्यानमें रखने हुए तीनों राष्ट्र आपसमें विचार विमर्श करके इस मसलेको हल करें।

दक्षिणी अफ्रीका ने इस प्रस्तावको यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि इस से उसके आन्तरिक मामलोंमें हस्तक्षेप होता है। लम्बी वार्तिक बाद दक्षिणी अफ्रीका गोलमेज सम्मेलनके लिए राजी हो गया। पर आसमानसे टपका और खजूरमें अटका की वृत्तवृत्तके अनुसार गोलमेज सम्मेलनकी कार्यविलि पर तीनों राष्ट्रोंमें मतभेद बना रहा और सम्मेलन नहीं हुआ।

बादमें विशेषकर चीन युद्धकी स्थितिके कारण पश्चिमी राष्ट्रों ने इस प्रश्न में रुचि लेना बन्द कर दिया। विश्व साम्यवादके विरुद्ध अपने युद्धमें उन्हें दक्षिणी अफ्रीका के सहयोग और उसके भौतिक साधनोंकी आवश्यकता है। एंगिमार्ई अफ्रीकी राष्ट्रोंमें बढ़ती हुई उपनिवेशवाद विरोधी भावना ने भी इस प्रश्नमें पश्चिमी राष्ट्रों की अनिच्छा कम करनेमें योग दिया। स्थिति यहां तक उल्टी कि अन्तमें सन् १९४५ में आम सभा ने अपने उस पूर्व प्रस्तावको भी रद्द कर दिया जिसमें दक्षिणी अफ्रीका की आनीयनविभेद नीतिकी निन्दाकी गयी थी। इस प्रकार कुल मामला खटाई में पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सभ के इतिहासमें यह एक काला घन्टा माना जायगा।

(६) फ़िलिस्तीन (Palestine). ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन का मामला संयुक्त राष्ट्र सभके अग्रेल, सन् १९४७, के पहले विशेष अधिवेशनमें पेश किया। यह अधिवेशन इसीलिए बुलाया गया था। यहूदी समिति और अरब उच्च समितिके प्रतिनिधियोंको अपने-अपने विचार प्रकट करनेके लिए बुलाया गया। विचार-विमर्श के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सभ ने फ़िलिस्तीन के बारेमें एक समिति बनायी। इस समितिको यह काम सौंपा गया कि वह फ़िलिस्तीन तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रोंमें जाय, मौके पर जाकर असली हालतका पता लगाये और अपनी जाचके आधार पर सिफ़ारिशें पेश करे। यह समिति फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, और ट्रान्सजॉर्डन गयी। समितिने जर्मनी और ऑस्ट्रिया में विस्थापितोंके केंद्रोंका भी दौरा किया। समितिकी रिपोर्टमें बहुमतने एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्यकी स्थापना करने तथा यहूदगलम को अन्तर्राष्ट्रीय शासनमें रखनेकी सिफ़ारिश की। सीनों को एक आर्थिक इकाईमें रखनेकी भी सिफ़ारिश की गई। अल्पमत ने सिफ़ारिश की कि अरब राज्य और यहूदी राज्यका फ़िलिस्तीन सभ बनाया जाय और यहूदगलम इस सभ की राजधानी रहे। आम सभाने बहुमतकी योजना स्वीकार की। भारत ने अल्पमत की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे।

इसके बादमें हालत बिगड़ने लगी। ब्रिटेन ने घोषणाकी कि वह १५ मई, १९४८, को फ़िलिस्तीन परसे अपना नियोग समाप्त कर देगा यद्यपि आम सभाकी योजनाके अन्तर्गत उसे पहली अगस्त तक की अवधि दी गयी थी। यहूदी समिति तथा अरब उच्च समिति दोनों ने बड़े जोर-शोरमें अपने-अपने पक्षका समर्थन किया। अरब राष्ट्रोंने घोषणा की कि वे किसी प्रकार किसी भी रूपमें विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी ओर यहूदी समितिवा कहना था कि विभाजनमें ही समस्या हल हो सकती है। उनमें आने तक और अपनी भाषका आधार उन बांटोंको बनाया जा

बालफूर (Balfour) घोषणामें और राष्ट्र मंध के नियोगमें किये गये थे। योरोप के उन विस्थापित यहूदियोंकी इच्छाको भी मागना आधार बनाया गया जो और नहीं नरण नहीं पा सकते थे।

अरब लोगोंने विभाजन रोक्नेके लिए भीषी कार्रवाईवा रास्ता अपनाया। उग्र विचारके यहूदियोंने भी अपनी हिमात्मक कार्रवाई जारी रखी। मुग़्धा परिषद ने सम्बन्धित राष्ट्रोंमें बार-बार अपील की कि फिलिस्तीन में बंढने वाली अव्यवस्था और अशान्तिको रोक्नेके लिए वे हर सम्भव प्रयत्न करें। हमी प्रतिनिधोंने मुरक्षा परिषदमें कहा था कि विभाजन शान्तिपूर्ण तरीक़ेसे हो सकता है। अमेरिका ने इन पर सन्देह करते हुए मार्च, १९४८, में यह प्रस्ताव किया कि फिलिस्तीन को कुछ समय के लिए प्रन्त्याम परिषदके अधीन कर दिया जाय और इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आम सभाका एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाय।

आम सभाकी प्रार्थना पर मुरक्षा परिषदने दीवान्गमें घिरे यरूशलम शहरमें युद्धबन्दीका आदेश जारी किया और दोनों पक्षोंने उसे स्वीकार किया। आम सभा ने अन्तर्राष्ट्रीय नियोग (mandate) का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और एक मध्यस्थ नियुक्त करनेका निर्णय किया जिसका काम फिलिस्तीनकी स्थितिका शान्तिपूर्ण हल निबालनेमें सहायता देना था। काउन्ट बर्नाडेट (Count Bernadotte) मध्यस्थ चुने गये। जिस दिन फिलिस्तीन पर ब्रिटनका नियोग समाप्त हुआ उसी दिन 'इसराईल' (Israel) नामके एक यहूदी राष्ट्रकी घोषणा की गयी।

संधर्ष फिर शुरू हो गया। सीरिया, लेबनान, ट्रान्सजॉर्डन (अब जॉर्डन) और मिस्र ने इसराईल पर तेज़ हमले शुरू कर दिये। एक बार फिर मुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षोंसे युद्ध बन्द कर देनेको कहा। यह याद रखना चिन्ताप्रद है कि मयुक्त्त राष्ट्र सघ ने अरबों और यहूदियोंके धारेमें समय-समय पर जो प्रस्ताव स्वीकार किये वे उनमें से कुछमें यह धमकी भी दी गयी थी कि आवश्यकता पडने पर मयुक्त्त राष्ट्र सघ दक्षिणसे काम लेगा। ४ जून, १९४८ को अरबों और यहूदियोंमें युद्ध बन्दी करार तो हो गया, पर लड़ाई बन्द नहीं हुई।

मध्यस्थ स्वयं फिलिस्तीन गये और कुछ समयके लिए युद्ध बन्द करानेमें वे सफल हुए। उन्होंने मयुक्त्त राष्ट्र सघ से चौकसी रखने वाले एक फौजी दस्तेकी भाग की जो तुरन्त मज़ूर कर ली गयी। युद्धबन्दीकी निगरानीके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये। बर्नाडेट ने बड़ा परिश्रम करके फिलिस्तीन के बटवारेकी एक नई योजना तैयार की जो पहली योजनामें अधिक अरबोंके पक्षमें थी। पर मयुक्त्त राष्ट्र सघके सम्मुख इस योजनाको रख सननेके पहले ही १७ मितम्बर, १९४८, को यरूशलम के इसराईल अधिकृत क्षेत्रमें उनकी हत्या कर दी गयी। अनुमान किया जाता है कि यह हत्या किसी यहूदी गैर-सरकारी सैनिक ने की थी।

इसराईल ने विपरीत परिस्थितियोंके बावजूद सैनिक शक्तिके बल पर अपने पंर ज़माये और संयुक्त्त राष्ट्र सघके फिलिस्तीन आयोगने उसके लिए जो मिफारिज़ें

की थीं उनसे अधिक प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र मंत्र मन्त्रिवालयके मध्य अमेरिकी नीपो डा० राल्फ बुच (Dr. Ralph Bunche) इन्डिटे के स्थान पर अन्तिम रूप से समझौता करानेके लिए नियुक्त किये गये। अफिरांगमें उत्तरीके धर्म और कौशलके फलस्वरूप युद्ध विराम करार हुआ जिसमें एक ओर इमराईल और दूसरी ओर मिस्र, लेबनान और ट्रान्सजॉर्डन ने हस्ताक्षर किये।

इमराईल की स्थापनासे लेकर अब तकका सारा समय इमराईल के लिए अशान्ति-शान्तिका ही समय रहा है। अरब राष्ट्र इस बातके लिए कृत-मन्त्र्य हैं कि यदि सम्भव हो तो इमराईल को बुचलकर नष्ट कर दिया जाय। इन पक्षियोंके लिये जाननेके समय मिस्र और जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मरुदी अरब के साथ मिलकर युद्धकी तैयारी कर रहे हैं और ऐसा मालूम होना है कि पुनः लड़ाई छिड़ सकती है। मिस्र और सीरिया ने अपना एक मण बना लिया है। मणका उद्देश्य बनाना तो बर्तन है, पर उमका अनुमान लगाना बर्तन नहीं है। पश्चिमी राष्ट्र जो कभी एक पक्षकी तरफ़दारी करते हैं और कभी दूसरे पक्षकी इस पक्षोन्नेयमें हैं कि इस क्षेत्रमें ही सीमरा महायुद्ध न आरम्भ हो जाय। बग़दाद समझौता (Baghdad Pact), जिसमें इस क्षेत्रके कुछ राष्ट्र शामिल हैं, न केवल अरब लीगमें एक दरार पैदा कर रहा है, बल्कि विश्व शान्तिको भी वह कोई सहाय नहीं दे रहा है। सोवियत रूस अेकोम्बोबाकिया को मिस्रके हाथों हथियार बेचनेकी सलाह देकर इस अशान्त क्षेत्रमें अपना दाव लगा रहा है। फिलिप्पीनके विस्तारित अरबोकी समस्याका हल सभी दिखामी नहीं दे रहा है।

(७) कोरियाई प्रश्न. जापान, कोरिया पर मन् १९१० से शासन कर रहा था। मित्र राष्ट्रोंने वादा किया था कि युद्ध समाप्त होने पर कोरिया को स्वतंत्र कर दिया जायगा। जब युद्ध समाप्त हुआ उस समय उत्तरी कोरिया पर रूस का और दक्षिणी कोरिया पर अमेरिका का अधिकार था। जापानी सेनाओंके तात्कालिक आत्ममर्गणके लिए यह निर्देश किया गया कि ३८° अक्षांशके उत्तर जापानी सेनाएँ रुमिया के मामले और उमने दक्षिण अमेरिकियों के मामले आत्ममर्गण कर दें। यह ३८° अक्षांश बहुत शीघ्र एक निर्दिष्ट विभाजन रेखा बन गयी जिसने कोरिया को उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में बाट दिया।

अमेरिका चाहता था कि सयामम्भव शीघ्र कोरिया से प्रौखें वापस बुला ली जाय और कोरियाई लोगोंकी स्वयं अपना शासन करने दिया जाय। पर रूस के विचार विन्तुल भिन्न थे। रूस की इच्छा थी कि आम सभा १९४८ के आरम्भमें विदेशी सेनाओंकी एक साथ वापसीका आदेश दे और आम सभाने कोरिया के भविष्यके बारेमें जो समिति बनायी है उसकी पहली बैठकमें होने वाले विचार विमर्गमें भाग लेनेके लिए कोरियाई जनताके निर्वाचित प्रतिनिधि आमंत्रित किये जाय।

आम सभाने रूसी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। पूरे कोरिया में निर्वाचन

कराने और एक राष्ट्रीय असेम्बली व एक राष्ट्रीय सरकार कायम करनेके लिए उसने एक अस्थायी कोरिया-आयोगका निर्माण किया। भारत इस आयोगका सदस्य था। साम्यवादी गुटने सहयोग करनेमें इन्कार कर दिया, इसलिए यह आयोग उत्तरी कोरिया न जा सका। ऐसी अड़चनके बावजूद आयोग अपने काममें लगा रहा। उसने दक्षिणी कोरियामें चुनाव कराये और दक्षिणी कोरियाके लिए एक सरकार बनायी गयी जिसे बादमें संयुक्त राष्ट्र मध्यने मान्यता प्रदान की। दक्षिणी कोरियाको कोरियाई गणतन्त्र कहा जाता है। डा० सिंगमान री (Syngman Rhee) इस गणतन्त्रके प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे।

इसके बाद आम सहानुभूति विदेशी सेनाओंकी वापसीकी सिफारिश की। अमेरिका ने उसे स्वीकार कर लिया पर सोवियत रूस ने स्वीकार नहीं किया। अस्थायी आयोगके स्थान पर एक स्थायी कोरियाई आयोग नियुक्त किया गया जिसे कोरिया में एकता स्थापित करने और उत्तरी तथा दक्षिणी कोरियाके बीचकी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य साझा पाटनेका काम सौंपा गया। देशमें एकता काममें करने में दुर्भाग्यवश कोई प्रगति नहीं की जा सकी। इसका कारण कुछ तो साम्यवादियों और कुछ दक्षिणी कोरिया के मब निर्वाचित राष्ट्रपति डा० सिंगमान री की अड़चन-बाजी थी। उत्तरी और दक्षिणी कोरियामें जब सब सीमान्त सघर्ष होते रहे। अन्त में २५ जून, १९५०, को उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया। मौके पर उपस्थित संयुक्त राष्ट्र सभके कोरियाई आयोगने और अमेरिकी सरकार दोनोंने तुरन्त सुरक्षा परिषदको इसकी सूचना दी और परिषदका एक आपाती अधिवेशन बुलाया गया। परिषदने तात्कालिक युद्ध-बन्दीका आदेश दिया और फौजों का ३८^० अंशान पर वापस बुला लेनेकी कहा। सभके सदस्योंमें कहा गया कि वे उत्तरी कोरिया को सहायता न दें।

उत्तरी कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सभके प्रस्तावको अनुसृत कर दिया। इसलिए दो दिनोंके अन्दर ही अमेरिका ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा स्थापित करनेके लिए उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की मांग की गयी। रूसी प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद की बैठको में से अनुपस्थित रहे। इसलिए बिना किसी कठिनाईके प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावमें संयुक्त राष्ट्र सभके सदस्य राष्ट्रोंसे मांग की गयी कि सैनिक हमलेको पराजित करनेके लिए कोरियाई गणतन्त्रको जितनी सहायता की आवश्यकता हो उतनी सहायता दी जाय। पर युद्धका बोझ अमेरिका पर पड़ा। वह इसके लिए तैयार भी था।^१ युद्ध अधिकांश

^१ उत्तरी कोरियाके हमलोकी आसवासे अमेरिकी सेनाएं २३ जून को ही चल चुकी थी और उन्होंने पीले सागर के कोरियाई समुद्रतट पर २७ जून को ही घेरा डाल दिया था। अमेरिका के सातवें बेड़े ने फारमोसा द्वीप को २४ जून को ही अपने घेरे में ले लिया था।

में अमेरिकी घन, अमेरिकी युद्ध सञ्जा और अमेरिकी सैनिकों द्वारा लड़ा गया। भारत ने एक डाक्टरों उपचार दल भेजा था।

इस युद्ध को प्रायः संयुक्त राष्ट्र संघका युद्ध कहा जाता है। इस युद्धको सामूहिक सुरक्षाकी सफलताका एक सुन्दर उदाहरण माना जाता है। पर असलियत यह है कि यह युद्ध अमेरिकी युद्ध था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघका आशीर्वाद प्राप्त था। हमारे वर्तमान उद्देश्योंके लिए युद्धके विवरणमें जाना जरूरी नहीं है। अब संयुक्त राष्ट्र संघकी सेनाओंने संगठित होकर आक्रमण करना आरम्भ किया तब भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें समझाया कि वे ३८° अक्षांशके आगे न जायें। पर संयुक्त राष्ट्र संघके झण्डेके नीचे संयुक्त कमानके सेनापति जनरल मैक्आर्थर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वह युद्धको न केवल कोरिया को मंचूरिया से अलग करने वाली यांग्गु नदी तक ही ले जानेके लिए कृत-सबल थे, बल्कि मंचूरियाके भीतर भी—जिसे वह सैनिकोंका और सामर्थ्यका स्रोत मानते थे—घुस जाना चाहते थे। वह मंचूरिया को “प्रवेश निषिद्ध” क्षेत्र माननेके लिए तैयार नहीं थे।

अब तक चीनी साम्यवादी भी युद्धमें कूद पड़े थे क्योंकि उन्हें भय था कि स्वयं उनकी सुरक्षा ही खतरे में है। जैसे ही युद्ध आरम्भ हुआ राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सातवा जहाजी बेड़ा चीनी सागरमें डबलिंग भेज दिया था कि न तो चीनी साम्यवादी फारमोसा के राष्ट्रवादियों पर और न फारमोसा के राष्ट्रवादी चीनी साम्यवादियों पर हमला कर सकें। साम्यवादियोंने इस कामको अपने आन्तरिक मामलोंमें अनुचित हस्तक्षेप बह्कुर इसका बड़ा विरोध किया। युद्ध विचार धाराओंका युद्ध बन गया जिसमें एक ओर “साम्यवाद और एशियाई राष्ट्रीयतावाद” था और दूसरी ओर “पश्चिमी प्रजातन्त्र और उपनिवेशवाद” की शक्तिया थी। एशिया के राष्ट्र जो साम्यवाद और उपनिवेशवाद दोनोंके विरोधी थे, एक अजीब पक्षो-नेषमें पड़ गये।

ऐसी हालतमें भारत ने एक मध्यस्थ और शान्ति स्थापनाका काम करनेका प्रयत्न किया। अन्ततः उसके समझानेसे चीनी गणतन्त्रको समस्याका हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आमन्त्रित किया गया। पर चीनी प्रतिनिधि मण्डल आवश्यकतासे कुछ अधिक दृढ़ और अड़ जाने वाला था। उसने साऊ-माऊ अमेरिका को कोरिया और ताइवान (Formosa) में हमलावर ठहराया। अमेरिका ने ईंटका जवाब पत्थरसे दिया। उसने चीन को आक्रमणकारी ठहराने वाले अपने मन्त्रालयके दफ्तरमें स्थायी सदस्य कर लिये। इससे चीनका रव और भी बड़ा हो गया और समस्याका शान्तिपूर्ण हल करीब-करीब असम्भव हो गया।

एक साल तक लड़ते रहनेके बाद जब युद्धमें ही गत्यावरोध आ गया तब दोनों पक्ष मनुक्त राष्ट्र संघको एक समिति द्वारा तैयार किये गये युद्ध-विराम करारको माननेके लिए तैयार हो गये। भारत, केनडा और आम सभाके अध्यक्ष इस समितिके सदस्य थे। भारत, मिस्र, बर्मा, आदिने समझौता बार्ता द्वारा शान्तिके

पक्षमें जोर दिया। संपुक्त राष्ट्र संपर्क कुछ सदस्योंके लिए इन्हीं स्वीकार करता बठिन था। फिर भी ऐसा ही हुआ।

युद्ध-विराम चार्ता २५ अक्तूबर, १९४१, को संपुक्त राष्ट्र गणके तत्वावधान में पानमुनजीम में शुरू हुई और २७ जुलाई, १९४३, को कोरियाई-युद्ध-विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौतेके सम्मेलनमें सबसे बड़ी बाधा युद्ध बन्धियोंकी बदला-बदलीका प्रश्न था। साम्यवादियोंका कहना था कि युद्ध बन्धियोंको जबरन स्वदेश वापस भेज दिया जाना चाहिए। पर अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा था कि किसीको भी उसकी इच्छाके विरुद्ध उमके अपने देशमें या देशके किसी भी भागमें नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मौलिक मानव अधिकारका उल्लंघन होगा। भारत के प्रयाससे यह प्रश्न भी अन्तको हल हो गया। युद्ध विराम समझौतेकी शर्तोंको ठीक तरह पूरी करानेके लिए तटस्थ राष्ट्रोंका एक निरीक्षण आयोग और तटस्थ राष्ट्र बदला-बदली आयोग तथा इसी प्रकारकी अन्य सम्पाएँ कायम की गयीं। जनरल चिमैमा तथा भारतीय मरदाक सेनाने युद्ध बन्धियोंकी वापसीमें और समझौतेकी कायम रखनेमें अमूल्य योग दिया, यद्यपि डा० सिगमान री ने अनेक अड़चनें उनके रास्तेमें डालीं। डा० सिगमान री ने २५,००० उत्तरी कोरियाई युद्ध बन्धियोंको संपुक्त राष्ट्र गणकी अवहेलना करते हुए उस समय छोड़ दिया जब उनकी वापसीकी सम्मस्याका हल खोजा जा रहा था। कोरिया के युद्ध बन्धियोंकी वापसीके प्रश्नने अन्तर्राष्ट्रीय विधि और मौलिक अधिकारों को जो एक महत्वपूर्ण देन दी है, वह यह है कि कोई सरकार किसी व्यक्तिको अपने देश वापस जानेके लिए विवश नहीं कर सकती, भले ही वह व्यक्ति अपने देशकी तरफ से लड़ता रहा हो।

शान्ति समझौता हुए सात वर्षोंमें अधिक बीत चुके हैं पर अभी तक कोरिया एक राष्ट्र नहीं बन सका है। सिगमान री समय-समय पर फिरसे युद्ध आरम्भ करने की धमकी देते रहते थे, पर अमेरिका अक्रुश लगामे रहा है।

(८) काश्मीरका प्रश्न. यह प्रश्न संपुक्त राष्ट्र गणके सामने आने वाले सबसे कठिन प्रश्नोंमें से एक है और अभी तक सुलझ नहीं सका है। सन् १९४७ में भारत स्वाधीन हुआ। जम्मू और काश्मीर राज्यको तब पर एक भारतीय मरदाका शासन था, यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे भारत या चाहे पाकिस्तान में अन्तिम समझौता न होने तक एक ब्यास्थिति करारके आधार पर शामिल हो सकता है। १ जनवरी, १९४८, को भारत ने सुरक्षा परिषदकी सूचना दी कि पाकिस्तान की माठ-गाठसे सीमा प्रान्तके कवामली लोगो तथा अन्य लोगों द्वारा काश्मीर में दुरु विये गये भयानक युद्धने अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिको खतारा पैदा हो गया है। इसी समय काश्मीर के महाराजाने भारत में सम्मिलित होनेकी प्रार्थना की। भारत ने इस प्रार्थनाको स्वीकार कर लिया और आक्रमणकारियोंकी मार भगानेके लिए अपनी फौजें काश्मीर भेज दी यह तब हुआ कि सामान्य स्थिति स्थापित हो जाने पर जम्मू

और काश्मीर की जनता एक स्वतंत्र जनमत गणना द्वारा अपना भविष्य निश्चित करेगी।

भारत ने अभियोग लगाया कि पाकिस्तान आक्रमण करनेका अपराधी है, क्योंकि उसने आक्रमणकारियोंको सहायता दी है। उसने आक्रमणकारियोंको अपन हथियार और अपना पेट्रोल दिया है और पाकिस्तानी नागरिकोंने आक्रमणमें भाग लिया है। पाकिस्तान ने अभियोगसे इन्कार किया और यह दावा किया कि कबायली लोगोंका धावा रोकनेके लिए युद्धमें बम मव कुछ उसने किया है और घांपणा की कि जम्मू-काश्मीर राज्यका भारत में सम्मिलित होना अवैध है। भारत और पाकिस्तान दोनोंने स्वीकार किया कि उनके बीच हालत ऐसी है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भंग हो सकती है।

इस समस्याको हल करनेके लिए सुरक्षा परिषदने २० जनवरी, १९४८, को तीन मदस्योंका एक मध्यम्य आयोग बना दिया जिसमें दो सदस्य बादमें और बढ़ा दिये गये। परिषदकी कई एक बैठकों और भारतीय तथा पाकिस्तानी प्रतिनिधि मण्डलों के बीच अनेक गुप्त परामर्शोंके बाद परिषदने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें दोनों पक्षोंमें युद्ध बन्द करने और सही तथा निष्पक्ष जनमतगणनाके लिए मार्ग प्रशस्त करने को कहा गया। इन कामोंको पूरा करनेके लिए संयुक्त राष्ट्रके आयोग को आदेश दिया गया कि वह तुरन्त भारत पहुंचे और वहां भारतीय तथा पाकिस्तानी सरकारोंकी सहायताके लिए अपनी मध्यस्थता प्रस्तुत करे।

परिषदने यह भी सिफारिश की कि विदेशी कबायली लोग और काश्मीर में न रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक काश्मीरमें हटा लिये जायें और यथामन्भव अधिक से अधिक भारतीय सैनिक भी वापस बुला लिये जायें। भारत द्वारा स्थापित किये जाने वाले जनमतगणना प्रशासन द्वारा ऐसे बानावरणमें जनमतगणना करानेकी तैयारी करनेको कहा गया जिसमें अभिव्यक्ति की, समाचार और विचार प्रकाशन करनेकी, भाषण देनेकी, सभा करनेकी और यात्राकी पूरी-पूरी आजादी हो।

आयोगने अपना काम आरम्भ किया। उसने १३ अगस्त, १९४८, को दोनों सरकारोंसे कहा कि यथामन्भव शीघ्रातिशीघ्र युद्ध-बन्दी आदेश जारी किये जायें तथा कुछ मिद्दान्त स्वीकार किये जायें जिनके आधार पर दोनों देशोंमें समझौता हो सके। वे मिद्दान्त ये थे: (१) पाकिस्तान हाल ही में काश्मीर में तैनात की गयी अपनी फौजोंको वापस बुला ले और विदेशी कबायलियोंको तथा काश्मीर में मायारण-तथा न रहनेवाले पाकिस्तानी नागरिकोंको वापस बुलानेका भरमभ प्रयत्न करे, (२) इस प्रकार खाली किये गये क्षेत्रका शासन आयोगके निकट निरोक्षणमें स्थानीय अधिकारी करे, (३) जब आयोग भारतको इस बातकी सूचना दे कि पाकिस्तान इन बातोंका पालन कर रहा है तब भारत अपनी अभिवाय सेना धीरे-धीरे वापस बुला लेगा। भारतीय सेनाकी वापसीका क्रम भारत और आयोग आपसमें तय करेगा और (४) अन्तिम या म्यादी समझौतेकी शर्तें पूरी होने तक भारत युद्ध-बन्दीकी

सीमाके भीतर उतनी सेना रखेगा जितनी कानून और व्यवस्था बनाने रतनेमें स्थानीय अधिकारियोंकी सहायताके लिए आवश्यक हो।

पाकिस्तान ने आयोगको सूचित किया कि आयोगके प्रस्तावके कुछ अंशों को विरोधतः जनमतगणना संगठनसे सम्बन्धित अशोको वह ज्योंका त्यों बिना किसी शर्तके स्वीकार नहीं कर सक्ता। बाकी विलम्ब और लम्बी वार्ताके बाद इस बात पर समझौता हुआ कि एक संयुक्त राष्ट्र सघीय जनमतगणना व्यवस्थापक की नियुक्ति की जाय और युद्ध-बन्दी हो। १ जनवरी, १९४९, को युद्ध-बन्दी हुई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सघने विविध देशोंमें पर्यवेक्षक नियुक्त किये। इन पर्यवेक्षकोंको युद्ध-बन्दी समझौतेके पालनके बारेमें रिपोर्ट देनेका काम सौंपा गया।

अमेरिका की नौसेनाके एडमिरल डब्ल्यू० निमिट्ज को जनमतगणना प्रशासक मनोनीत करके जम्मू और काश्मीर की सरकारसे उन्हें रस्मी तौर पर नियुक्त करनेको कहा गया। जनमतगणनाके बारेमें भारत और पाकिस्तान के बीच तीव्र मतभेद होनेके कारण प्रणामक अपना काम न कर सका और उसने कुछ महीनों बाद अपने पक्षमें इस्तीफा दे दिया।

आयोगने अपनी रिपोर्टमें सुरक्षा परिषदमें कहा कि प्रभावपूर्ण मध्यस्थताका काम अब अधिक नहीं किया जा सकता। आयोगने यह भी सिफारिश की कि भारत और पाकिस्तान के सभी झगड़े दूर करनेके लिए पांच सदस्योंके आयोगके स्थान पर एक ही व्यक्ति नियुक्त किया जाय। परिषदने फौजोंकी वापसीकी एक योजना बनायी। इस योजनाकी पूर्तिमें सहायता करनेके लिए ऑस्ट्रेलिया के सर ओवेन डिकसन को संयुक्त राष्ट्र सघका प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। पर वह भी सफल न हो सके। विसंन्याकरण और जनमतगणनाकी तैयारीके सम्बन्धमें भारत और पाकिस्तान में मतभेद बना रहा। फिर भी डिकसन ने पाकिस्तान से यह बात स्वीकार करा ली कि काश्मीरका युद्ध पाकिस्तान सरकारकी सक्रिय सहायतासे आरम्भ हुआ था। उन्होंने काश्मीरके बटवारेका सुझाव दिया। इस सुझावके अनुसार पाकिस्तानी फौजों और आजाद काश्मीरी फौजों द्वारा अधिकृत प्रदेश पाकिस्तान को मिल जाता और भारतीय फौजों तथा जम्मू-काश्मीर राज्यकी फौजों द्वारा अधिकृत प्रदेश भारत में मिल जाता और जनमतगणना केवल काश्मीर-घाटी के सीमित क्षेत्रमें होती। पाकिस्तान ने इसे भी स्वीकार नहीं किया और डिकसन ने भी अपने पक्षसे इस्तीफा दे दिया।

इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सघने अमेरिका के डा० फ्रैंक ग्राहम को अपना प्रतिनिधि बनाया। वह एकसे अधिक बार काश्मीर, भारत और पाकिस्तान आये। उन्होंने फौजोंकी वापसी और काश्मीर में ईमानदारीके साथ जनमतगणना करानेके लिए भारतीय और पाकिस्तानी फौजोंकी आनुपातिक तैनातीके सम्बन्धमें बहुत परिश्रमके साथ काम किया। उनका अन्तिम सुझाव यह था कि ६,००० पाकिस्तानी और १८,००० भारतीय सैनिक काश्मीर में रहें। पर वह भी सफल न हो सके।

जिन बातों पर समझौता हो सके वे दोनों देशोंके यह निश्चय थे कि दोनों युद्धवा रास्ता नहीं अपनायेंगे, युद्धकी स्थिति जैसे भाषण या वक्तव्य नहीं देंगे, युद्ध-बन्दी समझौतेको भंग नहीं करेंगे; और काश्मीर के विलयका प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सभ के तत्वावधानमें आयोजित स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमतगणना द्वारा तय करेंगे।

इस झगड़ेके दौरानमें ही जम्मू-काश्मीर की सरकारने अपने संविधान परिषद के द्वारा भारत में मिलनेका संकल्प कर लिया। इस संकल्पको काश्मीर के वर्तमान प्रधान मंत्री बन्शी गुलाम मोहम्मद बई वार शोहरा चुके हैं। इसके विपरीत आजाद काश्मीर सरकार है जो पाकिस्तान के अधीन है।

जब सर ओवेन डिक्मन और डा० ग्रैहम दोनों ही असफल हो गये तब यह मुझाया गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों पारस्परिक सीधी बातसि अपना मतभेद दूर कर लें। एक बार यह भी मुझाया गया कि पंच-निर्णयवा रास्ता अपनाया जाय पर यह मुझाव भारत को स्वीकार नहीं हुआ। फलतः गत्यावरोपकी स्थिति है। काश्मीर के बारेमें बड़े राष्ट्रोंकी स्वायंपूर्ण रुचि मामलेको और भी बिगाडनी है। इस क्षेत्रमें अमेरिका और ब्रिटेन सैनिक और सामयिक कारणोंसे बहुत अधिक रुचि लेते रहे हैं। यह हालत रुम की भी है। अपनी भारतीय यात्राके दौरानमें बुल्गारिन और रूडोल्फ ने घोषणा की थी कि वे भारत में काश्मीर के विलयको अन्तिम और अधिकृत मानते हैं। पश्चिमी राष्ट्रों (अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रान्स) ने तथा पाकिस्तान और सीटोंके अन्य सदस्योंने अपनी कराची की बैठकमें इसके उत्तरमें यह कहा कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र सभके निरीक्षणमें जनमतगणना द्वारा हल होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सभने १९५७ के आरम्भमें मुरसा परिषदके तत्कालीन अध्यक्ष जारिंग को भारत और पाकिस्तान भेजा। उनमें कहा गया कि वे काश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सभके पहले प्रस्तावके अनुसार अपने मुझाव दें। दोनों प्रधान मंत्रियोंने रुम्बी बार्नार्के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। आपने अपनी रिपोर्टमें कहा कि जनमतगणनाके आश्वासनके समयमें अब तक बहुत-सी बातें हो चुकी हैं, वर्तमान परिस्थितियोंमें जनमतगणनासे बहुत-से बिम्न पैदा हो सकते हैं और दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की शक्ति मन्तुलनवा क्रिममें १९४८के बादमें काफी परिवर्तन हो गया है, काश्मीरी प्रश्न पर काफी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जारिंग ने गत्यावरोपको पंच निर्णयसे दूर करनेका मुझाव दिया। भारत का कहना था कि पंचायत करानेके मतलब है यह मान लेना कि पाकिस्तान का काश्मीर पर भारत के समान ही दावा है। भारत पाकिस्तान के इस दावेको स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान काश्मीर में आक्रमणकारी है, न उममें कुछ कम और न कुछ अधिक।

हालके पिछले महीनोंमें भारत का कहना यह रहा है कि काश्मीर के भारत में मिल जानेमें और काश्मीर संविधान सभाके प्रस्तावके कारण क्रिमकी पृष्टि बाद के घुनावोंमें भी दुर्द्ध है, काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत बार-बार कह

घुना है कि यह जनमतगणनाको उम समय तक कार्यान्वित करनेको राजी नहीं है जब तक पाकिस्तान काश्मीर के उत हिस्सेमें हट नहीं जाता जिस पर उसने जवर्दस्ती अधिभार कर रखा है। धी० के० कृष्णमेनन ने संयुक्त राष्ट्र सभमें और भारत में इन विचारों पर जनमत तैयार करनेमें बहुत बड़ा और किया है। इस सबके बावजूद गत्यावरोधको दूर करनेके उपाय बनलानेके लिए फ्रैंक ग्राहम सुरक्षा परिषद द्वारा भेजे गये।

२. अन्य राजनीतिक तथा सुरक्षा-सम्बन्धी प्रश्न (Other Political and Security Issues)

स्थानाभावके कारण हम अन्य उन प्रश्नोंका सारासामें ही उल्लेख करेंगे जिनमें संयुक्त राष्ट्र सभको पूरी या सीमित मफलता मिल पायी है। इन प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण हैं और कुछ साधारण।

(१) यूनान (Greek) का प्रश्न. यूनान ने संयुक्त राष्ट्र सभ से शिकायत की कि अल्बानिया, बल्गेरिया और यूगोस्लाविया द्वारा उसकी सीमाओं पर साम्यवादी दबाव डाला जा रहा है। इसके विरोधीके बावजूद आम सभाने भारी बहुमतमें यूनान की सीमाओं पर एक "सतर्क निरीक्षक आयोग" ("watch dog" commission) नियुक्त करके बाल्कन प्रदेशमें शान्ति स्थापित करनेके लिए बंदम उठाया। इस कार्यमें सफलता मिली। यह कार्य संयुक्त राष्ट्र सभ के इस सफलताका द्योतक है कि छोटे राष्ट्रोंके अखण्डताकी रक्षा की जायगी।

(२) बर्लिनका प्रश्न. सन् १९४८ में सोवियत रूस ने पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के अधिवृत्त प्रदेश और बर्लिन शहरके बीच परिवहन और संचारके साधनों पर कुछ भन-मानी रोकें लगा दी। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सभ से अपील की। कुछ समयके लिए स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी और ऐसा लगा कि युद्ध शुरू हो जायगा। पर पश्चिमी राष्ट्रोंने अपना धैर्य बनाये रखा और एक सुमगठित हवाई यातायात द्वारा रूसी नाकेबंदीको विफल कर दिया। जब रूस ने देखा कि वह सफल नहीं हो, मफता तब उसने अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रोंसे संयुक्त राष्ट्र सभा भवनके गलियारेमें ही गैर-रस्मी तरीकेसे समझौता कर लिया।

(३) कॉर्फे चैनल का प्रश्न. सन् १९४७ में ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद से शिकायत की कि अल्बानिया द्वारा अपने समुद्रमें बिछाई गयी सुरणने अंग्रेजी युद्ध पोतोंको नुकसान पहुंचाया है और अंग्रेज नाविकों को घायल कर दिया है इसलिए अल्बानिया को हरजाना देना चाहिए। अल्बानिया ने इसका उत्तर यह दिया कि ब्रिटेन उनके क्षेत्रीय सागरकी सीमाका उल्लंघन करके उनकी सम्प्रभुता-भंग कर रहा है। अन्तमें मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयमें भेजा गया जिसने फैसला दिया कि अल्बानिया को हर्जाना देना चाहिए।

(४) हिन्द-चीन का युद्ध- दुर्लभ तो यह फ़ामीसी साम्राज्यवादी शासनके विरुद्ध हिन्द-चीन की जनताका विद्रोह था। बादमें यह पश्चिमी देशों और उपनिवेश-वादके विरुद्ध राष्ट्रीयतावाद और साम्यवादके गठबन्धनमें परिणत हो गया। आठ वर्ष तक युद्ध होता रहा और फ़ामकी गहरी हानि हुई। फ़ास ने हिन्द-चीन को विभाजित करके अपना शासन बनाये रखनेके लिए अनेक रास्ते अपनाये पर उसे सफलता नहीं मिली। बादमें अमेरिका ने फ़ाम को वाक़ी सैनिक और आर्थिक सहायता दी और चीन के साम्यवादियोंने उत्तरी वियतनाम को मदद पहुँचाई। जब गत्यावरोध की स्थिति उत्पन्न होगयी और दोनों पक्ष समझौतेके लिए उत्सुक हो गये तब १९५४ में जेनेवा में कुछ बड़े राष्ट्रों (ब्रिटेन, फ़ाम और चीन) की बैठक हुई और भारत ने सहायकता हिनकर कायं किया। इस सम्मेलनके परिणामस्वरूप हिन्द-चीनमें अपेक्षाकृत शांति स्थापित हो गयी, यद्यपि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में ज़िम निर्वाचनका वादा किया गया था वह दक्षिणी वियतनाम के प्रधान मंत्री की अड़गेबाजी के कारण पूरा नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्रके सम्मुख आनेवाले अन्य रोषक मसले निम्नलिखित हैं :

- (१) हैदराबादका सवाल,
- (२) इटलीके उपनिवेशोंकी भावी स्थिति,
- (३) विदेशी नागरिकोंकी सन्धी पत्तियोंका प्रश्न,
- (४) द्यूनिमका सवाल,
- (५) मोरक्कोका प्रश्न,
- (६) ब्रिटेन और ईरानके बीच तेलकी समस्या,
- (७) ड्रॉमेटके स्वतन्त्र-प्रदेशका प्रश्न।

इन प्रश्नों और ऐसे अन्य प्रश्नोंके विवरणके लिए पाठकोंको संयुक्त राष्ट्र सभके प्रकाशन "एवरी मैन्यूयूनाइटेड नेशन्स" (पृष्ठ ३९-१६५) को पढ़ना चाहिए।

३. राजनीतिक गत्यावरोध (Political Impasses)

संयुक्त राष्ट्र सभके सम्मुख अनेक मसलोंमें गत्यावरोध पैदा हो गया है। उचित साधनों की कमी, इस गत्यावरोधका इतना कारण नहीं है जितना राष्ट्रों द्वारा अपनी-अपनी सम्प्रभुता पर अड़ने और निहिन स्वायत्ती द्वारा अपना प्रभुत्व जमाये रखनेकी पुरानी समझौता है। स्वतन्त्र की कमीके कारण यहाँ भी हम इन प्रश्नोंकी सूची मात्र दे सकेंगे। जिन मामलोंमें संयुक्त राष्ट्र सभने अपनेको बरनाम किया है, वे ये हैं :

- (१) संयुक्त राष्ट्र सभमें राष्ट्रीयतावादी चीन का बराबर बने रहना और साम्यवादी चीन को सभने बाहर रखना।
- (२) दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयोंके साथ दुश्मन्वहार।
- (३) दक्षिणी अफ्रीका की जातीय-विभेदकी नीति।

(४) दक्षिणी अफ्रीका द्वारा दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका का वस्तुतः अपनेमें मिला लिया जाना।

(५) आण्विक अस्त्रोंके प्रयोगात्मक विस्फोटों पर रोक लगानेमें असफलता।

(६) निरुपस्थीकरण (पुरानी चालके और नये आण्विक आदि, दोनों)।

बीटो पर रोक लगाने और मंयुक्ता राष्ट्र मण में नये सदस्योंके प्रवेशके सम्मान-पूर्ण दायी गमस्पावा भी कोई तात्कालिक हल नही दियायी देता।

४. आर्थिक-क्षेत्रमें संयुक्त राष्ट्र संघकी सफलताएँ

(Accomplishments of the U.N. in the Economic Field)

चौर राजनीतिक क्षेत्रमें संयुक्त राष्ट्र संघका काम एक उत्साहवर्धक कहानी जैसा मालूम होता है। सगठन, अध्ययन, रिपोर्टें, मोट्टी, सम्मेलन, समन्वय, सूचनाओं और कर्मचारियोंकी अदला-बदली, कर्मचारियोंके प्रशिक्षण और ऐसे ही अन्य साधनों से संघने अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओंको मुलभूतानेमें सहायता दी है। विश्वके जन, धन और ज्ञान सम्बन्धी साधनोंके समुच्चय (pooling together) का यह एक महान् प्रयोग है।

आर्थिक आयोग (Economic Commission)

जून, १९४६, में आर्थिक और सामाजिक परिषदने क्षति-ग्रस्त क्षेत्रोंके आर्थिक पुनर्निर्माणके लिए एक अस्थायी उप-आयोगकी स्थापना की जिसकी बैठक लन्दन में २९ जुलाई १३ मितम्बर, १९४६, तक हुई। इसी वर्ष बादमें इस उप-आयोगने परिषदके सामने अपनी रिपोर्टें पेश की जिनमें जन-शक्ति, साधन, कृषि, ईंधन और विद्युत् शक्ति, प्रधान उद्योग व्यवसाय, आवाम, माताम्यात, अर्थ व मुद्रा और व्यापार सम्बन्धी दीर्घ-कालीन और अन्य-कालीन समस्याओंका विवेचन किया गया था। उसने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगके लिए सुझाव भी दिये जिनमे योरोप के लिए एक आर्थिक आयोग बनाये जानेवा सुझाव भी था। इस अस्थायी आयोग और उसके अन्तर्गत काम करनेवाले दलोंकी रिपोर्टोंके फलस्वरूप एशिया और सुदूर-पूर्वके क्षति-ग्रस्त क्षेत्रोंके अध्ययनके लिए आयोग स्थापित किये गये। अफ्रीकाके लिए भी एक आयोग बननेका था पर यह बन न पाया। आम सभाकी सिफारिश पर आर्थिक और सामाजिक परिषदने ये संस्थाएँ बनायीं : योरोप के लिए आर्थिक आयोग एशिया और सुदूर पूर्वके लिए आर्थिक आयोग और बादमें लेटिन अमेरिका के लिए आर्थिक आयोग। परिषद ने ७ मार्च, १९४८, को मध्यपूर्वके लिए एक आर्थिक आयोग स्थापित करनेकी समस्या का अध्ययन करनेके लिए एक तदर्थ (ad hoc) समिति नियुक्त की।

इन तीनों आयोगों में से प्रत्येकने विशिष्ट अध्ययन किये और सम्बन्धित देशों को बहुमूल्य सुझाव दिये। योरोप में इसके फलस्वरूप सहयोगात्मक व्यवस्थाओं के आधार पर अधिक उत्पादन सम्भव हुआ है। उदाहरण के लिए इस्पातका उत्पादन १५ लाख टन अधिक हुआ है। आयोग सदस्य राष्ट्रों के बीच कच्चे मालका विभाजन करता है जिनमें कोयला, लकड़ी और कच्चे खनिज प्रमुख हैं। योरोप के जो राष्ट्र मनुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वे भी इस संस्था के सलाहकार बन सकते हैं। इस सहयोग मूलक प्रयत्नों के कुछ उदाहरण ये हैं : अंग्रेजों ने अपनी कुछ बौद्धिक संपत्ति मोटर गाड़िया जर्मनी के फ्राम अविश्रुत प्रदेशों के लिए दी, इटली से कुतल मजदूर लाये गये, जर्मनी के अमेरिकी-क्षेत्र से स्टीम बेलचे (शॉवेल) व ब्रुलडोंगर मशीनें भेजी गयीं। अमेरिका ने टेक्नोशियन भी दिये। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में मिले ऋणने योरोप के बहुत बड़े भागकी आर्थिक स्थिति समालोचने में मदद की है।

एशिया और सुदूर-पूर्व के आर्थिक आयोगका प्रधान कार्यालय बैंकॉक में है। संयुक्त राष्ट्र संघकी अन्य समस्याओंकी भांति इस आयोगको भी अपनी इच्छा लागू करनेका वैश्विक अधिकार प्राप्त नहीं है। आर्थिक और सामाजिक परिपक्वता के सामान्य निरीक्षण में यह आयोग जो भी निर्णय करता है उन्हें सम्बन्धित देशोंकी स्वीकृतिमे ही कार्यान्वित किया जा सकता है। क्षेत्र विशेष के देशोंको आयोग एकत्र करता है ताकि वे उस क्षेत्र से सम्बन्धित सामान्य प्रश्नों पर विचार विमर्श कर सकें। ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। यह एक ऐसा मंच है जहाँ एकत्र होकर क्षेत्र विशेषकी सरकारें सामूहिक रूपसे अपनी सामान्य आर्थिक समस्याओं पर विचार करती हैं। इसके निश्चित विशिष्ट कार्य ये हैं :

(१) सामूहिक सुसंगठित कार्योंकी शुरुआत करना और उनमें भाग लेना।

(२) आर्थिक और प्राविधिक (technological) समस्याओं तथा विकास कार्योंकी जांच पड़ताल और अध्ययन करना या करवाना।

(३) आर्थिक, प्राविधिक और सांख्यिक सूचनाओंके संचय, मूल्यांकन और वितरणका कार्य करना या करवाना।

आयोगका कार्य निम्नलिखित विभागोंमें होता है : कृषि, औद्योगिक विकास प्राविधिक प्रशिक्षण और महायाना, व्यापारकी उन्नति, श्रम नियंत्रण और शोध।

लेटिन अमेरिका के लिए बने आर्थिक आयोगके कार्य-कलाप भी दोनो आयोगोंके कार्योंके समान ही हैं। यह आयोग उस क्षेत्रके विभिन्न राष्ट्रोंके आर्थिक माधनोंके बीच सहयोग और समन्वय कायम करनेमें लगा हुआ है।

आर्थिक और रोजगार आयोग समस्तकी आर्थिक स्थिति और गति पर अपनी नियमित रिपोर्ट दिया करता है। मुदा आयोग संयुक्त राष्ट्र संघकी विभिन्न समस्याओं को, प्रारंभिक विवेचने पर प्राविधिक परामर्श, सूचना और महायाना दिया करता है। इस विषय पर दो अन्य प्रकाशित हो चुके हैं।

सांख्यिक आयोग (Statistical Commission), जैसा कि इसके नामसे ही प्रकट है, सांख्यिक सूचनाएँ सफट करता है। परिवहन (transport) और संचार (communications) आयोगका काम दूर-संचार (tele-communications), डाक, हवाई, जल और स्थल परिवहन आदिमें सम्बन्धित है।

पुनर्निर्माण और विकासके लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (The International Bank for reconstruction and Development)

इस बैंककी अधिकृत पूँजी एक करोड़ अमेरिकी डालर है। यह पूँजी एक-एक लाख डालरके हिस्सोंमें बटी है। इन हिस्सोंको केवल सदस्य ही खरीद सकते हैं और वे केवल बैंकको ही हस्तान्तरित किये जा सकते हैं। १५ फरवरी, १९५४, को ५५ सदस्य राष्ट्रों द्वारा जमा की गयी पूँजी स्वर्ण, अमेरिकी डालरों और विभिन्न सदस्य राष्ट्रोंकी मुद्राओंमें २०,३८,५०० डालर यानी अधिकृत पूँजीकी २० प्रतिशत थी।

सदस्य राष्ट्रोंकी विकास योजनाओं और कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करनेके लिए अथवा जिन योजनाओंके लिए ऋणकी मांग की गयी है उनके लिए आर्थिक सहायताकी सम्भावना आदिके सम्बन्धमें बैंक अपने सदस्य राष्ट्रोंके साथ बराबर लिखा पढ़ी करता रहता है। सदस्य राष्ट्रोंको प्राविधिक परामर्श देने, दीर्घकालीन विकास योजनाएँ बनानेमें सहायता देने अथवा ऋणके उपयोगके सम्बन्धमें बैंकके प्रतिनिधि सदस्य देशोंका दौरा किया करते हैं।

बैंक अपने कर्जों पर निगरानी भी यह देखनेके लिए रखता है कि जिन प्रसाधन सज्जा (equipment), सामान और वस्तुओंके लिए सदस्य राष्ट्रोंको पैसा दिया जाता है उनका उपयोग उन्हीं कामोंमें ही होता है जिनके लिए वह दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक निम्नलिखित पाँच सिद्धान्तोंके आधार पर यह निश्चय करता है कि कर्ज दिया जाय या नहीं।

(१) यदि ऋण देने वाला किसी अन्य सूत्रसे उचित शर्तों पर ऋण पा सकता है तो बैंक ऋण नहीं देगा, जिस योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए ऋण मांगा जा रहा है वह चाहे जितनी उपयोगी क्यों न हो।

(२) दूसरा सिद्धान्त यह है कि साधारणतया बैंक किसी देशकी उसकी योजना से सम्बन्धित विदेशी सामान और सेवा प्राप्त करनेके लिए आवश्यक विदेशी रकमका ही ऋण देगा।

(३) तीसरा सिद्धान्त यह कि ऋण तभी दिया जाता है जब ऋण लेनेवाला और उसका जामिन मूलधन और व्याज अदा कर सके।

(४) चौथा सिद्धान्त यह है कि बैंक सबसे अधिक उपयोगी और आवश्यक योजनाओंको ही बरीयता (preference) देगा।

(५) पाबंदी शर्त यह है कि कर्ज लेनेवालेमें इतना ज्ञान, कौशल और आर्थिक साधन हों कि वह योजनाको सफल बना सके।

बैंकके कोषका उपयोग करनेवाली भारतकी प्रधान योजनाओंमें से एक दामोदर घाटी योजना है। सन् १९५२ में दूसरा कर्ज इण्डियन आवरन एण्ड स्टील कम्पनीको अपनी फैक्ट्रिया और यानों बढ़ानेके लिए दिया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund). "एवरी मेंम यूनाइटेड नेशंस" नामक ग्रन्थके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोषके उद्देश्य प्रानतः निम्नलिखित हैं:

आर्थिक नीतिके प्रधान उद्देश्यको निश्चित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके विस्तार और मन्तुलित विकासकी सुविधा प्रस्तुत करना और इसके द्वारा रोजगार और वास्तविक आयका स्तर ऊंचा करना और उसे कायम रखना तथा सभी सदस्योंके उत्पादक साधनोंकी उन्नतिमें सहायता देना,

मुद्रा विनिमयकी स्थिरताको बढ़ावा देना, सदस्योंके बीच व्यवस्थित विनिमयका प्रबन्ध करना और प्रतियोगिता मूलक विनिमय-मूल्यावरोह को बचाना या रोकना,

उपयुक्त सरक्षणोंके अन्तर्गत सदस्योंके लिए कोषके साधन मुलम बनाकर उनमें विश्वास उत्पन्न करना।

पिछड़े या अर्थविकसित देशोंके आर्थिक विकासके लिए प्राविधिक सहायता (Technical Assistance for the Economic Development of underdeveloped Countries). यह सहायता संयुक्त राष्ट्र मध्य और उसकी संस्थाओं द्वारा दी जाती है। यह योजना १९४९ में बनायी गयी थी। इस योजनाके अन्तर्गत आत्म-सम्मान सोये बिना और राजनीतिक हस्तक्षेपके भयमें मुक्त सहायता प्राप्त की जा सकती है। रकम खर्च करनेके पहले प्राविधिक ज्ञानकी कमी पूरी करना आवश्यक होता है।

प्राविधिक सहायता केवल सलाह, प्रशिक्षण, विधि-प्रदर्शन और कौशल इकट्ठा कर देनेके काममें होती है (Technical assistance is simply advice, training, demonstration, and the pooling of 'know how')। बर्मा ने अपने साधनोंका पता लगाने और उनका समुचित विस्तार करनेके लिए संयुक्त राष्ट्र मध्यमें एक सांख्यिक (statistician) की सहायता मांगी थी। मैक्सिको ने अपने कोदलेके अधिक उत्तम उपयोगके सम्बन्धमें परामर्श देनेके लिए तीन विशेषज्ञोंकी सहायता मांगी थी। ईरानने राजस्व, चुगी, आयात-निर्यात-कर, और मण्डनके सम्बन्धमें सहायताकी प्रार्थना की थी। स्पाम ने जल साधनोंके विकास और नियंत्रणके लिए राद्य और कृषि समझौते सहायता मांगी थी। औद्योगिक मजदूरोंके स्वास्थ्य और

* इस विभागकी मामची 'इष्टरनेशनल बामिहितेशन' जनवरी, १९५०, नं० ४५७ में ली गयी है।

निरोधनका सर्वोत्तम प्रबन्ध कैसे किया जाय—इसका अध्ययन करनेके लिए मित्र ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनसे सहायता मांगी थी। एवियोपिया ने मफाई निरोधकों और अस्पतालकी कर्मचारियोंका प्रतिक्षण आरम्भ करनेके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनसे सहायता मांगी थी। भारत ने क्षेपिक निरोधक बी० सी० जी० के टीके लगानेके विधिके प्रदर्शनकी प्रार्थना की थी।

सहायता निम्नलिखित रूपोंमें दी जानी है—विदेशोंमें अध्ययनके लिए छात्र-वृत्तिपा, शोषितपा, विशिष्ट सहायताएं—जैसे इन्वेडरमें आये भूकम्पमें पीड़ितोंकी, विशिष्ट समस्याओंका अध्ययन, जैसे लेटिन अमेरिका में भूकम्पसे घबस्त एक नगर की समस्याओंका, और साधारण ज्ञानकी बातोंका प्रचार। कुछ सामाजिक द्रव्यों और स्त्रे-मशीनोंकी सहायता पा जानेसे यूनान मलेरियाके मच्छरोंसे मुक्ति पा गया। भारत भी इस दिशामें बड़ रहा है, पर दुर्भाग्यसे नहीं।

पष-प्रदर्शन योजनाओंकी व्यवस्था करके तथा प्रदर्शन दस्तों और विशेषज्ञों को भेज कर लोगोंके जीवन स्तरको ऊँचा उठानेमें भी सहायता दी जानी है। उन्नति-शील और अल्प-विकसित दोनों प्रकारके राष्ट्रोंको गवेषणा कार्य और विचारोंके विनिमयसे लाभ होता है। उदाहरणके लिए, चीनके कुछ फलों और तरकारियोंके बीज अमेरिकी बीजोंसे अच्छे पाये गये और तुरन्त उनकी माग अमेरिका में बड़ गयी। अब यह अनुभव किया जाता है कि अल्पविकसित क्षेत्रोंमें उत्पादन बढ़नेसे लोगोंकी क्रय-शक्ति बड़ जाती है और फलतः औद्योगिक और उन्नत कोटिकी वस्तुओंकी अधिक माग होने लगती है। इससे नये बाजार उपलब्ध हो जाने हैं।

सर्वोत्तम राष्ट्र सघकी प्राविधिक सहायता योजनाका प्रशासन और कार्यान्वयन दैनिक कार्योंके लिए जिम्मेदार, एक प्राविधिक सहायता बोर्ड द्वारा, और एक प्राविधिक सहायता समितिके द्वारा होता है। समिति आर्थिक और सामाजिक परिपदकी ओरसे निरोधनका काम करती है।

यह सिद्ध करनेके लिए किसी तर्ककी जरूरत नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहायता में मिलनेवाले प्राविधिक सहायता हर हालतमें किसी एक देशसे मिलनेवाली सहायता से बड़ी अच्छी है। (१) इसमें सशयसे अपेक्षाकृत मुक्ति रहती है। (२) अनेक राष्ट्र अपने अनुभवको एक साथ संचित और समग्रित कर सकते हैं, और इस बातकी लाभदायक अनुभूति प्राप्त करते हैं कि किसी भी देशको प्राविधिक ज्ञान पर एकाधिकार नहीं प्राप्त है। (३) कोई-कोई समस्या ऐसी होती है कि उसके सम्बन्धमें अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई आवश्यक हो जानी है। हंजा और चेचक जैसी महामारियाँ, या टिड्डी जैसी आपदाएं भौगोलिक सीमाओंको नहीं मानती। मयुक्त राष्ट्र सघने योजनाओंके सम्बन्ध और मिलकर काम करनेकी आवश्यकता और महत्त्वकी अच्छी तरह साबित कर दिया है।

साथ और कृषि-संगठन (Food and Agriculture Organisation). यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रमें मयुक्त राष्ट्र सघके सबसे उत्तम संगठनोंमें से एक

हैं। अपने जीवनके प्रारम्भिक वर्षोंमें इसने साक्षात्कारी कभी और अकालोति उत्पन्न होनेवाली समस्याओं पर ध्यान दिया। अब यह कुछ दीर्घकालीन योजनाओं पर भी ध्यान देनेमें समर्थ हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघके कई एक संगठनोंने हिमालयकी तलहटीमें तराई क्षेत्रको कृषि योग्य बनानेमें सहायता दी है। इस क्षेत्रमें मलेरियाका जोर था और इसमें दल-दल बहुत थी, यद्यपि किसी समय इसमें अच्छी खासी खेती-बारी होती थी। सन् १९४९ में संयुक्त राष्ट्र मंत्र और भारतके विदेशों द्वारा यहां मलेरियाके मच्छरोंके विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया। जब यह युद्ध जीत लिया गया तब साक्ष और कृषि संगठनने यहां आधुनिक कृषिके एक मुनियोजित विकासमें भारत सरकारका माय दिया। एक कृषि इंजीनियर, एक ट्रैक्टर चलाने वाला, एक कृषि मशीनरी विनियम, एक वनस्पति-शास्त्रज्ञ ज्ञाना और विभिन्न देशोंसे आये ऐसे ही अन्य विदेशी तराईकी स्थापना करनेमें जुट गये।

हिन्देशियाका भस्म (मछली) उत्पादन एक दूसरा क्षेत्र है जिसमें साक्ष तथा कृषि संगठनने अच्छा काम किया है। हिन्देशियामें धानकी फसलें साध-साध छोटी मछलिया भी पैदा की जाती हैं। दोनों फसलें एक साथ तैयार होती हैं। मछलिया छोटे मच्छरोंको खाती हैं और जमीनको उपजाऊ भी बनाती हैं। मछलियोंमें किसानों को अनिखन भोजन मिल जाता है और आमदनी भी हो जाती है। साक्ष तथा कृषि संगठनके विदेशोंकी सहायतासे हिन्देशियाके अनुभव हैटी (Haiti) आदि अन्य देशोंके लिए मूल्य बनाये गये। इसराईल भी इसका प्रयोग करनेकी कोशिश कर रहा है। जब पाइलैण्डके किसानों ने संतोंको भूमिनेम वचानेके लिए अपनी धानकी फसलरा बलिदान करना शुरू किया—तीन महीनेमें धानकी फसल तैयार हो जाती है—तब साक्ष तथा कृषि संगठनके विदेशोंने एक तरीका निकाला जिसमें धान भी नष्ट न हो और मछलिया भी न मरे। यह तरीका था किसानोंको ऐसे गटे गोदनेके लिए प्रोत्साहित करना जिनमें मछलिया खेतोंमें फिर पानी भरने के समय तब सुरक्षित रह सके।

भारत सरकारने साक्ष तथा कृषि संगठनके तन्त्रावधानमें एक बाजार गोपशाला खोली है। इस शालाके कार्यमें एशियाके अन्य देश देश भी साझेदार हैं।

साक्ष तथा कृषि संगठन "रिण्डर पेस्ट" नामक पशुओंकी एक बीमारीने भी मोर्चा ले रहा है। इस बीमारीने निजट और मुद्गर पूर्वके देशोंमें हर साल लाखों पशु मरने हैं।

यूनान, ग्रेटब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और थाइलैण्ड में पोषक-आहार-सम्बन्धी कार्योंमें समन्वय स्थापित किया गया है।

साक्ष तथा कृषि संगठनके द्वारा योरोपीय इमारती लकड़ीकी पूर्ति (supply) में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस सम्बन्धमें लैटिन अमेरिकी देशोंको अपने राष्ट्रीय माधनके विकासकी योजना बनानेमें भी सहायता दे दी है।

खाद्य तथा कृषि संगठन इस प्रकार प्राविधिक सहायताकी कई योजनाएँ पूरी कर चुका है। इन योजनाओंका लक्ष्य अल्पविविध क्षेत्रोंके उत्पादन-कोशलकी उप्रति करना है। इस कामका अधिकांश सयुक्त राष्ट्र सघकी संवर्धित (expanded) प्राविधिक सहायता योजनाके अन्तर्गत किया जाता है।

जमींदारीकी समस्याका खाद्य तथा कृषि संगठनने विशेष अध्ययन किया है। इस संगठनने जापानमें किये गये प्रयोगोंके छात्रोंको अन्य देशोंके लिए मुलभूत बना दिया है। जापानमें वस्त्राधिकारियों (occupation authorities) ने ५० लाख एकड़ जमीन जमींदारोंके स्वरीय लेनेका आदेश दिया। फिर यह जमीन किसानोंको उचित मूल्य पर बेच दी गयी। किसानोंको जमीनकी कीमत किसानोंमें तीन बर्षोंमें चुकानी पड़ेगी और केवल ३.२ प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा।

खाद्य तथा कृषि संगठनने मई १९४६ में पहली बार विश्व खाद्य-सर्वेक्षण (survey) कराया और दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट १९५२ में प्रकाशित हुई। इसने १९५० में विश्व-कृषि आकलन (World Census of Agriculture) की व्यवस्था कराई।

अधिक भूत और दूसरी फसलें कैसे पैदा की जायं, टिड्डी जैसे नाशक कीड़े और पौधों तथा पशुओंकी बीमारियोंका नियंत्रण कैसे किया जाय, जंग खाद्यकी बर्तनी हो उसकी रक्षा कैसे की जाय और साधारणतया खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और जंगलों की पैदावार कैसे बढ़ाई जाय—आदि समस्याओंके सम्बन्धमें प्राविधिक सहायता चाहनेवाले देशोंकी सहायताके लिए खाद्य तथा कृषि संगठन अपने विद्यमान भेजता है। भूमि संरक्षण (soil conservation) और खादोंके उपयोगके सम्बन्धमें भी वह परामर्श देता है। संक्षेपमें वह वैज्ञानिक सूचनाओंका विनिमय गृह है। वह ऐसी प्राविधिक सहायता देता है जिसके लिए राष्ट्र सघके अधीन कोई सुविधा न थी। अपने विशिष्ट कार्यक्षेत्रके सम्बन्धमें वह राष्ट्रोंके बीच समान वैधिक व्यवस्थाओंको भी प्रोत्साहित करता है।

खाद्य तथा कृषि संगठनने अनेक क्षेत्रीय खाद्य सम्मेलनोंकी व्यवस्था की है। उसने अनेक देशोंको मक्काके प्रसक्त बीज (hybrid corn) तथा अन्य उन्नत बीजोंके नमूने भेजे हैं। कृषि मजदूरोंके लिए उसने प्राविधिक पत्रिकाएँ तथा अन्य प्रकाशन वितरित किये हैं। इथियोपिया और कुछ योरोपीय देशोंमें पशु चिकित्साके लिए उसने थोड़ा बहुत सामान भेजा है। उसने अच्छी नमलके पौधों और पशुओंका एक सूची पत्र तैयार कराया है।

यातायातकी सुविधाओंमें सुधार (Improvement of Transport Facilities). ईरानमें, धरतीकी बनावटके कारण, यात्रा करना बहुत कठिन होता है। यह कठिनाई दूर करनेके लिए हवाई यात्राका विस्तार ही ठीक समझा गया। अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक-उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organisation) ने जो संयुक्त राष्ट्र सघसे सम्बद्ध उसकी विशेषज्ञ मन्त्रालयोंमें

से एक है, अपने विशेषज्ञोंको इस समस्याका अध्ययन करने और ईरानकी हवाई यात्रा के विकासमें उसे परामर्श देनेके लिए तथा जमीन पर काम करनेवाले दलके प्रशिक्षणमें ईरानी सरकारके नागरिक उद्भूयन विभागकी सहायता देनेके लिए ईरान भेजा। एक दूसरा क्षेत्र जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ यातायातकी सुविधाओंका मुधार करने में व्यस्त रहा है, पूर्वी पाकिस्तान तथा अन्य कुछ ऐसे देश हैं जहां जल मार्ग ही परिवहन का प्रधान साधन है।

५. सामाजिक, मानवतावादी और सांस्कृतिक क्षेत्रोंमें सफलताएं (Accomplishments in the Social, Humanitarian and Cultural Fields)

मानव अधिकार. यदि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से सभी सरकारोंका प्राथमिक कर्तव्य मनुष्यके कल्याणकी वृद्धि है तो मानव अधिकारोंका प्रदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्र संघ (League of Nations) ने मध्य जीवनके कुछ अधिकारों पर विचार किया था, पर संयुक्त राष्ट्र संघने अनेक सांस्कृतिक अधिकारोंको भी विचारणीय विषयोंमें शामिल कर लिया है।

आर्थिक और सामाजिक परिपदके जरिए ऐसे अनेक अध्ययन किये गये जिनमें तत्पावित सांस्कृतिक अधिकार भी आ गये। इन अध्ययनोंके परिणाम मानव अधिकारोंके अन्तर्राष्ट्रीय विधेयके रूपमें संयुक्त राष्ट्रके सम्मुख पेश किये गये। मात्र-धार्मिक विचार-विमर्श करनेके बाद आम समाने १० दिसम्बर, १९४८, को मानव अधिकारोंका विश्व घोषणा-पत्र स्वीकार किया। यह घोषणा-पत्र अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर सभी मनुष्योंकी जन्म-जात स्वाधीनताओं और उनके जन्म-जात अधिकारों की परिभाषा करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: जीवन, स्वाधीनता और शरीरकी सुरक्षाका अधिकार, न्यायालयोंमें निष्पक्ष न्याय (a fair trial) का अधिकार, स्वच्छन्द धूमनेका अधिकार, राष्ट्रीयताका अधिकार, सम्पत्ति रखनेका अधिकार, विचार, विवेक और धर्मका अधिकार, स्वतन्त्र मन और मन-अभिव्यक्ति का अधिकार, गना करनेका और संघ बनानेकी स्वाधीनताका अधिकार, अपने देशकी सरकारमें भाग लेनेका अधिकार, सामाजिक सुरक्षाका अधिकार, काम करनेका अधिकार, रोजगारके स्वतन्त्र चयनका और समान कार्यके लिए समान वेतन पानेका अधिकार, विश्राम और अवकाशका अधिकार, जीवनके समुचित मान-दण्डका अधिकार, शिक्षाका और अपने देशके सांस्कृतिक जीवनमें भाग लेनेका अधिकार।

इनमें से अनेक अधिकारोंको 'मूल मान' कहा गया है। फिर भी जैसे-जैसे समय बीतता जाता है जैसे-जैसे शक्ति और अर्थ प्राप्त कर लेना शब्दोंकी प्रवृत्ति होती है।

आयिज और सामाजिक आयोमने मानव अधिभार आयोमने कहा कि वह मानव अधिभारो पर एक प्रमंविदा (covenant) का प्राश्य तैयार करे और उसके लागू किये जानेके उपायोको एक रूपरेखा बनाये। यदि अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा इन मानव अधिभारोकी प्राप्ति और सुरक्षा की जा सके तथा अदालतो द्वारा उन्हें लागू किया जा मरे तो संसार भरके लोकोके लिए न्याय सुलभ बनानेकी दिशामें हम बहुत बड़ा कदम उठायेगे।

इन स्वाधीनताओंके प्रश्नोमें सम्बन्धित कुछ मामलोमें कई एक कदम उठाये जा चुके हैं। इन कदमोमें निम्नलिखित विषयोका अध्ययन भी है: अल्पसंख्यकों के अधिभार, मजदूर सघोके अधिभार, बेगार और दामताकी समस्या, वृद्धावस्थाके अधिभार, जाति संहार (genocide), महिलाओंकी स्थिति, महिलाओंके लिए शिक्षाकी सुविधा, विवाह और सामाजिक प्रश्न। संसारके कम भाग्यवान् बन्धोकी सहायता करनेवाले दो संगठन ये हैं: समुक्त राष्ट्र सघका अन्तर्राष्ट्रीय बाल सकट कोष और बालकोके लिए समुक्त राष्ट्र सघीय चन्दा फण्ड।

सामाजिक, मानवतावादी और सांस्कृतिक क्षेत्रोंमें समुक्त राष्ट्र सघ द्वारा किये जानेवाले कार्यका लेखा-जोखा करते समय अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (ILO), समुक्त राष्ट्र सघका शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक मगठन (UNESCO) तथा अन्तर्राष्ट्रीय धरणाधी संगठन (IRO) द्वारा किये गये कार्यों पर भी विचार करना होगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization—WHO). इन संगठनकी स्थापना सन् १९४८ में उस समय हुई जब २८ सदस्य राष्ट्रोंने इसके विधानको स्वीकार कर लिया। इसकी स्थापनाके पहले ही मितम्बर सन् १९४७ में मिलने लैजेकी महामारीका प्रकोप हुआ। समुक्त राष्ट्र सघने तुरन्त संसार भरके चिन्चिका (cholera) विशेषज्ञोको एकत्र किया और आवश्यक सामग्री जुटाई। दिसम्बरका अन्त होते-होते महामारी मिटा दी गयी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, जन स्वास्थ्य और रोगोके नियन्त्रणके सम्बन्धोंमें अपने सदस्य राष्ट्रोंको परामर्श देता है। मलेरिया, तपेदिक, न्युपदय (yaws) और उपदंश (syphilis) जैसी व्यापक बीमारियोंके विरुद्ध यह संगठन युद्ध छेड़े हुए है और यह युद्ध कोड, टाइफस, पोलियो, डिप्थीरिया व बिल्हार जियासिस^१ (bilharziasis) जैसी कम व्यापक बीमारियोंके विरुद्ध भी चल रहा है।

स्वास्थ्यके कुछ क्षेत्रोंमें—जैसे स्वास्थ्य और खाद्यकी सम्बन्धित समस्याओंमें—यह संगठन साथ और कृषि संगठन (FAO) के साथ मिलकर काम करता है—क्योंकि दोनोंके कार्योंमें समानता होनी है।

इस संगठन द्वारा की गयी कुछ विशिष्ट सेवाएं ये हैं:

^१ A disease caused by trematode worms parasite in human and other blood, Common in Egypt—Chamber's Twentieth Century Dictionary.

(१) मलेरिया पर बाढ़ पानेके लिए यूनानको दी गयी सहायता; बोमारो ९५ प्रतिशतमें घटकर ५ प्रतिशत रह गयी।

(२) भारतको तपेदिक निरोधक जी० सी० जी० के टीका देना।

(३) एशियापिपाकी सरकारको डाक्टरी शिक्षाकी योजनाके सम्बन्धमें दिया गया परामर्श।

(४) बन्दरगाहोंकी सफाई करने वाले कर्मचारियोंके पुनर्वासिके सम्बन्धमें इटलीकी सरकारसे की गयी मिफारिसें।

(५) औषधियों, शरीर विज्ञान सम्बन्धी आवश्यकताओं और डाक्टरी मात्र-सामानके प्राप्ति करनेमें अपने मेडिकल सप्लाई व्यूरो द्वारा सरकारोंको दी गयी सहायता।

(६) जन-स्वास्थ्य और डाक्टरीके क्षेत्रमें अन्यविविधिन देशोंकी मिफारिस पर सरकारी अधिकारियोंको दी गयी टाउच-बायसा।

(७) मलेरिया विरोधी अभियानमें लगे देशोंको कीटाणु नाशक डी० डी० टी० देना और मूत्र रोगोंके नियंत्रणमें ब्यर्थ देशोंको पेंसिलीन देना।

मंशेमें हम कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कार्योंमें लगति बैठातेवाले अधिकारियोंकी भाति काम करना है, शोध-कार्यको प्रेरणा, और बज देना है, महामारियों और अन्य बीमारियोंको दूर करना है, पोषण, आवास, सफाई, शिक्षा, आर्थिक और कामकी परिस्थितियों तथा वातावरणमें सम्बन्धित स्वास्थ्य सफाईके अन्य पहलुओंमें सुधार करना है, गांव सामग्री, शरीर तथा औषधि निर्माण और अन्य ऐसी ही बातोंके सम्बन्धमें अन्तर्राष्ट्रीय मान-दण्डोंका विकास करता है, और उनकी प्रतिष्ठा और वृद्धि करता है।

संयुक्त राष्ट्र संघका अन्तर्राष्ट्रीय बाल संरक्ष बोध (UNICEF). यह सचरी एक और संस्था है जिसका स्वास्थ्यमें—विशेषकर बच्चोंके स्वास्थ्यमें—पनिष्ठ सम्बन्ध है। सन् १९४६ में आय समाने संयुक्त राष्ट्रके सहायता व पुनर्वास संगठनके अपूर्व कामको पूरा करनेके लिए इसका संगठन किया था क्योंकि सहायता व पुनर्वास संगठन १९४६ में अपना काम बन्द करने जा रहा था। इस संगठनको संयुक्त राष्ट्र संघके बजटमें धन नहीं मिलता। यह संगठन सरकारों और व्यक्तियोंसे स्वैच्छा दान और बड़े दिलों वाले बाड़ों (X'mas Cards) की विज्ञापन दितनेवाले धन पर टिका है।

संयुक्त राष्ट्र संघका अन्तर्राष्ट्रीय बाल संरक्ष बोध निम्नलिखित कार्यों पर विशेष ध्यान देता है—निम्न बाल्याप और मातृ तथा सम्बन्धी सामान सज्जा, भोजन और औषधियां मुक्त बनाना, बीमारियों—विशेषकर बच्चोंकी बीमारियों—का निमक्ता करना, निम्न पालन, और भूखण्ड, बाड़, अवाल तथा ज्वालामुखियोंके उद्गारमें बच्चोंकी रक्षा व सहायता करना। इसके अनिरिक्त यह संस्था बच्चा-बच्चा बाल्याप सेवाओंकी और शिक्षाकी व्यवस्था भी करती है। यह संस्था

विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य व कृषि संगठनके माध्यम से घनिष्ठ सहयोगमें काम करती है।

इस कोषके दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम हैं: न्यूपदंग (yaws) और तपेदिक के विरुद्ध अभियान। हिन्देनिया की सरकारकी प्रार्थना पर वहाँ न्यूपदंगके विरुद्ध डटकर काम किया गया है। एशिया और अफ्रीकाके अन्य ऐसे देशोंमें भी जहाँ यह बीमारी फैली हुई है, अभियान छोड़ा गया है। इस कोषकी और विश्वस्वास्थ्य संगठनकी सहायतासे बी० सी० जी० के टीके लगानेका काम जन-प्रिय बनाया गया है। सन् १९५३ तक इस कोषके द्वारा दो करोड़ बीम लाख बच्चोंको बी० सी० जी० टीका लगाया गया, तीस लाख बच्चे न्यूपदंगकी बीमारीसे और एक करोड़ बीम लाख बच्चे मलेरियाकी बीमारीसे बचाये गये। पेनिमिलीन और डी० डी० टी० के निर्माण के लिए और बी० सी० जी० के टीके लगानेके लिए भारतको इस मस्याने उदारताके साथ सहायता दी है। हाल ही में भारत सरकारने देशव्यापी कुष्ठ (काँड़) नियंत्रण योजनाके विकासके लिए इसकी सहायता मांगी है।

आम गभाने संसम्मतिसे इस कोषको अनिश्चित काल तक चालू रखनेका प्रस्ताव पाम किया है और उसे एक नया नाम दिया है—संयुक्त राष्ट्र मधका बाल कोष।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (International Labour Organization). इसका विचार राष्ट्र मधसे सम्बन्धित एक स्वायत्त सम्पाने हुआ है। यह संस्था समूचे युद्ध काल भर काम करती रही और अब यह संयुक्त राष्ट्र मधसे सम्बद्ध एक विशेषज्ञ समिति है।

इस संगठनका वार्षिक सम्मेलन केवल भौगी मजदूरोकी रक्षाके लिए विधियोंका विकास करता है। इसके लिए वह अन्तर्राष्ट्रीय करारोंको प्रस्तावित करता है। इन प्रस्तावोंको सम्मेलनमें आये प्रतिनिधि अपने-अपने देश से जाते हैं और अपनी सरकारोंके सम्मुख स्वीकार करनेके लिए पेश करते हैं। जो सरकार इन करारोंमें से किसी को मान लेती है वह अपनेको इस बातके लिए बाध्य बना देती है कि वह हर वर्ष इसकी रिपोर्ट भेजे कि करारोंमें जिन विधियोंकी मागकी गयी है उनके पाम करनेके लिए क्या और कितना काम किया गया। सन् १९१९ से अब तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनने १०० से अधिक प्रस्ताव इस प्रकार भेजे हैं और १,३०० से अधिक स्वीकृतियोंकी सूचना उसे मिल चुकी है।

यह संगठन सरकारोंको मलाह देता है कि मजदूरोकी रक्षा करनेवाले आधुनिक-सम विधियोंको किस प्रकार बनाया जाय। इसने हालमें अपना काम बड़ाकर ऐसी विधियोंके प्रशासनके विकासमें भी सहायता देना आरम्भ कर दिया है। रोजगार सम्बन्धी सेवाओं, श्रम सम्बन्धी सर्वेक्षणों और आकड़ों तथा औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्यका विकास भी यह संगठन करता है।

सन् १९४९ तक इस संगठनने निम्नलिखित कार्य खास तौर पर किये:

- (१) श्रम-सम्बन्धी विधियों और कामकी परिस्थितियोंमें सुधारके सम्बन्ध में सरकारोंको परामर्श देनेके लिए अनगिनत श्रम विनियमनोंको अन्य देशोंमें भेजा गया।
- (२) विविध देशोंकी रोजगार दिलानेमें सम्बन्धित नैवाञ्चिकोंके विषयमें एक छोटी पुस्तक-माला तैयारकी गयी।
- (३) औद्योगिक प्रतिष्ठानों (Industrial establishments) के लिए सुरक्षा नियमों (safety regulations) की एक आदर्श संहिता बनायी गयी।
- (४) कई क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन किये गये।
- (५) सन् १९४७ में हुए अपने दूसरे सम्मेलनोंमें इनने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं (social security systems) के विकासके सम्बन्धमें और छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों और हस्तकला व्यवसायोंको प्रोत्साहन दिये जानेंके सम्बन्धमें छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों और हस्तकला व्यवसायोंको प्रोत्साहन दिये जानेंके सम्बन्धमें विचार किया।

संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन (UNESCO) इस मस्यौदा सम्बन्धित शिक्षा और संस्कृति के विकासमें है। इस मस्यौदा नियमन करने वाले मविधान पर १५ नवम्बर, १९४५, को हस्ताक्षर किये गये थे। इसका काम अपने सदस्य राष्ट्रोंके धन्देमें चलता है। दैनिक व्यवस्था २० सदस्योंकी एक कार्यमिति करती है।

निरक्षरताका उन्मूलन इनके मुख्य कृत्योंमें से एक है। दक्षिणी एशिया और प्रशान्त महासागर क्षेत्रमें भी बड़ी प्रगति प्राप्त हुई है। बच्चोंमें से पांच बर्गों में लगभग बच्चोंको किसी प्रकारकी शिक्षा नहीं मिलती। प्रौद्योगिकी शिक्षाके सम्बन्धमें यह संगठन इस नीति पर धृष्ट है कि केवल अक्षर ज्ञान देना ही काफी काम नहीं होता। उनके लिए ये बातें ज्यादा जरूरी हैं—अपने जीवनमें कुछ सीखे-माझे व्यावहारिक सुधार माँगना जैसे पौनेके पानीको उबालना, पानानाका साँदना, ऊँचे उठे रसोईपर बनाना, स्थानीय सामानमें ही अधिक अच्छे घर बनाना, स्वर नरकारिया पैदा करने अपने भोजनमें सुधार करना, आदि।

ऐसी नयी-नयी बातें माँग लेनेके बाद लोग विनियम और अन्य तरीकोंसे शिक्षा पानेके लिए तैयार हो जायेंगे। संगठनके पास स्वयं इनका पर्याप्त कोष नहीं है कि वह शिक्षाका अपना शिक्षाके प्रवर्धनका व्यय उठा सके। वह केवल इन समस्तों पर सरकारोंकी सलाह देता है और माँग ही कुछ विनियम प्रकारके प्रशिक्षण और मशीन (equipment) का प्रवर्धन कर देता है। शिक्षाके हर स्तर पर वह विनियमों के अधिकारित उपयोगको प्रोत्साहन देता है। सन् १९५२-५३ में नई दिल्लीमें एक तीन महीनेकी गाँधी ट्रस्ट की जिसमें भारतीय शिक्षकोंको यह निम्नाया गया था कि तात्त्विक शिक्षा में वे चर-चित्रों, तस्वीरों और अन्य दृश्य-माध्यमोंका किन प्रकार उपयोग करें। जिसमें सन् १९५३ में अरब-राज्योंका तात्त्विक-शिक्षा-केन्द्र माना

गया था। इसके पाठ्य-क्रममें लिखना और पढ़ना सिखानेकी विधियां, घरेलू अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य, कृषि और कुटीर-उद्योग शामिल हैं। ये केन्द्र पाठ्य पुस्तकें, प्रारम्भिक बाल पाठ्यिका और दृश्य-भाषन जैसे चल-चित्र आदि और शिक्षा पद्धतियों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है।

यह संगठन साहित्यिक मामलों, फोटोग्राफ और चल-चित्र आदिके अन्तर्राष्ट्रीय आवागमनके विरासमें सहायता करता है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय कॉपी-राइटकी मान्यता पुरानेमें सहायता दी जिसके द्वारा लेखकों और कलाकारोंके अधिकारोंकी रक्षा होती है। पुस्तकोंके स्वतंत्र व्यापार और वैज्ञानिक औजारोंके परीक्षणके सम्बन्ध में भी करार हो चुके हैं। विद्यार्थियोंकी पद्धतियोंके विकासके सम्बन्धमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। मद्रहालयोंके सचालकोंके सम्मेलन बुलाये गये हैं जिनमें उन्हें और अन्य विशेषज्ञोंको इस बात में सहायता दी गयी है कि वे मद्रहालयोंका उपयोग जन-शिक्षाके महत्वपूर्ण साधनोंके रूपमें कर सकें।

भारत सरकारके मुझाव पर अन्धोंके लिए खेल (लिखित वर्णमाला) का एक निर्दिष्ट स्तर निर्धारित किया गया है। मन् १९५४ में पेरिसके यूनेस्को भवनमें अन्ध-संगीतज्ञोंका एक सम्मेलन इसलिए बुलाया गया था कि खेल-संगीत सकेतोका मानदण्ड सुधारा जाय।

अमेरिका जैसे कठोर मुद्रा क्षेत्रों (Hard Currency Areas) से पुस्तकों और शिक्षा सम्बन्धी सामग्रियोंकी खरीदमें नरम मुद्रा क्षेत्रों (Soft Currency Areas) के सम्मुख डालरोंकी कमी जो कठिनाई पैदा करती है उसे दूर करनेके लिए इस संगठन ने कई लाख डालरके कूपन जारी किये हैं जिनसे ऐसे देश शिक्षा सम्बन्धी सामान खरीद सकते हैं।

अतःउपजाऊ या ऊपर धरतीकी समस्याका अध्ययन करनेकी व्यवस्था करना इस संगठनकी एक विशेष योजना है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र सचकी प्राविधिक सहायता कार्यक्रममें भी भाग लेता है।

संयुक्त राष्ट्र सचके शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति संगठनके कुछ अन्य विशिष्ट कार्य निम्नलिखित हैं :

(क) लोगोंकी अपना जीवन स्तर ऊँचा उठानेके लिए आवश्यक आधार भूत ज्ञान और उसकी विधियां सुलभ बनानेके उद्देश्यसे पथप्रदर्शक योजनाएँ (पायलट प्रोजेक्ट्स) बनाना,

(ख) ग्रामीण क्षेत्रोंमें प्रौढ-शिक्षा पर गोंटिया करना;

(ग) विशिष्ट समस्याओंमें सहायता देनेके लिए विशेषज्ञोंको भेजना;

(घ) वैज्ञानिकोंके बीच सम्पर्क स्थापित करना; और

(च) चल-चित्रों व रेडियो द्वारा शिक्षा देनेका, विज्ञान और सामाजिक उत्थान का और शैक्षिक व्यवस्था आदिका अध्ययन करनेके लिए छान-बूत्तियां देना।

६. पराधीन जगत (The Dependent World)

प्रन्ध्याम व्यवस्थामे इन क्षेत्रोंकी स्थितिमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ है जो पहले "मैन्डेट्स्" कहलाते थे और अब न्याम प्रदेश कहे जाते हैं। एक लेखकरा कहता है : "नवीनता उनकी अधिक है, तथ्यकी कम"। न्याम प्रदेशोंका कुल क्षेत्रफल दोप पराधीन जगनकी तुलनामें बहुत कम है। अधिकतर पहलेके बी० और सी० क्षेत्रोंके "मैन्डेट्स्" ही आज न्याम प्रदेश हैं।

इनकी सूची इन प्रकार है :

न्याम-प्रदेश	प्रशासन सत्ता
कैमरून	ब्रिटेन
कैमरून	फ्रान्स
न्यूगिनी	ऑस्ट्रेलिया
नौरू	ऑस्ट्रेलिया
रुआन्डा-उरुण्डी	बेल्जियम
टागानिका	ब्रिटेन
तोंगोलैण्ड	ब्रिटेन
तोंगोलैण्ड	फ्रान्स
परिचामी मामोंआ	न्यूजीलैण्ड
मोमालीलैण्ड	इटली (इस वषर्के लिए, इसके बाद इटलीका पुराना उपनिवेश मोमालीलैण्ड स्वतंत्र हो जायगा)
मौरिशस अब स्वतंत्र हो गया है।	

पहलेकी व्यवस्थाकी तुलनामें प्रन्ध्याम व्यवस्था कुछ अपोमें पीछे ले जानेवाली और कुछ अपोमें प्रगतिशील व्यवस्था है। राष्ट्र सभकी व्यवस्थामें एक निश्चित दिशात्मक दृष्टि थी कि 'अ' और 'ब' क्षेत्रोंके "मैन्डेट्स्" में सन्ने द्वारकी नीति कायम रखी जायगी। यह भी आदेश था कि किसी प्रकारकी स्थानीय किलेबन्दी या विदेशोंमें केशा करनेके लिए देशी सेनाओंकी भर्ती नहीं की जायगी। ये पाबन्धिया सन्धुक्त राष्ट्र संघके घोषणापत्रमें नहीं हैं। प्रगतिशील जान यह है कि प्रन्ध्याम परिपद भरवागे प्रतिनिधियोंकी संस्था है न कि स्वतंत्र विधेयकों की।

सांस्कृतिक तौर पर साम्राज्यवाद कालमें कोई ज्ञानिवागे परिचर्चन नहीं हुआ। साम्राज्यवादी राष्ट्रोंने कुछ समय तक तो करने अधिकृत प्रदेशोंके सम्बन्धमें रिपोर्ट या सूचनाएं दीं। अब वह ऐसा करनेमें आना-जानी करते हैं और समंसे प्रश्नोंका स्वागत नहीं करते। अमेरिका तो आधिक्य अर्थोंके जीवन संहारक प्रयोगोंके लिए प्रमान्यके अपने "नागरिक क्षेत्रों" को उपयोगोंमें लाने समय उन्हें अपनी करानी

ही ममता है। सुरक्षा परिषदकी स्वीकृतिमें ये क्षेत्र-सैनिक अड़्डे बना दिये गये ह। एफ० एल० शुमन (F. L. Schuman) लिखते हैं : "कोई भी दूसरी शक्ति प्रण्यास व्यवस्थाको पुरानी उपनिवेशवादी व्यवस्थाके समान बनानेमें इतना आगे बढनेकी हिम्मत नहीं कर सका। "अमेरिकाको इन क्षेत्रोंमें सैनिक अड़्डे बना लेनेकी सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकृति दिये जानेमें ही इस बातका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रण्यास व्यवस्था पुरानी उपनिवेशवादी व्यवस्था में कहां तक वास्तविक सुधार कर सकेगी।" (International Politics, पृष्ठ ३५२-५३—१९५३—का संस्करण)

व्यवहारमें प्रण्यास व्यवस्थासे अनेक लाभ हैं। चूंकि प्रण्यास परिषदके आधे सदस्य गैर साम्राज्यवादी राज्योंके प्रतिनिधि होते हैं इसलिए न्याय प्रदेशोंका शासन करनेवाली शक्तियोंको अपने हर कदमका औचित्य सिद्ध करना होता है। विश्वके जनमतकी तेज निगाहे इन देशों पर रहनी है। न्याय प्रदेशोंके व्यक्तियों और समुदायों दोनोंमें लिखित और मौखिक प्रमाण लिये जाते हैं। संपूर्ण राष्ट्र सभके द्वारा करने वाले प्रतिनिधि मण्डल न्याय प्रदेश जाते हैं, मौके पर जाकर स्वयं बहसकी परिस्थितियोंका अध्ययन करते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं। वार्षिक रिपोर्टों पर विस्तृत और पर विचार होता है। विभिन्न प्रदेशोंकी प्रशासनीय रिपोर्टोंकी परीक्षा करनेके बाद प्रण्यास परिषदने शासन करनेवाली सत्ताओंको कई एक सुझाव दिये हैं; जैसे जीवनके मानदण्डोंका सुधार, ऊँचे वेतन, शिक्षाकी सुविधाओंका विस्तार और स्थानीय शासनमें मूलनिवासियोंका अधिकाधिक प्रतिनिधित्व।

याचिकाएँ (Petitions). सन् १९५२ में अपने ग्यारहवें अधिवेशनके समाप्त होने समय तक परिषद न्याय प्रदेशोंसे प्राप्त एक हजारसे अधिक याचिकाओं और सूचनाओं पर विचार कर चुकी थी। यह याचिकाएँ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मामलोंमें किये जानेवाले अन्यायोंके विरुद्ध वैयक्तिक शिकायतोंमें लेकर सामूहिक विरोधों तक सभी प्रकारकी होती है। सोपोलैण्डके "हवी" लोगोंका एकीकरण करने और सामोआ को स्वशासनका अधिकार दिये जानेकी महत्वपूर्ण याचिकाओं पर परिषदने विचार किया है। अफ्रीकाके न्याय प्रदेशोंमें एक विश्व-विद्यालय स्थापित करनेकी याचिकाको दो कारणोंसे अस्वीकार करना पड़ा था। पहला कारण था भाषा सम्बन्धी और आर्थिक कठिनाइयाँ तथा दूसरा कारण था अभ्यासको एव विद्यार्थियोंकी कमी।

याचिकाओंकी सख्या इतनी अधिक बढ़ गयी है कि उन पर विचार करनेके लिए अब एक स्थायी समिति बना दी गयी है।

७. वैधिक झगड़े (Legal Disputes)

जैसा ऊपर कहा जा चुका है अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयके अधिकार क्षेत्र तीन प्रकार के हैं :

(१) स्वैच्छिक—धारा ३६,

(२) वैकल्पिक धाराको स्वीकार करनेवाले राष्ट्रोंके लिए वैकल्पिक, अनिवार्य और बाध्यकर अधिस्तर क्षेत्र (optional compulsory and obligatory jurisdiction for those states which acceded to the optional clause),

(३) परामर्श-मूलक अधिकार क्षेत्र।

सन् १९४५ से अब तक न्यायालयने अनेक मामलोंका फैसला दिया है; पर स्थानकी कमीके कारण हम यहाँ केवल निम्नलिखित तीन मामलोंका ही उल्लेख करेंगे।

(१) कॉर्बू चैनल का मामला. २ अक्टूबर, १९४६, को अल्बानिया के क्षेत्रीय समुद्रमें बिछाया गया मुरगोसे ब्रिटेनके जहाजोंको क्षति पहुँची और अपेक्ष नाविक घायल हुए। कुछ दिन बाद अल्बानियाके अधिकारियोंकी अनुमति लिये बिना अंग्रेजी बेड़ेने सागरकी सफाई की और मुरगोसा पता लगा लिया। पता लगा लेनेके बाद ब्रिटेन ने मुरगोसा परिषदमें शिकायत की कि इन मुरगोके लिए अल्बानिया जिम्मेदार है।

जुक्ति परिषद किसी फैसले पर न पहुँच सकी, इसलिए मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयके सामने रखा गया। न्यायालयने सन् १९४९ में फैसला दिया कि (अ) अल्बानियाका गणतन्त्र इन मुरगो और विस्फोटोंके लिए जिम्मेदार है, (ब) अल्बानिया के क्षेत्रीयभागमें जाकर ब्रिटेन ने अल्बानिया गणतन्त्रकी सम्प्रभुता भंग नहीं की और न दुर्घटनाके बाद उस सागरकी सफाई करके ही ब्रिटेन ने अल्बानिया की सम्प्रभुता भंगकी और (स) अल्बानिया ब्रिटेनको ८,४३,९४७ पौण्ड स्टर्लिंगके रूपमें दे।

(२) आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनीका मामला (१९५२). जब डा० मोसादेघ (Mosadegh) के शासनमें ईरान ने अपने तेल खानोंका राष्ट्रीयकरण कर दिया तब ब्रिटेन और आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनीने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयमें प्रार्थना की कि जब तक मामलेका फैसला न हो जाय तब तक ईरान में उनके अधिकारोंकी सुरक्षित रखनेके लिए अस्थायी कार्रवाई की जाय।

इसी बीच ईरान ने आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनियों पर अधिकार कर लेनेका आदेश दे दिया। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयने अपने ५ जुलाई, १९५१, के निर्णयमें अपेक्ष-सरकारकी इस प्रार्थनाको मान लिया कि ईरान के तेल झण्डे पर विचार न कर झण्डेने पूर्व की व्यवस्था को ही बरकरार रखा जाय। न्यायालयके बहुमतने अपने निर्णयमें दोनों सरकारोंकी आदेश दिया कि वे ऐसा कोई काम न करें जिसमें तेलके स्वतंत्र प्रवाहमें कोई बाधा पड़े। ब्रिटेन और आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनीोंने उसी प्रकार तेल मिलता रहे जिस प्रकार १ मई, १९५१, के पूर्व मिलता था जब ईरान ने तेलका राष्ट्रीयकरण किया था।

न्यायालयने तेल उद्योग चालू रखनेके लिए एक निरोधक बोर्ड तैयार किया

जानेका मुझाव दिया जिसमें दो-दो मंदस्य ब्रिटेन व ईरान के हों और पाचवां मंदस्य किसी ऐसे तीसरे देशका प्रतिनिधि हो। त्रिमे ब्रिटेन व ईरान आपसमें तय करें। ईरान की सरकारने इस मुझावको यह बह बर अस्वीकार कर दिया कि यह ब्यादेन (injunction order) के समान है।

तब १९ अक्टूबर, १९५०, को ब्रिटेन ने मामला सुरक्षा परिषदके सामने पेश किया। परिषद तब तक के लिए स्थगित हो गयी जब तक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय यह फैसला न कर दे कि न्यायालयको इस विवादग्रस्त मामले पर विचार करनेका अधिकार है या नहीं।

न्यायालयने यह फैसला दिया कि वह ब्रिटेन के इस अभियोगको नहीं मान सकता कि ईरान ने आगल-ईरानी तेल कम्पनीकी ५० बगैड पाँचवां सम्पत्तिका राष्ट्रीयकरण करके अन्तर्राष्ट्रीय विधिसे भंग किया है और इसलिए न्यायालयको आगल-ईरानी तेलके झगड़े पर विचार करनेका अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दोंमें इस उद्योगके राष्ट्रीयकरण हो ईरानके आन्तरिक अधिकार क्षेत्रका मामला माना गया।

(३) दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीकाकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिका मामला। आम सभाके पहले अधिवेशनमें ही दक्षिणी अफ्रीका ने यह दावा किया कि दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के समानाधिकृत प्रदेश (mandate) को जिस पर वह अब तक एक समानाधिकारी की तरह शासन करता रहा था, अपनेमें मिला लेनेका उसे अधिकार है। आम सभा दक्षिणी अफ्रीकाके तर्कोंको माननेके लिए तैयार नहीं थी। इसलिए निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसने न्यायालयमें सलाह मागी :

(अ) दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीकाके समानाधिकृत प्रदेशके प्रति दक्षिणी अफ्रीकाके क्या अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व हैं ?

(ब) क्या दक्षिणी अफ्रीका को दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीकाको अपनेमें मिला लेने का कोई वैधिक अधिकार है ?

११ जुलाई, १९५०, को न्यायालयने निर्णय दिया कि दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका अब भी एक अन्तर्राष्ट्रीय समानाधिकृत प्रदेश ही है और दक्षिणी अफ्रीकाकी दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीकाकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिमें किसी प्रकारका परिवर्तन करनेका अधिकार नहीं है। न्यायालयने यह भी फैसला दिया कि समानाधिकृत प्रदेशोंमें ऐसी कोई बात नहीं है कि दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका अपना भू-प्रदेश दक्षिणी अफ्रीकाको दे या अपनी सम्प्रभुता उसको हस्तान्तरित करे। दक्षिणी अफ्रीका का जो एक माम काम सौंपा गया था वह यह था कि दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीकाके निवासियोंकी ओर से उन्हींके कल्याण एवं उत्थानके उद्देश्यमें उस प्रदेशका शासन समालें।

जब दक्षिणी अफ्रीका की सरकारने यह तर्क रखा कि चूँकि राष्ट्र संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, इसलिए समानाधिकृत प्रदेश भी समाप्त हो गये तब न्यायालय ने विस्तृत ठीक उत्तर दिया कि यदि समानाधिकृत प्रदेश समाप्त हो गये हैं तो उस पर दक्षिणी अफ्रीका की अधिकार-मत्ता भी समाप्त हो गयी है।

एम, वेल्जियम और बिनी के प्रतिनिधि न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त न्यायालयका उत्पन्न मत इस पक्षमें था कि दक्षिण अफ्रीका को वैधिक तौर पर मजबूर किया जाना चाहिए कि वह समाजापित प्रदेशको संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रत्याप्त व्यवस्थाको सौंप दे क्योंकि सौंप सभी समाजापी शक्तियोंने समाजा व्यवस्थाको प्रत्याप्त व्यवस्थामें परिवर्तित करना स्वीकार कर लिया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व सरकार (The United Nations and World Government)

समय-समय पर लोग एक ऐसी विश्व सरकारका स्वप्न देखते रहे हैं जो राष्ट्रीय राज्योंको स्थानीय सरकारोंके स्तर पर उतार दे। ऐसे सोंगोंमें विश्व विजेता और साम्राज्य निर्माता भी रहे हैं। पर जिन लोगोंका दृष्टिकोण लोकतन्त्रवादी है और जिनके हृदयमें राष्ट्रीय अधिकारी तथा राष्ट्रीय विरासतके प्रति कुछ सम्मान है वे लोग एक विश्व सपना सपना देखते रहे हैं। यदि १८वीं शताब्दीमें नैपोलियन की चल पानी तो उमने कमसे कम योरोप भरके लिए अवश्य ही एकात्मक सरकार काममें कर दी होगी। हिटलर ने भी इसी दिशामें सोचा और कार्य किया।

लोकतन्त्रवादी दृष्टिकोणने इस समस्या पर विचार करने वालोंमें १९वीं शताब्दी के अंग्रेज कवि अल्फ्रेड टेनिसन (Alfred Tennyson) का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने "समूचे मानव जातिकी एक सत्तार और एक विश्व सभ" की कल्पना की थी। हमारे युगके एक दूसरे अंग्रेज एच० जी० वेल्स (H. G. Wells) भी विश्वको एक इकाई मान कर सोचते और लिखते थे।

राजनीतिक तौर पर सभारको एक मूख में बाधने की यह उत्कण्ठा अपेक्षाकृत नयी है। द्वितीय विश्व युद्धके पहले स्पेन के मदारियागा (Madariaga) ने विश्व सभके पक्षमें लिखा था। अन्य अनेक अमेरिकियों की भांति इस विषयके अमेरिकी अग्रदूत क्लेरेन्स स्ट्रीट (Clarence Streit) ने अमेरिकी सपवादके आधार पर पश्चिमी लोकतन्त्रवादी राष्ट्रोंके एक सभ (Federal Union) का समर्थन किया था।

युद्ध समाप्त होनेके बादने विश्व सरकारमें लोगोंकी रुचि बहुत बढ़ गयी है। संयुक्त राष्ट्र सभ के घोषणापत्र (charter) की स्थाही मूलने भी न पायी थी कि आलोचकोंने यह कहना शुरू कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति और सुरक्षाकी अन्तिम समस्याओं को हल करनेमें घोषणापत्रमें बोटीकी व्यवस्था होनेके कारण ग्रासतौर पर असमर्थ है। राष्ट्रीय सभ्यताके मिट्टानको बार-बार शान्तिके मार्गमें बाधक बनाया जाता है और कहा जाता है कि जब तक राष्ट्रीय सभ्यता का नियंत्रण नहीं कर लिया जाता तब तक किसी प्रकार की भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था

असम्भव है। ध्यान देनेकी एक बात यह है कि किसी न किसी प्रकारकी विश्व सरकार के प्रति जो उत्साह है उसका कामे कम एक अंग उम निराशाकी भावनामें पैदा हुआ है जिसका कारण मयूक्त राष्ट्रकी कार्यवाहियोंमें कम का नकारात्मक या उतेजक रवैया रहा है। इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि विश्व सरकारके प्रति जो धार्मिक उत्साह दिखाई देता है उसके भीतर कभी-कभी कम विरोधी भावना छिपी रहती है।

विश्व सरकारकी मफलताके लिए यह जरूरी है कि लोगोंमें विश्व समाजकी प्रबुद्ध चेतना और भावना हो। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले एक पूर्ण विश्व समाजकी स्थापना हो जाय तभी विश्व सरकार सन्तोषजनक ढंगसे कार्य कर सकती है। दोनों एक दूसरेकी सहायता करेगे ही। पर एक विश्व समाजकी स्थापनाकी दिशामें पहले कुछ प्रारम्भिक कदम उठाये जाने चाहिए तभी सक्रिय राष्ट्र और व्यक्ति विश्व सरकारके हाथों अपना भविष्य सौंपनेके लिए तैयार होंगे। आज दिन समारमें एक विश्व समाजकी कोई प्रबुद्ध चेतना नहीं है। संसारके प्रभावशाली राष्ट्रों में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी धोषण तथा आनीय विभेदको दूर करनेका कोई सकल्प नहीं दिखाई देता। मानव अधिकारों तथा व्यक्तिके गौरवके प्रति सम्मानकी भावना अधिकांश रूपमें अभी तक स्वप्न ही है। पिछड़े राष्ट्रोंकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगतिमें सहायता देनेकी इच्छा भी अधिक गहरी नहीं है। जहां कहीं ऐसी इच्छा दिखाई भी देती है वहां वह राजनीतिक और सामरिक विचारोंसे दूषित है।

प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक राइनहोल्ड नाइबूर (Reinhold Niebuhr) का कहना है कि विश्व सरकारके लिए विश्व समाज अत्यन्त आवश्यक है। उनका यह कथन बिल्कुल सही है कि विश्व समाजकी स्थापना वैधिक, सांविधानिक और सरकारी साधनों द्वारा नहीं की जा सकती। उन्हींके शब्दों में, "समाज पर दबाव डालकर उसमें मौलिक व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती। मौलिक व्यवस्था तो आन्तरिक सलाह (innate cohesion) से ही उत्पन्न हो सकती है।" अभी तक संसारमें 'ममदृष्टि भावना' नहीं दिखाई देती।

विश्व समाजकी प्रबल भावनाके अभावमें विश्व सरकार आसानीसे अत्याचार और दमन का साधन बन कर ययास्थितिको कायम रखने का प्रयत्न करेगी। ऐसी विश्व सरकारकी स्थापनाके बादकी स्थिति पहलेकी स्थितिसे भी बुरी हो होगी। कुछ सार्वभौमिक परिवर्तन मान हो जानेसे मानव प्रकृतिमें यकायक कोई आदर्शपर्यन्तक परिवर्तन नहीं हो सकता। यह आशा नहीं की जा सकती कि जो लोग विश्व सरकार का संचालन करेंगे वे उन लोगोंमें बहुत अधिक अच्छे होंगे जो आज संयुक्त राष्ट्र सभ अथवा राष्ट्रीय सरकारोंका संचालन कर रहे हैं। अपने वैयक्तिक, वर्णगत, जातीय, राष्ट्रीय अथवा आदर्शात्मक स्वार्थोंकी सिद्धिके लिए विश्व सरकारके सगठनके भीतर भी अपना घनिष्ठ गुट बना लेना उनके लिए बहुत सम्भव होगा।

“जैसा हमारा समार है और जो माघन हमें प्राप्त है उन्हीमें हमें काम करना होगा।”

विश्व सभमे मतदान स्पष्टतः विश्वकी जनसंख्याके आधार पर नहीं होगा। यदि जनसंख्याको ही आधार माना जाय तो संयुक्त राज्य अमेरिका को केवल ६ प्रतिशत ही वोट मिलेंगे। यदि आर्थिक उत्पादनशीलताको आधार माना जाय तो संमारके २० प्रतिशतमें भी कम जनसमाजको ७५ से ८० प्रतिशत तक वोट मिल जायगे और तब शेष समार इमे एक साम्राज्यवादी षडयंत्र मान सक्ता है। साक्षरता, राजनीतिक परिपक्वता और आर्थिक विकासके पक्षमें कुछ अधिक प्रतिनिधित्व (weighted representation) उचित मानलूम होना है। पर एक विश्व समारको भावनाके अभावमें इस प्रकारके विचारोंके पीछे स्वार्थपरताको छिपाया जा सक्ता है। विश्व समारकी प्रबल भावनाके अभावमें विश्व पुलिस दल अत्याचारी हो सक्ता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि लोकतन्त्रके कण्ठों पर चढ़ कर शक्ति पानेके बाद ही हिटलर ने लोकतन्त्रका विनाश किया था। भावी अत्याचारी अथवा असीमित अहंकार तथा महत्वाकांक्षावाले व्यक्ति ऊपर से दिखावे के तौर पर लोकतांत्रिक पद्धतियोंमें काम करते हुए भी एक विश्व सरकारके साथ बहो कर सकते हैं जो हिटलर ने लोकतन्त्रके साथ किया था।

विश्व सरकारके समर्थक बड़ी आसानीसे यह कल्पना कर लेते हैं कि यदि रूस और उसके अनुगामी राज्य अलग भी रहें तो भी शेष समार उनके साथ आ जायगा। पर आज भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि रूसी और आंग्ल-अमेरिकी गुटके अलावा ऐसी शक्तिशाली एक तीसरा गुट भी बन रहा है जिन्हें तटस्थ तथा मकोचशील और कभी-कभी अवसरवादी भी कहा जा सकता है। पूर्वी देशोंमें अनेक लोग इस बातको समझने और माननेमें असमर्थ हैं कि सभी नैतिक और राजनीतिक अच्छाईया वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय बादविवादके एक गुटमें हैं और सभी बुराईया दूसरे गुटमें। पूर्वके कुछ राष्ट्र जिन्हें साम्राज्यवादी षडयंत्रमें हालमें छुटकारा मिल गया है फिरसे अपनेको उस षडयंत्रमें भागनेके लिए उत्सुक नहीं हैं। हम के बिना विश्व सरकारको उन की आर्था भी सफलता नहीं मिल सकती जितनी संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना राष्ट्र संघ की मिली थी। रूस और तटस्थ राष्ट्रोंके बिना विश्व सरकार एक भारी-भरकम असफलता ही सिद्ध होगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ के आलोचकोंने उसे अरुण औचित्य सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। पीछेकी बार-बार उग्राइ कर यह देवना कि उसकी जड़ें जितनी कम घुरी हैं, उमको पनपने देनेका बहुत अच्छा तरीका नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार १६० वर्षोंमें अधिक पुरानी है। फिर भी बहाली मॉनटेने १९४९ तकमें नागरिक अधिकार योजनाके सम्बन्धमें अनिवार्यक बाधा डाली है। ऐसी हालतमें जो काम संयुक्त राज्य अमेरिका १०० वर्षोंमें नहीं कर सका उसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इनके कम वर्षोंमें पूरा विवे जाने की आशा कोई क्यों करे।

संयुक्त राष्ट्र-संघ के माध्यमसे विश्व-सरकार (World Government Via the United Nations)

इसो दीर्घकाले लिखते हुए क्लार्क एम० आइचेलबर्गर* (Clark M. Eichelberger) कहते हैं कि किसी न किसी हद तक विश्व सरकारकी आवश्यकता पर सभी लोग सहमत हैं। लोगोंमें मतभेद इस बात पर है कि विश्व सरकारकी स्थापना कब हो, उसका स्वरूप और उसकी अधिकार शक्ति क्या हो। संयुक्त राष्ट्र मध्य राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और मानव अधिकारोंकी गारण्टी देकर इस दिशामें बढम उठा चुका है। इसलिए आइचेलबर्गर की रायमें संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र पर पुनर्विचार करनेका अभी उपयुक्त समय नहीं है। उनके कुछ तर्क निम्नलिखित हैं:—

(१) किसी भी अच्छी सरकारके लिए यह जरूरी है कि वह सामान्य हितों और आवश्यकताओं पर आधारित हो। आज हमें संयुक्त राष्ट्र मध्य में विवादोंकी बढ़ती हुई एकता दिखाई देती है। यही विश्व सरकारका आरम्भ है। एशिया निवासी अधिष्ठे अधिक मध्यमें संयुक्त राष्ट्र संघ की परिपदोंमें आ रहे हैं जो विश्व समाज की स्थापनामें व्यावहारिक शिक्षा दे रही है। आइचेलबर्गर का विश्वास है कि ऐसे सम्बन्धोंसे जिनके परिणामस्वरूप पारस्परिक विश्वास और भरोसा पैदा हो सके, संयुक्त राष्ट्र मध्य क्रमशः एक विश्व सरकारके रूपमें विकसित हो सकता है। उन्हीं के शब्दों में "विश्व सरकारका उदय हो चुका है और संयुक्त राष्ट्रके माध्यमसे उस का विकास होता ही रहेगा क्योंकि लोग उसे विकसित करने के लिए उत्सुक हैं।"

(२) संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणापत्र (charter) लचीला है और हममें विकासकी गुंजाइश है। वह एक विकासशील आलेख है और इसलिए यह सम्भव है कि उसकी कुछ धाराओंकी उदार टीका की जाय जैसाकि सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयोंके सम्बन्धमें किया जाता है। सैनक्रान्तिस्को सम्मेलनके समय शायद ही कोई व्यक्ति अणुशक्तिकी बात जानता रहा हो फिर भी जब वह शक्ति एक तथ्य बन गयी तब उसके नियंत्रणकी भी व्यवस्था की गयी; यद्यपि रुस ने उसे स्वीकार नहीं किया है। इसी प्रकार बर्नाडेट (Bernadotte) की दुर्भाग्यपूर्ण हत्याके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासत्री को यह अधिकार दिया गया कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक रक्तक दण्ड रखे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बर्दी पहने और उसके झण्डे के नीचे चले। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई प्रतिनिधि किसी देशकी सीमाके भीतर उस देशकी सरकारकी असावधानीसे या उसकी गुप्त सहमतिसे मारा जाता है या पायल किया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उस देश पर क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक साम्प्रतिक अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस दल कायम

* *The Annals of the American Academy of Social and Political Sciences*, July, 1949.

कर सकता है। आम सभाकी मिफारिशोको अधिकाधिक अधिकार-शक्ति दी जा रही है और उसके प्रस्तावोंको अधिकाधिक अधिकार-भत्ता लगानेपर प्राप्त होती जा रही है। विवादों और संघर्षोंमें मध्यस्थता तथा समझौता करानेके लिए अधिकाधिक राष्ट्र सघीय प्रतिनिधि-मण्डल कायम किये जा रहे हैं। इन सब बातोंमें हमें आइर्वेल-बर्गेर की भांति विश्वास करना होता है कि विधायिका और कार्यपालिकाके साधनोंमें नहीं बल्कि प्रशामकीय माध्यमसे विश्व सरकारकी स्थापना हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र सघ की निरन्तर बढ़ती हुई नैतिक अधिकार सत्ताको कोरियाई युद्धके बादसे कुछ घक्का लगा है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद द्वारा २७ जून, १९५०, को उत्तरी कोरिया के सम्बन्धमें की गयी तात्कालिक कार्रवाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा कायम रखी है। फिर भी यह एक खेदजनक बात है कि उस शान्ति मूलक कार्यको बहुत कुछ उपेक्षाकी गयी है जो संयुक्त राष्ट्र सघ के धोरणापत्रके अनुसार सघका प्रधान उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र सघ की किसी राष्ट्र का या कुछ राष्ट्रोंके एक गुटका मुविषाजनक चिद्दीरसा बना देना उसे शक्तिशाली बनानेका तरीका नहीं है।

फिर भी जैसा कि आइर्वेलबर्गेर कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सघ दूसरा राष्ट्र सघ नहीं है। वह उत्तरोत्तर सम्प्रभु सम्प्रा बनती जा रही है। बहुत समय नहीं बीता जब कैलिफोर्निया में एक न्यायाधीशने यह फैसला दिया था कि संयुक्त राष्ट्र सघ के धोरणापत्रको और मानव अधिकार सम्बन्धी उनकी घोषणाको, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की मॉनेट ने स्वीकार कर लिया है; अमेरिकी राज्य विधि पर प्राथमिकता प्राप्त है। यदि इस निर्णयको उच्चतर न्यायालय स्वीकार कर ले तो सम्प्रभुता सम्बन्धी परम्परागत धारणाओंमें बहुत बड़ा मनोपन हो जायगा।

यह दुबारा जोर देकर कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सघ के धोरणा पत्र में बुद्धि और विकासकी पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। यह विश्व सरकारका श्रीगणेश है। बुद्धिमानों इस बातमें हैं कि संयुक्त राष्ट्र सघ को कुछ इस ङगमें चलाया जाय कि सघकी अन्तिम स्थिति विश्व सरकारकी प्रारम्भिक स्थिति हो। अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघ ही अन्तमें विश्व सरकार बन जावे। हमारे कहनेका मतलब यह नहीं है कि हम विश्व सरकारका निर्माण अगले कालके लिए स्थगित करना चाहते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि जितनी शीघ्र विश्व सरकारकी स्थापना हो सके उतना ही अच्छा है। हमारे कहनेका मतलब केवल इतना है कि केवल भावुकता और मार्क्सवादीक परि-
वर्तनोंमें ही नये युग का आरम्भ नहीं हो जायगा। विश्व सरकार तो तब तक नहीं हो सकेगी जब संसारके मनुष्योंमें एक विश्व गमात्रके प्रति प्रबल निष्ठा उत्पन्न होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले मनुष्योंके चिन्तनमें गहरा नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन हो तब विश्व सरकार बन सकती है। यदि पहले न हो तो छाप ही माप होना तो लाजमी है। विश्व सघवादी एक सरल मार्ग सोचते हैं। आइर्वेलबर्गेर के अनुसार, यदि उन्हें अपने प्रयत्नोंकी मरुत बनाना है तो उन्हें अपनेको पलायनवादिना

(escapism) से बचना चाहिए। वे जड़ोंकी उपेक्षा कर, फलोंकी कामना करना मियाते हैं। दूसरी ओर सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्प्रभुताकी धारणाको दूर कर उन्होंने एक महान् कार्य किया है। उन्हें तथा अन्य लोगोंको दूसरा कदम यह उठाना है कि विश्व समाजको साम्यबिक्रानावा रूप दें और मनुष्यन लोगोंका विश्वास प्राप्त करनेके लिए अपने-अपने देशके मद्भाग्यों को मिट्ट करे। मन्त्रिधान द्वारा समाजकी रक्षा नहीं की जा सकती। समाजकी रक्षा ऐसे स्त्री और पुरुषों द्वारा हो सकती है जो मनुष्यों मनुष्य जाति के प्रति उत्कट निष्ठा रखते हों और अपनी सरकारों पर इस बातका दबाव डाल सकते हों कि वह अपने सभी नागरिकोंके साथ समान व्यवहार करे और परमात्माकी निम्नतम सृष्टिके प्रति भी अपनी जिम्मेदारियोंको पूरा करें।

SELECT READINGS

- BENTWICH, N., AND MARTIN, A.—*A Commentary on the Charter of the United Nations.*
 CHASE, E. P.—*The United Nations in Action.*
 EAGLTON, C.—*International Government.*
 EVATT, H. V.—*The United Nations.*
 EVERYMAN'S UNITED NATIONS.
 GOODRICH, L. M., AND HAMBRO, E.—*Charter of the United Nations.*
 HALL, H. D.—*Mandates, Dependancies, and Trusteeships.*
 HASLUCK, P.—*The Workshop of Security.*
 LEONARD, HARRY—*International Organization.*
 MANDERS, F.—*Foundation of Modern World Society.*
 MEYER, CORD—*Peace or Anarchy.*
 RFEVES, EMERY—*The Anatomy of Peace.*
 SCHWARZENBERGER, GEORG—*Power Politics.*
 UNITED NATIONS—*Handbook of the United Nations and Specialised Agencies.*
 UNITED NATIONS—*Yearbook of the United Nations.*
 UNITED NATIONS—*These Rights and Freedoms.*

PERIODICALS

- India Quarterly.*
International Organization.
Documents of International Organization:
United Nations Bulletin.

Foreign Affairs.
Foreign Policy Reports.
Headline Series.
International Conciliation.
World Politics.
International Affairs.
World Report.

समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराका विकास

(The Evolution of Socialistic and Communist Thought)

“औद्योगिक समाजका जो विस्फेपण भाक्स ने किया है, उसमें हम सहमत हो या न हो, यह तो रहा हो जा सकता है कि भाक्स का अध्ययन—जैसे अध्ययनके वे अधिकारी हैं—तब तक नहीं हो सकता जब तक यह न स्वीकार कर लिया जाय कि शायद रिवाइजोंको छोड़ कर, अर्थ-विज्ञानके समूचे इतिहासमें, भाक्स से बड़ कर मौलिक दायित्वमान और तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ।” प्रो० ई० आर० ए० सेलिंगमैन अपनी पुस्तक “इकोनॉमिक इण्टरप्रेटेशन आफ हिस्ट्री” (इतिहासकी आर्थिक व्याख्या) में, पृष्ठ, ५९।

आधुनिक समाजवाद और साम्यवाद दोनों की उत्पत्ति एक ही मूल श्रोत काल मार्क्स (Karl Marx) से हुई है। मार्क्स १८१८ से १८८३ तक जीवित रहे। उन के माता-पिता यहूदी विधि-शास्त्रियों (Jewish rabbis) के बराबर थे। सामाजिक न्यायकी प्रबल इच्छाके लिए यहूदी हमेशा से प्रसिद्ध हैं। मार्क्स के पिता प्रोटेस्टेंट इसाई हो गये थे। मार्क्स बुरे दिन देख चुके थे और लगता है कि इन बुरे दिनोंका सामाजिक प्रश्नमें सम्बन्धित उनके विचारों पर गहरा असर पड़ा। जीवनके आरम्भ ही में उनमें और एंगेल्स (Engels) में मित्रता हो गयी थी। इस मित्रता के कारण दोनोंने राजनीतिक क्षेत्रमें तथा अनुसन्धान एवं पुस्तकें लिखनेमें मिल कर काम किया। अपने क्रांतिकारी कार्योंके कारण मार्क्स को अपने जीवन के अनेक वर्ष एक राजनीतिक निर्वासीके रूपमें जर्मनी, हार्लैण्ड और फ्रान्स से बाहर बिताने पड़े। उनका बहुत-सा समय लन्दन में ब्रिटिश सप्रहालयमें बीता। अपने जीवन-कालमें वे योरोपीय मजदूर आन्दोलनोंके सर्वमान्य नेता माने जाते थे। आज भी वह आधुनिक समाजवादके पिता माने जाते हैं। उन्होंने एंगेल्स के साथ सन् १८४८ में कम्युनिस्ट पार्टीका घोषणापत्र प्रकाशित किया। उनका महान् ऐतिहासिक ग्रन्थ “डायलैक्टिक्स” १८६७ में प्रकाशित हुआ था।

हीगेल और फ्योर्बाख (Hegel and Feurbach) (१८०४-७२) का मार्क्स की विचारधारा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मार्क्स ने हीगेल से द्वन्द्ववाद (dialectic) की धारणा ली। द्वन्द्ववाद का अर्थ है कि दो विरोधी तत्वोंकी अन्त-क्रियाके परिणामस्वरूप प्रगति होती है। हीगेल के अनुसार इतिहास द्वन्द्वात्मक मार्ग से अपने पूर्व निश्चित लक्ष्यकी ओर बढ़ता है। हीगेल ने द्वन्द्ववाद की शिक्षा विचारों के क्षेत्रमें दी थी, पर मार्क्स ने उसका उपयोग कार्य-क्षेत्र में किया। हीगेल ने द्वन्द्वात्मक

आदर्शवादकी शिक्षा दी पर मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादकी शिक्षा दी। इस विभेद पर लिखते हुए मार्क्स ने दावा किया कि वह हीगेल को सीधा खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना था कि "हीगेल ने द्वन्द्ववाद को सरके बल खड़ा कर रखा है। उसे सीधा खड़ा किया जाना जरूरी है।" हीगेल विचारोंके विकासको सबसे अधिक महत्त्व देते हैं। पर मार्क्स पदार्थको प्रधान मानते हैं। आत्मा, विचार और चेतना तो गौण हैं और पदार्थके ही परिणाम (derivative) हैं। समाजका भौतिक जीवन ही उसके आध्यात्मिक जीवनका विधाता है।

द्वन्द्ववादकी अत्यधिक काल्पनिक धारणाको मनुष्यके आर्थिक जीवनमें प्रयुक्त कर के मार्क्स ने बताया कि मनुष्य के आर्थिक विकासकी प्रारम्भिक अवस्था आदिम साम्यवादकी अवस्था थी। बादमें इस अवस्थाका सर्वथ सामन्तवाद (feudalism) और पूँजीवादसे हुआ और इन दोनोंकी अन्तर्क्रियासे वैज्ञानिक साम्यवादका उदय हो रहा है।

प्योरबाख से मार्क्स ने सीखा कि परमात्मा मनुष्य को नहीं बल्कि मनुष्य परमात्मा को बनाता है। उनके अनुसार "मनुष्य धर्म को बनाता है—धर्म मनुष्य को नहीं बनाता।" उनका कहना था कि धर्म "जनताके लिए अफीम है" और ये शब्द सारे सत्सारमें बड़े प्रसिद्ध हो गये हैं। मार्क्स के अनुसार ईश्वर केवल मनुष्यके दिमाग में रहता है।

इन विचारधाराकी व्याख्या करते हुए हैलोवेल (Hallowell) लिखते हैं कि मार्क्स के विचारमें इतिहास, आत्मा और पदार्थका मध्यम नहीं है, यह परमात्मा की खोज नहीं है। इतिहास "अपने उद्देश्योंकी निधिमें लगे हुए मनुष्यके कार्य-कलाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।"

समूहवाद (Collectivism) सामाजिक विज्ञानोंके विश्व कोश (Encyclopaedia) के अनुसार समूहवाद व्यक्तिवाद (Individualism) के विरोधी सिद्धान्तोंका सामान्य नाम है। समूहवाद शब्दका उपयोग भौतिक तौर पर सामाजिक प्रगतिकी प्रवृत्ति, आर्थिक सुधारोंका कार्यक्रम, मार्क्सवादी कम्युनिज्मके सिद्धान्त और एक आदर्श मानव व्यवस्थाके लिए होता है। प्राविधिक तौर पर इस शब्दका उपयोग समाजवाद (socialism), साम्यवाद (communism), श्रमिक मध्यवाद (syndicalism) और बोल्शेविकवाद (Bolshevism) आदि अपिचारिक नियंत्रणकी व्यापक योजनाओंके लिए होता है। इस शब्दका उपयोग खासकर उन प्रवृत्तियोंके लिए होता है जो १९वीं शतीकी 'अत्यधिक अहस्तक्षेप की नीति' (laissez faire) के विपरीत हैं।

वाल्टर हैमिल्टन (Walter Hamilton) के अनुसार, जिनके वाक्य ऊपर उद्धृत किये गये हैं, व्यक्तिवाद भी एक प्रकारका समूहवाद है, क्योंकि यह भी सामान्य कम्युनिज्मकी उपनिमित्त विन्यास करता है पर इसका तरीका भिन्न होता है। व्यक्तिवाद का विश्वास है कि प्रबुद्ध आत्महित (enlightened self-interest) से ही अधिकतर जन-व्यवस्था हो सकता है।

हो जाते हैं और बादमें एकाधिकार पूँजी (monopoly capital) और वित्त पूँजी (finance capital) का बोलबाला हो जाता है। यह स्थिति पूँजीवादकी चरम सीमा है और यहीसे पूँजीवाद का तेजीमें पतन होने लगता है।

(३) अतिरेक मूल्यका सिद्धान्त (The Doctrine of Surplus Value). मार्क्स ने उपयोगिता मूल्य (value in use) और विनिमय मूल्य (value in exchange) के बीच अन्तर किया है। उपयोगिता मूल्य मानव आवश्यकताओंकी पूर्तिमें है। विनिमय मूल्य इस बातमें है कि उस वस्तुके बदलेमें क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य किये गये श्रममें ही निश्चित होता है। मार्क्स ने पूँजी की परिभाषा इस प्रकारकी है—“अतिरेक मूल्य (surplus value) की प्राप्तिके लिए काम में लाये गये उत्पादनके सभी निजी स्वामित्वके साधनोंका योग पूँजी है (Capital is the sum total of all the privately owned means of production employed for the acquisition of surplus value)। श्रमिकोंका शोषण ही पूँजीका सार है। पूँजीपति श्रमजीवियोंको केवल निर्वाहके लिए मजदूरी दे कर उनसे इतना श्रम करवाते हैं कि उसके द्वारा उत्पन्न वस्तुओंका बाजार मूल्य उनकी मजदूरीसे अधिक होता है। इस अतिरेक मूल्यको पूँजीपति हड़प कर लेते हैं। पूँजीपति लाभ, किराया और व्याजके रूपमें अतिरेक मूल्यको साराका सारा स्वयं ले लेते हैं और उसका उपयोग और अधिक अतिरेक मूल्य प्राप्त करने के लिए उत्पादन बढ़ा कर तथा अधिक मजदूरोंको काममें लगा कर करते हैं।

अतिरेक मूल्यकी परिभाषा इस प्रकारकी गयी है: जितना मूल्य श्रमिकोंके निर्वाहके लिए आवश्यक है उसके अतिरिक्त जो मूल्य उन्होंने उत्पादित किया वह अतिरेक मूल्य है। (इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। मजदूर अपने निर्वाह भर की मजदूरी पाकर कुछ वस्तुएं बनाता है। इन वस्तुओंका बाजार मूल्य मजदूर को मिलने वाली मजदूरीके मूल्यसे अधिक होता है। बाजार मूल्य और मजदूरी मूल्य का अन्तर अतिरेक मूल्य है। उदाहरणके तौर पर मान लीजिए कि मजदूरको एक महीनेमें ६० रुपये मिलते हैं। वह महीने भरमें जो वस्तुएं बनाता है वे ९० रुपयेमें बिकती हैं। इस हालतमें ३० रुपये अतिरेक मूल्य हुआ। पूँजीपतियों द्वारा उसका हड़प लिया जाना एक प्रकारकी चोरी है।

मार्क्स ने ‘मजदूरी का कठोर नियम’ (the iron law of wages) वाक्य का भी उपयोग किया है। इस का आशय यह है कि मजदूरको अपने कामके बदले में बस इतना दे दिया जाता है कि उसके प्राण पखेरू उड़ न जाय और गुजर चलानेके लिए उसे दूसरे दिन काम पर आना ही पड़े। इससे अधिक जो कुछ कमाया जाता है वह मालिककी जेबमें चला जाता है।

मार्क्स का कहना है कि पूँजीवादके परिणामस्वरूप आवश्यकतासे अधिक पूँजी व माल पैदा हो जाते हैं। श्रमिक वर्गकी थोड़ी आय होनेके कारण उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, इसलिए देशके बाजारोंमें मालकी बिक्री कम हो जाती

है। फलतः विदेशोंमें बाजार दूढ़े जाते हैं और इसका परिणाम साम्यवाद और युद्ध होता है।

(४) वर्ग युद्ध. मार्क्स का विश्वास था कि दिन प्रतिदिन धनी लोग अधिकाधिक धनी और गरीब लोग अधिकाधिक गरीब होते जा रहे हैं। अन्तमें एक ऐसा समय आयेगा कि गरीब लोग, जिनका समाजमें अत्यधिक बहुमत है, धनी लोगोंको हरा कर एक नये समाजकी स्थापना करेंगे। मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग (भूमिहीन, संपत्तिहीन वर्ग) की वर्ग-चेतना पर और मध्यम वर्गके लोप हो जाने पर अधिक जोर दिया था। उनका विश्वास था कि सर्वहारा वर्ग अधिकाधिक सघनशूल होता जायगा जिसके परिणामस्वरूप एक अन्तिम क्रान्ति होगी। क्रान्ति के कारण पूँजीपति समाप्त हो जायेंगे और वर्ग-विहीन समाज की स्थापना होगी। स्वयं मार्क्स के ही मवल शब्दों में "पूँजीवादी उत्पादन (capitalist production), प्रकृति के अजेय नियम के अनुसार स्वयं ही अपने विनाशका कारण बनता है। मार्क्स ने यह भी कहा था कि "अब तकके सभी समाजोंका इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है।"

अन्तिम लक्ष्य है ऐसी क्रान्ति जिसमें पूरे तौरमें मध्यम वर्ग सर्वहारा वर्ग में लीन हो जाय और सर्वहारा वर्ग राजनीतिक शक्ति हासिल कर ले। कम्युनिस्ट घोषणापत्रके अन्तिम शब्द, जिनमें वक्तृता (oratory) का सा ओज है, महत्वपूर्ण हैं: 'साम्यवादी अपने विचारों व लक्ष्योंको छिपानेसे घृणा करते हैं। वे खुले आम घोषणा करते हैं कि वर्तमान सामाजिक ढाँचेको बलान् हटा कर ही उनके उद्देश्यों की निधि हो सकती है। सामक वर्ग साम्यवादी क्रान्तिसे कापता है, तो बापे, सर्वहारा वर्गको अपनी जजींदीके अलावा और क्या खोना है? और पाना है सारा ससार। दुनिया भरके मजदूरों—एक हो जाओ।" अपने जीवन के बादके वर्षोंमें मार्क्स ने यह स्वीकार कर लिया था कि ब्रिटेन, अमेरिका और हॉलैण्ड के मजदूर शान्तिमय तरीकेसे भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पर उनका विश्वास था कि सामान्यतः बल से ही काम चलेगा। उनके ही शब्दोंमें: "बल एक नये समाजको जनने वाले प्रत्येक पुराने समाजकी दाई है।"

(५) सर्वहारा वर्गका अधिनायकत्व (Dictatorship of the proletariat). मार्क्स और एंगेल्स दोनोंका विश्वास है कि पूँजीवादी समाजको बलान् नष्ट कर देनेके बाद वर्गविहीन समाजकी स्थापना करनेमें कुछ समय लग जायगा। उस मर्यादित कालमें हैन्सोवेल द्वारा दी गयी स्थिति के अनुसार साम्यवादका निम्न-लिखित कार्यक्रम होगा:

(१) हर प्रकारकी जमींदारीका, उन्मुक्त और भूमिसे प्राप्त होने वाले सामान्य राजस्वका मार्गदर्शक सामक बापों पर खर्चे किया जाना;

(२) आपके साथ तेजीसे बढ़ने वाला आय कर;

(३) सब प्रकारके उत्तराधिकारकी समाप्ति;

(४) देश छोड़ कर अन्य देशोंमें बगने वालोंकी और विद्रोहियोंकी सम्पत्ति की जर्नी,

(५) संचार (communication) और परिवहन (transport) के साधनों का राज्यके हाथोंमें केन्द्रीकरण,

(६) राज्य-स्वामित्व वाले कारखानों और उत्पादनके साधनोंका विस्तार; एक सामान्य योजनाके अनुसार बज्रर भूमिकों खेतीके योग्य बनाना और जमीन को अधिक उपजाऊ बनानेका उपाय करना,

(७) काम करनेका सब पर एकमा दायित्व;

(८) खेती और उद्योगका उचित समायोजन और नगरों तथा गांवों में आबादी का अधिक न्यायपूर्ण वितरण;

(९) निःशुल्क मार्शजनिन स्कूलों सिखा और बच्चोंमें मजदूरी कराने पर रोक।

सक्रान्ति कालमें मजदूरोंको, कामके अनुसार वेतन दिया जायगा। दूसरे शब्दोंमें कार्य-कौशलके अन्तरके अनुसार वेतनमें अन्तर होगा। इसका मतलब शोषण इसलिए नहीं होगा क्योंकि नये समाजमें उत्पादनके साधन व्यक्तियोंके हाथमें न हो कर राज्यके हाथोंमें रहेंगे। अन्तिम रूपसे प्राप्त किया जाने वाला आदर्श है "प्रत्येकमें उसको सामर्थ्यके अनुसार (काम) और प्रत्येकको उसकी आवश्यकताके अनुसार (दाम)।"

(६) परिवार, धर्म आदिका लोप. वैयक्तिक परिवार और वैयक्तिक सम्पत्ति दोनोंका उदय साथ-साथ हुआ था। दोनोंका लोप भी साथ-साथ होगा। अवश्यम्भावी है। भविष्यमें विवाहका एकमात्र आधार 'पारस्परिक प्रेम' होगा। विवाहका कोई नैतिक, धार्मिक अथवा आर्थिक महत्व न होगा। परिवारके लुप्त होनेके साथ ही धर्म भी लुप्त हो जायगा। समाजवादी राज्यमें "धर्मकी स्वामयिक मृत्यु हो जाती है।" जो कुछ भी नैतिकता होगी वह विशिष्ट आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर एक आपेक्षिक नैतिकता होगी। परम नैतिकता या स्वतः सिद्ध नैतिकता जैसी कोई चीज न होगी। मध्य वर्गीय नैतिकताके स्थान पर सर्वहारा वर्गकी नैतिकता प्रतिष्ठित होगी। ऐसी विधि (law) जिसका आधार चिन्तनमात्र है, अर्थात् जो कठोर सन्या पर आधारित न होकर विचारों पर आधारित है, समाप्त हो जायगी।

(७) राज्यका श्रमिक लोप (The withering away of the State). साम्यवादके अन्तर्गत राज्य धीरे-धीरे लुप्त हो जायगा क्योंकि यह आरम्भसे ही "एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर दबाव डालनेका साधन रहा है।" एंजेल्स के शब्दोंमें "राज्य समाजके विकासकी एक विशिष्ट स्थितिकी उपज है। उस विशिष्ट स्थितिमें राज्य की आवश्यकता थी इसलिए उसका निर्माण हुआ।" एक पूर्ण, वर्गविहीन समाजकी स्थापना हो जानेके पश्चात् राज्यकी आवश्यकता नहीं रह जाती और वह समाप्त

हो जावेगा। राज्य का उन्मूलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं मर जाता है। इसका स्थान एक ऐसा प्रशासकीय उपकरण ले लेता है जो उत्पादनके साधनोंका नियंत्रण और उनकी व्यवस्था करता है।

(८) वैज्ञानिक समाजवाद: जब यह होता है तब टॉमस मोर (Thomas More), ओवेन (Owen), फोरियर (Fourier) और सेंट गाइमन (Saint Simon) महोदयोंके एक आदर्शवादी और वस्तुनामूलक समाजवादके बजाय एक वैज्ञानिक समाजवाद प्रतिष्ठित होता है। इस नये समाजमें शोषण समाप्त हो जाता है और हरेकको आवश्यकताएं पूरी होती हैं। मनुष्य पहली बार अपने भाग्य का स्वयं विधाता बनता है। क्रिस्टोफर डॉयसन (Christopher Dawson) ने इस सबको धार्मिक प्रतिवन्दों से मुक्त राम-राज्यका उदय ठीक ही बतलाया है (a secularisation of the coming of the Messianic Kingdom)।

माक्सवादीकी आलोचना:

(१) यह मानना गलत है कि मनुष्यके जीवनमें या इतिहासमें आर्थिक तत्त्व ही एकमात्र तत्त्व है। मनुष्य शारीरिक जीव-समूहना मात्र नहीं है। वह एक आध्यात्मिक प्राणी भी है। इसी बातको हम दूसरे शब्दोंमें इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य मुक्त जैसा ही नहीं है। स्पष्टकी बदल कर हम कह सकते हैं कि वह "मिट्टी और आगवा एक अद्भुत पुनरा है।" जो नहीं है उसे प्राप्त करनेकी उसमें बड़ी लालसा रहती है। मार्क्स ने ऊंचे लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए स्वयं गरीबी सहनकी थी जैसा कि ह्यूजेल्स ने कहा है, मार्क्सवादकी भौतिक सम्भावना नहीं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक सम्भावना मजदूरकी अपनी और आकर्षित करती है। इसलिए इतिहास को केवल आर्थिक ध्याख्या करना मनुष्यको आवश्यकतासे अधिक सरल बनाना है। यह ध्याख्या मनुष्य जीवनके सब पहलुओं पर विचार नहीं करती है। यह कुछ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्योंकी विवेक कर उपेक्षा करती है। मनुष्य केवल सम्पत्ति प्राप्तिकी भावनासे ही काम नहीं करना बल्कि अहंकार, प्रतिद्वन्द्विता अधिकार के लोभ, सत्ताजन्य आनन्द और सफलताकी भावनासे भी काम करता है।

ह्यूजेल्स की यह दलील सही है कि आर्थिक आवश्यकताएं तो कभी पूरी ही नहीं की जा सकती। केवल मनुष्यके साथ ही हमारी आवश्यकताओं की समाप्ति होती है। जितना ही अधिक हम प्राप्त करते हैं, हमारी आवश्यकताएं उतनी ही अधिक बढ़ती जाती हैं। इसका उत्तम उदाहरण ईश्वरकी कृपा ही है न कि प्रतिद्वन्द्विता या ऐतिहासिक प्रक्रिया। ह्यूजेल्स ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि महान् वैज्ञानिक आविष्कार साधन ही कभी आर्थिक चक्रको से प्रेरित हुए हों। जिनकी भी सोचमें सन्तुष्टि-प्रतिष्ठा है, वह अर्थ-शास्त्रमें उतनी ही दूर हैं जितना अर्थ-शास्त्रमें विज्ञान दूर है।

(२) नैतिक आचरणके शाश्वत (eternal) और मार्गभूमि (universal) सिद्धान्तों से इनकार कर भावसर्ववाद बहुत बड़ी भूल करता है। नैतिक निर्णय तो आपेक्षिक होते हैं पर नैतिक सिद्धान्त निरपेक्ष हैं। दूसरे शब्दोंमें सिद्धान्त शाश्वत हैं पर आदेश (precepts) अस्थायी। यह सब कुछ मार्क्स की दृष्टि में बाहर मान्य होता है।

(३) मार्क्सवाद अत्यधिक सूक्ष्म (abstract) और सैद्धान्तिक (doctrinaire) है। इसमें बहुत थोड़े माध्यमके आधार पर जल्दबाजीमें सामान्य सिद्धान्त बना दिये गये हैं। मार्क्स की अनेक भविष्यवाणिया सही नहीं मान्यित हुई हैं, जैसे कि यह भविष्यवाणी कि गरीब लोग और अधिक गरीब होने जायेंगे। बात यह है कि शक्तिका स्वभाव ही यह है कि जो उसे प्राप्त कर लेता है, वह उसे बढानेवा और अधिकने अधिक समय तक बनाये रखनेकी यथामुम्भव कोशिश करता है। उस शक्तिको हम सर्वहाराका दामन बहें या कुछ और। उस शक्तिको अच्छा नाम देने का प्रयत्न करे तो क्या होगा? मार्क्सवाद सर्वहारा वर्गको बह्युत्पन्न देता है और उसका परिणाम मतान्वयता तथा निर्दयता हो जाना है। मार्क्सवाद मनुष्यकी सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दृष्टावलीमें करनेकी कोशिश करता है। मार्क्सवाद भविष्य के मुनहरे स्वप्न दिखाते समय यह भूल जाता है कि मानव स्वभावमें कुछ कमजोरियाँ भी हैं।

(४) मार्क्सवादकी यह कल्पना गलत है कि "राज्य अपने आप धीरे-धीरे समाप्त हो जायगा।" वास्तविकता तो यह है कि आजकल कम्युनिस्ट देशोंमें राज्य की शक्ति और अधिकार दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। राज्य मनुष्यका शत्रु नहीं है। वह उसका सबसे अच्छा मित्र है। साम्यवादी अगले दरवाजेसे राज्यको बाहर निकालता है और पिछले दरवाजेसे उसे किसी अन्य रूपमें वापस ले आता है।

(५) मार्क्सवाद वर्ग-युद्धको अनावश्यक महत्व दे कर चलती करता है। ईसा मसीह का यह कहना सही था कि "आप एक सैतानीकी सहायतामें दूसरी सैतानी दूर नहीं कर सकते।" प्रेमसे प्रेम और घृणा से घृणा पैदा होती है। सपपंके द्वारा और विरोधी दलोंका विनाश करके बनाया गया वर्गविहीन समाज इस योग्य नहीं है कि उसके लिए इतना कष्ट उठाया जाय। यदि केवल पार्श्विक बल ही से ऐसे समाजकी स्थापना कर भी दी जाय, तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा। ऐसे लोगोंका प्रत्येक समाजमें चौड़ी पर पहुँचना अनिवार्य है, जिन में पोषण, महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य हैं। ऐसे लोगोंको अपनी शक्तियोंका उपयोग आत्मतोषके लिए करने देनेके बजाय उन्हें सामाजिक उद्देश्योंको सिद्धिमें लगा देना चाहिए।

(६) मार्क्स की यह भविष्यवाणी सही नहीं मान्यित हुई कि जर्मनी और ब्रिटेन जैसे अत्यधिक औद्योगिक देशोंमें औद्योगिक क्रान्ति पहले होगी। यह क्रान्ति तो पिछड़े हुए जारजाही रूस में हुई।

(७) मार्क्सवाद राष्ट्रीयता और जातीयता की शक्तियों पर विचार नहीं करता। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों ने अन्तिम रूपसे सिद्ध कर दिया है कि युद्धों को, जो कि मूल्यतया पूँजीपति वर्ग अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए लड़ते हैं, न होने देने के लिए सारे संसार के मजदूर एक नहीं हो जाते। यही नहीं मजदूर अपने-अपने देश की सरकार का साथ देते हैं और सभी देशों के मजदूरों पर अकथनीय मुसीबतें लाते हैं। साम्यवादी देशों में भी जातीयता का एकदम अभाव नहीं है।

(८) यद्यपि मार्क्सवाद धर्म पर निंद्यतापूर्वक प्रहार करता है पर वह स्वयं मनुष्यवा एक प्रतिपक्षी धर्म बन गया है। हैलोवेल लिखते हैं : "मार्क्सवाद सिद्धान्ततः 'धर्म' को अस्वीकार करता है पर व्यवहारतः जो तीव्र भावना मार्क्सवाद के पीछे काम करती है, उसकी प्रकृति भी धार्मिक ही है।" इन्हीं लेखक के शब्दों में "मार्क्सवाद मानव पाप की समस्या के गहन विश्लेषण का शिकार हो गया है। मार्क्स ने ईश्वर के स्थान पर ऐतिहासिक आवश्यकता की, ईश्वर के प्रिय लोगों के स्थान पर सर्वहारा वर्ग की और रामराज्य के स्थान पर स्वाधीनता के राज्य की स्थापना की। मार्क्सवाद के अपने सिद्धान्त हैं, अपने पुरोहित वर्ग और अपने कर्मकाण्ड हैं, तथा अपने पापमोचक अनुष्ठान हैं। मार्क्सवाद भ्रष्ट आदर्शवाद है।"

(९) अन्य सभी धार्मिक सिद्धान्तों की भाँति मार्क्सवाद भी अपनी मान्यताओं में दृढ़ और अपने सङ्गनों में शिथिल है (Marxism is strong in what it asserts and weak in what it denies)।

(१०) लास्की लिखते हैं कि साम्यवाद एक ऐसा मत है कि जिसमें बौद्धिक भूल, नैतिक अन्वेषण और सामाजिक विषयन (perversity) है।

साम्यवाद का आकर्षण (Appeal of Communism). अपनी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक असफलताओं के बावजूद साम्यवाद अधिकाधिक लोगों को लुभाता जा रहा है। हैलोवेल लिखते हैं, "हम मार्क्सवाद के कार्यक्रम को अस्वीकार कर सकते हैं पर इसने पूँजीवाद के विरुद्ध जो अभियोग लगाये हैं, उनकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं (पृ० ४४६)।"

आर० बी० ग्रेग, जो किसी प्रकार भी साम्यवादी नहीं है, अपनी पुस्तक *Which Way Lies Hope* में लिखते हैं कि साम्यवाद सामाजिक न्याय की भावना में ओन-ओन लोगों को लुभाता है। एक भावनामय मनुष्य दुर्लभ और गरीब लोगों को कष्ट पहुँचा कर भुविपाए और आराम भोगने पर मन हो मन करने को अपराधी अनुभव करता है। ग्रेग के अनुसार साम्यवाद आकर्षण के कुछ अन्य कारण निम्नलिखित हैं :

(१) साम्यवाद लोगों को पूँजीवाद द्वारा दिये गये अत्याचारों की स्पष्ट और खोरदार अनुभूति कराता है और इन बुराइयों के मुकाबले में अपनी ओर से वह न्याय का दावा करता है।

(२) इतिहास की साम्यवादी व्याख्या (इन्डुस्ट्रियल और वैज्ञानिक भौतिकवाद) मनुष्य को वैज्ञानिक यथाशक्ती, मनुष्य और सहोपन की भावना देती है। यह उम्मी

प्रकारका विश्वास है जैसे रोमन कैथोलिक चर्च अपने धर्मके अधिकतर अनुयायियोंमें पैदा करता है।

(३) साम्यवादी सिद्धान्त लोगोंमें यह ब्याल पैदा करता है, कि उन्हें वास्तविकताका, मनुष्यका और सत्तारमें जो कुछ हो चुका है और हो रहा है उस सब का सही बोध हो रहा है। साम्यवादी सिद्धान्त मानो इतिहासके रहस्य खोलनेकी कुञ्जी हो।

(४) साम्यवाद पुरानी बातोंके विरुद्ध विद्रोह करता है और मनुष्यको नये प्रयोगों के आह्लाद (thrill) का अवसर देता है।

(५) यह व्यक्तिके सामने निम्नलिखित मोहक विचार रखता है :

(क) व्यक्तिकी अपेक्षा समाज अधिक महत्वपूर्ण है;

(ख) साधन (means) की अपेक्षा साध्य या लक्ष्य (end) अधिक महत्वपूर्ण है; और

(ग) विचारोंकी अपेक्षा वातावरण अधिक महत्वपूर्ण है।

(६) साम्यवादी दलमें शामिल होनेसे व्यक्तिमें यह भावना पैदा हो जाती है कि वह सबसे महान् लक्ष्यकी प्राप्तिके प्रयत्नमें हाथ बटाने जा रहा है। साम्यवाद घोर परिश्रम करनेका आह्वान करता है और हिम्मत, सहनशक्ति और बहादुरीकी मांग करता है। यह सबके लिए एक-सा अनुशासन, व्यवस्था और आत्मसंहति (self-integration) की भावना पैदा करता है। साम्यवादी दलमें शामिल होने वाले व्यक्तिको वह सन्तोष व आनन्द प्राप्त होता है जो एक महान् उद्देश्यके लिए अपने आपको अर्पित कर देने से होता है। साम्यवादियोंका दावा है कि पूंजीवादी व्यवस्थामें व्यक्तिके व्यवहारमें विविधताएँ सम्भव हैं, पर वह निरर्थक और दिखावटी हैं। साम्यवाद इन बेकार विविधताओंको भौका नहीं देता।

इन सब प्रलोभनोंके बावजूद यह कहना पड़ेगा कि साम्यवादकी विचार-प्रणाली गलत है और वह अपने इरादोंकी पूरा करनेके लिए अनुचित तरीकोंका उपयोग करने की चेष्टा करता है।

मार्क्स के निधनके बाद समाजवाद.

मार्क्स के निधनके बाद उनके अनुयायियोंकी दो शाखाएँ हो गयी—एक विकासवादी और दूसरी कान्तिवादी। विकासवादियोंका प्रतिनिधित्व जर्मनी और योरोप में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टिने किया जिसमें मार्क्सवादकी जैसी ताकत और ओज न था। जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टिका कार्यक्रम नरम था। हैलोवेल के अनुसार उनके कार्यक्रमकी मुख्य बातें ये थी :

(१) सबको, सीधा (direct) और समान मताधिकार,

(२) जनसंख्याके अनुपातसे प्रतिनिधित्व,

- (३) लोक निर्देश (referendum) और लोकनिर्देश (initiative) के जरिए जनता द्वारा सीधे विधि निर्माण,
- (४) स्थायी सेनाके स्थान पर नागरिक सेना (militia),
- (५) लोक-निर्देश प्राप्त करनेके बाद ही युद्धकी घोषणा,
- (६) धार्मिक कार्योंके लिए मार्क्सवादी कोषोंके उपयोगकी प्रथाका अन्त,
- (७) शिवालयोंको धर्म-निरपेक्ष बनाना,
- (८) न्यायाधीशोंका जनता द्वारा चुनाव और वकीलकी निशुल्क प्राप्ति,
- (९) मृत्यु-दण्डका अन्त,
- (१०) निशुल्क विविधता,
- (११) क्रमिक आय-कर (progressive income-tax),
- (१२) आठ घण्टे काम (प्रति कामके दिन),
- (१३) छतमें काम लेने और बच्चोंमें काम देनेका निषेध और प्रत्येक नागरिकके जीवनका बीमा।

यह नरम कार्यक्रम मई १९२५ के बाद और भी नरम हो गया।

कार्ल काउत्स्की (Karl Kautsky) (१८५४-१९३८). कार्ल काउत्स्की प्रथम विश्व-युद्धके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीके मुख्य प्रवक्ता थे। वह लेनिन और स्त्री कान्तिके विरोधी थे। वह मानते थे कि मार्क्सवादकी सिद्धांत-टीका है। उनका विश्वास था कि समाजवादी लक्ष्यकी सिद्धिके लिए अन्तिम ही अन्तिम साधन है। पर उनका यह भी विश्वास था कि समाजवादी लक्ष्य प्राप्त करनेके लिए बहुत अधिक हिंसाकी आवश्यक नहीं है। हैनोवेलके शब्दों में वह ट्रेड यूनियन आन्दोलनके विकासका, महत्वाची समितियोंके विस्तारका, संघद्वारा कार्यान्वयन और मजदूरोंकी स्थिति सुधारने के लिए विधि-निर्माणका समर्थन करते थे। उनका कहना था कि इन सब सुधारोंकी ही समाजवाद नहीं समझना चाहिए बल्कि ये समाजवादके लिए रास्ता तैयार करते हैं।

इन कालके विकासवादी (revisionists) इन बातोंके समर्थक थे कि समाजवाद क्रमिक विकास द्वारा प्रतिष्ठित किया जाय। काउत्स्की अपनेको विकासवादियोंमें गिनतेको तैयार न थे। जहां तक उनके निश्चालनका सम्बन्ध है वह दावा ठीक था। किन्तु व्यवहारमें वह विकासवादियोंके विपरीत नज़दीक थे। वह लोकतन्त्र (democracy) और लोकतन्त्रीय तरीकोंके समर्थक थे और सम्भवतः उनकी दृष्टि में लोकतन्त्र समाजवादमें भी ज्यादा महत्त्व रखता था। वह रूसीनरतशीय और आन्तरिक दोनों ही प्रकारके विचलन (derivation) के विरोधी थे। हैनोवेलके शब्दों-नुसार उन्होंने मार्क्स का आशय यह निकाला कि सरकार पर मार्क्सवादी सत्ताधिकार द्वारा गणराज्य का नियन्त्रण होना चाहिए। वह बोल्शेविकवाद का विरोध यह कह कर करते थे कि यह अल्पमत का शासन है और पशुत्व का प्रतिनिधित्व करता है। लेनिन ने अपनी पुस्तक *The Proletarian Revolution and Kautsky, the*

Renegade में कॉस्टस्की पर जबर्दस्त प्रहार किये हैं। कॉस्टस्की ने मोनल डेमोक्रेटिक पार्टीके कार्यकलापोंकी नींव रखी। वीमर रिपब्लिक (Weimar Republic) (प्रथम महायुद्धके बाद जर्मनी का गणतन्त्र राज्य जो १९१९ में बना था, समाजवादी प्रवृत्ति रखता था और इसको सन् १९३३ में हिटलर ने समाप्त कर दिया) के दिनोंमें साम्यवादी बराबर इस पार्टीका विरोध करते रहे। वह एक कमजोर पार्टी थी और ऐसी ही कमजोर पार्टियोंके बन्धों पर चढ़कर हिटलर और नाज़ीवाद मत्तारुढ़ हुआ। इटली में इसी प्रकारकी कमजोरी मुसोलिनी और फासिस्ट पार्टीके उदय और उत्थानका कारण बनी।

श्रमिक संघवाद (Syndicalism). यह सारत फ्रान्सीसी विचारधारा है। फ्रान्स का मजदूर आन्दोलन इसका जन्मदाता है। जार्ज सॉरेल (George Sorel) (१८४७-१९२२) इस आन्दोलनके महत्त्वपूर्ण बौद्धिक नेता थे। फ्रान्स की कॉन्फेडरसियो जेनेराल दु ट्रावेल (Confederation Generale du Travail) नामक संस्थाने जो अखिल फ्रान्स मजदूर संघ थी, इस विचारधारा को जनप्रिय बनाया। यह मार्क्स के राजनीतिक कार्य-क्रमको अस्वीकार करती है पर उनके हिसाब द्वारा फ्रान्तिनके सिद्धान्तको मानती है। इस दृष्टिसे यह अराजकतावाद और मार्क्सवाद का विरोध है। सिंडिकैलिज्म (syndicalism) शब्दकी उत्पत्ति फ्रान्सीसी शब्द सिंडिकेट (syndicat) से हुई है जिसका अर्थ है मजदूर संघ (trade union)। कुछ दृष्टियोंमें यह सिद्धान्त स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्वके फ्रान्सीसी फ्रान्तिवादी आदर्शों की प्रतिक्रिया है। फ्रान्सके मजदूरोंने देखा कि महान् फ्रान्तिने उन्हें काम करने की कुछ भी स्वतन्त्रता नहीं दी। वाणिज्य और निर्माण वर्गोंने शान्ततन्त्र पर अपना सिक्का जमा लिया और मजदूरोंको आम आर्थिक और राजनीतिक उपायोंके अपनाने से भी वंचित रखा। मजदूर संघके रूपमें जो वैधिक और उचित हथियार उनके हाथमें होना चाहिए था वह भी उन्हें नहीं दिया गया। फ्रान्सकी विधिया मजदूर संघके कार्योंमें बाधा डालती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि जब फ्रान्सका मजदूर ताकतवर हुआ तब वह मजदूर संघ और राजनीतिक समाजवाद दोनोंको तिलांजलि देकर निर्मम वर्गयुद्ध, आम हड़ताल, विध्वंस कार्य और काममें ढील डालने आदि अतिवादी तरीकोंसे अपनी मुक्तिका मार्ग खोजने लगा। फ्रान्सके मजदूरका उद्देश्य हो गया 'सधार भरके मजदूरोंको एकसूत्रमें बांधना और उनके दिलोंसे राष्ट्रीय देश भक्ति की भावनाको समाप्त करना।

श्रमिक संघवादकी परिभाषाएं. सी० ई० एम० जोड (C. E. M. Joad) लिखते हैं: "श्रमिक संघवाद सामाजिक शास्त्रका वह दृष्टिकोण है जो श्रमिक संघोंके संगठन (trade union organization) को नये समाजकी नींव और उस समाजकी स्थापनाका साधन दोनों मानता है।" एफ० डब्ल्यू० कोकर (F. W. Coker) कहते हैं: "मोटे तौर पर श्रमिक संघवादका अर्थ है कि मजदूर जिन परिस्थितियोंमें काम करते और रहते हैं, उन पर अकेले मजदूरोंका ही नियन्त्रण होना चाहिए; जिन

सामाजिक परिवर्तनोंकी मजदूरोंकी आवश्यकता है, वे मजदूरोंके अपने प्रयत्नोंसे ही, अपने सधोंमें भीषी कार्रवाई द्वारा और ऐसे साधनों द्वारा, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओंके अनुरूप हों, हो सकते हैं।^१ लेडलर (Laidler) के अनुसार धर्मिक सभवाद व्यापार और उद्योग दोनोंके धर्मिक मधों के मजदूर संगठन पर इसलिए बहुत अधिक जोर देना है ताकि वह नये औद्योगिक आवेगोंका व्यापार हो। वह उपभोक्ताकी अपेक्षा उत्पादकों अधिक महत्त्व देना है; सामाजिक स्वरूपको बदलनेके साधनके रूपमें आम हड़ताल और भीषी कार्रवाईके अन्य तरीकोंको महत्त्व देना है; राजनीतिक राज्यके उन्मूलनकी आवश्यकता पर और मजदूर वर्गके मुक्ति साधनके रूपमें राजनीतिक कार्रवाईको प्रभावगुन्यता पर भी वह बहुत जोर देना है। जी० ई० हूवर (G.E. Hoover) *Twentieth Century Political Thought* में लिखते हैं "आजकलके उपयोगके अनुसार धर्मिक सभवादका अर्थ है उन दार्शनिकारियों के मिश्रित और कार्यक्रम, जो औद्योगिक मधोंकी आर्थिक शक्तिका उपयोग पूँजीवाद को नष्ट करने और समाजवादी समाजका संगठन करनेके लिए करते हैं।"

धर्मिक सभवादकी शिक्षाएँ (Teachings of Syndicalism). ऊपर दी गयी परिभाषाओंमें धर्मिक सभवादकी शिक्षाएँ स्पष्ट की जा सकती हैं—

(१) धर्मिक सभवाद अविचल रूपमें राज्यके विरुद्ध है और उसे नाशक वर्ग और मध्य वर्गकी समस्या मानता है। राज्यका रूप चाहे जो कुछ भी हो, वह पूँजीवादी शोषणका ही एक धन है। सभी राज्य वर्ग शासनके साधन होते हैं। इसलिए राज्यकी शक्तिको नष्ट बिना मजदूर वर्ग नहीं जीन सकते। राज्य द्वारा दिये गये मुषार और दी गयी रियायते तां रोगका अमन्त्रोपचरक निदान हैं; इन तरीकों द्वारा बेचारे गरीब धर्मिकको इस बातका ज्ञान ही नहीं होने दिया जाता कि शोषकोंने अपने लाभके लिए वर्ग-अवस्था बना रखी है जबकि यह गरीबी, अमीरी और वर्ग-विरोध जन प्रतिमान अन्वाम है और बनावटी है। अतः लोकतन्त्रीय राज्य भी समाजको एक रम नहीं बना सकता, और राज्यकी शक्तिको ध्वंस करना आवश्यक है।

सरकारी बर्मकारियोंके रूपमें राज्यकी मंत्राने मनुष्योंमें अकनरोकी प्रवृत्ति हो जाती है और उन्हें मजदूरोंकी आवश्यकताओं और आकाशाओंके प्रति उदासीन बना डालती है। राजकीय काम शासनेन एक-रूपता और यात्रिकता है। रन्पना तथा भ्रम-भ्रमके लिए उनमें कोई स्थान नहीं रहता और नत्वाचीन कामों पर और व्यक्तिगत उद्योगशीलता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

(२) धर्मिक सभवादी ध्यावमायिक आधार पर मरुतिन मजदूर मधोंको मार्वा मनाजकी आधारशिला मानता है। वह चाहता है कि उत्तरादक सदितियोंका एक जाल बिछे जो राज्यका स्थान ले ले। २ बर्यों या इसके आन्वाम जब आम

^१ एड० डब्ल्यू० कोपर-सेन्ट्रल पब्लिशिंग हाउस (D. Appleton-Century CO., N.Y.) पृ० २२९.

पुनाव होते हैं तब वोट दे आनेके अतिरिक्त, आजकी व्यवस्थामें श्रमिकों का सरकारके कार्य-कलापमें और कुछ भी हिस्सा नहीं है। इस वोटका भी कोई मूल्य है? आजकल जो वोट दिये जाते हैं उनका कोई महत्त्व नहीं है। श्रमिक संघवादियोंका विश्वास है कि उनकी व्यवस्थाके अन्तर्गत मजदूर अपने काममें व्यक्तिगत रुचि लेगा और इससे सामान अच्छा और अधिक परिमाणमें बनेगा। श्रमिक संघवादी अपने सामने "स्वतंत्र समाजमें स्वतंत्र काम" का आदर्श रखता है। उगवा विश्वास है कि "जब कारखानोंमें स्वतंत्रता होगी तभी समाजमें भी स्वतंत्रता होगी।"

(३) जैसा कि हेन्रि वेल्सने कहा है इस सबका मतलब यह है कि श्रमिक संघवादियोंने वर्ग-युद्धको ही एकमात्र महत्त्व नहीं दिया है तां उसे केन्द्रीय महत्त्व तो दिया ही है। श्रमिक संघवाद मजदूर वर्गमें दृढ़ एकता कायम करनेका प्रयत्न करता है। उसके अनुसार मजदूर राजनीतिक दलोंके चक्करोंमें दूर रह कर किनी भी राजनीतिक दलसे सहयोग नहीं करेगा और मजदूर-वर्गका अपना कोई देश नहीं होगा। हेन्रि वेल्स के शब्दोंमें श्रमिक संघवाद मार्क्सवादी आर्थिक मिथ्यात्व और वर्ग-युद्धको मजदूर-संघोंके साधनसे सिद्ध मानता है।

श्रमिक संघवादकी पद्धतियाँ (Methods of Syndicalism). श्रमिक संघवादी मार्क्सवादियोंके इस विश्वासमें विश्वास नहीं करते कि वह समय दूर नहीं जब सर्वहारा-वर्ग सम्पत्तिशाली वर्गके विरुद्ध विद्रोह कर देगा। उनका कहना है कि मार्क्स यह माननेमें आवश्यकतामें भी अधिक आशावादी थे कि मालिक लोग मजदूरों से लड़ बैठेंगे और इस प्रकार स्वयं अपना विनाश कर लेंगे। मालिक मजदूरोंसे सौदे-बाजी और मुलहनामें करेंगे। इसलिए उनमें निवृत्तनेका एकमात्र रास्ता यह है कि हड़ताल, ध्वंसारम्भ, कार्रवाइयों, मशीनोंकी तोड़-फोड़, बहिष्कार विरोधी बिल्ले लगाव और काममें ढील डालनेकी रीतियोंमें उनके विरुद्ध निरन्तर आक्रामक नीति अपनाई जाय।

श्रमिक संघवादियोंको सीधा लड़ाइयोंमें पक्का विश्वास है। वे राजनीतिक तरीकोंमें विश्वास नहीं रखते। उनका क्याल है कि मजदूरोंको शिक्षित करनेका और अन्तिम लड़ाईके लिए उन्हें तैयार करनेका एकमात्र तरीका सीधा जेहाद (direct action) ही है। इस संघर्षमें मध्यस्थोंके लिए कोई स्थान नहीं है। अपनाये जानेवाले तरीके हिंसात्मक ही सक्ते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि ये तरीके हिंसात्मक ही हों। आम हड़ताल मुख्य हथियार है। इस आम हड़तालको साधारण हड़ताल, राजनीतिक हड़ताल या सहानुभूतिमें की गयी हड़ताल समझनेकी मूल नहीं करनी चाहिए। यह हड़ताल तब होगी जब विशिष्ट हड़तालको एक लम्बी शृंखलाके द्वारा मजदूरोंको अच्छी तरहसे हड़ताल करनेमें कुशल बना लिया जायगा। आम हड़ताल अन्तिम और शक्तिशाली हथियार होगा जो राज्यके सारे कार्य-कलाप ठप कर देगा। तब श्रमजीवी समाजके मालिक हो जायेंगे।

अपने लक्ष्यको पानेके तरीके अपनानेमें श्रमिक संघवादी पक्षोपेक्ष नहीं करते। लोग ऐसे तरीकोंका समर्थन करते हैं जैसे खराब काम करना, मशीनोंकी तोड़ना,

जंगलदा और जी चुरानेवाले डग अपना काम लेकर बैठ जाय ।
यामिक सभसे बाहर रहनेवाले श्रमिकों द्वारा बनाई गयी चीजोंका बहिष्कारभी
है जो आज असफल हो सकती हैं पर "आजकी असफलता कलकी होने वाली
श्रमिक संघवादके अन्तर्गत समाजका दांचा (The Syndicalism)

er Syndicalism). थर्मिक सपवादो योजना प्रत्यक्ष, बलवती और चत होती है। पर इसके अन्तर्गत समाजकी हालत बिल्कुल अस्पष्ट रहेगी। - सपवाद प्रधानतः विरोध करनेमें विश्वास करता है। यह नकारात्मक है। कि एक लेखकने लिखा है, "यह प्रधानतः नान्तिकी रीति प्रस्तुत करता है, नकी नहीं।" थर्मिक सपवादके अन्तर्गत थर्मिकसथ (syndicate) ही औद्योगिकका आधार होगा। थर्मिक उत्पादनका नियन्त्रण करेंगे। व्यक्तिगत पूजीका सामूहिक पूजी लेगी। यातायात, रेलें और डाकघराने जैसी राष्ट्रीय सेवाएँ रॉके राष्ट्रीय सथके अधिकारमें रखी जायगी। जेलों और अदालतोंका अन्त त्या जायगा और दण्ड सामाजिक बहिष्कारके रूपमें दिया जायगा। गरीबोंमें, थर्मिक सपवादका उद्देश्य राज्य-विहीन समाज है इसका अर्थ यह है कि उनके साधनों पर समाजका अधिकार होगा और थर्मिक सथ उत्पादनका नियंत्रण करेंगे। थर्मिक सपवाद और समाजवाद. थर्मिक सपवाद यह है कि अधिकार

धर्मिक संप्रदाय और समाजवाद. धर्मिक संप्रदाय और समाजवाद में मुख्य रूप से अधिक उपयोग करना चाहते हैं, पर धर्मिक संप्रदायी राज्यको एकदम से बन्धन पर ध्यान देना है। समाजवाद आमतौर पर उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर ही ध्यान देता है। इस मानीमें वह समाजवादका विरोधी सिद्धान्त है। ईश्वरवाद करता है, पर धर्मिक-संप्रदायका विद्वान हिमा, जालि और सीपी धर्मिक संप्रदायकी आलोचना. अपनी मौलिक...

धार्मिक संप्रदायों की आलोचना। अपनी मौलिक कमजोरियों के कारण धार्मिक
तान्त्रिक और इटली के बाहर बहुत कम प्रगति कर सका। यह अपने तीर-तरीकों
बहुत बढ़ा-बढ़ाकर रहता है और अपने जटिलों को जान-बूझकर अस्पष्ट रमता
व्यावहारिक राजनीतिकी दुनिया में स्वभाविक समझौतों (compromises)
पर रतने वालों पर इसका कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता कि यह "अत्यधिक

Laidler : History of Socialistic Thought

सिद्धान्तवादी, अत्यधिक अतिवादी और अत्यधिक तर्कवादी है।" "उत्पादकोंके अधिकारों और उत्तरदायित्वों पर बहुत अधिक और उपभोक्ताओंके अधिकारों और उत्तरदायित्वों पर बहुत कम" ध्यान देकर यह उपभोक्ताओंको अपने विरुद्ध कर देता है।^१ आम हड़ताल एक कल्पनामात्र है। यह संगठित अराजकतासे अधिक और कुछ नहीं है। एक बार सीधी कार्रवाई आरम्भ हो जाने पर कोई नहीं जानता कि उसका अन्त कहा होगा। अतः सुपरीक्षित सार्वभौमिक-तरीकोंको ही अपनाना बुद्धिमानी है। समाजमें बुद्धिमान लोगोंको हिंसा हमेशा कष्टदायक होती है। हैलोवेल लिखते हैं कि "श्रमिक सघवाद और फासिस्टवाद में बहुत नजदीकी नाता है। इसीलिए मुसोलिनी बहुत थोड़ासे सोरेल की पुस्तकोंको पढ़ा करते थे।"

अनुभव बताता है कि हड़ताल मजदूरोंको बल प्रदान करनेके बजाय बहुधा उनमें निराशाकी भावना भर देती है। यह विचार बिल्कुल बंशुका है कि मजदूरोंका कोई अपना देश नहीं होना चाहिए और सब देशोंके मजदूरोंको अपना एक मोर्चा बनाकर शेष संसारके विरुद्ध डट जाना चाहिए।

फैबियनवाद. श्रमिक सघवादको छोड़कर फैबियनवादका विवेचन करना बड़ा सुखद है। फैबियनवाद समाजवादकी एक अग्रंजी विचारधारा है और यह अग्रज विद्वानों के मस्तिष्ककी ही उपज है। फैबियनवाद और मार्क्सवादमें तीव्र अन्तर यह है कि फैबियनवादके तरीके नम्य (flexible) होते हैं और यह धीरे-धीरे लोगोंको राजी करके समाजवाद स्थापित करनेमें विद्वानों करता है।

फैबियनवाद शब्दकी उत्पत्ति रोमके एक जनरल फैबियस कक्टेटर (Fabius Cunctator) के नामसे हुई है, जो अपने विरोधी हैनीबल (Hannibal) के ऊपर घातक आक्रमण करनेके उचित अवसरकी प्रतीक्षा, धैर्यपूर्वक, तब तक करता रहा, जब तक कि आक्रमणका सुन्दर अवसर न आ गया। एच० जी० वेल्स (H. G. Wells) ने, जो स्वयं एक फैबियन थे, लिखा है कि फैबियस ने कभी भी सख्त प्रहार नहीं किये।

'फैबियन सोसाइटी'की स्थापना ४ जनवरी, १८८४, को हुई। तभी उसने निम्न-लिखित सुविधाजनक आदर्श अपनाया: "आपको उचित अवसरके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए जैसी कि फैबियस ने हैनीबल से युद्ध करनेमें बड़े धैर्यसे की थी यद्यपि बहुतोंने इस विलम्बकी तीव्र आलोचना की, लेकिन जब अवसर आ जाय तब आपको पूरी शक्तके साथ प्रहार करना चाहिए, जैसा कि फैबियस ने किया था, अन्यथा आपका प्रतीक्षा करना व्यर्थ तथा निष्फल हो जायगा।"

फैबियनवादका सिद्धान्त १८८७ में निश्चित किया गया। कुछ घोटोंसे संशोधनों के बाद सन् १९१९ में इसकी दुबारा धोषणाकी गयी। वह धोषणा इस प्रकार है—

^१ Laidler, op. cit., p. 310.

^२ पीज की दि हिस्ट्री आफ दि फैबियन सोसाइटी, पृष्ठ ३२ से उद्धृत।

“भूमि और औद्योगिक पूंजीको व्यक्तिगत स्वामित्वसे मुक्त करके और उन्हें सार्वजनिक हितके लिए समाजके हाथोंमें सौंपकर समाजका पुनर्संगठन करना इसका लक्ष्य है। देशकी प्राकृतिक और अर्जित सम्पत्तिको पूरी जनतामें न्यायपूर्वक बांटना इसी प्रकार सम्भव है।”

‘इसलिए भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्वका उन्मूलन करनेके लिए समाज बंदम उठाता है। ऐसा करनेमें वह प्रतिष्ठित आशाओंका और घर तथा बगीचेके स्वामित्वका न्यायमंगत विचार रखता है। यह उन सब उद्योगोंकी समाजके आधिपत्यमें लानेकी कोशिश करता है जिनका मंचालन सामाजिक रीतिमें किया जा सकता है और उत्पादन, वितरण और सेवाके नियमनमें व्यक्तिगत लाभके स्थान पर सार्वजनिक हितकी प्रधान लक्ष्यके रूपमें प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न करता है।’^१

फेबियनवाद पर प्रकाश डालते ह्यूमे लेडलर^२ (Laidler) कहते हैं कि फेबियनवाद पूंजीवाद के स्थान पर समाजवादकी स्थापना कथनः ही करना चाहता है। उसका विद्वान है कि मौजूदा शान्तिपूर्ण आर्थिक एवं राजनीतिक तरीकोंमें उद्योगोंका समाजीकरण किया जा सकता है। वह मध्यवर्गको एक ऐसा समुदाय मानता है जिसका उपयोग नवीन सामाजिक व्यवस्था प्रणामनशुल्काके विकासमें कर सकता है। फेबियनवाद के अनुसार समाजवादकी स्थापनाकी दिशामें एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि समाजवादके पक्षमें समाजकी चेतनाको जाग्रत किया जाय और सक्रिय बनाया जाय।

फेबियनवाद और धर्मिक सपवादमें अन्तर—फेबियनवाद समदीय सरकारके साधनसे अपने लक्ष्यको प्राप्त करनेमें विद्वान करता है। वह शान्तिपूर्ण शान्तिका समर्पण करता है। भूमि, उद्योगों और वित्तीय संस्थाओं पर निजी स्वामित्वके स्थान पर राज्यका स्वामित्व शान्तिपूर्ण तरीकोंसे स्थापित किया जाय। हैन्सोवेल के मन्त्रोंमें फेबियन समाजवादका लक्ष्य “भूमि और औद्योगिक पूंजीको वैयक्तिक स्वामित्वसे मुक्त करके सार्वजनिक हितके लिए समाजके अधिकारमें लाकर समाजका पुनर्संगठन करना है।” न तो भूमि पर वैयक्तिक स्वामित्व रहेगा और न लगान ही रहेगा। औद्योगिक पूंजी, जैसे-जैसे समाज उसका उपयोग करने योग्य होता जायगा, वैसे-वैसे समाजकी हस्तान्तरित होनी जायगी।

इस प्रकारके समाजवादके प्रधान समर्थक सिडनी तथा बीट्रिस वेब (Sidney and Beatrice Webb), ग्राहम वॉलस (Graham Wallas), ऐनीबेसेन्ट (Annie Besant), ई० आर० पीज (E. R. Pease), एच० जी० वेल्स (H. G. Wells), जी० बी० शाव (G. B. Shaw) और जी० डी० एच० कोल (G. D. H. Cole) हुए हैं। इन्होंने बहुत-सी छोटी-छोटी पुस्तिकाएं और लेख लिखे हैं और इनके द्वारा जनताकी सामाजिक चेतनाको जाग्रत करनेका यत्न

^१ वही, पृष्ठ २५९.

^२ Social-Economic Movements, p. 184.

किया है। जी० बी० शा ने फेबियन लेखोंका सम्पादन किया और इन लेखोंको १८८५ में सर्वप्रथम भाषणोंके रूपमें जनताके सामने प्रकाशित किया। हेंलोवेल लिखते हैं कि सिडनी वेब लोकतन्त्रीय, श्रमिक, शान्तिपूर्ण और वैधिक तरीकोंके द्वारा समाजवादी समाजके उदयकी कल्पना करते थे। एक महत्त्वपूर्ण वाक्यांशके लिए हम फेबियनोंके ऋणी हैं। वह है—“समाजवादकी अनिवार्यता (the inevitability of socialism)।”

माक्सवाद और फेबियनवादमें अन्तर. माक्सवाद अधिकांश श्रम-सिद्धान्त और वर्गपुट्ट पर आधारित है। पर फेबियनवादका आधार है लगान सिद्धान्त (Theory of Rent) का विस्तार और राज्यकी सामाजिक चेतनाका विकास। माक्सवाद क्रान्तिवादी है, फेबियनवाद विकासवादी।

फेबियनों द्वारा फेबियनवादका परित्याग (Defection in Fabian's ranks). फेबियनोंकी सख्या कभी अधिक नहीं रही। वह अधिकतर मेधावियों (intellectuals) तक ही सीमित रहा है। सन् १९४३ में वह अपनी लोकप्रियता के शिखर पर था तब भी इसके केवल ३,६०० सदस्य थे। १९२० के बाद १० वर्षों तक फेबियनोंमें परस्पर अनेक मतलों पर तीव्र विवाद हुआ फलतः बहुत-से युवा मेधावी फेबियनवादको छोड़कर श्रेणी समाजवाद (guild socialism) में शामिल हो गये। वेब-दम्पतीकी सहानुभूति स्वमें होनेवाले प्रयोगके प्रति बड़ी और उन्होंने एक महान् ग्रन्थ लिखा जिसका नाम है “सोवियत कम्युनिज्म—एन्यू सिविलाइजेशन।” कोल ने १९४२ में फेबियनवादकी निम्नलिखित शब्दोंमें फिरसे व्याख्या की—

“हमारा विश्वास है कि समाजवादी आन्दोलनमें कहीं न कहीं एक ऐसी संस्थाकी आवश्यकता है जो नवीन विचारोंको सोचने और उनका प्रचार करनेके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। भले ही ऐसे विचार समाजवादी परम्पराके अनुसार शास्त्र-सम्मत न हो। समाजवाद कुछ ऐसे निश्चित नियमोंका समूह नहीं है जिन्हे समय या स्थानका विचार किये बिना ही हर समय उपयोगमें लाया जाय।” कोल आगे लिखते हैं : ‘फेबियन समाज का संगठन विचार-विनिमयके लिए है न कि चुनाव लड़नेके लिए। चुनावको उसने अन्य संस्थाओंके लिए छोड़ दिया है, फेबियनोंको अपने चुने हुए काम—लेखन और गवेषणमें लगे रहना चाहिए। पर चूँकि अब यह विस्तृत कार्य (समाजवादी दलमें समाजवादका प्रचार) को करनेवाला कोई नहीं है, इसलिए फेबियन पुस्तक लेखन कार्य और गवेषण कार्य पूरे दल पर अपना वाञ्छित प्रभाव डालनेमें असमर्थ हैं। यदि अन्य कोई इस कार्यको नहीं करता है तो फेबियनोंको ही सामने आना होगा और समाजवादका प्रचार करनेका बीड़ा उठाना पड़ेगा।”

भारत के लिए फेबियनवादकी अनुकूलता (Applicability of Fabian-

१ जी० डी० एच० कोल : फेबियन सोशियलिज्म, पृष्ठ १९४.

ism to India). हमारे अहिंसावादी होनेके कारण फेबियनवाद और उससे उत्पन्न मजदूर दलका कार्यक्रम, किसी अन्य प्रकारके समाजवादकी अपेक्षा हमारे स्वभाव और हमारी आवश्यकताओंके अधिक अनुकूल है। हम पूँजीवादी समाजवादी समाजमें परिवर्तन शान्तिपूर्ण ढंगमें करना चाहते हैं। जैसे-जैसे हमारे ज्ञान, अनुभव और चरित्रका विकास होता जायगा, वैसे वैसे-अधिकाधिक मात्रामें निजी श्रेष्ठता स्थान सार्वजनिक क्षेत्र लेगा जायगा, और उत्पादनके सभी नाघन समाजके स्वामित्वमें आ जायंगे। समाजिक न्याय और हिंसामें किसी प्रकारकी भी समानता नहीं है।

ब्रिटेन का मजदूर दल (The British Labour Party). बहुत छोटेसे रूपसे आरम्भ होकर ब्रिटेनके मजदूर दलने पिछले पचास वर्षोंके अन्दर बहुत प्रगति की है। यह दल तीन बार १९२४ में, १९२९-३१ में और १९४५-४६ में सत्ताह्व रह चुका है। पहले दो अवसरों पर अपना पूर्ण बहुमत न होनेके कारण इस दलको दूसरे दलोंकी दया और मदभावना पर निर्भर रहना पड़ा। किन्तु १९४५-४६ की अवधिमें यह दल न केवल पशुबल रहा बल्कि इसके हाथोंमें वास्तविक शक्ति भी रही और इसने समाजवादकी दिशामें अनेक परिवर्तन किये और अंग्रेजी साम्राज्यवादकी जमीरे डीली करके उसे एक लोकतन्त्रीय राष्ट्रमण्डलमें परिणत करनेकी दिशामें भी कदम उठाया।

आरम्भमें ही मजदूर दलकी शक्ति उसके मजदूर-समूहों और उसकी तरफ नीतिमें ही रही है। मई १८८९ में कॉमलेकी खानमें काम करनेवाले स्काँव किअर हाडी ने एक स्काँटिश मजदूर दलकी स्थापना की थी। उन्होंने ही १८९१ में अन्य व्यक्तियोंके साथ स्वतंत्र मजदूर दलकी स्थापना की जिनके प्रारम्भिक सदस्योंमें से रैमजे मैकडोनाल्ड (Ramsay Macdonald) भी थे, जो १९२४ में प्रथम मजदूर दलीय प्रधान मंत्री हुए। वह एक बार फिर १९२९-३१ में प्रधान मंत्री हुए, पर इसके बाद उन्होंने मजदूर दल छोड़ दिया।

ट्रेड यूनियन कॉन्फ़ेन्सकी समन्वय कमेटीका नाम १९०६ में ब्रिटिश लेबर पार्टी रखा गया। यह दल व्यक्तियोंका दल होने के बजाय मजदूर समुदायका एक मण है। सही मानांमें ब्रिटिश मजदूर दलका आरम्भ १९०६ के बाद ही हुआ। उसी वर्ष उसने पार्लियामेंटमें अपनी शक्तियों ट्रेड डेस्पेंडेंस ऐक्ट पास कराया। इस कानूनने मजदूरों की धरना देनेका अधिकार दिया और इस प्रकार होनेवाले हानिके कारण किये जाने वाले सामूहिक जुर्मानीको अवैध घोषित किया। पार्लियामेंटमें अल्पमतमें होनेके कारण मजदूर दल दूसरे गुफार न कर सका। लेकिन इसने आयरिश स्वशासन विधेयक (Irish Home Rule Bill), मतदाताधिकार विधेयक (Suffrage Bill) और वेल्श विस्थापना विधेयक (Welsh Disestablishment Bill) को तरफदारोंमें उतार दलका साथ दिया।

प्रथम विश्व युद्धके पहले समाजवादकी ओर आने लगाये रखने पर भी मजदूर

दलने अपने आपको समाजवादी घोषित नहीं किया था। सन् १९१८, में उसने 'मजदूर और नवीन सामाजिक व्यवस्था' शीर्षक कार्यक्रम स्वीकार किया जो निम्नलिखित चार मौलिक सूत्रों पर आधारित था—

- (१) सबके लिए न्यूनतम राष्ट्रीय आय।
- (२) उद्योगका शोषतन्त्रीय नियंत्रण।
- (३) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थामें शान्ति।
- (४) अतिरिक्त सम्पत्तिका सार्वजनिक बल्याणके लिए उपयोग।

मजदूर दलने सन् १९२९ में 'मजदूर और राष्ट्र' के नामसे प्रसिद्ध एक और घोषणापत्र प्रकाशित किया। इस घोषणापत्रमें मजदूर दलने कोयलेकी खानों, भूमि, वातावात और जीवन बीमाके समाजीकरण और बैंक आफ इंग्लैंड (इंग्लैंड में रिजर्व बैंक आफ इण्डियाके तुल्य) के राष्ट्रीयकरणका वादा किया। १९२९ में मजदूर दलको २८८ सीटें मिली पर बहुमतमें होनेके लिए २० सीटोंकी बम्भी रह गयी। अतः इसे अपनेकी दो वर्ष तक शासनाल्लङ्घ करनेके लिए उदार दल पर निर्भर रहना पड़ा। ससदमें अल्पमतमें होनेके कारण यह दल बहुत अधिक समाजवादी विधान न प्रस्तुत कर सका।

मैकडोनाल्ड और स्नोडेनके अनुदार दल (Conservative) में शामिल हो जानेके बाद मजदूर दलके सामने विरोधी दल बननेके अतिरिक्त और कोई चारा न रह गया। द्वितीय विश्व युद्धके आरम्भमें सन् १९४० में मजदूर दलने अपना एक कार्यक्रम प्रकाशित किया जो 'मजदूर, मुद्र और शान्ति' के नामसे प्रसिद्ध है। उसी वर्ष उसने चर्चिल के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया और जब तक जर्मनीका विनाश न हो गया तब तक मजदूर दल एक छोटे सामेदारके रूपमें पदार्ढ्य रहा। जुलाई, सन् १९४५, के आम चुनावमें, हरेककी आशाके विपरीत मजदूर दल अच्छे खासे बहुमतमें निर्वाचित हो गया और यह अपने कार्यक्रमका कुछ अंश कार्यान्वित कर सका।

सन् १९४२ की अपनी कांग्रेसमें मजदूर दलने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया था—

"देशके मौलिक उद्योगों और सेवाओंका समाजीकरण तथा सामाजिक उपयोग की दृष्टिसे उत्पादनकी योजना बनाना; क्योंकि यही एक ऐसी न्यायसंगत और समृद्ध आर्थिक व्यवस्थाकी स्थायी आधार-जिला है जिसमें राजनीतिक लोकतन्त्र और व्यक्तिगत स्वाधीनताके साथ सभी नागरिकोंके लिए जीवनके एक न्यायसंगत मानदण्डकी सगति बैठाई जा सकती है।"

सन् १९४५ में क्लेमेंट एटली (Clement Attlee) के नेतृत्वमें सत्तालब्ध होनेके बाद मजदूर दल ने कोयले और इस्पातके उद्योगों, बैंक आफ इंग्लैंड, नागरिक उद्द्ययन, विद्युत् पारेषण (power-transmission), दूर-संचार (tele-communication), रेल और मोटर-बस परिवहन, लन्दन-परिवहन, जलमार्गों और गैस (इंग्लैंडमें गैसका अत्यधिक महत्त्व है। यह नलियो द्वारा घरोंमें भेजी जाती है जहाँ

यह परोक्षों गमं रखने और ईंधनके काम आती है) का राष्ट्रीयकरण कर दिया। रोटी (bread) और दूधके व्यवसायको आर्थिक सहायता दी गयी। आवास योजनाओं (housing scheme), वृद्धावस्थामें पेन्शनकी व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थाका २० प्रतिशत सार्वजनिक नियन्त्रणमें ले आया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (national health service) की व्यवस्था मजदूर दलकी महान्तम मकसदाओंमें से एक है।

मजदूर दलके सामनाबद्ध होनेके दिनोंमें ही भारत, पाकिस्तान, बर्मा और लका को स्वाधीनता मिली।

जबमें मजदूर दल सत्ताच्छ नहीं रहा तबसे इधर कुछ दिनों दलके भीतर ही दक्षिणपन्थी और वामपन्थी गुटोंमें तीव्र मनमंथ रहा है। वामपन्थी अल्पमत है। रुडि-बाई दल जो इन समय सत्ताच्छ है, मजदूर दल द्वारा किये कुछ कामोंको नष्ट करनेकी कोशिश कर रहा है। इमान्दारी राष्ट्रीयकरण समाप्त किया जा चुका है। अने १९२९ के बजटमें राजकोष महामात्य (Chancellor of the Exchequer) हेरोल्ड मैकमिलन (जो अब प्रधान मंत्री हैं) ने रोटी और दूधके तयोंपोंको दी जानेवाली महापनामें कमी करनेका प्रस्ताव किया था।

ब्रिटेन का मजदूर दल दायीरिक और बाँधिक काम करनेवाले दोनों ही प्रकारके मजदूरोंको साम्यवाद देता है। वह लोकतन्त्र और न्यायके आधार पर समाजके समाज-वादी पुनर्निर्माणका समर्थक है। वह दक्षिणपन्थी और वामपन्थी दोनों ही प्रकारकी तानाशाहीको अस्वीकार करता है। इन दलके सदस्य अपनी नीति व अपने कार्यक्रम को 'महानति द्वारा जान्ति' कहते हैं। 'उदारवाद' (Liberalism) और 'एक-दलीयतन्त्रवाद' (Totalitarianism) के बीच मंथन है। कुछ सदस्योंका विश्वास है कि समाजवादकी प्राप्तिके लिए कुछ स्वेच्छाचारी कदम उठाने पड़ेंगे।

थेनी समाजवाद (Guild Socialism). ब्रिटेन के अतिवादी विचारकों में कुछ समयके लिए थेनी समाजवादका फैलान रहा है। रॉको (Rockow) ने इसे "अपेजी फंडिशनवाद और फ़ाल्सीमी धर्मिक संघवादका बोधिक गिनू माना है"।^१ हेनरीक जो इसके प्रति अधिक कठोर है, लिखते हैं: "थेनी समाजवाद फ़ाल्सीमी धर्मिक संघवादका दुर्बल मरगिनन्ता स्थापनर रहा है और है। मूलरूपमें यह एक केवल अपेजी मिथ्या है। कुछ लोग इसे धर्मिक संघवाद और समूहवाद (Collectivism) के बीचका विषय गिजिर मानते हैं। छोटी कार्रवाई द्वारा राज्यका उन्मूलन करनेमें यह धर्मिक संघवादमें सहमत नहीं है और न यह सभी उद्योगोंका राज्य द्वारा नियन्त्रण हो चाहता है जैसा कि समूहवाद चाहता है। यह बीचका रास्ता अपनाता है। यह राज्यके ढाँचेके भीतर ही उद्योगोंका और उत्पादकोंके मध्य बनाना चाहता है। थेनी (Guild) का परिभाषा इस प्रकार की गयी है—“अन्तर्गन्नाथन

* कन्टिंगोरेटी पोलिटिकल साट इन इंग्लैंड, पृष्ठ ११०.

या अपनी इच्छासे एक दूसरे पर आश्रित लोगोंकी श्रेणी जो स्वयं अपना शासन करती हो और जिसका संगठन समाजके एक विशेष धर्मव्यवस्थाकी जिम्मेदारीके साथ पूरा करनेके लिए हुआ हो।”

श्रेणी समाजवादके प्रधान समर्थक हैं—वस्तुतः इसकी नींव डालनेवाले ए० जे० पेण्टी (A. J. Penty), ‘न्यू एज’, के सम्पादक ए० आर० ओरेज (A. R. Orage), इस आन्दोलनके प्रबान बर्मंड एस० जी० हावमन (S. G. Hobson) और जी० डी० एच० कोल (G. D. H. Cole) जो इसके सर्वाधिक प्रभावपूर्ण, विचारक और प्रचारक हैं।

निम्नलिखित कारणोंसे श्रेणी-पद्धतिका उदय हुआ।

(१) मजदूरी की प्रथा और पूँजीवादियोंकी मुनाफाखोरी पर समाजवादी प्रहार;

(२) जान रस्किन (John Ruskin), थॉमस कार्लाइल (Thomas Carlyle) और विलियम मोरिस (William Morris) जैसे साहित्यिक व्यक्तियोंका प्रभाव। इन सबने अति उत्पादनके विरुद्ध आन्दोलन किया था;

(३) राज्यके विरुद्ध फ्रान्स का श्रमिक सपवादी आन्दोलन;

(४) सुप्रसिद्ध चर्च मैन फिगिस (Figgis) का प्रभाव जिन्होंने राज्यकी सम्प्रभुताकी कपोल-कल्पनाका भण्डाफोड किया और राजनीतिक अधिकार सत्ताको “एक सप, न कि अधिपति” (an association, not a lordship) बतलाया;

(५) व्यापारवाद या उद्योगवाद (functionalism)। इसके अनुसार सम्पत्तिकी व्यापार या उद्योगबद्ध होना चाहिए और उस पर नियंत्रण स्वयं अपने हाथों व्यापार या उद्योग न करने वाले लोगोंके हाथोंसे हटकर काम करनेवालोंके हाथोंमें चला जाना चाहिए।

श्रेणी समाजवादका कार्यक्रम. इस कार्यक्रमके निम्नलिखित दो मुख्य अंग हैं : (१) मजदूरी प्रथाका उन्मूलन और (२) “राष्ट्रीय श्रेणियोंकी पद्धतिसे उद्योगके क्षेत्रमें स्वशासनकी स्थापना, यह राष्ट्रीय श्रेणी समाजके अन्य लोकतांत्रिक संगठनोंसे मिलकर काम करेगी।”^१

श्रेणीवादी मार्क्सवादकी इस भागका समर्थन करते हैं कि मजदूरी प्रथाका उन्मूलन किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रथा नैतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और कलात्मक सभी दृष्टियोंसे बुरी है। मजदूरी प्रथा मजदूरोंमें दास भावना उत्पन्न करती है और उनकी सर्जक प्रवृत्ति (creative instinct) को कुण्ठित करती है।

^१ जोड द्वारा उद्धृत मार्टिन पोलिटिकल थ्योरी, पृष्ठ ७५.

थेनोवादियोंका कहना है कि व्यक्तिको बेतन मनुष्य समझकर देना चाहिए न कि 'इम नाते' कि उसने कितना थम प्राप्त हुआ है। समाजको उसे काम करते समय तथा बेकारीके समय, बीमारोंके समय और उनके स्वस्थ रहते समय दोनों हालतोंमें बेतन देना चाहिए। इसके अनिश्चित उत्पादनकी व्यवस्थाका नियंत्रण मजदूरोंके साथ मिलकर किया जाना चाहिए।

जोड थेनो-समाजवादको व्यावसायिक लोकतंत्र कहते हैं। उद्योग पर बोद्धिक व सारौरिक दोनों ही प्रकारके काम करनेवालोंका नियन्त्रण होना चाहिए। समाजमें शक्ति और उत्तरदायित्व किसे गये कामोंके अनुपातमें होना चाहिए।

व्यावसायिक प्रतिनिधित्व (Functional Representation) यह थेनी समाजवादका मूल मन्त्र है। यह दलील दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तिका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। थेनी-समाजवादियोंका विश्वास है कि "यद्यपि एक व्यक्ति अपने पड़ोसियोंका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता पर वह कुछ ऐसे सामान्य उद्देश्योंका प्रतिनिधित्व कर सकता है जो उनके और उनके पड़ोसियों दोनोंके हों।" यह व्यावसायिक प्रतिनिधित्व द्वारा ही सम्भव है। ऐसा प्रतिनिधित्व स्थानीय व राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर होगा। कर-आरोपण (taxation), प्ररिक्षा (defence) और शिक्षा जैसे राष्ट्रीय मामलोंका प्रतिनिधित्व एक राष्ट्रीय मस्था द्वारा होगा। स्थानीय मस्थाएँ गैम, बिजली, और पुलिस जैसे मामलोंकी देख-भाल करेगी।

कारखानोंकी निर्वाचित समितियाँ मजदूरों, कामके घण्टों और उत्पादनके परिणाम आदि प्रश्नोंका निपटारा करेगी। कारखाना समितियोंके साथ मिलकर उपभोक्ता समितियाँ उत्पादन-व्यय, मूल्यों और उत्पादनकी सीमाके प्रश्नोंका फैसला करेंगी।

थेनीवादियोंका कहना है कि लोकतंत्रको पहले आर्थिक क्षेत्रमें जाना चाहिए, बादमें इसे राजनीतिक क्षेत्रमें लागू किया जाना चाहिए। आज तो इनका उल्टा होना दिखाई दे रहा है। थेनी-समाजवादके अनुसार आधुनिक औद्योगिक परिस्थितियाँ इनकी अल्प-अल्प और गौणमूलक हैं कि उनको पहले मुषारे बिना सामाजिक जीवनके अन्य-क्षेत्रोंमें कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है।

थेनी-समाजवादके अन्तर्गत न केवल औद्योगिक थेनी होगी, बल्कि उपभोक्ता-थेनी, नागरिकथेनी, और अन्य कृषो व औद्योगिकोंकी थेनिया होगी। इन सबका मूलतः स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आधार पर होगा।

राज्यके स्थान पर कम्पून या स्वयंनिर्णय समाजकी स्थापना होगी। इसके बर्तव्य सीमित रहेंगे। उत्पादनके यह थेनियोंकी राज्यके न्यायधारी वा दृष्टीके रूपमें सीत दिये जायेंगे।

थेनी-समाजवादकी पद्धतियाँ (Methods of Guild Socialism). अधिकांश मण्डारने भिन्न थेनी समाजवाद विचारवादी पद्धतियों पर विचार्य करता

है। पर उसे साथ ही साथ संसदीय कार्यों में सीमित विश्वास है। यह मजदूर संपोका बहुत उपयोग करना चाहता है। "आजके ट्रेड यूनियन कलकी श्रेणियां होगी।" ये श्रेणियां सम्पत्तिशाली वर्गों के हाथसे धीरे-धीरे गन्ति छीन लेंगी। इस मामले में वे श्रमिक सघवादसे भिन्न हैं जो सीधी कारंवाई और आम हड़तालका रास्ता अपनाता है।

आलोचना. (१) श्रेणी-समाजवादी मध्ययुगकी श्रेणी व्यवस्थाको आदर्श मानता है और उसकी उपासना करता है। (२) व्यवसायवादका अर्थ होगा समाज को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट देना। (३) श्रेणी-समाजवाद अव्यावहारिक है क्योंकि उत्पादको और उपभोक्ताओं के बीच विभेदकी निरिच्छता रेखा खींच सकना सम्भव नहीं है और यदि यह विभेद स्पष्ट हो भी तो उपभोक्ताओं पर उत्पादको के हावी होने की सम्भावना है। (४) एक आर्थिक समूह राजनीतिक समूहका स्थान आसानीसे नहीं ले सकती। अधिकसे अधिक वह एक सलाहकार परिषदका कार्य कर सकती है।

गुण (Merits). ऊपर बताई गयी कमजोरियों के बावजूद यह मानना ही पड़ेगा कि उद्योगों में लोकतन्त्रकी आवश्यकता और महत्त्व व कर्मचारीतन्त्रीय नियन्त्रण के ज़रूरी और जनताका ध्यान केन्द्रित करके तथा कारखानों के संचालन में श्रमिकों के योग एवं राजनीति और उद्योग दोनों में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के लाभोंसे जनताको अवगत करके श्रेणी समाजवादने मानव समाजकी बहुत बड़ी सेवाकी है।

लेनिन और लेनिनवाद. लेनिन (१८७०-१९२४), १९१७ की रूसी क्रान्ति के विधाता और वर्तमान रूसी राष्ट्रके पिता थे। वे सिद्धान्तवादी भी थे और कर्मयोगी भी। वह १८९० ही में क्रान्तिकारी आन्दोलन में सम्मिलित हो गये थे। उन्होंने मार्क्स और एंगेल्सका अध्ययन करने में अनेक वर्ष विदेशों में बिताये। परिस्थितियों के सुखद-संयोग-वश वह प्रथम विश्व-युद्धके दौरान में जर्मन लोगों द्वारा स्वदेश लाये गये। उन्होंने इस अवसरका उपयोग जारशाही शासनको उखाड़ फेंकने और क्रान्ति कराने में किया। नवम्बर, १९१७, से लेकर अपनी मृत्युपर्यन्त १९२४ तक वह बराबर सोवियत पार्टी के सर्वमान्य नेता रहे। उन्होंने मार्क्सवादका उपयोग रूसी परिस्थितियों में बहुत ही बुद्धिमत्तासे किया, यद्यपि उन्होंने कुछ विशेष बातों में मार्क्सवाद में संशोधन भी किया। उन्होंने मार्क्सवादकी एक बहुत बड़ी सेवा यह की कि मजदूरों में क्रान्तिके लिए लगन फिरसे भर दी।

लेनिन द्वारा मार्क्सवादका संशोधन. (१) यद्यपि मार्क्सने यह कल्पना कर ली थी कि साम्राज्यवाद पूँजीवादका अन्तिम रूप होगा पर लेनिन ने ही इस विचारको पूर्ण रूपसे विकसित किया। स्तालिन द्वारा की गयी व्याख्याके अनुसार लेनिनवाद "साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्ति (Proletarian Revolution) के युगका मार्क्सवाद है।" लेनिन ने यथा-सम्भव अनेक प्रकारोंसे यह सिद्ध किया कि साम्राज्यवाद मरते हुए पूँजीवादका अन्तिम रूप है। एकाधिकृत पूँजी (monopoly capital) और वित्त पूँजी (finance capital) का अवश्यम्भायी परिणाम साम्राज्य-

वाद है। साम्यवादमें मरुते लेकर अन्न तक मुद्ध और संघर्ष होता रहना है। पहले तो स्वयं साम्यवाद की देशों के भीतर ही संघर्ष होता है। उसमें अमीरों और गरीबों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है और ऊपर से देखनेमें यह देश समृद्धिगामी मान्य होता है। जो-जो समय बीतता जाता है त्यो-त्यो सर्वहारा और मध्यवर्ग के बीच यह संघर्ष अधिकाधिक तीव्र होता जाता है। साम्यवादों संघर्ष का दूसरा रूप होता है पूँजीवादी और साम्यवादों देशों की पारस्परिक होड़। साम्यवाद के क्षेत्रमें पुराने साम्यवादियों और नये साम्यवादियोंमें संघर्ष होता है। यह संघर्ष उनके बीच होता है जिनके पास साम्यवाद है और जिनके पास नहीं है। इसका मतलब होता है बच्चे माल, चाबूतों और प्रभाव-क्षेत्रों आदि के लिए छानाछानटो। इन संघर्ष का तीसरा रूप है पोलोनीय उपनिवेशवाद के विरुद्ध एंगिया और अफ्रीका का राष्ट्रीय आन्दोलन।

(२) लेनिन ने यह बनलाने के लिए बड़ा परिश्रम किया कि साम्यवाद सबसे पहले किसी अल्पधिक औद्योगिक देशमें न आकर, जिनकी भाषमें ने आभा की थी, रूप जैसे सामन्तशाही देशमें कैसे गया? इसका कारण लेनिन यह बनलाते हैं कि यद्यपि कम ने पूँजीवाद के चरम रूप का अनुभव नहीं किया था फिर भी उसने पूँजीवाद और उद्योगवाद का अनुभव अप्रत्यक्ष रूपमें किया। यह तो बहुत ही कमजोर स्पष्टीकरण मान्य होता है। तान्त्रालिक रूपों समाज अल्पधिक सामन्तशाही, मैनिक्वादी और निरकुल ही रहा था और उसे फ्रांसीसी पूँजी के शक्ति मिल रही थी, और जनता रहन देनेवाले किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार थी।

(३) मार्क्सवाद के प्रारम्भिक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूपों एक राष्ट्रीय व्याख्या करके लेनिन ने उसका मोधन किया। उन्होंने 'एक देशमें समाजवाद' की सम्भावना के सिद्धान्त को जन्म दिया। उनका कहना था कि जैसे पूँजीवाद अपने उत्थानमें समाज के विभिन्न भागोंमें एक-आ नहीं रहा, ठीक उसी तरह समाजवाद का विस्तार भी सब जगह एक समान नहीं होगा। एक ही प्रयत्नमें समाजमें साम्यवाद जैसी कोई चीज स्थापित नहीं हो सकती। उनका प्रचार असमान और असम्बद्ध रूपमें हो होगा। लेनिन का विश्वास था कि पूँजीवाद के भागों के बीच एक समाजवादी द्वीप मारे समाज के सर्वहारा वर्ग के आन्तरिक आन्दोलन के लिए एक प्रकाश-पुत्र का काम करेगा। 'एक देशमें समाजवाद' के प्रश्न पर स्थापित और ट्रांस्वीमें जागे चलकर तीव्र मतभेद हो गया। ट्रांस्वी की अपने देशमें बना दिया गया और एक हथियारों के मंत्रियों ने उनके मिरके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। कम के नये नेतृत्वने मत् १९२६ में ट्रांस्वी की रूपों के इतिहासमें उनका जीवन स्थान दिखाने का प्रयत्न किया है, और उसकी उन्निद्धि के रूपमें स्थापित के झगड़ों को विगलने का प्रयत्न किया जो मिलने तोमने अधिक मानने ऊँचा उड़ा चला जा रहा है। दोनों समयमें स्थापित के लिए भागों के दिनोंमें जो विशेष आदर भाव था उसे अब स्थिति पूरा बहुर उगरी निम्न हो जा रही है। इन विचारों का नेतृत्व स्पष्ट के कर रहे हैं

और आश्चर्यकी बात तो यह है कि वह अब स्वयं "व्यक्तित्व पूजा (personality cult)" के केन्द्र बनते जा रहे हैं।

(४) मार्क्स ने सर्वहारा वर्गके एकाधिनायकत्व (dictatorship) की शिक्षा दी थी पर लेनिनने पार्टीके एकाधिनायकत्वका समर्थन किया। लेनिनके सिद्धान्तमें पार्टीको सर्वहारा वर्गके हितमें और सर्वहारा वर्गके नाम पर काम करना था। उन्होंने ससदात्मक शासनका तिरस्कार करके शासनकी मौवियत प्रणालीके सिद्धान्तको अपनाया। उन्होंने इस विचारका प्रतिपादन किया कि केवल साम्यवादी दल ही सर्वहारा वर्गकी शक्ति ला सकता है। लोकतांत्रिक केन्द्रीयकरण (Democratic Centralism) के सिद्धान्त पर आधारित साम्यवादी दल मजदूर दलके अग्रिम दस्तेका काम करेगा। दलके 'आन्तरिक लोकतन्त्र' को जीवित रखनेके लिए लेनिन ने आलोचना और आत्मालोचनाका महत्त्व बतलाया। दलको सर्वहारा वर्गके एकाधिनायकत्वका साधन बनना था और उसे श्रमिक वर्गकी एकता, इच्छा-शक्ति और बुद्धिमत्ताका मूर्तरूप बनना था। अन्तमें समय-समय पर अवसरवादी लोगोंको बाहर निकाल कर दलको अपने आपको शुद्ध और सबल बनाना था।

(५) लेनिन इतने अधिक व्यावहारिक विचारक थे कि वह किसी कल्पनाके पीछे मर मिटनेको तैयार न थे। जब उन्होंने देखा कि १९१७-२१ के समर्थवादी साम्यवादका बड़ा प्रयत्न विरोध जनतामें किया जा रहा है, तब उसे वापस ले लेनेमें और उसके स्थान पर पूंजीवादको अनेक सहूलियतें देनेवाली नई आर्थिक नीति लागू करनेमें उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। वैयक्तिक पहलकदमी और वैयक्तिक मुनाफेको एक निश्चित सीमाके भीतर फिरोसे लागू किया गया।

लेनिन की मृत्युके बाद स्तालिन और ट्राट्स्की के व्यक्तिगत और सिद्धान्तिक मतभेदोंने पार्टीकी जड़े हिला दी। ट्राट्स्की किसानोंका पूरा-पूरा सामुदायीकरण करना चाहते थे पर स्तालिन उन्हें और अधिक रियायत देना चाहते थे। स्तालिन समाजवादको सबसे पहले हथमें सफल बनाना चाहते थे, यद्यपि उन्होंने विश्वव्यापी साम्यवादकी स्थापनाके सभी प्रयत्नोंका समर्थन किया।

आलोचना और मूल्यांकन. (१) यद्यपि लेनिन ने कभी-कभी मार्क्स के उपदेशोंसे भिन्न रास्ता अपनाया फिर भी वह मार्क्स के द्वन्द्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद सम्बन्धी उपदेश पर दृढ़ रहे। (२) मार्क्स की भांति ही उन्हें वर्गयुद्ध और सर्वहारा वर्गकी अन्तिम विजय पर विश्वास था। साथ ही उन्होंने मार्क्सवाद की स्वतंत्र व्याख्या भी की। लेनिन ने पार्टीको और पार्टीमें मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के महत्त्व और कार्यको बहुत अधिक प्रधानता दी। (३) लेनिन ने सम्भवतः रूस की परिस्थितियोंसे मेल बैठानेके लिए 'एक देशमें समाजवाद' के सिद्धान्तका प्रतिपादन किया। (४) लेनिनकी प्रधान देन सिद्धान्तकी बारीक व्याख्यामें उतनी नहीं है जितनी सक्रिय एवं गतिशील नेतृत्वमें है, जो उन्होंने अपने देशको उसके सवट काल में दिया। जैसा कि एक लेखकने लिखा है "लेनिनवाद एक वैज्ञानिक विश्वासकी

अपेक्षा एक भावनात्मक आह्वान अधिक है।”

स्तालिनवाद. मोवियन कम्य में १९१७ से आरम्भ होनेवाले समाजवादी पुनर्निर्माण युगके स्तालिनवादको लेनिनवादका ही अनुगामी कहा जाता है। जहां तक स्तालिन क्रान्तिके लक्ष्य पर दुइनामे जमे रहे, वह लेनिनवादके प्रति वफादार रहे। पर अपने व्यक्तिगत प्रभावको बढ़ानेके इरादेसे शक्ति प्राप्त करनेकी अपनी अत्यधिक लालचामें वह लेनिनवादसे दूर हट गये। लेनिन के लोकतांत्रिक-शक्ति-केन्द्रीयकरणके प्रति वह जवानों धड़ा दिखलाने रहे। पर उनके हाथोंमें यह मिडान्त लाइनवर्की अपेक्षा केन्द्रीयकरण अधिक हो गया। लेनिन द्वारा प्रतिपादित पार्टीके भीतर आलोचना और आत्म-आलोचनाका मिडान्त त्याग दिया गया और उसके स्थान पर पूर्ण-केन्द्रीयकरण अपनाया गया। स्तालिन ने न केवल सर्वहारा वर्गके अधिनायकत्वको पार्टीके अधिनायकत्वमें बदल दिया बल्कि पार्टीके भीतर मारे विरोधोंको कुचल कर पार्टी को सर्वोधिकारवादी शासनका माधन बना दिया। इस दृष्टिमें यह लेनिन की अपेक्षा हिटलर और मुसोलिनी के अधिक अनुरूप थे।

लेनिन के सिद्धान्त ‘एक देशमें समाजवाद’ पर स्तालिन कायम रहे। कम के भीतर पूँजीवादके बच्चे-बच्चे बनको उन्होंने निर्दयतापूर्वक कुचला। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओंकी शृंखलामें देशका महान् समाजवादी पुनर्निर्माण किया। कम ने अपनी छठी पंचवर्षीय योजना भी लागू कर दी है। लेनिन द्वारा किये गये साम्राज्यवादके विश्लेषणको स्तालिन मानने रहे और उन्होंने साम्यवादी दलके भीतरी मत-भेदोंमें मरुलतापूर्वक लाभ उठाया। उन्होंने मोवियन राज्यको और कम को ममारमें अकेला न पड़ने देनेमें मरुलता प्राप्त की। विश्व भरके सर्वहारा वर्गके आन्दोलनोंका पय-प्रदर्शन करनेमें लेनिन द्वारा स्थापित तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Third International) को कायम रले रहे। [अन्तर्राष्ट्रीय धनिक मय (International Workers' Association) का तीसरा मगठन पहला मगठन १८६४ में कार्ल मार्क्स ने किया जिसको प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय (First International) की मजा दी गयी है। दूसरा मगठन १८८९ में बनाया गया जिसे द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय कहते हैं। तीसरे मगठनकी स्थापना लेनिन द्वारा मार्च, १९१९, में हुई, इसे तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Third International) कहते हैं। इसका उद्देश्य है मारे ममारके मरुदूराकी एक मूनमें बापना और पूँजीवादी शोषणके विरुद्ध विद्रोह करना]। पर माय ही माय बोल्शेविक पार्टीके मगठनके सम्बन्धमें लेनिन के मिडान्तोंकी उन्होंने मरुलतापूर्वक हत्या की की।

इन सब बातोंमें यह स्पष्ट है कि लेनिनवाद स्तालिन के हाथोंमें आकर धष्ट हो गया। जिस आन्दोलनको स्तालिनने आरम्भ किया उसे मन्चे अपोंमें मरुदूगों और रिमातों की शक्ति नहीं कहा जा मरना। मोवियन (soviets, i.e. elected representative bodies of peoples) जनताके लोकन्धरा मर होनेके बजाय पार्टीके हाथोंमें एक माधन हो गयी जिसमें जनता पर निर्दय निरन्धन रला या मके।

सोवियत रुम के हिनोंकी सिद्धिके लिए "सर्वहारा वर्गकी अन्तर्राष्ट्रीय एकता" का घोषा नारा जीवित रखा गया। सन् १९४३ में कॉमिन्टर्नको अनावश्यक और रूसके युद्ध प्रयत्नोंमें बाधक बताकर उसे भंग करनेमें स्तालिन की कोई हिचक नहीं हुई। Communist International को ही संक्षेपमें Comintern कहते हैं। यह Third International का ही दूसरा नाम है। कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल द्वारा वही भी सफल क्रान्ति करानेका एक भी उदाहरण नहीं है। दूसरे देशोंके साम्यवादियोंको बहुधा सोवियत विदेश नीतिको हानि पहुंचानेवाला 'पांचवा दस्ता' (fifth columnist)^१ समझा जाता था।

स्वीकारात्मक (positive) और नकारात्मक (negative) दोनों ही तरीकोंसे स्तालिनवाद ने यह सिद्ध कर दिया कि साम्यवादकी अपेक्षा राष्ट्रीयतावाद अधिक सबल है। स्तालिन ने टीटो (Tito of Yugoslavia) को सम्मानित साम्यवादियोंकी श्रेणीसे अलग करने में कोई हिचक नहीं की क्योंकि टीटो ने अपनी गृहनीति व विदेश नीतिमें रुम की आज्ञा माननेसे इन्कार कर दिया, यद्यपि आर्थिक मामलोंमें वह अपनेको तथा अपने देशको साम्यवादी ही कहते रहे। स्तालिन की मृत्युके बादसे रुम के साथ यूगोस्लाविया के सम्बन्ध काफी सुधर गये हैं। चीन में भी जब साम्यवाद पूरी तरह कायम हो गया, तभी स्तालिन ने चीन को विश्वसाम्यवादी भातृमण्डलीका सदस्य माना। इसके पूर्व चीन के साम्यवादको वह एक दक्षिण पन्थी विचलन (a rightist deviation) मानते थे।

लेनिन एक अमाधारण प्रतिभाके व्यक्ति थे, उनकी तुलनामें, स्तालिन एक अल्पबुद्धि और मामूली क्षमतावाले व्यक्ति थे। उनके तरीके प्रायः भद्दे (crude) और तानाशाही (dictatorial) होते थे।

माओवाद (Maoism). माओवादको लेनिनवादका ही एक ऐसा स्वरूप माना जा सकता है जो खेतिहर देशकी परिस्थितियोंके अनुकूल हो। भूमि की भूल चीन की प्रधान समस्या रही है और माओवाद उसी समस्याका उत्तर है।

आधुनिक चीन में क्रान्तिकारी प्रवृत्तियोंका श्रीगणेश डा० सनयात सैन (Dr. Sunyat-sen) से हुआ। इन्होंने सन् १९११ में अपने तीन सिद्धान्त—राष्ट्रीयतावाद, लोकतंत्र तथा जनताकी जीविका अथवा समाजवाद—ससारके सामने रखे। केवल इन तीन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किसी नये स्वर्ण या नये ससारका निर्माण

^१ Fifth Columnist. १९३६ में स्पेनके जन विद्रोहमें जो जनरल फ्रांकोके नेतृत्वमें हुआ था, चार दस्तोने राजधानी मैड्रिड पर प्रत्यक्ष आक्रमण किया था, परन्तु बहुतेरे ऐसे लोग थे जिन्होंने गुप्त रूपसे तोड़-फोड़ उपद्रव करके, फूट डालकर और भेदिया बनकर गवर्नमेन्टको खोखला किया। इन छिपे हुए विद्रोहियोंको पाचवां दस्ताकी सजा दी गयी तबसे ऐसे लोग जो सगे बनकर दुश्मनकी मदद करते हैं पाचवां दस्ता (fifth columnist) कहलाने लगे हैं।

नहीं कर सका। सन् १९१९ तक चीन की हालत बिगड़ती ही गयी। इसी समय रूस में बोलशेविकवाद का मिनास दिन प्रतिदिन बलुप्त होना जा रहा था। चीन के पड़े-लिपे समझदार लोग साम्यवाद में महानुभूति रखने लगे। १९१८ में पेरिस में एक साम्यवादी पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। इसी समय प्रसिद्ध दार्शनिक ली ताओ-चाओ (Li Tao-chao) साम्यवाद की ओर झुक रहे थे। उनके पुस्तकालय में काम करनेवाले माओ-जे-तुंग (Mao Tse-tung) पर अपने मान्यता गहरा प्रभाव पड़ा और वह साम्यवादी समाज में एक विद्यार्थी मन्दिर के रूप में शामिल हो गये।

इस बीच चीन और रूस के बीच बर्तारियों का आदान-प्रदान हो रहा था। डा० मनयात सेन स्वयं भी साम्यवाद की ओर महानुभूति पूर्ण हो रहे थे। मुम्बई, १९२१, तक पेरिस, कैंट, गोंगाई और हुनान में साम्यवादी दल की स्थापना हो गयी। साम्यवादी दल के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग का उत्थान करना मार्ग बना रहा था।

साम्यवादी दल का संगठन ठोस लेनिनवादी तरीके पर हुआ था। इसका मनयात सेन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अपने तीन निष्ठान्तों में से एक राष्ट्रीयतावाद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने लेनिनवादी पद्धति पर अपने दल का संगठन किया। डा० मनयात सेन द्वारा स्थापित को-मिन-तांग (Kuo Min-tang) दल मन्त्री वर्ग का समूह बन गया। साम्यवादियों ने कहा गया कि इस दल में शामिल होकर इसे शांति की गतिशील शक्ति बनायें। साम्यवादी वैयक्तिक रूप से इस दल में शामिल हुए। साथ ही साथ साम्यवादी दल भी पृथक् कायम रखा गया। ऊर्जा साम्यवादी नेना बोरोदिन (Borodin), जो रूस में चीन आ चुके थे, और मनयात सेन—ये दोनों—को-मिन-तांग दल के प्रधान मंचालक थे।

इस समय चीन के लोग नेतृत्व के लिए संगठित हो रहे थे। माओ-जे-तुंग जो स्वयं एक दृढ़ परिवार के थे, ज्ञान के लिए विमानों का संगठन करने लगे। वह जानते थे कि जनता में किस प्रकार अमनोप पैदा किया जाता है। विद्यार्थी, पत्रकार और इस प्रकार के अन्य लोग उनके दल में शामिल हो गये। साम्यवादियों ने को-मिन-तांग दल में अनेक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिये और एक साम्यवाद विरोधी और मानव-विरोधी कार्यक्रम तैयार किया गया।

इसी बीच डा० मनयात सेन की मृत्यु हो गयी और उनके उत्तराधिकारी दक्षिण-पश्चिमी मेनागति फ्यांग काई-शेक (Chiang kai-shek) साम्यवादियों और शान्ति-कारियों के विरुद्ध हो गये। शान्तिकारियों का बड़ी संख्या में को-मिन-तांग में विकास दिया गया और जिन पर जरा भी सन्देह था उन सबको गोली मार देने का आदेश हो गया। बोरोदिन छिड़ कर रूस भाग गये।

जब फ्यांग काई-शेक अपने निर्दय तरीकों का उपयोग कर रहे थे तब विमानों और मशीनों के गहरे सम्बन्ध मूत्र (alliance) कायम किये जा रहे थे और लोक-तंत्रीय अधिनायकत्व स्थापित करने की योजनाएं बनाई जा रही थीं। यह मनयात सेन की मौलिक शक्त के बिना प्रभावपूर्ण बरत नहीं उठाना जा सकता क्योंकि लोक मेनाओं

(साम्यवादी झण्डेका रंग लाल होता है। इसीलिए प्रायः साम्यवादियोंको लाल या reds भी कहते हैं) की स्थापना हो रही थी।

सन् १९२७ से राष्ट्रवादियों (को मिन-तांग) और साम्यवादियोंके बीच तीव्र मतभेद हो गया। कृषि सुधारों और सशस्त्र विद्रोहों पर जोर दिया गया। साम्यवादियोंका निर्दयतापूर्वक दमन किया गया और देशमें गृह-युद्धकी आग भड़क उठी। पर माओ से-तुंग अपनी शक्ति बढ़ानेमें सफल हुए और १९३१ में वहनवस्थापित अस्थायी (Provisional) सोवियत सरकारके अध्यक्ष बने। (सोवियतके अर्थ रूमकी सरकार नहीं है। सोवियत सरकारका अर्थ है सोवियत प्रणालीकी सरकार जिसमें सोवियतों द्वारा शासन होता है।)

इसी समय मंचूरिया पर जापानका हमला हुआ। सन् १९३१ में के० एम० टी० (को मिन-तांग) द्वारा मुकुदेन और जहोल प्रान्तोंको छोड़ देनेसे साम्यवादियोंको विरोधी प्रचारका बड़ा अवसर मिल गया। जिस समय राष्ट्रीयतावादी जापानियोंसे युद्ध करनेमें लगे हुए थे उसी समय साम्यवादियोंने राष्ट्रीयतावादियों (K.M.T.) के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन सगठित किया। के० एम० टी० इस परिस्थितिका मुकाबला न कर सका और उसने सन् १९३५ में बाहरी सफ़टकी समाप्त करनेके उद्देश्यसे साम्यवादी दलसे राष्ट्रीय एकताकी प्रार्थना की। दोनों दल अपने मतभेद भूल कर और एक होकर अपने सामान्य शत्रु जापानको हरानेमें लग गये। पर युद्धके दौरानमें च्यांग काई-शेक ने अपनी विशिष्ट फौजें सुरक्षित रखी ताकि युद्धके बाद साम्यवादियोंसे निपटा जा सके।

युद्धके बाद च्यांग काई-शेक का दल भ्रष्टाचार और कुनबापरस्ती (nepotism) के कारण दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बदनाम होता जा रहा था। जनताकी कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओंकी बराबर उपेक्षाकी जाती रही। इससे साम्यवादियोंको आगे बढ़नेका मौका मिला। थोड़ा-थोड़ा करके उन्होंने सारे चीन पर कब्ज़ा कर लिया और १९४९ में च्यांग काई-शेक और उनके अनुयायियोंको फारमूसा द्वीपमें खदेड़ दिया गया। जहाँ वे अमेरिकी मददसे समय-समय पर साम्यवादियोंके विरुद्ध संग्राम करते आ रहे हैं। चीनकी नई सरकारको ब्रिटेन, रूस और अनेक एशियाई देशों द्वारा मान्यता मिल चुकी है। पर अब भी वह संयुक्त राष्ट्र संघके बाहर है। बड़े देशोंमें, सम्भवतः अमेरिका चीनकी इस साम्यवादी सरकारको मान्यता देनेमें बिल्कुल आखीरमें होगा।

मार्क्सवाद-लेनिनवादकी शिक्षाओंमें माओ का योग.

साम्यवादी चीनमें साम्यवादी रूसके सगठनका बड़ी बारीकीसे अनुकरण किया गया है। सामन्तवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद पर सबल प्रहार किये गये हैं। पर चीनमें किसानोंके सगठनके सम्बन्धमें रूससे बिल्कुल भिन्न मार्ग अपनाया गया। साम्यवादी रूस तो खेतोंके समूहीकरणमें बहुत आगे बढ़ चुका है पर चीनमें

किसानोंका स्वामित्व (peasant proprietorship) एक सामान्य व्यवस्था है। किसी ऐसे व्यक्तिको जमीन रखनेकी आज्ञा नहीं है जो स्वयं उसे जोत न सके। इसके परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग समाप्त हो चुका है। माओ ने ग्रामीण सर्वहारा और शहरी सर्वहारामें बहुत विभेद किया है। उनका साम्यवाद इस समय ग्रामीण सर्वहारा वर्गका साम्यवाद है।

विरोधियोंमें और यहाँ तक कि ईमानदारोंसे मतभेद रखनेवालोंमें भी निपटनेमें सख्त तरीके अपनाये गये हैं। विचारोंको यात्रिक एकरूपता कायम करनेमें 'मस्तिष्क धुद' (brain washing) का तरीका अपनाया गया है। फिर भी माओ से-तुंग की प्रतिभा विरोधियोंको अपनेमें मिला लेनेमें रहो है न कि उन्हें समाप्त कर देनेमें, जैसा कि स्तालिन किया करते थे। न केवल किसानों और शहरी सर्वहारा वर्गको बल्कि मध्यम वर्गों और सम्पन्न देश-भक्त लोगोंको भी कम्युनिस्ट पार्टीमें शामिल होने दिया गया है। इस प्रकार सर्वहारा वर्गकी प्रभुताके पुराने विचारोंको 'वर्गों सहयोगकी दिशा' में संशोधित कर दिया गया है। माओने अपनी पुस्तक 'नवीन लोकतन्त्र (A New Democracy-१९३८)' में 'सामन्तो और देशद्रोही पूँजीपतियोंके बचेखुबे प्रतिक्रियावादी अशोंके विरुद्ध 'लोकतन्त्रीय अधिनायकत्व' की धारणाके आधार पर जनताके एक नये मित्र-सम्बन्धका समर्थन किया है।

एक अमाधारण सैनिक नेता होते हुए भी माओ-से-तुंग का विश्वास है कि सेना को असैनिक (civilian) सत्ताके अधीन होना चाहिए। यह उनका सचम्प है कि साम्यवादी आन्दोलनको महत्वाकांक्षी मेनापतियोंका खिलाफ नहीं बनने दिया जायगा जैसा कि सनयात सेन की मृत्युके बाद वर्षों तक होता रहा।

विचारों और सत्ताओंके क्षेत्रमें हीगेल और मार्क्स के 'अन्तर्विरोधों के मिद्धान्त' को माओ ने माना है। मार्क्स की भाँति उनका भी विश्वास है कि विचारोंका विकास पदार्थोंसे होता है। युद्धोत्तर सत्ताके बारेमें माओ स्वीकार करते हैं कि सरकार समाजवादी और पूँजीवादी गुटोंमें बँटा हुआ है। दोनों ही में अपने अन्तर्विरोध हैं। माओ के अनुसार उनमें केवल एक अन्तर यह है कि पूँजीवादके अन्तर्विरोध केवल युद्ध और क्रान्तिके द्वारा ही दूर हो सकते हैं पर समाजवादके अन्तर्विरोध क्रान्तिपूर्वक दूर हो जायेंगे। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह केवल ख्याली पुलाव है और साम्यवादके पिछले इतिहासमें माओ के इस दावेकी पुष्टि नहीं होती।

बी० आई० श्वार्ट्ज़ (B. I. Schwartz) अपनी पुस्तक *Chinese Communism and the Rise of Mao* में लिखते हैं कि चीनी साम्यवादी अपने आपको बट्टर मार्क्सवादी लेनिनवादी मानते हैं। वे अपनी पार्टीको 'ऐतिहासिक मुक्तिका एजेंट' और सर्वाधिकारवाद (totalitarianism) को 'लेनिनवादी धारणामें निहित प्रवृत्ति' मानते हैं (Chinese Communists regard the party as the agent of historic redemption and look upon totalitarianism as a tendency inherent in Leninist conception

of the party)। द्वादश के अन्तिम शब्दोंमें 'सारासमें यद्यपि चीनी साम्य-वाद्ने अन्तिम रूपमें तथ्यो द्वारा यह मिथ्य कर दिया है कि साम्य-वादी पार्टी और सर्वहारा वर्गके बीच किसी प्रकारके भी आवश्यक संगठनात्मक सम्बन्धका अभाव है; फिर भी इस आन्दोलनमें मार्क्सवादी लेनिनवादी परम्पराके कुछ आधारभूत तत्त्व अब भी कायम हैं। (In sum,.....while Chinese Communism did conclusively demonstrate in fact the utter back of any necessary organic relation between Communist parties and the industrial proletariat, the movement still retains certain fundamental elements of Marxist-Leninist tradition.)^१

भारत के लिए समाजवादी ढांचा या समाजवादी समाज.

जबसे जवाहरलाल नेहरू मई १९५४ में चीनसे वापस आये तबसे वह भारतमें समाजवादी समाजकी स्थापनाके लिए उत्साहसे बहुत भरे हुए हैं। १९५५ के आरम्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अवादी (Avadi) अधिवेशनमें यह स्वीकार किया गया कि ऐसे समाजकी स्थापना ही हमारा लक्ष्य है। १९५६ में अमृतसर अधिवेशनमें 'समाजवादी ढांचा (socialist structure)' शब्दका उपयोग किया गया। सम्भवतः इस परिवर्तनका अर्थ यह है कि जो आदर्श योजनाके नक्शेके रूपमें अब तक फाइलमें दबा था, वह अब एक ढांचेकी तरह अपने पावों पर खड़ा होने लगा है। "समाजवादी समाज" या "समाजवादी ढांचा" शब्द जानबूझकर अस्पष्ट रखे गये हैं। क्योंकि समाजवादका अर्थ सिद्धान्तमें या व्यवहारमें सबके लिए एक नहीं होता। ब्रिटेनके मजदूर दलका समाजवाद, योरोपीय देशोंके समाजवादमें अनेक रूपोंमें भिन्न है और ये दोनों रूस और चीन के साम्यवादमें भिन्न हैं। भारत में भी सभी समाजवादी समाजवादके अर्थ पर एक मत नहीं है।

कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) में भाषण देते हुए श्री नेहरू ने कहा कि "भावी भारतके सम्बन्धमें जो कुछ मेरे दिमागमें है वह निश्चित और पूर्ण रूपसे समाजका एक समाजवादी चित्र है।" उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत उद्यम समाप्त करनेका उनका कोई इरादा नहीं है। पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सम्पत्ति जोड़नेकी प्रवृत्ति न केवल समयके विपरीत है बल्कि अनैतिक भी है। नेहरूजी के अनुसार नये समाजको अवसरकी समानता पर आधारित होना होगा और आश्चर्यकी बात यह है कि यह समानता बहुत बड़ी मात्रामें पूँजीवादी समाजमें भी घरनी जाती है, जैसे अमेरिकी समाजमें। नेहरूजी आगे कहते हैं कि भारत के विधानमें यह निश्चय किया गया है कि भारतीय जनताका लक्ष्य कल्याण-

^१ वही पुस्तक पृष्ठ २०४.

कारी राज्य है जिसमें व्यक्तिको समाजके लिए और समाजको व्यक्तिके लिए जीवित रहना है। व्यावहारिक दृष्टावलीमें नेहरूजीके अनुसार समाजवादी समाजवा अर्थ है "जीवित रहनेका अधिकार; जीविकोपार्जनके लिए काम पानेका अधिकार, और जो कुछ कोई अर्जित करे वह सारा वा सारा उसे मिले।"

प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, विद्वान और व्यवहारविद् डा० जॉन मयाई का कहना है कि समाजवादी समाजकी दो मुख्य बातें स्वाधीनता और समानता हैं। समाजवादको एक मत या संगठनका एक प्रकार माननेसे इन्कार करते हुए डा० मयाई जोर देकर कहते हैं कि "समाजवाद जीवनकी एक पद्धति और समाजके प्रति एक दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य है, ऐसे साधनों द्वारा, जो एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाजके लिए उपयुक्त समझे जा सकें, सामाजिक न्यायका अधिकतम व्यावहारिक विस्तार करना। जिन साधनों द्वारा इस समाजवादी समाजकी स्थापना होती है वे हैं—(१) प्रत्येक मानव व्यक्तित्वका सम्मान व प्रतिष्ठा, (२) प्रेमका मिद्वान्त, और (३) साहचर्य या सहयोगकी भावना।

आश्चर्यकी बात तो यह है कि डा० मयाई राष्ट्रीयकरण या उत्पादनके साधनों का राज्य द्वारा अपने अधिकारमें लिया जाना समाजवादके लिए अनिवार्य नहीं मानते क्योंकि उन्हींके शब्दोंमें "राष्ट्रीयकरणकी मांग करनेवालोंके दिमागमें जो उद्देश्य होते हैं उनमें से अनेककी सिद्धि राष्ट्रीयकरणके अनिद्विष्ट अन्य मापनेसे—विधान, शासकीय आदेश और राजस्व सम्बन्धी उपायोंसे भी हो सकती है। इसकी सम्भावना नहीं है कि नेहरूजी और अन्य अनेक व्यक्ति जिनमें वर्तमान लेखक भी शामिल हैं इस विचारमें सहमत होंगे। पर डा० मयाईके इस कथनमें उनका तीव्र मतभेद होनेकी सम्भावना नहीं है—"मैं नहीं समझता कि यह समाजवाद का कोई तात्त्विक अंग है कि व्यक्तिगत उत्थान या पहलूदमोहा नियंत्रण किया जाय या उसे दबा दिया जाय।"

डा० मयाई भारतीय अर्थ-व्यवस्थाको मार्क्सवादीक क्षेत्र और निजी क्षेत्रमें बांटे जानेके वर्तमान ढंगका समर्थन करते हैं। यद्यपि उन्हें आशंका है कि यदि मावपानीसे काम न लिया गया तो आपिक लोकतन्त्रके नाम पर वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर बठोर प्रतिबन्ध लगा दिये जायेंगे। वह चाहते हैं कि छोटे उत्पादक और बड़े उत्पादकके बीच एक उचित सन्तुलन कायम रखा जाय ताकि दोनोंमें किसी एकका दूसरेके लिए बलिदान न हो। एक दूसरा भय उन्हें यह है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य आनेवाली योजनाओंकी आवश्यकताएँ देशके साधनोंके बूतेके बाहर होनेके कारण एक ऐसी स्थिति पैदा कर देंगी कि जिसमें बीमन बड़ेगी और "एक निश्चित मुद्रा-स्फीतिकी प्रवृत्ति" फैलेगी। हम अपने चारों ओरकी परिस्थिति देखकर समझ सकते हैं कि वह बेबन काल्पनिक भय नहीं है।

समाजवादी समाजमें धनका न्यूनतम वेतन निश्चय होगा। हर व्यक्तिके लिए पर्याप्त अवकाश होगा और वृद्धों व अरोंकी देखभाल की जायगी। समानता

के सिद्धान्तके बारेमें डा० मयाई "न्यायकी समानता (Equality in justice), सबके लिए समान विधि (Equality before law), विकास और उन्नतिके लिए सबको समान अवसर, शिक्षा, उद्यम और आजीविका-चयनमें सबको समान अवसर" पर जोर देते हैं। वह आय और सम्पत्तिकी भी समानताका प्रश्न उठाते हैं, किन्तु अपने देशकी मौजूदा अवस्थामें वह इसको लागू करनेके पक्षमें नहीं हैं। खेतीकी भूमि व्यवस्थाके प्रश्न पर भी वह अपना कोई निश्चित मत प्रकट नहीं करते। एक स्वतंत्र समाजमें स्त्रियों और बच्चोंके साथ न्यायोचित व्यवहार पर, समाज सेवा संघ, भारत सेवक समाज और सामुदायिक योजनाओं द्वारा की जानेवाली निःशुल्क सामाजिक सेवाओं पर तथा धार्मिक आश्रमों तथा अन्तर्राष्ट्रीय माई-चारे पर वह विशेष रूपसे जोर देते हैं।

एक कृत्रिवादी और धार्मिक दृष्टिकोणसे समाजवादी समाजका यह एक प्रशस्नीय चित्र है। पर अतिवादी चाहेगें कि राज्य हमसे बहुत आगे बढ़े। कांग्रेसके भूतपूर्व अध्यक्ष यू० एन० डेबर ने समाजवादी समाजकी परिभाषा देनेका प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि आर्थिक पक्षमें समाजवादी समाजमें कमसे कम निम्नलिखित तीन बातें व्यक्त होती हैं—(१) कुछ मौलिक या आधारभूत उद्योगोंका राष्ट्रीय स्वामित्व या राष्ट्रीय नियंत्रण, (२) सम्पत्तिका न्यायसंगत वितरण और (३) अवसरकी समानता। हम अपनी तरफसे कह सकते हैं कि सामाजिक पक्षमें समाजवादी समाजका अर्थ होना चाहिए, एक जातिहीन और वर्गहीन समाज, एक ऐसा समाज जिसमें मनुष्य मनुष्यके बीच वर्तमान कृत्रिम विभेद नष्ट कर दिये गये हों। हमारा विश्वास है कि जब तक मानव प्रवृत्तियों, और इच्छाओं तथा राष्ट्रीय चरित्र में पूरा-पूरा परिवर्तन नहीं होता तब तक बड़े-बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन सम्भव नहीं हैं।

पहले हम आर्थिक पक्षको ले। यद्यपि "राष्ट्रीयकरण" बहुतेके लिए एक मोहक शब्द है पर वह कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको घुमाते ही रात भरमें एक नये समाजकी रचनाकी जा सके। भारत में समाजवादी समाजकी रचना हो रही है। यह रचना हो रही है बहुमुखी जलविद्युत् योजनाओं (जिनमें सिंचाई योजनाएँ भी शामिल हैं) द्वारा, पड़ती जमीनको खेती योग्य बनाने, और खादकी मिलों द्वारा, देशके भीतर भस्म पालन, पशु सुधार, रेलों, हवाई जहाजों, और नागरिक उड्डयनों और जीवन बीमाके राष्ट्रीयकरण द्वारा, जमींदारीके उन्मूलन, बशीनोंके यंत्र निर्माण और छोटे-छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगोंको दी जानेवाली सरकारी आर्थिक सहायताके द्वारा। द्वितीय पंचवर्षीय योजनामें निजी उद्योगों (१५०० और १७०० करोड़ रुपयेके बीच) की अपेक्षा सार्वजनिक उद्योगों पर (४८०० करोड़ रुपये) बहुत अधिक व्यय करनेकी व्यवस्थाकी गयी है। पहलेकी अपेक्षा अब सभी स्तरोंकी शिक्षा पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आवास व्यवस्था, और सामाजिक कल्याण तथा लोगोंको काम धन्योमें लगाने की समस्या पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा। द्वितीय योजनाके

पांच वर्षोंमें ९० लाखमें लेकर एक करोड़ तक नयी कामकी जगहें बनानेका लक्ष्य रखा गया है। पर समयकी आवश्यकताओं देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है।

प्रो० जॉन साउंडर्स (Prof. John Saunders) लिखते हैं कि समाजवादी समाजकी मांग है न्याय (एक अधिक न्यायमग्न विवरणके अर्थ में), सामाजिक सुरक्षा और अधिक पूर्ण जीवन। उनका कहना है कि भूमि मुधार, ऋणमुक्ति, और वैज्ञानिक मनो को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दोहरी फसल, मिर्चाई और खाद आदिके द्वारा धन उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए।

भूमिमुधार और उनमें सम्बन्धित विषयोंके बाद साउंडर्स पूर्ण रोजगारी (सबके लिए काम) और जीवन स्तरको ऊंचा उठानेको तात्कालिक लक्ष्य मानते हैं जिसे पूरा किया जाना चाहिए। उन्हें इस बात पर शंका है कि खेतिहर मजदूरोंको सालमें ८२ से लेकर ११५ दिनों तक बेकार रहना पड़ता है। बेकारोंके साथ-साथ दूसरी बहानी हुई बुराई आवादीकी अधिग्रहण है। अनेक प्रगतिशील देशोंमें जन्मका अनुपात या तो स्थायी है या कम होना आ रहा है। पर भारतमें उनके कम होनेके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। दूसरी ओर मृत्युकी संख्या घटती जा रही है।

श्री विनोबा भावे स्वतः ग्रैंटिग तरीकोंमें समाज में नयी व्यवस्था लाना चाहते हैं। एक स्थानमें दूसरे स्थान की पदमावा करने वाले अपने कुछ माधियोंकी सहायता से वह गरीबोंमें बांटनेके लिए ४० लाख एकड़में अधिक भूमि प्राप्त करनेमें सफल हुए हैं। फिर भी गरीबोंकी हला कुछ अधिक मुफ्ती नहीं दिखाई देनी। भावे का विश्वास है कि किसी भी स्थान में सामुदायिक योजना लागू करनेमें पहिले भूमि का किरमें विवरण हो जाना चाहिए।

सर्वोदय आन्दोलनका ध्यान भारतके ६ लाख गावों पर केन्द्रित है। भारत सरकार द्वारा चालू किये गये बड़े औद्योगिक कारखानों और सिंचाई के कार्योंकी वह संका की दृष्टिमें देखता है। ग्रामीण जीवन में नयी स्फूर्ति लाना ही उसका आदर्श है। यह उत्पादक और उपभोक्ता पर केन्द्रित अर्थव्यवस्थाका समर्थन करता है और उस अर्थ-व्यवस्थाका विरोध करता है जिसका प्रथम उद्देश्य विदेशी मुद्रा और शान्तर पूँजी प्राप्त करना है। गावोंके वर्तमान तालाबोंको नये सिरेमें ठीक किया जाना चाहिए; उन्हें गहरा किया जाना चाहिए और पानीके छोटे-छोटे तालाबोंमें उन्हें भरना चाहिए। देश भरमें नहरोंका जाल बिछा हो। नदियों और उनकी घाटियोंको सीमाएँ मानकर आपस परिसम्पत्तियोंके आधार पर राज्योंका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। जलविद्युत् योजनाओंके लिए छोटे-छोटे उत्पादक केन्द्र होने चाहिए। नदियोंके उद्गम क्षेत्रोंमें उद्योगोंको और मृत्तानों की तरफके क्षेत्रों पर शीतो को केन्द्रित किया जाना चाहिए। जल यातायात का इनका अधिक विकास किया जाना चाहिए कि वह देशके आन्तरिक व्यापार व्यवसाय को संभाल सके और लाखों व्यक्तियोंकी रोजगार दे सके। ग्रामीणों और उनकी बँसगाइयोंकी आवश्यकताओंको पूरा करने के लिए ही मरकोंका निर्माण होना चाहिए। बड़े उद्योगोंको निजी हाथोंमें नहीं छोड़ना

चाहिए। कोयला और बिजली ग्रामीणोंके लिए सुलभ होनी चाहिए। सर्वोदय आदोलन हाथकी कताई हाथकी बुनाई, तेलके पेरे जाने तथा अन्य दस्तकारियों पर बहुत अधिक जोर देता है।

विद्वकी अर्थव्यवस्थामें भारत का योग उसके गांव है। इस सम्बन्धमें महात्मा गांधी कहते हैं: "यदि गांव नष्ट हो जाता है तो भारत भी नष्ट हो जायगा। तब फिर वह भारत नहीं रह जायगा और तब मसारके प्रति उमका सन्देश लुप्त हो जायगा।"

सगठनके पथमें, २ अगस्त, सन् १९५२, को आरम्भ की गयी सामुदायिक योजनाएँ (community projects) जिनकी संख्या ५५ हैं, समाजके समाजवादी ढाँचेके अनुरूप ही मानी जायेंगी। उन्हें जनताके हितके लिए, जनता द्वारा, जनता की योजना कहा गया है। इन योजनाओंको आरम्भ करनेवालोंको आशा है कि ये योजनाएँ सारे देश भरके लिए पथप्रदर्शक हो जायेंगी। इन योजनाओं पर होने वाले व्ययका ६४ प्रतिशत जनतासे रुपयों, भामानों या धर्मदानके रूप में मिलता है। यह हमके कुछ भागों में प्रचलित अनिवार्य धर्मसे कितना भिन्न है! हर योजनाको तीन क्षेत्रों (blocks) में बांटा जाता है और हर क्षेत्रमें १०० गांव होते हैं। हर गावमें एक ग्रामसेवक (village level worker) होता है जिसकी सहायता एक 'स्टॉकमैन' करता है। हरेक क्षेत्रमें एक क्षेत्रीय योजना अधिकारी (Block Development Officer) होता है। जिलेका कलक्टर डिप्टी विकास कमिशनर का काम करता है। यह सब अंग्रेजी कालकी प्रशासनीय व्यवस्था से आश्चर्यजनक तीर पर विपरीत है।

हालमें सामुदायिक विकास योजनाओंके काममें राष्ट्रीय विकास सेवा योजनाओं द्वारा वृद्धि की गयी है। इन योजनाओंने सामग्री और रसदके रूप में सामुदायिक योजनाओंमें महत्वपूर्ण योग दिया है। ६ लाख गावोंमें से १ लाख २० हजार गाव इन दो योजनाओंके भीतर आ गये हैं और शेष गाव भी शीघ्र ही योजनाओं में आ जायेंगे।

कल्याणकारी राज्य. यह रोचक बात है कि भारत ने सन् १९५० में अपने संविधान का शुभ आरम्भ जिस कल्याणकारी राज्यके आदर्श के साथ किया था वह आदर्श धीरे-धीरे वर्तमान समाजवादी समाजकी धारणाके साथ घुल-मिल गया है, यद्यपि यह स्पष्ट है कि एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी होना आवश्यक नहीं है। २१ जुलाई, १९५४, को अजमेर के कांग्रेस अधिवेशनमें इस आशयका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था: "सहकारी सामान्य सम्पत्ति (Co-operative Commonwealth) या कल्याणकारी राज्यकी स्थापना करना कांग्रेसका लक्ष्य है"। तबसे कल्याणकी व्याख्या अधिकतर आर्थिक शब्दावलीमें की गयी है।

डा० अब्राहम (Dr. Abraham) (जिनका उद्धरण प्रो० एस० घोष ने दिया है) ने कल्याणकारी राज्यकी व्यवस्था इस प्रकार की है: "एक ऐसा समाज जिसमें राज्य शक्तिका उपयोग जानबूझकर, समाजकी आर्थिक शक्तियों की सामान्य प्रक्रियामें सुधार करनेके लिए, इस उद्देश्यसे किया जाता है कि हर नागरिकके लिए आयका अधिक

न्यायमंगत वितरण हो और उसकी सम्पत्ति और उसके कामके बाजार मूल्यका ब्याल विये बिना उसे एक आधारभूत न्यूनतम वास्तविक आय प्राप्त हो सके। टी० डब्ल्यू० केण्ट (जिनका उद्धरण भी प्रो० घोष ने दिया है) का कहना है कि "कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकोंके लिए सामाजिक सेवाओंका एक व्यापक क्षेत्र प्रस्तुत करता है। नागरिकोंकी सुरक्षा उसका मुख्य उद्देश्य होता है। यदि कोई अपनी आपका साधन खो देता है तो उसकी सहायता करनेका उत्तरदायित्व राज्य होता है।"

घोषके कथनानुसार एक कल्याणकारी राज्यके निम्नलिखित तीन आधार होते हैं : अधिक न्याय, बेकारी-वृद्धावस्था आदिमें सुरक्षा और व्यक्तिके लिए स्वाधीनता। कल्याण की धारणा केवल भौतिक अर्थोंमें ही न की जा कर मानव स्वतंत्रता और प्रगति के अर्थोंमें भी की जानी चाहिए। बांधेमेंके अजमेर प्रस्तावमें, जिसकी चर्चा ऊपरकी गयी है, कल्याणकारी राज्यकी व्याख्या बेकारीके विनाश, अधिक उत्पादन और न्यायमंगत वितरणके रूपमें की गयी है।

कल्याणकारी राज्यकी जो भी धारणा हम करें, इसमें अनेक सामाजिक सेवाएँ जैसे शिक्षा, वृद्धावस्थामें पेंशन, बेकारीमें वेतन, और मार्गजनिक सहायता सम्मिलित रहेंगी। यद्यपि अमेरिका की भरदार इनमें से अनेक सेवाएँ करती है, पर कल्याणकारी राज्य इसके ऊपर उठेगा और देशमें दैवी शाप माना जाना है क्योंकि इसे समाजवादी राज्य गन्द का पड़ोसी समझा जाता है।

कल्याणकारी राज्यमें सर्वत्र एक बहुत बड़ा खतरा यह होता है कि यह राज्य अपने आपको बहुत आसानीसे एक सर्वाधिकारवादी राज्यमें बदल सकता है। घोष का यह विचार सही है कि मनुष्यको नैतिक स्वाधीनताके साधनके रूप में ही भौतिक कल्याण सार्थक है। यदि भारतमें कल्याणकारी राज्य या समाजवादी समाजकी स्थापना भली भाँति करनी है तो यह काम अहिंसात्मक और लोकतांत्रिक ढंगसे ही किया जाना चाहिए। लोकतन्त्र और कल्याणकारीराज्यके आदर्शोंमें मेल बैठाया जाना निरन्तर आवश्यक है। कुछ लोगकोई कहना है कि योजना और गवर्नर दोनों माप-माप नहीं चल सकते।

योजनाके बर्तकारी तंत्रीय हो जानेका खतरा सर्वत्र हमेशा रहता है। यदि योजनाको सफल होना है तो सम्पूर्ण कार्य-कलापका नियंत्रित होना जरूरी है। यदि आजकलके बहुभार सम्बन्धी विचारोंको बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया तो सम्भावना यह है कि नियोजन अधूरा और दोषपूर्ण रह जायगा और स्वयं ही अपनेको पराजित कर देगा अर्थात् विफल हो जायगा। नियोजनके सफल होने के लिए यह जरूरी है कि यह अत्यधिक केन्द्रीयकरणसे तथा दलगत तानाशाहीसे मुक्त रहे और इसका बम न टूटे। इस अन्तिम विषय पर लिखते हुए बारबारा वूटन (Barbara Wootton) कहती है : "यदि राजनीतिक दलोंके अस्तित्वका अर्थ यह है कि हर छत्रों महीने हम अपने इरादे बदला करें तो मुझे भय है कि लम्बी अवधि वाली

योजनाए पूरी नहीं हो सकेंगी। प्रो० जॉन साउंडर्स (Prof. John Saunders) का मत है कि आजकी परिस्थितियोंमें भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा आर्थिक अधिनायकत्वमें नहीं बल्कि निष्फल लोकतंत्रमें है।

एक दूसरा इतना ही बड़ा खतरा जनताकी अरुचि या अग्रहानुभूति है। जब तक जनतामें उत्साह न हो, समाजवादी समाजके प्रति लगन न हो और लोग इसके लिए सत्यनिष्ठा और ईमानदारीसे काम करने की तैयारी न हो तब तक नियोजनमें पूरा-पूरा लाभ उठा सकना असम्भव है।

विषयके हर पहलूका निचोड़ देते हुए प्रो० थोप बुद्धिमतापूर्वक लिखते हैं, "हमें समृद्धिके लिए योजना बनानी चाहिए, पर स्वतंत्रताका भूख्य देकर नहीं, हमें अपनी योजनाओंको राज्यकी दबाव डालनेवाली शक्ति अथवा सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियोंके बलमें नहीं बल्कि जनताके सक्रिय और उत्साहपूर्ण सहयोग द्वारा कार्यान्वित करना चाहिए। हमें राजनीतिक पार्टियां रखनी चाहिए—इसलिए नहीं कि वह दूसरी पार्टियोंको दबावें या अपने सदस्योंको ही अपनी पार्टीके भीतर दबावें बल्कि इसलिए कि वे जनताको सार्वजनिक महत्त्वके मामले पर शिक्षित करें और सार्वजनिक नीतियोंके कार्यान्वयन में सहयोग देनेके लिए उन्हें प्रेरित करें; हमें ऐसा राज्य चाहिए जिसका गठन एकात्मक न हो बल्कि जो छोटे-छोटे लोकतंत्रोंका एक सन्तुलित जाल हो जिसमें जनता सक्रिय और मीधा हिस्सा ले सके। इसलिए ही नहीं कि एक अमूर्त राज्यकी मदद हो बल्कि इसलिए कि जनता सम्प्रभु नागरिक बननेकी शिक्षा ले।"

SELECT READINGS

BHAVE, V.—*The Bhoodan Movement.*

COLE, G. D. H.—*Guild Socialism Restated.*

COKER, F.—*Recent Political Thought*—Chs II, VIII, IX.

GANDHI, M. K.—*Sarvodaya.*

HALLOWELL, J. H.—*Main Currents in Modern Political Thought*—Chs. XI to XIV.

HUNT, CAREW—*The Theory and Practice of Communism*—Chs. IV, XV, XVI.

JOAD, C. E. M.—*Modern Political Theory*—Chs. III, IV, V.

LAIDLER, H. W.—*Social-Economic Movements*—Chs. XVI, XVIII, XXII, XXIII.

LASKI, H. J.—*Karl Marx—An Essay.*

NARAIN, JAI PRAKASH—*Articles in Newspapers, 1957.*

STRACHEY, JOHN—*The Theory and Practice of Socialism.*

THE FIRST TWO YEAR PLANS—*Government of India Publication.*

THE COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECTS—*Government of India Publication.*

सर्वाधिकारवादी राज्य (The Totalitarian State)

१. सर्वाधिकारवादका अर्थ

आधुनिक राजनीतिक साहित्यमें 'सर्वाधिकारवादी राज्य' शब्दका उपयोग 'उदार लोकतंत्रीय राज्य' शब्दके विरोधमें किया जाता है। सर्वाधिकारवादी राज्य मनुष्यके सम्पूर्ण जीवन पर अधिकार रखनेका दावा करता है। मनुष्यके जीवनका कोई भी अंग इसके सूक्ष्म निरीक्षण और नियन्त्रणसे बाहर नहीं होता। जिस प्रकार बाइबिल का उपदेश है कि "हमारा जीवन, हमारी क्रियाशीलता और हमारा अस्तित्व परमात्मा में ही होता है;" उसी प्रकार सर्वाधिकारवाद हमें सिखाता है कि 'हमारा जीवन, हमारी क्रियाशीलता और हमारा अस्तित्व राज्यमें ही है।' सर्वाधिकारवादके अनुसार मनुष्यका अपने जीवन पर अधिकार नहीं होता है। वह राज्यकी घरोर है और इसका उपयोग राज्यके हितमें ही होना चाहिए। मुसोलिनी के शब्दोंमें 'यदि उन्नीसवीं शताब्दी समाजवाद, उदारवाद और लोकतन्त्रका युग थी तो बीसवीं शताब्दी अधिकार सत्ता, समष्टिवाद (collectivism) और सर्वाधिकारवादी राज्यका युग है।'

प्राचीन कालमें यूनानका नगर राज्य सर्वाधिकारवादी था पर अनेक अर्थमें। उस समयकी परिस्थितियां आजकी परिस्थितियोंमें बिल्कुल भिन्न थीं इसलिए राज्य के कृत्य भी अनेक प्रकारके थे। उस समय का राज्य धर्ममण्ड (church), शिक्षा-मण्डाल (school) और राज्य इन तीनोंका सम्मिलित रूप था। राज्य और समाज को बरीब-बरीब एक ही माना जाता था। नागरिक जीवन ही यूनानियों का जीवन था। जैसा कि मैक्लिवर (MacIver) का कहना है, एक यूनानीके लिए नागरिकता उसका धर्म था। यूनानी नागरिकको अपने नगर राज्यके प्रति इतना अधिक स्नेह था कि उसका यह आदर्श मही था कि "वह (नगर राज्य) हमारा है और हम उसके हैं।"

आजकलका सर्वाधिकारवादी राज्य यूनानी नगर राज्यमें बिल्कुल भिन्न होता है। यह फ़ामके बादशाह चौदहवें लुई की प्रसिद्ध उक्ति "मैं ही राज्य हूँ" का आधुनिक रूप है। सर्वप्रथम होमेल ने सर्वाधिकारवादी राज्यको दार्शनिक रूप दिया। उन्होंने राज्यको मानव आगमान तक पट्टा दिया। वह राज्यको धरती पर ईश्वर मानते थे। उनके विचारमें राज्य 'इतिहासमें ईश्वरकी गति (the march of God in history)', 'निवेष्टका प्रत्यक्ष रूप' तथा वास्तविक स्वाधीनताका यथार्थ रूप है।

सर्वाधिकारवादके अनुसार राज्य ही सब कुछ है। यह सर्वशक्तिमान है। इससे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। मुसोलिनी (Mussolini) के शब्दोंमें 'राज्यसे परे कुछ भी नहीं है।' राज्य परमपूर्ण है। इसकी तुलनामें व्यक्तिगत और समुदायकी स्थिति आपेक्षित है। राज्य एक परमपूर्ण, चिरस्थायी और दैवी शक्तिसे प्रेरित सत्ता है। मुसोलिनी ने इटली की जनताके समक्ष यह आदर्श रखा था : "राज्यके भीतर सब कुछ, राज्यके बाहर कुछ नहीं ; राज्यके विरुद्ध कुछ भी नहीं।"

अमेरिका के वैदेशिक नीति सघ (Foreign Policy Association) ने सर्वाधिकारवादी राज्यका विवेचन इस प्रकार किया है : "फासिस्टवादने आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यके बहुलवादके स्थान पर सर्वाधिकारवादी राज्यका प्रतिपादन किया है। बहुलवादके अनुसार राज्य उन अनेक सघोंमें से एक है जिन्हें व्यक्तिकी निष्ठा प्राप्त रहती है। पर सर्वाधिकारवादी राज्य व्यक्तियोंके सभी कार्यवालापो पर अपना अधिकार रखता है और उन्हें राष्ट्रीय हितके विपरीत कोई कार्य नहीं करने देता। इटली के एक उच्च अधिकारीके कथनानुसार सर्वाधिकारवादी राज्य "वह राज्य है जिसमें एक ऐसी सम्प्रभुता हो जो देशकी समस्त शक्तियोंको अपने अधीन रखे।"

सर्वाधिकारवाद राज्यकी पूजा करना सिखाता है। इसकी शिक्षाके अनुसार व्यक्ति राज्यकी सेवा करके ही महत्व प्राप्त कर सकता है और इस सेवामें ही उसकी पूर्णता है। साइबर्ग (Seiburg) का कहना है कि नाजीवादके आविर्भावसे जर्मनी में कोई मनुष्य नहीं रह गया है, वहाँ अब केवल जर्मन है। "जो कोई जर्मनी में, जर्मनी के साथ और जर्मनी के माध्यमसे रहना चाहता है उसे अपनेको राष्ट्रके अधीन करना होगा और उसे अपनेको सर्वाधिकारवादी राज्यके अनुकूल बनाना होगा।" 'व्यक्तिकी जीवन उसका नहीं है, वह राज्यका और केवल राज्यका है।'

इस प्रकार सर्वाधिकारवादी राज्यके अधिकार असीमित हैं। स्वेच्छामूलक सघ जीवनकी अनोखी विभिन्नता पर वह आपात करता है। धर्म, आचार-विचार और शिक्षा सभी राज्यके अधीन हैं। इटली में तो खेल-कूद, शिक्षा और मनोरंजन की सस्थाएँ भी फासिस्टोंके हाथोंमें केन्द्रित थीं। नाजी सिद्धान्तवादी फ्रैंज शानवेचर (Franz Schanwecher) ने लिखा था। "राष्ट्रकी ईश्वरके साथ प्रत्यक्ष और बहुत घनिष्ठ एकता है . . . जर्मनी ईश्वरका राज्य है।" सर्वाधिकारवादका लक्ष्य राज्य और समाजके बीचके मौलिक विभेदको मिटाना और राज्यको सर्व-शक्तिमान बनाना है।

सर्वाधिकारवाद विभिन्न देशोंमें विभिन्न रूप धारण करता है। इसने रूस में साम्यवाद, इटली में फासिस्टवाद और जर्मनी में नाजीवादका रूप धारण किया। आंग्ल-संस्कृति देशोंमें भी जहाँ वैयक्तिक स्वाधीनताके प्रति प्रेम बहुत गहरा है, राज्यका कार्य-क्षेत्र बढ़ रहा है। इसका परिणाम एक नये प्रकारका सर्वाधिकारवाद हो सकता है जिसे लोकतंत्रीय सर्वाधिकारवाद (democratic totalitarianism)

कहा जा सकता है। अमेरिका में “नार्वेयानिक तानाशाही” (constitutional dictatorship) का उदय सम्भव है। ग्रेट ब्रिटेन के बारेमें लन्दन के एक दैनिक समाचार पत्रने विनोदमें लिखा है : “भले ही हमारा देश सबसे अच्छा शासित न हो, भले ही हमारा देश सबसे बुरा शासित भी न हो, पर ईश्वर की मौज्जा हमारा देश सबसे अधिक शासित अवश्य है।”

यह मानना गलत है कि राज्यका सर्वाधिकारवादी निदान आरम्भमें ही पूर्ण विकसित रूपमें प्रतिपादित किया गया था जिसकी प्रेरणाने आधुनिक सर्वाधिकारवादी आन्दोलन हुए। तथ्य यह है कि समय-समय पर हुए आन्दोलनोंमें नया जीवनकी वास्तविक परिस्थितियोंने सर्वाधिकारवादी निदानका विकास हुआ। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें तथ्योंने निदान बना है। तथ्योंने निदानका अनुकरण नहीं किया है। वह बात फासिस्टवाद और नाज़ीवादके बारेमें विशेष तौर पर सही है। ये दोनों ही नवतः बुद्धि-विरोधी (anti-intellectual) आन्दोलन थे। प्रथम विश्व-युद्धके बादके वर्षोंकी इटली और जर्मनी की विशेष आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियोंकी पृष्ठभूमिमें ही इन्हें ठीक प्रकारसे समझा जा सकता है।

२. सर्वाधिकारवादी राज्यकी विशेषताएं (Features of the Totalitarian State)

(१) सर्वाधिकारवादी राज्यमें बुद्धि-विवेकका तिरस्कार किया जाता है और स्वाभाविक प्रवृत्तियों (instincts) और अल्पप्रेरणाओं (impulses) को बहुत महत्व दिया जाता है। फासिस्ट इटली और नाज़ी जर्मनी में यह बात विशेष रूपसे सही थी। इन राज्यों में जिस राज्य-निदानका विकास किया गया वह बुद्धि-विरोधी था। स्वभाविक प्रवृत्ति और इच्छाको बुद्धि-विवेकमें अधिक महत्व दिया गया। मारे ही पश्चिमी समाजमें मनुष्यको परमात्माका प्रतिबिम्ब माननेकी धारणा समाप्त होनी जा रही है।

(२) सर्वाधिकारवादी राज्यका स्वरूप तानाशाही (dictatorial) होता है। यह उदारवाद और मर्यादित शासनका विरोधी है।^१ यह एक व्यक्ति या एक पार्टीके हाथोंमें सर्वोच्च-शक्ति सौंप देता है। कम की तानाशाही बायसेली (leftist) ताना-

^१ नाज़ीवादका मारा यह था : ‘विधिवे सम्पूर्ण व्यक्ति नहीं, राष्ट्र सर्वप्रधान है।’

‘उदारवाद जीवनका वह दर्शन है जिसे अब जर्मन युवक घृणा तथा प्रोक्षकी और हेन दृष्टिमें देखता है क्योंकि दूसरा कोई भी जीवन-दर्शन हमने अधिक घृणास्पद और उससे स्वयं अपने जीवन-दर्शनसे इतना अधिक विच्छेद नहीं है। आज दिन जर्मनी का युवक उदारवादीको अपना शत्रु मानता है।’

—मोन्टर जॉन डेर बर, १९३४

शाही हैं और इटली और जर्मनी की तानाशाही दक्षिणपन्थी (rightist) तानाशाही थी। रूस की तानाशाही एक पार्टी^१ की तानाशाही है। पर इटली और जर्मनी की तानाशाही एक व्यक्तिकी तानाशाही थी। फासिस्ट इटली और नाज़ी जर्मनी दोनों में एक व्यक्तिके नेतृत्वको बिना किसी तर्क-वितर्कके माना जाता था।

ससदीय लोकतन्त्र सर्वाधिकारी राज्यके लिए अभिन्न है। इसे मूर्ख, भ्रष्ट और मुस्त बतलाया जाता है। ससदीको बानूनीयोवा बाज़ार, कुछ कर पानेमें असमर्थ, और सकटके समय एकदम असहाय बनाकर उनका तिरस्कार किया जाता है। एक फासिस्टवादीके कथनानुसार लोकतन्त्र एक सड़ती हुई लाश है। सर्वाधिकारवाद प्रत्यक्ष कार्रवाईमें विश्वास करता है। फिर भी सर्वाधिकारवाद शुद्ध एकतन्त्रवाद (autocracy) नहीं है। सर्वाधिकारवादमें अभिजात तन्त्र (aristocracy) के इस सिद्धान्तको कि शासनकी बागडोर कुछ विशिष्ट लोगोके हाथोंमें हो, लोकतन्त्रके इस सिद्धान्तके साथ मिलाया गया है कि शासक वर्गका चुनाव विस्तृत आधार पर किया जाय।

(३) सर्वाधिकारवादी राज्य वैयक्तिक स्वाधीनताको कुचल देता है। साम्यवाद वैयक्तिक स्वाधीनताको मध्यवर्गीय (bourgeois) धारणा मानता है। समय समय पर राजनीतिक विरोधियों और सेनानायकोका हटाया जाना इस बातका प्रमाण है। फासिस्टवाद और नाज़ीवाद जन साधारणमें कुछ भी विश्वास नहीं करते। वे वैयक्तिक स्वाधीनताकी धारणाको पुराने जमानेकी दकियानूसी, अविवेकपूर्ण तथा असम्य धारणा मानते हैं।

सर्वाधिकारवाद किसी प्रकारका राजनीतिक विरोध सहन नहीं करता। यह एक पार्टीका शासन होता है। केवल पार्टीके भीतर ही आलोचना करनेकी छूट रहती है। आलोचनाका उद्देश्य शासन यन्त्रमें सुधार करना होना चाहिए, उसे उल्टाड़ फेंकना नहीं। सर्वाधिकारवादी राज्यमें सौचने-समझने, भाषण देने और लिखनेकी स्वतन्त्रता नहीं होती। समाचार पत्रों पर, पुस्तकोके प्रकाशन पर, रेडियो, चलचित्र उद्योग, थियेटर, संगीत और कला पर बहुत बड़ा नियन्त्रण रखा जाता है। सभा करने या सभ बनानेकी स्वतन्त्रता नहीं होती।^२ फासिस्ट इटली में हड़ताल करनेकी मनाही थी।

^१ सन् १९५३ में स्तालिन की मृत्युके बाद आजके रूस में यह बात और भी सत्य है। स्तालिन के व्यक्ति-मूलक अधिनायकत्वके स्थान पर सामूहिक नेतृत्व कायम किया जा रहा है, यद्यपि लुश्चेव एक तानाशाह होते जा रहे हैं। अपने प्रतिद्वन्द्वियोंसे छुटकारा पाकर तथा उन्हें पीछे ढकेलकर लुश्चेव १९५८ में प्रधान मंत्री बन गये। तबसे उन्हें अर्ध-स्तालिनवादी कहा जाता है।

^२ "व्यक्तिकी स्वाधीनता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। स्वाधीनता जाति या राष्ट्रकी होती है, क्योंकि ये ही वे पार्थिक और ऐतिहासिक वास्तविकताएँ हैं जिनके द्वारा व्यक्तिके जीवनका अस्तित्व कायम रहता है।"—(डा० आर्टो डीड्रिच, १९३७)

इटली और जर्मनी में प्रोफेसरों और म्यूज मास्ट्रोसी बार-बार जाब-पडनाय की जाती थी। म्यूजोंका उपयोग राजनीतिक प्रचारके लिए किया जाता था। जनता के सम्पूर्ण जीवन पर राज्यका नियंत्रण रहता था। प्रशासन सेवा (civil service), न्यायपालिका, सेना और विश्वविद्यालयमें 'राष्ट्र विरोधी तत्वों' को निकाल दिया गया था। जर्मनी में विश्वविद्यालयके अध्यक्षोंको सरकारके मन्त्रि-विभागके सभी निदुस्त किया करते थे। समाचार पत्रोंको सामन्यी आलोचना करनेकी इजाजत नहीं थी। इटली में प्रमुख मेधावियों (intellectuals) की या तो हत्या कर दी गयी थी, या उन्हें जेलोंमें बन्द कर दिया गया था या फिर देशमें निकाल दिया गया था। १९२४ में इटली में मैट्टियोटी (Matteotti) का रहस्यपूर्ण शमन होना और जर्मनी में १९३४ में रौएन (Röhm) और उनके दलकी मौतोंका घाट उतारा जाना सर्वविदित है और उन पर टीका टिप्पणी करनेकी आवश्यकता नहीं है।

फासिस्टवाद और नाज़ीवाद दोनों ने घोर प्रचार किया और जनताको प्रभावित करनेके लिए सभी सम्भव मनोवैज्ञानिक माधनोंको अपनाया। उन्होंने जनताकी उत्तेजित करनेके लिए सैनिक प्रदर्शनों, बचावदो और भाषन बलाका उपयोग किया। जर्मनी में राजनीतिक विरोधियोंको जेलों और बन्दों गिरियोंका सामना दिनाया गया। नाज़ियोंके शासनारम्भ होनेके कुछ महीनोंके भीतर ही पचास हजारसे अधिक हजार राजनीतिक कैदियोंको बन्दी गिरियोंमें डूब दिया गया। हिटलर (Hitler) का कहना था कि प्रचार कार्यमें अच्छे लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए बुरे माधनोंका अनायास जाना भी उचित है।

सर्वाधिकारवादी राज्यमें समाचार पत्रोंको अलग बन्दकर सरकारका पूरा-पूरा समर्पण करना पड़ता था। डॉ॰ गोबेल्स (Dr. Goebbels) का कहना था कि समाचार पत्रोंको नियंत्रणका बाधा बन जाना चाहिए तबले सरकारी प्रचार विभाग अब जैसा चाहे सब बँना स्वर निकाल सके। देशमें बेबल एक ही मत हो सकता था और समूचे राष्ट्रको एक होकर सोचना पड़ता था। रेडियो पर होनेवाले भाषन सैनिक दलके मुख्याधीन जागीले भाषन होते थे। युद्धकी तैयारी ही इन भाषनोंका एकमात्र विषय होता था। युद्धकी हालतमें शत्रुका प्रचार मुनता इनका बदकर अराध माना जाता था कि मौन तबकी मर्रा की आ सकती थी। इसी प्रकार फासिस्ट इटली में सरकारी समाचार विभागका प्रधान बनता था कि बीन-या समाचार

‘स्वेच्छामें घूमने फिरनेकी स्वतंत्रता न देना हमारे समस्त भारी जीवनके लिए बहुत आवश्यक है, और इन पर जोर दिया ही जाना चाहिए, भले ही लोगों को ये वैयक्तिक स्वतंत्रता पर समनैवासी इन रीतोंकी हानिप्रद समझें।’—(रोबेनसन)

‘वे सभी व्यक्ति विधिवे समस्त समस्त समस्त जो राष्ट्रीय उद्देश्यकी पूर्तिमें सहायक हैं और सरकारका समर्पण करनेके इन्तार नहीं करते।’ (हिटलर, १९३३)

प्रकाशित किया जाय और कौन-सा दवा दिया जाय। ऐसी परिस्थितियोंमें हममें कोई आश्चर्य नहीं कि जनता ने समाचार पत्रोंको पढ़ना ही छोड़ दिया था।

सर्वाधिकारवादी राज्यमें व्यक्ति अपने नेता और नेता वर्गकी अधिकार सत्ताके पूर्ण-रूपेण अधीन होता है। जब कोई व्यक्ति फासिस्ट पार्टीमें शामिल होता था तब वह यह शपथ लेता था—“परमेश्वर और इटली के नाम पर मैं शपथ लेता हूँ कि मैं म्यूसर (मुसोलिनी) के आदेशोंका पालन बिना किसी प्रकारके तर्क-वितर्कके किया करूँगा और अपनी सम्पूर्ण शक्तोंसे तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना रक्त देकर भी फासिस्ट प्रान्तिका लक्ष्य प्राप्त करूँगा।” अधिकार सत्ता, अनुशासन, और अधीनता फासिस्ट पार्टीके मूल मन्त्र थे। देशके युवक सगठनके समक्ष मुसोलिनी ने यह आदर्श रखा था—‘विद्वान् करो, आज्ञा मानो, लड़ो।’

(४) सर्वाधिकारवाद राष्ट्रको अत्यधिक गौरव प्रदान करता है। वह राज्यको एक शक्ति-व्यवस्था (power system) मानता है। सकीर्ण राष्ट्रीयता, अन्ध देश प्रेम (chauvinism), आयमण मूलक युद्ध और साम्राज्यवादी विस्तार फासिस्ट-वाद और नाज़ीवाद दोनोंकी कुछ मौलिक विशेषताएँ थी। रूसी साम्यवाद भी राष्ट्रीयतावादी और सैन्यवादी हो गया है।

फासिस्टवादके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कायरोका स्वप्न है। शान्ति-प्रियता “बलिदानका अवसर आ जाने पर भीष्मता है।” फासिस्टवादी राष्ट्रीयतावादी भावनाओंका दुरुपयोग करते हैं। वे समाजवादियों और साम्यवादियोंके अन्तर्राष्ट्रीयतावादको बहुत बढ़ा-बढ़ा कर तथा तांड-मरोड़ कर चित्रित करते हैं। वे समाजवादियों पर यह ठाना भारते हैं कि समाजवादी अपने देशको छोड़ कर अन्य सभी देशोंके हितचिन्तक होते हैं।

फासिस्टवादी इटली की शिक्षा प्रणाली अधिकतम अन्ध-देश प्रेम पूर्ण थी। स्कूलोंका संचालन सैनिक अनुशासनके ढंग पर होता था। शक्ति और हिंसाकी भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती थी। विचारोंकी अपेक्षा क्रियाशील व्यक्तिको अधिक महत्व दिया जाता था।

इटली और जर्मनी दोनों ही कच्चा माल पानेके लिए, अपनी बतायी हुई चीजों की बिक्रीके लिए तथा अपनी ‘अधिकार-लिप्ता’ को मनुष्ट करनेके लिए उपनिवेश चाहते थे। मुसोलिनी ने कहा था, साम्राज्यवाद जीवनका अनन्त और कमी न बदलनेवाला नियम है। ‘हम चार करोड़ व्यक्ति अपने सकीर्ण पर अर्धवैनीय प्रायद्वीपमें न जाने किस प्रकार गुजर कर रहे हैं। मुसोलिनी का कहना था कि इटली का विस्तार इटली के लिए जीवन और मरणका प्रश्न है। इटली का “या तो विस्तार होगा या विनाश होगा।”

मुसोलिनी और हिटलर दोनों ही युद्धकी आवश्यकताका खुले-आम प्रचार करते थे। पीछे पूर्ण गुणोंके विकासके लिए वे दोनों युद्धको जरूरी बतलाते थे। फासिस्टवादी नीतिके परिणामस्वरूप युद्ध अनिवार्य था। हिटलर विजयी तलवार

की शक्तिमें विश्वास करना था। उनमें लार्ड बर्केनहेड (Lord Birkenhead) के इन बयनकी मन्चाई निम्नकी कि नगर उन्हींकी सुरि-सुरि प्रशंसा करना है और उन्हींकी पुरस्कार देना है जिनकी नदवाररी धार तेज होती है और जिनके दिल मजबूत होते हैं। रोएम (Roehm) ने कहा था: "एक सैनिक के दृष्टिकोणसे शान्तिवाद सैद्धान्तिक कायरता है। कामरता कोई दर्शन नहीं है; बल्कि यह चरित्र का दोष है।" सर्वाधिकारवादी देश सैनिकवादी होते हैं और मूर्खो रहकर भी सम्झौते पर बिगल घन व्यय करने हैं।

हिटलर को महत्वावाशा न केवल उन प्रदेशोंको फिरसे जीत लेनेकी थी जिन्हें जर्मनीने वारसाईकी सन्धिके परिणामस्वरूप खो दिया था, बल्कि वह उन सब प्रदेशोंकी भी जर्मनी में मिला लेना चाहता था जिनमें पर्याप्त जर्मन अन्यमन्थक रहते थे। म्युनिक समझौते (१९३८) के बादकी घटनाओंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हिटलर केन्द्रीय और पूर्वी योरोप पर मुनरो-मिडान्त (Munroe doctrine)^१ जैसी कोई व्यवस्था लागू किये बिना सन्तुष्ट न होगा। पर युद्धमें रूस के हाथों बार-बार पराजित होने के कारण उसके इस स्वप्नका पूरा होना अमम्भव हो गया।

(१) सर्वाधिकारी राज्यमें किसी अन्य राजनीतिक मिडान्त या आदर्शकी गुंजाइश नहीं होती। यह उदारवाद और मानवतावादमें विश्वास नहीं करता। जर्मनी में जानीय द्वेष और धृमाकी भावनाओंको बढ्प उमास गया था। जर्मनी का विश्वास था कि नाटिक ज्ञानि सब जानियोंमें सबसे अच्छी है। पर नाटिक ज्ञानि यह जानीय धेष्टता विमानने नयी प्रकार प्रमाणित नहीं होती। यद्यपि आधेने कम ही जर्मन नाटिक ज्ञानिके हूँ पर शुद्ध आर्य ज्ञानिका विकास ही नाट्यवादका लक्ष्य था। नाटिकोंने अपनी भाषा, अपने माहित्य और अपनी ज्ञानिकी शुद्धता बनाये रखनेका प्रयत्न किया था।

सर्वाधिकारवादी राज्य अपनेकी आर्थिक नीति पर स्वावलम्बी बनानेका प्रयत्न करता है। इटली और जर्मनी दोनोंकी आर्थिक नीति यह थी कि युद्ध मचाकतमें काम आनेवाले पदार्थोंके लिए उन्हें विदेशों पर समामम्भव कमने कम निर्भर रहना पड़े। इसी नीतिके अनुसार जर्मनी ने नवनी ऊन, रई और रबड़ कासी भावामें पैदा की। अपने तैयार माटकी बिक्री बढानेके लिए उनने एक राष्ट्रके रूपमें विदेशी बाणिज्य और व्यापारने क्षेत्रमें प्रवेश किया।

(२) सर्वाधिकारवादी राज्य धर्मका प्रतिद्वन्दी हो गया। साम्यवादने ती

^१ अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो (१८२३) के नामसे प्रसिद्ध, इस मुनरो मिडान्त का आशय यह है कि कोई भी योरोपीय देश अमेरिकी महाद्वीपके राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया करे। इसी प्रकार हिटलर भी चाहते थे कि कोई भी बाहरी देश केन्द्रीय और पूर्वी योरोपके राजनीतिक मामलोंमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप न किया करे।

आरम्भमे ही धर्म पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, पर फ़ासिस्टवाद और नाज़ीवादने तो धर्मको सर्वाधिकारवादी राज्यके उद्देश्यकी मिट्टिका साधन बना लिया। नाज़ीवादका तो खासकर यह आदेश था कि लोग जो भगवान्‌को अर्पण करना चाहते हैं वह शामक को दें। नाज़ीवाद एक संकीर्ण, बहिष्कार मूलक (exclusive) और गैर-ईसाई-ईसाई-धर्म (un-Christian Christianity) स्थापित करना चाहता था जिसे नाज़िक ईसाई-धर्म कहा जाता था। वाइबिलकी, ईसा मसीह के उपदेशोंकी तथा ईसाई परम्पराओंकी वे बातें, जो नाज़िक विचारधाराके अनुरूप नहीं थी निकाल बाहर की गयीं। हिटलर को नया त्राता (saviour) माना जाता था। उन्हें मसीहा, और धरती पर भगवान्‌का प्रतिनिधि समझा जाता था। सर्वाधिकारवादी राज्य सर्वाधिकारवादी धर्मका तानू था। जे० ए० स्पेण्डर (J. A. Spender) ने लिखा था: "हम ने धर्मको समाप्त करनेकी कोशिश की है, मुमोलिनी ने उसे निष्क्रिय और निष्प्राण बनानेकी चेष्टाकी पर हिटलर ने इसे अपने अधीन बनानेका यत्न किया।"^१ स्पेण्डर के उक्त कथनमें इतना और जोड़ा जा सकता है कि फ़्रांको ने धर्मका शोषण किया।

(७) तीनों तानाशाही राज्योंमें सर्वाधिकारवाद जन आन्दोलन बन गया। स्वतन्त्र मतदानके अभावमें यह कह सकना कठिन है कि सर्वाधिकारवादको जनताका समर्थन कहा तक प्राप्त है। आरम्भमें तो सर्वाधिकारवादी आदर्श और तानाशाही तरीके कुछ थोड़ेमें लोगों तक ही सीमित थे और बहुतेसे लोग इनकी खिल्ली भी उड़ाते थे। पर दृढ़ निश्चय, सकल्य और लक्ष्यके बल पर मुगगटित और पूर्णरूपेण अनुशासित स्पष्ट राजनीतिक और राष्ट्रीय लक्ष्य रखनेवाले मुट्ठी भर सदस्योंका दल अपनेको देशका भाग्य विधाता बनानेमें सफल हुआ। यही नहीं, उन्होंने जनताका पूरा-पूरा समर्थन भी प्राप्त कर लिया। जनताका समर्थन प्राप्त करनेमें, विशेषकर इटली और जर्मनी में, जन मनोविज्ञान, प्रत्यक्ष कार्रवाई और आतंकवादने बड़ा काम किया। रूस में, खाने पीनेकी अत्यधिक सुख-मुविषाके वादोने जनताको बोल्शेविक आन्दोलनका समर्थक बना दिया। जर्मनी और इटली में घृणा और प्रतिहिंसाकी भावनाका, साम्यवादके हौवेका, तथा विस्तृत साम्राज्य विजयके प्रलोभनका उपयोग जन समर्थन प्राप्त करनेके लिए किया गया। जनताको समझाया गया कि विस्तृत साम्राज्यमें उनके अभाव दूर हो जायेंगे और उन्हें विस्तार करनेका पर्याप्त अवसर मिल जायगा। जनताके विवेकको जाग्रत करनेके बजाय उसकी ओड़ी भावनाओंको उभारा गया। फलतः जनताने राज्यकी आज्ञाओंका पालन आखिरी मीचकर मशीनकी

तरह किया। उन्हें भौतिक शिक्षा इतनी अच्छी तरह दी गयी कि वे अन्धी, विवेकहीन प्रवृत्तिके बशीभूत होकर दूसरी जातियोंके प्रदेशोंको जीतनेके लिए युद्धके मैदानमें टिड्डी दलकी तरह फिल पड़ते थे।

३. सर्वाधिकारवादकी सफलता (What Totalitarianism Has Done)

सर्वाधिकारवादके उद्देश्यों और उसकी नीतियोंसे हम चाहे कितना ही असहमत क्यों न हो, पर यह बात माननेमें इन्कार नहीं किया जा सकता कि साम्यवाद, फासिस्ट-वाद और नाज़ीवादने अपने-अपने देशकी जनतामें अपने लक्ष्योंके प्रति इतनी अधिक निष्ठा पैदाकी कि लक्ष्योंकी प्राप्ति ही लोगोंके जीवनका एकमात्र उद्देश्य हो गया और वे अपनी जान देकर भी लक्ष्य प्राप्त करनेकी तैयार हो गये। सर्वाधिकारवादने जनता को एक मूत्रमें बांध कर राष्ट्रीय एकताकी वृद्धि की।

नाज़ी जर्मनी और फासिस्ट इटली में सर्वाधिकारवादने जनताका कुछ बन्ध्याग अवश्य किया पर इसके बदलेमें जनताको अपनी स्वाधीनता खोनी पड़ी। इस बन्ध्याग के लिए लौह अनुशासन, नैतिक शक्ति और युद्धका सहारा लेना पड़ा। सर्वाधिकारवादी शासनमें इन देशोंकी जो कुछ समृद्धि हुई वह थोड़ा ही समय तक रही क्योंकि इसका आधार ही गलत था।

यद्यपि इन देशोंमें सर्वाधिकारवाद पराजित हो चुका है, पर इस बातकी गारण्टी नहीं है कि वह एक बार फिर अपना सिर न उठायेगा। जर्मन जैसी समझदार और ज्ञानी जातिने किस प्रकार अपनेको सर्वाधिकारवादके हाथों समर्पित कर दिया, यह बहुत समय तक एक रहस्य ही बना रहेगा। सर्वाधिकारवादकी सफलतामें यह पता चलता है कि मनुष्यमें नेतृत्व और अधिकार सत्ताका अनुगमन करनेकी तथा कार्य करनेकी उत्कट इच्छा होती है। इस इच्छाको सही मार्ग पर बनाये रखनेके लिए यह जरूरी है कि इस इच्छाके साथ ही साथ लोगोंमें स्वावलम्बी बनने, अपने पैरों पर खय खड़े होने और स्वयं माँवने-दिखानेकी भी इच्छा हो।

४. सर्वाधिकारवादका भविष्य (What of the Future?)

सर्वाधिकारवादी राज्योंने जनताका जो कुछ बन्ध्याग किया है वह उस मूल्यके सामने कुछ भी नहीं है जो जनताको उस बन्ध्यागके लिए चुकाना पड़ा है। जैसा कि ए० डी० लिण्डसे (A. D. Lindsay) ने कहा है, "सर्वाधिकारवादी सरकारके साथ लोच-तंत्रका मौलिक मध्यम यह नहीं है कि यह सरकार जनता द्वारा चुनी न जाकर तानाशाही तरीकेसे बनती है और अपनी शक्तिसे जनताको अपने बशमें रखती है। मध्यम इस बातका है कि सर्वाधिकारवादी राज्य अपना लक्ष्य उचित और अनुचितता

विचार किये बिना बनाता है और उसे गलत तरीकोंमें धेन केंन प्रकारेण प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है। सर्वाधिकारवादी राज्यवा कहता है कि व्यक्तिका काम केवल राज्यकी सेवा करना, उसकी शक्ति बढाना और उसके गौरव-गीत गाना है। इसके विपरीत लोकतन्त्रवादी कहता है कि राज्यका एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह समाज की सेवा करे और उसके स्वतन्त्र जीवनका उत्थान करे (५२-७-८)।

सर्वाधिकारवादका परिणाम वैयक्तिक स्वाधीनताका अन्त, मानव व्यक्तित्वका दमन, देशके भीतर हिंसाका उपयोग और विदेशों पर लज्जाहीन आक्रमण हुआ है। यही नहीं, सर्वाधिकारवादके कारण मानव स्वभावका पाशबीकरण और पूरी जातिका सैन्धीकरण भी हुआ है। बारम्बार सन्धिके अन्याय, जो तानाशाहोंकी सामरिक और आक्रमण-मूलक नीतियोंके लिए बरदान साबित हुए तथा वर्तमान समयमें होनेवाले अन्य अन्याय स्थायी नहीं हो सकते।

सर्वाधिकारवादने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपनी स्वाधीनता कायम रखनेके लिए हमें हमेशा और हर प्रकारसे सावधान रहना चाहिए। वैयक्तिक स्वाधीनता, समानता, बन्धुत्व और मानवतावादके प्रति केवल मौखिक सहानुभूति ही काफी नहीं है। हमें इन आदर्शोंके लिए बराबर प्रयत्न करते रहना होगा। आधुनिक ताना-शाहियोंके उदय और विस्तारने यह साबित कर दिया है कि तानाशाहीका मूल कारण भय और अरक्षाकी भावना है। भय कर्णके भयभीत होने पर ही फासिस्टवादका उदय होता है।

सर्वाधिकारवादकी इतनी सफलताका मुख्य कारण यह है कि इसने इस अर्थ मत्पसे पूरा-पूरा लाभ उठाया कि मनुष्य मूलतः अविवेकी होता है। मनुष्यकी प्रवृत्तियों, भावनाओं, और राग-द्वेषोंकी ठीकसे समझ कर और इन भावनाओंका कुशल उपयोग करके ही सर्वाधिकारवाद शक्तिशाली बना। इसने यह साफ-साफ सिद्ध कर दिया है कि हर राजनीतिज्ञ और प्रशासकके लिए बर्गमन मनोविज्ञानका गूढ़ ज्ञान और प्रचार कलामें क्षमता अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे समयमें जब समाज और संस्कृति दिन प्रतिदिन राजनीतिसे अधिकाधिक ओत-ओत होती जा रही है, सर्वाधिकारवाद हमें बताता है कि राजनीतिक शक्तियोंका वास्तविक अध्ययन बहुत आवश्यक है। सर्वाधिकारवाद हमें यह भी बताता है कि हर प्रकारका जीवन वर्णन अच्छा होता है, यदि लोगोमें उसके प्रति हार्दिक लगन हो और वे इसके लिए सब कुछ करने और मरनेको तैयार हो।

सर्वाधिकारवादकी एक मौलिक कमजोरी यह है कि यद्यपि यह मनुष्यके सामूहिक स्वभाव (gregarious nature) को अच्छी तरह समझता है पर वह यह नहीं समझता कि हर मनुष्यमें एकान्तचिन्तन और आत्मपरीक्षणकी भी लालसा रहती है।

यदि लोकतन्त्रको सफल होना है तो तानाशाहोंसे केवल मुँह करते रहनेसे ही उसे कोई लाभ न होगा। लोकतन्त्रको केवल एक धारणा बने रहनेके बजाय एक जीता जागता तथ्य बनना होगा, उसे अपनेको बर्गमन आधिपत्य, आर्थिक अन्याय और

साम्राज्यवादी शोषणसे मुक्त करना होगा। उसे जीवनके प्रत्येक क्षेत्रको प्रभावित करना होगा और स्वार्थानता तथा समानताके उन मिथानोंकी प्रतिष्ठा करनी होगी जो ऊपरसे देखनेमें एक दूसरेके विरोधी भागूम होने हैं।

रूस में सर्वाधिकारवाद (Totalitarianism in Russia)

रूस में सर्वाधिकारवादका उदय (Emergence of Totalitarianism in Russia).

इटली और जर्मनी के सर्वाधिकारवादको तुलनामें रूसी सर्वाधिकारवादका उदय भिन्न प्रकारसे हुआ। रूसी सर्वाधिकारवादका एक निश्चित बौद्धिक आधार था। पहले साम्यवादके विविष्ट मिथानोंको मार्क्सवादी रूपमें प्रतिष्ठित किया गया और फिर उसे व्यावहारिक रूप दिया गया। जारनार्ही रूप निरंकुश एकनत्र शासन वाला देश था, यद्यपि उस समय समद (जिसको Duma कहने थे) आदि भी थी जो लोकनग्रीय स्वायत्त बनाये हुए थी। उदारवादी और क्रान्तिकारी आन्दोलनोंकी पूरी तरह कुचल दिया गया था। मंत्राग बर्गमें लोकनग्रीय संगठनोंको पनपने नहीं दिया गया। किसान अपद्र, अज्ञानी, अन्ध-विश्वासी और दरिद्र थे। धार्मिक सत्ता (church) का पतन हो रहा था और उसने राज्यमें अपवित्र गठ-बन्धन कर रखा था। शेष योरोप की तुलनामें रूस बहुत पिछड़ा था।

उक्त सब कारणोंमें देश क्रान्तिकारी परिवर्तनके लिए बिल्कुल तैयार था। उस समय रूस में दो पाटिया थी। पहली बोलशेविक और दूसरी मेनशेविक। बोलशेविक बहुमतमें थे। प्रथम महानुष्ठमें रूस का पतन हो जानेमें बोलशेविकोंको अपने मिथानोंको कार्य रूपमें परिष्कृत करनेका मौका मिल गया। बोलशेविक पार्टीके नेता और विचारक लेनिन थे। जार और उनके परिवारको फासी दे दी गयी। पुरानी व्यवस्थाको समाप्त कर दिया गया। कमजोर लोकनग्रीय संगठन दबा दिये गये। किसानोंमें जमीन देनेका वादा किया गया। मजदूर और सैनिक समितियोंका भारी पक्षि मौप दी गयी। बोलशेविकवादको साम्यवाद कहा जाने लगा। इनने आन्ध्र-जनक मरुतता प्राप्त की। यह मरुतता इसलिए मिठी 'क्रेपो' राज्य दुबल था, उद्योगधन्य पिछड़े थे, लोकनग्रीय परम्पराओंका अभाव था। लेनिन और ट्रांश्कि की प्रतिभा भी इस मरुतताका बहुत बड़ा कारण थी। जर्मनी और मित्रराष्ट्रोंके हस्तशरणे बोलशेविकोंको और भी मौका मिल गया। उन्होंने राष्ट्रीयताका मकर और आन्ध्रके नाता लगाकर अपनी मरुतता और भी मुद्द कर ली (१२: २४१-२)।

रूसी जनताके जीवनमें 'युद्धरत साम्यवाद' की अवधि (१९१८ से लेकर १९२१ तक) में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। इन चार वर्षोंमें रूसी उद्योगोत्पादा या तो राष्ट्रीय-करण कर दिया गया या उन्हें स्थानीय शासनके नियन्त्रणमें रख दिया गया। निजी

व्यापार पर रोक लगा दी गयी। जिसान अपनी उपजना बेचल उतना अना अपने पास रख सकते थे जितना उनके निजी उपभोगके लिए आवश्यक था। उत्पादनमें तेजीसे कमी हुई और लाखों व्यक्ति तबाह हो गये। इन कठिनाइयोंके अतिरिक्त सभी सरकारको एक और कठिनाईसे गुजरना पड़ा। उमे 'स्वेन दल' (Whites) की क्रान्ति-विरोधी मेनाश्रोमे निर्दम युद्ध करना पड़ा। १९२१ तक रूस-करीब-करीब तबाह हो चुका था। अतः १९२१ में सोवियत क्रान्तिके भाग्यविघाता लेनिन ने बड़ी ही दूरदर्शिता और बुद्धिमानीसे काम लेकर नयी आर्थिक नीति लागू की। इस नीतिके अन्तर्गत पूँजीवादको अनेक सुविधाएँ दी गयी। लेनिन का यह कार्य उस युद्ध-कौशलके समान था जब युद्ध-रत मेना आगे बढ़ने के पूर्व कुछ समयके लिए स्वतः पीछे हट जाती है। लेनिन की इस नयी आर्थिक नीतिके फलस्वरूप सरकारको मास लेनेकी फुर्त मिल गयी; इसकी बहुत आवश्यकता थी। सरकारने अपनी आन्तरिक स्थिति सुदृढ़ बना ली।

प्रयोगात्मक साम्यवादकी इस प्रारम्भिक अवस्थामे अनेक रूसी नेताओंका निश्चित मत हो गया कि जिस विश्व-क्रान्ति पर उन्होंने अपनी आशाएँ केन्द्रित कर रखी थी वह करीब-करीब असम्भव है। १९२० तक यह स्पष्ट हो गया कि अधिक प्रगतिशील और औद्योगिक देशोंके समाजवादी आन्दोलन, व्यवस्थित प्रगति और राष्ट्रीय राज्यका आदर्श त्याग कर विश्व-क्रान्ति और विश्व-व्यापी साम्यवादका आदर्श अपनाने को तैयार न थे। इसका परिणाम यह हुआ कि रूस में साम्यवाद क्रमशः राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप धारण करता गया और अन्य देशोंकी भाँति रूस का विकास भी एक राष्ट्रीय राज्यके रूप में होता रहा।

१९२१ के बादसे अब तक रूसने गॉसप्लान (Gosplan), प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९२५-३२) और बादकी अन्य योजनाओं द्वारा साम्यवादकी दिशामें बहुत प्रगति की है। बूजर्वा (मध्य वर्ग) और समृद्ध किसानोंको जिन्हें कुलक (kulaks) कहते थे, प्रायः समाप्त कर दिया गया। उद्योगोंका राष्ट्रीयकरण और खेतीका सामूहिकरण तेजीसे होता गया। प्रारम्भिक वर्षोंमें, भारी उद्योग-धन्धोंके विकास पर अधिक जोर दिया गया। विदेशोंसे मशीनें बड़ी मात्रा में मगायी गयी। देशकी समृद्धी श्रम शक्तिका उपयोग देशके औद्योगिक जीवन का निर्माण करनेमें किया गया। यहाँ तक कि बहुत वर्षों तक खाद्यान्न, वस्त्र, जूतों और मकानोंकी कमी रही। लोगोंको अपना दैनिक राशन पानेके लिए लम्बी कतारोंमें खड़ा होना पड़ता था। रूस के बड़े-बड़े नगरोंमें तागा, मुई और दजियोकें अगुस्ताने जैसी साधारण वस्तुएँ भी नहीं मिलती थी। १९३२-३३ में रूस के ग्रामीण क्षेत्रोंमें भयानक अकाल पड़ा। इस अकालमें लगभग ४० लाख व्यक्ति मर गये। इस अकालकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर थी क्योंकि उसने समृद्ध किसानों (kulaks) के विरुद्ध निर्दम युद्ध छेड़ रखा था और इसके कारण इन किसानोंने सरकारसे सहयोग करनेसे इन्कार कर दिया था।

तबसे हालत बहुत सुधर गयी है। वेव और उनके बादके अन्य आलोचकोंका कहना

है कि सोवियत साम्यवाद एक नयी मन्थना है। साम्यवादी आदर्शों की प्राप्ति के लिए जिस नियम बटोरना और आनुवादका उपयोग किया गया था, वेब उसकी कोई सहाई नहीं देते। पर उनका कहना है कि "इन कथन में कोई अन्वृत्ति नहीं है कि १९१७ से रूसी जनताका दूसरा जन्म हुआ है।" द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भ तक जहाँ एक ओर मन्थारके अनेक देश बेकारी के बोझ में पिने जा रहे थे, वहाँ रूस में बेकारी की कोई समस्या ही नहीं थी। १९२८ में व्यक्तिवादी व्यवस्था की तुलना में सामूहिक क्षेत्रों में शोषणा उत्पादन हुआ।^१ विमानों की वैयक्तिक प्रवृत्ति को मनुष्य करने के लिए उन्हें अपने निजी मकान, उद्यान, कुठ भुंजर, गाँव और मुगिया रखने की अनुमति दी गयी। गेहूँ पैदा करने वाले क्षेत्रों का मकोरण या एकीकरण कर दिया गया है।

रूस का बहुत अधिक औद्योगीकरण हो चुका है। उत्पादन और वितरण की योजना एक केन्द्रीय योजना के अनुसार तैयार की जाती है। और फिर यह योजना फैक्ट्री-मन्थों और केन्द्रीय मन्थियों की श्रमिका द्वारा कार्यान्वित की जाती है। दिन-दिन बन्धुओं का उत्पादन किया जाय और उनका वितरण कैसे किया जाय— यह निश्चय करने में साधारण मन्थारका भी हाथ रहता है। योजना इनकी भावधानी और मन्थारता से बनती जाती है कि किसी प्रकार की बर्बादी या ना विस्तृत नहीं होनी या बहुत ही कम होनी है। विदेशी व्यापारका मन्थालन इस प्रकार से किया जाता है कि बाहरी देशों की मुद्रास्फीति (inflation) या मुद्रासंकट (deflation) का सोवियत अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिनकी रकमका माल बाहर में मन्थारा जाता है उसी की रकम का माल रूस में बाहर भेजा जाता है। इस प्रकार आपनका मूल्य निर्यात द्वारा चुका दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को उधार 'ट्रेड-यूनियन वेज' (Trade-Union Wage) मिलता है। यह सही है कि रूस में भी वेतन और मन्थारों में असमानता है। पर उसी नहीं जिनकी पूँजीवादी देशों में। उद्योगों में भी श्रम-बूट की भावना में काम लिया जाता है। जिस प्रकार श्रम-बूट में सम्मान और आनन्द पाने के लिए परिश्रम किया जाता है, ठीक उसी प्रकार बहुत से उत्पादी मन्थार सम्मान और आनन्द पाने के लिए श्रम करते हैं। मन्थारों की भावना मन्थाल कर दी गयी है। पूँजीवाद हमेशा के लिए बिदा कर दिया गया है।

सोवियत रूस में ऐंसे भी उत्पादन है जो मन्थार होते हैं। पर जिनकी मन्थारा कमाल के लिए मन्थारी पर काम लेने की इजाजत नहीं है। पर हाल के पंचवर्षाकी

^१ रूस में 'सामाजिक उपयोग के लिए व्यवस्थित उत्पादन होता है' (वेब)। हाल ही के एक अधिकारी के कथनानुसार मार्क्सवादी स्वामित्व की व्यवस्था में १९२७ और १९२८ के बीच रूसी लोगों ने अपना औद्योगिक उत्पादन ८०० प्रतिशत बढ़ा दिया जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, और अमेरिका वैयक्तिक स्वामित्व की व्यवस्था में केवल पचास प्रतिशत ही वृद्धि कर सके।

युद्ध में विजय पाने वाले और पराजित होने वाले दोनों ही, युद्ध में अच्छी तरह ऊब चुके थे। शान्ति, अन्तर्राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र के लिए जनता में मत्वा उत्साह था। पर सभ्यता के भविष्यका निर्माण करने के लिए वारमार्ड में जो राजनीतिज्ञ एकत्र हुए थे वे इस योग्य न थे कि अपने कार्यको ठीक प्रकार कर सकते। सम्प्रमुद्राष्ट्र राज्य के जर्जर सिद्धान्त को 'राष्ट्रोका आत्म-निर्णय' कहकर भावी व्यवस्थाओंका आधार बना दिया गया (The outworn doctrine of the sovereign nation State in the form of 'the self-determination of nations' was made the basis of future arrangements.)। फलतः कई ऐसे छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण हुआ जो अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ थे। योरोपीय सभ्यता मही अर्थों में निर्माण करने के बजाय राष्ट्रसंघ (League of Nations) का निर्माण किया गया। बड़े राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघका उपयोग अपना मतलब निकालने के लिए किया। मन्त्रापित-प्रणाली (mandatory system) के नाम पर विजयी राष्ट्रोंको उपनिवेश सौंप दिये गये। पराजित राष्ट्रों पर भारी जुर्माने ठोके गये। जर्मनी को ही युद्धका एकमात्र अपराधी ठहराया गया। वारसाई सन्धिकी 'युद्ध अपराध धारा' बहुत वर्षों तक जर्मनी की आखी में घुलकी तरह चुभनी रही। युद्धसे उत्पन्न समस्याओंको हल करने के लिए कोई सम्मोच प्रयत्न नहीं किये गये। युद्धके बाद प्रारम्भिक वर्षों में तो इस दिशामें ऑस्ट्रिया और जर्मनी को श्रृंखला दिये जाने के अलावा बिल्कुल यत्न ही नहीं किया गया। राजनीतिक और आर्थिक समस्याओंको एक दूसरे से बिल्कुल पृथक् रखा गया। विश्वका वित्तीय नियंत्रण विजयी राष्ट्रोंके हाथों में रहा। सामूहिक सुरक्षाकी व्यवस्था तो की गयी पर यह वागज पर ही रही। सामूहिक सुरक्षाका स्थान क्राँसमैन के शब्दों में 'सामूहिक शान्तिवाद' (collective pacifism) ने ले लिया। ऐसा मालूम पड़ता है कि विजय ने फ्रांस और ब्रिटेन की चुस्ती में बनी कर दी। इन देशोंके अनुदारवादी (conservatives) पहले की भांति प्रचण्ड साम्राज्यवादी न रह गये और समाजवादियों ने शान्ति की क्षमता खो दी'। (क्रॉसमैन, २५६)। इन देशोंकी सैनिक शक्ति अब भी पर्याप्त थी, पर वे उस समय तक इसका उपयोग नहीं करना चाहते थे जब तक कि यथावत् स्थिति अमहनीय न हो जाय। अनुशास्ति व्यवस्थाका पालण्ड रखा गया (The myth of sanctions was invented) पर उसका उपयोग केवल एक ही बार अबीसीनिया युद्धके दौरान १९३५-३६ में किया गया। और उस समय भी इसका उपयोग करनेवालों ने ही इसे विफल कर दिया। इन सब बातोंके फलस्वरूप लोकतन्त्रीय निष्ठाको भारी धक्का लगा। दूसरी ओर, युद्धके एकदम बादके वर्षों में खास तौर पर, साम्यवादका होवा विश्व शान्ति करा देनेकी धमकी दे रहा था। युद्धोपरान्त योरोपीय स्थितिको इस पृष्ठ भूमि में ही इटली के फासिस्टवाद और जर्मनी के नाजीवादको ठीक प्रकारसे समझा जा सकता है।

१. इटली में फासिस्टवादका उदय (The Emergence of Fascism in Italy). 'फासिस्टवाद' (fascism) शब्दकी उत्पत्ति 'fascio' शब्दसे हुई है जिसका

मनलव है लकड़ीका एक मट्ठा जो अनुशासन, एकता और शक्तिका प्रतीक है। युद्धके दौरानमें इसका मनलव उन सब लोगोंने था जिन्होंने अपनेको एक सूत्रमें बांध लिया था और इटली के लिए जीने और मरनेको तैयार थे। सर्वप्रथम 'fascio' नामक मस्याकी स्थापना मुमोलिनीके नेतृत्वमें मिलान नामक शहर में १९१५ में हुई थी। इसके बाद १९१९ में साम्यवाद का मुखावला करने के लिए मस्याका पुनर्निर्माण किया गया। सन् १९१९ के ममरीय चुनावमें फासिस्टोको एक भी सीट नहीं मिली। मुमोलिनी स्वयं मिलानसे खड़े हुए थे और बुरी तरह हारे थे। उस समय मुमोलिनीके बारे में कहा गया था कि 'यह एक मूर्ख है जो शीघ्र ही दफना दिया जायगा।' पर 'मूर्ख' जो उठा और तीन मालके भीतर ही इटली में फासिस्टवादी सरकारकी स्थापना हो गयी।

इटली को कुछ घटनाओंने फासिस्टवादके इस आदर्शपर्यन्त उत्थानमें बड़ी महायत्ना पहुंचायी। युद्धके बाद इटली में उदारवादी सरकार शासनाखंड थी। यह सरकार बहुत कमजोर थी। इस सरकारके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि पैरिस शान्ति सम्मेलनमें यह इटली का पूर्णरूपेण हित साधन करनेमें विफल रही है। विजयी राष्ट्र होने पर भी इटली को कोई महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नहीं मिला। स्मर्ना या अन्य कोई भी प्रदेश न मिलनेसे इटली को घोर निराशा हुई। आग्ल-मैसमन देशोंके बटने हुए भारी क्षणों ने आगमें ईंधन का काम किया। इटली में एकके बाद एक करके अनेक हड़तालें हुईं। फलतः देशका आर्थिक जीवन बुरी तरह अस्थिर हो गया। समाजवादी शान्तिवादी पैपारी कर रहे थे। समझमें भी सरकारके कार्योंमें बाधाएं पैदाकी जा रही थी। इन सब बानोंके बावजूद इटली को तात्कालीन सरकार बड़ा कदम उठानेमें डरती रही और हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।

इटली की इस दयनीय स्थिति में मुमोलिनी ने रंगमंच पर पदार्पण किया। वह सम्पूर्ण इटली को एक सूत्रमें बांधकर देशमें शान्ति, व्यवस्था और अनुशासन कायम कर एक शक्तिसाली सरकार स्थापित करना चाहते थे। मुमोलिनी अपने जीवनके आरम्भमें अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादमें विदगम करने वाले शान्तिवादी विचारोंके व्यक्ति थे। पर प्रथम विश्व युद्धके दौरानमें उनके विचारोंमें एकदम परिवर्तन हो गया और उन्होंने सेनामें भर्ती होकर दो वर्ष तक अपने देशके लिए युद्ध किया। देशभक्तिवादी आग उनके हृदयमें जोरोंसे पक रही थी। वह इटली को प्रथम धर्मोकी यांरोपीय शक्ति बना देना चाहते थे। उनका कहना था कि उदार लोकतन्त्रका भार ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ऐसे अमीर देश ही उठा सकते हैं, इटली जैसे गरीब देश नहीं। उनका कहना था कि इटली को इस समय सबसे बड़ी जरूरत नेतृत्व की और अनुशासन की है। इटली की जनता दो कारणोंसे लोकतन्त्रके एकदम विरुद्ध थी। पहला कारण तो यह था कि इटली में लोकतन्त्र अपनेको प्रभावहीन सिद्ध कर चुका था। और दूसरा कारण यह था कि शान्ति सम्मेलन में और उसके बादके वर्षोंमें इटली को पश्चिमी लोकतन्त्र के हाथों हानि उठानी पड़ी थी। इटली की जनताका लोकतन्त्रमें विश्वास तो

उठा ही, माथ ही वह राष्ट्रसभ में भी अविश्वास करने लगी और वह ब्रिटन और फ्रांस के गठ-बन्धनको नष्ट करनेको बैचैम हो उठी। मुसोलिनी इस गहरे अमन्तापको भावनाके मूर्तरूप थे (All this surging discontent found an embodiment in Mussolini)।

अपने जीवनके आरम्भमें मुसोलिनी पर मोरेल की श्रमिक मंधवादी शिक्षाओं का बहुत प्रभाव पड़ा था। आम हड़ताल में तथा वर्गयुद्धमें उनका पक्का विश्वास था पर युद्धके बाद की दृष्टि की हालत ने उन्हें मोरेल की शिक्षाओंको त्यागनेके लिए बाध्य किया यद्यपि सामान्य श्रमिक मंधवादी विचारधारामें, विरोधपर सीधी कार्रवाईमें उनका विश्वास बना रहा। पहली अगस्त १९२२ को आम हड़तालकी घोषणा की गयी। यह घोषणा फासिस्टवादियोंके लिए धरदान साबित हुई। फासिस्टवादियोंने मौलिक सेवाओंको चालू रखनेका भार अपने ऊपर लेकर हड़तालको २४ घण्टेके अन्दर समाप्त कर दिया। अपने इस वायेंसे फासिस्टवादियोंने जनताके एक बहुत बड़े अंशकी श्रुतशक्ता प्राप्तकी और उसके विश्वास पात्र हो गये।

सत्कालीन इटली की सरकार जनताकी दृष्टिमें और भी नीचे गिरती गयी। अन्तमें २८ अक्टूबर, १९२२ को मुसोलिनी ने अपने अनुयायियोंके साथ रोम पर घावा बोलकर सार्वजनिक कार्यालयों, रेलों, डाक और सारपरो आदि पर अधिकार कर लिया। यह सब दान्तिपूर्ण ढंगसे ही हुआ। सरकारके पाम इस्तीफा दे देनेके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया। एक दिन बाद इटली के राजाने मुसोलिनी को मन्त्रिमण्डल बनानेके लिए आमन्त्रित किया। मुसोलिनी ने फौरन ३० अक्टूबर, १९२२ को अपना मन्त्रिमण्डल बनाया। उसके बाद मुसोलिनी २४ जुलाई, १९४३ तक इटली के एकछत्र शासक रहे और फिर उनका पतन हो गया।

आन्दोलनके प्रारम्भिक दिनोंमें जब मुसोलिनी राज्य सत्ताकी ओर अपने कदम बढ़ा रहे थे, उनके पास कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था और उन्होंने एक बारसे अधिक अपनी स्थिति बदली। उन्होंने घोषणाकी कि इटली को 'कार्यक्रम' नहीं 'कार्य' चाहिए। उनके मूलके मन्त्रिमण्डलमें विभिन्न दलोंके लोग थे। १९२६ के बाद ही इटली की सरकार पूरी तरहसे फासिस्टवादी और तानाशाही बनी। उसी वर्ष नवम्बर में फासिस्ट दलके अतिरिक्त दोष मभी राजनीतिक दल दबा दिये गये और समाचारपत्रोंका मुह बन्द कर दिया गया। कई एक कानून पास करके मन्त्रिमण्डल का समदके प्रति उत्तरदायी होनेसे बरी कर दिया गया। मुसोलिनी सरकारके 'प्रधान' बन गये। वह केवल राजा ही के प्रति उत्तरदायी रहे। उन्हें ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार हो गया जो विधियोंके समान ही गवितपान थे। मन्त्रिगण उनके सहयोगी न रहकर उनके अधीन हो गये। मुसोलिनी 'द्यूस' कहे जाने लगे। द्यूम शब्दका मतलब है 'नेता'।

१९२८ में पुरानी प्रतिनिधि सभा (Chamber of Deputies) को समाप्त कर उसके स्थान पर एक नये मदनकी स्थापनाकी गयी जिसे 'Corporative Parliament'

इसमें चार भी सदस्य थे। ये सदस्य आदादी या क्षेत्रका प्रतिनिधित्व न करके आर्थिक हितोंका प्रतिनिधित्व करते थे। इस मदनकी सदस्यता की व्यवस्था फासिस्ट दलकी महामहिनि (grand council of fascism) करती थी जो राष्ट्रीय राज्यकी भी महामहिनि थी। मदनको पहलखदमी (initiative) का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। वह केवल प्रधान द्वारा दिये गये मुद्दोंके पर ही अपनी राय दे सकता था, पर उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता था। फासिस्ट दलका प्रधान फासिस्ट सरकारका प्रधान होता था।

मदनके ऊपरी मदन, मिनेटमें राजघरके राजकुमार और वे जीवन सदस्य होते थे जिन्हें प्रधान मंत्रीको सलाहने राजा नियुक्त करता था। आजीवन सदस्योंकी संख्या सीमित नहीं थी। मिनेट निचले मदन द्वारा भेजे गये विषयोंके पर विवाद करती थी, उनमें सुधार कर सकती थी और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती थी। मिनेट द्वारा सलाहित या अस्वीकृत विषयक निचले मदनकी पुनः विचार करनेके लिए भेज दिये जाने थे।

फासिस्टवादकी विचारधारा (The Ideology of Fascism)

इटली में इक्कीस वर्ष तक निरन्तर राज्य करने पर भी फासिस्टवादका कोई मुखिधारित सिद्धान्त नहीं था। प्रथम विश्व युद्धके समाप्त होने पर इटली में जो साम्यदिक परिस्थितियाँ थी उन्हीं परिस्थितियोंकी उपर फासिस्टवाद है। यह राष्ट्रकी कार्य करनेकी निज्ञा देता है। उसका प्रधान मंत्र शक्ति और सज्जीवता है। फासिस्टवाद, व्यक्तिवाद, पूँजीवाद, अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद, उदारवाद और मनुष्यात्मक प्रज्ञानवाद का विरोधी है। फासिस्टवाद वर्ग-युद्ध और सर्वहारावर्गकी तानाशाही पर आधारित साम्यवादका विरोध तौर पर विरोधी है। पर साम्यवादका तो अपना एक दर्शन है जो प्रमाणों द्वारा तर्कपूर्ण ढंगसे व्यक्तमिथ और सिद्ध किया गया है और जिसका विचारपूर्ण मूल्यांकन किया गया है। भले ही अपनायी गयी पद्धतिका आधार एक बौद्धिक उत्पन्न ही हो। इसके विपरीत फासिस्टवादका दर्शन कार्य-मापक रहा है। इसका प्रधान मन्त्र यह है काम निकालना, किये हुए कार्योंका औचित्य सिद्ध करना और आनन्दाली परिस्थितियोंका सामना करना और इसके लिए वह अपने विचारोंमें समझ-गमय पर परिस्थितियोंके अनुसार रद्दोबदल करता रहा है। फासिस्टवाद भूलन-तर्कहीन है। उसमें प्रेरणा अथवा स्वाभाविक प्रवृत्ति पर आधारित बर्तन बर्तना ही मिलती है। फासिस्टवाद इच्छा और विश्वासके कारण ही मय है। (मिशाइन)।

फासिस्टवाद सक्रिय और नास्तिकवादी राज्यका मनर्पन करता है। मुनोत्पत्ती नें दिया था कि फासिस्टवाद एक धार्मिक धारणा है। इस धारणाके अनुसार

अपना भाग्य जोड़कर जर्मनी का साथ दिया और फ्रांस का पतन आसान कर दिया।

फासिस्टवाद अन्तर्राष्ट्रीयतावादका शत्रु है। उसका कहना है कि 'अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कायरोंका स्वप्न है।' मुसोलिनी के कथनानुसार 'साम्राज्यवाद जीवनकी पुरानी और कभी न बदलने वाली विधि है।' एक बार उन्होंने लिखा था कि हम चार करोड़ व्यक्ति अपने सक्ने पर अर्चनीय (adorable) प्रायद्वीपमें न जाने किस प्रकार गुजर कर रहे हैं और इस अर्चनीय प्रायद्वीपके इन चार करोड़ व्यक्तियोंको हाथ-पैर फैलानेका अवसर देनेके लिए, १९३६ में जरासे बहानेको लेकर एक वर्षर युद्धके बाद अवीसीनिया को इटली में मिला लिया गया। मुसोलिनी का कहना था कि 'इटली का विस्तार उसके लिए जीवन और मरणका प्रश्न है।' इटली का विस्तार होना ही चाहिए अन्यथा उसका विनाश हो जायगा।

सरकारकी आन्तरिक कठिनाइयोंसे लोगोका ध्यान हटानेके लिए इटली ने युद्ध का सहारा लिया। फासिस्टवादने जानबूझ कर देशमें ऐसी नीति अपनायी कि जिसका परिणाम दूसरे देशोंके साथ युद्धके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता था। वह न तो विद्व शान्तिको सम्भव ही मानता था और न उसे उपयोगी ही समझता था।

फासिस्ट विचारधारा पर लिखते हुए हैलोवेल (Hallowell) कहते हैं कि फासिस्टवाद वैयक्तिक स्वाधीनता और समानताकी धारणाओंको अस्वीकार करता है। फासिस्टवाद का कहना है कि व्यक्तिका अस्तित्व राज्यके लिए है। मुसोलिनी ने राज्यको स्वयं अपने आपमें एक आत्मिक और नैतिक शक्ति बतलाया है।

फासिस्टवाद प्रेरणा और स्वाभाविक प्रवृत्ति (instinct) से काम करता है, विवेकसे नहीं। वह समस्त मूल्य महत्त्वको आपेक्षिक ही मानता है। अपने आपमें किसीका कुछ मूल्य महत्त्व नहीं है। सत्य वही है जिसे तानाशाह सत्य कह दे। अधिकार वही है जिसे तानाशाह अधिकार मान ले। यदि नाजीवाद जातिकी कल्पित गौरव-भाषा गाता है तो फासिस्टवाद राष्ट्र की दुहाई देता है। दोनों ही के मूलमें प्रतिकार (vengeance) की भावना है।

आज दिन भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियोंमें भी फासिस्ट प्रवृत्तिया पायी जाती हैं।

फासिस्टवाद की सफलताएं (Achievements of Fascism).

मुसोलिनी और उनके अनुयायियोंने सत्तास्थ होनेके बाद कुछ वर्षों तक अपने देशके लिए निस्सन्देह बहुत कुछ किया। उन्होंने देशकी वित्तीय स्थिति ठीक की। राष्ट्रीय जीवनके प्रत्येक पक्षकी कमजोरिया दूर करनेके लिए उसे फिर से सगठित किया गया। कृषिकी उन्नति की गयी। मुद्द आधार पर उद्योगोकी स्थापना की गयी। दलदलोको साफ किया गया और जहा पहले मच्छर भनभनाते थे वहा एक नया

शहर बनाया गया। मातापिता के माधनोंका इतना विकान किया गया कि उनका स्वरूप ही बदल गया। सुन्दर आकारकी आकर्षक इमारतें बनायी गयीं।

पर बादके वयोंकी कहानी बिल्कुल भिन्न है। एक ओर वस्तुओंका मूल्य बढ़ता गया और दूसरी ओर चेतन तथा मजदूरी जानबूझ कर घटायी गयी। औद्योगिक मजदूरोंकी अपेक्षा जमींदारों और किसानोंकी भलाईके लिए अधिक प्रयत्न किये गये। अवोनीनिया युद्धके पहले बेकारीकी समस्या गम्भीर हो गयी थी और बेकारी दूर करनेके लिए सैनिक तैयारियाँ आरम्भ की गयीं। जनताका जीवन स्तर गिर गया। इटली धान्यका अपोष्टिक भोजन फानिस्ट राज्यमें और भी निरूप्य हो गया। बड़े पूँजीपतियोंकी अपेक्षा छोटे व्यापारियोंको अधिक हानि पहुँची। पूँजीवादकी मानि फानिस्टवादमें भी व्यापारमें मन्दी और तेजीका क्रम चला और मन्दीका जमाना लौट-लौट कर आना रहा। जैसा सेबाइन लिखते हैं: "आत्मबलिदान, साम्राज्यालन और राष्ट्रीय युद्धमें प्राण अर्पण करनेके आदर्शोंकी शिक्षा उनके नैतिक महत्त्वके कारण नहीं दी जाती थी। जनतामें हमेशा यह कहा गया कि वर्तमान बलिदानके बदले उसे भविष्यमें अधिक लाभ होगा। और यह लाभ उन्हींको होगा जो सबसे अधिक बलिदान करेंगे। धर्मांधता अथवा कुटिल स्वार्थ मोपे-मापे लोगोंको लाभका प्रलोभन देता है। पर भविष्यका यह फानिस्टवादी स्वप्न माननात्मक है (१२ : ७७४-५)।

निगमित राज्य (The Corporative State.) फानिस्टवाद का दावा है कि आर्थिक क्षेत्रमें उसकी सबसे अधिक मौलिक और महत्त्वपूर्ण देन निगमित राज्य है। फानिस्टवाद बड़े गर्वसे कहता है कि निगमित राज्य न तो पूँजीवाद है और न समाजवाद। यह नवीन और उच्च कोटिकी व्यवस्था है। मुमोलिनी के शब्दोंमें निगमवाद (Corporatism), समाजवाद और उदारवाद दोनोंमें ही ऊँचा है। हमने एक नयी व्यवस्थाको जन्म दिया है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है कि उनके समस्त कार्योंमें से निगमित राज्यका निर्माण सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और मौलिक कार्य है या दूसरे शब्दोंमें सबसे अधिक कान्तिकारी कार्य है। यद्यपि हम फानिस्टवादके इस लम्बे-छोटे दावेको माननेके लिए तैयार नहीं हैं पर हम यह विश्वास करने को तैयार हैं कि निगमित राज्यमें तो नहीं पर नियमित समाजकी धारणामें अवश्य हमें आधुनिक राज्यके पुनर्गठनका आधार मिल सकता है।

फानिस्टवादी निगमित राज्यकी धारणामें मध्यकालीन धेनीवाद (guild) और आधुनिक श्रमिक मण्डलवाद (Syndicalism) दोनों ही का मेल है। कुमारी विलकिंसन (Miss Wilkinson) का यह कथन सही है कि फानिस्टवाद कोरी पूँजीवादी प्रतिरक्षा ही नहीं है। इसमें अपने समाजवादी तत्व भी हैं। जैसा कि एक अन्य संस्करण कहा है, फानिस्ट समाजवादी और पूँजीवादी दोनों ही हैं। क्योंकि उनमें पूँजीवादी और समाजवादी दोनों ही प्रवृत्तियाँ समर्थ रूपमें पायी जाती हैं।

फानिस्टवाद वर्तमान पूँजीवादकी आलोचना करते हुए कहता है कि वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्थामें मानिक और मजदूर दो परस्पर विरोधी दलोंमें भगड़न रहने

है और सामान्य जनहित की अवहेलना की जाती है। फासिस्टवाद मजदूरों, मालिकों और उपभोक्ताओं इन तीनों के हितों की रक्षा समानरूपसे करने का प्रयत्न करता है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि और मार्बजनि कल्याण की मिट्टि फासिस्टवाद के मुख्य लक्ष्य हैं। फासिस्टवाद का दावा है कि मजदूर, मालिक और उपभोक्ता तीनों ही समाज के अंग हैं और इसलिए तीनों ही के हित एक दूसरे में बंधे हुए हैं।

सिद्धान्त रूपसे यह सब सही सत्य भी हो पर अमली प्रश्न तो यह है कि फासिस्ट-वादी राज्य अपने इस उद्देश्य को कहा तक पूरा कर पाया है। इटली के निगमित राज्य होने हुए भी १९३४ तक देश में एक भी निगम नहीं था यद्यपि मन्निमण्डल में निगम विभाग कई वर्षों से था। ५ फरवरी, १९३४ की विधि द्वारा ही सरकारी तौर पर निगमों की स्थापना की गयी।

इटली के निगमित राज्य के संगठन से यह स्पष्ट है कि राज्य और फासिस्ट दल प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका कारण यह मान लेना है कि राज्य और फासिस्ट दल उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर यह दावा आसानी से सिद्ध नहीं किया जा सकता कि मालिकों और मजदूरों की अलग-अलग समान्तर समस्या होती है। राज्य और फासिस्ट-दल मालिक और मजदूर के बीच पंच और संयोजक का काम करता है। निगमों को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकारने कुछ शर्तें निश्चित कर दी हैं। जो संस्थाएँ इन नियमों को पूरा नहीं करती उनकी कोई वैधिक स्थिति नहीं होती। कच्चे माल में लेकर तैयार माल तक उत्पादन का सारा काम निगम के अधीन होता है। प्रत्येक निगम का नियंत्रण एक समिति करती है जिसका अध्यक्ष मन्निमण्डल का कोई सदस्य, राज्य का उपसचिव या फासिस्ट दल का मंत्री होता है।

निगमित राज्य का संगठन अमाधारण तौर पर जटिल होता है। विभागों में कामों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि एक ही काम एक से अधिक विभाग किया करते हैं। १९२५ में इटली में २२ निगम और ९ राष्ट्रीय संघ थे। राष्ट्रीय संघों की संख्या बाद में तेरह हो गयी थी। राष्ट्रीय संघों का संगठन मालिकों और मजदूरों के पदानुक्रम सम्बन्ध के आधार पर और निगमों का संगठन समान आधार पर होता है।

निगमित स्थानों के अधिकार अधिकतर परामर्शमूलक हैं। वे स्थान मजदूरों के झगड़ों का निपटारा करते हैं, सामूहिक धर्म सविदाओं को पूरा करते हैं, शिक्षा और समाज सम्बन्धी कार्य करने हैं और राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाते हैं। वे ही वेतन, काम के घण्टे, उत्पादन और वितरण निर्धारित करते हैं। शिक्षार्थी मजदूरों का नियंत्रण भी वे ही करते हैं।

निगमित राज्य का दावा है कि उसकी योजना का आधार व्यक्तिवादी न होकर सामूहिक है, पर असत्यत यह नहीं है। उत्पादन अब भी व्यक्तिगत उद्योग पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत उत्साह (initiative) और व्यक्तिगत सम्पत्तिका अन्त नहीं किया गया है। मुगोलिनी के कथनानुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति मानव व्यक्तित्व को

पूर्णता प्रदान करती है। यह एक अधिकार है; और अगर यह अधिकार है तो एक कर्तव्य भी है। निगमित राज्यके कट्टर आलोचक जॉन स्ट्रुची का कहना है कि फासिस्ट-वादी योजना पूँजीपतियोंकी महमतिसे बनती है और इसे बनाते समय इस बातको महत्त्व दिया जाता है कि योजना ऐसी हो जिसमें सबसे कम अड़चनें आवें।

देश भरके मजदूर-मधो और मालिकोंके संगठनोंको समाप्त कर उनके स्थान पर निगमोंको स्थापना की गयी। ये निगम पूरी तरहसे राज्य पर आश्रित थे। निगमोंमें मजदूरों और मालिकोंको समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। पर जैसा सेबाइन कहते हैं: "यह मानना भूल होगी कि समान प्रतिनिधित्वका अर्थ समान अधिकार या भविष्यदल तक समान पहुँच थी। यह मानना भी गलत है कि निगमके माध्यमसे ही प्रभाव डाला जाता था या काम करवाया जाता था।" हड़ताल या तालाबन्दी पर वैधिक रोक लगा दी गयी थी। हड़ताल करने वालोंको सात वर्ष तककी कैदकी सजा दी जा सकती थी। यदि तीनसे अधिक मजदूर एक साथ हड़ताल करते थे तो उन्हें दण्ड देनेका अधिकार विरोध मजदूर अदालतोंको दे दिया गया था। मालिकों और मजदूरोंके झगड़ोंको मजदूर अदालतें राष्ट्रके हितोंको ध्यानमें रखते हुए निपटानी थी। ये अदालतें स्वयं अपनी ओरसे झगड़ोंमें हस्तक्षेप कर सकती थी। ये इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती थी कि झगड़ोंमें सम्बन्धित कोई पक्ष आकर उनका दरवाजा खटखटाये। जॉन स्ट्रुची का कहना है कि ऐसा मानूँ होता है कि इस व्यवस्था द्वारा इटली के पुराने 'कॉम्बिनेशन कानून' (Combination Act) को पुनः लागू कर दिया गया। मजदूरोंके लिए मजदूर अधिकार पत्रकी घोषणा कर उन्हें कुछ अधिकार दिये गये। इन अधिकारोंमें सवेतन छुट्टियाँ, नाम-मात्रके सच पर डाकटरी महामता, विभिन्न प्रकारके मुआवजे, बुढ़ापे और मृत्यु सम्बन्धी बीमाके अधिकार प्रमुख थे। जोड़ ने इस अधिकार पत्रकी 'मजदूरोंका महाधिकार पत्र' (Magna Carta of Labour) कहा था और इसका स्वागत किया था।

हड़तालोंके साथ ही मर्दुवाजी और अव्यधिष मुनाके पर भी वैधिक रोक लगा दी गयी थी। १९३० और १९३३ में सरकारी आजाओ द्वारा चीजोंके दाम कम कर दिये गये थे। मालिक अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे।

निगमित राज्यने उत्पादन तो अवश्य बढ़ाया पर वह साम्यविक्रि वेपनोंमें कोई शाम मुधार नहीं कर सका। १९२६-२७ के बाद इटली के बैंकों पर नियन्त्रण कर लिया गया। बैंक और इटली ही समस्त ऋणका नियमन करता था। सरकारकी स्वीकृतिसे बिना कोई नया बैंक नहीं मोला जा सकता था। नोट आदि कुछ उद्योगों को एवमें मिला दिया गया। जहाज उद्योग आदि कुछ उद्योगोंको सरकारी सहायता दी गयी।

इस सम्पूर्ण योजनाका उद्देश्य इटली और जर्मनी दोनों ही में साम्राज्यवादी विस्तार और युद्ध था। उद्योग धन्य ही नहीं, खेती भी बहुत कुछ सरकारी सैनिक नियंत्रणसे अधीन थी। मारा संगठन सैनिक आधार पर ही किया गया था। कमबद्ध

अधिकारियोंकी शृंखला नेतृत्वकी एकता तथा अनुशासन इस संगठनके मूल सिद्धान्त थे। सारा संगठन जनप्रतिष्ठत फासिस्ट दल पर निर्भर करता था। फासिस्ट दल आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक शासन दोनोंका ही एक समान मुख्य आधार और स्तम्भ था।

यद्यपि हम उन सब कार्योंका समर्थन नहीं करते जो इटली में निगमित राज्यके नाम पर किये गये, पर निगमित समाजका विचार एक ऐसा विचार है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसा कि रेवरेण्ड पी० कार्टी ने कहा है: समाजका सार्वजनिक कल्याण, राज्यके अधिकार और व्यक्तियोंके अधिकार इन तीनोंका एवमा सम्मान और विकास होना चाहिए। इटली के निगमित राज्यके भाष्य खराबी यह थी कि इसका संगठन ही युद्धके लिए किया गया था। हमें आवश्यकता एक ऐसे निगमित समाजकी है जिसका संगठन शान्तिके लिए हो। निगमोंका निर्माण राज्य द्वारा न होकर स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा हो। व्यक्ति राज्यको सहमतिसे अपना संगठन करे। निगमित राज्य और निगमित समाजमें यही मुख्य अन्तर है। निगमका कार्य-क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक होता है राजनीतिक नहीं; अतः इसे राजनीतिक दलके नियंत्रणसे मुक्त होना चाहिए। इटली और जर्मनी दोनोंमें मजदूरों और मालिकोंके पूँछ-मूँछ संगठनोंको समाप्त कर दिया गया था। होना यह चाहिए कि इन दोनोंको निगमित समाजका अभिन्न अंग बना दिया जाय।

प्रो० कार्टी आगे कहते हैं कि निगमित समाजमें निश्चित समुदायके स्थायी हितोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले प्रत्येक निगमको सार्वजनिक विधि द्वारा मान्यता प्रदानकी जाती है और विधि द्वारा ही उसका नियंत्रण किया जाता है। अधिकार पत्र द्वारा दिये गये अधिकारोंकी सीमाके भीतर निगमका प्रशासन लोकतंत्रीय आधार पर होता है। निगम अपने सदस्योंके प्रति विधायिका, कार्यकारिणी, और न्याय-पालिका सम्बन्धी तीनों प्रकारके कर्तव्योंको पूरा करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यकी सम्प्रभुता समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ केवल इतना है कि राज्य द्वारा दिये गये अधिकारोंकी सीमाके भीतर और सामान्य सार्वजनिक कल्याणके अनुकूल निगमको स्वप्रामाण्य अधिकार प्राप्त रहता है (११: १५४)। मजदूरोंको समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 'अच्छी तरह विचार-विमर्श करनेके बाद निगम एक ऐसी नियमावली तैयार करता है जो सारे व्यावसायिक समुदाय पर एक निश्चित अवधि तक लागू रहती है (११: १५५)।' यह नियमावली राज्य द्वारा स्वीकृत हो जाने पर ही लागू होती है। राज्य नियमावलीको स्वीकार करनेके पूर्व सामान्य सार्वजनिक हितकी दृष्टिसे जांचता है। राज्य विभिन्न नियमावलियोंको समन्वित करके एक मानव अर्थ व्यवस्था तैयार करता है।

यह नियमावली सम्बन्धित व्यावसायिक समुदायकी आर्थिक कारंवाइयोंका नियमन करती है। नियमावली ही निश्चित करती है कि कौन वस्तु कितनी और किस प्रकार तैयार की जाय—उसका व्यापार कैसे किया जाय और नियमावली

(Code) ही वस्तुओंका कोटा निर्दिष्ट करती है। तैयार भालका मूल्य, यातायात कर और सम्बन्धित व्यावसायिक समुदायोंके साथ होनेवाले सौदोंका तथा तैयार भालके विज्ञापनों और बाजारोंका नियंत्रण भी नियमावली द्वारा ही किया जाता है (११:१५५)। इसके अतिरिक्त नियमावली व्यवसायके भीतर सामाजिक व आर्थिक सम्बन्धोंका नियंत्रण करती है। वेतन, कामके घण्टे और परिस्थितियाँ, भुआवजा, सेवेतन छुट्टी, पारिवारिक भत्ते, लाभ और विभिन्न प्रकारके बीमोंमें प्रबन्धकोंके भाग आदिकान नियंत्रण भी नियमावली द्वारा ही होता है (११:१५५)।

देशमें इस प्रकारके निगमोंकी स्थापना हो जाने पर जनताके आर्थिक और व्यावसायिक हितोंकी देखभाल ये निगम ही करते हैं। राज्य आर्थिक और व्यावसायिक समस्याओंमें निश्चिन्त होकर अपना सारा समय राजनीतिक और सैनिक कार्योंमें लगाता है। प्रत्येक निगमके उद्देश्य, कार्य-प्रणाली और अधिकार पर विस्तृत प्रकाश डालना कठिन है। निगमका उद्देश्य तो यह हो सकता है कि अधिकसे अधिक उत्पादन हो, वेतनके अनुकूल वस्तुओंके दाम रहें, प्रतियोगिता समाप्त हो, राष्ट्रीय शक्ति अधिकमें अधिक बढ़े, और अधिकसे अधिक सामाजिक शान्तिकी स्थापना हो। उद्देश्य चाहे जो कुछ हो, और यह देश और कालके अनुसार भिन्न होगा ही, 'विवेकपूर्ण और व्यावहारिक मानव उद्देश्यकी सिद्धि ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।'

जर्मनी का नाज़ीवाद (Nazism in Germany)

१. नाज़ीवाद का उदय (The Emergence of Nazism).

जर्मनी में नाज़ीवादका उदय जिन परिस्थितियोंमें हुआ था वे अनेक बानोंमें उन परिस्थितियोंमें मिलनी-जुलनी थी जिनमें इटली में फासिस्टवादका उदय हुआ था। पर जर्मनी और इटली की परिस्थितियोंमें कुछ महत्वपूर्ण अन्तर भी थे।

१९१८ में जर्मनी विश्व युद्धमें पराजित हो चुका था और उसकी आर्सें मूल चुकी थी। इससे पूर्व जनताको विश्वास दिलाया गया था कि जर्मनी को मेना अजेय है, पर जब जर्मनी की इन तयार-रखित 'अजेय' सेनाको मित्रराष्ट्रोंकी सेनाके आगे घुटने टेक देने पड़े तब देश भरमें व्याकुलता छा गयी। युद्धके अन्तमें हुई वारसाइकी सन्धियों जर्मनी की जनताने कभी पगन्द नहीं किया। शीघ्र ही इसे विद्रोहियों द्वारा जबरदस्ती लादी गयी दानि बहा जाने लगा। सन्धियों अनेक बातें बहुत बटोर दी। उनका उद्देश्य जर्मनी को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें द्वितीय या तृतीय श्रेणीका राष्ट्र बना देना था। जर्मनी की सैनिक प्रतिष्ठा बम करनेके लिए निरस्तस्वीकरणकी एक बहुत बड़ी मोत्रना बनायी गयी। सन्धियोंके फलस्वरूप जर्मनी कई बरों तक अपनी हवाई सेना न रग सका। जर्मनी में दानिपूनिके रूपमें इनकी बड़ी रकमें मांगी गयी जिनका बदा करना जर्मनी के घुनेके बाहर था। यह सही है कि बादमें ये रकमें कम

कर दी गयी—विशेषकर डाव्स (Dawes) और यंग (Young) योजनाओं द्वारा, और अन्तमें एक दिन वह भी आया कि जर्मनी ने हर्जना देनेमें बिल्कुल इन्कार कर दिया। पर जब तक मित्रराष्ट्रों द्वारा जर्मनी से हर्जनिकी मांगकी जाती रही तब तक जर्मनी की जनताका खून खौलता रहा और नवयुवक यह समझ कर बेचैन होते रहे कि उन्हें बहुत दिनों तक मित्रराष्ट्रोंके वेंतन भोगी दाम बनकर रहना है।^१ राइन नदीके पश्चिमके प्रदेशका विसंन्धीकरण कर दिया गया। जर्मनी का पुनः सैनिक शक्ति न बनने देनेके लिए उस पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। क्षतिपूर्तिकी रकम अदा न होने पर सन् १९२३ में फ्रांस और बेल्जियम ने हर पर आक्रमण कर दिया और वे कई वर्षों तक उस प्रदेश पर अधिकार बिये रहे।

इन सब बातोंके अतिरिक्त जर्मनी से उसके उपनिवेश छीन लिये गये। मित्रराष्ट्रों के चतुर राजनीतिज्ञोंने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन की आश्रामें धूम झांक कर जर्मनी से छीने गये उपनिवेशोंको समानाधिकारित प्रदेशों (mandated territories) के रूपमें आपसमें बांट लिया। समानाधिकारित प्रणालीके नाम पर एक भारी भ्रम योजना बनायी गयी। इस बात का दावा किया गया कि समानाधिकारित राष्ट्रोंका प्रधान उद्देश्य अपने सरक्षणमें आने वाले क्षेत्रोंको यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र इस योग्य बना देना है कि वह अपना शासन स्वयं कर सकें। मित्रराष्ट्रोंकी कयनी और करनी में अन्तर इतना स्पष्ट है कि उस बारेमें कुछ कहना अनावश्यक है। एक-आध अपवादको छोड़कर सारे विजेता समानाधिकारित प्रदेशोंको अपने उपनिवेश ही मान बैठे।

जर्मनी की आन्तरिक आर्थिक स्थिति दिवालिया हो चुकी थी। जर्मनी के सिक्के मार्क का मूल्य तेजीसे घटता जा रहा था और मुद्रास्फुटि हो रही थी। फलतः व्यावसायिक वर्गोंका करीब-करीब विनाश हो गया। एक और मध्यवर्ग क्षतिग्रस्त हो गया था और दूसरी ओर वे लोग अपने वैभवका प्रदर्शन कर रहे थे जो युद्धके दौरान और उसके बाद मुनाफालोरीसे घनी बन बैठे थे। इस द्वितीय वर्गमें यहूदियोंकी महत्ता कम नहीं थी। देशमें बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। १९३२ में ६० लाख व्यक्ति बेकार थे। देशकी नयी सीमाओंके कारण जर्मनी के भारी उद्योग बर्बाद हो गये थे। इन नयी सीमाओंने केन्द्रीय योरोप के नक्शेको ही बदल दिया। जर्मनी के कुछ प्रदेश उससे छिन गये, उसके कुछ नागरिक दूसरे देशोंमें बिखर गये।

इस दयनीय दशाके कारण जर्मनी में साम्यवादका प्रसार तेजीसे होने लगा। ऐसा मालूम पड़ता था कि जर्मनी इस तेजीसे बढ़ने वाली साम्यवादी विचारधारा और पद्धतिका शिकार हो जायगा। पश्चिमी लोकतन्त्रकी परम्पराके अनुरूप जर्मनी के लिए लोकतन्त्रीय संविधान बनाना ही इससे बचनेका एकमात्र उपाय था। फलतः वीमर गणतन्त्र (Weimar Republic) की स्थापना हुई। पर जनताने इसे कभी पसन्द

^१ एक जर्मन नवयुवकने १९३२ में लिखा था: “हम एक ऐसे युवक समाजके सदस्य हैं जिसे न तो भविष्यमें कोई आशा है और न वर्तमान कालमें कोई सुख।”

नहीं किया। बीमर गणतन्त्रका संविधान पण्डिताऊ और शास्त्रीय संविधान था। इसमें जर्मनी की विशिष्ट परम्पराओं और जर्मन जनताकी प्रवृत्तियोंका विन्कुल ध्यान नहीं रखा गया था।

एकतन्त्र निरंकुश सत्ताके बजाय, जिसके जर्मन लोग उपामक हैं, उन्हें एक राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष, समदके प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल और मौलिक अधिकारों की एक लम्बी सूची दी गयी। एक बात और हुई कि जो लोग बीमर-संविधान बनाने के लिए जिम्मेदार थे उन पर यह आरोप भी लगाया गया कि वे बिजयी मित्र राष्ट्रोंसे जर्मनी के लिए यथामुम्भव अच्छीसे अच्छी शर्तें नहीं मनवा सके। राष्ट्रीय गौरवके इस अपमानका पुराने सामक वर्ग, नौकरशाही और मध्यवर्गके हृदयमें बड़ा गहरा आघात लगा। जर्मन जनताने बारम्बारकी सन्धि और जर्मन गणतन्त्रको मजबूर होकर अनिवार्य बुराई ही समझा। केवल औद्योगिक मजदूरों में ही इनके प्रति उत्साह था।

बीमर-संविधानके अन्तर्गत बनने वाली विभिन्न सरकारोंको अनेक अमाध्य कठिनाईयोंका सामना करना पड़ा। एक ओर जनतामें असन्तोष बढ़ रहा था और वह निरुत्साहित हो रही थी और दूसरी ओर मित्रराष्ट्र अपनी उन असम्भव शर्तोंको जर्मनी से पूरा करानेका प्रयत्न कर रहे थे जो जर्मनी पर जबरदस्ती लादी गयी थी। १९१९ और १९३३ के बीच १२ अध्यक्षाँके नेतृत्वमें २१ मन्त्रिमण्डल बने। देशमें अनगिनत राजनीतिक पार्टियाँ थीं। इन पार्टियोंके उद्देश्य एक दूसरेके विरोधी थे। १९३२ में जर्मन समद (Reichstag) का जो चुनाव हुआ उसमें ३८ राजनीतिक पार्टियोंने भाग लिया था। सामाजिक लोकतन्त्रवादी (Social Democrats) पार्टीके अनुयायियोंकी संख्या बहुत बड़ी थी। यह पार्टी यदि अपनी घोषणाओंके प्रति सच्ची होती, और देशके आर्थिक पुनर्निर्माणके लिए व्यापक स्वतन्त्रतापूर्ण कार्यक्रम अपनाती तो वह देशको बचा सकती थी। पर साम्यवादके भयके कारण यह पार्टी माहमपूर्ण नईम उठानेमें डरती रही। यही नहीं; इस पार्टीने उद्योगपतियों और भूम्यामियोंमें समझौता कर लिया। फलतः राजनीतिक दृष्टिकोने विभाजनके मामलेमें युद्धके पूर्वके जर्मनीमें युद्धके बाद का गणतन्त्रीय जर्मनी अधिक मित्र नहीं था। जर्मन लोगों की कहना है कि सामाजिक लोकतन्त्रवादियोंकी इस कायरतापूर्ण और समझौता-परम्परा नीतिके कारण ही नाज़ियोंको राजनीतिक सत्ता हासिलानेका अवसर मिला।

मित्रराष्ट्र जर्मनी की मजबूर बनाकर उसकी लोकतन्त्रवादी सरकारको अपने नियन्त्रण में रखना चाहते थे। दार्शनिक प्रारम्भिक शर्तोंमें मित्रराष्ट्र शान्तिपूर्विका एक एक पैसा जर्मनी में समूल कर लेना चाहते थे। बारम्बार सन्धिको अन्यायपूर्ण धाराओंको हटानेके लिए दिये गये मुझावोंकी एकदम उपेक्षा की जाती थी। जर्मन राजनीतिज्ञोंने अनेक तरह निवेदनोंकी भी निरन्तरके साथ टुट्टरा दिया गया। बाद में जर्मनी के साथ कुछ रिमायनों की गयी पर वे शर्तों मूल जाने पर बरसिक समान थी। १९३० में निश्चित समयमें पाब बंधे पूर्व राइन प्रदेश ग्राह्य कर दिया गया। १९३२ में शान्तिपूर्विका मार्ग समाप्त कर दी गयी। पर इनमें से किसी भी शर्तोंके लिए न

तो जर्मनी की गणतंत्र सरकारको कोई शाबाशी दी गयी जिसने यह कूटनीतिक सफलता प्राप्त की थी और न जर्मनोने रियायतें करने वाले मित्रराष्ट्रोंको ही कोई कृतज्ञता मानी।

इस राजनीतिक और आर्थिक पुष्ठभूमिमें ही हमें नाज़ी आन्दोलनकी राजनीतिक सफलताको समझना है। इसका आरम्भ एक अत्यन्त सामान्य आन्दोलनके रूपमें हुआ जो कुल २८ व्यक्तियों तक ही सीमित था। इस आन्दोलनका जन्मदाता ताले बनानेवाला एक लोहार था जिसका नाम ऐंटन डैम्मलर था। आरम्भमें आन्दोलनका कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था। यह जर्मन सेनाओंकी पराजयको अस्वीकार करता था। इसका कहना था कि जब जर्मन सेनाएं विजयके निकट थी तभी विजय के एम भौके पर जर्मन सेनाओं के 'पीठ में छुरा भोका गया।' २८ प्रारम्भिक सदस्योंमें से केवल ६ सदस्य सक्रिय थे। ऐडोल्फ हिटलर इस दलमें सातवें सदस्यके रूपमें शामिल किये गये। उस समय हिटलर एक विल्कुल ही अज्ञात व्यक्ति थे। वह ऑस्ट्रिया में उत्पन्न जर्मन थे और १९१२ में जर्मनी चले आये थे। वह युद्धमें लड़े थे और घायल हुए थे। उन्हें सेनाओंके उपलक्षमें एक लौह पदक दिया गया था। सेनामें उनकी तरक्की कार-पोरलके पद तक हुई थी। इसके विपरीत मुसोलिनी इटली का राष्ट्रीय नेता था। मुसोलिनी फासिस्टवादी तानाशाही स्थापित करनेके पहले भी युद्धमें महत्वपूर्ण कार्य कर चुके थे।

हिटलर और मुसोलिनी में एक अन्तर और था। मुसोलिनी एक प्रतिभावान विचारक तथा दर्शनशास्त्र और राजनीतिक सिद्धान्तीकरणमें रुचि रखनेवाला व्यक्ति था। पर हिटलर की शिक्षा अपूर्ण थी, यद्यपि उसमें व्यक्तिगत गुण थे। हिटलर अत्यधिक भावुक और अपनेको अत्यधिक महत्व देनेवाला व्यक्ति था। सम्भवतः उसने हीगेल और ऑस्टिन वेम्बरलेनके मूल ग्रन्थोंको कभी नहीं पढ़ा था। यद्यपि उसने इन दोनों विचारकोंके अनेक विचारोंको अपनी आत्मकथा (*Mein Kampf*) में स्थान दिया।

आरम्भमें नाज़ी पार्टीका नाम जर्मन मजदूर पार्टी (*German Workers' Party*) था। पर जीवनके दूसरे ही वर्ष यानी १९२० में इसका नाम राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर पार्टी (*National Socialist German Workers' Party*) रखा गया। फिर कुछ वर्षों बाद उसका नाम केवल राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (*National Socialist Party*) हो गया। नाम का यह अन्तिम परिवर्तन महत्वपूर्ण था। क्योंकि इस नामके कारण वे बहुतसे लोग इस पार्टीमें शामिल हो गये जो अपनेको राष्ट्रीयतावादी और समाजवादी कहते थे। इस पार्टीके कार्यक्रम की मुख्य बातें जिसे आरम्भमें गॉटफ्रीड फेडर (*Gottfried Feder*) ने २५ परिच्छेदों में लिखकर तैयार किया था, बहुत क्रान्तिकारी थीं। उनमें से कुछ ये थीं—अनर्जित आयका उन्मूलन, युद्धकालके मुनाफोंको जन्त करना, व्यासोंका और भूमिका राष्ट्रीयकरण आदि। किसी ने भी आरम्भमें इस आन्दोलनको अधिक महत्व नहीं दिया यद्यपि यह विल्कुल स्पष्ट था कि मित्रराष्ट्रों द्वारा किये गये जर्मनी के राष्ट्रीय अपमान के कारण ही इस आन्दोलन का जन्म हुआ था। निम्न मध्यवर्गीय जनता, सैनिक सगठनोंके सदस्य और छात्र ही

इस आन्दोलनकी ओर आकर्षित हुए। अधिकांश उद्योगपति और उच्च मध्यवर्गीय व्यक्ति इस आन्दोलनमें दूर ही रहे। जो लोग इस आन्दोलनकी ओर आकर्षित हुए भी वे उसके त्रान्तिकारी कार्यक्रमके कारण उसकी ओर उतना नहीं झुके जितना उसकी सैनिक प्रवृत्ति के कारण। घृणा और बदलेके आधार पर ही इस पार्टीकी स्थापना की गयी थी। इस पार्टीने 'अमल जर्मनी' के सभी शत्रुओंमें विशेषकर मार्क्सवादी उदार-पन्थियों, साम्यवादियों और यहूदियोंमें लोहा लेने की ठानी थी।

१९२३ तक आन्दोलनका विकास धीरे-धीरे हुआ। उस वर्ष हिटलर ने जनरल लुडेनडोर्फ (General Ludendorff) के साथ स्पूनिखके घावमें भाग लिया। घावा असफल रहा। हिटलर गिरफ्तार हो गया, उस पर मुकदमा चला और उसे पांच वर्षकी बंदकी सजा दी गयी। पर उसे आठ महीने बाद छोड़ दिया गया। जेलमें ही हिटलर ने अपनी आत्मकथा (*Mein Kampf*) लिखी। यह पुस्तक आगे चलकर नाजी-वादियोंकी गीता बन गयी।

इसके बाद से आन्दोलनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। दिन प्रतिदिन अधिकाधिक लोग इस आन्दोलनमें शामिल होने लगे। ज्यो-ज्यो समय बीतता गया त्यो-त्यो आन्दोलनकी शक्ति बढ़ती गयी। घनी बांका भय दूर करनेके लिए आन्दोलनके प्रारम्भिक कार्यक्रममें आवश्यक सुधार किये गये। उदाहरणके लिए 'बिना मुआवजेके भूमिके राज्याधिकरण' सम्बन्धी धाराकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की गयी कि वह भूमि का सट्टा करने वाले यहूदियों पर ही लागू हो मके। सेनाके कुछ भूतपूर्व अधिकारी इस पार्टीमें शामिल हो गये। उन्होंने 'तूफानीदल (Storm Troopers)' के मगडन में सहायता दी। यह दल नाजी पार्टीका मेरुदण्ड बन गया। सैनिक प्रदर्शन, सैनिकवादिया, स्वस्तिक जैसे दलके चिह्न, साम्यवादियों और पुलिसके साथ मूक्केबाजी आदि जर्मन युवकोंकी लड़ाकू और स्वच्छन्द प्रवृत्तिको बहुत आकर्षक लगे। नाजी नेताओं के कुशल प्रचारने, हिटलर की बहुत अधिक जोशीले भाषण देनेकी शक्तिने, और मगडन महान् जर्मनी के नाम पर बलिदान और अनुशासनकी नाजी नेताओंकी अपीलोंने इस आन्दोलनको लोकप्रिय बनानेमें बड़ा काम किया।

जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे-वैसे उद्योगपति, सम्पत्तिगाली वर्ग और नौकर-चाही अधिकाधिक रूपमें नाजी आदर्शोंके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होने लगे। उग्र राष्ट्रीयता का उन पर अधिक प्रभाव पडा। ऐसा विशेषकर इमालिण् भी हुआ कि उन्हें इस बातका विश्वास हो गया था कि हिटलर को मंगा उन त्रान्तिकारी योजनाओंको कार्यान्वित करनेकी नहीं हैं जिन्हें नाजी पार्टीने शुरू-शुरूमें अपने कार्यक्रममें रखा था।

नाजीवादने शुरू-शुरूमें कोई उन्नेयनीय प्रगति नहीं की। पर १९२९ में इसने जोर पकडा। तत्कालीन विश्वव्यापी मन्दी और चारों ओर फैली बेकारीने इस आन्दोलनको और भी बल दिया। १९३२ में राष्ट्रपतिता चुनाव हुआ। इस चुनाव में हिटलर हिट्लेनबर्ग के विरुद्ध मारा हुआ। हिटलर को प्रथम मतदान (ballot) में १ करोड १३ लाख और दूसरे मतदानमें १ करोड ३४ लाख मत मिले। इसके बाद

से बराबर नाज़ी पार्टी विधायिकामें सबसे बड़ी पार्टी रही। यद्यपि समय-समय पर इसकी स्थिति अस्थायी तौर पर बिगड़ी भी। नाज़ी पार्टीको जितनी सीटें मिली थी उसकी आधीसे कुछ ही अधिक सीटें सामाजिक लोकनरवादीयोको मिलीं। नवम्बर १९३२ में हिण्डेनबर्ग ने हिटलर से संयुक्त सरकार बनानेको कहा। पर हिटलर ने संयुक्त सरकार बनाना अस्वीकार कर दिया। लगभग दो महीने बाद ३० जनवरी १९३३ को हिण्डेनबर्ग ने फिर हिटलर को संयुक्त सरकार बनानेके लिए आमन्त्रित किया। इस बार हिटलरने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इसके बाद से हिटलर और उसके नाज़ी साधियोंका ही जर्मनी में बोलवाला रहा।

हिटलर की प्रथम मन्त्रिपरिषद् नरम और अक्रान्तिकारी ही थी। पर नाज़ी पार्टीका देश पर पूरा प्रभुत्व था। इस प्रभुत्वका कारण नाज़ी पार्टीका अपना आन्तरिक सुदृढ़ संगठन और राजनीतिक व्यवस्था और पुलिस पर उसका नियंत्रण था। ५ मार्च, १९३३ को जर्मन ससद (Reichstag) भंग कर दी गयी। इसके कुछ दिन पूर्व रहस्यमय ढंगसे ससद भवनमें आग लगी थी। जिससे ससद भवन बुरी तरह जल गया था। इस आगको साम्यवादी क्रान्तिका संकेत चिह्न ठहराया गया। इसके बाद देशमें अव्यवस्था फैल गयी। इस स्थितिमें मन्त्रिपरिषद् द्वारा दिये गये नागरिकों के अनेक मौलिक अधिकारोंको राष्ट्रपतिने रद्द कर दिया। इसी उत्तेजनापूर्ण वातावरण में ससदका चुनाव हुआ और नाज़ियोंको ५२ प्रतिशत सीटें मिल गयी। यह चुनाव सक्षम कानून (Enabling Act) के प्रश्न पर लड़ा और जीता गया था। इस कानूनने नाज़ी सरकारको चार सालके लिए करीब-करीब अपरिमित शक्ति दे दी।

अब नाज़ी पार्टीके विशेष कार्यक्रमोंको कार्यान्वित किया जाने लगा। प्रशासन सेवा और न्यायपालिकासे 'अनाथों' को निकाल बाहर किया गया। एक जन न्यायालयकी स्थापना की गयी। यह अदालत सरकारके हाथकी कठपुतली थी। समाचार पत्र, रेडियो, थियेटर, और सिनेमा—प्रचारमंत्री डा० गोयबेल्स (Dr. Goebbels) के आधीन कर दिये गये। इसी प्रकार स्कूलों और विश्वविद्यालयोंको शिक्षा मन्त्रीके संरक्षण में रख दिया गया। एक कानून द्वारा नाज़ी पार्टीको देशकी एकमात्र वैधिका पार्टी घोषित किया गया। किसी अन्य पार्टीकी स्थापना अपराध हो गया। मजदूर संघों को भंग कर मजदूर वर्गको नाज़ियोंके नियंत्रणमें लाया गया। नवम्बर, १९३३ में ससदका निर्वाचन हुआ। इस चुनावमें नाज़ी पार्टीको ९२ प्रतिशत मत मिले, पर यह सफलता काफ़ी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबावके बिना नहीं मिली। पहली दिसम्बर को नाज़ी पार्टीको राज्यके शासन यंत्रमें सम्मिलित कर लिया गया।

संघ प्रणाली समाप्त कर दी गयी। राज्योंको जिलोंका रूप दे दिया गया। हर जिलेको हिटलर के एक निजी प्रतिनिधिके अधीन कर दिया गया। उसे वस्तुतः ताना-शाही अधिकार प्राप्त थे। इसके बाद संघके इकाइयोंका प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे सदन (Reichsrat) को भंग कर दिया गया। १९३४ में हिण्डेनबर्ग के निधन के बाद हिटलर ने राष्ट्रपति और अध्यक्ष दोनोंके सारे अधिकारोंको अपने हाथमें कर

लिया। यही नहीं हिटलर ने कार्यपालिका और विधायिकाके सर्वोच्च अधिकारोंको भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। वह जर्मनी में अध्यक्ष, सर्वोच्च नेता और एकछत्र शासक अर्थात् सर्वसर्वा बन गये। समदकी बैठकें कभी-कभी बुलाई जाती थी—कोई निर्णय करनेके लिए नहीं, हिटलर की कारमुजारियोंकी प्रशंसा करनेके लिए।

२. नाज़ीवादकी विचारधारा (The Ideology of Nazism).

नाज़ीवादकी विचारधारा बतलाना आसान नहीं है क्योंकि नाज़ीवाद राज्य या सरकारका कोई व्यवस्थित सिद्धान्त नहीं है। वह केवल एक आन्दोलन है जो व्यापक भावनापूर्ण आवश्यकताके कारण उठ खड़ा हुआ था। युद्धोत्तर जर्मनी की और विघेप-कर हिटलर की बौद्धिक और भावनान्मक विघेप परिस्थितियोंके कारण इस आन्दोलनका उदय हुआ था। यह मही है कि नाज़ीवाद राजनीतिक सिद्धान्तके कुछ तत्व जर्मन जातियों विघेपताओंके अनु रूप हैं। पर साथ ही इस सिद्धान्तके अनेक तत्वोंको युद्धके बादकी जर्मनी की परिस्थितियोंकी पृष्ठ भूमिमें ही समझा जा सकता है। हिटलर का व्यक्तित्व और जाति तथा समाजमें स्थितियोंका स्थान जैसे प्रश्नोंके बारेमें हिटलर की विशिष्ट मनोवैज्ञानिक धारणाएँ नाज़ी सिद्धान्तके साथ इस प्रकार घुली मिली हैं कि नाज़ीवादको 'हिटलरवाद' कहना अधिक ठीक होगा। नाज़ी आन्दोलनके आध्यात्मिक जन्मदानाओंमें जर्मनीके वाय्ट, फिस्ले, हीगेल, गाँविन्सु और एच० एम० चेम्बरलेन जैसे महान् आदर्शवादी और इटली के मुसोलिनी थे।

जर्मन परम्पराके अनुसार ही नाज़ीवाद राज्यको सार्वभौमिक अधिकार पर पट्टा देना है। पर राज्यको इतना ऊँचा स्थान देनेका कार्य किसी भी उच्च दार्शनिक तरीकेसे नहीं किया गया। यह कार्य जर्मनी की साम्यवादी आवश्यकताओंका पूरा करनेके लिए बहुत ही व्यावहारिक ढंगसे किया गया। देशके खोये हुए राष्ट्रीय गौरवको फिरसे वापस लानेके लिए राष्ट्रीय एकताको सबसे अधिक आवश्यक समझा गया। इसलिए राष्ट्रीय एकताके स्थापनाके नाज़ियोंने राज्यको मानवोपरि मत्ता (Superhuman entity) का रूप दिया। 'समाज' (Volk) को बच्चे माल के समान माना गया जिसमें समाजका निर्माण होता है। समाजकी मजबूत बनानेके लिए नाज़ियोंने देशके मानने लगातार यह आदर्श रखा कि 'एक व्यक्तिके हितोंकी अपेक्षा समाजके हित' अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिटलर ने सिद्धान्तके अनुसार "व्यक्ति कुछ नहीं है, समाज ही सब कुछ है।" अधिकारोंकी अपेक्षा कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया जाना है।

अधेज़ी परम्पराके अनुसार राज्य एक सेवक के समान है। प्रजा की परम्परा समाजकी स्वामी मानती है। इन दोनों परम्पराओंका पारस्परिक विरोध दिखाने हुए स्पेंग्लर (Spengler) लिखते हैं कि "अधेज़ी परम्परा में हमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, आत्मनिर्णय, सत्य और सहृदयता मिलती है। जर्मनी परम्परामें राज्य-भक्ति, अनुगमन, आत्मबलिदान और आत्मप्रतिपक्ष पर जोर दिया जाता है। व्यक्ति

कोई महत्व नहीं होता। उसे अपने को समाजके लिए बलिदान करना चाहिए। किसी एक व्यक्तिका जीवन स्वयं उसके लिए नहीं है। सबका जीवन उसके लिए है। और आजापालनसे मिलनेवाली आन्तरिक स्वाधीनता सबको प्राप्त है।" इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्तिको अपने मनका काम करनेकी या पहलकदमीकी स्वाधीनता नहीं है। एक सुव्यवस्थित राज्यकी आज्ञाओंका पालन करनेमें ही उसे अपने जीवनका महत्व और सुख मानना चाहिए। राज्यकी अनिवार्य सेवा ही पूर्ण स्वाधीनता है। नाज़ियों के इस सिद्धान्तमें हमें हीगेल के सितल्लिखकाइट (Sittlichkeit) सम्बन्धी सिद्धान्तोंकी प्रतिध्वनि ही सुनायी देती है। एक सूक्ष्मदर्शी पर्यवेक्षकके कथनानुसार इस शिक्षाके फलस्वरूप जर्मनी के लोग अपने देशको महान, पर अपनेको कुछ बनाने लगे।

नाज़ी पार्टी समाज और राज्यको जोड़ने वाली कड़ी थी। उसने जनताको एक सूत्रमें बांधकर उसे एक सामान्य नेतृत्वके अधीन काम करनेका अवसर दिया। राज्य तो केवल नाज़ी पार्टीके कार्यक्रम और कार्यकलापको अपनी सम्प्रभुसत्ताका दल प्रदान करता था। फलतः राज्य और नाज़ी पार्टी एक रूप हो गये। किसी भी दूसरी पार्टीका अस्तित्व सहन नहीं किया जा सकता था क्योंकि उससे राज्य कमजोर होता और शक्तियोंका अपव्यय होता। जुलाई, १९३३ की विधिके अनुसार (१) 'जर्मनीमें केवल एक ही राजनीतिक दल है और वह है राष्ट्रीय सामाजिक जर्मन मजदूर दल, (२) जो कोई किसी दूसरे राजनीतिक दलकी स्थापना करनेका प्रयत्न करेगा या किसी अन्य राजनीतिक दलको कायम रखेगा उसे तीन वर्ष तक की कैदकी सजा दी जा सकेगी।' कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि हिटलर और उसके साथी लोकतन्त्र और लोकतन्त्रीय सस्थाओंसे घृणा करते रहे। वे तो राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता चाहते थे। वे किसी प्रकारका विरोध सहन नहीं कर सकते थे।

नाज़ियोंने अपनी परम्पराओंके अनुसार अपनी पार्टीका संगठन नेतृत्वके आधार पर किया था। नेताओंकी एक शृंखला पार्टीका संचालन करती थी। उसकी कार्यपद्धति नीचेसे ऊपरकी ओर न होकर ऊपरसे नीचेकी ओर थी। नाज़ियोंने जिस नेतृत्वकी कल्पनाकी थी वह व्यापक आधारवाला ऐसा लोकतन्त्रीय नेतृत्व नहीं था जो जनताकी इच्छाओंका ध्यान रखता है और जनताके प्रति उत्तरदायी होता है। नाज़ियोंके नेतृत्वका आधार शक्ति था। शक्तिसे ही नेतृत्वकी स्थापना की गयी थी और शक्तिमें ही उसे कायम रखा गया था। नाज़ी विचारधाराके अनुसार कुछ लोगोंका जन्म नेता बननेके लिए होता है और शेष लोगोंका जन्म इन नेताओंके पीछे चलनेके लिए होता है। हिटलर राज्य, सरकार और सेना सभीके प्रधान थे। वह जो कुछ कहे वही विधि था। शासनका संचालन करने वाले जितने लोग होते थे उनमें सबको हिटलर ही मनोनीत करता था। वे सब हिटलर के प्रति पूर्ण रूपेण वफादार थे। तूफानी दल और काली कुर्ती वालोंका संगठन सैनिक ढंगसे किया गया। शुरूमें इन दोनों संगठनोंकी स्थापना नाज़ी पार्टीकी रक्षा करने और सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था कायम रखनेके लिए की गयी थी। इन दोनों संगठनोंके बल पर ही

नाज़ियोंने सत्ता हथियाई थी। नाज़ियोंके सत्ताखंड हो चुकनेके बाद अपने नेता हिटलर की रक्षा करना ही इन दोनों संगठनोंका मुख्य काम था। जर्मनीमें आत्मघाती टुकड़िया (suicidal squads) भी थी जो राज्य और पार्टीके नाम पर हिटलर की आज्ञा पाते ही तुरन्त शरीर बलिदान करनेको तैयार थी। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें नाज़ीदलने अपना अधिकार जमा रखा था। प्रान्त और जिला अधिकारी नाज़ीदलके प्रमुख सदस्य होते थे। इन्हें गृह मंत्रालयकी सिफारिशों पर हिटलर नियुक्त करता था। पुराने ट्रेड यूनियनोंके स्थान पर भजदूरोंके बीच नाज़ियोंने अपने अड्डे बना रखे थे जो भजदूरोंमें जोरोसे नाज़ीवादका प्रचार करते थे। भजदूर मोर्चा पूरा-पूरा नाज़ी संगठन बन गया था। नाज़ी एजेंट सब कहीं पाये जाते थे। परिवारोंकी अन्तरगत गोष्ठियों तकमें नाज़ी एजेंट मौजूद रहते थे। ऐसी घटनाएँ कम नहीं होती थी जब नाज़ी उद्देश्यके प्रति उत्साह कम होने पर लड़के मा-बापके विरुद्ध या मा-बाप लड़कोंके विरुद्ध गवाही देते थे। देशके युवकोंका संगठन 'हिटलर युवक दल' नाज़ी पार्टीका शक्तिशाली सहायक था।

नाज़ी पार्टीके सत्ताखंड होने और मानव जीवनके सभी क्षेत्रों पर उसके छा जाने के फलस्वरूप जन-जीवनका निम्न कोटिका संन्योकरण हो गया। यद्यपि यह संन्योकरण जर्मन परम्परा और प्रवृत्तिके अनुकूल ही था। राजकुमार बुलो (Bulow) का यह कहना गलत नहीं था कि उनके देशवासी इस अर्थमें 'अराजनीतिक' हैं कि उनमें नागरिक अधिकारों और नागरिक साहमकी कमी है। जर्मन युद्ध क्षेत्रमें पाहे जिनना साहमी हो पर उनमें अपने शानकोंके विरुद्ध खड़े हो सकनेकी नैतिक शक्ति नहीं होती। वह शासकके सामने चुपचाप घुटने टेक देता है। युद्ध और आक्रमणमें जर्मन की मौन स्वीकृति और उनकी सन्दिग्ध राजनीतिक नैतिकताका भी यही कारण है। अपनी इसी कमजोरीके कारण जर्मन नागरिक बड़ी आसानीसे बड़े मवाद-नियंत्रण (censorship) को और बिना मुकदमा चलाये ही बाराबासकी व्यवस्थाको स्वीकार कर लेता है। एक प्रसिद्ध जर्मन समाचार पत्रने १९३६ में लिखा था कि 'बन्दी गिबिर किसी प्रकारसे भी अपमानकी बात नहीं है बल्कि वे सभ्यताके धानूपन हैं। इन गिबिरोंमें उपेक्षित व्यक्तियोंको दृढ़ दमायुताके साथ सच्चे जीवन की शिक्षा दी जाती है।' जर्मनी में शत्रु देशोंके रेडियोको मुनका भारी अपराध माना जाता था। पर इनके विपरीत बलिनने होनेवाली साइड हॉर्स की रेडियो पर चिल्लाते सेंट्रिन में अंधेरा करना काज़ी मनोरंजन करने थे।

नाज़ियोंके अनुसार राज्यकी प्रधान विशेषता शक्ति और ओत्र है, न्याय और नैतिकता नहीं। नाज़ीवाद इस जर्मन मिथान पर जोर देता है कि शक्ति ही न्याय है। फ़िशेर (Fischer) ने १९वीं सदीमें लिखा था कि राज्योंके बीच शक्तिका मिथान ही लागू होता है। नाज़ीवाद 'जिसकी लाठी उसकी बेंग' के मिथानका प्रचार करता है और इसी पर अमल करता है। हिटलर के शब्दोंमें 'जिने जीना है उसे युद्ध करना होगा। जो हथ ममारमें युद्ध नहीं करना चाहता उसे जीनेका अधि-

कार नहीं है। यह कथन भले ही कठोर मान्य हो पर असंलियत यही है। 'मैनहीम सावर्जनिक स्कूलके प्रपानाध्यापक डा० क्रीक (Dr. Krieck) का कहना था कि 'विश्वविद्यालयोंका काम सैनिक युद्ध सम्बन्धी विज्ञान पढ़ाना है, न कि पदार्थ-मूलक विज्ञान पढ़ाना।' राइखस्वरे के भूतपूर्व प्रधान जनरल फॉन सील (General Von Seeckt) ने लिखा था कि युद्ध मानव सफलताकी पराकाष्ठा है। युद्ध मानव जातिके इतिहास में विकासकी अन्तिम स्वामाविक अवस्था है। युद्ध ही समस्त वस्तुओं का जनक है। जीवनके अस्तित्वका सबसे अधिक सरल तत्व युद्ध ही है। युद्धको रोकनेका प्रयत्न प्रकृतिकी विधिकी रोकनेका प्रयत्न है। यह भयानक बात है।

युद्धके लिए जोरदार तैयारियाँ करते हुए भी नाज़ियोने समारको यह विश्वास दिलाया कि वे शान्तिके परम प्रेमी हैं और वे जो भी सैनिक तैयारियाँ कर रहे हैं वे सबके हितके लिए हैं। हिटलर ने अपने दलकी एक बैठकमें १९३५ में कहा था कि हमारे व्यवहारको परखनेकी केवल एक ही कसौटी हो सकती है और वह है शान्तिके लिए हमारा महान अडिग प्रेम। नाज़ी सिद्धान्तके अनुसार शान्तिमूलक घोषणाएँ शत्रुको असावधान बनाये रखनेके लिए की जाती रही। पर जैसे ही हिटलर ने अपनेको सामरिक शक्तिका प्रदर्शन करने योग्य समझ लिया वैसे ही उसने पड़ोसी क्षेत्रोंको एक न एक बहानेसे हड़पना आरम्भ कर दिया।

शक्तिका उपयोग करनेके लिए आरम्भ करने योग्य समझ लिया वैसे ही उसने पड़ोसी शत्रु द्वारा किये गये अन्यायोंको मिटाना और समस्त जर्मन जनताको एक छण्डके नीचे एकत्र करना। नाज़ीवाद एक शुद्ध राष्ट्रियतावादी आन्दोलनसे बदलकर बहुत जल्द सर्व जर्मनवादी (pan-Germanic) आन्दोलन बन गया। विदेशोंमें रहने वाले अल्पसंख्यक जर्मनोंको उकसाया गया कि वे झगड़े पैदा करे और यह आवाज़ उठाये कि उनके साथ विदेशी मालिकों द्वारा अमानुषीय व्यवहार किया जाता है ताकि नाज़ियोंको सम्बन्धित प्रदेश हथिया लेनेका अवसर मिले।

आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैण्ड में यही हुआ। जिन क्षेत्रोंमें काफी मख्यामें जर्मन अल्पसंख्यक थे उन्हें जर्मनी में सम्मिलित कर देने पर भी जब हिटलर को सन्तोष नहीं हुआ तब वह ससारको अपने अधीन करनेमें लग गया। उसने नावे, डेन्मार्क, बेल्जियम, हॉलैण्ड, फ्रांस, ग्रीस और बाल्कन राज्योंको अपने कब्जेमें ले लिया।

द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ होनेके महीनो पहले ही से हिटलर ने जोरदार शब्दों में यह शिकायत करना आरम्भ कर दिया था कि जर्मनी के जो उपनिवेश वारसाई सन्धिके अनुसार उससे ले लिये गये थे वे अभी तक उसे लौटाये नहीं गये हैं। वह बराबर यह माग करते रहे कि 'चुराई हुई सम्पत्ति वापस की जानी चाहिए।' हिटलर ने यह माग करते समय इस बातका विनये ध्यान रखा कि चुराई हुई सम्पत्तिके असली मालिकोंके अधिकारोंकी यानी उन देशोंके अधिकारोंकी जिनसे पहले जर्मनी ने स्वयं ये उपनिवेश छीने थे चर्चा तक न होने पावे। अपनी आक्रामक योजनाओंको छिपाने

के लिए और अपने अनुयायियोंकी भावनाओंको उत्तेजित करने के लिए वह यह प्रचार करते रहे कि जर्मनोंको जीनेके लिए स्थान चाहिए तथा जर्मनी के शत्रु उन्हे चारों ओरसे घेर लेना चाहते हैं। शूद्ध राष्ट्रीय आन्दोलनके रूपमें आरम्भ होकर नाज़ी आन्दोलनने शीघ्र ही सर्व जर्मनवादी आन्दोलनका रूप धारण कर लिया। और फिर यह एक बरंर साम्राज्यवादी आन्दोलन और समारकी शान्तिके लिए एक सफट बन गया।

नाज़ी आन्दोलनका लक्ष्य जर्मन जातिको शक्तिशाली तथा आंशपूर्ण और जर्मन राज्यको युद्धके लिए ऐसा तैयार करना था कि वह सारे समार पर हावी हो सके। इसीलिए नाज़ीवाद बहुत अधिक जातीयवादी था। नाज़ियोंने यूहूदियोंकी महत्त्व ही में बलि का बकरा बनाकर उन्हें उन सारी विपत्तियोंका उत्तरदायी ठहराया जिनका सामना जर्मनीको पिछले बीस वर्षोंमें करना पड़ा था। आर्य जातिकी महानताकी श्रमिण गाया गयी गयी। तथाकथित अनाथ लोकोको जर्मन भूमिमे बाहर नदेई देनेके लिए कठोर कार्रवाईया की गयी। जनतामें यूहूदियों के विरुद्ध घृणा और भ्रष्ट फैलानेके लिए अनेक एक्कम झूठी बातोंका प्रचार किया गया। हिटलर ने एक बार कहा था: "आश्चर्य है! तुम जर्मन लोग जो समारमें सबसे उत्तम हो, तुम जिनकी नमोमें जर्मन, नॉर्डिक आर्योंका रक्त बह रहा है, तुम दीन-हीन बना दिये गये हो, दरिद्र बना दिये गये हो! तुम्हें यह भी पता नहीं चल तुम्हें तुम्हारी रोटी कैसे मिलेगी! ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि तुम्हारी मेनाए युद्धमें पराजित हो गयी थी? नहीं, वे कभी पराजित नहीं हुई, कभी नहीं। वे सब जगह विजयी रही थी। पर जब अन्तिम विजय उन्हें मिलने वाली थी तब यूहूदी मार्क्सवादी देशद्रोहियोंने हमारी पीठमें छुरा भोंक दिया।" जर्मनी की जनतामें यह कहावने प्रचलित थी; "यूहूदी हमारा दुर्भाग्य है, हिटलर हमारा नागा है।" यूहूदियों और अपने राज-मैनिश विरोधियोंके प्रति नाज़ियोंने निर्दयताके इतने घृणित कानें किये कि जिन पर बीसवीं सदीमें विश्वास नहीं किया जा सकता।

नाज़ी विद्वान यह था कि आर्य लोग सम्मताके महान् निर्माता हैं और दोष भवार निम्न कोटिकी जातियोंमे भरा हुआ है। हेरमन गाँथ (Hermann Gauch) का कहना था कि अनादिक या अनाथ लोग आर्यो या नॉर्डिक लोगों और पशुओंके बीचकी स्थितिमें हैं। वे वनमानुषने कुछ ही अच्छे हैं। इन जातियोंका शक्ति पूर्ण अनुप्य नहीं है। वह पशु और अनुप्यके बीचका प्राणी है। इसलिए उनको निम्न उप-मानव (sub-human) की उपाधि दी गयी है। इन्हीं केवक्ता यह भी कहना है कि 'यह निम्न नहीं किया गया है कि अनादिक लोग वनमानुषोंने महान् नहीं कर सकते।' शिक्षा अपवाद बढ़ते हुए वानावरनने लाभ उठानेने वे जर्मनमें हैं।

नाज़ियोंको इस वैज्ञानिक विद्वानने कोई परेशानी नहीं हुई कि समारमें सम्मकत: नहीं भी कोई जाति शुद्ध नहीं है। नाज़ियोंने इस तथ्यकी भी परवाह नहीं की कि जर्मन जनताका आधेमे कम हिस्सा ही नॉर्डिक है; शेषका अधिकांश अनादिक

जातिका है। जातीय शुद्धताके नाम पर जातीय मिलावट पर कड़ी रोक लगा दी गयी। उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियोंको बरखास्त कर दिया गया जिनमें स्वयं, या दो या तीन पीढ़ी तकके जिनके पूर्वजोंमें यहूदी रक्त था। वह सरकारी कर्मचारी भी नौकरीमें नहीं रह सकता था जिसकी पत्नीकी नसोंमें यहूदी रक्त होनेका सन्देह होता था।

इस अतिवादी जर्मन जातीयतावादके साथ ईसाई धर्मके एक विकृत रूप अर्थात् जर्मन द्वाण्ड के धर्ममें आस्था दिलायी गयी। और इस सिद्धान्तमें भी निष्ठा बैठायी गयी कि जर्मन स्त्रीका महत्त्व केवल इस बातमें है कि वह शुद्ध नॉर्डिक बच्चे पैदा करे और नॉर्डिक जातिकी सत्ता कायम रखे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों ही धर्मोंकी निन्दा की गयी। दोनों ही के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीयतावाद और नैतिक दासताके आरोप लगाये गये। प्रो० अर्नस्ट बर्गमान (Prof. Ernst Bergmann) ने लिखा था: "जर्मन धर्मके मानने वाले हम लोग आज इस प्राचीन नॉर्डिक भारतीय जर्मन (Indo-Germanic) ज्योति-पूजप्रतिमाको अपनाते हैं और मानव जातिको हानि पहुँचाने वाली ईसाई धर्म तथा झूठी और दृष्टि ईसाकी प्रतिमासे छुटकारा पाते हैं। नवीन जर्मन मूर्ति पूजावादका महापुरोहित स्वयं हिटलर ही है। वही सच्ची पवित्र आत्मा है। हिटलर एक है। ईश्वर भी एक है। हिटलर ईश्वर के समान हैं। हिटलर एक नवीन, एक महत्तर और अधिक शक्ति सम्पन्न ईसा हैं।" जर्मनी की ईसाई चर्चका मुह बन्द कर दिया गया। बन्दी सिविरोंके भयके कारण उन्हें अपना मुह खोलनेका साहस नहीं होता था।

हर फॉन पापेन (Herr Von Papen) का कहना था कि नाज़ीवादी योजनाके अनुसार 'माताओंको बच्चे पैदा करनेमें अपने आपको अर्पित कर देना चाहिए। पिताओंको अपने बच्चों का भविष्य सुन्दर बनानेके लिए युद्ध क्षेत्रमें लोहा लेना चाहिए।' 'लाल स्वस्तिक महिला सभ' की घोषणामें कहा गया था कि एक महिलाके लिए अपने बच्चोंको युद्धमें भेजनेसे बढकर और कोई ऊँचा और सुन्दर सम्मान नहीं है। हिटलर के अनुसार, जो स्वयं अपनी मृत्युसे थोड़े समय पहले तक अविवाहित था, 'महिलाओंकी शिक्षामें मुख्यतः उनके शारीरिक विकास पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही आध्यात्मिक महत्ताओं पर और सबसे बादमें माननिक विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। निश्चित रूपसे मातृत्व ही स्त्री शिक्षाका उद्देश्य है।'।

कुछ नाज़ी लेखकोंने अधिकसे अधिक संख्यामें शुद्ध नॉर्डिक बच्चे पैदा करनेके लिए यौन अनैतिकताका खुले आम समर्थन किया था। डा० विलीयाल्ड हेन्डेल (Dr. Willibald Hentschel) ने लिखा था, "शुद्ध रक्तवाली एक हजार जर्मन लड़कियोंको पकड़ लो। उन्हें एक शिविरमें अलग रख दो। फिर शुद्ध रक्तवाले सौ जर्मन पुरुषोंको उनके बीचमें छोड़ दो। यदि इस प्रकारके एक सौ शिविर भी खोले जा सकें तो हमें एक साथ एक लाख शुद्ध रक्तवाले बच्चे मिल जायेंगे।"

नाज़ी राज्यने अपनी कर नीति द्वारा तथा अन्य अनेक उपायोंसे अधिक वच्चे पैदा करनेकी प्रोत्साहित किया। सन्तति निरोधको राष्ट्रके प्रति पाप माना जाता था। पर ही स्त्रियोंका स्वाभाविक स्थान था। पर बादमें आगे चलकर युद्धकी आवश्यकताओंके कारण स्त्रियोंको घरों तक ही सीमित न रखा जा सका। निस्सन्देह नाज़ीवादकी इन सब बातोंमें एक उच्च कोटिका आदर्श है, पर इसका मार्ग गलत है। बाहरी लोगोंके लिए इसमें भाईचारेकी भावना नहीं है। राज्य और समाज सम्बन्धी नाज़ी सिद्धान्त नेतृत्व, अनुशासन, अधिकार सत्ता, एकता, और कठोर एकरूपता पर बहुत जोर देता है। व्यक्तिवाद, उदारवाद, शान्तिवाद, अन्तर्राष्ट्रीयतावाद समाजवाद और साम्यवादका नाज़ीवाद घोर शत्रु है। नाज़ीवाद उदारवादको आरामतलब सिद्धान्त बतलाता है। उसका कहना है कि उदारवाद एक ऐसी विलासिता है जिसका बोझ जर्मनी की तरह जीवन-संग्राममें लगा कोई राष्ट्र नहीं उठा सकता। नाज़ीवाद मार्क्सवादी वर्ग युद्धको राष्ट्रकी आत्मिक एकताको नष्ट करने-वाला मानता है। वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिको कायरका स्वप्न मानता है। बुख (Herr Buch) ने १९३७ में कहा था कि जो कोई भी व्यक्ति जर्मनी में महत्वपूर्ण काम करना चाहता है वह किसी भी ऐसे दलका सदस्य नहीं हो सकता जो अन्तर्राष्ट्रीय गठबन्धन में हो।

जब हम नाज़ियोंके राजनीतिक सिद्धान्तोंको छोड़कर उनके आर्थिक सिद्धान्तों पर विचार करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इनमें भी राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता पर उतना ही जोर दिया गया है। सार्वजनिक कल्याणको व्यक्तिगत स्वार्थोंसे ऊँचा स्थान दिया जाता है। जर्मनी को आर्थिक तौर पर आत्म-निर्भर बनानेके लिए आर्थिक स्वतन्त्रताकी नीतिका व्यवस्थित और नियोजित तौर पर अनुगमन किया गया है। शुद्ध पूँजीवाद और समाजवाद दोनोंको मलिन अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि इनसे जनता दो परस्पर विरोधी और लड़नेवाले बगोंमें बंट जाती है। जनताके कल्याणके नाम पर पूँजीपति और मजदूर दोनों पर राज्यका नियंत्रण रहना है। निर्गमित इटली के विपरीत जर्मनी में मालिकों और मजदूरोंके पृथक्-पृथक् संगठन नहीं थे क्योंकि नाज़ीवाद मालिकों और मजदूरोंके हितोंमें किसी प्रकारका भेद नहीं मानता। मालिकों और मजदूरों दोनोंको मजदूर मोर्चेमें शामिल किया गया। मजदूर मोर्चेके दरवाजे अनाथोंके लिए बन्द रखे गये। बड़े उद्योगोंको कायम रहने दिया गया। पर इन उद्योगों पर राज्य ने अपना कठोर नियंत्रण रखा। कोई भी जर्मनी में बाहर धन नहीं ले जा सकता था। राज्यकी अनुमतिमें ही नयी पूँजी प्राप्त की जा सकती थी। वित्त-मन्त्रीके अधीन काम करनेवाली अर्थ समितिना उद्योग व्यवसाय, बैंकों, बीमा, सार्वजनिक उपयोगिताओं और हस्त नित्य वस्तु पर नियंत्रण था पर व्यक्तिगत उद्यम पर रोक नहीं लगायी गयी थी। १९३३ के बाद जर्मन सरकार देनके बंधों पर पुरा-पुरा नियंत्रण रखने लगी। वस्तुओंके आयात और निर्यातके लिए सरकारसे अनुमति लेनी होगी थी। हड़ताओं और सामाजिक

पर रोक लगा दी गयी थी। 'सामाजिक सम्मान' के भंग होने पर अर्थात् मजूरों के आत्म सम्मान के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों पर विचार करने के लिए मजूर न्यायालय कायम किये गये। वेतन और मूल्य निर्धारित किये गये। हिटलर छोटे व्यक्तियों को अवसर देने की नीतिका समर्थक था। राजनीतिक ढाँचे की भाँति सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचा भी नेतृत्व के सिद्धान्त पर सैनिक ढंगसे तैयार किया गया था। फ्रासिस्टवादी इटली की अपेक्षा नाज़ी जर्मनी में निजी सम्पत्ति और वैयक्तिक पहलकदमी के अधिकारों पर अधिक प्रतिबन्ध लगाये गये थे।

जर्मनी की घेकारो की समस्या को हल करने में शस्त्रीकरण की योजना के साथ सार्वजनिक बाज़ों की योजना भी बड़ा काम किया। 'मकान बनाना, सड़कें बनाना और बेकार भूमिकों उपयोगी बनाना' इस योजना के मुख्य अंग थे। 'बेहो-वही २५ वर्षों में कम उम्र के नवयुवकों को हटाकर उनके स्थान पर अधिक उम्र के लोगों को रखा गया। उद्योगों से निर्यातों को निकाल कर पुरानों को स्थान दिया गया। एक विशेष आयकर मत्ता देकर बड़े-बड़े परिवारों को आवश्यकता से अधिक नीकर रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

खानों की चीज़ों को युद्ध के अवसर के लिए सुरक्षित रखने के हेतु भोजन की अनेक सामग्रियों की राशनिंग की गयी। देशका नाश था "मक्खन के बजाय बन्दूक"। नाज़ी नीति पर प्रकाश डालते हुए गोयरिंग (Goering) ने १९३५ में कहा था कि हमें यह निश्चय करना था कि हम अपने विदेशी विनिमय का उपयोग धातुओं के लिए करें या अन्य चीज़ों के लिए। या तो हम अपनी स्वतंत्रता देकर मक्खन खरीद सकते थे या मक्खन छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे। हमने मक्खन छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त करने का निश्चय किया। जर्मन जनता ने यह दिखला दिया है कि वह एक महान् उद्देश्य के लिए महान् बलिदान करने की तैयार है। इस सबसे यह सिद्ध होता है कि जर्मन जनता को वर्षों तक एक 'स्थायी युद्धकालीन अर्थ नीति' के अधीन रखा गया।

तीन बातें नाज़ी कार्यक्रम की कार्यान्वित करने और नाज़ी सिद्धान्त को पूरा करने में असाधारण काम किया। ये बातें थी हिटलर का अक्षितशाली व्यक्तित्व, निर्दय संगठन और जोरदार प्रचार। एक क्रियाशील व्यक्ति होते हुए भी हिटलर एक स्वप्नदर्शी और रहस्यवादी व्यक्ति थे। वह अपने को ससारका भाग्य विधाता मानते थे। अपने को देग की सेवा करने के योग्य बनाये रखने के लिए वह बहुत ही संयमका जीवन बिताते थे। वह माँम नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे और न धूम्रपान ही करते थे। वह अपने अनुयायियों से भी ऐसे ही दृढ़ अनुशासन तथा जनता और राज्य के प्रति अनन्य निष्ठा की माँग करते थे। वह स्वयं देश के लिए एक मूस थे, अपनी जबदस्त भाषण शक्त से वह जनता को अपने वश में कर लेते थे। इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जर्मनी की जनता हिटलर को देवता मानने लगी थी। एक तत्कालीन लेखक के शब्दों में "वह बात नहीं करता; भाषण देता है; वह विवाद नहीं करता, निर्णय देता है; वह चलता नहीं है, लम्बी छलांगे मारता है।"

सम्भवतः इतिहास हिटलर को आधुनिक युगका सबसे प्रसिद्ध दीवाना मानेगा।

नाज़ियोनें अपनेको सबल संगठन कर्ता और प्रवीण प्रचारक सिद्ध कर दिया। जर्मनी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कदम-कदम पर नाज़ियोका प्रभाव महसूस न करता हो। बच्चे, नवयुवक, स्त्रिया, उद्योगपति, और मजदूर सभी का संगठन नाज़ीवाद का प्रचार करनेके लिए किया गया। गोयबेल्स, गोयर्स और ली आदिके मुँहसे कोई बात निकलने ही वह पलक भारते-भारते समूचे देशके कोने-कोनेमें फैल जाती थी। हिटलर ने जो स्वयं ही प्रचार कलामें दक्ष थे, अपनी आत्मकथा 'मेरा संघर्ष' (*Mein Kampf*) में सकल प्रचारके लिए निम्नलिखित मुद्राव दिये हैं : "जनता पर व्यापक प्रभाव, कुछ वानों पर अधिक जोर देना, उन्ही बातों को बार-बार कहना, आत्म निश्चय और आत्म विश्वासके साथ निश्चयात्मक धोषणाओंके रूपमें भारणकी रचना, प्रचारमें अधिकतम परिश्रम, और फल प्राप्तिमें धैर्य"। हिटलर का सूत्र यह था कि "प्रचार का बौद्धिक स्तर जितना ही नीचा होगा, उतनी अधिक मध्यामें लोगोंको अपने पक्षमें करनेमें सफलता मिलेगी।" हिटलर के इस सूत्रको गोयबेल्स ने एक वाक्यमें इस प्रकार प्रकट किया है : "प्रचार सामान्यीकरण (simplification) की कला है।" जर्मन जनताके सीधेपनके सम्बन्धमें हिटलर ने लिखा है "जर्मन लोगोंको इस बातका पता ही नहीं है कि जनताका समर्थन प्राप्त करनेके लिए लोगोंको कितना धोखा दिया जाना चाहिए।" उनका कहना था कि प्रचारका सच्चाईसे कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका मत था कि "यदि एक झूठ बात साहसके साथ बही जाती है और वह बड़ी झूठ होनी है तो लोग उसके बड़ी होनेके कारण ही उसमें विश्वास करने लगते हैं।"

भाषणमंच, विद्यालय, रंगमंच, मिनेमा, रेडियो, समाचार पत्र, कला, विज्ञान और साहित्य सभीको नाज़ीवादकी उद्देश्य-मिद्धिमें सहायक बनना पड़ा। स्कूलोंमें पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषयको नाज़ी प्रचारका भाषन बनाया गया। अक्षरगणितमें बर्मेके आकार और उनकी विभिन्न शक्तिकी नाप-तोल मिलायी जाने लगी। हिटलर की पूजा ही धर्म मानी जाने लगी। जब बच्चा भोजनके लिए स्कूलमें घर लौट कर आता था तब उसके मां बाप 'हेल हिटलर' (हिटलर की जय) कह कर उसका स्वागत करते थे। हर जर्मन प्रति दिन ५० से लेकर १५० बार तक 'हेल हिटलर' कहा करता था। प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चेके लिए किसी न किसी नाज़ी संगठनका सदस्य होना जरूरी था। प्रत्येक जर्मन बच्चे द्वारा पढ़ी जाने वाली नाज़ी पाठ्य पुस्तकमें हिटलर के प्रति निम्नलिखित बहुमूल्य भावना प्रकटकी गयी गयी थी :

‘हमारे नेता, एडोल्फ हिटलर,

हम तुम्हें प्यार करते हैं,

हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं,

हम तुम्हारी बात सुनना पसन्द करते हैं,

हम तुम्हारे लिए बाम करते हैं,
तुम्हारी जय हो।'

३. नाजीवाद का मूल्यांकन (Estimate of Nazism).

इस शताब्दीके तीसरे और चौथे दशकमें नाजीवाद मानव-जातिके लिए उस समय तक सबसे बड़ा संकट बना रहा जब तक १९४५ में वह पूरी तरह पराजित न कर दिया गया। पराजित होने पर भी नये रूपोंमें पुनः जीवित और सक्रिय हो उठने की शक्ति उसमें है। नाजीवादके उत्थानसे पता चलता है कि निम्नतर भावनाओं और प्रेरणाओं का सहारा लेकर किस प्रकार साधारणतया बुद्धिमान जनताको गलत मार्ग पर ले जाया जा सकता है।

नाजीवादने युद्धसे घसी हुई जनताकी शिकायतोंका अधिकसे अधिक लाभ उठाया। उसने समस्त बुराइयोंके लिए उत्तरदायी बलि का एक बकरा खोज निकाला और जनताको बतलाया कि उसकी सारी तकलीफें किस प्रकार दूर की जा सकती हैं। नाजीवादका आरम्भ पूँजीवादके अन्तिम रक्तके रूपमें हुआ। एक बार सत्तास्थ हो जानेके बाद उसने पूँजीवादने स्वतंत्र होकर काम करना आरम्भ किया। यही नहीं, उसने पूँजीवादको समाप्त कर देनेके लिए कदम उठाये। उसने समाजवादी पद्धतियों और समाजवादी संस्थाओंका उपयोग किया—समाजवाद और सामाजिक न्यायकी स्थापनाके उद्देश्यसे नहीं अपितु सर्वाधिकारवादके आधार पर सैनिक राज्यकी स्थापना के लिए। आर्थिक आवश्यकताओं पर सैनिक सुविधाओंकी प्राथमिकता दी गयी। एक व्यापक लोकप्रिय आधार पर तानाशाहीकी स्थापनाकी गयी। उदार परम्पराएँ होघिमारीके साथ उखाड़ फेंकी गयी। जनता पर जाड़ का सा असर हुआ। बर्बरता और हिंसा दिन बर्षा बन गयी। मानव इतिहासका सबसे बड़ा युद्ध छेड़ दिया गया। इस युद्धने लगभग ६ वर्षों तक प्रलय मचा दी। जाति सम्बन्धी कपोल गाया कुछ इस प्रकार रची गयी कि यहूदी लोग समस्त बुराइयोंके मूर्तरूप माने जाने लगे। हेंल्रोवेल के शब्दोंमें: 'नाजीवाद आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक, और राजनीतिक अराजकताकी राजनीतिक अभिव्यक्ति' था।

नाजीवाद और फासिस्टवादकी इन तेजीके साथ हुए उन्नति और पतन—दोनों से बहुत-सी शिक्षाएँ मिलती हैं। मनुष्य अब भी एक विचारवान प्राणी होनेकी स्थितिमें बहुत दूर है। इसलिए यह जरूरी है कि उसकी अन्धी लालसाओं और प्रेरणाओं पर समुचित नियंत्रण रखा जाय। यदि उदारवाद घुटने टेक देता है, और जनताके नागरिक और राजनीतिक अधिकारोंकी रक्षा करनेमें डरता है तो वह फासिस्टवादके लिए दरवाजा खोल देता है। लोकतंत्र राजनीतिक रूपमें तब तक स्थिर है जब तक कि वह आर्थिक और सामाजिक न्यायके रूपमें दैनिक उपयोगमें न लाय

जाय; उसके पीछे ईश्वर पर अडिग विश्वासका बल न हो, और उसे व्यक्ति रूपमें मनुष्यों पर और उनके ऊंचे भाग्य पर भी उतनी ही अडिग आस्था न हो।

अविवेकवाद और सैनिकवादकी प्रतिक्रिया भी देर-सवेर होती है। फासिस्टवादी मनोवृत्तिमें विचार और चिन्तनकी गृहाज्ञा नहीं है क्योंकि वह तो तर्क-वितर्ककी अस्वीकृति है। सैनिकवाद स्वयं अपना पतन शीघ्र लाता है। तलवार उठाने वाले तलवारके घाट स्वयं उतर जाते हैं। जानीय विद्वेषवाद एक बर्बरता है जिससे समार यदि अपनी रक्षा चाहता है तो अब उसे अधिक सहन नहीं कर सकता। राजनीतिक और आर्थिक राष्ट्रीयता बड़ी तेज़ीसे समयके अनुपमृक्त होनी जा रही है और इसलिए लोगोंको अब अपनेको विश्व लोकतन्त्र और विश्व-नागरिकताकी नवीन धारणाओंके अनुकूल बनाना चाहिए।

SELECT READINGS

- Works of KARL MARX, LENIN, TROTSKY, AND STALIN.*
 BRADY, R. A.—*The Political and Social Doctrine.*
 CROSSMAN, R. H. S.—*Government and the Governed.*
 DRUCKER, B.—*End of the Economic Man.*
 FINER, H.—*Mussolini's Italy.*
 FLORINSKY, M. T.—*Fascism and National Socialism.*
 GOAD AND CURRY—*The Corporative State.*
 GOBINEAU, ARTHUR LEE—*The Inequality of Human Races.*
 HALLOWELL, J. H.—*Main Current in Modern Political Thought—*
 Chs. 11-17.
 HECKER, J.—*The Communist Answer to the World's Needs.*
 HITLER, A.—*Mein Kampf.*
 LASKI, H.—*Communism.*
 LIGHTENBERGER, H.—*The Third Reich.*
 MUSSOLINI, B.—*The Political and Social Doctrine of Fascism.*
 OAKSHOTT, M.—*The Social and Political Doctrines of Contemporary*
 Europe.
 ROBERTS, S. H.—*The House that Hitler Built.*
 ROUCEK, J. S. E.—*Twentieth Century Political Thought.*
 SABINE, G. H.—*A History of Political Theory.*
 SALVEMINI, G.—*Under the Axe of Fascism.*
 SCHUMAN, F. L.—*Hitler and the New Dictatorship.*
 SLOAN, PAT—*Russia Without Illusion.*
 STRACHEY, J.—*The Menace of Fascism.*
 WILKINSON E. & CONYA, E.—*Why Fascism?*

बहुलवाद

(Pluralism)

हमने पिछले अध्यायोंमें राज्यकी हीगेलवादी धारणाका अध्ययन किया था। हमने देखा था कि हीगेलवाद राज्यको सातवें आसमान तक उठा देता है। वह राज्य को 'पृथ्वी पर ईश्वर' मानता है। हीगेलवाद के अनुसार राज्यको केवल सर्वोच्च वैधिक अधिकार ही नहीं वरन् सर्वोच्च नैतिक अधिकार भी प्राप्त है। इस हीगेलवादी सम्प्रभुताकी धारणाके विरुद्ध हालके वर्षोंमें स्पष्ट प्रतिक्रिया हुई है। बहुलवाद इसी प्रतिक्रियाका परिणाम है। बहुलवादके अनुसार समाजमें अनेक संप्रदाय होते हैं जिनकी क्षमता और जिनके अधिकार सीमित होते हैं। राज्य ऐसे संप्रदायों से केवल एक संप्रदाय है। इससे अधिक और कुछ नहीं।

हालके वर्षोंमें लोकतंत्रकी असफलता और लोकतंत्रवादी संगठनोंकी स्वाभाविक दुर्बलताके फलस्वरूप बहुलवादी धारणाको और भी बल मिला। कुछ लोगोंका निश्चित मत है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व एकदम असन्तोषजनक है। इससे समाजके विभिन्न हिस्सोंका उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता और अल्पसंख्यक समुदाय निस्महाय हो जाता है।

बहुलवादी धारणाको और अधिक बल इस तथ्यसे मिलता है कि अत्यधिक कार्य-भारसे दबे होनेके कारण वर्तमान राज्य-व्यवस्था अपने सारे कार्य ठीक प्रकार नहीं कर पाती। आधुनिक राज्य बहुत अधिक कार्य करनेका प्रयत्न करता है और फलस्वरूप उसकी कार्य कुशलता या क्षमता कम हो जाती है। जैमा वार्ड (Ward) ने कहा है : 'केन्द्र रक्तस्राव (haemorrhage) से और धीरे-धीरे, रक्तहीनतासे पीड़ित होते हैं।' एक ओर केन्द्र अत्यधिक कार्य-बोझसे इतना दबा रहता है कि कार्य ठीक प्रकार नहीं हो पाते और दूसरी ओर ग्राम या नगर स्तर पर कोई कार्य ही करनेकी नहीं होते। केन्द्रके इस कार्य-भारको कम करनेके लिए और समाजकी कार्य दक्षता बढ़ानेके लिए बहुलवादी विकेंद्रीकृत राज्य (decentralised state) का समर्थन करते हैं। मैकलिवर (MacIver) का कहना है कि 'सर्वसामर्थ्य (omnipotence)' का मतलब अक्षमता और असामर्थ्य होता है।

अराजकतावादी और धर्मिक संप्रदायी राज्यका उन्मूलन चाहते हैं, पर बहुलवादी ऐसा नहीं चाहते, यद्यपि उनके सिद्धान्तका तर्कसंगत परिणाम राज्यका उन्मूलन हो सकता है। बहुलवादी राज्यको बनाये रखनेको इच्छुक हैं पर उससे सम्प्रभुता

छीन लेना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि सम्प्रभुताका मिद्धान्त योरोपीय देशोंके गृह-युद्धका तर्कसंगत परिणाम या [उदाहरण के लिए बोदा (Bodin के समयका फ्रांस) और इसलिए सम्प्रभुता राज्यके विकासकी दिशामें एक स्वाभाविक कदम था। पर आज जबकि राज्य अपेक्षाकृत रूपमें गृह-युद्धसे मुक्त है और राष्ट्रीय कल्याण पर जोर दिया जा रहा है, तब एवात्मक मिद्धान्तकी अपेक्षा बहुलवादी मिद्धान्त ही अधिक तथ्यसंगत है। ए० डी० लिण्ड्से (A. D. Lindsay) के अनुसार यदि हम तथ्योंको देखें तो स्पष्ट मालूम होना है कि राज्यकी सम्प्रभुताके सिद्धान्तको उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। अर्नेस्ट बार्कर (Ernest Barker) का कहना है कि "कोई भी राजनीतिक सिद्धान्त इतना निष्प्राण और निष्कल नहीं हो गया है जितना कि सम्प्रभु राज्यका मिद्धान्त।" क्राब (Krabbe) की सम्मतिमें "सम्प्रभुताकी धारणाको राजनीतिशास्त्र में निकाल दिया जाना चाहिए।"

" राज्यकी सम्प्रभुता पर निम्नलिखित तीन प्रकारसे आक्रमण किया जाता है .

(१) राज्य समाजके अन्य आवश्यक मयोंसे न तो श्रेष्ठ है और न उनसे पहले का है। इसलिए सम्प्रभुताका विभाजन होना चाहिए और सत्ता सधोंमें बंट जानी चाहिए। (२) जहां तक एक राज्यका अन्य राज्योंसे सम्बन्ध है वह न तो स्वतंत्र है और न उसे स्वतंत्र होना चाहिए। (३) राज्य विधिके ऊपर नहीं है, विधि राज्यके ऊपर और राज्यमें क़रीब-क़रीब स्वतंत्र है।

(क) राज्यकी सम्प्रभुता और संघकी स्वायत्तता

(State Sovereignty and Group Autonomy)

बहुलवाद मूलतः राज्यकी परम निरंकुशता या उसके सर्वव्यापी दावोंके विरुद्ध विद्रोह है। हीगेलवादी, फ़ामिस्ट और दूसरे सर्वाधिकारवादी यह दावा करते हैं कि राज्य निरंकुश अधिकारों पर ही नहीं, नैतिक तौर पर भी सर्वोपरि है। वे राज्यको सर्वशक्तिमान मानते हैं। बहुलवाद इस दृष्टिकोण पर आपात करता है। बहुलवाद का कहना है कि उन विविध संगठनोंको, जो मानव जीवनके लिए उनसे ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य, राज्यके साथ समानता मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि मनुष्यके व्यक्तित्वके बहुतसे पहलू होत हैं और हर पहलूकी अभिव्यक्ति मिश्र मार्गमें होनी है। एफ० डब्ल्यू० कोकर (F. W. Coker) के शब्दोंमें, "बहुलवादियोंका दावा है कि मनुष्यकी सामाजिक प्रवृत्तिकी अभिव्यक्ति विविध गुटोंमें होती है। इन गुटोंके लक्ष्य धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, आदि होते हैं। इनमें से कोई भी एक गुट, नैतिक या व्यावहारिक तौर पर किसी दूसरे गुटसे श्रेष्ठ नहीं है।" बहुलवादी दृष्टिमें राज्य न तो सबको समेट लेने वाला है, न सर्वशक्तिमान है और न सर्वव्यापी ही है।

बहुलवादकी उत्पत्ति मध्य युगकी श्रेणी व्यवस्थामें हुई थी। उस समयकी अव्यवस्थित परिस्थितियोंमें व्यापारियों और शिल्पियोंके संघोंकी स्वायत्तशासनके पर्याप्त अधिकार मिल गये थे और उन्होंने निगमोंका स्वरूप प्राप्त कर लिया था। पर राष्ट्रीय राज्यतन्त्रोका उदय होने पर इन संघोंका पतन होने लगा। जर्मनीमें गीअर्क (Gierke) और ब्रिटेन में मैटलेण्ड (Maitland) को आधुनिक समयमें बहुलवादी भावनाओंका जन्मदाता माना जा सकता है। इन दोनों ही लेखकोंका कहना है कि समाजके स्थायी संघोंकी अपनी चेतना और अपनी इच्छा होती है। और संघोंकी यह चेतना और इच्छा संघोंके सदस्योंकी चेतना और इच्छासे भिन्न होती है। उनका कहना है कि प्रत्येक सामुदायिक संघका अपना व्यक्तित्व होता है और विधियोंको बनाने और विस्तृत करनेमें उनका हाथ रहता है। यह सही है कि विधियोंके बनानेमें राज्यका हाथ प्रधान रूपमें रहता है पर राज्य अकेले ही विधि नहीं बनाता। यद्यपि ये दोनों ही लेखक राज्यकी चरम सम्प्रभुताको अस्वीकार करते हैं, पर वे राज्यकी उच्चतर वैधिक स्थितिको अस्वीकार नहीं करते। समाजके विभिन्न संघोंमें समन्वय और सन्तुलन स्थापित करनेके लिए वे राज्यको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं।

संघोंके जिन 'वास्तविक व्यक्तित्व' के सिद्धान्तकी चर्चा ऊपर की गयी है वैसे ही सिद्धान्तका समर्थन फिगिस (Figgis) ने धर्म सभ (church) के बारेमें किया है। उनका कहना है कि धर्म सभका अस्तित्व राज्यकी कृपा पर निर्भर नहीं करता। धर्म संघमें 'एक व्यक्तिकी भाँति ही आत्मविकासकी शक्ति' होती है। उसका निगमित व्यक्तित्व न तो राज्य द्वारा दिया जाता है और न राज्य द्वारा छीना जा सकता है। राज्य तो केवल इस व्यक्तित्वको स्वीकार भर कर लेता है। फिगिस का कहना है कि "मानव समाज व्यक्तियोंका कोई ऐसा बालूका ढेर नहीं है जो केवल राज्यके माध्यमसे ही एक दूसरेसे मिले हुए हों; बल्कि समाजमें तो नीचेसे लेकर ऊपर तक क्रमशः एकके बाद एक अनेक समूह होते हैं।" इसलिए फिगिस के कथनानुसार "सम्प्रभुताका परम्परागत सिद्धान्त एक आदरणीय अन्वयिस्वास्त मान है।" उनकी विचारधारा यह है कि समाजमें विभिन्न कार्य-क्षेत्र होते हैं और इनमें विभिन्न संघोंकी स्वतंत्र रूपसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेपके काम करना चाहिए।

इसी प्रकारके दावे एम० पॉल बोकूर (M. Pual Boncour) और डर्कहाइम (Durkheim) ने समाजके व्यावसायिक और आर्थिक संघोंकी ओरसे किये हैं। एफ० डब्लू० कोकर (F.W.Coker) के अनुसार पॉल बोकूर का दृष्टिकोण यह है कि राष्ट्रीय सम्प्रभुताके अतिरिक्त, जो कि राष्ट्रके सार्वजनिक हितके मामलोंको तय करती है, कुछ विशिष्ट सम्प्रभुताएँ भी होनी चाहिए जो उन मामलोंको तय करें जिनमें किसी संघका कोई विशिष्ट स्वार्थ, बहुमतके किमी दूरस्थ स्वार्थकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो। इसी प्रकार डर्कहाइम चाहते हैं कि प्राचीन व्यावसायिक संघोंको एक मान्य सामाजिक संस्थाके रूपमें फिरसे जीवित किया जाय। वह चाहते

है कि व्यावसायिक संघोंको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका आधार और आर्थिक नियमन का स्रोत बनाया जाय। इसका कारण वह यह बताते हैं कि आर्थिक जीवन इतना विशिष्ट (specialised) हो गया है कि राज्य उस तक नहीं पहुंच सकता।

हाल ही में एच० जे० लास्की (H. J. Laski) ने एक ऐसी व्यवस्थाका समर्थन किया है जिसमें ऐसे संघोंको स्वायत्त शासनके पूर्ण अधिकार प्राप्त हो और राज्यको एकमात्र अनिवार्य संघ और मनुष्यके सार्वजनिक हितोंका एकमात्र प्रतिनिधि न माना जाय। उनका सामान्य दृष्टिकोण यह है कि "असीमित और अनुत्तरदायी राज्यका सिद्धान्त मानवताके हितोंसे मेल नहीं खाता" और राज्यकी सम्प्रभुता भी उसी प्रकार समाप्त हो जायगी जिस प्रकार राजाओंके दैवी अधिकार समाप्त हो गये हैं। वह चरम सम्प्रभुताके सिद्धान्तको वैधिक डकोमला और अर्थहीन धारणा मानते हैं। लास्की राज्यको मजदूर संघके स्तर पर तो नहीं उतार लाने पर उनकी यह सम्मति अवश्य है कि सम्प्रभुता अनेक संघोंमें बंट जानी चाहिए। राज्यको विभिन्न संघोंमें समन्वय स्थापित करनेका अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। राज्यको सर्वोच्चकारी बननेका कोई हक नहीं है। शक्तियोंका समन्वय होना चाहिए। नीचेसे लेकर ऊपर तक एकके ऊपर दूसरी शक्तिका जाल नहीं बिठना चाहिए। अधिकार सत्ता संपादक होनी चाहिए।

जी० डी० एच० कोल (G. D. H. Cole) और अन्य श्रेणी समाजवादियोंका विश्वास है कि समाज का विभाजन उपभोक्ताओं और उत्पादकोंमें हो जाना चाहिए। वे इन दोनोंकी सह-सम्प्रभुता (co-sovereignty) का समर्थन करते हैं। उत्पादकों को राष्ट्रीय संघोंमें संगठित होना चाहिए और इन संघोंको न केवल प्रणामनीय बल्कि विधायी (legislative) अधिकार भी होने चाहिए। ऐसी हालतमें न्याय-पालिकाका कर्तव्य यह होगा कि वह राज्यकी विधिकी और संघोंकी उन विधियोंकी व्याख्या करे जिन्हें उपभोक्ताओं और उत्पादकोंकी समझें ब्रह्म बनायेगी। इन दोनोंके बीच होने वाले संघोंको एक समन्वय संस्था (coordinating agency) तय करेगी। इस संस्थामें सभी आवश्यक संघोंके प्रतिनिधि रहेंगे। इसका स्वरूप समझके दोनों सदनोंकी एक संयुक्त समितिके समान होगा। इस समन्वय संस्थाको दबाव बाधनेकी शक्ति और न्यायपालिका तथा विधि और पुलिसके सारे अधिकार प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति उस व्यक्तिके लिए तर्कमंगत नहीं जान पड़ती जो राज्यकी सम्प्रभुताकी विल्कुल ही अस्वीकार करता है। वार्ड (Ward) का यह कहना ठीक है कि "जिमि की भांति ये श्रेणी समाजवादी भी अधिकार सत्ताको अर्थात्कार नहीं करते। वे तो अधिकार सत्ताके ऐसे विभाजनको अस्वीकार करने हैं जिमके कारण उन संघोंकी अगुवि होनी है जिनमें उनकी रुचि होनी है (८०: १२३-२४)।"

मैकाइवर जैसे समवादीन विचारकोंके विचारोंमें बहुलवादकी स्पष्ट छाप है। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक 'मार्डन स्टेट' में इसी गुणवैचित्र्य बहुलवादी धारणाका समर्थन किया है कि राज्य समाजकी अन्य अनेक संस्थाओंमें से केवल एक मात्र है,

यद्यपि इसके वृत्त्य अद्वितीय ढंगके हैं। राज्यमें वे सभी अनिवार्य विशेषताएं होती हैं जो एक निगममें पायी जाती हैं। उसकी भीमाएं, उसके अधिकार और उसके उत्तरादायित्व सभी निश्चित होते हैं (५६:४७३)। निगमके रूपमें राज्यके भी अधिकार और कर्तव्य होते हैं। राज्यके ये अधिकार और कर्तव्य उसे एक इकाईके रूपमें ही प्राप्त हैं (५६:४७३)। समाजके अन्य सभ, समाजके लिए उतने ही स्वाभाविक होने हैं जितना कि स्वयं राज्य। इसलिए राज्यको अन्य सभोंका निर्माता नहीं माना जा सकता। निस्सन्देह राज्यका अस्तित्व व्यक्तियों और सभोंके सार्वजनिक सम्बन्धोंके लिए है पर सभी सार्वजनिक हित राज्यकी सीमाके भीतर नहीं आते (५६:४७३)। हजारों सांस्कृतिक और आर्थिक सभोंके आर्थिक हित भी सार्वजनिक हितके अंग हैं (५६:४७६)। 'सामाजिक सम्बन्धोंकी पूरी व्यवस्थामें एकता स्थापित करना ही राज्यका असली कार्य है।'

मैकाइवर आगे चलकर सम्प्रभुताकी वैधिक धारणाको झूठी और राज्यकी प्रकृति की ध्याख्या करनेमें असमर्थ बतलाते हैं। उनका कहना है कि इस धारणामें पहली त्रुटि यह है कि यह धारणा औपचारिक है। वैधिक तौर पर राज्य असीमित है क्योंकि यह स्वयं विधि निर्माणका स्रोत है। पर यही बात धार्मिक सभ (church) पर भी लागू होती है क्योंकि यह भी धार्मिक विधियोंका स्रोत है। सम्प्रभुताकी वैधिक धारणामें दूसरी त्रुटि यह है कि इसमें शक्ति और अधिकारकी तो दुहाई दी जाती है पर सेवा की नहीं। सेवा ही राज्यका उद्देश्य है; शक्ति तो सेवाका साधन है। राज्यकी सेवा असीमित नहीं है और इसलिए असीमित सम्प्रभुताकी धारणा "एक खतरनाक झूठ" है।

ए० डी० लिण्डसे (A. D. Lindsay) के अनुसार "निगमों पर राज्यका नियंत्रण सभी और उतना ही हो सकता है जब और जितना नियंत्रण रखनेका अधिकार राज्य के नागरिक राज्यको देनेको तैयार हों।" राज्यका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, क्योंकि निगमोंके सम्बन्धमें 'सभ बनना', 'सभ इच्छा' अथवा 'सभ व्यक्तित्व' की बात अर्थहीन है। राज्य तो 'समूहोंका समूह' है। अन्य सभोंकी सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। जो लोग इन सभोंके सदस्य बनना चाहते हैं वे सदस्य बनते हैं, जो नहीं बनना चाहते वे नहीं बनते। ये सभ सबकी अपना सदस्य बनाते भी नहीं। पर राज्यकी सदस्यता अनिवार्य और व्यापक होती है। कोई भी व्यक्ति राज्यका सदस्य होनेसे इन्कार नहीं कर सकता। पर लिण्डसे का कहना है कि अनिवार्य और व्यापक सदस्यता की यह विशेषता सम्प्रभु राज्यके सिद्धान्तके औचित्यको सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त नहीं है।

अर्नेस्ट बार्कर (Ernest Barker) सभोंके 'वास्तविक व्यक्तित्व' की धारणाको अस्वीकार करते हैं। पर वह विधि-वेत्ताओंके इस दावेको स्वीकार करते हैं कि राज्यमें पहले समाजमें स्थायी सभ भीजूद थे। इन सभोंमें से हर सभका अपना निगमित स्वयं और कार्यक्षेत्र था। बार्कर (Barker) का कहना है कि 'जीवनकी एक

सामान्य और व्यापक व्यवस्था होने के नाते राज्यके लिए यह जरूरी है कि वह अपने और मंधोंके सम्बन्धोंको, संघोंके पारस्परिक सम्बन्धोंको तथा मंधों और उनके सदस्योंके बीचके सम्बन्धोंको सन्तुलित रखे। अपनी व्यवस्थाको कायम रखनेके लिए राज्यके लिए यह जरूरी है कि वह अपने और मंधोंके बीचके सम्बन्धोंको सुरक्षित रखे। विधिके सम्मुख संघोंकी समानता कायम रखनेके लिए मंधोंके पारस्परिक सम्बन्धोंको सन्तुलित रखना जरूरी है। व्यक्तिनी मंधोंकी निरकुशताके ध्वस्तिके लिए संघों तथा उनके सदस्योंके सम्बन्धोंको सन्तुलित रखना जरूरी है।" राज्यकी व्याख्या मंधोंके मध्य अथवा समुदायोंके समुदाय के रूपमें की गयी है।

मूल्यांकन (Evaluation)

बहुलवादमें सत्यका बहुत बड़ा अंग है यद्यपि इसे बहुत बड़ा धड़ा कर कहा गया है। राज्यकी अत्यधिक प्रशंसाके विरुद्ध यह एक उचित प्रतिक्रिया है। राज्यकी वैधिक प्रधानता चाहे जितनी हो पर उस पर नैतिक प्रतिबन्ध होने ही चाहिए। गेटेल (Gettell) का कहना है कि सम्प्रभुता सम्बन्धी ऑस्टिन के सिद्धान्तकी कठोर और हठवादी विधिवादिका विरुद्ध बहुलवादी सिद्धान्त एक सामयिक प्रतिक्रिया है। "बहुलवादी अराजनीतिक मंधोंके बढ़ते हुए महत्त्वकी ओर, राज्य द्वारा इन मंधोंके उचित कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेपके खतरोंकी ओर तथा ऐसे मंधोंको राजनीतिक व्यवस्थामें अधिक भाग्यता देनेकी आवश्यकताकी ओर मनेन करते हैं। सरकारकी मध्यमक व्यवस्था और विधायिकाओंमें सघ प्रतिनिधित्वके जो सुझाव बहुलवादियोंने दिये हैं वे शासन-व्यवस्थाके लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं।"

कुमारी फॉलेट (Miss Follett) ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक 'द न्यू स्टेट' में बहुलवादकी निम्नलिखित अच्छादमा बनायी है: (१) बहुलवादियोंने राज्यके सम्प्रभुता-सम्पन्न सिद्धान्तको निराधार मिट्ट कर दिया है, (२) वे मंधोंके महत्त्वकी ओर हम तथ्यको स्वीकार करते हैं कि हमारे आजके मध्यजीवनकी विविधतामें एक ऐसी महत्ता है जिसे राजनीतिक तौर पर मान्यता प्रदानकी जानी चाहिए, (३) वे स्थानीय जीवनको फिले जीवित करनेकी माग करते हैं, (४) उनका कहना है कि राज्य और उसके अंगोंके हित हमेशा एकसा नहीं होते, (५) बहुलवाद जनताके समगठित मुण्ड रूपकी समाप्ति का ध्येय है और (६) बहुलवाद व्यक्तिके निजी व्यक्तित्वके स्वरूपको, उसके दलके सदस्यके स्वभावको और उसके राज्यके सदस्यके स्वभावको नहीं-नहीं बनानेका प्रयत्न कर रहा है (It has seized upon the problem of identity, of association, and of federalism.)।

इन गुणोंके होने हुए भी हम राजनीतिक बहुलवादको निम्नलिखित कारणोंसे स्वीकार नहीं कर सकते:—

(१) बहुलवादका सर्वमान्य परिणाम अराजकतावादी व्यक्तिवाद है यद्यपि

बहुलवादी इसे स्वीकार नहीं करते। सम्प्रभुताको विभाजित करनेका अर्थ उसे नष्ट करना है। सम्प्रभुताका विभाजन करनेके बाद भी अनेक बहुलवादी, राज्यको समन्वय और सन्तुलन स्थापित करनेका काम सौंपनेके इच्छुक हैं। हमारा कहना है कि इस कार्यको सन्तोषजनक ढंगसे करनेके लिए राज्यको वैधिक प्रधानता प्राप्त होनी चाहिए। सर्वोच्च नियंत्रण शक्तिके बिना राज्य अपने और दूसरे संघोंके सम्बन्धोंको, संधोंके पारस्परिक सम्बन्धोंको तथा संघों और उनके सदस्योंके सम्बन्धोंको सन्तुलित नहीं रख सकता। यदि राज्यको वास्तवमें संधोंका संघ तथा समुदायोंका समुदाय बनना है और समाजके विभिन्न संधोंके बीच समन्वय और सन्तुलन कायम रखनेका अपना कर्त्तव्य ठीक प्रकार निभाना है तो निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं: (क) राज्यको किसी ऐसी संस्था या संघका अस्तित्व सहन नहीं करना चाहिए जो सार्वजनिक हित या नीतिके विरुद्ध हो, (ख) राज्यको सभी संघों या संस्थाओंके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी भी संधको उसकी भारी सदस्यताके कारण या उसकी दबाव डालनेकी क्षमताके कारण विशेष रीतिपर नहीं देनी चाहिए, (ग) उसे किसी भी संस्था या संधको ऐसे कार्य नहीं करने देने चाहिए जिनका भार राज्यने या अन्य संघों ने अपने ऊपर ले रखा हो या जो उस संस्थाके घोषित ध्येयोंके विपरीत हो। उदाहरणके लिए किसी मजदूर संघको राजनीतिक कर लगानेकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। न किसी धार्मिक संस्थाको राजनीतिक कार्य करनेकी अनुमति दी जानी चाहिए। इस सबका निष्कर्ष यह है कि सरकारके विभिन्न अंगों पर विधि द्वारा बांटे जाये जो प्रतिबन्ध लगाये जाय पर राज्यको अन्तिम और चरम वैधिक अधिकार सत्ता प्राप्त होनी चाहिए।

(२) बहुलवादी यह मान लेते हैं कि समाजके भीतर विभिन्न संध या वर्ग परस्पर समानान्तर होते हैं और उनके कृत्य परस्पर नहीं टकराते। यदि उनका ऐसा मान लेना सही होता तो सम्प्रभु राज्यकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। पर सामाजिक जीवनमें कृत्योंका अतिक्रमण, स्वार्थों और निष्ठाओंमें सघर्ष रोजकी घटनाएं हैं। ऐसी परिस्थितियोंको ठीक करनेके लिए ही हमें राज्यकी आवश्यकता होती है। अंगी समाजवादी यह भूल जाते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नोंको एक दूसरेसे एकदम अलग नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सत्ता और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यसम 'सहसम्प्रभुता' (co-sovereignty) का समर्थन करते हुए भी अंगी समाजवादी राज्य तथा समस्त व्यावसायिक संधोंके प्रतिनिधियोंकी एक समुक्त संस्था स्थापित करते हैं। और ऐसा करनेसे उन्हें एकात्मक अधिपतियोंकी उस धारणाकी धारण लेनी ही पड़ती है जिससे वे इतनी घृणा करते हैं। बहुलवादी हमें इस बातका भी कोई मकेत नहीं देते कि वे किस आधार पर यह निर्णय करेंगे कि कौन संध आवश्यक है और कौन अनावश्यक है और किस आधार पर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जायगा।

(३) जिस एकात्मवादी धनु पर बहुलवादी हमला करते हैं वह अधिकतर काल्पनिक ही है। हम होमेल के निरकुसतावादकी वकालत नहीं करते पर आज दिन

बहुत ही कम एकात्मवादी हीगेल के अनुयायी हैं। हीगेल के अनुयायियोंको छोटकर सम्प्रभुताके परम्परागत समर्थकोंमें से कोई भी राज्यके सर्वसमर्थ होनेका दावा नहीं करता। वे लोग इस बातको स्वीकार करते हैं कि राज्यकी वास्तविक शक्ति मफ़ल अवज्ञाकी सम्भावनाओंसे और नैतिक तथा बौद्धिक प्रतिबन्धोंसे सीमित है। पर इस स्वीकृतिसे बहुलवादियोंको यह निष्कर्ष निकालनेका अधिकार नहीं मिल जाता कि राज्य सम्प्रभुता सम्पन्न नहीं है और व्यक्तिकी निष्ठा पर उसका उच्चतर अधिकार नहीं है। गेटेल (Gettell) का यह कहना ठीक है कि राज्य अपनी धरम वैधिक प्रभुताका बलिदान किये बिना भी नैतिक उत्तरदायित्वोंको स्वीकार कर सकता है, अपना कार्यक्षेत्र सीमित कर सकता है, स्थानीय विवेन्द्रोत्तरण और वर्ग-स्वार्थोंके प्रतिनिधित्व का अवसर दे सकता है। बोर्दा, हांस्म, क्लो आदि परम्परागत मिडलान्-वादियोंमें से कोई भी इस बातका दावा नहीं करता कि राज्यकी सत्ताकी आलोचना करना, या उसकी चुनौती देना, उसकी अवज्ञा या उसका विरोध करना अनैतिक, अधार्मिक, तर्कहीन अथवा असामाजिक या अस्वाभाविक ही है (एफ० डब्लू० कोकर)। वे केवल इतना ही कहते हैं कि राज्यका अस्तित्व विधियोंको बनाने और उन्हें लागू करनेके लिए है। राज्य अपनी ही तरहके किसी दूसरे अधिकारीके सम्मुख समर्पण करके सम्प्रभु नहीं रह सकता। वे राज्यको अनुत्तरदायी नहीं बनाते। वह केवल अपनी ही तरहके किसी दूसरे अधिकारीके सम्मुख उत्तरदायी नहीं है। "मधोपमें विधिनिर्माता होनेके नाते राज्य अपने क्षेत्रके अन्य सभी सामाजिक सघोंसे उच्च तथा श्रेष्ठ है।"

कोकर के अनुसार एकात्मवादी मिडलान्की मुख्य बातें ये हैं :

(क) एक ऐसा संगठन आवश्यक है जो व्यक्तियों और गणोंके पारम्परिक सम्बन्धोंमें एकता और समन्वय कायम कर सके।

(ख) इस संगठनको यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने विशिष्ट क्षेत्रके लोगोंको संगठनमें शामिल होनेके लिए विवश कर सके।

(ग) उसे अपने आदेशोंका पालन करानेका अधिकार होना चाहिए।

(घ) किसी एक क्षेत्रमें इस प्रकारका संगठन एतने अधिक नहीं हो सकता।

उन सभी धारणाएं इतनी विचारपूर्ण हैं कि इनका कोई गम्भीर विरोध नहीं हो सकता।

(४) राज्यकी एक विशेषता यह है कि उसकी सदस्यता अनिवार्य और व्यापक होती है अर्थात् राज्यका सदस्य होना हर व्यक्तिके लिए अनिवार्य है। डा० लिन्ड्से (Dr. Lindsay) इस विशेषताको स्वीकार करते हैं। पर उनका कहना है कि इनसे वे ही सम्प्रभु राज्यका औचित्य सिद्ध नहीं होता। यदि पिछले अनुच्छेदमें की गयी सम्प्रभुताकी व्याख्या यही है तो हम इस स्थिति का औचित्य नहीं समझ पाते। राज्य ही एक ऐसा मध्य है जो सबको समेट लेता है। वह सभी गणोंके ऊपर है। केवल उसे ही शक्ति का उपयोग करनेका अधिकार है। राज्य समाजके सदस्योंके

सर्वानुमोक्षी हितोंकी रक्षा करता है, जबकि अन्य सभ केवल आगिक हितोंकी ही रक्षा करते हैं। राज्य ही निष्ठाओंके सभों और व्यवस्थाके बीच व्यवस्था स्थापित कर सकता है। कुमारी फॉलिट (Miss Follett) का कहना है कि राज्य एकमात्र स्थापित करनेवाला एक साधन है। राज्य व्यक्ति पर केवल उन सभोंके माध्यम से ही काम नहीं करता जिनका वह सदस्य होता है बल्कि प्रत्यक्ष रूपसे भी नहीं बहा जा सकता क्योंकि किसी भी सभ या सभोंके समूहमें सम्पूर्ण व्यक्तिका समावेश नहीं होता। और आदर्श राज्य व्यक्तिकी पूर्णताकी मांग करता है.... व्यावसायिक सभकी सदस्यताकी अपेक्षा नागरिकता बड़ी बड़ी चीज है। राजनीतिमें हमें पूर्ण मनुष्यकी आवश्यकता होती है। आदर्श समाजित राज्य सबको हजम कर जाने वाला नहीं होता। वह सबको समेटने वाला होता है। मजबूत राज्यको अपने भीतर सभी हितोंका समावेश करना चाहिए। राज्यको हमारी अनेक निष्ठाओंकी लेकर उन्हें एक फर देना चाहिए। हमारी आत्माका निवास राज्यमें है।" राज्यकी अद्वितीय विनोयताओंकी यह प्रशंसा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका मुवाब बहुलवादकी ओर हो, सचमुच बहुत ही अत्यंतपूर्ण है।

(५) केवल कुमारी फॉलिट ही नहीं बल्कि अनेक बहुलवादी सम्प्रमुताहीन राज्यके बहुलवादी आदर्शोंको स्पष्ट तौर पर स्वीकार नहीं करते। इनका अर्थ यह है कि वे इस बातके इच्छुक तो हैं कि सभी आवश्यक सभोंको समानता दी जाय। पर परिस्थितियां उन्हें राज्यकी प्रधान स्थान देनेके लिए बाध्य करती हैं (E. W. Coker)। इस प्रकार हम देखते हैं कि गिअर्क (Gierke) और मैटलैण्ड (Maitland) सभोंकी वास्तविक व्यक्तित्व प्रदान करते हुए भी यह स्वीकार करते हैं कि राज्य अन्य मामा-जिक समस्याओंसे ऊपर है।

पॉल बॉकर (Paul-Boncour) राज्यकी सार्वजनिक हितोंका और राष्ट्रीय एकात्मताका एकमात्र प्रतिनिधि मानते हैं। यद्यपि वह अन्य सभोंको सम्प्रभु बताते हैं पर वह उन सभोंको राज्यके अधीन स्थान देते हैं। वह चाहते हैं कि राज्य सन्तुलन और समन्वय स्थापित करनेवाला साधन बने। वह इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि राज्यका कर्तव्य है कि वह किसी भी सम्प्रभु सभको जनता या अन्य सभोंके साथ अपना अपने सदस्योंके साथ किसी प्रकारका अत्याचार पूर्ण व्यवहार न करने दे। इसी प्रकार फिगिस (Figgis) राज्यको समुदायोंका समुदाय मानते हैं और उसे समन्वय और सन्तुलन स्थापित करनेवाले साधनके रूपमें एक निश्चित कर्तव्य और उच्चतर अधिकार-मत्ता प्रदान करते हैं।

जॉर्ज बार्कर (E. Barker) लिखते हैं, "व्यावसायिक सभ, राष्ट्रीय सभ, और सभोंके प्रगतिके सामने राज्यसे दब जानेकी कहा जाता है। पर ये सभ चाहे जितने अधिकारोंका दावा करें और चाहे जितने अधिकार इन्हें मिल जाय फिर भी व्यवस्था स्थापित करनेवाली शक्तिके रूपमें राज्यकी आवश्यकता बनी ही रहती।"

यह भी सम्भव है कि यदि इन संधीको नवीन अधिकार मिलते हैं तो राज्यको भी नये अधिकार मिलें। जितने अधिकार राज्यने छीने जायें उनमें वही अधिक अधिकार राज्यको मिल सकते हैं क्योंकि राज्यको व्यवस्थाकी जिन समस्याओंको हल करना होगा वे अधिक गम्भीर और पेचीदा होंगी (३ : १८३)।"

(६) बहुलवादी यह एकदम स्पष्ट नहीं कर पाते कि आखिर वे चाहते क्या हैं? यदि वे चाहते हैं कि राज्य अन्य संधीकी भांति केवल एक संध रहे तो क्या वे अनिवार्य राज्य कर और अनिवार्य नागरिकताको समाप्त कर देंगे। एक बात जो विन्कल स्पष्ट है वह यह है कि बहुलवादी राज्यकी सम्प्रभुता पर दमलिए बांट करते हैं कि समाजके अन्य स्थायी संधीको यथामन्भव अधिकतम अधिक स्थानीय स्वायत्तता प्राप्त हो जाय। कोई भी एकात्मवादी इस पर आपत्ति नहीं कर सकता। यह उचित ही है कि उद्योग और सरकारके नियंत्रणमें उन लोगोंको और अधिक भाग मिले जो इस समय हमने वचन हैं। "पर राजकीय सम्प्रभुताके मिद्वान्तको दोषपूर्ण होनेमें बचानेके लिए तथा राजकीय नीतियोंको लागू करनेकी व्यवस्थाको अधिक विवेचिष्ठ और नाना-विध बनानेके लिए राजकीय सम्प्रभुताके मिद्वान्तको छोड़ देना न तो आवश्यक जान पड़ता है और न हमने कुछ लाभ ही है (F. W. Coker)।" मन्त्री सम्प्रभुता और व्यावसायिक संधवादमें परस्पर कोई विरोध नहीं है। गटेल (Gattel) तो यह भी सम्भव मानते हैं कि जैसे ही राज्य और स्थायी संधीके बीचके झगड़े तय हो जायेंगे और राज्य सामाजिक जीवनकी नयी शक्तियोंको समझ वैधिक मान्यता देगा वैसे ही बहुलवाद समाप्त हो जायगा। सम्प्रभुताके अनिवारी परम्परा-गत विचारको ठीक करनेवाले और उसकी कमियोंको पूरा करनेवाले मिद्वान्तके रूपमें बहुलवाद एक महत्वपूर्ण मिद्वान्त है।

यह एक आश्चर्यकी बात है कि राज्यकी मतावा औरतार विरोध करने हुए भी अनेक बहुलवादी अन्य सामाजिक दबावोंका यदि समर्थन नहीं करते तो कमसे-कम उन्हें सहन तो कर ही लेते हैं। लास्की (Laski) जैसा स्वाधीनतावा पुजारी भी कहता है "कोई भी इन बात की अस्वीकार नहीं कर सकता कि वैधिक दृष्टिमें हर राज्यमें एक ऐसी मता होती है जिसकी अधिकार शक्ति अनिमीन होती है।"

(ख) राज्यकी सम्प्रभुता और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद (State Sovereignty and Internationalism)

मिलने कुछ समयमें अन्तर्राष्ट्रीय विधिबेता और विद्व शान्ति तथा व्यवस्थाके प्रेमी बाह्य सम्प्रभुता (external sovereignty) के मिद्वान्तकी आलोचना करने आ रहे हैं। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संधीवादी कहता है कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय विधिको अभी तक वास्तविक विधिरा पद प्राप्त नहीं हुआ है और उसमें किसी प्रकारकी दृष्ट व्यवस्था भी नहीं है पर उसके पीछे जनमनकी बहुत बड़ी शक्ति है। उनका यह भी

कहना है कि अब इस बातकी कोशिश हो रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधिको दण्ड व्यवस्थामें युक्त करके वास्तविक विधिका रूप दे दिया जाय। वे बाह्य सम्प्रभुताके आपेक्षित स्वरूप पर जोर देने हैं और अर्ध-सम्प्रभु राज्योंकी चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि राज्यको आन्तरिक मामलोंमें अवश्य सम्प्रभुता सम्पन्न होना चाहिए, पर बाहरी मामलोंमें राज्यको मनमानी करनेकी छूट नहीं होनी चाहिए। वे इस वर्तमान परिस्थितिको बनाये रखना बिल्कुल मूर्खता समझते हैं कि कोई भी राज्य जब चाहता है तब अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठनके अधिकारको माननेसे इन्कार कर बैठता है और अन्तर्राष्ट्रीय करारोंको भंग कर देता है।

यह एक रोचक बात है कि द्वितीय विश्व युद्धके बाद नूरेम्बर्ग के मुकदमोंमें यह स्वीकार नहीं किया गया कि राज्योंकी सम्प्रभुताको आक्रामक युद्ध छेड़नेका अधिकार है। उस समय कॉमनवील (Commonwealth) ने लिखा था, "हमने जर्मन सम्प्रभुताको भंग कर दिया... (लेकिन ऐसा करनेमें) विजयी राष्ट्रोंने अपनी पूर्ण सम्प्रभुताको भी भंग कर दिया है।" इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र भण्डे घोषणापत्र की दूसरी धाराके चौथे और सातवें अनुच्छेदोंमें और चौबीसवी धाराके पहले अनुच्छेदमें सम्प्रभुता पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

लास्की (Laski) जो अन्तर्राष्ट्रीय धान्ति और सद्भावनाके प्रबल समर्थक माने जा सकते हैं, बाह्य सम्प्रभुता पर की जानेवाली आधुनिक आपत्तियोंको बहुल-वादका सहायक मानते हैं। असीमित बाह्य सम्प्रभुताको बनाये रखनेका विरोध वह इन शब्दोंमें करते हैं - "अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें एक स्वतंत्र सम्प्रभु राज्यकी धारणा मानव कल्याणके लिए घातक है। एक राज्यको दूसरे राज्योंके साथ किस प्रकार रहना चाहिए, इसका निर्णय करनेका अधिकार एकमात्र उसी राज्यको नहीं दिया जा सकता।" राज्योंका पारस्परिक जीवन एक ऐसा विषय है जिस पर राज्योंमें समझौता होना चाहिए। उदाहरणके लिए ब्रिटेन को अकेले इस बातका निर्णय नहीं करना चाहिए कि वह किस प्रकारके शास्त्रात्मक बनायेगा और दूसरे देशोंसे किन लोगोंको वह अपने यहाँ आने देगा। "इन मसलोंका अमर सर्व सामान्य जनताके जीवन पर पड़ता है। और उनकी व्यवस्थाके लिए एक सुसंगठित विश्व सङ्गठनकी आवश्यकता है। यदि मनुष्योंको महान् मानव समाजमें रहना है तो उन्हें सहयोग मूलक व्यवहार सीखना होगा। एक विश्व राज्यमें, उसका निर्माण चाहे जिस प्रकार हो और उसमें चाहे जिस मात्रामें विकेन्द्रीकरण हो, पृथक सम्प्रभुताके लिए स्थान नहीं है (४७ : ५५-५६)।" लास्की का कहना है कि संसार और मानवताके प्रति हमारी निष्ठा सम्प्रभुता पर महत्त्वपूर्ण प्रतिबन्ध है।

मूल्यांकन और आलोचना (Appreciation and Criticism)

उक्त दृष्टिकोणमें हम बहुत कुछ सहमत हैं। हमें ऐसा लगता है कि बाह्य सम्प्रभुता उतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि आन्तरिक सम्प्रभुता। अब वह समय आ गया है

जब एक मजल, निष्पक्ष, और सर्वमान्य विद्व मंडल स्थापित किया जान और सामान्य हितोंके समझों पर उनके नियंत्रणकी सभी राज्य स्वीकार करें। राष्ट्र मंड और हेग ट्राएब्यूनल इसी दिनामें उठाये गये कदम थे। आज दिन मयुक्त राष्ट्र मंड विद्व मंडल और शान्तिका माधन बन सकता है। पर यह तभी सम्भव है जब संसारके राष्ट्र अपनी चरम सम्प्रभुताकी धारणामें आवश्यक सुधार कर ले।

यह पूछा जा सकता है कि यदि संसारके राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें अपनी सम्प्रभुता पूर्णरूपेण या आंशिक तौर पर त्याग दें तो परमपूर्ण, असीमित और अविभाज्य सम्प्रभुता के मिद्धान्तका क्या होगा? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि केवल बात बनाये रखनेके लिए एक पहलेसे बने हुए मिद्धान्तके साथ संसारकी परिस्थितियोंका बलान् मेल बैठानेकी अपेक्षा मानवताका कल्याण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

बाह्य सम्प्रभुताको त्यागनेकी नयी परिस्थितिके दो तर्कपूर्ण समाधान विभा- जित सम्प्रभुताके मिद्धान्तका सहारा लिये बिना भी दिये जा सकते हैं। यदि एक विद्वमण्डलको केन्द्र बनाकर एकीकृत वैश्व नियंत्रण स्थापित करनेमें हमें सफलता मिलती है तो उस हालतमें भी सम्प्रभुता उस विद्व राज्यमें निहित रहेगी। यह विद्व राज्य एकात्मक या संघात्मक दो में से किसी भी प्रकारका हो सकता है। यह तो विद्व राज्य और उसके अंग राष्ट्रीय राज्योंके सम्बन्धों पर निर्भर करता है। दूसरा समाधान बोदो (Bodin) तथा कुछ अन्य एकात्मवादियोंने दिया है। उनका कहना है कि हर राज्यका दूसरे राज्योंके प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होता है और इस उत्तरदायित्वमें उस राज्यकी सम्प्रभुता सीमित रहती है। यह सही है कि यह नैतिक उत्तरदायित्व या कर्त्तव्य स्वयं अपने ऊपर लागू किया जाता है और उनके पीछे कोई वैश्व बल नहीं होता। फिर भी संसारके जनमनको इनके पक्षमें इतना अधिक समार दिया जा सकता है कि कोई भी राज्य इसका उत्पन्धन करनेका साहस न कर सके। आन्तरिक सम्प्रभुताके क्षेत्रमें भी राज्यों पर प्रतिबन्ध होने हैं। इन सब बातोंके बावजूद यदि मानवताके हितमें विभाजित सम्प्रभुताकी आवश्यकता होती है तो हमें इसे महर्ण स्वीकार करना चाहिए।

(ग) राज्यकी सम्प्रभुता और विधि

(State Sovereignty and Law)

डुग्गी (Duguit) ने फ़्रांस में और क्राब (Krabba) ने होर्लेन्ड में बहुलवाद पर एक विस्तृत भिन्न दृष्टिकोणमें विचार किया। यह दृष्टिकोण विधिवा दृष्टिकोण है। डुग्गी के अनुसार विधि 'राजनैतिक सभ्यतामें स्वयं, उसमें ध्येय और पूर्वकालिक होती है'। यह प्रेरणाश्रोत न बनकर, तथ्यों और दोन आवश्यकताओंके आधार पर बनती है' (कोरर)। विधिके बिना सामाजिक एकाता और सभ्यता या मनुष्योंका एक दूसरे पर निर्भर करना सम्भव नहीं है। विधिवा सामाजिक जीवनका ही परिणाम

है। उनका मानना इसलिए आवश्यक है कि वे ऐसे नियमोंको प्रवट करती हैं जो स्वयं अपने आपमें ही आवश्यक हैं न कि इसलिए कि उन्हें किसी निश्चित उच्चतर मनुष्यने बनाया है या बनानेकी अनुमति दी है। उनका पालन इसलिए किया जाता है कि वे सामाजिक नियमोंके प्रकट रूप हैं। राज्यका काम इन विधियोंको बल देना है। राज्यका व्यक्तित्व एक कोरी कल्पना है क्योंकि राज्यका उन व्यक्तियोंसे भिन्न कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है जिनसे राज्य घनता है और जो सामाजिक अन्वयोन्याय्य सम्बन्धमे एक दूसरेमे बंधे हुए हैं। विधि राज्यको सीमित करती है, राज्य विधिको सीमित नहीं करता। अतः राज्यके कर्तव्यों पर जोर दिया जाना चाहिए, न कि उसके अधिकारों पर। राज्यकी तात्त्विक विरोधता सम्प्रभुता न होकर जनता की सेवा है। जैसा गेटेल (Gettel) ने कहा है: दुग्बी का मुख्य उद्देश्य राज्यके भीतरके विभिन्न सामाजिक सघोंका राजनीतिक महत्त्व कायम करना नहीं है; उनका मुख्य उद्देश्य सामकोंके कार्यों पर ग्याय मूलक प्रतिबन्ध लगाना और राज्यके उत्तरदायित्वका मिदाम्त विकसित करना है।

सामाजिक एकता और दृढ़ता दुग्बी के राजनीतिक विचारोंकी कुंजी है। वह राज्यके पहले की प्राकृतिक विधिसे मिलती-जुलती है। वह विधिका धार्मिक स्रोत है। सामाजिक एकता और सगठनमे उत्पन्न आचार शास्त्रका निषोड दुग्बी यह देते हैं—ऐसे काम मत करो जो दूसरोंके जिम्मे हों और जिनसे अम विभाजन द्वारा उत्पन्न सामाजिक दृढ़ता में कमी आवे। सामाजिक दृढ़ताकी वृद्धिके लिए जो अभीष्ट हो वह व्यक्तिको करना चाहिए (१६: २९६)। “दुग्बी के लिए सामाजिक दृढ़ता आभ्यात्मिक विषय है, वह नैतिक आदर्शोंका स्रोत और विधिका सर्वसंगत आधार है। वह सामाजिक संभोंके तात्त्विक महत्त्वको प्रकट करती है (५०: १२९)।”

उक्त कारणोंमे दुग्बी सम्प्रभुताकी धारणाको अनावश्यक मानते हैं। पर वह यह नहीं बतलाते कि इस बातका निर्णय कौन करेगा कि विधिका कोई नियम जनता के हितमें है या नहीं, और उसे किम प्रकार एक स्थापित विधिका रूप दिया जाय। दुग्बी के सिद्धान्तका प्रभाव न्यायालयोंके अधिकारोंको बढ़ाना, विधिका सामाजीकरण और राज्यको उपयुक्त सेवाओंके लिए न्यायालयोंके प्रति उत्तरदायी बनाना मालूम होता है।

क्राव (Kraab) के विचार दुग्बी के विचारोंसे मिलते-जुलते हैं। नाव केवल एक विधिकी ही सम्प्रभुता स्वीकार करते हैं। विधि राज्यसे स्वतंत्र और उससे श्रेष्ठ है। उसकी उत्पत्ति सामाजिक एकता और दृढ़तासे नहीं हुई है जैसा कि दुग्बी मानते हैं। विधिकी उत्पत्ति राज्यका निर्माण करनेवाले व्यक्तियोंके बहुमतके विवेकसे हुई है। इस प्रकार उसकी उत्पत्ति अनुभूति मूलक (subjective) है। राज्यकी तात्त्विक विरोधता शक्ति नहीं है। राज्यकी मुख्य विशेषता यह है कि यह एक वैधिक समाज है। “एक वैधिक समाजके अतिरिक्त राज्य और कुछ भी नहीं है—वह मानव समाजका एक ऐसा अंग है जिसकी वैधिक सम्बन्धोंकी अपनी स्वतंत्र व्यवस्था

हैं। इसलिए राज्य कुछ हितोंको वैधिक महत्त्व देनेके अतिरिक्त और कोई काम नहीं करता।" नाब के ही शब्दों में, "विधिक अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार सत्ता मान्य नहीं है। विधिका सच्चा स्वरूप मनुष्यका 'आत्मिक' स्वभाव अर्थात् उसका विवेक है।" दुखी के विपरीत नाब विधिकी इस धारणाको अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंके क्षेत्रमें भी ले जाते हैं। उनका विश्वास है कि किसी भी राष्ट्रको स्वतंत्र वैधिक जीवन बिताने का अधिकार नहीं है। "यदि स्वतंत्र वैधिक जीवनसे अन्तर्राष्ट्रीय समाजके हितोंकी वृद्धि नहीं होगी तो किसी भी राष्ट्रका यह दावा माना नहीं जा सकता कि वह अपने सामाजिक जीवनका नियंत्रण स्वयं ही करे (८-१५९)।" नाब का कहना है कि न्यायका विचार अन्तर्राष्ट्रीय मामलोंमें भी होना चाहिए। और जिस हद तक हम दिशामें प्रगति होंगे उस हद तक आधुनिक राज्योंके वैधिक कार्य कम होंगे जाने चाहिए। नाब का विश्वास है कि आगे चलकर वर्तमान राज्य एक राष्ट्रोत्तर राज्य (Supernational State) के प्रवेश बन जायेंगे। पर इस राष्ट्रोत्तर स्थितिके पूर्व "अन्तर्राष्ट्रीय समाजको सम्प्रभुताकी भावनाको पारकर आगे बढ़ना होगा (४४-२१७)।" अन्तर्राष्ट्रीय समाजके एक स्वतंत्र वैधिक समाजके रूपमें विवर्धित होनेके पहले एक स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय अधिपति की आवश्यकता है (८०-१६१)।

नाब के सिद्धान्तका निचोड़ राज्यको वैधिक समुदायके रूपमें समुचित कर देना और न्यायाधीशको समाजमें दायित्व केन्द्र बनाना है। उनकी राजनीतिक रधि अन्तर्राष्ट्रीयतावाद में है।

इन लेखकोंके विचारसे विधि केवल विधायिका तथा राज्यके अन्य अंगों पर ही नहीं बल्कि स्वयं राज्य पर भी प्रतिबन्ध लगाती है। फ्रांसीसी लेखक लु फूर (Le Fur) ने इन विचारोंको इस प्रकार प्रकट किया है—“अन्य सभी ध्येयोंकी भांति राज्य भी केवल अपनी इच्छा द्वारा ही नियमित होनेके बजाय कुछ अंगोंमें एक ऐसी बाह्य शक्ति द्वारा भी नियमित होता है जो राज्यमें ध्येय और पूर्वधारित है। यह उच्चतर शक्ति प्राकृतिक या बौद्धिक विधि (Natural Law or Rational Law) (२३:१९९) है।”

मूल्यांकन और आलोचना (Appreciation and Criticism)

हम इस दृष्टिकोणकी मन्त्री-भाति स्वीकार नहीं कर सकते। यदि हम सिद्धान्तका कुल अर्थ इनका है कि किसी राज्यकी विधि उनकी विधायिकाकी ऐसी आज्ञा अथवा किसी उच्चतर व्यक्तिके ऐसे आदेश मात्र नहीं हैं जिन पर लोगोंकी आकांक्षाओं और रायोंका असर नहीं पड़ना, बल्कि उन पर उनका विवेक, प्रचलित सामाजिक न्यायकी भावना तथा इसी प्रकारके अन्य तत्त्वोंका प्रभाव पड़ना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी राज्यमें कोई भी मरदण विधिको 'बनाना' नहीं। जिन

प्रकार विधिया बनायी जाती हैं और जिस प्रकार वे लागू की जाती हैं दोनों ही में एक ऐसी दृष्टा प्रतिबिम्बित होती है जो रम्पी तौर पर बनायी गयी विधायिकाओंकी दृष्टा से भिन्न होती है। यदि विधिको स्वयं अपने ही प्रति सच्चा होगा है तो उसमें विवेकवा तत्पर होना ही चाहिए। एकात्मवादीको यह सब स्वीकार करनेमें कोई हिचक नहीं है। फिर भी वह बहुलवादियों द्वारा की गयी विधिकी परिभाषाका स्वीकार नहीं कर सकता।

इसके अतिरिक्त जैसा कि कोकर (Coker) कहते हैं: विधि निर्धारित (prescribed) की जाती है। विधि केवल वह नहीं है जो हमारी सामान्य बुद्धिकी ठीक जान पड़ता है या जो समाज चाहता है। यह सही है कि एक निश्चित व्यक्ति अथवा विधायिकाके अतिरिक्त हम विधिकी भावना, एक सामान्य दृष्टा, आदिकी बात कर सकते हैं; पर हम साधारणतया स्वीकृत अर्थोंमें विधिकी बात नहीं कर सकते। सामाजिक एकता, दृढ़ता और विवेक हमें ऐसी निश्चित विधिया देनामें असमर्थ हैं जिनकी व्याख्या की जा सके और जिन्हें न्यायाधीश लागू कर सके।

एक बात और है। जिस मिद्धान्तका हम विवेचन कर रहे हैं उससे प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों के वे प्रदन फिर से उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे राजनीति-शास्त्र आधुनिक समयमें मुक्त रहा है। प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों तक वापस लौटनेसे राजनीति शास्त्र एक ऐसे गडमें गिर जायगा जिससे बाहर निकलना आसान न होगा।

यह सिद्ध करनेके लिए प्रमाण है कि जब ये विधि शास्त्री राज्यकी सम्प्रभुताको विधिके द्वारा सीमित करनेका यत्न करते हैं तब उनके दिमागमें सरकारके विभिन्न अंग रहते हैं; स्वयं राज्य नहीं।

निष्कर्ष (Conclusion)

(क) जैसाकि पहले कहा जा चुका है, बहुलवाद सम्प्रभुताके उग्र अतिवादी रूप के विरुद्ध एक वांछित प्रतिक्रिया है जो हीगेल आदि ने सम्प्रभुताको प्रदान की थी। राज्यको नैतिक सम्प्रभुता देना, जैसाकि हीगेल ने किया है, बहुत ही खतरनाक है। निरुसन्देह वैधिक तौर पर राज्य सर्वोपरि है। पर उसे यह अधिकार नहीं है कि वह अपने-बो अपने नागरिकों या अन्य राज्योंके प्रति नैतिक दायित्वोंसे मुक्त करे। हीगेल का यह विचार गलत है कि राज्यको आज्ञाएँ सही ही होती हैं। पर हीगेल द्वारा प्रतिपादित राज्यकी निरकुशताको अस्वीकार करनेका अर्थ यह नहीं है कि हम बहुलवादी बन जाते हैं।

(ख) बहुलवादने राज्योंका ध्यान मध्य जीवनकी ओर आकर्षित करके आधुनिक राजनीतिशास्त्र की बहुत बड़ी सेवा की है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक और धार्मिक सर्वाका सामाजिक जीवनमें बहुत हो महत्वपूर्ण

और अद्वितीय स्थान रहता है। इसलिए यह मानना कि इन सघोंका अस्तित्व राज्यकी कृपा पर निर्भर करना है, धुष्टता है। यह उचित है कि समाजके स्थायी सघोंको स्वयं अपनी व्यवस्था करनेके लिए यथामम्मव अधिकसे अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए। राज्यकी सामान्य नीति और विधियोंके निर्माणमें भी उनका प्रभावपूर्ण भाग होना चाहिए। पर इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यको घटाकर उसे दूसरे सघों के बराबर बना दिया जाय। राज्यको स्वयं अपने आपमें एक विशिष्ट वर्ग बना रहना चाहिए। इसे सर्वोच्च ही रहना चाहिए।

(ग) समाजके आवश्यक सघोंको पूर्ण आन्तरिक स्वायत्त अधिकार देनेके बाद भी, हमें एक उच्चतर सगठनकी आवश्यकता है जो इन सघोंमें सन्तुलन और समन्वय स्थापित कर सके। यदि राज्य सघोंमें से केवल एक सघ हो और उसके अधिकार और उसकी प्रतिष्ठा अन्य सघोंके समान ही हो तो यह समझमें नहीं आता कि राज्य सन्तुलन और समन्वय स्थापित करनेका अपना काम सन्तोषजनक ढंगमें कैसे कर सकेगा। राज्यकी सदस्यता अनिवार्य और उसकी अधिकार मत्ता व्यापक होनी है। इन अद्वितीय विशेषताओंके बिना राज्य समाजमें स्थायपूर्ण और बन्ध्यापकारी परिस्थितियाँ कायम नहीं रख सकता। कोकर का यह कहना सही है कि समाज के गैर राजनीतिक सघ राज्यकी सहायताके बिना न तो पनप सकते हैं और न अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियाँ भी राज्यके कार्योंकी अनुमति नष्ट नहीं करती। यही नहीं ये परिस्थितियाँ हमें बताती हैं कि प्रत्येक समाजमें एक अन्तिम अधिकार-मत्ताकी आवश्यकता होती है।

(घ) मानव कल्याणके लिए बहुतने कार्योंकी जरूरत होती है। समाजमें अनगिनत संघ होते हैं। फिर भी ये सघ उन सब कामोंको पूरा नहीं कर पाते जिनके कार्योंकी मानव कल्याणके लिए जरूरत होती है। वे केवल आंगिक हिस्सा ही पूरा करते हैं। राज्य ही एक ऐसा सगठन है जो समाजके सदस्योंकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करनेमें समर्थ है। इसीलिए हर सभ्य राज्य सामान्य हिंसोंकी रक्षाओं अपना विशेष कर्तव्य समझता है।

(ङ) यदि हम सम्प्रभुताके एकात्मवादी मिडान्तको अस्वीकार कर देने हैं तो हमारे लिए सर्व-संगत स्थिति केवल अराजकतावादियों और श्रमिक सघवादियोंकी ही रह जाती है। बहुलवाद तो एक ऐसा मध्य मार्ग अपनानेका प्रयत्न करता है जो असम्भव है। बहुलवादी मिडान्त अल्लोपगन्था अराजकतावादी मिडान्त ही है।

(च) यदि 'सम्प्रभुता' शब्दका दुरुपयोग होता है और उसे उस प्रकारकी निरंकुशतासे सुझ नहीं दिया जा सकता, जो हीगेल ने उसे दी है तो प्रधानता (supermacy), अथवा अन्तिम अधिकार मत्ता (final authority) नन्द हमारे दृष्टिकोण को व्यक्त करनेके लिए अपनाये जा सकते हैं। इन पृष्ठोंमें व्यक्तकी गयी विचारधारा सम्प्रभुताके परम्परागत समर्थकोंसे मिडान्तोंकी अपेक्षा बोदा (Bodin) के मिडान्त से अधिक मिलती-जुलती है।

(छ) हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उसे सेबाइन (Sabine) के शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है : "में यथामग्नव एकात्मवादी (monist) बननेका अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, और कोई चारा न रह जाने पर बहुलवादी बनने को तैयार हूँ।"

राजनीतिक बहुलवाद और भारत (Political Pluralism and India)

बहुलवादके अर्थसत्यको मान लेनेसे अधिक खतरनाक भारत की एकता के लिए और कुछ नहीं हो सकता। भारत में हमेशासे एक बातकी कमी रही है। वह कमी है एकता की कमी। भारत सदासे एकता कायम करनेमें असमर्थ रहा है। और यदि कभी एकात्मता कायम भी हुई है तो वह बहुत समय तक टिकी नहीं। हमेशासे भारत की कमजोरी और उसकी क्षति दोनोंके कारण-द्वेषमें विभक्त समुदाय और विभक्त निष्ठाएं रही हैं। यदि भारत को एक राष्ट्र या एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाईके रूपमें जीवित रहना है तो भारतीयोंको सीखना होगा कि वे सबसे पहले भारतीय हैं और इसके बाद और कुछ। यह तभी हो सकता है जब जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, राज्य, अथवा भाषा सम्बन्धी निष्ठाएं कमजोर हो जायें। और इनमें से कुछ निष्ठाएं तो समय बीतने पर विलुप्त लुप्त हो जायें।

यदि हम अपनी जातीय समानता और साम्प्रदायिक संगठनोंको बहुलवादीकी शिक्षाओंसे लाभ उठाने देंगे, तो हमारे गणतंत्रका न सही पर हमारे धर्मनिरपेक्ष आदर्शका अवश्य ही अन्त हो जायगा। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब राजनीतिक पार्टियोंने पहले अपनेको सैनिक प्रशिक्षण और सैनिक माज-नमानसे युक्त किया और फिर अन्तमें राज्य-सत्ता पर कब्जा कर मनमाने अत्याचार किये। इनका सबसे अच्छा उदाहरण जर्मनी की नाज़ी पार्टी है।

पहले कभी भले ही इस बातकी आवश्यकता रही हो कि सम्प्रभुताको बहुलवाद की दिशामें मोड़ा जाय पर आज दिन तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बातकी है कि सम्प्रभुताको एकात्मवादी जामा पहनाया जाय। कमसे कम जहां तक संघोंका सम्बन्ध है ऐसा अवश्य ही होना चाहिए।

SELECT READINGS

- AUSTIN, J.—*Lectures in Jurisprudence*—Vol. I, Lecture VI.
BARKER, E.—*Political Thought in England from Spencer to Today*—pp. 175-183.
BOSANQUET, B.—*The Philosophical Theory of the State*—Preface and Introduction to the Second Edition.

- BRYCE, J.—*Studies in History and Jurisprudence*—Essay X.
- COKER, F. W.—*Chapter on Pluralistic Theories and the Attack upon State Sovereignty in Political Theory in Recent Times by Merriam, Barnes and others.*
- DICEY, A. V.—*Law of the Constitution*—Lecture II.
- DICEY, A. V.—*Law and Public Opinion*—Lecture I.
- FOLLETT, M.P.—*The New State.*
- GARNER, J. W.—*Political Science and Government*—Chapters VIII and IX.
- GETTELL, R. G.—*Introduction to Political Science*—Ch. VIII.
- GILCHRIST, R. N.—*Principles of Political Science*—Ch. V.
- GREEN, T. H.—*Principles of Political Obligation*—Section E.
- HSIAO—*Political Pluralism.*
- KRABBE—*The Modern Idea of the State* (Translated by Sabine and Shepard).
- LASKI, H. J.—*A Grammar of Politics*—Ch. II.
- LEACOCK, S.—*Elements of Political Science*—Ch. IV.
- LORD, A. R.—*Principles of Political Science*—Chs. III, IV and V.
- MACIVER, R. M.—*The Modern State*—Chapters VI, VII, XV, Sections II and XVI.
- MERRIAM, C.E.—*History of the Theory of Sovereignty Since Rousseau.*
- POLLOCK, F.—*History of the Science of Politics.*
- ROUCEK, J. S. AND OTHERS—*Introduction to Political Science*—Ch. III.
- ROUSSEAU, J. J.—*Social Contract*—Books I and II.
- SIDGWICK, H.—*Elements of Politics*—Ch. XXXI.
- WARD, P.W.—*Sovereignty—A Study of Contemporary Political Nation.*
- WILDE, N.—*The Ethical Basis of the State*—Chs. IV and VIII.
- WILLOUGHBY, W. W.—*The Nature of State*—Chs. IX and XI.

जो मेरे प्रति सच्चे हैं मे उनके लिए सच्चा हूँ जो मेरे प्रति सच्चे नहीं हैं मे उनके लिए भी सच्चा हूँ और इस प्रकार सभी सच्चे होते जायेंगे।" महात्मा गांधी ने कन्स्यूमिज्म से वह सिद्धान्त सीखा जिसके अनुसार मनुष्योंको दूसरेके प्रति वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार वे स्वयं दूसरेके द्वारा अपने प्रति न चाहते हों। यह ईसा मसीह के इस स्वर्ण नियमका नकारात्मक रूप है कि दूसरोंके प्रति वैसा बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। इसीलिये भी जितने बहूना हिंसा और जोर दबावसे सम्बद्ध किया जाता है, गांधी जी ने अहिंसाकी शिक्षा दी। गांधीजी जानते थे कि "इस्लाम" शब्दके मतलब ही है शीलतावा सन्देश पाया। गांधीजी जानते थे कि "महत्त्वपूर्ण शिक्षा है 'धर्म' और अहिंसा"।

यह निरपेक्ष लेखकोंमें से थोरो (Thoreau), रस्किन (Ruskin) और टॉल्स्टॉय (Tolstoy) ने गांधीजी को सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधीजी ने थोरो से सविनय अवज्ञा (Civil disobedience) और करवन्दो (non-payment of taxes) की प्रेरणा प्राप्त की। थोरो के राजनीतिक विचार यह थे, "अनहित करनेवाले सभी व्यक्तिगत् और सम्पत्तिके माध्यम अधिकतम सहयोग, और यदि वे अनहित करे तो अमहयोग।" गांधीजी ने रस्किन की पुस्तक 'अल्ड विल्ड ओलिव्स' (Unto this Last) और 'क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिव्स' (Crown of Wild Olives) से धार्मिक परिश्रम का आदर करना सीखा और इन अपने जीवनके अन्त तक अपने व्यवहार में लाते रहे। थोरोटांल्टॉय ने गांधीजी को "ईसाई अराजकता" (Christian anarchism) की शलक मिली।

महात्मा गांधी के मन्त्रि और उनका जीवन चरित्र लिखनेवाले प्यारे लाल इन विभिन्न सूत्रोंके बारेमें लिखते हुए कहते हैं "मनवद्गीता, उपनिषद् और ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं ने गांधीजी और थोरो को समान रूपसे प्रभावित किया है।" यह आगे कहते हैं "जीवनके बारेमें गांधीजी के सम्पूर्ण दृष्टिकोणको टॉल्स्टॉय ने बदल दिया। कला, धर्म, अर्थशास्त्र, पुरुष और महिलाओंके पारस्परिक सम्बन्ध तथा राजनीतिक अमहयोगके पूरे कार्यक्रमका आधार टॉल्स्टॉय की गहरी छाप पड़ी थी।" गांधी जी के अधिकतम अमहयोगके पूरे कार्यक्रमका आधार टॉल्स्टॉय का यह प्रतिष्ठ वाक्य है—
"ईश्वरका राज्य तुम्हारे भीतर है।"^१
यद्यपि महात्मा गांधी ने इन पुस्तकों पर दार्शनिक दृष्टिकोणसे विचार किया था फिर भी वह एक पद्धति निर्माता (system builder) नहीं थे। इस सम्बन्धमें थोरो और गांधीजी की तुलना करते हुए प्यारे लाल कहते हैं कि इन विचारकोंमें

१ The Statesman, February 1, 1957.
२ Ibid.
३ Ibid.

से कोई भी पद्धति निर्माता नहीं था, पर दोनों गम्भीर विचारक, सत्यको खोज करने वाले और सत्य बना धर्म। दोनोंमें सत्यके लिए प्रबल इच्छा थी, और दोनों कार्यरूपमें दर्शन-शास्त्रका प्रतिनिधित्व करते थे।

गांधीजी की विचारधारामें पद्धतिकी कमी के सम्यन्धमें लिखते हुए हमायू कबोर ठीक ही कहते हैं कि गांधीजी वास्तविकताके एक निष्पक्ष छात्र (objective student) थे और उनका दृग मूलन प्रयोगात्मक (experimental) और वैज्ञानिक निर था। गांधीजी के जीवनकी विनोपता, आत्मप्रेरणा और कार्यसम्पादन धी न कि तर्क और पद्धति थी। जयाहूरलाल नेहरू, जो बहुत वर्षों तक गांधीजी को अन्य अनेक लोगोंकी अपेक्षा अधिक नब्बदीकमें जानने में, कहते हैं "हम लोगोंमें और गांधीजी में शायद ही कभी किसी प्रश्न पर वादविवाद, बहस-मुवाहमा या दार्शनशास्त्रीय स्तर पर विचार विमर्श होता था। हम लोग मिलकर काम करते थे।"

राजनीतिज्ञ नहीं। यदि गांधीजी एक पद्धतिपूर्ण राजनीतिक विचारक नहीं थे तो वह राजनीतिज्ञ तो और भी कम थे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है जनताकी कल्याणकी चिन्ताने ही उन्हें राजनीति में डूबेला दिया। उनके जीवनमें ऐसे भी अवसर आये जब उनका राजनीतिक आन्दोलन जोरोंमें चल रहा था और तब उन्होंने छुजाछून मिटाने, मध्य-निषेध, धामीण उद्योगको जनप्रिय बनाने और हिन्दू मुस्लिम एकाता स्थापित करने तथा इसी प्रकारके अन्य काम करनेके लिए अपना राजनीतिक आन्दोलन बन्द कर दिया। इन्हीं सब बागीके कारण आचार्य इरलाजी गांधीजी की मूलन एक समाज सुधारक मानने हैं। पर हमारी राय में इरलाजी की यह विचार मनुचिन्त और एकपक्षीय है और महात्मा गांधी के बहुपक्षीय स्वरूपके प्रति पूर्ण न्याय नहीं करता है।

यद्यपि गांधीजी साधारण अर्थमें राजनीतिज्ञ नहीं थे पर उन्होंने अपने अतिमक आन्दोलनोंमें आरम्भ करनेका समय निश्चित करनेमें और उसकी स्वरूपा निर्धारित करनेमें असाधारण बुद्धिमानीका परिचय दिया था। इस दृष्टिकोणमें हम गांधीजी की हत्याके समय प्रवृत्त किमें गये 'मैकेन्टरगात्रिपन' (ब्रिटन का प्रतिष्ठित दैनिक पत्र) के इस नाने अंगल महमल हो सकते हैं कि गांधीजी राजनीतिज्ञोंमें महात्मा और महात्माजीमें राजनीतिज्ञ थे। ब्रिटिश सामनके विरुद्ध प्रत्येक आन्दोलनमें उन्होंने नया प्रतीक और नये तरीके अपनाये। १९१९-२० में यह अहिंसा अग्रद्वाराय पात्रिनमें छात्रों, वर्गीयों और सरकारी नीतियों अपना-अपना काम छोड़नेकी कड़ा गया था; १९३० में सरकारके विरोधका प्रतीक नमक बना। १९३९ में यह कुछ बुने हुए स्थितियों द्वारा स्थानगत मविनय अवज्ञा आन्दोलन था; १९४० में आन्दोलन का रूप जनताके एक स्थान पर एक होने पर लगी रोककी तोड़ना था। १९४२ में 'भारत छोड़ो' का आन्दोलन चला जिनका नारा था "करो या मरो"। इन सभी आन्दोलनोंमें अर्रेजी कम्युनोका अहिंसा और मरुद के उपयोग और करने की निगानीका विशेष महत्व रहा है।

अपने आन्दोलनोंकी रूपरेखा निर्धारित करनेमें गांधीजी ने अपनेको एक अत्यन्त निपुण व्यक्ति (tactician) और अनुभवी मनोवैज्ञानिक प्रमाणित किया है। वह जानते थे कि जनतासे कैसे अपीलकी जाय और वह जनताको पीछे छोड़कर अकेले खड़ा हुआ जाय। वह जानते थे कि किसी एक कार्यको अनगिनत बार दोहराकर जनता के धर्मनिरपेक्षको प्रभावित किया जा सकता है। वह अपने आन्दोलनका आधार किसी ऐसी वस्तु को बनाने थे जिसके छिपे अर्थको जनता आसानीसे समझ सकती थी। वह जनताको उस समय तक एक-एक कदम करके आगे ले जाते थे जब तक कि जनता में नैतिक और आध्यात्मिक बल पूरी तरह नहीं आ जाता था। वह पहले सामान्य जनतामें अपील करते थे और फिर पढ़े-लिखे मेधावी उनका अनुसरण करते थे। अपने एक समकालीनके शब्दोंमें 'गांधीजी अपने आदर्शों पर अमल करनेके पूर्व इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करते थे कि सारे संसारको अपने मनका बना लिया जाय। वह अपनेमें ही आरम्भ करते थे और आशा करते थे कि समय आने पर अन्य लोगोंको भी अपने साथ ले चलेंगे।'

राजनीतिका आध्यात्मिकरण (Spiritualisation of Politics). राजनीतिका आध्यात्मिकरण राजनीति और राजनीति शास्त्रको महात्मा गांधी की स्थापी देन है। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि राजनीति को मानवममताके लिए आप न होकर आशीर्वाद होना है तो उसे उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए। किसी तरह भी काम निबालने में कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनका कहना था कि साधन भी उनका ही महत्व रखते हैं जितना लक्ष्य। उनका विश्वास था कि केवल अच्छे साधन से ही अच्छे लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं। दूसरे शब्दोंमें साधन और लक्ष्य या माध्य एक ही वस्तु है जो विविध दृष्टिकोणोंसे देखी जाती है। यदि साधनों पर समुचित ध्यान दिया जाय तो लक्ष्य अपने आप सिद्ध हो जायगा। गांधीजी के विचार और व्यवहारके मौलिक आधारोंमें से एक आधार साधनोंकी पूर्ण स्वच्छता थी। इसी सम्बन्धमें मर्त्तु १९५३ में नयी दिल्ली में हुई गांधी गोष्ठीमें भाग लेनेवाले डा० अल्वे मर्दल (Alve Myrdal) ने लिखा था, "साधन और माध्य एक दूसरेमें अलग नहीं किये जा सकते क्योंकि गलत साधनोंमें सही लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता।"

दार्शनिक अराजकतावाद (Philosophical Anarchism). गांधीजी के विचार पश्चिमी राजनीतिक विचारधाराके दार्शनिक अराजकतावाद (philosophical anarchism) से मिलते-जुलते हैं। इसका कारण अराजकतावादियों का प्रभाव था। योरो की पुस्तक 'एन आन मिनिव डिमोबेडीयेंस' (Essay on Civil Disobedience) के अनधिकृत भारतीय संस्करणकी भूमिका में महात्मा गांधी ने लिखा है : (इसका उद्धरण प्यारे लाल ने किया है) "मैं इस आदर्श को हृदयमें स्वीकार करता हूँ कि वह सरकार सर्वोत्तम होती है जो कमसे-कम शासन करती है.... इसका मतलब अन्तोनोगन्वा यह होता है और जिस पर मेरा पूरा

विश्वास है कि वह सरकार बनने अच्छी होंगी हैं जो विन्कुल हो मानन नहीं करती।"

गांधीजी ने राज्यके व्यापक कार्यक्षेत्रका मनर्थन नहीं किया, यद्यपि आज बहुतने लोग भारतमें राज्यके कार्यक्षेत्रका विस्तार चाहते हैं। गांधीजी का दृढ़ विश्वास था कि लोगोंको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। वह ग्राम-स्तरके स्वच्छा प्रेरित सहयोग पर बहुत जोर देने थे। उनका कहना था कि राज्य द्वारा अध्याधिक कार्य किये जानेंगे जनताकी पहलुद्धमी (immature) नमाल हो जानी है और भ्रष्टाचार तथा दुनवा परम्पती (nepotism) को प्रोत्साहन मिलता है। दार्शनिक अराजकतावादियोंकी भांति गांधीजी भी उन बानमें विश्वास करने थे कि राज्यका, बातांकी अवदंस्ती मनवानेवाला, स्वरूप वैधानिक कर्मको नैतिकतामें जुड़ा कर देना है। जब मनुष्य मशीनोंकी तरह काम करने हैं तब नैतिकताका प्रश्न ही नहीं उठता। गांधीजी और थोरो (Thoreau) दोनों ही राज्यको आत्माहीन मशीन मानते थे। इसलिए गांधीजी राज्यविहीन लोकनककों आदर्श समाज मानते थे। गांधीजी ने अपने पत्र "यंग इण्डिया" (Young India) के ७ जुलाई, १९३१ के अकमें लिखा था "इस प्रकारके (अराजकतापूर्ण) राज्यमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना कामक है। वह अपना कार्य इस प्रकारमें करता है कि उनके किसी कार्यमें उनके पक्षीको कमी किसी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ती। इसलिए आदर्श राज्यमें राजनीतिक शक्ति नहीं होनी क्योंकि राज्य ही नहीं होता।" गांधीजी चाहते थे कि जो मुपार हो वह सब भीतरमें हो। वह नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा मुपार लाये जायें।

राज्य कार्य (State Action). यद्यपि गांधीजी का मुभाव दार्शनिक अराजकतावादकी ओर था पर वह इसके लिए कट्टरता पूर्वक अडुते न थे। अपने विचार और कार्य में गांधीजी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो मिडानों पर ही अडे रहें और दयासंवादी न हो। वह चाहते थे कि राज्य कमसे-कम कार्य करे और अपने अधिकाधिक अधिकार स्वच्छा प्रेरित सम्माजी (voluntary associations) को हस्तान्तरित कर दें। राज्य के प्रत्येक कार्यको अपने परिणामकी कमीदी पर क्या जाना चाहिए। यदि राज्यके किसी कार्यमें जनताके कल्याणकी बाधा होती थी तो गांधीजी राज्यके प्रति अपने अविरवासेके बावजूद राज्यके कार्यका स्वागत करते थे। राज्यके कार्यको एकमात्र लक्ष्य जन सेवा ही होना चाहिए। लेकिन राज्यको अपना कार्य करने में कमसे कम शक्तिका उपयोग करना चाहिए।

गांधीजी का विश्वास था कि राज्य हिंसा पर आधारित होता है; वह गरीबों का शोषण करता है; और अपनी बाज लोगों पर अवदंस्ती लादकर व्यक्तिके स्वनामन-दीनको कम करता है। इसलिए अहिंसा पर आधारित समाजमें राज्य कमसे कम शासन करेगा और कमसे कम शक्तिका उपयोग करेगा। जनताका नैतिक स्तर जैमे-जैमे ऊपर उठता जाएगा जैमे-जैमे राज्यके कार्य कम होने जायेंगे, और एक

दिन वह आयेगा कि राज्यवा अन्त होकर स्वनिर्वाचित और नियमित अराजकताका उदय होगा ।

कल्याणकारी राज्य (The Welfare State).— हुमायूँ कबीर के कयना-नुमार गांधीजी उदार परम्परा (व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आदि) व दार्शनिक अराजकताकी परम्पराके उत्तराधिकारी थे । समाजवादी विचारमें पाये जानेवाले इस समूहवाद के भी वह उत्तराधिकारी थे कि जीवनकी अच्छी वस्तुएं सबको बराबर-बराबर मिलनी चाहिएं । यदि गांधीजी आज जीवित होते तो वह सामाजिक कल्याणकारी राज्यके आदर्शका समर्थन तो करते पर ऐसे राज्यकी व्याख्या उनकी अपनी होती । जन हितैषी होनेके कारण और इस कारण कि अविधित और पिछड़े वर्गके प्रति उनकी हार्दिक और गहरी सहानुभूति थी गांधीजी कल्याणकारी राज्यका समर्थन करते । गांधीजी समाजवादी समाजको और विभिन्न पंच-वर्षीय योजनाओंको सभी पसन्द करते जब जनता ही उन्हें बनानी और कार्यान्वित करनी । वह यह कभी पसन्द न करते कि पंचवर्षीय योजनाओंके फलस्वरूप सरकारी कार्योंका क्षेत्र बढ़ता जाय, मार्बजिनिक धनकी भारी बर्बादी हो, लोगों को भ्रष्टाचार और आलस्यका अधिक अवसर मिले । गांधीजी यह कभी पसन्द न करते कि भारी उद्योगों और बहुधनी विशाल नदी-घाटी योजनाओं पर इतना अधिक ध्यान दिया जाय क्योंकि इन पर खर्च होनेवाले भारी धनके अनुपातमें गरीबोंको इन योजनाओंसे लाभ नहीं पहुंच सका है । वह सामुदायिक कल्याणकारी योजनाओंका समर्थन करते और इन्हीं योजनाओंको कल्याणकारी राज्यका आधार बनाते ।

कष्ट और शोषण का विरोध (Against Misery and Exploitation). गांधीजी हर प्रकारके कष्ट, दरिद्रता और शोषणके विरुद्ध थे । वह जाति व्यवस्था की निन्दा करते थे और छुआ-छूतको पाप मानते थे पर वह वर्णाश्रम धर्मके हिन्दू आदर्शका समर्थन करते थे जिसके अनुसार हर व्यक्तिको समाज में अपनी समताओं और प्रशिक्षण के अनुसार निश्चित काम करना पड़ता था । जनताका कल्याण करनेके उत्साहमें गांधीजी ने समाजको समृद्ध और सर्वहारावर्ग में (the haves and the have-nots) या शोषकों और शोषितोंमें विभाजित नहीं किया था । उन्होंने अपनेको जनतासे पूर्ण रूपेण मिला दिया था । गांधीजी मार्क्सवादी नहीं थे । वह अपनेकी जुलाहा और किसान कहते थे । और उन्होंने खाना, कपड़ा और बोल-चालमें अपनेको जनतासे एक कर दिया था । मन्दिर प्रवेश के समर्थनमें और छुआ-छूतके विरुद्ध लगातार प्रचार करके उन्होंने जाति-व्यवस्थाकी रीढ़ तोड़ दी थी । उन्होंने एक अछूत बन्ध्याको अपनी लड़की बनाया और अछूत शब्दके स्थान पर 'हरिजन' शब्दका उपयोग किया और हरिजनको हिन्दू समाजमें सम्मानित स्थान दिया । उन्होंने अछूतोंके लिए पृथक निर्वाचन प्रणालीके विरुद्ध अनशन किया और सयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा अछूतोंके लिए स्थानोंको सुरक्षित करके विधायिका में अछूतोंको उनकी सख्यामें अधिक स्थान दिये । उन्हें महिलाओं और बच्चोंकी विशेष

बिना रहती थी और दक्षिणी अफ्रीका में अपने अहिंसक आन्दोलनोंके प्रारम्भिक कालमें उन्होंने महिलाओं की नैतिक शक्तियों को खोज निकाला। वह किनारों और मजदूरोंकी भी उनकी ही बिना करते थे। आरम्भमें जब उनके पास अधिक समय रहता था छोटेसे छोटा व्यक्ति भी उनके पास जाकर अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर उनके विचारपूर्वक विचार विमर्श कर सकता था। गांधीजी की नई शिक्षा प्रणाली जिसे 'नयी नालीम' कहने में सम्य और मानव प्रतिष्ठाके ही मिडान्ता पर आधारित थी। वैसे तो उनमें पूर्वके विचारकोंने भी मानव-प्रतिष्ठा, समानता और भ्रान्त्य का जोरदार समर्थन किया था पर गांधीजी इन पर ज़रूर करने थे और इन्ने राजनीति और मानव जीवन के लिए उनकी सबसे बड़ी देन माना जा सकता है। मसौपमें, उन्होंने राजनीतिका आध्यात्मोत्तरन किया।

अहिंसाका दर्शन-शास्त्र (The Philosophy of Non-violence)

इतना सब कहने के बाद भी यह स्वीकार किया जावेगा कि राजनीतिको और साधारण मानव जीवनको गांधीजी की सबसे बड़ी देन उनकी अहिंसाकी शिक्षा और व्यवहार था। उन्होंने १९२० में ही लिखा था "जिस प्रकार हिंसा पशुओंकी विधि है उसी प्रकार अहिंसा मानव ज्ञानिको विधि है। आत्मा (spirit) पशुओंमें प्रसूत रहती है और वह केवल शारीरिक शक्तियों ही जानता है। मानव महत्त्वका सङ्काश है कि हम एक उच्चतर विधि—आत्माके मरनेको—मानें.....अहिंसा एक पूर्णता (perfection) की स्थिति है। यह वह लक्ष्य है जिसकी ओर मानव समाज स्वाभाविक और अनजाने तौर पर बढ़ता जाता है" (यंग इन्डिया, १४ अगस्त १९२०)। उन्होंने फिर लिखा "मेरे लिए अहिंसा केवल एक दार्शनिक मिडान्त ही नहीं है। यह मेरे जीवनका ताना-बाना है.....यह हिंसा की चीज न होकर हृदयकी चीज है।" गांधीजी किसी भी अपेक्षे अहिंसाने मिडान्तके या इसी प्रकारके अन्य मिडान्तोंके प्रवर्तक (originator) नहीं थे। पर वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामूहिक तौर पर और राजनीतिक क्षेत्रमें इन मिडान्तोंको लागू किया।

अहिंसा निष्क्रियता नहीं है (Non-violence is not Passivity)

गांधीजी की अहिंसाका अर्थ पुरजोर जुम्ले बदलित करना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शत्रुता या बुराईके सामने हाथ पर हाथ रखकर बैठ रहा जाय। "यह आत्म-शक्ति या सत्यताकी खोज करनेवाली शक्ति है। मसौपमें यह सत्यापट है जिसका अर्थ है अपनी समस्याओं नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति में सम्य या सत्य बातों का मुकाबला करना। यह सत्यके लिए नैतिक शक्ति का दुहाया उपगम है।" यह आत्म-शक्ति या हमारे भीतर रहनेवाले परमात्माकी शक्ति है। यह आत्म-बलिदानके

प्राचीन हिन्दू सिद्धान्तके अनुकूल है। इसका मतलब है ज्ञान-वृद्धकर कष्ट उठाना। गांधीजी के ही शब्दोंमें “इसका अर्थ बुराई करनेवालेके सामने चुपचाप घुटने टेक देना नहीं है।” “यह नकारात्मक शक्ति नहीं है.....यह बिजलीमें अधिक निश्चयात्मक और ईयर (ether) में अधिक शक्तिशाली है।” “बड़ीसे बड़ी हिंसाका बड़ी से बड़ी अहिंसामें मुकाबला किया जा सकता है।” गांधीजी अपने को “सत्याग्रह नामक प्रकाशगृह (light house) का चौकीदार कहते थे।” “यह वह सिद्धान्त है जिसके लिए मैं जीवित रहता हूँ, जिसके लिए मैं जीवित रहना चाहता हूँ और मेरा विश्वास है कि जिसके लिए मैं मरनेको भी तैयार हूँ।” (इस वाक्यका अन्तिम अंश ३० जनवरी, १९४८ को सही प्रमाणित हुआ)।

गांधीजी को अहिंसाकी व्याख्या करनेवाले अन्य लोगोंने इसे ‘आत्माकी धीरता’ ‘साधू का युद्ध’ और ‘प्रेम पूर्ण साहसिक कार्य’ कहा है। यह नकारात्मक होनेमें कौनो द्वार है। यह निश्चयात्मक, शक्तिशाली और रचनात्मक है।

अहिंसाका आधार (Non-violence rooted in Ahimsa)

जिस अहिंसाकी गांधीजी शिक्षा देते थे और जिस पर वह अमल करते थे उसका आधार अहिंसा या किसी को दुःख न पहुँचानेका भारतीय सिद्धान्त है। नकारात्मक तौर पर इसका अर्थ है किसी को कष्ट न देना या किसी की जान न लेना। “अहिंसा का अर्थ है सत्कारकी किसी वस्तुको मनसा, वाचा और कर्मणा क्षति न पहुँचाना।” (हरिजन, ७ सितम्बर, १९३५, पृष्ठ २३५)। इसका मतलब है कठोर शब्द न बोलना कड़ी बात न कहना, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, और क्रूरतासे बचना। इसका मतलब शासक तौर पर यह है कि किसी व्यक्तिको अपने शत्रुके प्रति भी बुरे विचार नहीं रखने चाहिए।

क्रियारमक पक्षमें (On the Positive Side), अहिंसा ईसाई धर्मके प्रेमके सिद्धान्त के निष्पत्ति है। यह सर्वशक्तिमान, अनन्त और परम ईश्वरका पर्यायवाची है। यह सर्वत्र व्यापक तथा अनादि सिद्धान्त है जिसको जीवनकी हर स्थिति पर लागू किया जा सकता है। डा० जी० एन० धवन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘द पॉलिटिकल फिलॉसॉफी आफ महात्मा गांधी’ में इस प्रकार लिखते हैं “अहिंसाका अर्थ है हिंसाको छोड़नेका प्रयत्न जो जीवनमें अनिवार्य है। अहिंसाका लक्ष्य है मनुष्यको शारीरिक बन्धनसे छुड़ाना ताकि वह ऐसी स्थिति प्राप्त कर सके जिसमें नाशवान शरीरके बिना जीवन सम्भव हो।”^१

दुर्बलका अस्त्र (Weapon of the Weak). सत्याग्रह उन लोगोंका अस्त्र है जो शारीरिक तौर पर दुर्बल लेकिन नैतिक तौर पर सबल होते हैं। यह उन लोगोंका भी अस्त्र हो सकता है जो शारीरिक और नैतिक दोनों तरह से ताबतबर होते हैं। पर

नैतिक तौर पर दुर्बल लोगोंका यह कभी अर्थ नहीं हो सकता। प्यारे लाल लिखते हैं "गांधीजी की तकनीक (technique) का आरम्भ इस सिद्धान्तसे होता है कि अहिंसा निर्वलता का बल है।" "मुझ्से नेतृत्वमें अहिंसाका उपयोग महिलाएँ, बच्चे तथा अपढ़ लोग और ऐसे अन्य लोग भी कर सकते हैं जिन्हें हम दुर्बल मानते हैं। अहिंसाका मतलब है बुराईका प्रतिरोध, बुराईमें न करके अच्छाई में करना। यह बुराई को अच्छाईमें जीतना है। गांधीजी के ही शब्दोंमें "तन्त्रुमें प्रेम करनेका आदेश केवल उच्चतम आदेश ही नहीं है अपितु यह सबसे अधिक व्यावहारिक राजनीति भी है।"

सत्य आधारभूत सिद्धान्त है (Basic Principle is Truth). अहिंसाका आधार सत्य है। गांधीजी के कथनानुसार केवल इतना ही कहना काफी नहीं है कि ईश्वर सत्य है, हमें यह भी कहना चाहिए कि सत्य ईश्वर है। (हमारे युगके प्रसिद्ध जर्मन ईसाई पादरी और विचारक नीमोलर (Nietmoller) का कहना है कि जिसे हिन्दू सत्य कहते हैं उसे ईसाई 'ईश्वर में विश्वास' मानते हैं)। अहिंसा सत्य के लिए सपर्य है। इस सपर्यमें यदि यह ठीक प्रकार किया जाता है, तो दोनों पक्ष सत्यकी खोज करते हैं, और इसलिए एक-का विजयी होने और दूसरेका पराजित होनेका प्रश्न ही नहीं उठता है। अहिंसा के सपर्यमें "लड़ते-झड़ते मर जाना" की भी बात नहीं होती। अहिंसाका सपर्य करते समय व्यक्ति को क्या-मन्त्रव इस बात के लिए आवश्यक रहना चाहिए कि उसके सपर्यका लक्ष्य पूर्ण सत्य है, अर्थात् तब कि ईश्वर सत्यको पराजित देता है। यदि सपर्य के दौरानमें किसी समय इस बातकी आका हो कि वह सपर्यके पक्षमें हट गया है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करनेमें हिचक नहीं होनी चाहिए और सपर्य से प्राप्त लाभको छोड़ देना चाहिए जैसे गांधीजी ने १९२२ में अपना अहिंसक आन्दोलन यह कहकर वापस ले लिया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल की थी। यद्यपि वह सपर्यकाके शीघ्र पड़ुष चुके थे। सत्याग्रहीके लिए विजयसे अपेक्षा सत्य अधिक मूल्यवान है। इस मन्दर्भमें सत्यके सिद्धान्तका मतलब है कि अहिंसाका उपयोग बहुत मोक्ष-मार्ग कर करना चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपनेको ईश्वरके निकट रखना चाहिए और ईश्वरके आदेश पर ही अहिंसाका सपर्य करना चाहिए; जैसाकि गांधीजी करते थे।

प्रेम भावनासे अन्तःकरणको अपील (Appeal to the Moral Sense in a Spirit of Love). महाप्राप्तोंका मुख्य कथ उसकी यह पारना है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वरता कुछ न कुछ अंग होता है और इस अंगमें प्रेमके अति और स्वयं कष्ट उठाकर अपील की जा सकती है। सत्याग्रहीको यह पक्कर विश्वास होता है कि प्रेम और कष्ट उठानेके सिद्धान्तमें वह उन नैतिक भावनाको जाग्रत कर सकता है जो उसके विरोधीमें सुगुण रहती हैं। पादरी नीमोलर के शब्दोंमें "कष्ट होलने वालेको

कष्ट बल प्रदान करता है और कष्ट देनेवालेको कमजोर करता है। यदि गांधीजी के कथनानुसार सत्य आधारभूत मिडान्त है तो प्रेम वह माधन है जिसके द्वारा मृत्यु की अनुभूति की जाती है। गांधीजी कहते थे कि अहिंसा कठोरमे कठोर हृदयोको भी पिघला सकती है। गांधीजी का विश्वास था कि जनताको अधिकार दानिकी अपेक्षा समझाबुझाकर अपने पक्षमें करना चाहिए। उनका यह भी विश्वास था कि बुराई करनेवाले से घृणा किये बिना बुराई घृणा की जा सकती है। अंग्रेजोंमें अपने सम्बन्धमें उन्होंने एक से अधिक अवसर पर स्पष्ट तौर पर यह कर दिया था। गांधीजी का कहना था कि अंग्रेजों से घृणा किये बिना अंग्रेज दामवत्त्वमें घृणा की जा सकती है और इसे पैदाचिक तक कहा जा सकता है। यह ईसा मसीह की इस शिक्षाके अनुरूप है कि 'अपने शत्रुओंको भी प्यार करना चाहिए'। गांधीजी के शब्दोंमें "यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे अंग्रेजों में विश्वास न रखते हुए भी उनमें प्रेम करना चाहिए।" एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था "मैं ब्रिटिश साम्राज्यवादसे लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं अंग्रेजसे नहीं लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई अंग्रेज या किसी अन्य व्यक्तित्वसे नहीं है। वे मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं ब्रिटिश साम्राज्यवादसे अवश्य लड़ूंगा।"

गांधीजी के इस प्रेमपूर्ण व्यवहारके कुछ उदाहरण ये हैं : जिस अंग्रेज न्यायाधीश ने १९२२ में गांधीजी को ६ सालकी सजा देकर अपना 'धर्म' निभाया था उसकी गांधीजी ने प्रशंसा की थी। १९२४ में जिस डाक्टर ने गांधीजी के 'अपेण्डिसाइटिस' (appendicitis) का आपरेशन किया था, उसके प्रति गांधीजी प्रेमकी भावना रखते थे। गांधीजी लार्ड इरविन, लार्ड लिनिनियोगो और लार्ड बेबेल वाइसरायो के प्रति प्रेमकी भावना रखते थे, यद्यपि इनमें से हरएक से समय-समय पर उनका तीव्र मतभेद रहा है। १९३९ में जब इस बातकी आशंका हो गई थी कि नाज़ी जर्मनी के विमान अपनी बमबाजीसे लन्दन को तबाह कर देंगे तब युद्धके प्रश्न पर उनका तात्कालिक सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण था। गांधीजी तत्कालीन राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए बारम्बार जिन्ना के पास जाकर अपनी प्रतिष्ठता खोते थे। जिन्ना ने वार्ता के लिए गांधीजी को हमेशा अपने पास बौझाया और खुद गांधीजी के पास कभी नहीं गये।

अहिंसाके उपयोगमें प्रेमके महत्त्वके सम्बन्धमें महात्मा गांधी इस प्रकार लिखते हैं : "प्रेम कभी कोई मांग नहीं करता, वह हमेशा देता है। प्रेम हमेशा कष्ट उठाता है, वह कभी बदला नहीं लेता।" वह आगे कहते हैं कि अहिंसाका आधार सत्य और उसका अस्त्र प्रेम है। स्वयं कष्ट उठानेके बारेमें गांधीजी कहते हैं "एक राष्ट्र जो अनीमित कष्ट उठानेकी क्षमता रखता है, असौमित ऊँचाई तक उठने की भी क्षमता रखता है। जितना ही अधिक त्याग होगा उतनी ही जल्दी प्रगति होगी।" गांधीजी आत्म बलिदान, आत्म त्याग और स्वयं कष्ट झेलनेकी शिक्षा देते थे, और इन पर अमल करते थे।

अहिंसा की अन्य आवश्यकताएँ (Other Requisites of Non-violence)

१. आन्तरिक शुद्धि (Inner Purity). गांधीजी के विचारमें सत्याग्रहों को केवल प्रेमका व्यवहार ही नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी अन्तरात्माकी भी शुद्ध होना चाहिए। गांधीजी के कथनानुसार यदि अहिंसाका ताम्बीका अम्त्र होता है तो आत्म-अनुशासन, गिच्छता और आन्तरिक शुद्धि द्वारा इसके लिए तैयारी की जानी चाहिए। जिस प्रकार विषकी एक बूंद दूधको खराब कर देती है, ठीक उसी प्रकार अगिच्छता सत्याग्रहको दूषित कर देती है। एक अन्य स्थान पर गांधीजी लिखते हैं कि सत्याग्रहोंको ब्रह्मचारी रहकर दंडितनाचों अपनाना चाहिए, मन्थका अनुसरण करना चाहिए, और निर्भय रहनेकी आदत डालनी चाहिए। आन्तरिक शुद्धि पर बल देने हुए गांधीजी मन्थाग्रहको राष्ट्रीय पूर्णताका आन्दोलन कहते थे। गांधीजी ने अपने जीवनके ३७वें वर्षमें ब्रह्मचर्य का पालन किया, पर उन्होंने हरेक में ब्रह्मचर्य पालन करनेको नहीं कहा। सर मैलेहेड की भांति गांधीजी मधुमख कह सकते थे कि मेरी शक्ति दस व्यक्तियोंकी शक्तिके समान है क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध है। शुद्धताके महत्त्वकी खर्चा करते हुए डा० मुगीला नायर कहती हैं "मन्थाग्रहका आधार आन्तरिक शुद्धि और निम्नार्थनाकी चट्टान होनी चाहिए ताकि विरोधीके हृदयको प्रभावित करके उसमें सुगुल अच्छाई और ईश्वरत्वकी चिनमासीकी मुलगाथा जा सके।" गांधीजी के ही शब्दोंमें "ब्रह्मचर्य महानगम् अनुशासनोमे मे एक है जिसके बिना मन्थिक आवश्यक दुइना नहीं प्राप्त कर सकता।"

२. अनशन (Fasting). गांधीजी अनशनको भी अहिंसाके उपपानमें महत्त्वपूर्ण तत्व मानते थे। ऐसा मानना भारतीय परम्परा और व्यवहारके अनुष्ण ही है। यह आत्मशुद्धिका एक साधन है, और राष्ट्रीय आन्दोलन में यह राष्ट्रीय पदचालाका साधन है। गांधीजी का दावा है कि "शुद्ध अनशन शरीर, मन्थिक और आत्माको शुद्ध करता है। यह शरीर को कष्ट देकर आत्माको वन्धन-मुक्त करता है।" अनशन प्रार्थना है। ईसा मसीह की भांति गांधीजी के जीवनमें अनशन और प्रार्थना अभिन्न थे। वह लिखते हैं : "अनशन या तो प्रार्थना है या प्रार्थनाकी नैयारी है बसने कि अनशन आप्पान्थिक कार्य हो। अनशन टूटे हृदयकी प्रार्थना है।" गांधीजी के कथनानुसार "शरीरको कष्ट देना आप्पान्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। पूर्ण अनशन पूर्ण और सही अर्थ में आम-निर्भय है।"

अनशनके विरुद्ध बहुधा आरोप लगाया जाता है कि यह नैतिक बन्ध प्रयोग है। इस आरोपके उत्तरमें गांधीजी कहते हैं कि "अनशन आन्थिक प्रेरणाके कारण किया जाता है और वह किसी व्यक्ति विशेषके विरुद्ध नहीं होता है।" "विरोधकर तो यह आने ही विरुद्ध होता है," "यह आत्म शुद्धिके लिए हृदयकी प्रार्थना है और अनशन-कारीको अधिक सावधान और सतर्क बनाता है।" गांधीजी का कहना था कि "पर्याप्त

मानसिक और आध्यात्मिक संघर्षके बाद अनशन करने की प्रेरणा उन्हें ईश्वरसे मिलती थी।" ईश्वर की आवाज उतनी ही स्पष्ट होती थी जितनी प्रत्यक्ष बानचीत करने वाले मनुष्यकी आवाज और इमे मानना ही होता था। यह भ्रान्ति नहीं थी। "मेरे लिए ईश्वरकी आवाज मेरे अस्तित्व से भी अधिक वास्तविक थी।"

राजकोट अनशनके अवसर पर लिखते हुए गांधीजी ने कहा था "मुझे अपने एक भी ऐसे अनशनका स्मरण नहीं है जो व्यर्थ रहा हो। यही नहीं, मुझे अपने सभी अनशनमें अमूल्य भ्रान्ति और अनन्त आनन्दका अनुभव होता रहा है। मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि ईश्वरकी प्रेरणाके बिना किया गया अनशन अपनेकी व्यर्थमें भूखों मारना है। जिसने मुझे अनशन करने की प्रेरणा दी है वह ही मुझे इसे सहन करनेकी शक्ति भी देगा। यदि परमात्मा चाहता है कि मैं कुछ दिन और जीवित रह कर अपना मिशन पूरा करूँ तो कोई अनशन वह चाहे जितना लम्बा क्यों न हो, मेरे शरीरका अन्त नहीं कर सकता।"

जय-जय गांधीजी ने अनशन किया तब-तब उन्होंने चाहा कि जनता उनकी बात में विश्वास करे और यदि उसे गांधीजी की बात न्यायपूर्ण मालूम पड़े तो वह उसे माने। एक समय गांधीजी ने कहा था "मैं चाहता था कि सरकार मेरी बात पर विश्वास करे और यदि वह समझती है कि जिन सुविधाओंको पानेकी मैंने इच्छा प्रकट की थी उन्हें दिया जाना न्यायपूर्ण नहीं है तो वह मुझे शान्तिसे मरने दें।" गांधीजी का कहना था कि उनके सभी अनशनका लक्ष्य जनताको नैतिक तौर पर प्रभावित करना था, न कि उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव डालना। अनशनका उद्देश्य जनताकी अन्तरात्मा को जाग्रत करना था। गांधीजी अनशनके द्वारा आत्म-हत्या नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक अवसर पर लिखा था "मेरी इच्छा मरनेकी नहीं है; मैं अपने लक्ष्यकी सिद्धिके लिए जीवित रहना चाहता हूँ। यद्यपि इसके लिए मैं मरनेकी भी तैयार हूँ।" अनशन गांधीजी के लिए राजनैतिक दाव-पेच की बात नहीं थी। उसका नैतिक और आध्यात्मिक महत्त्व था।

महात्मा गांधी निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकारके अनशनका समर्थन करते थे। पर यदि इनमें से कोई भी अनशन स्वायं निश्चिके लिए किया जाता था तो वह महत्त्वहीन हो जाता था। गांधीजी ने अनेक बार अपने अनुमायियोंकी गलतियोंके विरुद्ध अनशन किया था। उनका कहना था कि आन्तरिक अनशन भी उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है जितना बाहरी अनशन। आन्तरिक अनशनके तरीके ये हैं: मरग के लिए प्रयत्नशील रहना, प्रेमपूर्ण व्यवहार और भौतिक सम्पत्ति और महत्वा-कालाको त्यागना। गांधीजी के अनुसार "विशेष परिस्थितियोंमें आमरण अनशन सत्याग्रहका अविच्छिन्न अंग है।" अन्य अछे कार्योंकी भाँति अनशन करनेमें भी फल की आशा नहीं करनी चाहिए। "जो व्यक्ति फलकी आशाने अनशन करता है वह आमतौर पर विफल होता है।" सक्षेपमें, स्वायं निश्चिके लिए अनशन करना गलत है।

३. **अभय (Fearlessness).** निर्भयता भी उननी ही महत्वपूर्ण है जिननी पवित्रता और अनशन। अहिंसा पर सफलतापूर्वक अमल करनेके लिए सत्याग्रही में किंचित् मात्र भी कायरता नहीं होनी चाहिए। गांधीजी का अभय निस्स्वार्थतामे उत्पन्न अभय था। व्यक्ति भयका शिकार नहीं होता है जब वह अपनी और अपने स्वार्थकी अत्यधिक चिन्ता करना है। आत्म-न्यायके बाद भयका कोई कारण नहीं रह जाता। गांधीजी के ही शब्दोंमें "यदि आप सत्यका अनुकरण करना चाहते हैं तो आपके लिए अभय विन्तुल अनिवार्य है। अभय आध्यात्मिकताके लिए सर्वमे अधिक जरूरी है, बायर बन्नी नैतिक नहीं हो सकते।" इसी सम्बन्ध में लाओ-त्से ने कहा था "हमारे भयका कारण 'आत्म' है। यदि हम आत्मको आत्म न मानें तो फिर डरनेका कारण क्या रह जाता है?" मन् १९५३ में हुई गांधी-गोष्ठी में जापान के प्रतिनिधि त्सुमुमी (Tsurumi) ने गांधीजी को साहम और निर्भयतामे अंत-ग्रोह शान्तिवादी बोंडा (Militant pacifist) कहा था। आचार्य कृपालानी के कथनानुसार गांधीजी चाहते थे कि जनता केवल बहादुर ही न हो बल्कि निर्भय भी हो। कायरता और भय पाप है। गांधीजी स्वयं कहा करते थे कि कायरको तरह भाग बड़े होंनेमे तो हिंसा का उपयोग ही अच्छा है। यदि किसी व्यक्ति को अहिंसा में पूर्ण विश्वास न हो और वह प्रेमने और बल उद्योकर अपनी और दूसरोंकी रक्षा करनेमें असमर्थ हो तो उसे हिंसा का उपयोग करना चाहिए।

४. **अपरिग्रह (Non-possession).** जिन निर्भयताका गांधीजी समर्थन करते थे वह निर्भयता तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्तिमें जीवनके भौतिक पक्षोंके प्रति वैराग्य हो। ईसाई धर्मके शब्दोंमें व्यक्ति नमारमें रहे, पर नमारका हांकर नहीं। अहिंसाको भारत में जिननी सफलता मिली उननी उसे पश्चिममें नहीं मिली। इसका कारण यह है कि पश्चिममें निर्विघ्न (non-attachment) की भावना नहीं प्रबल नहीं है, जिननी भारत में, यद्यपि ईसा मसीह ने अत्यन्त गम्भीरमें दूसरी शिक्षा दी थी। उनकी एक प्रसिद्ध शिक्षा यह है "कल की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल स्वयं अपनी चिन्ता कर लेगा।" उनका कहना था कि व्यक्ति को अपना ही निश्चिन्त होना चाहिए जिननी कि निश्चिन्त हवामें उड़ने वाली चिरिया या बगीचेमें उगने वाले पुष्प। गांधीजी का कहना था कि "जीवनकी नपाकपिण घड़न की सुविधाएँ मानवके उत्थानमे बाधक हैं और इन मुत्रियाओंके बिना जीवनका काम चल सकता है। रसागमे ही सिद्ध होनी है।" गांधीजी की शिक्षाओं पर प्रभाव डालने हुए दूसरे शाल कहते हैं कि सम्पत्ति का रखना अहिंसा के, और अपने को सम्पत्ति नमारके एक रूप बनानेके आशुनके किरीन है। सम्पत्ति न रखना ही आदर्श है। क्योंकि सम्पत्ति रखनेके लिए हिंसाका उपयोग जरूरी हो जाता है। ऐसी हालत में गांधीजी की अधिक व्यवस्थामें कलंध्य पर बल दिया गया है, अधिहार पर नहीं।

५. **धर्म (Perseverance).** यदि अहिंसा एक शास्त्र (eternal) सद्धान्त है तो फिर व्यक्ति को परिश्रमोंके लिए अट्ठबाजी नहीं करनी चाहिए।

व्यक्तिको दैवी धैर्य और सन्नकी आदत डालनी चाहिए। उसे यह समझ लेना चाहिए कि बहुधा हिंसाकी अपेक्षा अहिंसाको सफलता प्राप्त करनेमें अधिक समय लगता है। हमें यह भी न भूलना चाहिए कि लड़ाईमें परिणाम जल्दी तो निकल सकता है पर यह परिणाम कभी स्थायी नहीं होता। एक अहिंसक व्यक्ति पराजय जानता ही नहीं, क्योंकि उसका परमेश्वरमें असीमित विश्वास होता है। विफल होने पर भी उसे यह सन्तोष रहता है कि वह अनन्त काल के लिए कार्य कर रहा है। टी० एच० ग्रीन के शब्दोंमें एक अहिंसक व्यक्ति जल्द ही यह समझ लेता है कि एक अच्छे लक्ष्यकी प्राप्ति के लिए बार-बार प्रयत्न करना और बार-बार विफल होना जरूरी हो सकता है।

गांधीजी आलस्य और भाग्यवादको धैर्य और सन्न नहीं मानते थे। आवश्यकता पड़ने पर गांधीजी एक क्षणकी भी देर बिना तत्काल कार्य करते थे। सन् १९४२ की 'करो या मरो' की नीति इसका एक अच्छा उदाहरण है। भीषण सघर्षके बीच सन् १९४२ में जब भारतका भाग्य अघोरमें लटक रहा था उस समय गांधीजी में इतना नैतिक साहस था कि उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि वे भारत को भगवान और अराजकताके भरोसे छोड़कर भारतसे चले जाय।

गांधीजी की अहिंसा (*Gandhiji's Non-violence Graded*). महात्मा गांधी की विचारधाराके विचार्यों बहुधा इस असमंजसमें रहे हैं कि गांधीजी की अहिंसा असीमित और परमपूर्ण है या नहीं। मोलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों का विचार है कि गांधीजी की अहिंसा परमपूर्ण (*absolute*) है। पर आम तौर पर ऐसा नहीं माना जाता है जैसा कि पहले बताया जा चुका है। गांधीजी का कहना था कि जो लोग अहिंसा पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, वे अपनी शक्तिका उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रोंमें होनेवाले सघर्षमें भी गांधीजी हमेशा निष्क्रिय प्रतिरोध (*passive resistance*) की निन्धा नहीं देते थे। १९३०-३९ और १९४०-४९की अवधिमें जब जापान ने चीन में निर्दय युद्ध छेड़ रखा था, गांधीजी के विचारमें यह उचित ही था कि चीन जापान के विरुद्ध हथियार उठाये। उनकी ऐसी ही राय पोलैण्ड के बारेमें भी थी जब १९३९ में जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण किया था। ऐसी हालातोंमें भौतिक प्रतिरोधको गांधीजी अहिंसाके निकटतम मानते थे। साथ ही उन्होंने अहिंसाको कार्य-सम्पादनका साधन नहीं माना। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सत्याग्रहीको अहिंसाका पालन, मनसा, वाचा और कर्मणा से करना चाहिए।

गांधीजी की अहिंसा का आधार धार्मिक (*Gandhiji's Non-violence Religiously Motivated*). जैसा कि बार-बार कहा जा चुका है, गांधीजी मूलतः धार्मिक पुरुष थे। अपने धार्मिक विचारोंके कारण, ही उन्होंने अहिंसाको अपनाया। वह नैतिकताको धर्मका पर्यायवाची मानते थे। उनके धर्ममें रीति रिवाजों या अन्धविश्वास आदि का कोई स्थान नहीं था।

उनका कहना था कि "नैतिकता वस्तुओंका आधार है और नैतिकताका आधार सत्य है।" मनुष्यकी आध्यात्मिक मुक्ति जीवन और ममारे वाप बलापेमे पृथक नहीं है। हर प्रकार से अच्छा जीवन विना ही मुक्ति है। "यदि कोई व्यक्ति आत्म-अनुमति करना चाहता है और अपने भीतर दबी भावना को जागृत करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित बातों पर बल करना चाहिए - आत्म-शुद्धि, अहं में मुक्ति, त्याग, भक्ति, ज्ञान, आत्म लोप (self-effacement), प्रार्थना, मौन, श्रद्धाचर्य, द्रव और नियंत्रित भोजन। इन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित जीवनके बल पर ही गांधीजी अहिंसाका उपयोग किया करते थे। गांधीजी ने निम्नलिखित पांच बातोंकी प्रतिज्ञा ले रखी थी। सत्य, अहिंसा, सम्पत्ति त्याग, चोरी न करना और श्रद्धाचर्यका पालन।

गांधीजी शक्तिके पुंज (Gandhiji a tower of Strength). गांधीजी अपनी नैतिक और आध्यात्मिक महानताके कारण लोगों व्यक्तिपोंके लिए शक्ति के पुंज थे। गांधीजी की इस शक्तिके पांच मुख्य कारण थे। गांधीजी का परमेश्वरमें अडिग विश्वास था। वह ईश्वरको सर्वव्यापी मानने थे। अपने जीवनके आरम्भमें ही उन्होंने परमेश्वरमें आदेश लेना सीख लिया था। एक बार ईश्वरका आदेश पा लेनेके बाद फिर पीछे लौटनेका प्रश्न ही नहीं उठता था। किसी प्रकार के मोच-विचारकी जरूरत नहीं रह जाती थी। उन्होंने लिखा था "शक्ति ईश्वरमें आती है मैंने अपनी कोई शक्ति होनेका दावा कभी नहीं किया।" "परमेश्वर अहिंसकी दाग है।" आमरण अनशन को भी वह "मर्यादग्रह का अभिन्न अंग" मानने थे।

गांधीजी को जितना विश्वास परमेश्वरमें था उतना ही अडिग विश्वास उन्हें अपने साथी मनुष्योंमें था। उन्हें मानव सम्भावनाओंमें असीमित विश्वास था। उनका पक्का विश्वास था कि मानव स्वभाव हमेशा मुधारा जा सकता है। आज के संसारमें जब लोगोंका विश्वास परमेश्वर और मनुष्योंमें हटकर मर्दानोंमें होता जाता है, गांधीजी का यह विश्वास बहुत ही स्कूनिदायक है। यदि ईसा मसीह के जन्मके समय देवदूतोंने "उच्चतमका ध्येय परमेश्वर को है" का नारा लगाया था और १९वीं शताब्दीमें म्विनबर्न ने "उच्चतमका ध्येय आदमी को है" का नारा लगाया तो आधुनिक युगका नारा है "उच्चतमका ध्येय मर्दानोंको है।" यदि हम परमेश्वर और मनुष्यमें विश्वास करना छोड़कर केवल मर्दानोंमें ही विश्वास करें तो हम अपनेको मनुष्योंमें सबसे अधिक निराशावादी प्राणी पायेंगे।

निस्स्वार्थता, पवित्रता और अनुशासित जीवन तथा इन्द्रिय नियन्त्रणमें उन्मत्त गांधीजी की निर्भयताकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। अन. इस बारेमें और अधिक नहीं लिखा जायगा।

अपनी महानता, शमाशीलता, और मेल करने (reconciliation) की प्रवृत्तिके कारण गांधीजी शक्तिके स्तम्भ थे। वह अपनी विजयको कभी उस हद तक नहीं ले जाने थे कि विरोधीने हमेशाके लिए सम्बन्ध टूट जाय। वह कभी विरोधीको नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। उनके विभिन्न अहिंसक आन्दोलनोंमें विजय और पराजय

पश्चिमी देशों में भी जहाँ व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता का स्तर ऊँचा है वहाँ भी पारिवारिक एकता और बड़े परिवारों के प्रति वंशदायीको धक्का लगा है। पड़ोसी सम्बन्धों और सामुदायिक भावनाने रम्मी हूँ ग्रहण कर लिया है। इस सबके बावजूद यह मानना ही चाहिए कि मनीन भी उसी प्रकार ईश्वरकी देन है जिस प्रकार सारोरीक थम। इसलिए धुड़मानो यहो है कि दोनोंका विकास किया जाय और मनीनको मनुष्यका स्थान न लेने दिया जाय और उसे यह भीका न दिया जाय कि वह मानव व्यक्तित्वको कुचल दे।

ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था का पुनरुद्धार (Revival of Village Economy). गांधीजी के विचारोंका केन्द्र ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था थी। उन्होंने अपना समय और ध्यान गाँवोंके आन्तरिक विकासमें लगाया था। वह सबसे पहले स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगोंको काफी भोजन मिल सके और वे क्षुधासे पीड़ित न हों। उनकी रायमें ऐसी आर्थिक व्यवस्था निन्दनीय है जो जनताका शोषण करके कुछ थोड़ेसे लोगोंके हाथोंमें सम्पत्ति केन्द्रित करती है। वह हाथकी बनाई और बुनाई पर अधिक जोर देते थे। इसका आर्थिक महत्त्व तो था ही पर साथ ही साथ इसने अंग्रेजी साम्राज्यवादके मिहामनको हिला दिया था। अन्य कुटीर उद्योगों जैसे, गूड़ बनाना, धान फूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़ेका काम, टोकरियाँ बनाना आदि पर भी गांधीजी ने जोर दिया। हालांकि इन उद्योगोंकी उन्नति मात्रसे ही भारतके करोड़ों लोगोंके भोजन बस्त्र, और आवासकी समस्याएँ हल नहीं हो सकती। गांधीजी ने सर्वोदयकी योजनाके जरिए सबकी उन्नतिके विचारको जन्म दिया। सर्वोदयका आज भारतमें व्यापक रूपसे प्रयोग किया जा रहा है।

आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रमें गांधीजी चाहते थे कि भारतमें स्वशासन और स्वायत्तता का ग्राम गणतंत्रोंका जाल बिछ जाय। हर गाँव या गाँवोंके समूहमें अपने उद्योग धंधे हों और उनमें से हर एक का स्वशासित अस्तित्व हो। आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन दोनोंका विकेन्द्रीकरण मुख्य बात थी। गांधीजी राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाके लिए क्षेत्रीय आत्म-निर्भरताके विचारका समर्थन करते थे। खाद्यान्न और वस्त्रोंमें अन्तराष्ट्रीय व्यापारके वह विरोधी थे। वह चाहते थे कि सपत्तसे अधिक पैदा होनेवाली वस्तुओंका और विलासकी चीजोंका ही अन्तराष्ट्रीय व्यापार हो, पर आज हालत यह है कि जिन जमीनों पर खाद्यान्न पैदा किया जाता चाहिए उनमें से कुछ पर ऐसी चीजें पैदा की जाती हैं जिन्हे बाहर भेजकर डॉलर प्राप्त किया जा सके। मुमकिन है कि व्यापक मिर्चाई और विद्युत् योजनाओंके कारण आगे चलकर भारतको अपने मतलब भरका खाद्यान्न पैदा करनेके लिए इतनी जमीनकी जरूरत न पड़े जितनी को जरूरत आज दिन पड़ती है। पर गांधीजी के इस विचार पर ध्यान न देना बेवकूफी होगी कि भारतके गाँव अपनी आधारभूत आवश्यकताओंकी स्वयं पूरी करनेमें मर्बूफ हों। एक ममबालीन देखकर अनुसार गांधीजी नहीं मानते थे कि किसी तरहका

शांति के अर्थ 'ईश्वर का आश्रय' है बल्कि वह शांति के अर्थ में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का माध्यम मानने थे।

सोमा सिद्धान्त (Doctrine of Limits). नैतिक सिद्धान्त में गांधीजी का सिद्धान्त सोमा-सिद्धान्त में मिलता-जुलता था। वह जीवन-मरण के मरल बनाने में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति को स्वयं अपनी सम्पत्ति को सीमित कर, त्याग की नीति अपनानी चाहिए। गांधीजी अनुभव करते थे कि सम्पत्ति चिन्ता का कारण होती है और इसके बढ़ने से मनुष्य विगोपी परिणाम होने हैं। मनुष्य अपने ही जाल में फँस जाता है। गांधीजी का यह विचार ठीक ही था कि जीवन की सच्चाई यह है कि मनुष्य केवल अनायास ही नहीं है अपितु मानव उत्पादन में बाधक भी है। "इस सम्बन्ध में प्यारेलाल जी का कहना है कि अहिंसा और वनस्पतिवाद के आदर्श में सम्पत्ति का मेल नहीं बैठता। सम्पत्ति न रखना ही आदर्श है। गांधीजी का कहना था कि सम्पत्ति के एकाधिकार के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गांधीजी की अहिंसा का आधार किसी वस्तु के प्रति अनुराग न होना था।

सोमा के सिद्धान्त में गांधीजी ने त्याग (Trusteeship) के सिद्धान्त का विकास किया। वह चाहते थे कि अमीर लोग अपने को सम्राट मानें। उन्हें अपनी सम्पत्ति का उपयोग समस्त समाज के हित में करना चाहिए। ईसाई धर्म के कथानुसार कोई व्यक्ति सम्पत्ति का मालिक नहीं होता। वह केवल ईश्वर की तरफ से सम्पत्ति रखवाला होता है। गांधीजी के ही शब्दों में "धनी लोगों में यह आगा नहीं की जानी कि वह अपनी सम्पत्ति को फँस दें, पर उनमें यह आगा अवश्य की जानी है कि वह अपनी सम्पत्ति में निष्ठा न रहे।"

दुर्भाग्यवश इतिहास में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन बहुत ही कम पाया जाता है। मनुष्य सम्पत्ति में इतना ज्यादा लिप्त रहता है कि मैक्सवेल की प्रभावपूर्ण शब्दों में, "मनुष्य अपने पिता की हत्या की जन्दी बन जाता है, पर अपनी पैतृक सम्पत्ति की हानि को देखते भूलता है।" फिर भी इस साम्यवाद के अन्तर्गत निम्नलिखित कारणों से आगा पड़ती है कि विनाश नावे छोटे और बड़े भूमिालयों में ४० लाख एकड़ भूमि हानि में पा चुके हैं। सम्भव है उचित, नैतिक और आध्यात्मिक बाधाओं पर पार न्याय का सिद्धान्त साम्यवाद हो जाय। मानव विकास के वर्तमान स्तर में किसी न किसी विमर्श का दबाव जरूरी मान्य होता है। अतः गांधीजी इसे हिता मानेंगे।

क्या गांधीजी समाजवादी थे? (Was Gandhiji a Socialist?)
ऊपर जो कुछ कहा गया है उसमें यह स्पष्ट है कि गांधीजी उस अर्थ में समाजवादी नहीं थे जो अर्थ मात्र इस शब्द को दिया जाता है। यदि वह समाजवादी थे तो उनका समाजवाद धर्म समाजवाद था। वह उस प्रकार के सिद्धान्तवादी समाजवादी नहीं थे जो चाहते हैं कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार रहे। उनका विश्वास था कि जो मनुष्य आवश्यकताओं के अधिक उपयोग करता है वह दूसरों का हक मारता है। एक

बार लुई किमर ने गांधीजी से पूछा कि आप समाजवादके क्या मतलब समझते हैं। इसके उत्तरमें गांधीजी ने कहा "मेरे समाजवादका मतलब है सबके लिए समाजवाद। मैं अन्धे, गूंगे और बहुरोकी राग पर प्रगति नहीं करना चाहता; मैं अपने व्यक्तित्वकी पूर्ण अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता चाहता हूँ अन्य प्रकारके समाजवादमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहनी। आपका कुछ नहीं होता। आपका शरीर भी आपका नहीं होता।" १

यद्यपि गांधीजी सामान्य अर्थमें समाजवादी नहीं थे पर सहयोगके विभिन्न साधनों में उनका दृढ़ विश्वास था। वह कहा करते थे कि "मैं जन्मतः सहयोग करने वाला हूँ।" साथ ही वह अनुदारता और उदारता, समाजवाद और साम्यवाद तथा अराजकतावाद में भी कुछ न कुछ अच्छाई पाते थे।

ऊपर हमने जो कुछ कहा है उसका निचोड़ काका माहव कालेलकर के कथनानुसार यह है कि भारतकी समस्याओंका हल गांधीजी निम्नलिखित बातोंमें पाते थे: उत्पादनका विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय आत्म निर्भरता; अत्यधिक धन और दारिद्र्यता में बचाव, सभी धर्मोंके लिए समान आदर; समाजमें ऊंच और नीचकी भावना का त्याग, धन और सम्पत्तिका समुचित मानव समाजके कल्याणके लिए उपयोग; विलासी जीवनके भौतिक स्तरको कम करके जीवनके नैतिक स्तरको उठाना; प्रतिशोध मूलक सजाओंकी समाप्ति और शान्ति तथा व्यवस्था कायम करनेके प्रयत्नमें कमसे कम शारीरिक शक्तिका उपयोग।" २

क्या गांधीजी अन्तर्राष्ट्रीयतावादी थे? (Was Gandhiji an Internationalist?)

गांधीजी के समयमें भारतके देशभक्तोंका सारा ध्यान और प्रयत्न राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करनेमें केन्द्रित था। गांधीजी इसके अपवाद नहीं थे। फिर भी भारतके बाहर ससारकी हलचलोंमें उनकी दिलचस्पी थी। एक फ्रांसीसी समाचार पत्रमें उन्होंने कहा था "मेरी राष्ट्रीयता गहरी अन्तर्राष्ट्रीयता है।" गांधी-गोष्ठीमें भाग लेनेवाले डॉ॰ राल्फ बुंच के कथनानुसार यद्यपि गांधीजी के प्रयत्न भारत पर केन्द्रित थे, पर वह सच्चे अन्तर्राष्ट्रीयतावादी थे।

एक बात और है, गांधीजी के जीवन और विचारधाराके दो महान् मौलिक कार्य सिद्धान्त—महत्त्व और अहिंसा, विश्वव्यापी सिद्धान्त हैं। इस अर्थमें गांधीजी एक अन्तर्राष्ट्रीयतावादी थे। फिर भी उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और कर्तव्योंके बारेमें किसी पूर्ण सिद्धान्तका प्रतिपादन नहीं किया। यद्यपि उन्होंने शान्ति-सेनाओं

१ Quoted by Pyarelal in 'Harijan' 4-8-46.
२ Gandhian Outlook and Technique, pp. 372-73.

की चर्चा की, पर इन सेनाओं की भर्ती, इनके मण्डन और उपयोग के प्रश्नों पर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। वे सुदूर भविष्य के स्वप्न ही बने रहे। यदि गांधीजी आरंभ जीवन होने नों सम्भव है कि अन्तर्गच्छाक्षेत्र में वह हमारे नेत्र में होंगे। पर वह तो केवल कल्पना मात्र है।

गांधीजी के धार्मिक विचार (The Religious Ideas of Gandhiji)

आम तौर पर किसी व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा लिखने समय उसकी धार्मिक विचारों का जिक्र नहीं किया जाता पर गांधीजी के सम्बन्ध में बात भिन्न है। उनके लिए राजनीति और धर्म एक दूसरे में इनमें फेरे-मिले थे कि उनके धार्मिक विचारों का सक्षिप्त विवरण देना अनुचित न होगा।

सब धर्मों की समानता (The Equality of All Religions). गांधीजी का एक ही विश्वास था कि सभी धर्म सच्चे, सप्रमाण हैं, साथ ही सभी धर्म अपूर्ण हैं। उन्हीं के शब्दों में 'हर राष्ट्र का धर्म अपना ही अच्छा है जितना किसी दूसरे राष्ट्र का धर्म।' निम्नलिखित भारत के धर्म उसकी जनता के लिए ठीक हैं। हमें आध्यात्मिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। "समस्त की आवश्यकता यह नहीं है कि एक ही धर्म हो बल्कि यह है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक दूसरे का आदर करें और सहनशीलता के काम लें।" सभी धर्म सत्य पर प्रकाश डालते हैं पर सभी धर्म अपूर्ण हैं और गलती कर सकते हैं। "मेरा विश्वास है कि ईसाई धर्म अपना ही अच्छा है जितना कि मेरा धर्म। ऐसा एक भी धर्म नहीं है जो बिल्कुल पूर्ण हो। सभी धर्म समान रूप से कुछ न कुछ अपूर्ण हैं।" "सभी धर्म सत्य पर प्रकाश डालते हैं, पर सभी अपूर्ण हैं और गलती कर सकते हैं।"

यद्यपि गांधीजी सभी धर्मों की समानता पर एक ही विश्वास करते थे और अपने विश्वास पर अमल करते थे पर उन्होंने इस धारणा का विस्तारण बहुत सावधानी से नहीं किया था। हमारे विचारों में सभी धर्म एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं हैं। उनमें समानता भी है और असमानता भी और असमानता भी उनकी महत्त्वपूर्ण है जितनी समानता।

किन्तु भी गांधीजी का इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बड़ी सावधानी से, आरम्भ में केवल अन्य नर, अपने सभी अधर्मों में धार्मिक एकता पर प्रामाण्य किया। वह सभी धर्मों की प्रार्थनाओं और सभी धर्मों के धार्मिक रीतों, भगवद्-गीता, अवस्था, मर्मन आदि के माउन्ट, अन्य साहित्य और बुखान, का उपयोग करते थे। साथ ही उन्होंने इस बात में जोर दिया कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका लगाव किसी गान धर्म से नहीं था। उन्होंने सभी धर्मों के कुछ समानताओं की समझने अनुसार हिन्दू धर्म में मिलाना और उन सबका पुनर्निर्माण किया। उनकी धार्मिक एकता की भावना का सबसे बड़ा उदाहरण वह प्रार्थना है जो एक मुस्लिम

भूतपूर्व न्यायाधीशने १९३० में नमक मत्स्याग्रह आरम्भ करनेके पूर्वकी थी। इसे हिन्दू प्रेरणाके अन्तर्गत एक समन्वयमान द्वाराकी गई ईमार्द प्रार्थना कह सकते हैं। प्रार्थना यह है

"हे ईश्वर तेरे नाम पर हम आज नुभारम्भ करने हैं। हमें आगे बढ़नेको, हमसे-हसने गभी बप्टोको सहनेकी शक्ति दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपके गुण गीत गाये। हमें अपने ज्ञानमें प्रकाशित कीजिए और हमारे हृदयमें दुर्भावना और घृणाको दूर कीजिए। हमारे किसी भी काममें कालिमा न लगने पाये। हमारे विरोधियों को भी गही मार्ग पर लगाइए और उन्हें आशीर्वाद दीजिए। हमारे कार्यको भी अपना आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आपका यह आश्रयमान है कि अच्छाई और गन्धकी हमेशा विजय होती है।

विभिन्न धर्मोंके बारेमें गाधीजी के निम्नलिखित बयन महत्वपूर्ण हैं। "संसार के धर्मोंका मैत्रीपूर्ण अध्ययन हरएकका पावन कर्त्तव्य है, "मेरे लिए बाइबिल उसी प्रकार धार्मिक पुस्तक है जिस प्रकार गीता और कुरान।" मैं बाइबिल में उनका ही विश्वास करता हूँ जितना गीतामें। "मैं समारंभ सभी बड़े धर्मोंको अपने धर्मके समान ही गच्छा मानता हूँ।"

धर्मका तत्त्व (The Essence of Religion). यद्यपि गाधीजी बहुत रहस्यवादी थे और बहुधा 'आन्तरिक पुकार' (The Inner Voice) में प्रेरित होने पर जब-जब धर्मकी व्याख्या करनेका अवसर आया उन्होंने इसकी व्याख्या व्यावहारिक तौर पर की। गाधीजी ने एक बार कहा था कि सबकी सेवा करना तथा सबको मित्र बनाना सबके धर्मका मार है। उन्होंने एक अन्य अवसर पर अच्छाईमें बुराईको जीतनेको धर्म कहा था। उन्होंने कहा था अपने मित्रोंके प्रति मैत्रीपूर्ण रहना तो सरल है। पर धर्मका मार-तत्त्व है ऐसे व्यक्तिको भी मित्र बनाना जो आपको अपना शत्रु मानता हों। सज्जनता और उदारता उनके धर्मकी कुजिया थी।

हृदय-धर्म (Heart Religion). गाधीजी का धार्मिक दृष्टिकोण केवल मानववादी या मानवतावादी ही नहीं था। वह अपने भीतरी धर्मको 'हृदयका धर्म' कहते थे। उनके स्मरणीय शब्द ये हैं "मुझे तो ईश्वर पर विश्वास और उसकी प्रार्थनाका महारा है। यदि मेरे टुकटे-टुकटे भी नष्ट दिये जाय तो ईश्वर मुझ-उममें विश्वास करने और उसके अस्मिन्त्वकी घोषणा करनेकी शक्ति देगा।" जब वह १९१८ में दक्षिण अफ्रीका में लौटकर भारत आये थे तब उन्होंने कहा था कि "धर्म ही उनके जीवनका निश्चित पथ-प्रदर्शक है।" अपने ज्ञादिव धर्मके दृष्टिकोणमें गाधीजी वैष्णव व जैन धर्ममें तथा गीतामें बहुत प्रभावित हुए थे। जीवनकी परिवर्तनाकी पहली सलक उनको जैन धर्मकी शिक्षाओंमें मिली थी। सभी मूल्य धार्मिक पुस्तकों भाति ही गाधीजी का ईश्वरमें विश्वास युक्तिका विरोधी न होकर उनके ऊपर नियन्त्रण चुका था।

सत्य ही ईश्वर है (Truth is God). जैसा कि पहले कहा जा चुका है, गांधीजी के लिए सत्य ही सबकुछ था। उनका कहना था कि सत्य ही ईश्वर है। उनके शब्द इस प्रकार हैं "मे ईश्वर को व्यक्ति नहीं मानता। मेरे लिए सत्य ही ईश्वर और ईश्वरको विधि है, ईश्वर सत्यके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।" "हम सबमें सत्य होता है पर पूर्ण सत्य नहीं।" "धर्म आत्माके विज्ञानमें सम्बन्ध रखता है।" आत्माका बल समारम्भ सबसे बड़ा बल है। इस सबमें यह स्पष्ट है कि गांधीजी केवल व्यक्तिवादी ही नहीं थे।

हिन्दुओंके हिन्दू (A Hindu of Hindus). यद्यपि गांधीजी सभी धर्मोंके प्रति—आदिम धर्मोंके प्रति भी—महजगील और उदार थे, पर वह अपनेको "हिन्दुओंके हिन्दू" और खतालनी कहते थे। लेकिन वह यह भी बता करते थे कि जितने वह हिन्दू हैं उतने ही वह ईसाई या मुसलमान भी हैं। वह हिन्दू धर्मको बुगझोको जानते थे, लेकिन उन्होंने उसको भीतर में सुधारनेकी कोशिश की। वह मूर्ति-पूजाका समर्थन करते थे, यद्यपि वह स्वयं मूर्ति-पूजा नहीं करते थे। वह या रथमें बिछाम करते थे पर इसे उस हद तक नहीं ले जान थे जित हद तक कुछ राजनीतिक और धार्मिक स्थिति में जाने है। उन्होंने छुआछनेके विषय बृद्ध छोड़ा, पर साथ ही वह वर्णाश्रम धर्मको मानते थे। वह रामनामके उच्चारणका मानवीय बुरादोका अचूक इलाज मानते थे। हिन्दूधर्मकी महजगीलताकी विमर्शताके कारण उनके हृदयमें हिन्दू धर्मके लिए बड़ा आदर था। वह इस व्यापक मानते थे। वह कहते थे कि हिन्दू धर्म 'अपनी महजगीलताके कारण उस समय तक कायम रहेगा जब तक कि सूर्य क्षयना है।' उनका कहना था कि दूसरे धर्मोंके दावोंका हिन्दू धर्ममें और हिन्दू धर्ममें उनके उतनेकी जगह नहीं है।

गीतामें धृष्ट (Regard for Gita). गांधीजी का गीतामें विशेष श्रद्धा थी। वह कहते थे "मे गीताका सत्यके जानके लिए अद्वितीय पुस्तक मानता हूँ।" जीवनके अन्तिम वर्षोंमें गांधीजी को 'Sermon on the Mount' में भी अधिक गीतामें मनोप मिला। "हिन्दू धार्मिक पुस्तकोंमें मेरी आत्माकी मूल निद्रा जाती है।" साथ ही साथ वह धार्मिक पुस्तकोंकी तकीरके करीब न थे। उन्होंने लिखा था "धार्मिक पुस्तकोंकी किसी बात को मे अपनी सर्वशुद्धिमें अधिक महत्त्व नहीं देता।"

धर्म परिवर्तनका विरोध (Opposition to Proselytism). गांधीजी धर्म परिवर्तनके विरोधी थे। विशेषकर जब धर्म परिवर्तन सामुहिक रूप ग्रहण करना था और मुख्यतः धार्मिक लाभोंके लिए किया जाता था। उनका कहना था कि धर्म परिवर्तन तो हृदय में होता है। इसका अर्थ होता है आत्म शुद्धि और आत्म अनुभूति। मानव कल्याणके नाम पर जोस व लाभच दिखाकर धर्म परिवर्तनकी गांधीजी निन्दा करते थे। उन्होंने ईसाई मिशनरियोंको मलाह दी थी कि वे धर्म-परिवर्तनके कार्यको अपने वैश्विक, मेडिकल और इसी प्रकारके अन्य कार्योंमें पृथक् रखें। गांधीजी ने एक बार लिखा था "यदि मुझे अधिकार होता और मे विधि

बना सकता तो मैं भौतिक लाभके लिए धर्म परिवर्तनको एकदम बन्द कर देता।" उनका कहना था कि धर्म परिवर्तनके तरीकोको मीडरकी पत्नीकी तरह मन्देहमे परे होना चाहिए। उनका कहना था कि यदि कोई हिन्दू अपने धर्ममे असन्तुष्ट है तो "उसने कहिए कि वह हिन्दू धर्मका अध्ययन करके अच्छा हिन्दू बने।" प्रत्येक धार्मिक व्यक्तिका कर्तव्य है कि वह एक हिन्दूको अच्छा हिन्दू बननेमें, एक मुसलमान को अच्छा मुसलमान बननेमें और एक ईसाईको अच्छा ईसाई बननेमें सहायता दे। एक व्यक्तिको यह अधिपार है कि वह हिन्दू धर्ममें सुधार करे पर उसे यह अधिकार नहीं है कि वह उसे उखाड़ फेंके। एक व्यक्तिको यह भी अधिकार है कि वह प्रार्थना करे कि दूसरा व्यक्ति उसके धर्मका स्वीकार करले पर उसे यह अधिकार नहीं है कि वह धर्म परिवर्तनका प्रचार करे और दूसरोंको अपने धर्ममें लावे। गांधीजी का कहना था कि हिन्दू धर्मकी कठिनाइयोंका ईसाइयोंको लाभ नहीं उठाना चाहिए। छुआछूतकी समाप्ति हिन्दुओंके प्रयत्न मे ही होगी। ईसाई मिशनरियों को हिन्दू धर्मके दुर्भावसे लाभ नहीं उठाना चाहिए। 'यदि हम हिन्दू छुआछूत हपी दैत्यको नष्ट नहीं कर देते तो वह हिन्दुओंको और हिन्दू धर्म दोनोंको नष्ट कर देगा।'

ईसाई मिशन और मिशनरियों के प्रति दृष्टिकोण (Attitude towards Christian Missions and Missionaries). यद्यपि गांधीजी ईसा मसीह के व्यक्तिगतसे बहुत आकर्षित थे पर ईसाइयों और ईसाई मिशनरोंके बारेमें उनका दृष्टिकोण बहुत कुछ विरोधी था। इसका एक कारण यह था कि अपने जीवनके आरम्भमें जिन मिशनरियों और भारतीय ईसाइयोंसे उनका सम्पर्क रहा था वे मकुचित विचारोंके थे। करीब-करीब उन सबके बारेमें उनकी राय यह थी कि अछूतोंको येन-केन प्रकारेण ईसाई बनाना ही उनका काम था। साथ ही स्वर्गीय भी० एक० एन्ड्रयूज जो पहले ईसाई मिशनरी रह चुके थे, और कुछ भारतीय ईसाई गांधीजी के घनिष्ठ मित्रों और साथियोंमें से थे। उनमेंसे बहुतसे अब भी जीवित हैं और शिक्षा तथा अर्थशास्त्र सम्बन्धी गांधीजी के विचारोंका व्यावहारिक रूप देने में लगे हैं। गांधीजी बराबर निस्स्वार्थ सेवा करनेकी सलाह मिशनरियोंको दिया करते थे। "निस्स्वार्थ सेवा जिसमें स्वार्थका लेशमात्र भी अंश न हो स्वयं उच्चतम धर्म है... धर्म परिवर्तन और सेवा एक साथ चलेंगे।" "उन्होंने मिशनरियोंमें अपना साम्राज्यवाद छोड़ देनेको कहा था।" जैसे ही आप साम्राज्यवाद छोड़ देंगे वैसे ही आपके लिए सेवाका क्षेत्र असीमित हो जायेगा। "उन्होंने उनमें कहा था कि भारतीयोंको जो कुछ वह देना चाहते हैं उसे वह खुद अपनायें।" गांधीजी का कहना था कि "मिशनरियोंको अध्यात्म विद्यासे अधिक मत्पका प्रचार और अनुकरण करना चाहिए।" उनका विश्वास था कि ईसाई उतने त्यागी नहीं होंगे जितने त्यागी हिन्दू होते हैं। उन्हें यह पसन्द नहीं था कि मिशनरी लोग भारतीय ईसाइयोंके विशेष संरक्षक या विरोधी बनें। वह चाहते थे कि ईसाई लोग दूसरे धर्मोंको भी मान्यता

दं। "दूसरे धर्म चाहे जितने अधूरे हों पर वे अपने अनुयायियोंके लिए मूल्यवान हैं।" मैं जनताकी आस्था और निष्ठाको मजबूत बनाना हूँ पर ईसाई मिशन इसे कमजोर करना है।

ईसा मसीह के लिए आदर (Reverence for Christ). ईसाइयों और उनके मिशनरी के प्रति कुछ विपरीत विचारोंके बावजूद गांधीजी ईसा मसीह के स्थानित्ववादीवृत्त आदर करते थे। उनका कहना था कि "ईसा मसीह पूर्णताके उत्तम नमूना है जो जितना ज्यादासे ज्यादा नजदीक होना सम्भव है।" पर उन्हें पूर्ण कहनेका मतलब है कि ईश्वर को भी ईसा मसीह में थोड़ा न मानना। वह ईश्वर के पुत्र उसी प्रकार थे जिस प्रकार हममें से हर एक ईश्वर का पुत्र है। वह मानवताके महान् मिशन और गद्दीद थे, पर वह एकमात्र ईश्वर के अवतार और ईश्वर और मनुष्यके बीच मध्यस्थ नहीं थे। वह भुक्तिदाता (saviour) नहीं थे। उनके प्रायश्चित्तका आध्यात्मिक महत्व ही सकता है पर इसमें अधिक और कुछ नहीं। उनके आदर्शमें जनक कार्योंका कारण उनका आत्मिक बल (psychic power) था।

गांधीजी के प्रिय भजनमें ईसाइयोंके निम्नलिखित भजन भी थे 'Lead kindly Light' और 'When I Survey the Wondrous Cross'। ये भजन गांधीजी की हत्याके बाद भारतीय आराधनावादी द्वारा गाये गये थे।

मौन व्रत (Practice of Silence). गांधीजी मौन रहनेका महत्व जानते थे। अपने जीवनके अन्तिम वर्षोंमें वह नियमित तौर पर सप्ताहमें एक दिन मौन रहते थे। दारौरीक और आध्यात्मिक कामके लिए वह मौन रहना जरूरी मानते थे। मौन रहनेके क्षणोंमें ही वह भगवान की आवाजको सुन सकते थे। ईसाई मिशनरिजिन वह कहा करते थे "आपके हाँडोंकी अपेक्षा आपका जीवन अधिक वाक्पान है (your whole life is more eloquent than your lips.)।

अन्तिम मूल्यांकन (Final Estimate). हमारा गांधीजी जैसे बहुपक्षीय पुरातन को आमातीते नहीं भूल सकता जो परिश्रमी जीवन व्यतीत करते थे और अपनी प्रमदना की परवाह नहीं करते थे। उन्होंने अपने जीवनके ४० वर्षोंमें अधिकमें मध्य और अहिंसा का पालन किया था। वह अपने बारेमें ठीक ही कहते थे "पूर्ण प्रेमकी विधि ही मेरे जीवनकी विधि है।" जिनमें गांधीजी को समझनेकी क्षमता नहीं थी वह उन्हें "पीछे फेंकने वाला" (a throw back) कहते थे जैसा कि हरपट मैथ्यूज के न्यूपर्क टाइम्स में लिखा था। वास्तविकता यह थी कि गांधीजी "आगे ले चलने वाले" और अपने समयमें सदियों आगे थे। हमारे युगके एक उत्कृष्ट प्रगतिशील दार्शनिक पण्डितों ने गांधीजी की हत्या पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था "बहुत अच्छा होता सत्तरनाक है।" अमेरिका के अन्तर्गत पर-राष्ट्र मंत्री जार्ज मार्शल ने कहा था "महात्मा गांधी सारे मानव समाजकी आत्माके प्रवक्ता है।" जीवन पदार्थ भारत के मित्र स्वर्गीय मर स्टैफर्ड रिप्ल ने इसी प्रकार लिखा था "मेरे विमो भी समयके या आधुनिक इतिहासके विमो ऐसे अन्य व्यक्ति नहीं जानता

जिपने भांतिक वस्तुओंके ऊपर आन्मार्गी चक्किवा प्रदर्शन इतने प्रभावपूर्ण और बिगस्तनोय नरीके में बिधा हों।"

SELECT READINGS

- H. T. MAZUMDAR—*Mahatma Gandhi, Peaceful Revolutionary, Twentieth Century Library, Charles Scribner's Sons, New York, 1952.*
- CHANDRASHANKAR SHUKLA—*Gandhiji's View of Life, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1951*
- J. B. KRIPALANI—*The Gandhian Way, Vora & Co. Publishers, Ltd, 3 Round Building, Kalbadevi Road, Bombay 2, 1945.*
- D. K. DUTTA—*The Philosophy of Mahatma Gandhi. The University of Wisconsin Press, Madison, 1953.*
- The Nation's Voice—Gandhi's speeches at the Round Table Conference, Navajivan Publishing House, Ahmedabad 14, 1932.*
- HUMAYUN KABIR (ed.)—*Gandhian Outlook and Techniques—Ministry of Education, Government of India, 1953—Papers Read at International Seminar held at New Delhi in January, 1953 to consider the contribution of Gandhian outlook and techniques to the solution of tensions within and among nations.*
- G. N. DHAWAN—*The Political Philosophy of Mahatma Gandhi, Navajivan Publishing House, Ahmedabad 14, 1951.*
- ROY WALKER—*Sword of Gold, Indian Independence Union, London, 1945.*
- BISHAN SARUP SHARMA—*Gandhi as a Political Thinker, Indian Press (Publications) Ltd., Allahabad, 1956.*
- BHARATAN KUMARAPPA—*Indian Democracy—A Symposium—Article on Sarvodaya Democracy; Association Press, Calcutta, 1955*
- M. K. GANDHI—*Sarvodaya, Navajivan Publishing House, Ahmedabad 14, 1945.*
- M. K. GANDHI—*For Pacifists, Navajivan Publishing House, Ahmedabad 14, 1949.*
- VINOBA BHAVE—*Swaraj Shastra, Padma Publications, Lakshmi Building, Ferozeshah Mehta Road, Bombay, 1945.*

BIBLIOGRAPHY

1. APPADURAI, A.—*The Substance of Politics*, Madras, Oxford University Press.
2. BARKER, ERNEST—*Greek Political Theory Plato and his Predecessors*, London, Methuen.
3. BARKER, ERNEST—*Political Thought in England Spencer to Present Day (H. U. L.)*, London, Oxford University Press.
4. BARNES, LEONARD—*Future of Colonies*, London, Hogarth.
5. BOSANQUET, B.—*The Philosophical Theory of State*, London, Macmillan.
6. BROWN, IVOR—*English Political Theory*, London, Methuen.
7. BRYCE, VISC.—*International Relations*, London, Macmillan.
8. BUELL, R. L.—*International Relations*, London, Pinter.
9. BURNS, C. D.—*Democracy (H. U. L.)*, London, Oxford University Press.
10. BURNS, C. D.—*Political Ideas*, London, Oxford University Press.
11. CARTY, P.—*Economics: A Social Science*.
12. CROSSMAN, R. H. S.—*Government and the Governed: History of Political Ideas and Political Practice*, London, Christopher.
13. DAVIDSON, W. L.—*Political Thought in England: From Hooker to Mill (H. U. L.)*, London, Oxford University Press.
14. DEWEY, J.—*German Philosophy and Politics*.
15. DICEY, A. V.—*Introduction to the Study of the Law of Constitution*, London, Macmillan.
16. DUGUIT—*Modern French Legal Philosophy*.
17. DUNNING, W. A.—*History of Political Theories (3 Vols)*, New York, Macmillan.
18. ELDRIDGE—*The New Citizenship*.
19. ELLIOT—*Lecture at Harvard*.
20. FINEK, H.—*Theory and Practice of Modern Government*, London, Methuen.
21. FORD, J.—*Social Problems and Social Policy*, London, Gurn.
22. GARNER, J. W.—*Introduction to Political Science*, London, American Book Supply Co. Limited.
23. GARNER, J. W.—*Political Science and Government*.

- GETTELL, R. G.—Political Science, London, Gunn.
- GETTELL, R. G.—History of Political Thought, London, Allen & Unwin.
- GETTELL, R. G.—Problems of Political Evolution.
- GIERKE, O.—Political Theories of the Middle Ages, Tr. Montland, London, Cambridge University Press.
- GILCHRIST, R. N.—Principles of Political Science, London, Longmans.
- GREEN, T. H.—Lectures on Principles of Political Obligation, London, Longmans.
- HARRISON, FRIDERIC—On Jurisprudence and the Conflict of Law.
- HALLOWELL, J. H.—Main Currents in Modern Political Thought.
- HAYES C. J. H.—Essay on Nationalism, London, Macmillan.
- HEARNshaw, F. J. C.—Democracy at the Cross-ways.
- HEGEL, G. W. F.—Philosophy of History.
- HOBBS, THOMAS—Leviathan, Ed. Pogson Smith, London, Oxford University Press.
- HOCKING, W. E.—The Philosophy of Law and of Rights, New Haven, Yale University Press.
- HOCKING, W. E.—Lectures at Harvard.
- HOLLAND, T. E.—Elements of Jurisprudence, London, Oxford University Press.
- JENKS, EDWARD—The State and the Nation.
- JOAD, C. E. M.—Liberty Today, (Thinker's Library), London, Watts.
- JOAD, C. E. M.—Modern Political Theory, London, Oxford University Press.
- JONES, SIR HENRY—Idealism as a Practical Creed.
- JOSEPH, BERNARD—Nationality, London, Allen & Unwin.
- KRABBE—Modern Idea of State.
- KRANENBURG, R.—Political Science, London, Oxford University Press.
- LAHIRI & BANERJEE—An Introduction to the Principles of Civics.
- LASKI, H. J.—A Grammar of Politics, London, Allen & Unwin.
- LASKI, H. J.—Introduction to Politics, London, Allen & Unwin.
- LASKI, H. J.—Liberty in Modern State, London, Allen & Unwin.
- LASKI, H. J.—The State in Theory and Practice, London, Allen & Unwin.

BIBLIOGRAPHY

७५५

51. LEACOCK, STEPHEN—*Elements of Political Science*, London, Constable.
52. LINDSAY, A. D.—*I Believe in Democracy*.
53. LINDSAY, A. D.—*Parliament or Dictatorship*.
54. LORD, A. R.—*Principles of Politics*, London, Oxford University Press.
55. MACIVER, R. M.—*The Modern State*, London, Oxford University Press.
56. MACILWAIN, C. H.—*Political Science Quarterly*, March, 1933, Pages 98-100.
57. MAINE, SIR H.—*Early History of Institution*
58. MARRIOTT, J. A. R.—*Mechanism of Modern State*, London, Oxford University Press.
59. MAZZINI GUISEPPI—*Life and Writings*
60. MERRIAM, C. E.—*History of the Theory of Sovereignty since Rousseau*.
61. MILL, J. S.—*On Liberty* (Thinker's Library), London, Watts
62. MILL, J. S.—*Utilitarianism*, (N Univ. Series), London, Routledge
63. MOON, P. T.—*Imperialism in World Politics*, London, Macmillan.
64. RALEIGH, T.—*Elementary Politics*, London, Oxford University Press
65. RANLAUER—*Politics*.
66. RITCHIE, D. G.—*Natural Rights* (Philos. Series), London, Allen & Unwin.
67. ROUSSEAU J. J.—*Social Contract* (Eo'man. Series), London, Dent.
68. RUTHNASWAMY, M.—*Making of the State*, London, Williams & Norgate Ltd.
69. SASTRI, S.—*Rights and Duties of the Indian Citizens*, Calcutta University Press.
70. SCHULMAN, F. L.—*Imperialism and World Politics*.
71. SEITH, JAMES—*Study of Ethical Principles*, Edinburgh, William Blackwood & Sons, Limited.
72. SIDGWICK, HENRY—*Elements of Politics*, London, Macmillan
73. SPECTATOR BOOKLETS—*Parliament or Dictatorship*, London. Methuen.
74. SPENCER, H.—*Social Statics*, London, Watts.
75. STEPHEN, SIR, LESLIE—*Science of Ethics*, London, John Murray
76. TAWNEY, R. H.—*Equality*, London, Allen & Unwin.
77. TAYLOR ■ BROWN—*Human Relations*.

78. TOYNBEE, A. J.—*A Study of History*, London, Oxford University Press.
79. VAUGHAN, G. E.—*Studies in the History of Political Philosophy Before & After Rousseau*, Manchester University Press.
80. WARD, J.—*Sovereignty*.
81. WILDE, N.—*Ethical Basis of the State*, London, Oxford University Press.
82. WILLOUGHBY, W. W.—*Social Justice*.
83. WOOLF, LEONARD—*Imperialism and Civilisation*, London, Hogarth.
84. ZIMMERIN, A. E.—*The Third British Empire*.
85. THE LEAGUE OF NATIONS—*Aims, Methods & Activity*, London, Allen & Unwin.

अनुक्रमिका

तरेके मूल्य,
 मिदान्त, ६३०
 मार्क्स द्वारा परिभाषा, ६३०
 पत्र प्रतिनिधित्व, ६२१
 पत्र पत्र (घोषणा पत्र), मणोपन, ५७४
 शास्त्रिया (समुक्त राष्ट्र सभ), ५४८
 पत्राचारिक नियन्त्रण, ५१५
 तर्क विज्ञान, ५५३-५५४
 राष्ट्रीय नागरिक-उद्घरण मण्डन
 (समुक्त राष्ट्र सभ), ६०८
 अन्तर्गर्णीय न्यायालय (समुक्त राष्ट्र
 सभ), ५४२-५४३, ५८३-५८५
 अन्तर्गर्णीय प्रत्यास-व्यवस्था, ५८०
 अन्तर्गर्णीय बाल मकट कोष (समुक्त
 राष्ट्र सभ), ६११-६१२
 अन्तर्गर्णीय बैंक (पुनर्निर्माण और
 विकास के लिए), ६०४-६०५
 अन्तर्गर्णीय मुद्रा-कोष, ६०५
 अन्तर्गर्णीय विधि, ४३४, ४३९-४४६
 अन्तर्गर्णीय विधि की परिभाषा,
 ४४०
 अन्तर्गर्णीय विधि वास्तव में विधि है,
 ४४१-४४२
 अन्तर्गर्णीय विधि के खान, ४६२
 प्रवृत्ति और अर्थ, ४३९-४४०
 राष्ट्रीय और अन्तर्गर्णीय विधि
 का सम्बन्ध, ४४४-४४६
 व्यक्तिगत अन्तर्गर्णीय विधि और
 मार्क्सवादी अन्तर्गर्णीय विधि,
 ४४४
 स्वयं के सम्बन्ध में वाद, ४४३
 अन्तर्गर्णीय श्रमिक मण्डन (समुक्त
 राष्ट्र सभ), ५४३-५४५;
 ६१२-६१३

अन्तर्गर्णीयतावाद, ४३६-४५२
 अब्राहम डा०, वन्द्यापकागी राज्य की
 व्याख्या, ६६२
 अभिज्ञान नव ६६८
 अम्बेदेकर डा०. मार्क्सवादी इच्छा, ५००
 अरस्तु, राज्य का उदय और जस्तित्व, ६६६
 अराजकतावाद, ४६७
 अन्तर्-मन्यको का मरक्षण (समुक्त राष्ट्र
 सभ), ४६८
 आर्चबलबर्गर, ब्लाक एम०, विदेश सरकार,
 ६२२-६२४
 आग्ल-ईरानी तेल कम्पनी का मामला
 (समुक्त राष्ट्र सभ), ६१७
 आजाद, मोलाना अबुल कलाम,
 गांधीजी की अहिंसा परमपूर्ण, ७६०
 आत्म निर्णय, राष्ट्रीयता का, ५००-५०१
 ६८०
 आर्थिक आयोग, ६०२-६०४
 आर्थिक और सामाजिक परिपक्व
 (समुक्त राष्ट्र सभ), ५७६-५७९
 आदर्शवाद, ४६४-४८७
 आलोचना और समर्थन, ६८०-४८६
 मन्वावन, ४८६-४८७;
 राजनीति में परम्परा, ४६६-६६६
 मिदान्त की व्याख्या, ४६६-६६९
 आदेशात्मक मार्क्सवादी (मुख्य परिपक्व),
 ५७४
 आम सभा (समुक्त राष्ट्र सभ), ४३९-
 ४४०; ५६६-५६९
 आयम जेन्टिलम, ४३१
 ऑस्टिन, विधि की परिभाषा, ४७८
 उत्तरदायित्व का माग्माग्रवाद, ५११

उधार पट्टा करार, ५१०

उपयोगिता मूल्य, ६३०

उपयोगितावाद, ४४७-४६३

उपयोगितावादी विचारक, ४५२-

४६३

परिभाषा और आलोचना, ४४७-

४५०

मूल्यांकन, ४५०-४५२

एकतन्त्रवाद, ६६८

एकात्मवादी दृष्टिकोण (राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सम्बन्ध), ४४५

एकाधिकृत पृजी, ६५०

एटलाण्टिक घोषणा पत्र, ५५७

एण्ड्रूज, सी० एफ०, साम्राज्यवाद, ५२५

एजरस, मार्क्सवाद, ६२९

ऐक्टन, लॉर्ड, राष्ट्रीयता के मिद्वान्त का विरोध, ५००

ओपेनहेम, अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा, ४४१, ४४२

ओपनिवेशिक सम्प्रभुता, ५०५

कन्यूशियस, ७२७-७२८

कल्याणकारी राज्य, भारत में, ६६२

काण्ट, व्यक्ति की स्वाधीनता, ४७१

अन्तर्राष्ट्रीयतावाद, ५३६

कॉटम्की, कार्ल, ६३७

कॉमिन्टर्न, ६५४

कारलेगी, ऐंड्रयू, व्यापार जघड़े के पीछे नहीं चलता, ५०७

कॉर्कू चैनल का मामला (संयुक्त राष्ट्र संघ), ६१७

कार्टी, रेवरेण्ड, पी०, निगमित समाज, ६९०

कालेलकर, काका साहब, गांधीजी के विचार में भारत की समस्याओं

का हल, ७४६

किसानों का स्वामित्व, चीन में, ६५७

केण्ट, टी० डब्ल्यू, कल्याणकारी राज्य की व्याख्या, ६६३

कोकर, एकात्मवादी सिद्धान्त, ७१५

बहुलवादियों का दावा, ७०९

राज्य की सत्ता को सीमित करने के प्रयत्न, ४३७

विधि, ७२२

धार्मिक संघवाद की परिभाषा, ६३८

कोमिन-तांग, ६५५, ६५६

कोल, फेविमनवाद की व्याख्या, ६४४

मह-सम्प्रभुता, ७११

काब, सम्प्रभुता की धारणा, ७०९

विधि की सम्प्रभुता, ७२०-७२१

क्रिस्, मर स्टैफर्ड, गांधीजी का मूल्यांकन, ७५१

क्रौक, डा०, विश्वविद्यालयों का काम, ७००

मुद्र-विज्ञान पद्धान्ता, ७३८

कैब, विधि की परिभाषा, ४३८

खुलचेव, ६५१

खाद्य और कृषि-संगठन, (संयुक्त राष्ट्र संघ), ६०६-६०८

खुला द्वार और बन्द द्वार, ५१५

गांधी, महान्मा, अन्तिम मूल्यांकन, ७५१-७५२

अनवान, ७३७-७३८

अपरिग्रह, ७३९

अमय, ७३९

अर्थ शास्त्र पर विचार, ७४३-७४६

अहिंसा, ७४०

अहिंसा वा दर्शन-शास्त्र, ७३३

अहिंसा निष्क्रियता नहीं, ७३३-

७३४

अहिंसा का आधार, ७३४

अहिंसा की अन्य आवश्यकताएँ, ७३७-७४३

अहिंसा का आधार धार्मिक, ७४०-

- ३६१
अहिंसा सम्पूर्ण जीवन दर्शन, ३६०
अहिंसा सम्मेलन पर निर्भर नहीं, ३४०-
३४३
अहिंसा दवाव नहीं, ३४३
ईमाममोह के लिए आदर, ३५१
ईसाई मिशन और मिशनरियों के
प्रति दृष्टिकोण, ३४०-३५१
कल्याणकारी राज्य, ३३२
बुद्ध और शोषण का विरोध ३३०-
३३३
नया गांधीजी समाजवादी थे?,
३४५-३६६
क्या गांधीजी अन्तर्गद्दीपतावादी
थे? ३४६-३४७
गीता में धर्म, ३६९
शामीन आर्थिक व्यवस्था या पुनर्गठन,
३४६-३६४
दार्शनिक अराजकतावादी, ३३०-
३३१
दुर्बल या अस्त्र, ३३४-३३५
धर्म का मूल, ३४०
धर्म परिवर्तन का विरोध, ३६९-
३४०
धार्मिक विचार, ३४३-३५०
धर्म, ३३९
प्रेम भावना में अन्तःकरण की अपील,
३३५-३३६
भारत में अंग्रेजी शासन, ५००
भारत के गांव, ६२०
मर्जीन युग, ३४३-३६६
मोहनजोदड़, ३४१
राजनीतिक विचारधारा, ३०६-
३५०
राजनीतिज्ञ नहीं, ३२९-३३०
राजनीति का आध्यात्मिकरण, ३३०
राज्य-कार्य, ३३१-३३२
विचारों के मूल, ३०६-३०९
नक्ति के पुत्र, ३४१
मध्य ही ईश्वर है, ३४९
मध्य का आचारभूत सिद्धान्त,
३३५
मव धर्मों की समानता, ३६३-३६८
सोमा सिद्धान्त, ३४५
हिन्दुओं के हिन्दू, ३४९
हृदय-धर्म, ३६८
गांधि, हरमैन, अनाथ वनमानुष में
कुछ ही अच्छे, ३०१
गान्धे, आदर्शवाद का समर्थन, ६८३
गिलब्राइड, राज्य नीतिक प्रहरी के
रूप में, ६३६
वैज्ञानिक टीका, ६३१
माध्याधिकार की परिभाषा, ६३१
माध्याधिकार का विनाश, ६३१
मीअक, बहुलवाद के आधुनिक जन्मदाता
३१०
मोटेल, बहुलवाद, ३१३, ३१५, ३१७
राज्य की आवश्यकता रीति-रिवाजों
की व्याख्या करने और उन्हें
लागू करने के रूप में, ६३०
मीमन, विलियम, लांग्ड, अन्तर्गद्दीपता-
वाद, ५३६
मोयरिंग, नाजी नीति, ३०६
मोवेल्स, डा०, प्रचार-कार्य, ६६९
प्रीत टी० एच०, अहिंसक व्यक्ति, ३६०
गम्भीर आदर्शवादी, ६६९-४८०
उपयोगितावाद, ६४१
ग्रेग, आर० बी०, माध्यवाद का आकर्षण
६३५
घरेलू या आन्तरिक सामन्ते, ५३४-५३५
घोष, प्रो०, कल्याणकारी राज्य का
आधार, ६६३
गोत्रनाम, ६६४
घोषणा पत्र, मयूख राष्ट्र, मध्य का, ६२२
चार स्वाधीनताएँ, एडवोकेट, ५५८-५६२
समी नियम, ५१६
सेम्बरलैन्, जोसेफ, माध्याधिकार का
मनलव कागिज, ५०३

राजनैति-शास्त्र

दह मूय, विल्मन के, ५६२
पाग-वर्ड-जोक, ६५५-६५६

जातीय तत्त्वपता, ४९३-४९५
जिम्मेन, ए० ई०, जातीय एकता, ४०३
राष्ट्रीयता का अर्थ, ४९०
राष्ट्रीयता के मिद्वान्त का विवेचन,
५००

मामान्य कष्ट, ४९९
जेनिम, डा०, आइवर, पश्चिमी योरोप
के सीमित मघ की योजना,
५५४
जोजेक, अन्तर्राष्ट्रीयतावाद, ५३६
राष्ट्रीय निष्ठा और राज्य की निष्ठा
५००

जातीय एकता, ४९४
राष्ट्रीयता की भावना, ४९६
मामान्य कष्ट, ४९९
मामान्य भाषा, ४९६
जोड, आदर्शवाद की निन्दा, ४६९
ममूहवाद और राज्य समाजवाद
एक ही, ६२८
धर्मिक मघवाद की परिभाषा, ६३८

टाएन्वी, सार्वजनिक इच्छा, ५००
टॉमस, नार्मन, साम्राज्यवाद, ५२५
टॉमटॉय, लिमो, गांधीजी पर प्रभाव,
७२८

टीटो, ६५४
टेनिमन, अल्फ्रेड, लोबननवादी दृष्टि-
कोण मे विचार, ६१९
ट्रॉट्स्की, ६५१

इकहाइम, व्यावसायिक मघ, ७१०
डॉज योजना, ६९२
डालर-कृतनीति, ५०७
डिग्वी, विधि का अन्तिम श्रोत, ६३८
टुग्वी, विधि, ७१९

डेवर, ए० एन०, समाजवादी समाज की
परिभाषा, ६६०

तूफानी दल, ६९५
लुबनी, गांधीजी शान्तिवादी मोर्चा,
७३९
तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय, ६५३

थोरो, गांधीजी पर प्रभाव, ७२८-७३०

दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका की अन्तर्राष्ट्रीय
स्विति का मामला (सयुक्त राष्ट्र
संघ), ६१८

दण्ड, ग्रीन के विचार, ४७७
इन्द्रवाद, इन्द्रवादी श्रौतिकवाद, ६२८
इतवादी दृष्टिकोण, (राष्ट्रीय और अन्त-
राष्ट्रीय विधि का सम्बन्ध), ४४४

धर्म (विधि का श्रोत), ४३०
धवन, डा० जी० एन०, अहिंसा का अर्थ,
७३६

नयी तालीम, ७३३
नादवूर, राइन हॉल्ड, विश्व सरकार के
लिए विश्व समाज आवश्यक, ६२०

नाटो, ५१०
नार्जोवाद, आर्थिक मिद्वान्त, ७०३

उदय, ६९१-६९७
जर्मनी का, ६९१-७०७
मूल्यांकन, ७०६-७०७
विचार-धारा, ६९७
मिद्वान्त, ७०१

निगमित राज्य, ६८७
निश्चस्त्रीकरण (सयुक्त राष्ट्र मघ),
५४७-५४८

नैतिक विधिया, ४२७
न्यू फंय, ऑम्बर, विज्व-मघ, ५५३

पच निर्णय (विधि का स्रोत), ४३०
पट्टा, ५१२

परजीवी, ६२९
परिपद (सयुक्त राष्ट्र मघ), ५६०-५४१
परिवहन आयोग (सयुक्त राष्ट्र मघ), ६०४
पाचरा दस्ता, ६५४

पापेन, हर फौन, माताओ का काम
केवल वच्चे पैदा करना, ३००
पिट कॉलेट, अन्तर्राष्ट्रीय विधि की
परिभाषा, ४४०

पिन्डवर्गी, जातीय एकता, ६९४
प्लेटो,

राज्य नैतिक मर्यादा, ६६६

मव मे अच्छा राज्य, ४३६

प्रथम परिषद (मयुक्त राष्ट्र मध)

५७९, ५८१

प्रभाव-शेष, ५१३-५१४

प्रणामी विधि, ४३४

प्रमविदा (राष्ट्र मध), ५६५-५६६

प्राकृतिक विधि, ४३८

प्राविधिक कार्य कलाप, (मयुक्त राष्ट्र
मध) ५४९

प्राविधिक मर्यादा, (पिछटे या अध-
विवक्षित देशों के आर्थिक विकास
के लिए) ६०५

फकिम, आर०, मास्त्र व्यववाद, ५३३

फ्लेट्ट, कुमारी, बहुलवाद की अच्छाईया,
३१३

राज्य एकता स्थापित करने का माधन

३१६

फामिस्टवाद,

इटली का, ६७९-६८३

उद्देश्य ६८०-६८३

अन्तर्राष्ट्रीयता का मनु, ६८६

विचारधारा, ६८३-६८६

मफलताप, ६८६-६८७

फिल्मे, राज्यों के बीच शक्ति का मिडान
ही लागू, ६९९

फिगिम, ३१०

धर्ममय, ३१०

राज्य समुदायों का समुदाय, ३१६

फेन्डिक, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अध-
६४०

फेबियनवाद, ६६०-६६६

फेबियनो द्वारा परित्याग, ६४४

भारत के लिए फेबियनवाद की

अनुकूलता, ६६६-६६७

माकसवाद में अन्तर, ६६४

श्रमिक मर्यादा में अन्तर ६६३

पयो/वास्तु मार्ग की विचारधारा पर

प्रभाव ६०६

वगदाद समझौता, ५९३

वर्गमान प्रो० अर्नेस्ट हिटलर टुमर के
समान, ३००

वर्त्म, मो० डो० मास्त्राववाद १०६

वर्नाइमर, गांधीजी का मर्यादा ५१

वर्हिदेमिता ५१४

वहुलवाद, ३०९-३२६

राज्य की सम्प्रभुता और मध की
मर्यादा, ३०९-३१३

मर्यादा, ३१३-३१७

राज्य की सम्प्रभुता और अन्त-
राष्ट्रीयतावाद, ३१७-३१८

मर्यादा और आलोचना ३१८-
३१९

राज्य की सम्प्रभुता और विधि,
३१९-३२१

मर्यादा और आलोचना, ३२१-
३२२

निष्कर्ष, ३२२-३२६

राजनैतिक बहुलवाद और भारत,
३२६

बार्बर, अर्नेस्ट, अमेज़ी मास्त्राव और
विश्व शांति, ५३०

चीन का राजनैतिक दर्शन, ६७०

राज्य का कार्य समायोजन, ६७३

राज्य व्यवस्था स्थापित करने वाला,
३१६

मधों का व्यक्तित्व, ३१०

बार्नेम्, लियोनार्ड, अमेज़ी मास्त्राव
भारतमयी का मिडारा, ५००-५२१

आधुनिक युग और मास्त्राववाद
उपनिवेग, ५०७

- साम्राज्यवाद, और विज्वशान्ति,
५३०
वाह्य सम्प्रभुता, ७१७
बुध, अन्तर्राष्ट्रीय गठबन्धन का विरोध,
७०३
ध्वजे, डॉ० रान्क, गांधीजी मन्त्र अन्त-
राष्ट्रीयतावादी, ७४६
जेम्स, जेम्स,
अन्तर्राष्ट्रीयतावाद, ५३६
उपयोगितावाद, ४४८-४४९,
बेवरिज, सर विलियम, विश्व संघ, ५५४
बोकर, पॉल, राज्य सार्वजनिक हितों
और राष्ट्रीय एकता का एकमात्र
प्रतिनिधि, ७१६
विधिष्ट सम्प्रभुताएँ ७१०
ओरोदिन, ६५५
बोल्लोविशवाद, ६२७
बौद्धिक सहयोग (समुक्त राष्ट्र संघ),
५५०
ब्युएल, आर० एल०, प्रभाव-क्षेत्र, ५१३
साम्राज्यवाद और व्यापार, ५०७
ब्राह्म, लार्ड, जातीय एकता, ४९३
राष्ट्रीयता की भयाना, ४८९
ब्रायली, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास
के कारण, ४३९
परिभाषा, ४४०
ब्रिटेन का मजदूर दल, ६४५-६४७
भावे, विनोबा, समाज में नयी व्यवस्था
६६१
भाषा की एकता, ४९६-४९७
भौगोलिक एकता, ४९१
मयाई, डॉ० जान,
समाजवादी समाज, ६५९-६६०
मदारपागा,
अन्तर्राष्ट्रीयतावाद, ५३४
विश्व समाज का समर्थन, ५५३,
६१९
मध्यवर्ग, ६२९
मईल, डा० अलवे, माधन और माध्य
७३०
मन्त्रिष्य शुद्ध, ६५७
माओ, ६५४
माओवाद, ६५४
लेनिनवाद की शिक्षाओं में माओ
का योग, ६५६
मानव अधिकार (समुक्त राष्ट्र मन्त्र),
६०९-६१०
मार्कवी, सर विलियम, वैज्ञानिक
टीकाएँ, ४३०
मार्क्स,
पूँजी की परिभाषा, ६३०
साम्यवाद, ६२६-६२७
शिक्षाएँ, ६२८-६३३
आलोचना, ६३३-६३५
मार्शल, जार्ज,
गांधीजी का मूल्यांकन, ७५१
मिल, जॉन स्टुअर्ट,
उपयोगितावाद, ४४९
प्रतिभावान व्यक्तिवादी, ६०८
विचारों की एकता, ४९६
सरकार और राष्ट्रीयता की सीमाएँ
एक ही हो, ५००
मिल, जेम्स,
उपयोगितावाद, ४५९
मुनरो-सिद्धान्त, ६७१
मुसोलिनी, इटली के एकछत्र शासक,
६८२
जातीय एकता, ४९४
निगमवाद, ६८७
फास्टिवाद एक धार्मिक धारणा,
६८३-६८४
वीसवी शती सर्वाधिकारी राष्ट्र
का युग, ६६५
युद्ध की आवश्यकता, ६७०
राज्य की महत्ता, ६६९
व्यक्तिगत सम्पत्ति, ६८८
साम्राज्यवाद जीवन का अनन्त

नियम, ६७०
 मून, पाकेंर, कच्चा माल और रगभेद
 ५२७
 भारत में विटिग साम्राज्यवाद,
 ५२१-५२२
 साम्राज्यवाद मध्य विक्टोरियन युग
 का बचा-बुचा अंग, ५३१
 मेटलैण्ड, बहुलवाद के आधुनिक जन्म-
 दाता, ७१०
 मेन, साम्याधिकार, ४३१
 मैकाइवर,
 ग्रीन की आलोचना, ४७३
 यूनानी का धर्म नागरिकता, ६६५
 राज्य और विधि, ४३३
 विचारों में बहुलवाद की छाप,
 ७११-७१२
 विधि और नैतिकता, ४३४, ४३५
 विधि का अर्थ, ४२७
 विधि का स्रोत, ४२९
 व्यक्तिवाद और समूहवाद, ६२८
 सर्वसामर्थ्य का मनलव अगामर्थ्य,
 ७०८
 मैकियावेली,
 मनुष्य सम्पत्ति में लिप्त, ७४५
 मैजिनो,
 जातीय एकता, ४९३
 भौगोलिक एकता, ४९२
 सार्वजनिक इच्छा, ५००
 व्यक्तिवाद, ४६७
 मग योजना, ६९२
 माचिकाए (मधुवन राष्ट्र मंत्र), ६१६
 मुड,
 चीन के विचार, ४७३
 मुड को उद्घेप करना (सधुवन
 राष्ट्रमंत्र), ५४६-५४७
 रलम्यामी, एम० भौगोलिक एकता, ४९३
 रवीन्द्रनाथ ठाकुर,
 राष्ट्रीयवाद की निन्दा, २०१-२०२

रत्किन,
 गांधीजी पर प्रभाव, ७२८
 रॉको,
 श्रेणी समाजवाद, ६४७
 राजनीतिक विधि, ४२७
 राजनीतिक सम्प्रनुता, ४९९
 राज्य का कार्य,
 चीन के विचार, ४७७
 राज्य-मिडान्न, चीन का, ६७२
 राष्ट्रीयतावाद, ८८९-५०६
 राष्ट्र और राष्ट्रीयता की परिभाषा
 ४८९-४९०
 राष्ट्रीयता का अर्थ, ४९०
 राष्ट्रीयता के तत्त्व, ४९०-५००
 राष्ट्रीयता का आत्म निर्णय, ५००-५०१
 क्या राष्ट्रीयता एक वरदान है?
 ५०१-५०४
 राष्ट्र मंत्र, ५३७
 मूल्यारन, ५६४-५५७
 अंग, ५३९-५६४
 मइस्यना और प्रत्याहरण, ५३८-
 ५३९
 मइस्य डुय्य ५६८-५५७
 रिची, डी० जी०,
 उपयोगितावाद, ६५१
 रीति-रिवाज (धर्म का स्रोत), ४२९
 रूतो,
 पागलों की दुनिया में स्वस्थ दिमाग
 का होना भी एक प्रकार का
 पागलपन, ७४२
 रेनन,
 जातीय एकता, ४९३
 सामान्य आदिता हिन, ४९८
 रैम्जे म्योर,
 भाषा की एकता, ४९६
 राष्ट्रीयता का आत्म निर्णय,
 ५००
 राष्ट्रीयता की भावना का पोषण,
 ४९५
 सामान्य अधीनता, ४९९

रोएम,

कामरता चरित्र का दोष, ६७१

रोज० जे० एच०,

जातीय एमता, ६९८

भाषा का प्रभाव, ४९६

राष्ट्रीयता की परिभाषा, ६९०

लोड्स, मेमिल, लोकोपकार, ५२२
लॉरम, अन्तर्गट्टीय विधि की परिभाषा,
४४०

लास्को, अनौमित अधिकार मत्ता, ७१७

बाह्य सम्प्रभुता, ७१८

विधि की कसौटी, ४३९

श्रममन्वन्धी अभिसमयों का महत्त्व,
५४४

सधों का स्वायत्त, ६३५

लिण्डने, ए० डी०,

निगमों पर राज्य का नियन्त्रण, ७१२

मन्त्रभु राज्य, ७१५

मन्त्रभुता मिढान्त, ७०९

मर्वाधिकारवाद, ६७३

लिबिनीक,

शान्ति अभिभाग्य, ५५९

ली ताओ-चाओ, ६५४

लेडलर, फेबियनवाद, ६४३

श्रमिक मधवाद की परिभाषा, ६३९

लेनिन, ६५०

लेनिनवाद, ६५०

लेनिन की आलोचना और मूल्यांकन,
६५०-६५३

मावर्मवाद का मञ्जोधन, ६५०

लांबतानिक केन्द्रीयकरण, ६५२

लांप, परिवार, धर्म आदि का, ६३२

राज्य का श्रमिक, ६३२

लांग युद्ध, ६३१

लॉन्टेयर,

भाषा और माहिल्य, ४९५

लाई,

बेन्द्रीकृत राज्य, ७०८

मत्ता का विभाजन, ७११

विकामवादी, समाजवाद श्रमिक विकाम,
द्वारा, ६३७

वित्त पूजी, ६५०

वित्तीय नियन्त्रण, ५१४

विधान (विधि का स्रोत), ४३२

विधि, ४२७-४४६

नैतिकता और विधि में समानता,
४३६

परिभाषा, ४२८

प्रकार, ४३२-४३४

विधि का अर्थ, ४२७-४२८

विधि और नैतिकता, ४३४-४३६

विधि शब्द का उपयोग, ४२७

विधि और राज्य, ४३७

विनिमय मूल्य, ६३०

विल्किंसन, कुमारी,

फाबिस्टवाद, ६८७

विशिष्ट-समितियां

(संयुक्त राष्ट्र सभ), ५८१

विश्व स्वायत्त संगठन (संयुक्त राष्ट्र
सभ), ६१०-६११

वीटो (संयुक्त राष्ट्र सभ), ५७०

वीमर गणराज्य, ६९२-६९३

वुड्रो विल्सन,

विधि की परिभाषा, ४२८

विधि के विकास की प्रक्रिया, ४३२

वूटन बारबारा,

योजनाएँ और राजनीतिक दल, ६६३

वूल्फ, लियोनार्ड,

माक्राज्यवाद, ५२१; ५३३

वेव,

मांविपल साम्यवाद एक नयी सम्मना,
६७७

वेल्म, एच० जी०,

विश्व एक एकाई, ६१९

माक्राज्यवाद, ५२५

वैज्ञानिक टीकाएँ (विधि का स्रोत),
४३०

वैज्ञानिक विधि, ४२७

- वैज्ञानिक समाजवाद, ६३३
 वैदिक नीति मध. (अमेरिका का) सर्वा-
 धिकारवादी राज्य का विवेचन, ६६६
- वैधिक-न्याय-न्याय (मयूक्त राष्ट्र मध)
 ५६९
 वैधिक दण्ड (मयूक्त राष्ट्र मध) ६१६
 ध्यानवाद, ६७७
 व्यक्त-प्रदेश और स्वनामनशील क्षय,
 ५७९-५८०
 व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, ६६०
- शास्त्र, डा०,
 साम्राज्यवाद, ५०६
 शान्तनगर, फंज
 नाजीवाद, ६६६
 शान्तपुष्प समजीता, मृच्छा परिषद
 ५७०-५७३
 शिल्पिटी,
 राष्ट्रीयतावाद की निन्दा ५००
 शमन, एफ० एल०,
 प्रत्याग व्यक्त्या, ६१६
 शमन, एफ० जी०,
 अन्तर्राष्ट्रीय समाज की व्यापार
 गिलाए, ६३९
 लाकोरकार, ५०३
 समाजार्थन प्रदेश, ५१७, ५१८
 साम्राज्यवाद, ५०५
 साम्राज्यवाद और भावद्वेग की जनता
 ५२६
 साम्राज्यवाद के दिन अब इनेगिन
 ५३१
 स्वादेश, बी० आर्०
 चीनी साम्यवाद, ६७७-६७८
 स्वादेशवादी,
 अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास के
 कारण, ६३९
 स्वाधीनता का भाव, ५०६, ५१३
 शक्ति मयवाद, ६३८
 अन्तर्गत समाज का क्षाया, ६६३
- पद्धतिया, ६४०
 परिभाषाए, ६३८-६३९
 समाजवाद से तुलना ६४१
 गिलाए, ६३९-६४०
 शक्ति मयवाद की आलोचना,
 ६६१-६६२
 श्रेणी समाजवाद ६४७-६४८
 आलोचना, ६५०
 गुण, ६५०
 मल मत्र व्यावसायिक प्रतिनिधित्व
 ६४९
 श्रेणी की परिभाषा, ६६३
 श्रेणी पद्धति के उदय के कारण,
 ६४८
 श्रेणी समाजवाद के प्रधान समर्थक
 ६६८
 श्रेणी समाजवाद का कार्यक्रम,
 ६६८-६६९
 श्रेणी समाजवाद की पद्धतिया,
 ६६९, ६७०
- सचर और पारगमन (मयूक्त राष्ट्र मध),
 ५६९, ६०६
 मयूक्त राष्ट्र मध ५६०
 आधिक-शोध से मयूक्त राष्ट्र मध
 की गरमनाय, ६००-६०९
 उद्देश्य, ५६६
 कार्य सम्पादन ५८७-५८८
 घोषणा पत्र पर पुनर्विचार, ५८६
 ग्राफीन जगत, ६१५-६१६
 दानादान की सुविधाओं में सुधार
 ६०८-६०९
 गवर्नीतिव मयादगण, ६०१-६०२
 गवर्नीतिव और मुराशानाव, ५८८-
 ६००
 गवर्नीतिव मया सुधारा-
 सम्बन्धी प्रश्न, ६००-६०१
 अन्तर्गत समर्थ, ६०१
 उत्पन्न, ५८८
 फॉरे चेंबल का प्रश्न, ६००

काश्मीर का प्रश्न, ५९६-६००
 कोरियाई प्रश्न, ५९३-५९६
 दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय वनजों
 के माय व्यवहार, ५९०-५९१
 किलिगतीन, ५९१-५९३
 बर्लिन का प्रश्न, ६००
 यूनान का प्रश्न, ६००
 ग्रीस और लेबनान, ५८८
 स्पेन का प्रश्न, ५८९-५९०
 हिन्द-चीन का युद्ध, ६०१
 हिन्दोसिया का प्रश्न, ५८९
 वैश्विक झगड़े, ६१६
 समुक्त राष्ट्र सभ के अग, ५६६-
 ५८६
 समुक्त राष्ट्र सभ, और विश्व सरकार
 ६१९-६२१
 समुक्त राष्ट्र-सभ के माध्यम में
 विश्व-सरकार, ६२२-६२४
 सदस्यता, ५६५-५६६
 सामाजिक, मानवतावादी और
 सांस्कृतिक क्षेत्रों में सफलताएँ,
 ६०९-६१४
 सिद्धान्त, ५६५
 समुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान और
 संस्कृति संगठन, ६१३
 समुक्त विदेशी शासन, ५१४
 मरुस्थित राज्य और अर्ध-मरुस्थित राज्य,
 ५१२
 मन्त्रिपरिषद् (समुक्त राष्ट्र सभ), ५४१-
 ५४२, ५८५-५८६
 समाजवाद, ५१६
 समाजवाद, समाजवादी और साम्यवादी
 विचारधारा का विकास, ६२६-६६४
 भारत के लिए समाजवाद, ६५८-
 ६६४
 मार्क्स के निधन के बाद समाजवाद,
 ६३६
 समाजसेवी और मानवताप्रेरित कार्य
 (समुक्त राष्ट्र सभ), ५५०-५५०
 ५६२७

सम्मान, धर्म के विचार, ४७८
 सर्वोच्च, ६३३
 भविष्य, ६३३
 हम में सर्वोच्चवाद, ६३५-६३९
 लोकतन्त्रीय सर्वोच्च, ६६६
 सर्वोच्चवाद की राज्य, ६६५-७०३
 सर्वोच्चवाद का अर्थ, ६६५-६६७
 सर्वोच्चवाद की सफलताएँ, ६६७
 सर्वोच्चवाद की विरोधताएँ,
 ६६७-६७३
 सर्वोच्च, आन्दोलन, ६६१
 सांख्यिक आयोग (समुक्त राष्ट्र सभ), ६०६
 सांख्यिक विधि, ६३३
 सांख्यिक तानाशाही, ६६७
 साइबेरिया, नाजीवाद, ६६६
 साइबेरिया, प्रो० जॉन, भारत को सब में
 अधिक सगरा निष्फल लोकतन्त्र में,
 ६६४
 साधारण विधि, ४३३
 सामाजिक विधियाँ, ४२७
 सामान्य अधीनता, ४९८-४९९
 सामान्य आधिकारिक हित, ४९८
 सामान्य कष्ट, ४९९
 सामान्य संस्कृति, ४९५-४९६
 सामुदायिक योजनाएँ, ६६७
 सामूहिक शान्तिवाद, ६८०
 साम्राज्यवाद, ५०४-५३४
 अर्थ, ५०४-५०५
 आधुनिक साम्राज्यवाद, ५१०
 कारण, ५०५-५१२
 क्या साम्राज्यवाद का औचित्य है?
 ५१९-५२०
 क्या साम्राज्यवाद औपनिवेशिक
 जनता के लिए लाभप्रद है?
 ५२०-५२६
 क्या साम्राज्यवाद मानवता की जनता
 के लिए लाभप्रद है? ५२६-
 ५२९
 क्या साम्राज्यवाद
 मध्य के कारण स

विश्वशान्ति में सहायता देना है? ५२९-५३१

क्या साम्राज्यवाद का कोई विकल्प है? ५३१-५३४

अम्यवाद, ६२६

आलोचना, ६३३-६३४

आवरण, ६३५-६३६

अम्याधिकार (विधि का स्रोत), ४३१

तीन वर्ग, ४३१

वैज्ञानिक इच्छा, ४९९-५००

वैज्ञानिक विधि और वैयक्तिक विधि, ४३३

मोन्स, फॉन, युद्ध मानव सफलता की पराकाष्ठा, ७००

मुलवाद, ४४७

मुरझा-परिपद, ५६९-५७६

मिठ, जेम्स, इन्द्रिय चेतना, ४४८

यूनानी मोति-शास्त्र, ४६५

विद्रोह कय उचित, ४६८-४६९

सेबाइन, नियम का महत्त्व, ६८९

क्रांतिवाद, ६८७

बहुलवाद, ७२४

सेमुअल, बाइबाउण्ट,

एकपक्षीय निरासनीकरण से सद्भावना नहीं, ५५९

सैनिक गठबन्धन, ५१६

सोवियन, ६५३

हरमुले, जूलियन, अक्रोबा में साम्राज्यवाद, ५११

हॉकिंग, प्रो०,

राष्ट्रीयता का आत्मनिर्णय, ५०१

साम्राज्यवाद, ५२५

साम्राज्यवाद का नैतिक प्रभाव, ५२८; ५२९

हॉज्मन,

आदर्शवाद की आलोचना,

४८२

हॉर्लेय, विधि की परिभाषा,

४२९

साधारण विधि का विभाजन, ४३३

हिटलर, जीने के लिए युद्ध करना

आवश्यक, ६९९

तानाशाही रूप, ६९७

प्रचार कार्य, ६६९; ७०५

प्रथम मन्त्रिपरिषद, ६९६

म्युनिख पर घावा, ६९५

संयुक्त सरकार का निर्माण, ६९६

युद्ध की आवश्यकता, ६७०

हिटलर और मुसोलिनी में अन्तर

६९४

हिटलर एक अज्ञात व्यक्ति के रूप

में, ६९४

हिटलर राष्ट्रपति और अध्यक्ष दोनों,

६९६

हित-क्षेत्र, ५१३

होगेल,

इन्द्रवाद, ६२६

सर्वाधिकारवादी राज्य को दार्शनिक

रूप, ६६५

मितलिनकास्ट-सिद्धान्त, ६९८

हमामु कवीर,

गांधीजी उदार परम्परा व दार्शनिक

अराजकता की परम्परा के उत्तरा-

धिकारी, ७३२

गांधीजी की विचारधारा में पद्धति

की बमो, ७२९

ह्वर, जी० ई०,

अमिक सपवाद की परिभाषा, ६३९

हेन, सी० जे० एच०,

आतीय एकता, ४९४

धर्म एवता, ४९७

राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रीयता में

अन्तर, ४९०

राष्ट्रीयता का निर्माण भूगोल द्वारा

नहीं, ४९२

राष्ट्रीयता वरदान कब, ५०३

राष्ट्रीयतावाद की निन्दा, ५०२

हेन्री जोन्स,

दयार्थवादियों की आलोचना, ४८१

हेनरी ड्रमण्ड,	नाजीवाद, ७०६
उपयोगितावाद, ४४८	फॉसिस्ट विचारधारा, ६८६
हेनरी मेन,	मानवता का आदर्श समस्त राष्ट्रों
विधि की परिभाषा, ४२८	से ऊँचा, ५०३
हैन्सोल, डा० विलीबाल्ड,	मार्क्स के विचार, ६२७
यौन अनैतिकता का समर्थन, ७०२	मार्क्सवाद की आलोचना, ६३३
हैमिल्टन, वाल्टर,	६३५
व्यक्तिवाद भी समूहवाद, ६२७-६२८	श्रेणी समाजवाद, ६४७
हैलोवेल,	
उपयोगितावाद, ४४७	क्षेत्रीय व्यवस्थाएँ, ५७४

